© भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

http://agua.cag.gov.in

Printed at Shiva Offset Press, Dehradun Ph. 0135-2715748

उत्तराखण्ड सरकार प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2013

सत्यमेव जयते

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए





उत्तराखण्ड सरकार
प्रतिवेदन संख्या 1 वर्ष 2013

विषय सूची

विवरण	प्रस्तर सं.	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		vii
अध्याय-1 **सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्रों का परिचय**		
सामान्य प्रस्तावना	1.1	1
अध्याय-2 **सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्रों का परिचय**		
सामान्य प्रस्तावना	2 क	5
लेखापरीक्षा अधिदेश	2.1	5
लेखापरीक्षा आयोजना एवं संचालन	2.1.1	5
राज्य सरकार का व्यय विवरण	2.1.2	6
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव	2.1.3	7
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	2 ख	9
निष्पादन लेखापरीक्षा		
ग्राम्य विकास विभाग		
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	2.2	13
विषयक लेखापरीक्षा		
निर्वाचन विभाग	2.3	43
श्रम विभाग		
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली	2.4	51
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग		
समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई सी डी एस)	2.5	61
लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
समाज कल्याण विभाग		
निष्फल व्यय	2.6	75
धन का अवरोधन	2.7	76
खेल विभाग		
अतिरिक्त परिहार्य व्यय	2.8	77
उच्च शिक्षा विभाग		
परिहार्य लागत वृद्धि	2.9	79
लोक निर्माण विभाग		
ठेकेदार को अदेय लाभ	2.10	80
अनियमित व्यय	2.11	81
परिहार्य अतिरिक्त व्यय	2.12	82
मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा		
उद्यान विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा	2.13	84

अध्याय-3 **राजस्व विभाग**		
सामान्य परिचय	3 ग	119
लेखापरीक्षा आदेश	3.1.2	119
लेखापरीक्षा के आयोजना एवं क्रियान्वयन	3.1.3	119
राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ	3.1.4	119
बजट अनुमानों (बी ई) तथा वास्तविक में भिन्नता	3.1.5	123
राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत	3.1.6	124
कर राजस्व के संग्रह का विश्लेषण	3.1.7	125
राजस्व बकायों का विश्लेषण	3.1.8	125
कर निर्धारण का बकाया	3.1.9	126
करापवंचन	3.1.10	126
कर वापसी दावों का निस्तारण	3.1.11	127
विभागों/सरकार की लेखा परीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया	3.1.12	127
राज्य सरकार के हित के संरक्षण एवं जवाबदेही लागू करने में विभागाध्यक्ष की विफलता	3.1.13	128
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	3.1.14	128
प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर	3.1.15	129
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग का प्रत्युत्तर-संक्षिप्त स्थिति	3.1.16	129
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	3.1.17	129
स्वीकृत प्रकरणों के राजस्व की वसूली	3.1.18	130
लेखापरीक्षा परिणाम	3.1.19	130
इस रिपोर्ट के राजस्व अध्याय के विषय	3.1.20	130
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3 घ	131
निष्पादन लेखापरीक्षा		
वाणिज्य कर विभाग		
उत्तराखण्ड में मूल्यवर्धित कर प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	3.2	132
केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा		
राज्य आबकारी विभाग	3.3	156
अध्याय-4 **आर्थिक खण्ड (पी एस यूज)**		
सामान्य प्रस्तावना	4 ई	165
लेखापरीक्षा अधिदेश	4.1.2	165
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में निवेश	4.1.3	166
बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण	4.1.4	167
सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान	4.1.5	168
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) की कार्यकुशलता	4.1.6	169
लेखे के अन्तिमकरण में बकाया	4.1.7	171
अकार्यरत सा क्षे उ का समापन	4.1.8	172
लेखा टिप्पणियाँ और आन्तरिक लेखापरीक्षा	4.1.9	172
आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली	4.1.10	174

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति (पृ ले प प्रति)	4.1.11	175
सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन	4.1.12	175
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार	4.1.13	175
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	4 एफ	176
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	4.2	178
लेन-देन की लेखापरीक्षा		
उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड		
ब्याज की हानि	4.3	221
उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड		
₹ 3.14 करोड़ की परिहार्य हानि	4.4	222

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.1	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 से संबंधी प्रावधान	225
2.2	31 मार्च 2012 को लम्बित विभागीय टिप्पणियों (सामान्य और सांख्यिकीय प्रस्तरों के अतिरिक्त) का विवरण	226
2.3	योजना के कार्यान्वयन में सम्बद्ध सरकारी पदाधिकारियों के कार्य और जिम्मेदारियाँ	227
2.4	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयकों (डी पी सी) के लेबर बजट का विवरण	228
2.5	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयकों (जि का स) की वित्तीय स्थिति	229
2.6 *(अ)*	राज्य, नमूना जाँच किये गये जि का स और नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड में रोजगार सृजन का विवरण	230
2.6 (ब)	राज्य, नमूना जाँच किये गये जि का स और नमूना जाँच किये गये कार्यक्रम अधिकारियों में रोजगार सृजन का विवरण	230
2.7	एम आई एस और एम पी आर में वर्णित आँकड़ों का विवरण	231
2.8	पदस्थापन स्थिति	232
2.9	लोकसभा चुनाव-2009 के दौरान अधिक व्यय को दर्शाता विवरण	233
2.10	विधान सभा चुनाव-2012 के दौरान अधिक व्यय को दर्शाता विवरण	234
2.11	आई सी डी एस सेवाएँ (2011-12)	235
2.12	प्रशिक्षण	235
2.13	पर्यवेक्षण का विवरण (2011-12)	236
3.1	अधिनियम के मुख्य अंश	237
3.2	वसूली हेतु लम्बित बकायों की सूची (आर 3 पंजिका के अनुसार)	239
3.3	कर का न्यूनारोपण	241
3.4	कर का अनारोपण	243
3.5	पलायित कराधेय कारोबार	245
3.6	ब्याज का कम जमा	246
3.7	आई टी सी का अनियमित लाभ	253
3.8	प्रपत्र-*XI* का अनधिकृत निर्गमन	255
3.9	प्रपत्र-*XI* पर अनियमित रियायत	256
4.1	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे	262
4.2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबधित, 31 मार्च 2012 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं जन शक्ति को दर्शाती विवरणी	268
4.3	मार्च 2012 के अन्त में वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान व उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी, ऋण अपलेखन एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण तथा गारन्टी वचनबद्वता को दर्शाती विवरणी	276

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ संख्या
4.4	राज्य सरकार द्वारा कम्पनियो में किया गया निवेश जिनके लेखे 30 सितम्बर 2012 तक अन्तिमीकृत हुए को दर्शाती विवरणी	278
4.5	2007-08 से 2011-12 के दौरान ई एच टी स्तर पर पारेषण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण	280
4.6	पिछले पांच वर्षो के दौरान 2011-12 तक वोल्टेज वार क्षमता, वृद्धि लक्ष्य; वास्तविक वृद्धि व कमी को दर्शानेवाला विवरण	281
4.7	2007-12 के दौरान पारेषण लाइनों के कार्य सम्पादन अधिनिर्णत में देरी को दर्शाने वाला विवरण	283
4.8	कम्पनी की उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना (यू आई टी पी) की योजना को दर्शाने वाला विवरण	284
4.9	2007-08 से 2011-12 के दौरान पारेषण हानियों को दर्शाने वाला विवरण	287

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन का अध्याय-1 सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्रों का सामान्य परिचय एवं प्रत्येक क्षेत्र के लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा देता है।
3. इस प्रतिवेदन का अध्याय-2 सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यूज) का सामान्य परिचय देने के साथ-साथ क्षेत्र से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा, विषयक लेखापरीक्षा, एक सरकारी विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा लेन-देन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के निष्कर्षों की रुपरेखा देता है।
4. इस प्रतिवेदन के अध्याय-3 में राजस्व क्षेत्र का सामान्य परिचय एवं राजस्व क्षेत्र में हुई निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभागीय केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं।
5. इस प्रतिवेदन का अध्याय-4 आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज) के सामान्य परिचय तथा सभी चार क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेन-देन लेखापरीक्षा प्रस्तरों से सम्बन्धित है।
6. 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे की जाँच से उठे मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों को समाविष्ट करते हुए, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन-शीर्ष के अन्तर्गत पृथक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।
7. इस प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रकरणों में, जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की ले प की प्रक्रिया में संज्ञान में आये प्रकरणों के साथ-साथ वैसे प्रकरण भी सम्मिलित हैं, जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आये थे पर पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, एवं वर्ष 2011-12 की अवधि के उपरान्त भी संज्ञान में आये प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित हैं।
8. भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों (मार्च, 2002) के अनुरूप ले प का सम्पादन किया गया है।

अध्याय 1

सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्रों का परिचय

1.1 सामान्य परिचय

लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए सरकारी विभागों को सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-पी एस यू) तथा सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समूहीकृत किया गया है। इस प्रतिवेदन में सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्रों के गैर-पी एस यू एवं पी एस यू दोनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ आच्छादित हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-2** सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यू) से सम्बन्धित है। क्षेत्रवार पुनर्गठन के अन्तर्गत, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिवों/ सचिवों/ प्रबन्ध निदेशकों/ निदेशकों की अध्यक्षता में राज्य के सामाजिक क्षेत्र में 32 सरकारी विभाग एवं 38 स्वायत्त निकाय, आर्थिक क्षेत्र में 20 सरकारी विभाग तथा तीन स्वायत्त निकाय, सामान्य क्षेत्र में 23 सरकारी विभाग एवं एक स्वायत्त निकाय हैं जिनकी लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा की जाती है।

इस अध्याय में राज्य सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित इकाईयों की विस्तृत रूपरेखा, इन विभागों/निकायों के विभिन्न क्षेत्रों के अधीन पिछले तीन वर्षों (2009-12) के दौरान व्यय की रूपरेखा तथा लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों के आच्छादन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, निष्पादन लेखापरीक्षा, विषयक लेखापरीक्षा, सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों में लेन-देन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निष्कर्ष एवं एक सरकारी विभागों के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी (सी सी ओ) आधारित लेखापरीक्षा परिणाम भी इस अध्याय में शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-3** राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित है। क्षेत्रीय पुनर्गठन के अन्तर्गत राजस्व क्षेत्र के अधीन सरकार के पाँच विभाग (वाणिज्यिक कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन, मनोरंजन कर) सम्मिलित किये गये हैं। ये कर राजस्व से सम्बन्धित है। सामाजिक क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले अन्य विभाग करेत्तर राजस्व का योगदान करते हैं। कर प्राप्तियों के प्रमुख क्षेत्र - बिक्री/ व्यापार पर कर, वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा प्रशासित सेवाओं पर कर, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रशासित राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस, वाहनों पर कर आदि हैं। उपर्युक्त पाँच विभागों की कुल 239 इकाईयों में से 106 इकाईयों की लेखापरीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व क्षेत्र द्वारा सम्पादित की गई है।

इस अध्याय में राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र की कर एवं करेत्तर प्राप्तियाँ, राजस्व बकायों का विश्लेषण आदि के अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयों की विस्तृत रूपरेखा सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, इस

अध्याय में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा राजस्व क्षेत्र सम्बन्धी विभागीय केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-4** आर्थिक क्षेत्र (पी एस यू) से सम्बन्धित है। क्षेत्रवार पुनर्गठन के अन्तर्गत, आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के 20 विभाग हैं। जिनमें कुछ प्रमुख विभाग यथा उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन एवं मत्स्य, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राम्य एवं लघु उद्योग आदि हैं। राज्य में 22 कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम हैं। जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को करने हेतु कार्यशील राज्य पी एस यूज को स्थापित किया गया है। उत्तराखण्ड में राज्य के पी एस यूज के उपक्रमों का राज्य आर्थिकी में प्रमुख स्थान है। सितम्बर 2012 तक कार्यशील राज्य पी एस यूज द्वारा अपने अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वर्ष 2011-12 में ₹ 3258.60 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है। उनका कारोबार वर्ष 2011-12 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) ₹ 60898 करोड़ के 5.35 *प्रतिशत* के समतुल्य था। राज्य पी एस यूज की प्रमुख गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित हैं। कार्यशील पी एस यूज ने वर्ष 2011-12 में ₹ 562.75 करोड़ की हानि उठायी (**परिशिष्ट 5.1**)। उनके द्वारा 31 मार्च 2012 तक 18,329[1] कर्मचारियों को रोज़गार दिया था।

इस अध्याय में आर्थिक क्षेत्र (पी एस यूज) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाईयों की विस्तृत रूपरेखा लेखापरीक्षा अधिदेश, बजटीय व्यय, अनुदान/ सब्सिडी, गारंटियाँ तथा ऋण, लेखाओं के अन्तिम रूप देने में बकाये आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा साजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सम्बन्धित लेन-देन की लेखापरीक्षा पर टिप्पणियाँ भी शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक प्रयोजन महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानक अपेक्षा करता है कि वस्तुपरक वर्णन लेनदेन के विस्तार तथा प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षित है कि सरकारी कार्यपालकों को सुधारात्मक कार्यवाहियाँ कराने तथा नीति एवं निर्देशों को बनाने की क्षमता दें जिसके परिणामस्वरूप, राज्य में बेहतर शासन में योगदान देते हुए, संगठनों के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हो।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य है कि लेखापरीक्षित इकाईयों के व्यय, प्राप्तियों, सम्पत्तियों तथा देयताओं से सम्बन्धित लेन-देन की जाँच करना ताकि भारत के संविधान, लागू विधि, नियम, विनियम तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा अनुदेशों के अनुपालन सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

[1] 16 पी एस यू द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतन्त्र मूल्याँकण या जाँच है जिससे यह पता लगे कि कोई संगठन, कार्यक्रम या योजना कहाँ तक मितव्ययतापूर्वक, दक्ष एवं प्रभावी-ढंग से संचालित होती हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों के कार्यान्वयन में हुई कई महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ चयनित विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता, जिसने विभाग के क्रियाविधि एवं कार्यक्रमों की सफलता पर प्रभाव डाला हो, पर भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई कमियों को भी प्रतिवेदित किया है।

अध्याय 2
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-पी एस यू)

2 क. सामान्य प्रस्तावना

क्षेत्रवार पुनर्गठन के अन्तर्गत सामाजिक क्षेत्र में 32 सरकारी विभाग व 38 स्वायत्त निकाय, आर्थिक क्षेत्र में 20 सरकारी विभाग व तीन स्वायत्त निकाय तथा सामान्य क्षेत्र में 23 सरकारी विभाग व एक स्वायत्त निकाय है जिनके मुखिया अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/ प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक हैं और इनकी लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है।

2.1 लेखापरीक्षा अधिदेश

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (नि म ले) को लेखापरीक्षा करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 व 151 तथा नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 से व्युत्पन्न है। नि म ले (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-पी एस यू) के अन्तर्गत आने वाले विभागों के व्यय लेखापरीक्षा करते हैं। नि म ले के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम की धारा 19 (2) व 20 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में नि म ले एक मात्र लेखापरीक्षक हैं। इसके अतिरिक्त नि म ले के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम की धारा-14 के अन्तर्गत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित (विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए हैं) अन्य स्वायत्त निकायों की भी लेखापरीक्षा करते हैं। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए अपनाये जाने वाले सिद्धान्त व क्रिया-विधियाँ नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत 'लेखापरीक्षा मानकों एवं लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन, 2007' में निहित हैं।

2.1.1 लेखापरीक्षा आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया कतिपय मापदण्डों पर आधारित जोखिम निर्धारण से आरम्भ होती है जिसमें व्ययित राजस्व व्यय, क्रियाकलापों की नाजुकता/ पेचीदगी, सरकारी नीति, लोक लेखा समिति (पी ए सी) की संस्तुतियाँ, समग्र आन्तरिक नियन्त्रण-निर्धारण तथा हित-साधकों व प्रचार माध्यमों के प्रतिवेदन जैसे मापदण्ड शामिल हैं। इस अभ्यास में विगत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की बारम्बारता व सीमा निर्णीत होती है।

प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाईयों की लेखापरीक्षा पूर्ण करने पर इन संगठनों के अध्यक्षों को लेखापरीक्षा निष्कर्ष सहित निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के भीतर सम्बद्ध विभागों से लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। उत्तर प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो समायोजन कर लिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु आगामी कार्रवाई के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निरूपणों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित करने हेतु प्रक्रियान्वित किया जाता है एवं तत्पश्चात भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत इन्हें राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान 194[1] लेखापरीक्षित इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा/ निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए 5023[2] कार्य दिवसों (दिसम्बर 2012 तक) का उपयोग किया था। लेखापरीक्षा आयोजना में उन लेखापरीक्षार्थी संगठनों को समाविष्ट किया गया जो हमारे आंकलन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिम में संवेदनशील थे।

2.1.2 राज्य सरकार का व्यय विवरण

सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 तथा विगत दो वर्षों में वहन किए गए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे **तालिका -1.1** में दर्शित है:

तालिका 1.1 *(₹ करोड़ में)*

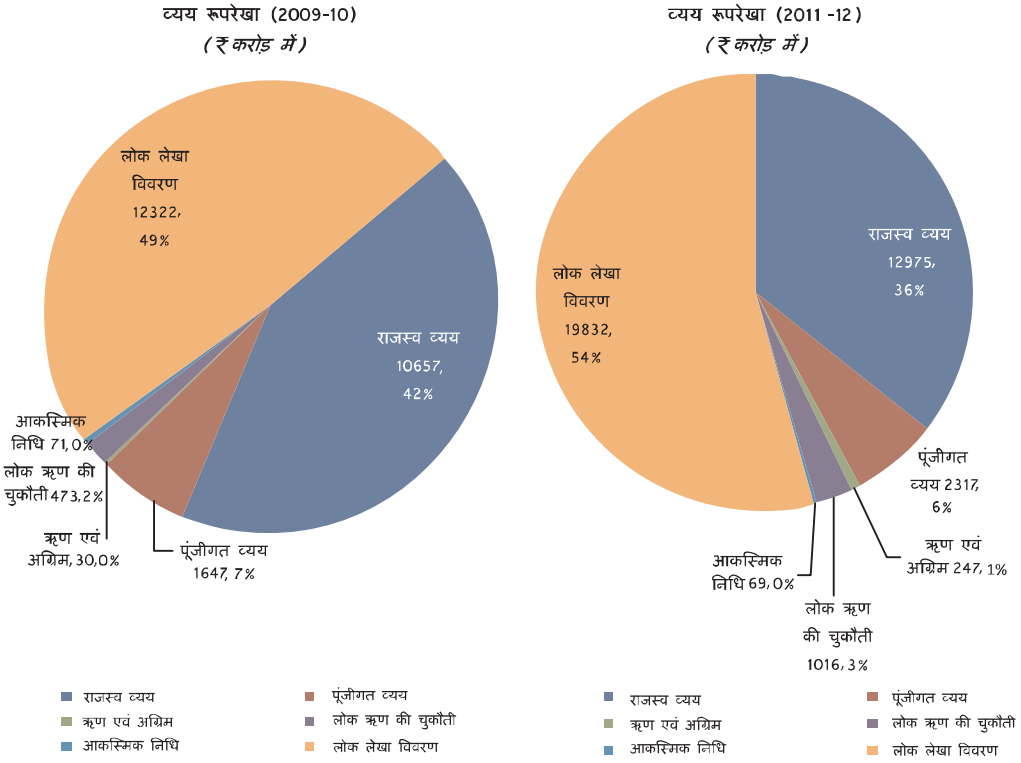
वितरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	कुल	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	कुल	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	कुल
राजस्व व्यय									
सामान्य सेवायें	2.86	3691.48	3694.34	20.63	4159.52	4180.15	3.72	4471.39	4475.11
सामाजिक सेवायें	1697.55	3282.73	4980.28	1723.79	3445.70	5169.49	1651.58	4368.07	6019.65
आर्थिक सेवायें	594.93	1063.19	1658.12	728.07	1135.68	1863.75	665.78	1435.85	2101.63
सहायता-अनुदान	3.70	321.03	324.73	0.01	407.67	407.68	0	378.80	378.80
कुल	**2299.04**	**8358.43**	**10657.47**	**2472.50**	**9148.57**	**11621.07**	**2321.08**	**10654.11**	**12975.19**
पूँजीगत व्यय									
पूँजीगत परिव्यय	992.46	654.27	1646.74	1858.52	-3.68	1854.84	2071.00	245.94	2316.94
ऋण एवं वितरित अग्रिम	24.32	5.74	30.06			59.68			246.83
लोक ऋण की चुकौती (डब्ल्यू एम ए के अधीन लेनदेन सहित)			472.87			519.36			1015.78
आकस्मिक निधि			71.42			536.71			69.07
लोक लेखा वितरण			12321.83			17608.20			19832.00
कुल	**1016.78**	**660.01**	**14542.92**	**1858.52**	**-3.68**	**20578.79**	**2071.00**	**245.94**	**23480.62**
कुल योग	**3315.82**	**9018.44**	**25200.39**	**4331.02**	**9144.89**	**32199.86**	**4392.08**	**10900.05**	**36455.81**

जबकि 2009-12 की अवधि के दौरान राज्य का पूँजीगत परिव्यय ₹ 1646.74 करोड़ से बढ़कर ₹ 2316.94 करोड़ (41 *प्रतिशत*) हो गया, इसी अवधि में राजस्व व्यय ₹ 10657.47 से बढ़कर ₹ 12975.19 करोड़ (22 *प्रतिशत*) हुआ।

---

[1] सामाजिक क्षेत्र-98 इकाईयों, आर्थिक क्षेत्र-76 इकाईयों एवं सामान्य क्षेत्र-20 इकाइयाँ।

[2] सामाजिक क्षेत्र-2,945 कार्य दिवस, आर्थिक क्षेत्र-1,922 कार्य दिवस एवं सामान्य क्षेत्र-156 कार्य दिवस।



2.1.3 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

(क) अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) विहित नियमों व क्रियाविधि के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखाभिलेखों के अनुरक्षण की पुष्टि हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए जाते हैं जिनकी एक प्रति उन कार्यालयाध्यक्षों के उच्चप्राधिकारियों को प्रषित की जाती है। कार्यालयाध्यक्षों एवं उनके उच्चप्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अवगत करवाएँ।

मार्च 2012 के अन्त में वर्ष 1990-91 से 2010-12 तक निर्गत 3761 निरीक्षण प्रतिवेदन व 7,164 प्रस्तर समायोजनार्थ बकाया पड़े थे।

विभागीय अधिकारी विहित समयाविधि के अन्दर निरीक्षण प्रतिवेदनों के निरूपणों पर कार्रवाई करने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ। सरकार को मामले पर ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि (क) समय सूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/ प्रस्तरों के उत्तर प्रेषित करने में विफल रहे कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई, (ख) समयबद्ध रूप से हानि/ बकाया पड़ी अग्रिम धनराशियों/ अधिक भुगतान की वसूली हेतु कार्रवाई, तथा (ग) में लेखापरीक्षा निरूपणों पर त्वरित एवं समुचित प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था में सुधार हो।

(ख) प्रारूप प्रस्तरों पर विभागों का प्रत्युत्तर

छः सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप प्रस्तरों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं की प्रतियाँ सम्बद्ध विभागों के आयुक्तों/ सचिवों को प्रेषित की गई थी, लेकिन किसी भी प्रारूप प्रस्तर का प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य सरकार के सभी विभागों से अपेक्षित है कि वे विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा रहे प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण से चार माह के भीतर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निरूपणों पर 'कृत कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन)' के माध्यम से विस्तृत आख्याएँ प्रस्तुत करें जिसकी प्रतियाँ लेखापरीक्षा कार्यालय को भी भेजी जाएँ। तथापि 18 विभागों ने, जिनके द्वारा 'कृत कार्रवाई टिप्पणी' देय थी, राज्य के सृजन से वर्ष 2009-10 व मार्च 2012 तक की अवधि तक 93 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ प्रस्तरों की 'कृत कार्रवाई टिप्पणी' प्रस्तुत नहीं की थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

2 ख. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मुख्य अंश

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा, निर्वाचन विभाग, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड व एकीकृत शिशु विकास सेवाओं पर विषयक लेखापरीक्षाएँ, उद्यान विभाग का मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा और लेन-देन लेखापरीक्षा प्रस्तरों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार निम्नवत् हैः

(क) कार्यक्रमों/ क्रियाकलापों/ विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

संसद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (नरेगा) अधिनियमित किया गया था (सितम्बर 2005) जिसका प्राथमिक उद्देश्य उन सभी पंजीकृत परिवारों के वयस्कों का वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारन्टी युक्त श्रम रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन सुरक्षा बढ़ाना था जो अकुशल श्रमिक कार्य करने के इच्छुक हैं। इस अधिनियम के अनुपालन में राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना तीन चरणों में क्रियान्वित की गई थी। प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था और अप्रैल 2008 तक योजना में राज्य के सभी जिले शामिल करा दिये।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा से कई खामियाँ उजागर हुई। राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की बैठकें नियमित अन्तराल पर नहीं हो रही थी जिससे आयोजना व अनुश्रवण जैसे मुख्य नीतिगत निर्णय उपेक्षित रहे। डी पी सी स्तर पर लगी विशेषज्ञता प्राप्त ऐजेन्सियों द्वारा तैयार जिला प्रस्पेक्टिव योजनाओं का अनुमोदन न होने से निष्फल व्यय हुआ। वार्षिक विकास योजनाओं में उन कार्यस्थल के विशिष्ट विवरण निहित नहीं थे जिनमें निर्माण कार्य निष्पादित होने थे। समय पर राज्यांश अवमुक्त नहीं किया जा रहा था और चार नमूना परीक्षित जिला कार्यक्रम समन्वयकों में 13 से 90 दिनों तक का औसत विलम्ब तथा सात माह का अधिकतम विलम्ब पाया गया।

राज्य के कुल 19.97 लाख परिवारों[3] में से 1.89 लाख से 5.42 लाख परिवारों ने 2007-12 की अवधि में रोजगार की माँग की और उन्हें 39 दिन प्रति परिवार प्रति वर्ष का औसत रोजगार दिया गया। 2008-12 की अवधि में राज्य में केवल दो से चार *प्रतिशत* पंजीकृत परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया गया। मजदूरी भुगतान में विलम्ब, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान न करना, सृजित सम्पत्तियों का अनुरक्षण न करना जैसे प्रकरण भी लेखापरीक्षा के ध्यान में आए।

[प्रस्तर 2.2]

(ख) विषयक लेखापरीक्षा

(i) निर्वाचन विभाग

उत्तराखण्ड निर्वाचन विभाग राज्य में संसद एवं राज्य विधानसभा के स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संचालित करने हेतु उत्तरदायी है। किसी भी राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत के निर्वाचन आयोग के निदेशन व नियन्त्रण के अन्तर्गत इन चुनावों के संचालनार्थ समग्र प्रभारी है।

[3] वर्ष 2011 की जनगणनानुसार।

निर्वाचन विभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि चुनावी खर्च प्रबन्धन कमजोर था। चुनाव के समय तम्बुओं व बैरिकेडिंग तथा रोशनी की व्यवस्था हेतु निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया था। विधान सभा चुनाव-2012 के काफी समय बीत जाने के बाद भी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे कर्मियों द्वारा ली गई अग्रिम धनराशियों के असमायोजन के प्रकरण भी लेखापरीक्षा में देखे गए। इसके अतिरिकत जब्त की गई जमानती धनराशियाँ समुचित सरकारी राजस्व लेखे में जमा नहीं की गयी। इसके अलावा स्रोत पर कर की कटौती किए जाने की अनदेखी की गई और तिजोरियों में भारी नकद राशि का प्रतिधारण व बैंक खातों में निधियों का जमा किया जाना अनाधिकृत था।

[प्रस्तर 2.3]

(ii) उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का कार्यचालन

भारत सरकार द्वारा अगस्त 1996 में अधिनियमित भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम के अनुपालन में उत्तराखण्ड सरकार ने सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएँ संचालित करने हेतु तथा उपकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दो *प्रतिशत* की दर से अधिक नहीं परन्तु एक *प्रतिशत* से कम भी नहीं की दर पर उपकर अधिरोपित करने हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया (अक्टूबर 2005)। उपकर अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में विगत बारह मासों के किसी भी दिन 10 या अधिक भवन श्रमिकों को नियोजित करने वाले स्थापनाओं से अपेक्षित है कि वे किसी नियोक्ता द्वारा वहन की गई कुल निर्माण लागत के एक *प्रतिशत* की दर से उपकर का भुगतान करेंगी। सन्निर्माण श्रमिकों को लाभ उठाने हेतु स्वयं को पंजीकृत करवाकर पहचान पत्र प्राप्त करने थे।

बोर्ड की विषयक लेखापरीक्षा में पाया गया था से उद्घाटित हुआ कि सरकार ने राज्य निर्माण के लगभग पाँच वर्ष बाद बोर्ड का गठन किया जबकि कल्याण निधि इस बोर्ड के गठन के लगभग तीन वर्ष बाद स्थापित की गई। पहले सन्निर्माण श्रमिक को बोर्ड के गठन के पाँच वर्ष बाद पंजीकृत किया गया और बोर्ड की शुरूआत से लेकर अब तक केवल 11 श्रमिकों ने ही इसका लाभ उठाया। बोर्ड ने अपने वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए। राज्य में कार्यरत प्रवासी स्थानीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उन सन्निर्माण अभिकरणों का 'डाटा बेस' भी तैयार नहीं किया गया था जो उपकर भुगतान के दायी थे। इस प्रकार यह बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत शामिल राज्य के अभिकरणों से शत-प्रतिशत उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने में असमर्थ था। विगत सात वर्षों के दौरान सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड समुचित औपचारिकताएँ तैयार नहीं कर पाया जिसके परिणामस्वरूप सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई।

[प्रस्तर 2.4]

(iii) एकीकृत बाल विकास सेवाएँ

पूरक पोषाहार, रोग प्रतिरोधी क्षमता, स्वास्थ्य जाँच, रेफरल सर्विसेज़, अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षावाली सेवाओं का पैकेज उपलब्ध करवाने हेतु उत्तराखण्ड (तत्कालीन उत्तरप्रदेश का भाग) के तीन चयनित विकास खण्डों[4] में वर्ष 1978-79 में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम को लागू किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है और लेखापरीक्षा में इस योजना को आवृत्त करने के लिए विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया था।

[4] चकरौता, धारचूला एवं कीर्तिनगर विकास खण्ड।

योजना की विषयक लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने योजना के अन्तर्गत अवमुक्त बजट का सम्पूर्ण उपयोग नहीं किया। जिला/ परियोजना प्राधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार नहीं की जा रही थीं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम और उपलब्ध पका- पकाया भोजन 300 दिवसों के विहित मानकों से काफी कम था। लाभार्थियों को चिकित्सा किट, विद्यालय पूर्व किट जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया जबकि भारत सरकार ने इस प्रयोजनार्थ निधियाँ-आवंटित की थी। राज्य में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के परिचालनार्थ प्रयास नहीं किए गए। यहाँ तक कि परिचालनशील आंगनबाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधाओं जैसे भवनों, शौचालयों, पेयजल, तराजुओं, पर्याप्त जनशक्ति और प्रशिक्षण का अभाव था। कर्मचारियों की न्यून संख्या, प्रशिक्षण के अभाव, आन्तरिक लेखापरीक्षा के अभाव तथा मापदण्डों के सापेक्ष पर्यवेक्षकों की कमी से योजना के सुचारू रूप से काम करने में बाधा आई। इस प्रकार राज्य में क्रियान्वित एकीकृत शिशु विकास सेवा योजना को अभावग्रस्त क्षेत्रों में मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

[प्रस्तर 2.5]

(ग) लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कई प्रमुख खामियों, जो लेखापरीक्षित इकाईयों के प्रभावी कार्यचालन पर असर डालते हैं, पर भी प्रतिवेदित किया।

- परियोजना की व्यवहारिकता का आकलन किये बिना मदरसों में पढ़ रहे मुस्लिम छात्रों के लिए ई-लर्निंग कार्यक्रम (प्रोजेक्ट तालीम) पर समाज कल्याण विभाग द्वारा किये गये अनुबंध के विरूद्ध ₹ 70.00 लाख का अग्रिम भुगतान अलाभकारी सिद्ध हुआ।

[प्रस्तर 2.6]

- समाज कल्याण विभाग में नियोजन की कमी के कारण हज-हाउस के डिजाइन में बदलाव एवं नई मदों के लगातार समावेश के कारण भवन निर्माण अपूर्ण रहना तथा ₹ 5.95 करोड़ का चार वर्षों से अधिक अवरूद्ध रहना।

[प्रस्तर 2.7]

- खेल निदेशालय भवन के निर्माण स्थल के चयन को अन्तिम रूप देने में यथासमय निर्णय न लिए जाने के कारण ₹ 60.28 लाख का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

[प्रस्तर 2.8]

- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालय भवन के निर्माण हेतु बाधा-रहित कार्य स्थल उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण ₹ 0.56 करोड़ लागत की वृद्धि।

[प्रस्तर 2.9]

- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा परिनिर्धारित क्षति (एल डी) की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.36 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

[प्रस्तर 2.10]

- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा जी आई सी सुकौली से डुंगरी रावल मोटर मार्ग के निर्माण में प्रथम संस्वीकृति को प्रतिधारित करते हुए, द्वितीय संस्वीकृति के सापेक्ष ₹ 51.15 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

[प्रस्तर 2.11]

- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, साहिया, देहरादून द्वारा बरोटीवाला-अम्बाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण में प्राइम कोट पेटिंग के बदले फर्स्ट कोट पेटिंग पर ₹ 39.41 लाख का अतिरिक्त परिहार्य व्यय किया।

[प्रस्तर 2.12]

(घ) मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा

उद्यान विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा

उद्यान विभाग का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र विस्तार, सिंचाई सुविधा और गुणवत्ता युक्त बीजों का नई तकनीक के साथ क्रियान्वयन, पौधो और उर्वरको से संबधित नयी तकनीकी के क्रियान्वयन के साथ किसानों को मूल्य वर्द्धित उत्पादों में गुणवत्ता वर्द्धन के माध्यम से किसानों तक पहुंच का विस्तार के द्वारा औद्यानिकी को बढ़ावा देना है। विभाग राज्य में आधारभूत संरचना का विनिर्माण कर रेशम कीट पालन, चाय उत्पादन, औषधीय व सगन्ध पौधों को प्रोत्साहित करने में भी संलग्न रहता है।

विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि विभाग राज्य में बागवानी के समग्र विकास के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिना कुशल नियोजन के कार्य कर रहा था। यह 'उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन' के सभी चार मिनी मिशनों का लाभ नहीं उठा सका सिवाय मिनी मिशन-द्वितीय के, जो कि केवल क्षेत्रफल विस्तार पर ही केन्द्रित था। केन्द्रीय निधियां विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जा सकीं और विभाग में संचालित केन्द्रीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कुप्रबंधन किया गया। विभाग के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक संस्थाएं परिकल्पना के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं कर सकी।

यद्यपि राज्य सरकार के पास अच्छी प्रकार से अभिलिखित नीतियां एवं प्रक्रियाएं हैं, तथापि विभाग अधिप्राप्तियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने एवं अपनी सामग्री की सुरक्षा करने में असफल रहा था। इसके पास आने वाले वर्षों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधनों का अभाव है। कमजोर आंतरिक नियंत्रणों एवं अपर्याप्त अनुश्रवण के कारण विभाग धोखाधड़ी एवं तंत्र मे होने वाले अन्य उल्लंघनों के प्रति कमजोर हुआ जैसा कि पौध रोपण सामग्री की फर्जी आपूर्ति तथा आधिकारिक दस्तावेजों की कपटपूर्ण रचना के मामलों में पाया गया।

(प्रस्तर 2.13)

निष्पादन लेखा परीक्षा

ग्राम्य विकास विभाग

2.2 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा), प्रत्येक पंजीकृत परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारण्टी वेतन रोजगार प्रदत्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ संसद द्वारा (सितम्बर 2005) अधिनियमित किया गया । अक्टूबर 2009 में इस योजना का पुनः नामकरण महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के रुप में किया गया । मनरेगा योजनान्तर्गत 2007-12 की अवधि के दौरान राज्य में उपलब्ध कुल ₹ 1335.80 करोड़ की धनराशि में से रोजगार सृजन पर ₹ 1312.88 करोड़ का व्यय किया गया । राज्य के कुल 19.97 लाख परिवारों[1] में से, 2007-12 अवधि के दौरान 1.89 लाख से 5.42 लाख परिवारों ने रोजगार की माँग की जिन्हें औसतन 39 दिनों का प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से रोजगार उपलब्ध कराया गया । मनरेगा की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं :

मुख्यांशः

राज्य में गठित राज्य रोजगार गारंटी परिषद के निष्क्रिय बने रहने से परिषद के गठन के अभिप्रेत उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

[प्रस्तर 2.2.6.1]

जनपदों द्वारा तैयार जिला पर्सपेक्टिव योजना प्रस्तुत/अनुमोदित नहीं करने के कारण ₹ 87.92 लाख का व्यय अलाभकारी रहा।

[प्रस्तर 2.2.7.1]

जनपद स्तर पर संकलित एवं अंततः राज्य द्वारा भारत सरकार को भेजे गए लेबर बजट के बीच भारी अंतर देखा गया ।

[प्रस्तर 2.2.7.3]

राज्यांश समय से अवमुक्त नहीं किए जा रहे थे तथा चार जाँच परीक्षित जिला कार्यक्रम समन्वयकों के संबन्ध में पाया गया कि अधिकतम सात महीनों के विलंब सहित औसतन विलंब 13 से 90 दिनों तक की थी।

[प्रस्तर 2.2.8.3]

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की ₹ 15.70 लाख की धनराशि मनरेगा योजना में हस्तान्तरित नहीं की गयी।

[प्रस्तर 2.2.8.4]

[1] जनगणना 2011 के अनुसार।

लाभार्थियों को समय से भुगतान नहीं किया गया था और 500 नमूना चयनित कार्यों में 669 दिनों तक की देरी के साथ 74 दिनों की औसत देरी देखी गयी । इस प्रकार की देरी के लिए मजदूरों को किसी मुआवज़े का भुगतान नहीं किया गया ।

[प्रस्तर 2.2.9.2]

दस नमूना जाँच किये गये विकास खण्डो में से तीन में ₹ 1.49 करोड़ की देयता देखी गयी जिसको मार्च 2012 तक भुगतान नहीं किया गया था ।

[प्रस्तर 2.2.9.3]

लेखा परीक्षा द्वारा भौतिक रुप से सत्यापित कुल 899 कार्यों में से ₹ 3.18 करोड़ लागत से सृजित 294 परिसम्पत्तियाँ रखरखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त पायी गईं।

[प्रस्तर 2.2.11.1]

ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न संवर्गों के सृजन के लिए सुझाए गए प्रशासनिक पद्धति को अपनाया गया, लेकिन इन संवर्गों में कुल 41 से 90 प्रतिशत की कमी देखी गयी ।

[प्रस्तर 2.2.13.1]

2.2.1 परिचय

नरेगा अधिनियम भारत सरकार द्वारा सितंबर 2005 में अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है । मनरेगा एक केन्द्र सहायतित योजना है जिसे भारत सरकार और राज्य के बीच लागत साझेदारी के आधार पर कार्यान्वित किया गया । योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और सामाजिक समानता को बढावा देना है । ग्राम्य विकास मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश 2006 में जारी किया गया, जिसे 2008 में संशोधित किया गया । योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एक गजट अधिसूचना सितम्बर 2006 में जारी किया गया ।

उत्तराखण्ड में मनरेगा फरवरी 2006 से आरम्भ की गई तथा अप्रैल 2008 से राज्य के सभी जनपद तीन चरणों में निम्नानुसार आच्छादित किए गए:

- फरवरी 2006 से चंपावत, चमोली एवं टिहरी गढवाल जनपदों में;
- अप्रैल 2007 से ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपदों में; और
- अप्रैल 2008 से शेष सभी आठ जनपदों[2] में ।

[2] अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी।

समीक्षा अवधि के दौरान राज्य के सांख्यिकीय प्रारुप का विवरण विस्तार से **तालिका 2.2.1** में निम्नवत हैः

तालिका 2.2.1

क्रम संख्या	विषय	2007-08	2011-12
1	(1) जनपदों की कुल संख्या : (2) कुल संख्या - विकास खण्ड : - ग्राम पंचायत :	13 95 7,541	13 95 7,555
2	(1) राज्य की कुल जनसंख्या : (2) सामान्य : (3) अनुसूचित जाति : (4) अनुसूचित जनजाति : *(स्रोतः जनगणना 2001)*	84,89,349 67,16,034 15,17,186 2,56,129	1,01,16,752 आँकडे जनगणना विभाग द्वारा संकलनाधीन। *(स्रोतः जनगणना 2011)*
3	(1) कुल परिवारों की संख्या : (2) सामान्य : (3) अनुसूचित जाति : (4) अनुसूचित जनजाति :	16,03,242 12,77,202 2,84,375 41,665	19,97,068 15,56,544 3,77,202 63,322
4	नमूना जाँच जनपदों/विकास खण्डों/ग्राम पंचायतों में (1) कुल बी पी एल परिवारों की संख्या : (2) सामान्य : (3) अनुसूचित जाति : (4) अनुसूचित जनजाति :	04 लेखापरीक्षित जनपदों 10 लेखापरीक्षित विकास खण्ड - - -	04 लेखापरीक्षित जनपदों 10 लेखापरीक्षित विकास खण्ड - - -
5	कुल निर्गत धनराशि (धनराशि करोड़ में) (भारत सरकार +राज्य सरकार)	114.41 (भारत सरकार) 13.59 (राज्यांश)	373.58 (भारत सरकार) 38.85 (राज्यांश)

स्रोतः जनगणना एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

2007-08 से 2011-12 अवधि के दौरान, योजना के अन्तर्गत राज्य में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 1335.80 करोड़ में से विभाग द्वारा कुल ₹ 1312.88 करोड़ (98 *प्रतिशत*) योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया गया जैसा कि नीचे **तालिका 2.2.2** में वर्णित हैः

तालिका 2.2.2 *(₹ करोड़ में)*

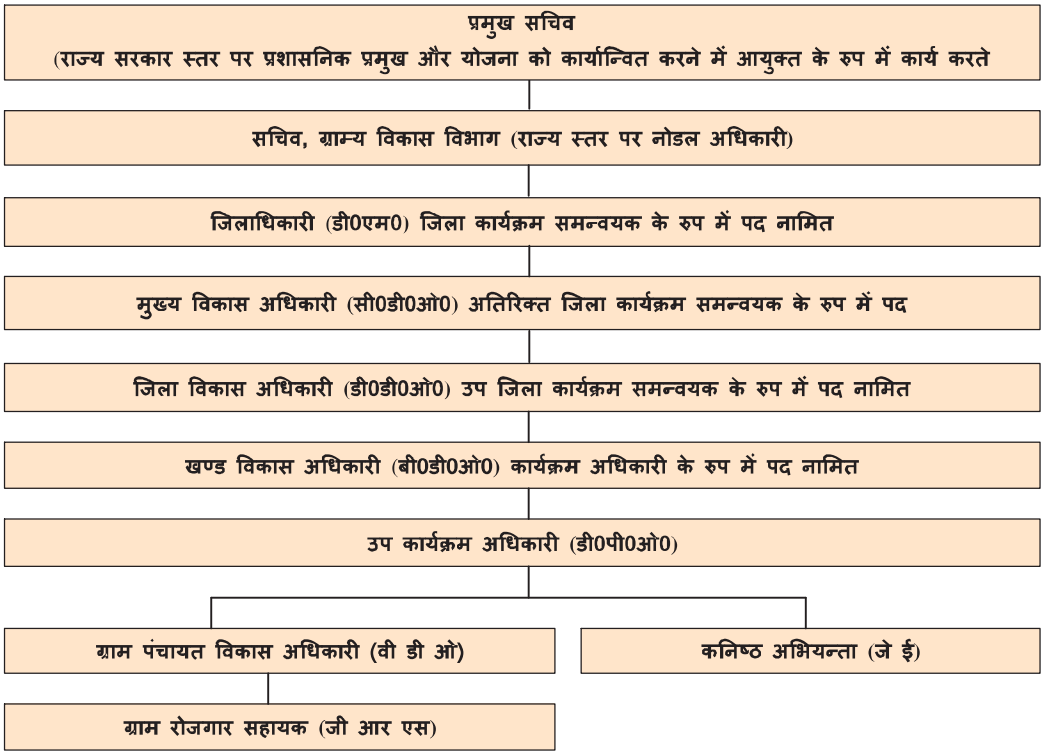
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय
2007-08	23.58	129.61	95.75
2008-09	68.67	106.69	135.79
2009-10	40.53	308.28	283.09
2010-11	65.72	339.67	380.20
2011-12	25.19	415.78	418.05

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

2.2.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

यह योजना ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रमुख सचिव के समग्र पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया गया जो कि आयुक्त, मनरेगा के रुप में भी कार्य करते थे । जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी पी सी) और कार्यक्रम अधिकारी (पी ओ) को क्रमशः जिला और विकास खण्ड स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है । योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढाँचा नीचे **चार्ट-1** में दिया गया है:

चार्ट-1



2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करने के लिए थे कि क्या :

- संरचनात्मक तंत्र ठीक था और योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त क्षमता निर्माण के उपाय किए गए थे;
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया (अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण सहित) कुशल और प्रभावी थी;
- वित्तीय प्रबन्धन (धनावंटन, उपयोग और उचित लेखांकन) कुशल और प्रभावी थे;
- जरुरतमंद व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में कुशल और प्रभावी रुप से योजना का कार्यान्वयन किया गया;

- आँकड़े और दस्तावेजों के रखरखाव के साथ-साथ प्रबंधन सूचना प्रणाली का रखरखाव कुशल और प्रभावी था;
- योजना के क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन कुशल था; तथा
- अनुश्रवण तंत्र (सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम अनुश्रवण समिति की बैठकें और विकासखण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यों का निरीक्षण) विद्यमान और प्रभावी था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से उद्धृत हैः

- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) और उसमें किए गए संशोधन;
- मनरेगा के लिए ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2006 और 2008 एवं ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा जारी सम्बन्धित परिपत्र;
- राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये गजट अधिसूचना और आदेश; तथा
- राज्य सरकार द्वारा योजना के आंतरिक अनुश्रवण के लिए जारी दिशानिर्देश/चेकलिस्ट।

2.2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, नमूना चयन एवं पद्धति

मनरेगा की निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए, राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, चार जि का स[3] जिला पंचायत सहित, चयनित जनपदों के दस कार्यक्रम अधिकारियों[4] और चयनित विकास खण्डों के 100 ग्राम पंचायतों (जी पी) के अभिलेखों को सम्मिलित करते हुए मार्च 2012 से सितम्बर 2012 के मध्य सम्पादित की गयी। चयनित जनपदों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू की गई थी तथापि, पूरे राज्य के आँकड़ों में अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया है। जनपद/ विकास खण्ड का चयन पंजीकृत परिवारों की संख्या के आधार पर 'सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद्आउट रिप्लेश्मेन्ट' (एस आर एस डब्ल्यू ओ आर) पद्धति से और ग्राम पंचायतों का चयन किए गए व्यय के आधार पर 'प्रोबेबिलिटी प्रपोर्शनल टू साईज विद्आउट' (पी पी एस डब्ल्यू ओ आर) पद्धति से किया गया। कुल मिलाकर इस योजना के अन्तर्गत इन ग्राम पंचायतों में कराये गये 899 कार्यों को विस्तृत जाँच के लिए चुना गया। इन कार्यों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण भी संबन्धित प्रतिनिधियों/ विभाग के कर्मचारियों और लेखापरीक्षा दल की उपस्थिति में किया गया। इसके अतिरिक्त, 1000 लाभार्थियों (प्रत्येक नमूना चयनित ग्राम पंचायत से 10 लाभार्थी) का एक लाभार्थी सर्वेक्षण लेखापरीक्षा द्वारा विकसित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया।

अधिनियम के प्रावधानों, योजना के दिशानिर्देशों, राज्य के गजट अधिसूचना, वित्तीय नियमों और सरकारी आदेशों/निर्देशों के संदर्भ में लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच पद्धति अपनाई गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और पद्धति पर 17 अप्रैल 2012 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ प्रवेश गोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया।

---

[3] अल्मोड़ा , देहरादून, पौड़ी और पिथौरागढ़।

[4] भिकियासेण, चकराता, डीडीहाट, द्वाराहाट, धौलादेवी, एकेश्वर, खिर्सू, पौड़ी, मुन्सियारी और विकास नगर।

सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड सरकार के साथ 21 दिसम्बर 2012 को प्रस्थान गोष्ठी में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार-विमर्श किया गया एवं उनके उत्तरों को यथोचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 संरचनात्मक तन्त्र

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बुनियादी स्तर अर्थात् ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में योजना के सफल राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी गयी है:

(i) राज्य स्तर:

प्रमुख सचिव/ सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार राज्य समन्वयक थे एवं राज्य स्तर पर योजना के समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार थे।

(ii) जनपद स्तर:

जिला कार्यक्रम समन्वयक समग्र नियोजन एवं योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्य अभिकरणों के बीच समन्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

(iii) विकास खण्ड स्तर:

कार्यक्रम अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर समग्र नियोजन एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं।

(iv) ग्राम पंचायत स्तर:

ग्राम पंचायत को योजना के क्रियान्वयन के लिए धुरीय संस्था बनाया गया है और इस स्तर पर योजना की सभी गतिविधियों के संचालन के लिए ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेदार बनाया गया है।

इन सभी पदधारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2.3** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित पाया गया :

2.2.6.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना

राज्य रोजगार गारंटी परिषद (रा रो गा प) को राज्य सरकार को योजना के क्रियान्वयन पर, अनुश्रवण एवं मूल्याँकन सहित, सलाह देना था। रा रो गा प की अन्य भूमिकाओं में जिला पर्सपेक्टिव योजना का अनुमोदन और शिकायत निवारण क्रियाविधि का अनुश्रवण सम्मिलित हैं। रा रो गा प को राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन पर एक वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु, तैयार करना था। योजना के भौतिक और वित्तीय प्रगति का जायजा लेने के लिए रा रो गा प को त्रैमासिक बैठक आयोजित करना भी अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि रा रो गा प की स्थापना राज्य में योजना के आरम्भ होने से 17 माह की देरी से 31 अगस्त 2007 को किया गया था। पुनश्च, रा रो गा प की मार्च 2012 तक अपेक्षित 18 त्रैमासिक बैठकों के सापेक्ष मात्र दो बैठकें (अक्टूबर 2007 और जनवरी 2011) ही आयोजित की गयीं। रा रो गा प के निष्क्रिय रहने के परिणामस्वरुप, छः जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा प्रस्तुत जिला पर्सपेक्टिव योजनाएँ, जिसमें सबसे पुरानी दिसम्बर 2008 में प्रस्तुत की गई थी, अनुमोदित नहीं हो पाई। राज्य स्तर पर कार्यों के निरीक्षण में 95 *प्रतिशत* की कमी भी अनुश्रवण रहित रही (प्रस्तर 2.2.14.2 संदर्भ ग्रहण करें)।

इसे इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2012) कि रा रो गा प के गठन में देरी राज्य में विधान सभा चुनाव के कारण हुई लेकिन नियमित रुप से बैठकों का आयोजन न किये जाने के सम्बन्ध में कोई कारण नहीं बताया। यद्यपि, प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव, ग्राम्य विकास ने, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए आश्वस्त किया कि आगे से रा रो गा प की बैठकें मानकों के अनुरूप नियमित रुप से आयोजित की जाएँगी।

2.2.6.2 राज्य रोजगार गारंटी निधि की स्थापना

राज्य सरकार को, प्रमुख अभिकरणों को निधि हस्तांतरण के लिए, राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस ई जी एफ) की स्थापना करनी थी । लेकिन राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना के लिए जनवरी 2007 में अधिसूचना जारी करने के बावजूद ऐसी निधि की स्थापना नहीं की गयी।

इसे इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2012), विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि एस ई जी एफ के गठन से सम्बन्धित प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

2.2.6.3 प्रमुख अभिकरणों और संस्थाओं को प्रशिक्षण

मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रमुख अभिकरणों/ हितधारियों को अधिनियम में प्राविधानित अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रशिक्षित किया जाना अपेक्षित था। इसमें मनरेगा के क्रियान्वयन में शामिल ग्राम पंचायतों, जनपदों और राज्य स्तर के विभागीय कार्मिकों को सम्मिलित किया जाना था।

2007-08 से 2011-12 की अवधि में आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्न **तालिका 2.2.3** में इंगित हैः

तालिका 2.2.3

वर्ष	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रतिभागियों का स्तर	प्रतिभागियों की संख्या	प्रशिक्षण का विषय
2007-08	41	पी ओ/ पंचायतीराज संस्थायें और निर्वाचित प्रतिनिधि/ डी पी ओ/ वी डी ओ/ जे ई / जी आर एस/ लेखाकार/ कम्प्यूटर आपरेटर/ रेखीय विभाग	2405	क्षमता निर्माण/मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यशाला/ लेखांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण/ नियोजन/ सामाजिक अंकेक्षण/ मनरेगा प्रचार प्रसार
2008-09	46		3095	
2009-10	94		3920	
2010-11	78		3358	
2011-12	104		6190	

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना ।

उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल और लक्ष्य तैयार किए गए तथा सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया गया ।

2.2.6.4 तकनीकी संसाधन समूहों की स्थापना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 13.1 और 13.2 में प्रावधानित है कि राज्य सरकार क्रियान्वयन के सभी पहलुओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्रियान्वयन अभिकरणों यथा ग्राम पंचायतों, रेखीय विभागों इत्यादि को तकनीकी संसाधन सहायता सुलभ कराए। दिशानिर्देश, जनपद/खण्ड स्तर पर आगणन और कार्यों के मापन में सहायता के लिए अधिकृत अभियन्ताओं का एक पैनल बनाने का प्रावधान करती है।

राज्य सरकार ने क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जनपद स्तर पर जिला अभियन्ता एवं विकास खण्ड स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता का पद सृजित किया था।

जिला अभियन्ताः योजना के अन्तर्गत करवाए जाने वाले कार्यों के लिए तैयार किये गये आगणनों पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने और न्यूनतम 20 *प्रतिशत* कार्यों का भौतिक सत्यापन करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक (13) के लिए एक जिला अभियन्ता का पद सृजित (जुलाई 2009) किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 13 जिला कार्यक्रम समन्वयकों में केवल दो जिला अभियन्ता, अल्मोड़ा और देहरादून प्रत्येक में एक, पदस्थापित थे। इसके अतिरिक्त, देहरादून में पदस्थापित जिला अभियन्ता को केवल एक विकास खण्ड का कार्यभार सौंपा गया था। जिला अभियन्ता, देहरादून द्वारा कार्यों के निरीक्षण की संख्या और प्रतिशतता सम्बन्धी कोई दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि जिला अभियन्ता, अल्मोड़ा ने बताया कि उनके द्वारा 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः दो और चार *प्रतिशत* कार्यों का निरीक्षण किया गया जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य भौतिक सत्यापन के (20 *प्रतिशत*) से कम था। किसी भी जिला अभियन्ता द्वारा निरीक्षण से सम्बन्धित किसी स्थाई दस्तावेज का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिसकी अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा द्वारा किए गये निरीक्षणों को सत्यापित नहीं किया जा सका।

कनिष्ठ अभियन्ताः राज्य सरकार ने कनिष्ठ अभियन्ता का एक पद सृजित किया (जुलाई 2009), (राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के 557 न्याय पंचायतों[5] में प्रत्येक हेतु एक और मैदानी क्षेत्र के 113 न्याय पंचायतों में प्रत्येक दो पर एक) और उनको कार्यों के तकनीकी आगणन तैयार करने, कार्यों की माप एवं ग्राम पंचायत अधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ता संवर्ग में जनशक्ति 64 *प्रतिशत* कम थी, जो कि नमूना चयनित जनपदों और विकास खण्डों में क्रमशः 71 एवं 73 *प्रतिशत* थी।

नमूना चयनित के 899 कार्यों की तकनीकी आगणनों की संवीक्षा में पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा तकनीकी आगणन तैयार करते समय अधिनियम के प्रावधानों को घ्यान में नहीं गया था एवं जिला अभियन्ता द्वारा इन कार्यों के लिए प्रदत्त तकनीकि स्वीकृतियों में विशिष्ट कार्यस्थल की स्थिति अंकित नहीं

[5] न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है। न्याय पंचायत प्राकृतिक न्याय के व्यापक सिद्धान्तों पर आधारित कार्यों के साथ सम्पन्न किया जा सकता है और न्याय की प्रक्रिया यथा सम्भव सरल कर सकते हैं। वे सिविल और लघु आपराधिक मामलों के क्षेत्राधिकार में निर्णय दे सकते हैं। लेकिन पूर्ण रुप से वे कभी सिविल और आपराधिक प्रक्रिया संहिता का पालन नहीं करते।

थी। पुनश्च, लेखा परीक्षा में पाया गया कि कार्यों के प्रारम्भ में विलम्ब था जो कि ग्राम सभा द्वारा कार्यों के प्रस्ताव की तिथियों एवं कार्य के प्रारम्भ की तिथियों के बीच बड़े समयान्तराल के कारण था, लेकिन तकनीकी स्वीकृतियों में उन्हें प्रस्तुत करने और स्वीकृति प्रदान करने की तिथियों के अंकित न होने के कारण यह तथ्य सत्यापित नहीं किया जा सका।

यह इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि यद्यपि जिला अभियन्ता के पद हेतु माँग विभिन्न विभागों को प्रेषित किया गया था परन्तु कोई भी अभियन्ता उपलब्ध नहीं करवाया गया। हालाँकि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में पदस्थापित अभियन्ताओं को कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। यह भी कहा गया कि प्रावधानों के अनुसार कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं इस हेतु स्थाई दस्तावेजों के रख रखाव किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गये थे। कनिष्ठ अभियन्ताओं के सम्बन्ध में यह बताया गया कि राज्य में विभिन्न संवर्गों के खाली पदों को सेवा प्रदाता के माध्यम से भरे जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगनादेश (नवम्बर 2009) के कारण नहीं भरा जा सका और इन पदों की भर्ती हेतु कुछ वैकल्पिक तरीकों पर विचार किए जा रहे थे। पुनश्य, सचिव, ग्राम्य विकास ने प्रस्थान गोष्ठी के दौरान कहा कि निरीक्षण के समर्थन में निरीक्षण लॉग बुक बनाने और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित तकनीकी आगणन के सभी विवरण की जाँच प्रस्तावित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व देखे जाने हेतु निर्देश दिये जाएँगें।

यद्यपि, डी आर डी ए के अभियन्ताओं को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तथापि अत्यधिक जरुरतों को देखते हुए तकनीकी आगणन में गलतियों को रोकने हेतु जिला अभियन्ता के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और उनके कार्यों को नियमित रुप से निगरानी की जाए।

2.2.7 नियोजन प्रक्रिया

मनरेगा के सफल क्रियान्वयन के लिए नियोजन महत्वपूर्ण थी। कार्य की माँग की तारीख से 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु समय से रोजगार सृजित करना सफलता का एक मुख्य संकेतक था। समय सीमा के भीतर ऐसा करने हेतु अग्रिम नियोजन आवश्यक है। नियोजन प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जनपद उत्पादक रोजगार की माँग पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पहले से तैयार रहे। इसके अलावा, मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश में एक पंचवर्षीय जिला पर्सपेक्टिव योजना (डी पी पी) अग्रिम आयोजना की सुविधा और जनपद के विकास की संभावना प्रदान करने हेतु बनाया जाना प्रावधानित है। जनपद में मनरेगा कार्यों के प्रकारों की पहचान कर बढावा देना और इन कार्यों के बीच संभाव्य संबन्ध और दीर्घकालिक रोजगार सृजन कर स्थाई विकास करना इसका उद्देश्य है।

2.2.7.1 जिला पर्सपेक्टिव योजना तैयार करने पर अलाभकारी व्यय

पाँच वर्षों के लिए एक जिला पर्सपेक्टिव योजना (डी पी पी) तैयार करना था जिससे दीर्घकालिक आयोजना के ढाँचे के रुप में वार्षिक श्रम बजट को सुकर बनाने का लाभ होगा ताकि वह क्षेत्र की नई उभरती आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया हो सके।

मनरेगा प्रकोष्ठ, देहरादून के अभिलेखों और नमूना परीक्षित जनपदों के नमूना जाँच में पाया गया कि भारत सरकार के दिशानिर्देश के परिपालन में राज्य सरकार ने जनपदों को 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि हेतु ₹ 10.00 लाख प्रति डी पी सी (13) की दर से कुल ₹ 1.30 करोड़ धनराशि के आबंटन के साथ जिला पर्सपेक्टिव योजना बनाने हेतु निर्देशित किया था। इसमें से, ₹ 75.96 लाख का भुगतान विशेषज्ञ अभिकरण को पहले ही किया जा चुका था और ₹ 11.96 लाख की देयता शेष है, ₹ 13.36 लाख योजना में उपयोग किये गये और ₹ 28.72 लाख जिला कार्यक्रम समन्वयकों के पास अभी भी अप्रयुक्त है। चम्पावत और उत्तरकाशी जनपदों द्वारा डी पी पी तैयार नहीं किया गया था जिनके विरुद्ध राज्य द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कुल 13 जनपदों में से मार्च 2012 तक केवल छः जनपदों द्वारा जिला पर्सपेक्टिव योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया जो कि अभी तक अनुमोदित नहीं हुए, जिसमें सबसे पुराना दिसम्बर 2008 को प्रस्तुत किया गया है।

इसे इंगित किये जाने पर (जून एवं अगस्त 2012), विभाग ने बताया (जून 2012) कि जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा डी पी पी देर से प्रस्तुत किये जाने के कारण यह अभी तक अनुमोदित नहीं हो सका। सात जनपदों द्वारा डी पी पी न प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में विभाग ने बताया (अगस्त 2012) कि संबन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयकों से स्पष्टीकरण माँगा गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डी पी पी 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए बनाए गये थे और अन्तिम वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले से ही परिचालनीय है। जबकि जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा प्रस्तुत डी पी पी के अनुमोदन के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी और उन जिला कार्यक्रम समन्वयकों, जिसके द्वारा डी पी पी प्रस्तुत/ तैयार नहीं किया गया, के सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरुप ₹ 87.92 लाख का इन डी पी पी पर अलाभकारी व्यय किया गया जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। यहाँ ₹ 28.72 लाख की धनराशि अवरुद्ध रही जो अब तक (अगस्त 2012) अनुप्रयुक्त रही। आगे, चूँकि जिला पर्सपेक्टिव योजना स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं ग्रामीण निर्धनों के जीवन यापन के संसाधनो के आधार को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ दीर्घकालीन विकास योजना से कार्यों की वरीयता निर्धारित करने के उद्देश्य से बनायी गयी थी, जिसकी अनुमोदन न होने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायी।

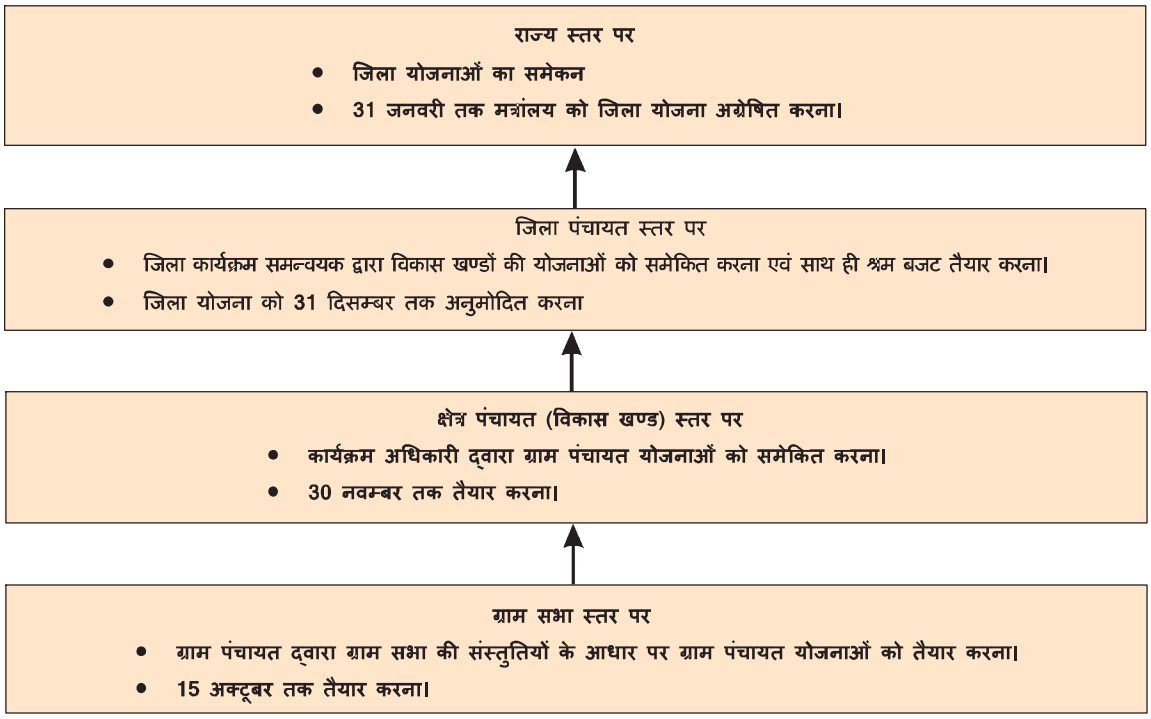
2.2.7.2 वार्षिक कार्य योजना तैयार किया जाना

वार्षिक कार्य योजना (वा का यो) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए जाने वाली वार्षिक योजना थी तथा उसमें प्रत्येक ग्राम के लिए प्रशासनिक व तकनीकी अनुमोदनों सहित परियोजनाओं के समूह निहित होने चाहिए ताकि कार्य की माँग हो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं को अन्तिम रूप देने की पूरी प्रक्रिया **चार्ट-2** में नीचे दर्शायी गयी हैः

चार्ट-2

वार्षिक योजनाओं की तैयारी की प्रक्रिया



विकास योजना में निम्न घटकों का समावेश सम्भावित थाः

- श्रम की माँग का आंकलन;
- कार्य की आंकलित माँग की पूर्ति हेतु कार्यों का चिन्हीकरण;
- स्थानों का चिन्हीकरण जहाँ कार्य निष्पादित होने हैं;
- कार्य की लागत एवं मजदूरी का आंकलन; एवं
- रोजगार सृजन एवं भौतिक सुधारों के रूप में अनुमानित लाभ।

वार्षिक कार्य योजना (वा का यो) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किए जाने वाली वार्षिक योजना थी तथा उसमें प्रत्येक ग्राम के लिए प्रशासनिक व तकनीकी अनुमोदनों सहित परियोजनाओं के समूह निहित होने चाहिए ताकि कार्य की माँग हो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

चयनित विकास खण्डों के कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर संकलित वा वि यो की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा योजनाएँ तैयार करने में निर्धारित समय सारणी का पालन नहीं किया गया था। किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम अधिकारी को वा वि यो प्रस्तुत करने की तिथि अंकित नहीं की गयी थी, तथापि, कार्यक्रम अधिकारी ने अवगत कराया (मई-जून 2012) कि सामान्यतः उन्हें ग्राम पंचायतों से वा वि यो दो से तीन माह की देरी से प्राप्त हुई है। इससे वा वि यो को कार्यक्रम अधिकारी से जिला कार्यक्रम अधिकारी को एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ।

परिणामस्वरूप वा वि यो की विलम्ब से प्रस्तुति और सम्पूर्ण राज्य के लिये इन वा वि यो पर आधारित श्रम बजट के प्रस्तावों के समय से भारत सरकार को प्रस्तुत करने में बाधा पहुँची।

इस ओर इंगित किए जाने पर (अगस्त 2012), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा (अगस्त 2012) कि मनरेगा योजना के परिचालन दिशानिर्देश को कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

इन निर्देशों के अनुपालन पर नजर रखने के कमज़ोर अनुश्रवण तंत्र ने विभाग के इन निर्देशों को प्रभावहीन बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप वा वि यो में कमियाँ हुई।

2.2.7.3 श्रम बजट तैयार किया जाना

दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा समस्त विवरण की जाँच के बाद अंतिम रूप से संकलित वा वि यो को श्रम बजट का आधार बनना था। मनरेगा की अद्वितीय विशिष्टता, इसका नीचे से ऊपर की तरफ संरचना,-अर्थात् ग्राम पंचायत (ग्रा पं) के नेतृत्व में नियोजन एवं कार्यों का चयन और उसका क्रियान्वयन आपसी सहयोग से होना था।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि जिला कार्यक्रम समन्वयक स्तर पर संकलित श्रम बजट **(परिशिष्ट-2.4)**, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तावित श्रम बजट एवं राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से दिये गये लेबर बजट के सापेक्ष ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्राधिकृत समिति द्वारा अंतिम रूप से दिये गये श्रम बजट में व्यापक अन्तर था जिसे नीचे दी गयी **तालिका-2.2.4** में देखा जा सकता हैः

तालिका-2.2.4 *(धनराशि ₹ लाख में)*

वर्ष	ग्राम पंचायतों की माँग पर आधारित नमूना चयनित जनपदों पर संकलित श्रम बजट	राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्तावित नमूना चयनित जनपदों का श्रम बजट (*प्रतिशत* में)	भारत सरकार द्वारा निधियों के विनियोजन के आधार पर नमूना चयनित जनपदों के विरूद्ध राज्य द्वारा अंतिम रूप दिया गया बजट (ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित श्रम बजट एवं दिये गये अंतिम बजट का अन्तर *प्रतिशत* में)	राज्य द्वारा भारत सरकार को प्रस्तावित कुल श्रम बजट	भारत सरकार द्वारा अंतिम रुप से निर्धारित किया श्रम बजट (राज्य द्वारा प्रस्तावित श्रम बजट के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कम किये गये श्रम बजट का *प्रतिशत*)
2008-09	68766	27186 (*40*)	27186 (*60*)	54654	54654 (00)
2009-10	48497	20580 (*42*)	10189 (*79*)	49745	37321 (25)
2010-11	49746	29955 (*60*)	13203 (*73*)	77218	38282 (50)
2011-12	57938	23324 (*40*)	15286 (*74*)	68229	46422 (32)

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना ।

नमूना चयनित जनपदों में राज्य सरकार द्वारा बजट प्रस्तावों में 40 से 60 *प्रतिशत* की कटौती लेखापरीक्षा के संज्ञान में आयी। भारत सरकार की प्राधिकृत समिति द्वारा इसके अतिरिक्त राज्य के बजट प्रस्तावों में 50 *प्रतिशत* तक की कटौती की गयी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयकों को अन्तिम आबंटन 79 *प्रतिशत* तक कम किया गया।

प्रस्थान गोष्ठी में सचिव, ग्राम्य विकास ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि विगत वर्ष में जनपद के निष्पादन को ध्यान में रखकर कटौती की गयी। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की प्राधिकृत समिति द्वारा राज्य के लिए निर्धारित श्रम बजट के आधार पर जनपदों को अंतिम रूप से आबंटन किया गया।

2.2.7.4 सूचना, शिक्षा एवं संचार

किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन जागरूकता महत्वपूर्ण है। मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.2 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को जागरूकता सृजन के लिए नरेगा के महत्वपूर्ण प्रावधानों को वृहद सूचना, शिक्षा एवं संचार द्वारा प्रचारित करना चाहिए। राज्य सरकार को एक सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना विकसित करनी थी एवं ऐसी संचार सामग्री तैयार करनी थी जो कि लोगों को प्राप्त करने में सहायता कर सके। इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार, विशेष तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में, अ जा/ अ ज जा बाहुल्य क्षेत्रों में टी वी, रेडियो, वृत्तचित्रों, समाचार पत्रों, स्थानीय समाचार पत्रों, पैम्फलेटों एवं पुस्तिकाओं के माध्यम से किया जाना चाहिये था।

राज्य सरकार ने कोई सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना नहीं बनायी एवं इसे जिला कार्यक्रम समन्वयकों पर छोड़ दिया, परिणामस्वरूप मनरेगा प्रावधानों का संचार एकरूपता से नहीं हो सका।

शिकायत पंजिका में कोई प्रविष्टि नहीं पायी गयी (10 नमूना चयनित विकास खण्डों में से तीन) एवं बेरोजगारी भत्ता एवं मुआवज़े की माँग न होना इस ओर इंगित करता है कि जागरूकता सृजन मानकों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा दल द्वारा कराये गये लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान भी यह पुष्ट हुआ कि 818 लाभार्थियों (1000 में से), जिनका सर्वेक्षण किया गया, ने अवगत कराया कि उन्हें कार्य की उपलब्धता के आधार पर रोजगार दिया जाता है एवं 697 ने बताया कि उन्हें कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के बाद भुगतान किया जाता है। 899 कार्यों के अभिलेखों की नमूना जाँच में, लाभार्थियों को 669 दिनों तक विलम्ब से भुगतान करना लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया है।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं अवगत कराया गया कि सूचना, शिक्षा एवं संचार योजना शीघ्र ही विकसित की जायेगी।

2.2.7.5 योजना के क्रियान्वयन में जिला पंचायत की अल्प भूमिका

जिला पंचायत योजना के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में प्रभावी भूमिका के साथ ही जनपद के विकास के लिये धुरीय निकाय थी। मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विकास-खण्डवार शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स एवं इस पर आधारित श्रम बजट एवं संस्तुति संशोधन हेतु यदि आवश्यक हो, जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा जिला पंचायत को प्रस्तुत किया जायेगा। पुनश्य, जिला पंचायत को क्रियान्वयन के सभी पहलुओं विशेषतया जॉब कार्डस् का समयानुसार जारी किया जाना, रोजगार का उपलब्ध करवाया जाना, सामाजिक अंकेक्षण, निधियों का प्रवाह, कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण करना था।

नमूना चयनित चार जिला कार्यक्रम समन्वयकों के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा संकलित वा का यो अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित की जा रही थी परन्तु जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वा का यो को जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने एवं अनुमोदन के पश्चात् जिला कार्यक्रम समन्वयक को वापस किये जाने सम्बन्धित अभिलेखों का रखरखाव जिला पंचायत में नहीं किया गया। यह भी देखा गया कि जिला पंचायतें योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में किसी भी स्तर पर शामिल नहीं थीं।

प्रस्थान गोष्ठी में सचिव, ग्राम्य विकास ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के सख्ती से अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे।

2.2.7.6 रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 14.1 के अनुसार, टिकाऊ सम्पत्तियों के सृजन के लिये मनरेगा निधियों को अन्य स्रोतों की निधियों के साथ अभिसरण (मिलाना) अनुमन्य था। हालाँकि यह सुनिश्चित करने में ध्यान देना था कि मनरेगा निधियाँ किसी अन्य योजना एवं श्रेत्र के स्रोत से स्थानापन्न न की जायें। मनरेगा निधियों का उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध/उत्पन्न कराना था। मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों हेतु अन्य कार्यक्रमों से निधियों का मनरेगा निधि के साथ युगपतिकरण (dovetailing) हो सकता था, परन्तु इसके उलट इसके उलट अनुमन्य नहीं था। केन्द्राभिसरण की समस्त पहलें, विशेषतया श्रम प्रधान कार्यों की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता एवं ठेकेदारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध, मनरेगा के मापदण्डों के अन्तर्गत ही की जानी थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में उद्घाटित हुआ कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/क्रियाकलापों के केन्द्राभिसरण/ युगपतिकरण (dovetailing) से सम्बन्धित निर्देश जारी किये गये थे (जुलाई 2008) परन्तु रेखीय विभागों एवं राज्य कार्यक्रम समन्वयक के बीच नियमित अन्तराल में बैठकें नहीं हुई। केन्द्राभिसरण योजनायें प्रतिवर्ष नहीं तैयार की गई थीं वरन् केवल वर्ष 2009-10 एक हेतु एक प्रारूप योजना तैयार की गई थी। योजनान्तर्गत किये गये कुल व्यय ₹ 1312.88 करोड़ में से वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान विभिन्न विभागों के केन्द्राभिसरण के माध्यम से मात्र ₹ 38 करोड़ (तीन *प्रतिशत*) का व्यय केन्द्राभिसरण के प्रति राज्य सरकार की कम प्राथमिकता को दर्शाता है। नमूना चयनित जनपदों में कार्यों पर व्यय लगभग पूर्ण रूप से मनरेगा निधियों से वहन किया गया। रेखीय विभागों द्वारा कराये गये कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण किये जाने के सम्बन्ध सूचनायें न तो रेखीय विभागों द्वारा और ना ही कार्यक्रम अधिकारी/ ग्रा पं स्तर पर रखी जा रही थी जिसके फलस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा जाँच नहीं की जा सकी।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान, सचिव, ग्राम्य विकास ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अन्य विभागों द्वारा मनरेगा के प्रति उत्साह की कमी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया एवं कहा कि अन्य रेखीय विभागों के साथ कार्यों के अभिसरण के प्रयास किये जायेंगे।

2.2.8 वित्तीय प्रबन्धन

2.2.8.1 वित्तीय ढ़ाँचा

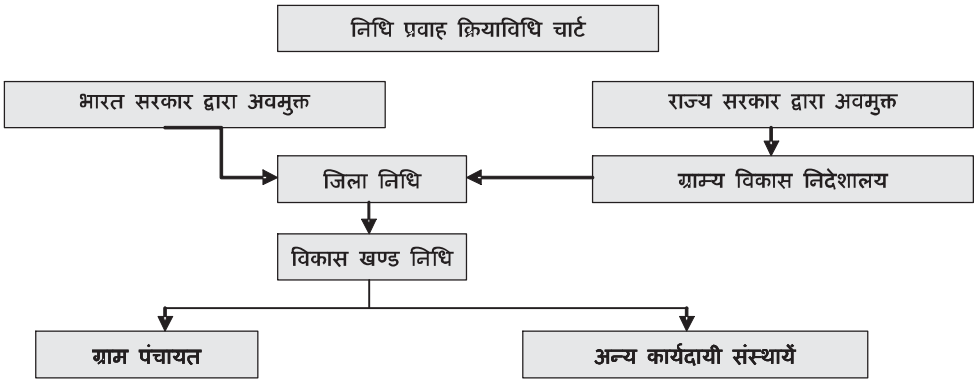
नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अनुसार, केन्द्र एवं राज्य सरकारें योजना के व्यय को वहन करेंगी जैसा निम्नवत् **तालिका 2.2.5** में वर्णित हैः

तालिका-2.2.5

व्यय की मदें	केन्द्रांश	राज्यांश
अकुशल श्रमिक	शत *प्रतिशत* अधिसूचित दरों पर	केन्द्र के अधिसूचित दरों से आधिक्य पर
कुशल श्रमिक	75 *प्रतिशत*	25 *प्रतिशत*
सामग्री	75 *प्रतिशत*	25 *प्रतिशत*
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	शत *प्रतिशत*
प्रशासनिक व्यय	भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित	रा रो गा प के प्रशासनिक व्यय

उत्तराखण्ड में अपनाई गयी निधि-प्रवाह क्रियाविधि नीचे **चार्ट-3** में दर्शायी गयी हैः

चार्ट-3



2.2.8.2 निधि की उपलब्धता एवं व्यय

2007-12 के दौरान, योजना के अन्तर्गत ₹ 1335.80 करोड़[6] उपलब्ध थे जिसमें से सरकार द्वारा ₹ 1312.88 करोड़[7] व्यय किये गये। राज्य सरकार द्वारा योजना पर किये गये व्यय एवं बजट आबंटन के विस्तृत विवरण निम्न **तालिका-2.2.6** में दर्शाये गये हैं। आगे, नमूना चयनित जनपदों के सम्बन्ध में यह विवरण **परिशिष्ट-2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2.6 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	योजनान्तर्गत आच्छादित जनपद	प्रारम्भिक शेष	अवमुक्त निधियाँ				कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अव्ययित निधि
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग	विविध प्राप्तियाँ			
2007-08	**05**	**23.58**	114.41	13.59	**128.00**	1.61	**153.19**	95.75	**57.44**
2008-09	**13**	**68.67**	92.15	10.66	**102.81**	3.88	**175.36**	135.79	**39.57**
2009-10	**13**	**40.53**	278.45	27.38	**305.83**	2.45	**348.81**	283.09	**65.72**
2010-11	**13**	**65.72**	300.05	37.45	**337.50**	2.17	**405.39**	380.20	**25.19**
2011-12	**13**	**25.19**	373.58	38.85	**412.43**	3.35	**440.97**	418.05	**22.92**
योग			**1158.64**	**127.93**	**1286.57**	**13.46**		**1312.88**	

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनायें।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि वर्ष 2007-08 के अन्तिम शेष (अं शे) एवं 2008-09 के प्रारम्भिक शेष (प्रा शे) में ₹ 11.23 करोड़ एवं 2008-09 के अं शे एवं 2009-10 के प्रा शे में ₹ 0.96 करोड़ का अन्तर था।

[6] केन्द्रांश और राज्यांशः ₹ 1286.57 करोड़ः विविध प्राप्तियाँ: ₹ 13.46 करोड़: 2007-08 का प्रारम्भिक अवशेषः ₹ 23.58 करोड़ और एस जी आर वाई से स्थानान्तरित निधिः ₹ 12.19 करोड़।

[7] कार्यों पर व्ययः ₹ 1263.15 करोड़ : प्रशासनिक व्ययः ₹ 49.73 करोड़।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान, सचिव, ग्राम्य विकास ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि इस ओर गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जायेगा। आगे, अपर सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 2008 में स ग्रा रो यो से मनरेगा में निधियों के स्थानान्तरण के कारणवश ऐसा असमाधान हुआ होगा, तथापि, समाधान करने के बाद लेखापरीक्षा को विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

राज्य सरकार का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि प्रा शे एवं अं शे में अन्तर का मिलान चार वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी नहीं हुआ जो राज्य स्तर पर कमज़ोर वित्तीय अनुश्रवण तंत्र की ओर इंगित करता है।

2.2.8.3 राज्यांश की अवमुक्ति में विलम्ब

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 8.4 के अनुसार, योजना को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार, भारत सरकार के प्रथम किश्त अवमुक्त करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर राज्यांश जनपदों को अवमुक्त करें।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में उद्घाटित हुआ कि राज्यांश निर्धारित समयावधि में अवमुक्त नहीं किया जा रहा था। 2008-09 से 2011-12 की अवधि में चार लेखापरीक्षित जिला कार्यक्रम समन्वयकों को राज्यांश अवमुक्ति में औसतन 13 से 90 दिनों तक का विलम्ब हुआ जिसमें अधिकतम विलम्ब सात माह का था।

केन्द्रीय निधि की अवमुक्ति (प्रथम किश्त) एवं राज्यांश की अवमुक्ति में विलम्ब निम्न **तालिका-2.2.7** इंगित है:

तालिका-2.2.7

जिला कार्यक्रम समन्वयक का नाम	केन्द्रीय निधि की अवमुक्ति की तिथि (प्रथम किश्त)				राज्यांश की अवमुक्ति की तिथि (विलंब दिनों में)				औसत विलंब (दिनों में)
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
अल्मोड़ा	07.05.08	30.06.09	14.05.10	27.04.11	02.06.08 (11)	22.09.09 (69)	15.07.10 (47)	14.07.11 (63)	48
पौड़ी	22.04.08	22.07.09	15.05.10	04.05.11	02.06.08 (26)	31.07.09 (00)	07.06.10 (08)	07.06.11 (19)	13
देहरादून	09.05.08	11.08.09	28.06.10	23.04.11	05.08.08 (73)	25.03.10 (211)	26.07.10 (13)	08.07.11 (61)	90
पिथौरागढ़	01.04.08	20.04.09	16.04.10	01.04.11	29.05.08 (43)	29.04.09 (00)	07.06.10 (37)	07.06.11 (52)	33

स्रोतः नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयकों के अभिलेखों से विवरण।

इस ओर इंगित करने पर (अगस्त एवं अक्टूबर 2012), विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि राज्यांश की अवमुक्ति प्रक्रिया में विलंब होता है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जनपदों को सीधे निधियाँ अवमुक्त की जाती हैं एवं भारत सरकार से इन निधियों की प्राप्ति के सापेक्ष सम्बन्धित जनपदों द्वारा राज्यांश की माँग पर निदेशालय, ग्राम्य विकास द्वारा राज्य स्तर पर प्रस्ताव सभी जनपदों से माँग का संकलन करने के बाद भेजा जाता था। पुनश्य, यह प्रस्ताव वित्त/ नियोजन विभाग को भेजे जाते थे एवं उनके अनुमोदन के पश्चात् उन्हें आबंटित राज्यांश के लिये निधियाँ अवमुक्त की जाती थी। इस विलंब के लिये राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ भी उत्तरदायी ठहराई गई। राज्यांश की अवमुक्ति में सात महीने के विलम्ब के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया (अगस्त 2012) कि अनुदान सं. 19-ग्राम्य विकास के अन्तर्गत पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण समयान्तर्गत राज्यांश अवमुक्त नहीं किया जा सका। यद्यपि, प्रस्थान

गोष्ठी के दौरान अपर सचिव, वित्त विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आश्वस्त किया गया कि भविष्य में राज्यांश समय से अवमुक्त किया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य को आने वाले वर्ष में केन्द्रांश की राशि अग्रिम तौर पर विदित होती है क्योंकि राज्य के बजट प्रस्ताव के सापेक्ष भारत सरकार की प्राधिकृत समिति द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाता था। अतः राज्य सरकार को योजना के प्रावधानों जैसे कि माँग पर रोजगार मुहैया कराना और एक पखवाड़े में श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने को ध्यान में रखते हुये वार्षिक बजट में राज्यांश की अवमुक्ति हेतु पर्याप्त प्रावधान करना चाहिये था।

2.2.8.4 स ग्रा रो यो से मनरेगा में निधियों का अन्तरण

ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (स ग्रा रो यो) बन्द किये जाने एवं इसकी अव्ययित शेष राशि को मनरेगा योजना में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश (मार्च 2008) जारी किये। इन निर्देशों के अनुसार, स ग्रा रो यो के खाते दिनांक 31 मार्च 2008 को बन्द कर दिये जाने थे एवं इस योजनान्तर्गत अव्ययित राशि को मनरेगा खाते में अन्तरित किया जाना था। देहरादून जिले के जिला कार्यक्रम समन्वयक/ विकास खण्ड/ ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न अनियमिततायें उद्घाटित हुई:

1. स ग्रा रो यो से विभिन्न संस्थाओं[8] को ₹ 5.28 लाख के अग्रिम (निर्माण, सामाजिक वनीकरण, सीमेन्ट क्रय, आकस्मिकता से सम्बन्धित) की वसूली लेखापरीक्षा दिनांक (जून 2012) तक नहीं की गयी थी। यद्यपि, इन निधियों को मनरेगा खातों में अन्तरित दर्शाया गया था।
2. देहरादून जनपद के विकासनगर विकास खण्ड में स ग्रा रो यो के ₹ 7.40 लाख मनरेगा के स्थान पर जैविक खाद खाते में स्थानान्तरित (अप्रैल 2008) कर दिये गये।
3. देहरादून जनपद के चकराता विकास खण्ड में, स ग्रा रो यो के ₹ 3.02 लाख लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2012) तक मनरेगा खातों में स्थानान्तरित नहीं किये गये।
4. जिला कार्यक्रम समन्वयक, देहरादून के नमूना चयनित ग्राम पंचायतों में स ग्रा रो यो के अन्तर्गत धनराशि स्थानान्तरित नहीं की गयी एवं अद्यतन (जून 2012) स ग्रा रो यो के खाते में जमा थी।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान, सचिव ग्राम्य विकास ने अवगत कराया कि प्रकरण की जाँच की जायेगी एवं लेखों/अभिलेखों में परिलक्षित किया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन

2.2.9 100 दिनों का रोजगार प्रदान कर जीवनयापन सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना

2.2.9.1 ग्रामीण परिवारों की जीवनयापन सुरक्षा सुनिश्चितता की पूर्ति न होना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों का प्रस्तर 1.1 अवगत कराता था कि योजना का प्रारम्भिक उद्देश्य प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारण्टीशुदा रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण इलाकों में जीवन यापन सुरक्षा प्रदान करना था।

---

[8] बेसिक शिक्षा अधिकारी, देहरादून (जरो यो); पैक्सफेड देहरादून; भारतीय खाद्य निगम, देहरादून; अधिशासी अभियन्ता, ऋषिकेश (जरो यो) अधिशासी अभियन्ता (प्रा.ख.) लो.नि.वि., देहरादून; उपजिलाधिकारी, देहरादून (ज.रो यो); उपजिलाधिकारी, चकराता (जरो यो); आयुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी; जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, देहरादून; उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कार्पोरेशन; सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया (जरो यो)।

राज्य के कुल 19.97 लाख परिवारों[9] में से, 2007-12 समयावधि के दौरान 1.89 लाख से 5.42 लाख परिवारों ने रोजगार की माँग की एवं उन्हें औसतन 39 दिनों का प्रति परिवार प्रतिवर्ष रोजगार उपलब्ध कराया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य के कुल पंजीकृत परिवारों में मात्र दो से चार *प्रतिशत* को ही 100 दिनों का रोजगार मुहैया किया गया जबकि चयनित जनपदों/ विकास खण्डों में यह दो *प्रतिशत* था। प्रति ग्रामीण परिवार औसत मानव दिवस, उक्त वर्णित अन्तराल में प्रति पंजीकृत परिवार जिनके लिये रोजगार प्रदान किया गया, राज्य स्तर पर 39 दिन था जबकि नमूना चयनित किये गये जनपदों एवं विकास खण्डों में यह क्रमशः 32 एवं 35 दिन था **(परिशिष्ट 2.6 अ एवं ब)**।

रोजगार की माँग हेतु प्राप्त किये गये सभी आवेदनों को आवेदन प्रारूप (सं. 6) में इन्द्राज़ किया जाना था जो कि योजना के माध्यम से जीवनयापन प्रदान किये जाने की ओर पहला कदम था। राज्य सरकार द्वारा रोजगार के लिये निर्धारित आवेदन प्रारूप (सं. 6) में अलग से दिनांक का कॉलम नहीं था जिससे आवेदक रोजगार की माँग करता था यद्यपि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित नमूना प्रारूप में यह प्रावधानित था। फलस्वरूप, रोजगार प्रदान किये जाने में विलंब को किसी स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका। लाभार्थी सर्वेक्षण में यह तथ्य और पुख्ता हो गया जहाँ 1000 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में 818 लाभार्थियों ने बताया कि कार्य के लिये आवेदन तभी लिये जाते हैं जब ग्राम पंचायत को निधियाँ आबंटित की जाती है। अतः, यहाँ पर राज्य पोषित बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का अवसर ही नहीं था जैसा कि मनरेगा के परिचालित दिशानिर्देशों में वर्णित था जिससे योग्य लाभार्थी इसे प्राप्त करने में वंचित रह गये।

लेखापरीक्षा टिप्पणी से सहमत होते हुए (अगस्त 2012) विभाग ने सूचित किया कि रोजगार की माँग के लिये आवेदन हेतु पूर्व में निर्धारित आवेदन प्रारूप (सं. 6) संशोधित कर दिया गया एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों को अपनाने हेतु संचरित कर दिया गया है। विभाग ने यह भी बताया कि योजना माँग आधारित थी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयकों को मनरेगा के प्रावधानों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देशित कर दिया गया। जिला कार्यक्रम समन्वयकों को दिये गये निर्देशों में यह तथ्य शामिल था कि प्रचार-प्रसार के दौरान यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रत्येक जॉबकार्ड धारक इस प्रावधान से जागरूक हो जाये कि उसे माँग के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान कर दिया जाये एवं लाभार्थी की माँग के सापेक्ष पावती प्रदान की जाये।

2.2.9.2 मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के लिये क्षतिपूर्ति का भुगतान न किया जाना।

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 7.1.4 एवं 7.1.5 में बताया गया है कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर, सप्ताह के पूर्व निर्धारित दिवस में प्रत्येक ग्राम पंचायत में होना चाहिये। बैंक/ डाकघर के माध्यम से होने वाले मजदूरी भुगतान का सम्पूर्ण विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिये। कामगार साप्ताहिक आधार पर एवं किसी भी दशा में कार्य समाप्त होने की तिथि के एक पखवाड़े के अन्दर भुगतान पाने के हकदार थे। मजदूरी के भुगतान में विलंब की दशा में कामगार मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (नरेगा, अनुसूची II, धारा 30) के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति पाने के हकदार थे, जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

मजदूरी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार

[9] 2011 जनगणना के अनुसार।

(अ) यदि मजदूरी के भुगतान में कोई विलंब हुआ हो तो पीड़ित व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत श्रम निरीक्षक या इस प्रयोजन हेतु नामित किसी प्राधिकारी को जिस तारीख को मजदूरी का भुगतान देय हुआ हो, के बारह महीनों के भीतर आवेदन कर सकता है।

(ब) प्राधिकारी आवेदक एवं नियोक्ता या मजदूरी के भुगतान हेतु उत्तरदायी अन्य व्यक्ति को सुनेगा एवं जाँचोपरान्त विलंबित मजदूरी के इस प्रकार की क्षतिपूर्ति, जो कि तीन हजार से अधिक न हो एवं एक हजार पाँच सौ (₹ 1500) से कम न हो, के साथ भुगतान हेतु निर्देशित कर सकता है एवं यदि विलंबित मजदूरी का भुगतान आवेदन पर कार्यवाही से पूर्व कर दिया गया हो तो प्राधिकारी इस प्रकार की क्षतिपूर्ति का भुगतान के निर्देश दे सकता है जो कि दो हजार से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा ने 10 विकास खण्डों के 100 ग्राम पंचायतों के नमूना चयनित 899 कार्यों में निम्नलिखित देखाः

- लाभार्थियों को भुगतान करने में 669 दिनों (लगभग दो वर्ष) के अधिकतम विलंब के साथ 500 कार्यों में औसत विलंब 74 दिनों का था।
- नमूना जाँच किये गये 100 ग्राम पंचायतों में किसी श्रमिक को क्षतिपूर्ति के रूप में कोई धनराशि दी गयी नहीं पायी गयी।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान, सचिव, ग्राम्य विकास ने कहा कि यह एक गम्भीर प्रकरण है एवं इसका निस्तारण किया जाएगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने में असमर्थ था एवं जो भी अल्प रोजगार उपलब्ध कराया गया, लाभार्थियों को उसका भुगतान समय से नहीं किया गया। नमूना परीक्षित जनपदों के 500 कार्यों में विलंबित भुगतान ने इन कार्यों पर लगाए गए कर्मियों को, कम से कम ₹ 1.99 करोड़[10] तक का प्रतिपूर्ति लाभ से अंततः वंचित रखा। राज्य सरकार को भुगतान में विलंब को कम करने के लिये भुगतान प्रक्रिया को दुरूस्त करने की आवश्यकता है।

2.2.9.3 विभिन्न कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ₹ 1.49 करोड़ की देयता का सृजन

राज्य सरकार द्वारा सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देशित (दिसम्बर 2011) किया गयाः (i) जहाँ निधियाँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध थी वहाँ निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाये एवं (ii) जहाँ निधियाँ अपर्याप्त थी वहाँ कार्य किया जाये एवं दायित्व सृजित किये जायें। भुगतान के संबंध में यह स्पष्ट रूप से विदित था कि किये गये कार्य के सापेक्ष लाभार्थियों को भुगतान भविष्य में किया जायेगा, जब धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। इन अनुदेशों के अनुसार सृजित दायित्वो को उपलब्धि माना जायेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, कार्यक्रम अधिकारी, विकास खण्ड, धौलादेवी, द्वाराहाट एवं चकराता द्वारा अवगत कराया गया कि निधियों की कमी के कारण उनके विकास खण्डों में 2011-12 के दौरान क्रमशः ₹ 80.72 लाख, ₹ 27.57 लाख एवं ₹ 40.33 लाख के दायित्व सृजित किये गये।

---

[10] 500 कार्यों में कुल 13278 श्रमिक नियुक्त थे जिसमें लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रमिकों को भुगतान देयतिथि के बाद प्राप्त हुआ जो कि कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के बाद थी। यदि प्रत्येक श्रमिक को ₹ 1500 की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया होता तो यह ₹ 1,99,17,000 (13278 × ₹ 1500) यथा ₹ 1.99 करोड़ होता।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), विभाग द्वारा तथ्य स्वीकार करते हुए कहा गया कि दायित्व सृजित किये जाने के निर्देश, जिला कार्यक्रम समन्वयकों द्वारा निधियों की अनुपलब्धता के फलस्वरूप रोजगार प्रदान करने में हो रही समस्याओं के विषय में बताए जाने के कारण निर्गत किये गये।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के निर्देशों में समय से भुगतान नहीं किए जाने पर क्षतिपूर्ति के प्रावधान का उल्लेख नहीं था एवं यह अनुदेश एक सप्ताह या अधिकतम 15 दिनों में भुगतान सुनिश्चित किए जाने के अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन में थे।

2.2.9.4 कामगारों को वेतन पर्ची जारी न किया जाना।

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों का प्रस्तर 7.2.1 कहता है कि जब धनराशि का भुगतान किया जाये, एक वेतन पर्ची निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार श्रमिक को सूचना देने के लिये बनायी जा सकती है। कामगारों को धन का वितरण मात्र वेतन पर्ची के प्रस्तुत करने और कामगारों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि आहरण पर्ची पर ही किया जाना चाहिए।

100 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि नमूना चयनित किसी भी ग्राम पंचायत में कामगारों को वेतन पर्ची जारी नहीं की गयी थी।

इस ओर इंगित करने पर (अगस्त 2012) विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं कहा गया (अगस्त 2012) कि वेतन पर्ची जारी करने के लिये निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2.2.9.5 मस्टर रोल का संधारण

मस्टर रोल विशिष्ट कार्यस्थल एवं विशिष्ट अवधि से सम्बन्धित श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका होती है। मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 9.4 के अनुसार, विकास खण्ड स्तर से निर्गत किये गये विशिष्ट पहचान संख्या के मस्टर रोलों का रखरखाव ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा निर्देशित प्रारूप में किया जाना था। मस्टर रोल मे जॉब कार्ड संख्या, कामगार का नाम एवं कार्य दिवस का उल्लेख किया जाना जरूरी था। कार्यकत्ताओं की उपस्थिति एवं प्रदत्त मजदूरी प्रत्येक नाम के सामने कामगार के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान के साथ दर्शाया जाना था।

नमूना चयनित 100 ग्राम पंचायतों में कराये गये 899 कार्यों में प्रयुक्त 10759 मस्टर रोल की जाँच में, 1110 मस्टर रोल में कटिंग, 510 मस्टर रोल में फ्लूड का प्रयोग एवं 771 मस्टर रोल में ओवर राइटिंग पायी गयी जो कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग-1 के प्रस्तर 307-A के विरुद्ध था।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान सचिव, ग्राम्य विकास ने बताया कि प्रकरण को देखा जायेगा एवं उसी अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। यद्यपि, वर्तमान में मस्टर रोल में किसी भी प्रकार की कटिंग, फ्लूड एवं ओवर राईटिंग का उपयोग न करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

2.2.10 जॉब कार्ड

2.2.10.1 जॉब कार्डों का रखरखाव

जैसा कि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 5.3 में उल्लिखित है, पंजीयन किये गये वयस्क सदस्यों के छायाचित्रों को जॉब कार्ड में चिपकाया जाना था। जॉबकार्ड उस परिवार की अभिरक्षा में होगा जिसे इसे निर्गत

किया गया हो तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना था। योजना के क्रियान्वयन एवं परिणामों को सुनिश्चित करने हेतु, लेखापरीक्षा दल ने नमूना जाँच में लिये गये 100 ग्राम पंचायत में से प्रत्येक में 10 की दर से 1000 लाभार्थियों का चयन किया एवं प्रत्येक चयनित लाभार्थी के साक्षात्कार हेतु गाँवों का दौरा किया। लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये-

- लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 279 प्रकरणों में जॉब कार्ड लेखापरीक्षा दल को नहीं दिखाये गये। इनमें से 210 लाभार्थियों ने बताया कि उनके जॉब कार्ड ग्राम प्रधान के पास हैं जो कि अधिनियम की मूल भावना के विपरीत था।
- लेखापरीक्षा दल के सामने प्रस्तुत 721 जॉब कार्डों में से 196 जॉब कार्डों में छायाचित्र लगे हुए नहीं पाये गये। छायाचित्रों के अभाव में लाभार्थियों की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- 316 प्रकरणों में भुगतान प्रविष्टियाँ अद्यतन नहीं पायी गयी, जिसके कारण लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार एवं उसके सापेक्ष किये गये भुगतान को मिलाया नहीं जा सका।
- 174 प्रकरणों में परिवार के सभी पंजीकृत वयस्क सदस्यों के छायाचित्र चिपकाये हुए नहीं पाये गये जो कि मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार जरूरी थे।
- सर्वेक्षण किये गये 1000 लाभार्थियों में से, 95 लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें निर्धारित 15 दिनों के पश्चात् जॉब कार्ड निर्गत किये गये जबकि जॉब कार्ड आवेदन के 15 दिनों के भीतर निर्गत किया जाना था।

सचिव, ग्राम्य विकास ने प्रस्थान गोष्ठी में इस बिन्दु की सराहना की एवं कहा कि इस प्रकरण पर पर्याप्त घ्यान दिया जायेगा।

2.2.10.2 जॉब कार्ड पंजिका का संधारण

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 9.1.1 में उल्लिखित है कि ऐसे परिवारों, जिन्हें जॉब कार्ड निर्गत किया जा चुका हो, का विवरण जॉब कार्ड पंजिका में अंकित किया जाना चाहिए। इस पंजिका का रखरखाव ग्राम पंचायत/ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाना था।

नमूना जाँच में लिये गये ग्राम पंचायतों के जॉब कार्ड पंजिकाओं की जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीः-

कुल 14707 पंजीकृत परिवारों में से -

- 6309 लाभार्थियों (43 *प्रतिशत*) के छायाचित्र चिपकाए हुए नहीं पाये गये।
- 2444 लाभार्थियों (17 *प्रतिशत*) के हस्ताक्षर अंकित नहीं थे।
- 1999 लाभार्थियों (14 *प्रतिशत*) में ग्राम विकास अधिकारियों के हस्ताक्षर अंकित नहीं थे।
- 5868 (40 *प्रतिशत*) प्रकरणों में बैंक/ डाक घर का खाता संख्या दर्ज नहीं थे।

जैसा कि इस प्रतिवेदन में ऊपर प्रस्तर संख्या 2.2.10.1 में उल्लिखित है कि लाभार्थियों की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि 43 *प्रतिशत* लाभार्थियों के छायाचित्र इस पंजिका में चिपकाए हुए नहीं पाये गये। उक्त के अतिरिक्त, लाभार्थियों का वास्तविक खाते द्वारा ही भुगतान किया गये इसे भी प्रमाणित नहीं किया जा सका क्योंकि 40 *प्रतिशत* प्रकरणों में किसी भी खाता संख्या का अंकन नहीं किया गया था।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान, सचिव, ग्राम्य विकास ने बताया कि इस प्रकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया जायेगा।

2.2.11 परिसम्पत्तियों का निर्माण

राज्य में 2007-08 से 2011-12 की समयावधि के दौरान ₹ 1263.15 करोड़ व्यय कर कुल के 1,52,292 कार्य कराये गये। इनमें से 1,00,631 कार्य मार्च 2012 तक पूर्ण कराये गये। इनका वर्षवार विवरण नीचे **तालिका-2.2.8** में दिया गया है :

तालिका-2.2.8 *(धनराशि ₹ करोड़ में)*

वर्ष	पूर्ण कराये गये कार्य		चालू कार्य		योग	
	कार्यों की संख्या	धनराशि	कार्यों की संख्या	धनराशि	कार्यों की संख्या	धनराशि
2007-08	6307	52.39	4664	39.28	10971	91.67
2008-09	10297	64.72	9882	62.69	20179	127.41
2009-10	24677	175.78	12296	96.59	36973	272.37
2010-11	29749	248.24	12457	118.07	42206	366.31
2011-12	29601	284.01	12362	121.38	41963	405.39
योग	**100631**	**825.14**	**51661**	**438.01**	**152292**	**1263.15**

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

2.2.11.1 निर्मित परिसम्पित्तियों का रखरखाव न हो पाना

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 6.1.3 में बताया गया है कि योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों (वनीकृत भूमि की सुरक्षा सम्मिलित करते हुए) का रखरखाव मनरेगा के अन्तर्गत अनुज्ञेय कार्य माना जायेगा।

नमूना परीक्षित चार जिला कार्यक्रम समन्वयकों में 10 कार्यक्रम अधिकारियों के 818 ग्राम पंचायतों में से, 100 ग्राम पंचायतों का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया एवं इन 100 नमूना परीक्षित ग्राम पंचायतों में 2008-09 से 2011-12 की समयावधि में योजनान्तर्गत किये गये 1692 कार्यों में से, 899 कार्यों का भौतिक परीक्षण लेखापरीक्षा कर्मियों और विभागीय प्रतिनिधियों के संयुक्त दल द्वारा किया गया। संयुक्त भौतिक परीक्षण के दौरान, 294 (कुल निरीक्षित कार्यों का 33 *प्रतिशत*) निर्मित परिसम्पत्तियाँ, जो कि ₹ 3.18 करोड़ की लागत से बनाई गयी थी, क्षतिग्रस्त पायी गयी जैसा कि नमूना छायाचित्रों में देखा जा सकता है।

चार जनपदों की 100 ग्राम पंचायतों के 899 कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि परिसम्पत्तियों के रखरखाव में कोई खर्च नहीं किया गया था।



चेक डैम निर्माण, वर्ष 2009-10 क्वीरीजिमियाँ ग्रा.पं., वि.ख. मुन्सियारी, जनपद पिथौरागढ़



चाल खाल निर्माण गोकुलधुरा, वर्ष 2008-09, कोट्टियूरा ग्रा.पं., वि.ख. मुन्सियारी, जनपद पिथौरागढ़

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान सचिव, ग्राम्य विकास ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पूरे राज्य में परिसम्पत्तियों के रखरखाव पर कोई खर्च नहीं हुआ है लेकिन आश्वासन दिया कि लेबर बजट की तैयारी के दौरान परिसम्पत्तियों के रखरखाव का कार्य लेने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।

2.2.11.2 कार्यस्थल सुविधाएँ

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 6.8.1 के अनुसार सुविधायें जैसे कि चिकित्सकीय सहायता, पेयजल, छाया और शिशु पालना गृह का प्रावधान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल पर सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा द्वारा दस विकास खण्डों में पड़ने वाले 100 ग्रामों के 1000 लाभार्थियों का घर-घर सर्वे किया गया जिससे उद्घाटित हुआ कि अधिकतर प्रकरणों में कार्यदायी संस्थाओं (ग्राम पंचायतों एवं रेखीय विभागों) द्वारा कार्य स्थल सुविधायें प्रदान नहीं की गयीं। विवरण नीचे **तालिका 2.2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.2.9

श्रेणी	प्रदत्त सुविधाएँ (संख्या में)	अप्रदत्त सुविधाएँ (संख्या/*प्रतिशत* में)	ज्ञात नहीं (संख्या में)
शेड	312	644 (64 *प्रतिशत*)	44
पेयजल	412	545 (55 *प्रतिशत*)	43
शिशु पालना गृह	004	950 (95 *प्रतिशत*)	46
प्राथमिक उपचार किट	360	596 (60 *प्रतिशत*)	44

स्रोतः लाभार्थी सर्वेक्षण से निकाला गया विवरण।

इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी कार्यस्थल पर मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह गये।

इस ओर इंगित करने पर (अगस्त 2012), विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और उत्तर दिया (अगस्त 2012) कि कार्यस्थल सुविधाएँ प्रदान करने संबंधित मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2.2.12 प्रबन्धन सूचना तंत्र

प्रबन्धन सूचना तंत्र (एम आई एस) ही केवल योजना से संबंधित संकलित सूचना का एकमात्र स्रोत था जो कि जन क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध था। मनरेगा का एम आई एस लाभार्थी, शोध संस्थान, शिक्षणार्थी एवं अन्य उत्तरदायी संस्थाओं द्वारा विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता था। यह योजना के प्रभावी एवं कुशल प्रबंधन का एक आवश्यक घटक था। केन्द्रीकृत आँकड़े प्रबंधन को अनुश्रवण, मूल्याँकन एवं योजना के सभी पहलुओं को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

जैसा कि प्रणाली कार्यान्वयन पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर वेबसाइट द्वारा प्रारम्भिक तौर पर विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गये प्रविष्टियों पर आधारित था, वेबसाइट में अपलोड किये गये डाटा के सूचना प्रवाह की सच्चाई जानने के लिए परीक्षण किया गया। योजना के कार्यान्वयन प्रक्रिया में उत्पन्न आँकड़ो को नरेगा वेबसाइट पर उपलब्ध सभी संक्षिप्त प्रतिवेदनों को बनाने में किया जा रहा है। योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं की निगरानी एवं मूल्याँकन के लिए आवश्यक सूचनाओं को उत्पन्न करने के लिए भी इस डाटा का उपयोग किया जाता था। वेबसाइट पर अपलोड किये गये डाटा की विश्वसनीयता जानने हेतु नमूना

जाँच जनपदों के वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में उपलब्ध डाटा से इसे मिलाया गया। विस्तृत विश्लेषण हेतु अग्रेषित श्रेणियों के डाटा लिए गये (अ) परिवारों की संख्या जिन्हे जॉब कार्ड निर्गत किये गये थे; (ब) परिवारों की संचयी संख्या जिन्होंनें रोजगार की माँग की थी; (स) परिवारों की संख्या जिन्हें रोजगार दिया गया; (द) प्रदत्त संचयी मानव दिवस; (य) जिला स्तर पर निधि की कुल उपलब्धता; एवं (र) जिले में किया गया कुल व्यय।

जैसा कि **परिशिष्ट: 2.7** से स्पष्ट होगा कि कुछ मूलभूत क्षेत्र जैसे ऊपर बताये गये 'अ' से 'र' के संदर्भ में मनरेगा की वेबसाइट पर एम आई एस में अपलोड की गयी संख्या एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन में उल्लिखित संख्या में उल्लेखनीय असमानता थी। यह एक गंभीर मुद्दा है और एम आई एस आँकड़े की विश्वसनीयता को खतरे में डालता है जो कि भारत सरकार द्वारा उपलब्धियों को दिखाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और जिस पर प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा विश्वास किया जाता है।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर में बताया (अगस्त 2012) कि कार्मिकों की कमी के कारण एम आई एस में डाटा को अपलोड करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को समय से आँकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये अतः दोनों आँकड़ों के बीच में अंतर विद्यमान है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसी असमानता एम आई एस के आँकड़ों की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करती है। विश्वसनीय एम आई एस के अभाव में, एम आई एस आँकड़ों पर आधारित कोई भी निष्कर्ष गलत एवं भ्रामक होंगे।

2.2.13 मानव संसाधन प्रबन्धन

2.2.13.1 प्रशासनिक संसाधन

ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने योजना को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रत्येक राज्य को उनके द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक प्रतिरूप को अपनाने के लिए कहा था। इस प्रतिरूप के अनुसार, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, कार्यक्रम अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी को भी कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार दिया जा सकता था और एक समर्पित उप कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी की सहायता हेतु नियुक्त किया जा सकता है) खण्ड स्तर पर और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना की समयबद्ध क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य पद के रूप में चिन्हित किए गए थे। पुनश्य, एक पदेन ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति ग्राम विकास अधिकारी की सहायता हेतु की जानी थी। उत्तराखण्ड सरकार ने प्रशासनिक प्रतिरूप को फरवरी 2006 में अपनाया। राज्य, नमूना चयनित जनपदों एवं विकास खण्डों में मुख्य पदों पर कर्मियों की स्थिति **तालिका-2.2.10** में विस्तृत हैः

तालिका-2.2.10

राज्य स्तर पर

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (*प्रतिशत* में)
जिला कार्यक्रम समन्वयक	13	13	00 (00)
उप कार्यक्रम अधिकारी	95	56	39 (41)
ग्राम रोजगार सहायक	1811	648	1163 (64)

नमूना चयनित जनपद स्तर पर

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (*प्रतिशत* में)
जिला कार्यक्रम समन्वयक	04	04	00 (00)
उप कार्यक्रम अधिकारी	40	14	26 (65)
ग्राम रोजगार सहायक	839	246	593(71)

नमूना चयनित विकास खण्ड स्तर पर

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (*प्रतिशत* में)
उप कार्यक्रम अधिकारी	10	01	09 (90)
ग्राम रोजगार सहायक	330	51	279 (85)

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उप कार्यक्रम अधिकारी: किसी भी नमूना चयनित विकासखण्ड में पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी पदस्थापित नहीं थे। बल्कि, खण्ड विकास अधिकारियों (ख वि अ) को कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि उप कार्यक्रम अधिकारी की राज्य स्तर पर कुल कमी (41 *प्रतिशत*) थी। यद्यपि, यह कमी नमूना चयनित जिलों एवं खण्डों में क्रमशः 65 *प्रतिशत* एवं 90 *प्रतिशत* थी।

चूँकि खण्ड विकास अधिकारी विभिन्न याजनाओं जैसे कि एम पी लैड, एम एल ए लैड, राज्य वित्त आयोग, बारहवाँ एवं तेरहवाँ वित्त आयोग, क्षेत्र पंचायत विकास निधि, स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना, आपदा प्रबंधन, इंदिरा आवास योजना, अटल आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना, सभी पेंशन योजनाएँ इत्यादि से जुड़े कार्यों को करने के कारण अधिक भारग्रस्त थे। पूर्णकालिक समर्पित उप कार्यक्रम अधिकारी की अनुपस्थिति ने योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन को प्रभावित किया। खण्ड विकास स्तर पर लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में ली गई गंभीर कमियाँ इस प्रकार थी:

- खण्ड स्तर पर कार्यों के निरीक्षण में 47 *प्रतिशत* तक की कमी पाई गई। (प्रस्तर 2.2.14.2 का संदर्भ लें)
- लाभार्थियों द्वारा किये गये कार्यों के सापेक्ष समयान्तर्गत होने वाले भुगतान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। (प्रस्तर 2.2.9.2 का संदर्भ लें)
- तकनीकी प्राक्कलनों में उल्लिखित विवरणों जैसे कि कार्यस्थल की विशिष्ट स्थिति की जाँच किये बिना ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही थी। (प्रस्तर 2.2.6.4 का संदर्भ लें)
- सामाजिक अंकेक्षण, जो कि वर्ष में दो बार की जगह एक बार की जा रही थी, अनुश्रवण विहीन रहे। (प्रस्तर 2.2.14.3 का संदर्भ लें)

ग्राम रोजगार सहायक : ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा के लिए मुख्य क्रियान्वयक थे, क्योंकि वह ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के बीच की संयोजक कड़ी थे तथा उनके कर्तव्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा से संबंधित सभी अभिलेखों, जिसमें निर्धारित लेखे भी शामिल हैं, का रखरखाव करने और यह सुनिश्चित करने कि ये सभी अभिलेख जनता को आसानी से उपलब्ध हों, पंजीकरण की प्रक्रिया की निगरानी, जॉब कार्ड का वितरण, रोजगार आवेदन पत्रों के सापेक्ष दिनांकित रसीद उपलब्ध करवाने, रोजगार आवेदन पत्रों

को देखने, कार्य के आबंटन, मजदूरी के भुगतान, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और यह सुनिश्चित करने कि आवश्यकतानुसार ग्राम सभा की बैठकें एवं सामाजिक अंकेक्षण होता रहे, शामिल थे।

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.1.1 में निर्धारित है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम रोजगार सहायक होना चाहिए जिसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक चार पर्वतीय ग्राम पंचायतों एवं छः मैदानी ग्राम पंचायतों पर एक-एक ग्राम रोजगार सहायक का पद अधिसूचित (जुलाई 2009) किया।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि नमूना चयनित 10 विकासखण्डों में ग्राम रोजगार सहायक संवर्ग में अत्यधिक कमी (85 *प्रतिशत*) थी। यद्यपि, नमूना चयनित जिलों और पूरे राज्य में यह कमी क्रमशः 71 और 64 *प्रतिशत* थी। ग्राम रोजगार सहायकों की यह कमी विभिन्न अभिलेखों जैसे कि रोजगार की माँग के सम्बन्ध में पावती रसीद न प्रदान किया जाना, जॉबकार्ड का अनियमित रखरखाव, लाभार्थियों को देरी से भुगतान इत्यादि के रूप में परिलक्षित हुई जिससे कि पात्र लाभार्थी को मिलने वाले लाभ से वंचित रह गये। (प्रस्तर 2.2.9.2 और 2.2.10.1 का संदर्भ लें)

पुनश्य, राज्य में मनरेगा के लिए बनाये गये अन्य संवर्गों जैसे जिला अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर और ग्राम विकास अधिकारियों में भी कमी पाई गई **(परिशिष्ट 2.8)**।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), विभाग ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक के पदों का सृजन उसकी आवश्यकतानुसार राज्य के वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर किया गया जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में सेवा प्रदाता के माध्यम से भर्ती पर रोक लगाये जाने के कारण (नवम्बर 2009), विभिन्न संवर्गो के रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका। प्रकरण की प्रगति के संबंध में, सचिव, ग्राम विकास ने प्रस्थान गोष्ठी के दौरान बताया कि उच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई जारी है।

2.2.13.2 कार्मिकों का अनुचित वितरण

किसी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए कर्मियों का उचित वितरण जरूरी होता है। राज्य, नमूना चयनित जिलों एवं विकासखण्डों की समग्र स्थिति इंगित करती है कि कमी समानुपातिक नहीं थी, परिणामस्वरूप पदों का पक्षपात-पूर्ण वितरण हुआ। चूँकि, राज्य में उप कार्यक्रम अधिकारी संवर्ग में कमी 41 *प्रतिशत* थी जबकि नमूना चयनित जिलों एवं विकासखण्डों में यह क्रमशः 65 और 90 *प्रतिशत* थी। इसी प्रकार, ग्राम रोजगार सहायक संवर्ग में पूरे राज्य में 64 *प्रतिशत* रिक्तियाँ थीं जबकि नमूना चयनित जनपदों एवं विकास खण्डों में यह क्रमशः 71 एवं 85 *प्रतिशत* थी।

समर्पित कर्मियों की अनुपस्थिति/ कर्मियों के अनुचित वितरण से संरचनात्मक व्यवस्था कमज़ोर हुई जिसके परिणामस्वरूप राज्य/ जिला कार्यक्रम समन्वयक/ विकास खण्ड/ ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा की सुचारू कार्यशैली प्रभावित हुई।

2.2.14 अनुश्रवण तंत्र

2.2.14.1 शिकायत निवारण तंत्र

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 11.7 में निर्धारित है कि यदि किसी व्यक्ति को योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी मुद्दे से शिकायत है, तो वह इसे कार्यक्रम अधिकारी के संज्ञान में ला सकता है।

यदि शिकायत कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध है, तो वह इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक या प्रखण्ड अथवा जिला स्तर पर पदेन शिकायत निवारण पदाधिकारी के संज्ञान में ला सकता है और यदि शिकायत जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरूद्ध है तो वह इसे राज्य स्तर के शिकायत निवारण प्राधिकारी के संज्ञान में ला सकता है।

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 9.1.1 में बताया गया है कि अभिलेखों का उचित रखरखाव मनरेगा के कार्यान्वयन की सफलता का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। शिकायत पंजिका उन्हीं महत्त्वपूर्ण अभिलेखों में एक है जिसका रखरखाव हर स्तर पर किया जाना था। इस पंजिका में शिकायत की प्राप्ति का दिनांक, शिकायतकर्त्ता का विवरण, इसकी प्रकृति सहित शिकायत का विवरण, शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं इसके अंतिम निस्तारण की तिथि का उल्लेख होना था। इस पंजिका का रखरखाव कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक/ग्राम पंचायत/ अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाना था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा द्वारा शिकायतों के निवारण में असामान्य देरी पाई गयी। राज्य स्तर पर शिकायतें तीन वर्षों से ज्यादा समय तक लंबित रहीं। सबसे पुरानी शिकायत तीन वर्षों से ज्यादा वक्त तक लंबित रहीं। इसी प्रकार, नमूना चयनित जिलों के अभिलेखों से स्पष्ट हुआ कि सिर्फ 19 *प्रतिशत* शिकायतों का निवारण 15 दिनों के भीतर किया गया। शेष शिकायतों का निवारण चार से 257 दिनों की देरी से किया गया। साथ ही, 10 विकास खण्डों के शिकायतों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि तीन विकास खण्डों- पौड़ी जिले के खिर्सू एवं एकेश्वर विकास खण्ड एवं देहरादून के चकराता विकासखण्ड के शिकायत पंजिकाओं में 2008-09 से 2011-12 के दौरान प्रविष्टियाँ रिक्त थी। शेष सात नमूना चयनित विकासखण्डों में 2008-09 से 2011-12 के दौरान सिर्फ 26 शिकायतें पंजीकृत की गई।

शिकायतों के निवारण में देरी इस ओर स्पष्ट इंगित कर रही थीं कि जन शिकायत गंभीरता से नहीं ली जा रही थीं।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अगस्त 2012), विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2012) कि राज्य स्तर पर लंबित रहने का कारण यह था कि प्राप्त शिकायतें संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयकों को वांछित कार्यवाही हेतु भेजी गयी थी जिसे कर्मियों की कमी के कारण समय पर नहीं निपटाया जा सका था। ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत पंजिका का रखरखाव न होने के संदर्भ में विभाग ने बताया कि प्रत्येक स्तर पर शिकायत पंजिका के रखरखाव हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2.2.14.2 कार्यों के पर्यवेक्षण में कमी

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश के प्रस्तर 10.3.1 के अनुसार, कार्यालयीन पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र स्तर पर कार्यों के आंतरिक सत्यापन हेतु त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिसके अनुसार सत्यापन कार्यों का खण्ड स्तर पर 100 *प्रतिशत*, जिला स्तर पर 10 *प्रतिशत* एवं राज्य स्तर पर दो *प्रतिशत* किया जाना था।

राज्य स्तर, चयनित जिलों, विकासखण्डों एवं ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभिन्न स्तरों पर किये जा रहे निरीक्षण से संबंधित किसी भी स्थायी अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। यद्यपि, 2008-09 से 2011-12 के दौरान कार्यों के निरीक्षण से संबंधित उपलब्ध करायी गयी सूचनायें नीचे **तालिका-2.2.11** में दी गई हैं:

तालिका-2.2.11

कार्यों की संख्या जिनका निरीक्षण किया जाना था	निरीक्षण किये गये कार्यों की संख्या	कमी (*प्रतिशत* में)
राज्य स्तर		
2826	147	*95*
जनपद स्तर (चार नमूना चयनित)		
4574	4693	शून्य
कर्यक्रम अधिकारी स्तर (10 नमूना चयनित)		
11527	6061	*47*

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

चूँकि मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दिखाये गये आँकड़ों के साक्ष्य के रूप में निरीक्षण से संबंधित किसी भी स्थायी अभिलेखों का रखरखाव किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था, लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षणों के प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान, सचिव, ग्राम्य विकास ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि किए गये निरीक्षण के संबंध में निरीक्षण लागबुक के रखरखाव हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2.2.14.3 पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही

परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से निरंतर सतर्कता प्रदान करता है जो कि हर छः महीने में एक बार, लोगों को पारदर्शिता और जबाबदेही के साथ अनुपालन की समीक्षा करने और मनरेगा के सभी कार्यों का विस्तृत लोक-लेखापरीक्षण संचालित करने का अवसर देते हुए, की जानी थी। प्रशासन और निर्णयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढाने के लिए, निर्णयन में प्रभावित व्यक्तियों की भागीदारी, प्रभावित लोगों के प्रति जबाबदेही और शिकायत के जबाब में निवारण हेतु, सामाजिक अंकेक्षण आयोजित की जानी आवश्यक थी।

नमूना चयनित के 100 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, 39 ग्राम पंचायतों ने सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित अभिलेख नहीं दिये/दिखाये। साथ ही, यह भी ज्ञात हुआ कि 49 ग्राम पंचायते दो के निर्धारित मानक के सापेक्ष मात्र एक बार सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित कर रही थीं। विवरण नीचे **तालिका-2.2.12** में दिया गया हैः

तालिका-2.2.12

वर्ष	नमूना-जाँच किये गये ग्राम पंचायतों की संख्या	मानकानुसार किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षणों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ सामाजिक अंकेक्षण किये गये (वर्ष में एक बार)	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ सामाजिक अंकेक्षण किये गये (वर्ष में दो बार)	ग्राम पंचायतों की संख्या जिन्होंने विवरण नहीं दिया	ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ सामाजिक अंकेक्षण नहीं किये गये
2008-09	100	200	44	00	39	17
2009-10	100	200	50	11	39	00
2010-11	100	200	49	12	39	00
2011-12	100	200	49	12	39	00

स्रोतः ग्राम पंचायतों द्वारा दी गयी सूचना।

किये गये सामाजिक अंकेक्षणों को कार्यवाही पंजिका में अभिलिखित किया जा रहा था और इस संबंध में कोई पृथक कार्यवृत्त तैयार नहीं किये जा रहे थे।

सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण के कार्यवृत्त के साथ ही अनियमितताएँ अभिलिखित नहीं की जा रही थीं जिसका परिणाम यह हुआ कि लेखापरीक्षा उठायी गयी आपत्तियों एवं उनके निराकरण को सत्यापित नहीं कर सका। यद्यपि, 10 विकास खण्डों के 100 ग्राम पंचायतों में पड़ने वाले 1000 लाभार्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 804 लाभार्थियों (80 *प्रतिशत*) को सामाजिक अंकेक्षण का कोई ज्ञान नहीं था जो इस तथ्य की ओर इशारा कर रहे थे कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही थी, जो कि इस अधिनियम के प्रावधान को निष्प्रभावी बना रहा था।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान सचिव, ग्राम्य विकास ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण करने एवं बैठकों के कार्यवृत्त को निर्धारित प्रारूप में अभिलिखित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2.2.15 निष्कर्ष

एम आई एस एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आँकड़ों में असमानता थी जो मनरेगा वेबसाईट पर आँकड़े अपलोड करने से पूर्व आँकड़ों की विश्वसनीयता की जाँच के किसी तन्त्र के विद्यमान नहीं होने को दर्शाता है। इसके कारण एम आई एस की विश्वसनीयता खतरे में है जो कि भारत सरकार और प्रबद्ध नागरिकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, समृद्ध योजना की पूरी प्रक्रिया समृद्ध एम आई एस आँकडों पर आधारित है। राज्य ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना की लेकिन नियमित अन्तराल पर इसकी बैठकें नहीं हो रही थीं जिसके कारण आयोजना एवं अनुश्रवण जैसे मुख्य नीतिगत निर्णय उपेक्षित रहे। ग्राम्य विकास मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रशासनिक प्रतिरूप को अपनाया गया लेकिन 41 से 90 *प्रतिशत* तक की कमी प्रमुखतः उप कार्यक्रम अधिकारी एवं ग्राम रोजगार सहायक संवर्ग में देखी गयी। जिसने राज्य में योजना के संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया। वर्ष 2008-2013 के लिए ₹ 87.92 लाख की लागत से तैयार जिला पर्सपेक्टिव योजना निरर्थक थी क्योंकि तीन वर्ष से अधिक समयावधि व्यतीत होने के पश्चात भी इसका अनुमोदन नहीं हुआ था।

योजना का प्राथमिक उद्देश्य, जिसमें लक्षित ग्रामीण समुदाय को निर्धारित मजदूरी दरों पर 100 दिनों का वार्षिक रोजगार उपलब्ध कराते हुए उनके जीवन स्तर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, प्राप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान केवल दो से चार *प्रतिशत* पंजीकृत परिवारों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा सका। राज्य सरकार द्वारा रोजगार के लिये निर्धारित आवेदन प्रारूप में अलग से दिनांक का कॉलम नहीं था जिससे आवेदक रोजगार की माँग करता जबकि मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के नमूना प्रारूप में यह प्रावधानित था। अतः रोजगार प्रदान किये जाने में विलंब को किसी स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा सका। जिससे राज्यपोषित बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का कोई अवसर नहीं था। परिणामस्वरुप, लेखा परीक्षा ने किसी लाभार्थी को प्रदत्त बेरोजगारी भत्ता का एक भी प्रकरण नहीं पाया। लेखा परीक्षा नें लाभार्थियों को भुगतान में औसतन 74 दिनों का विलम्ब पाया जो कि अधिकतम 669 दिनों (लगभग दो वर्ष) का था, जिसके लिए किसी भी लाभार्थी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। योजना के अन्तर्गत परिसम्पत्ति सृजन के रखरखाव के लिए कोई व्यय नहीं किया गया। कार्यों के निरीक्षण एवं

अनुश्रवण से सम्बन्धित कोई स्थाई अभिलेख का रख रखाव किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। अधिकतर ग्राम पंचायतों में वर्ष में निर्धारित दो सामाजिक अंकेक्षण के सापेक्ष एक सामाजिक अंकेक्षण ही आयोजित किया जा रहा था।

इस प्रकार, यद्यपि योजना वर्ष 2006 में प्रारम्भ हुई थी, विभिन्न कारकों जैसा कि ऊपर बताया गया है के कारण योजना की कमी और अकुशल कार्यान्वयन से ग्रसित रहीं और 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका।

2.2.16 अनुशंसाएँ

सरकार इस पर विचार कर सकती है कि;

- कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मनरेगा वेबसाईट में अपलोड की गयी प्रबन्धन सूचना प्रणाली आँकड़े और मासिक प्रगति प्रतिवेदन आँकड़े के सम्बन्ध में उचित मानचित्रण सुनिश्चित किया जाए।
- मनरेगा योजना का नियोजन, अनुश्रवण, शिकायत निवारण और सामाजिक अंकेक्षण जैसे मुद्दों से निपटने के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जाए।
- राज्य के वार्षिक योजना और श्रम बजट को अन्तिम रुप देते समय ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किये गये वार्षिक कार्य योजनाओं को महत्व दिया जाए।
- ग्रामीण लोगों को योजना के लाभ और प्रावधानों के बारे में मास मीडिया प्रचार-प्रसार के माध्यम से और अधिक जागरुक बनाया जाए।
- ग्राम पंचायतों को आगामी वार्षिक कार्य योजना में पूर्व में सृजित सम्पत्तियों के रख रखाव के लिए प्रावधान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- अनुश्रवण तंत्र, सामाजिक अंकेक्षण और जनता की शिकायतों के निवारण को मजबूत किया जाए।

विषयक लेखापरीक्षा

निर्वाचन विभाग

2.3 निर्वाचन विभाग पर विषयक लेखापरीक्षा

2.3.1 परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 में प्रावधान है कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (सी ई ओ, अपने आप में नियंत्रण प्राधिकारी) राज्य में लोकसभा और विधानसभा के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये भारत के निर्वाचन आयोग (ई सी आई) के नियंत्रण और दिशा निर्देश के अंतर्गत, समग्र प्रभारी है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-K और 243-ZA एवं अन्य प्रासंगिक अधिनियम और नियम के तहत उत्तराखण्ड में पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड जो कि सी ई ओ के अतिरिक्त एक अन्य निकाय है, के अधीक्षण, दिशा-निर्देश और नियंत्रण में आयोजित किये जाते हैं।

राज्य की कुल जनसंख्या 101.17 लाख[11] है, जिसमें से 62.78 लाख[12] (62 *प्रतिशत*) योग्य मतदाता हैं। उत्तराखण्ड राज्य में 5 लोक सभा सीटें व 70 विधान सभा सीटें हैं।

2.3.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

निर्वाचन विभाग के संगठनात्मक ढ़ाँचे को नीचे **चार्ट-I** में दर्शाया गया है:

चार्ट-I



2.3.3 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा के दौरान चुनाव विभाग की नियमितता मुद्दों एवं प्रभावोत्पादकता की जाँच हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देहरादून एवं 13 जिला निर्वाचन कार्यालयों में से, 10[13] जिला निर्वाचन कार्योलयों के अभिलेखों की

[11] 2011 की जनगणना के अनुसार।

[12] 32.84 लाख पुरुष मतदाता एवं 29.94 लाख महिला मतदाता।

[13] अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी, उधमसिंहनगर एवं उत्तरकाशी।

नमूना जाँच की गई। 2009-10 से 2011-12 तक 3 वर्ष की अवधि का समावेश करते हुए मई-जुलाई 2012 के मध्य लेखापरीक्षा संपन्न की गई जिसमें लोकसभा चुनाव 2009 (अप्रैल/मई) और विधान सभा 2012 (जनवरी) के साथ दो विधानसभा सीटों[14] के उपचुनाव भी शामिल थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर 17 दिसम्बर 2012 को अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ प्रस्थान गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया। शासन के विचार प्रतिवेदन के प्रासंगिक पैराओं के सापेक्ष उपयुक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिये गये।

2.3.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषयक लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या:

- मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ई पी आई सी) समय पर तैयार किये गये और पात्र मतदाताओं को शामिल किया गया;
- व्यय ई सी आई मापदण्डों के अनुसार किया गया;
- चुनाव कार्य में लगे हुये कर्मियों के अग्रिम भुगतान का समायोजन समय पर किया गया; और
- मानव संसाधन का अधिकाधिक उपयोग किया गया।

2.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्न स्रोतों से निष्कर्षित किये गये:

- सामान्य वित्तीय नियम और कोषीय नियम;
- भारत सरकार द्वारा संकलित निर्वाचन विधि निर्देशिका;
- रिटर्निंग अधिकारी की हस्तपुस्तिका; एवं
- ई सी आई दिशानिर्देशों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये अनुदेश/ आदेश।

2.3.6 वित्तीय स्थिति

लोक सभा चुनाव आयोजित करने के लिये चुनाव खर्च पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और विधानसभा चुनाव के संबंध में यह पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। स्थापना, मतदाता फोटो पहचान पत्र/निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं मुद्रण के खर्च, दोनों चुनावों के लिये, राज्य और केन्द्र के बीच समान रूप से वहन किया जाता है। निर्वाचन विभाग के संबंध में वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान आवंटित धनराशि और वास्तविक व्यय का विवरण निम्न **तालिका-2.3.1** में दिए हैः

तालिकाः 2.3.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	मतदाता सूची की तैयारी एवं मुद्रण			लोक सभा चुनाव			विधानसभा चुनाव		
	आबंटन	व्यय	समर्पण	आबंटन	व्यय	समर्पण	आबंटन	व्यय	समर्पण
2009-10	8.38	5.95	2.43	18.60	17.80	0.80	0.89	0.45	0.44
2010-11	10.13	9.14	0.99	0.48	0.46	0.02	0.06	0.04	0.02
2011-12	9.44	7.89	1.55	0.58	-	0.58	23.20	20.61	2.59
कुल	**27.95**	**22.98**	**4.97**	**19.66**	**18.26**	**1.40**	**24.15**	**21.10**	**3.05**

[14] मई 2009 में कपकोट एवं सितम्बर 2009 में विकासनगर।

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित व्यय स्थापना, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी एवं मुद्रण/ मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना, चुनावी व्यवस्था, मतदान एवं गणना आदि के लिये तैनात कर्मियों के यात्रा भत्ता, पारिश्रमिक और हल्के जलपान आदि की व्यवस्था हेतु है।

2.3.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सी ई ओ के पास उपलब्ध आँकड़ो के अनुसार राज्य में 62.78 लाख वैध मतदाताओं में से 62.68 लाख मतदाताओं (99.84 *प्रतिशत*) को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करा दिये गये हैं। 01 जनवरी 2012 तक 62.78 लाख वैध मतदाताओं में से 62.65 लाख मतदाताओं (99.79 *प्रतिशत*) की फोटो राज्य की मतदाता सूची में उपलब्ध थी। विभाग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2009 तथा विधानसभा चुनाव 2012 संपन्न कराये गये तथा लेखापरीक्षा में समावेशित समय के दौरान किसी प्रकार का पुनर्मतदान, आचार संहिता के उल्लंघन तथा चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के असमायोजित क्षतिपूर्ति का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। विभाग ने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता अभियान के लिये आवश्यक कदम उठाये जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवक संगठनों, शैक्षिक संगठनों आदि।

चुनाव खर्च और अन्य अनुपालन मुद्दों पर कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित प्रस्तरों में उल्लिखित हैं:

2.3.7.1 निर्धारित सीमा से अधिक व्यय

अ. राज्य सरकार ने (फरवरी 2004) में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन आदि के लिये तंबू, बैरिकेडिंग, फर्नीचर, प्रकाश, ध्वनि आदि की व्यवस्था पर होने वाले खर्च के लिये ₹ 0.80 लाख की वित्तीय सीमा निर्धारित की थी।

लोक सभा चुनाव 2009 से संबंधित 10 जिला निर्वाचन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच तथा मुख्य निर्वाचन कार्यालय से संग्रहित सूचना के आधार पर लेखापरीक्षा ने पाया कि 13 जिला निर्वाचन कार्यालयों में से 11 जिला निर्वाचन कार्यालयों में ठेकेदारों/फर्मों द्वारा ₹ 175.84 लाख के प्रस्तुत किये गये बिलों/दावे के विरूद्ध, विभागीय अधिकारियों द्वारा, विवरणों के सत्यापन के बाद ठेकेदारों/फर्मों को ₹ 137.53 लाख का भुगतान किया गया जो कि अनुमन्य निर्धारित राशि ₹ 42.40 लाख से ₹ 95.13 लाख अधिक थी। जिलों में अनुमन्य सीमा से अधिक व्यय का *प्रतिशत* 38 से 502 के बीच था (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2.9** में)।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (अक्टूबर 2009) ने भी निर्धारित सीमा से अधिक व्यय पर गंभीरता व्यक्त करते हुये कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा व्यय करते समय मितव्ययिता पर ध्यान नहीं दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उद्धरण करते हुये टिप्पणी की कि बागेश्वर में जलरोधक (वाटरप्रूफ) तंबूओं, सी एफ एल का किराया ₹ 200/- प्रतिदिन, नैनीताल, अल्मोड़ा व चमोली में बल्बों के किराये क्रमश: ₹ 10/- प्रतिदिन, ₹ 11/- प्रतिदिन, ₹ 9.50/- प्रतिदिन का कोई औचित्य नहीं था।

ब. इसी प्रकार, सरकार ने (अक्टूबर 2009) राज्य के विधानसभा चुनाव फरवरी 2012 के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन में होने वाली तंबूओं, बैरिकेडिंग, फर्नीचर, प्रकाश और ध्वनि आदि व्यवस्थाओं के लिये ₹ 1.60 लाख की वित्तीय सीमा निर्धारित की थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव 2012 से संबंधित संग्रहित सूचना और 13 जिला निर्वाचन कार्यालयों में से 10 के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने यह पाया कि तंबू, बैरिकोडिंग फर्नीचर और ध्वनि-प्रकाश आदि की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिये निविदायें आमंत्रित करते वक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त वित्तीय सीमा को संज्ञान में नहीं लिया गया था। ठेकेदारो/फर्मो के द्वारा ₹ 271.63 लाख के प्रस्तुत किये गये बिलों के दावे के विरूद्ध, विभागीय अधिकारियों ने, विवरणों के सत्यापन के बाद, ₹ 222.02 लाख के भुगतान की अनुशंसा की। जिसमें से ₹ 92.33 लाख ठेकेदारों/फर्मों को भुगतान कर दिया गया व अतिरिक्त धन की अपेक्षा में ₹ 129.69 लाख अभी भी ठेकेदारों/फर्मों को देय है (अगस्त 2012 के अनुसार)। अनुशंसित ₹ 222.02 लाख की राशि, अनुमन्य व्यय ₹ 80 लाख की राशि से ₹ 142.02 लाख अधिक थी। जिलों में अनुमन्य सीमा से अधिक व्यय का *प्रतिशत* 97 से 340 के बीच था। (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-2.10** में)

इसे इंगित करने पर सरकार ने उपर्युक्त दोनों मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि चुनाव खर्च प्रकृति में आपातिक थे और आवश्यकताओं के अनुसार किये गये थे। विधान सभा चुनाव 2012 के संबंध में सरकार ने कहा कि चुनाव (30 जनवरी 2012) तथा मतगणना (04 मार्च 2012) के बीच लंबे अन्तराल के कारण कानून व्यवस्था, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई वी एम) तथा चुनाव सामग्री की सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक व्यय हुआ। सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि चुनाव व्यय से संबंधित दावे/बिल की राशि निर्धारित व्यय सीमा से कहीं अधिक थे।

2.3.7.2 मतदान कर्मचारियों का असमायोजित अग्रिम परिश्रमिक

ई सी आई के मापदण्डों (जनवरी 2009) के अनुसार, मतदान व गिनती आदि कार्यों में तैनात कर्मचारियों को निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। विभाग द्वारा चुनाव कार्यों में नियुक्त कर्मिकों को एकमुश्त राशि अग्रिम के रूप में प्रदान की गई थी जिसका समायोजन संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बिलों के माध्यम से किया जाना था।

इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सी ई ओ (फरवरी 2012) द्वारा अनुदेश दिया गया था कि समायोजन के बिल मतदान कर्मियों से प्राप्त कर लिये जाये और सभी अग्रिम व शेष राशियों का समायोजन वित्तीय वर्ष 2011-12 में आवश्यक रूप से कर लिया जाये। जाँच-परीक्षित जिला निर्वाचन कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विधान सभा चुनाव 2012 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 2.04 करोड़[15] का कुल अग्रिम मतदान कर्मचारियों को प्रदान किया गया, जिसमें से केवल ₹ 65.20 लाख (32 *प्रतिशत*) को वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक समायोजित किया गया था और ₹ 1.39 करोड़[16] के शेष अग्रिम लेखापरीक्षा की तिथि (मई-जुलाई 2012) तक असमायोजित थे।

---

[15] अल्मोड़ाः ₹ 11.46 लाख, चमोलीः ₹ 15.43 लाख, देहरादूनः ₹ 37.00 लाख, हरिद्वारः ₹ 33.89 लाख, नैनीतालः ₹ 23.54 लाख, पौड़ीः ₹ 19.50 लाख, पिथौरागढ़ः ₹ 8.57 लाख, टिहरीः ₹ 19.51 लाख, उधमसिंहनगरः ₹ 20.98 लाख एवं उत्तरकाशीः ₹ 14.18 लाख।

[16] अल्मोड़ाः ₹ 2.87 लाख, चमोलीः ₹ 15.43 लाख, देहरादूनः ₹ 28.75 लाख, हरिद्वारः ₹ 32.18 लाख, नैनीतालः ₹ 7.04 लाख, पौड़ीः ₹ 13.18 लाख, पिथौरागढ़ः ₹ 7.21 लाख, टिहरीः ₹ 19.51 लाख, उधमसिंहनगरः ₹ 1.99 लाख एवं उत्तरकाशीः ₹ 10.70 लाख।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार (दिसम्बर 2012) ने उत्तर दिया कि मतदान कर्मचारियों को प्रदत्त ₹ 1.39 करोड़ के असमायोजित अग्रिम के खिलाफ ₹ 1.35 करोड़ का समायोजन करा लिया गया था और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये है कि अवशेष ₹ 4.23 लाख की राशि तुरंत समायोजित किया जाये ताकि इसे चालू वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जा सके। उत्तर इस तथ्य को दर्शाता है कि सी ई ओ द्वारा जिला अधिकारियों को दिये गये अनुदेश कि सभी बिलों का समायोजन वित्तीय वर्ष 2011-12 में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये, का अनुपालन नहीं किया गया तथा अभी तक (दिसम्बर 2012) बिलों का समायोजन किया जाना है।

इस प्रकार मतदान कर्मिकों को दिये गये अग्रिमों का समायोजन समय पर करने में विभाग विफल रहा है।

2.3.7.3 मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबन्धन में अवश्यंभावित है कि संगठन के संचालन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागीय गतिविधियों का उचित ध्यान रखते हुये एवं उचित/पारदर्शी नीतियाँ संरचित/अनुवर्तित कर नियमित अन्तरालो में कर्मचारियों की माँग का निर्धारण एवं समीक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा की तिथि तक विभाग के कर्मचारियों की स्थिति का विवरण नीचे **तालिका-2.3.2** में सारणीबद्ध हैः

तालिका: 2.3.2

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत व्यक्ति	रिक्त पद	रिक्त पदों का *प्रतिशत*
मुख्यालय स्तर पर				
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	01	01	-	-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी	01	01	-	-
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी	01	-	01	100
अनुभाग अधिकारी	02	01	01	50
वरिष्ठ सहायक	04	02	02	50
कनिष्ठ सहायक	09	04 (उपनल से अनुबंध पर)	05	56
जिला स्तर पर				
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	13	12	01	7.69
वरिष्ठ सहायक	42	42	-	-
कनिष्ठ सहायक	30	02 (इनमें से 1 उपनल से अनुबंध के आधार पर)	28	93

स्रोतः- सी ई ओ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग वर्ष 2009 से सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बिना चल रहा था जो सभी विभागीय कार्यों में सी ई ओ की सहायता करता है और विभाग के मुख्यालय में एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिसके माध्यम से प्रस्ताव और फाइलें उच्च स्तरीय अधिकारियो के पास अनुमोदन हेतु अग्रसारित की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग में स्वीकृत क्षमता के विपरीत एक अनुभाग अधिकारी तथा 33 कनिष्ठ सहायकों की भी कमी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि कनिष्ठ सहायकों की कमी के कारण मतदान कर्मिकों के अग्रिमों के समायोजन व अन्य प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक देरी हुई।

प्रस्थान गोष्ठी के दौरान संयुक्त सी ई ओ ने कहा कि विभाग, लगातार चुनाव कार्यों में व्यस्त रहने से रिक्त पदों को नहीं भर पाए। इसके अलावा सरकार (दिसम्बर 2012) ने यह भी कहा कि ग्रुप 'सी' (कनिष्ठ सहायकों) के पदों को भरने का अनुमोदन कार्मिक विभाग से प्राप्त कर लिया गया है तथा मौजूदा पदों को भरने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

2.3.8 अन्य रोचक बिंदु

2.3.8.1 जब्त जमानत राशि को सरकारी खाते में जमा न करना

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 158 के अन्तर्गत लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के उन प्रत्याशियों की जमानत की राशि जब्त की जाती है जो कुल पड़े मतों का छठा भाग प्राप्त करने में असफल हों। रिटर्निंग अधिकारी की हस्तपुस्तिका के 16वें अध्याय के प्रस्तर 8.2 के अनुसार जब्त जमानत राशि सरकार के राजस्व खाते में जमा की जाती है।

सात जिला निर्वाचन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच और सी ई ओ देहरादून द्वारा प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि चुनाव विभाग द्वारा विधान सभा चुनाव 2012 के 664 प्रत्याशियों की ₹ 46.85 लाख की जमानत राशि जब्त की गई। इसमें से ₹ 33.25 लाख सरकार के राजस्व खाते[17] में जमा होने के बजाय सिविल जमा खाते (मुख्य लेखाशीर्ष 8443)[18] में पड़े (अगस्त 2012 तक) थे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जमानत राशि को गलत लेखाशीर्ष में प्रतिधारण करना नियमों का उल्लंघन था।

इसे इंगित करने पर सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2012) कि 7 जिलों में से 5 जिलों की जमानत राशि को सरकारी खाते में जमा करा दिया गया है तथा शेष दो राज्यों (चमोली और उधमसिंहनगर) को भी सरकारी खाते में तुरन्त जमा कराने हेतु अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

2.3.8.2 रोकड़ तिजोरी में अनाधिकृत रूप से धन का प्रतिधारण

वित्तीय नियम[19] का सामान्य सिद्धांत है कि सरकारी खाते में लंबित सभी धनराशि सरकारी खजाने या ऐसे बैंक जिसे सरकार के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, में आवश्यक रूप से रखे जाने चाहिये तथा ऐसा कोई भी धन तब तक बैंक या सरकारी खजाने से निकासी नहीं किया जाना चाहिये जब तक तुरंत संवितरण अपेक्षित न हो।

चयिनत जिलों के लेखापरीक्षा जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आठ जिलों में सरकार की विशेष अनुमति के बिना चुनाव के दौरान भारी राशियाँ खज़ाने से निकाली गई (डी डी ओ द्वारा ए सी बिलों के माध्यम से) जो रोकड़ तिजोरियों में लंबे समय तक रखी पड़ी थीं, जबकि विधान सभा चुनाव 2012 की मतगणना मार्च 2012 को पूर्ण हो चुकी थी। रोकड़ तिजोरी में अवशेष धनराशि जो कि विधान सभा चुनाव 2012 के लिये वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में खजाने से निकाली गयी (जनवरी/फरवरी) तथा लेखापरीक्षा की तिथि (मई/जुलाई 2012) तक की लंबित स्थिति को निम्न **तालिका-2.3.3** में दर्शाया गया है:

---

[17] 0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-02-चुनाव-104-शुल्क, दण्ड और जब्त की गई अन्य प्राप्तियाँ-जब्त की गई सुरक्षा जमा राशि।

[18] बागेश्वरः ₹ 1.10 लाख; चमोलीः ₹ 2.10 लाख; देहरादूनः ₹ 5.60 लाख; हरिद्वारः ₹ 10.85 लाख; नैनीतालः ₹ 5.15 लाख; पिथौरागढ़ः ₹ 1.70 लाख एवं उधमसिंहनगरः ₹ 6.75 लाख।

[19] वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-V), भाग-I का प्रस्तर-20 एवं 162 और कोषागार नियम-3।

तालिका: 2.3.3 *(₹ लाख में)*

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	31 मार्च 2012 को अवशेष नकद धनराशि	लेखापरीक्षा की तिथि तक अवशेष धनराशि
1.	डी ई ओ, अल्मोड़ा	18.27	-
2.	डी ई ओ, देहरादून	17.37	3.18
3.	डी ई ओ, हरिद्वार	26.47	7.66
4.	डी ई ओ, नैनीताल	15.43	0.63
5.	डी ई ओ, पौड़ी	59.95	3.42
6.	डी ई ओ, पिथौरागढ़	7.82	0.28
7.	डी ई ओ, ऊधमसिंहनगर	5.35	-
8.	डी ई ओ, उत्तरकाशी	32.25	0.01
कुल योग		**182.91**	**15.18**

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा अधिक मात्रा में नकद राशि को अनाधिकृत रूप से अपने रोकड़ तिजोरी में प्रतिधारित किया गया जो कि वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2012) कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि किसी भी परिस्थिति में भारी मात्रा में नकदी को रोकड़ तिजोरी में नहीं रखा जाये।

2.3.8.3 स्रोत पर कर की कटौती न करना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 (सी) के अनुसार सभी डी डी ओ का यह कर्त्तव्य है कि वह फर्म/ठेकेदारों को, किये गये कार्य एवं आपूर्ति के एवज में भुगतान किये गये ₹ 30,000 से अधिक के बिलों पर स्रोत से आय कर काट लें और उसे सरकारी खाते में जमा करायें।

चार जिला निर्वाचन कार्यालयों के वाउचरों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि मुद्रण एवं चुनावी सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धी ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं के विभिन्न बिलों से ₹ 2.07 लाख[20] की टी डी एस राशि की कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) तथा आश्वासन दिया कि भविष्य के भुगतानों में आयकर के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.3.8.4 बैंक खातों के अनियमित संचालन

सरकार के अप्रैल 2003 तथा सितम्बर 2009 के अनुदेशों के अनुसार सरकारी धनराशि, खजाने या विभाग/ डी डी ओ के व्यक्तिगत लेजर खाते (पी एल ए) में रखी जानी चाहिए और सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बैंक खातों का संचालन सख्त वर्जित है।

[20] अल्मोड़ाः ₹ 0.17 लाख, नैनीतालः ₹ 1.01 लाख, पिथौरागढ़ः ₹ 0.55 लाख एवं टिहरीः ₹ 0.34 लाख।

लेखापरीक्षा जाँच में यह पता चला है कि विभाग में कोई भी पी एल ए संचालन में नहीं था जबकि चुनावों के दौरान अधिक मात्रा में व्यय डी डी ओ द्वारा किये जा रहे थे। बैंक खातों को बंद करने और पी एल ए को खोलने के लिए बार-बार सरकार के अनुदेशों के बावजूद छः जिलो में डी ई ओ/ उप डी ई ओ के नाम से बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था तथा इन खातों में मई-जुलाई 2012 के मध्य ₹ 53.36 लाख[21] की धनराशि को जमा पाई गयी। जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा पी एल ए का संचालन नहीं किये जाने का कारण ज्ञात नहीं हो सका; केवल डी ई ओ-टिहरी, जिसने बताया की पी एल ए खोलने सम्बन्धी किसी प्रकार के दिशानिर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे।

इसे इंगित करने पर सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि सभी डी ई ओ को पी एल ए संचालन करने और बैंक खाते बंद करने सम्बन्धी वित्त विभाग के निर्देश को सख्ती से पालन करने हेतु अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

2.3.9 निष्कर्ष

चुनाव खर्चों का प्रबन्धन कमज़ोर पाया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान तंबूओं, बैरीकेडिंग, प्रकाश आदि में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया। चुनाव प्रक्रिया में नियुक्त चुनाव कर्मियों के अग्रिमों का समायोजन विधानसभा चुनाव 2012 के समाप्त होने तथा उचित समय व्यतीत हो जाने के बाद भी लम्बित रहने का प्रकरण प्रकाश में आया। इसके अलावा जमानत राशि को भी उचित सरकारी राजस्व खाते में जमा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त स्रोत से आय कर की कटौती की उपेक्षा की गई तथा रोकड़ तिजोरी में भारी नकदी प्रतिधारण तथा धनराशि को बैंक खाते में जमा करने के प्रकरण अनियमित थे।

[21] अल्मोड़ाः ₹ 0.42 लाख, टिहरीः ₹ 51 लाख, नैनीतालः ₹ 0.14 लाख, पिथौरागढ़ः ₹ 0.13 लाख, ऊधमसिंहनगरः ₹ 0.63 लाख एवं उत्तरकाशीः ₹ 1.04 लाख।

श्रम विभाग

2.4 उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्य प्रणाली

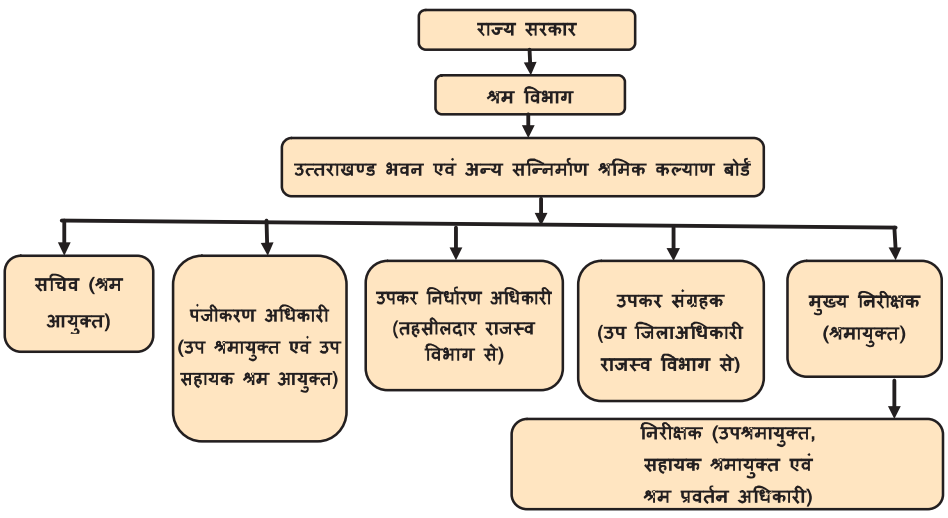
2.4.1 परिचय

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपायों को प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996 (बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट) और भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम), अधिनियमित किया। तदानुसार, उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2005 (यू के बी ओ सी डब्ल्यू रूल्स) बनायी (जून 2005)। साथ ही, उत्तराखण्ड सरकार ने निर्माण श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन (अक्टूबर 2005) किया। उपकर अधिनियम के प्राविधान के अनुसार स्थापनाओं, जिन्होंनें पिछले 12 महीनों में एक दिन भी किसी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में 10 या अधिक सन्निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया हो, को नियोक्ता द्वारा भवन की लागत पर किये गये कुल व्यय के 2 *प्रतिशत* से न अधिक एवं 1 *प्रतिशत* से न कम की दर से उपकर का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार एकत्र किया गया उपकर भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु व्यय किया जाना था। श्रमिकों को लाभों की पात्रता हेतु स्वयं को पंजीकृत करवाकर पहचान पत्र प्राप्त करने थे। भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की लेखापरीक्षा (अप्रैल, 2012), 31 अक्टूबर, 2005 से 31 मार्च, 2012 तक की अवधि को समावेशित करते हुए की गयी थी।

2.4.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक ढ़ाँचा नीचे **चार्ट-1** में दिया गया है:

चार्ट-1



2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि:

- क्या कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन की योजना प्रभावी थी;
- क्या वित्तीय प्रबंधन प्रभावी था;
- क्या कल्याणकारी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था;
- क्या मानव संसाधन प्रबन्धन प्रभावी था; और
- क्या अनुश्रवण और आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और अस्तित्व में थी।

2.4.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये थे:

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन), अधिनियम, 1996;
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996;
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998;
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन), नियमावली, 2005; और
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008।

2.4.5 लेखापरीक्षा अधिदेश

बी ओ सी डब्ल्यू अधिनियम की धारा 27 (2) के अनुसार बोर्ड के वार्षिक लेखे एक निगमित निकाय होने के नाते नि म ले के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के तहत भारत के नि म ले द्वारा लेखापरीक्षित किये जायेंगे।

2.4.6 लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र एवं कार्यविधि

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की विषयगत लेखापरीक्षा 31 अक्टूबर 2005 से 31 मार्च 2012 की अवधि को समावेशित करते हुये अप्रैल 2012 में संचालित की गयी थी। साथ ही, जुलाई और सितंबर से नवम्बर, 2012 तक बोर्ड से सूचना एकत्रित की गयी थी। इसके अतिरिक्त चार विभागों/ निर्माण इकाईयों यथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ प्र रा नि नि), मेडिकल कॉलेज यूनिट, हल्द्वानी, नगर निगम, देहरादून (न न दे), मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून (म दे वि प्रा) एवं उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (उ पे सं वि नि नि) से प्रश्नावली एवं लेखापरीक्षा ज्ञापनों के माध्यम से उपकर की वसूली के संबध में आँकड़े व सूचना एकत्र की गयी थी। इन विभागों/ निर्माण इकाईयों का यादृच्छिक (रैण्डम) नमूना विधि के आधार पर चयन किया गया था।

बोर्ड सचिव के उत्तरों को प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

2.4.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.7.1 नियोजन प्रक्रिया

राज्य सरकार, बी ओ सी डब्ल्यू अधिनियम में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य सलाहकार समिति, विशेषज्ञ समिति, राज्य वैलफेयर बोर्ड के गठन एवं नियम बनाने हेतु उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार पंजीकरण अधिकारी, मुख्य निरीक्षक, निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहकों की नियुक्ति के लिए भी उत्तरदायी थी। इसी प्रकार बोर्ड को देय धनराशि की उचित एवं समय से वसूली हेतु कल्याण निधि के गठन, देय राशि जमा करने हेतु नीति निर्धारण और लाभार्थी के रूप में भवन श्रमिकों के पंजीकरण के लिए बोर्ड, उत्तरदायी था। बोर्ड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी थी।

2.4.7.2 बी ओ सी डब्ल्यू अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नियमों का बनाया जाना

बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट में निहित प्राविधानों के अनुसार, राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने में परामर्श प्रदान करने हेतु भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में विशेष रूप से योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए एक या एक से अधिक विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकती है। राज्य सरकार ने नियम बनाने में सरकार को परामर्श देने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन (नवम्बर, 2003) किया। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन के डेढ़ वर्ष बाद दिनांक 25 जून 2005 द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा नियम बनाये गये।

2.4.7.3 बोर्ड का गठन

बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट में निहित प्राविधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार ऐसी तिथि से जैसे हो, अधिसूचना द्वारा, उसको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग एवं सौंपे गए कार्यों को करने हेतु "भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" के नाम से बोर्ड की नियुक्ति एवं गठन करेगा। यू के बी ओ सी डब्ल्यू रूल्स के नियम 251 के अनुसार बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नामित भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन सदस्य होंगें। नियुक्त सदस्यों में एक सदस्य महिला होगी। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि:

(क) उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड के गठन (नवंबर, 2000) के लगभग पाँच वर्ष बाद सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक वेलफेयर बोर्ड का गठन (अक्टूबर 2005) किया।

(ख) बोर्ड की संरचना बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट के प्राविधानों क अनुरूप थी। अध्यक्ष को छोड़ कर बोर्ड के दस सदस्य थे एवं बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष था।

(ग) 31 अगस्त, 2008 को बोर्ड के प्रथम कार्यकाल (तीन वर्ष) की समाप्ति के बाद बोर्ड निष्क्रिय रहा। उसके डेढ़ वर्ष के अंतराल के बाद 7 अप्रैल, 2010 को बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर बोर्ड के सचिव ने कहा (अक्टूबर 2012) कि मार्च 2007 से सितम्बर 2008 तक तथा दिसम्बर 2008 से बोर्ड के पुनर्गठन तक श्रम आयुक्त का पद रिक्त पड़े रहने के कारण बोर्ड

की बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका और परिणामतः जून 2009 में बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।

2.4.7.4 भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति का गठन

बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट की धारा 4 और यू के बी ओ सी डब्ल्यू रूल्स के नियम 10 में निहित प्राविधानों के अनुसार राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति का गठन किया। यद्यपि, समिति का कार्यकाल दिसंबर, 2009 को समाप्त हो गया था, इसके बाद सितंबर, 2012 तक कोई समिति अस्तित्व में नहीं थी।

इंगित किये जाने पर बोर्ड सचिव ने कहा कि (सितंबर 2012) कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक सलाहकार समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन को अग्रसारित (8 अप्रैल 2010) किया गया था जो सितंबर 2012 तक शासन में विचाराधीन था।

2.4.7.5 पंजीकरण अधिकारियों, निर्धारण अधिकारियों और उपकर संग्राहकों की नियुक्ति

यू के बी ओ सी डब्ल्यू रूल्स के नियम 263 के अनुसार बोर्ड सरकार की पूर्व सहमति से किसी सरकारी अधिकारी को, जो श्रम विभाग के सहायक श्रमायुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, एवं सरकार के किसी अन्य विभाग के ऐसे अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जैसा कि वह अधिनियम के अधीन बोर्ड कार्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

बोर्ड के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 2005 में उपश्रम आयुक्तों एवं सहायक श्रम आयुक्तों को पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था जबकि नवंबर 2005 में तहसीलदारों और उपजिला अधिकारियों को क्रमशः निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहक नियुक्त किया गया था। पंजीकरण अधिकारी, निर्धारण अधिकारी, उपकर संग्रहक और निरीक्षक अपने नियमित कार्य के अतिरिक्त इस कार्य को करते हैं।

बोर्ड सचिव ने कहा (जुलाई, 2012) कि अपने नियमित कार्य की अधिकता के कारण उपकर निर्धारण अधिकारियों एवं उपकर संग्रहकों द्वारा अतिरिक्त कार्य बी ओ सी डब्ल्यू उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सका।

2.4.7.6 बोर्ड की बैठकों का आयोजन न होना

बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट की धारा 20 और यू के बी ओ सी डब्ल्यू रूल्स के नियम 253 के अनुसार बोर्ड की बैठक सामान्यतः 2 माह में एक बार होगी। अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि अक्टूबर, 2005 से अक्टूबर 2009 तक कुल 24 बैठकों का आयोजन किया जाना था, किन्तु उक्त अवधि के दौरान मात्र एक बैठक का आयोजन किया गया। आगे, 25 मार्च 2006 में आयोजित बैठक के कार्यवृत्तों की जाँच में पाया गया था हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे बोर्ड का संगठनात्मक ढाँचा तैयार करना, बोर्ड के लिए अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोत्साहन की पेशकश पर स्वतंत्र इकाई को सन्निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य आवंटित करना, पर चर्चा की गई थी। इसके अनुपालन में श्रमिकों के पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम से तीन 'ग' श्रेणी कर्मियों की तैनाती के अतिरिक्त कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर बोर्ड सचिव ने उत्तर दिया (अक्टूबर, 2012) कि बोर्ड के सचिव के नामित न होने के कारण मार्च, 2006 से मई, 2010 तक नियमित बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका।

2.4.7.7 सन्निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण

यू के बी ओ सी डब्ल्यू रूल्स के नियम 266 एवं 267 के अनुसार बोर्ड को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों का पंजीयन करना था। श्रमिकों को लाभार्थी होने के लिए ₹ 20 प्रति माह की दर से अंशदान करना था। यदि कोई पंजीकृत सन्निर्माण श्रमिक एक वर्ष की कालावधि तक अंशदान का भुगतान नहीं करता तो वह निधि का लाभार्थी नहीं रहेगा। तथापि, बकाया की धनराशि का पुनर्भुगतान करने पर उसकी सदस्यता पुन: स्थापित हो सकेगी। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि:

(क) राज्य सरकार के पास राज्य के सन्निर्माण श्रमिकों की संख्या के कोई सांख्यिकीय आँकड़े नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वे (1999-2000) के अनुसार राज्य में विभिन्न निर्माण गतिविधियों जैसे जल विद्युत परियोजनाओं, बाँधों, पुलों एवं सड़कों के निर्माण इत्यादि में लगभग एक लाख श्रमिक नियोजित थे। यह देखा गया कि बोर्ड के गठन के पाँच वर्ष बाद सितंबर 2010 में प्रथम श्रमिक का पंजीकरण किया गया था और अगस्त 2012 तक कुल 4,201 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया था।
(ख) बोर्ड द्वारा वैध पंजीकृत सन्निर्माण श्रमिकों का डाटा-बेस नहीं रखा गया था। इसे इंगित किए जाने पर बोर्ड के सचिव ने उत्तर दिया (जुलाई व अक्टूबर 2012) कि वैध सन्निर्माण श्रमिकों के संबंध में पंजीकरण अधिकारियों से सूचना एकत्र की जा रही थी।
(ग) राज्य में लगे स्थानीय एवं प्रवासी भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के सर्वेक्षण हेतु राज्य सरकार/ बोर्ड द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर बोर्ड सचिव ने स्वीकार (जुलाई 2012) किया कि राज्य में लगे प्रवासी एवं स्थानीय श्रमिकों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

2.4.8 वित्तीय प्रबंधन

2.4.8.1 उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण निधि का गठन

राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रवर्तन (जून 2005) के तत्काल बाद बोर्ड द्वारा राज्य में बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट के कार्यान्वयन हेतु उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण निधि का गठन किया जाना था। बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की कुल लागत के 2 *प्रतिशत* से अनाधिक एवं 1 *प्रतिशत* से न कम की दर पर कल्याण उपकर के अधिरोपण एवं संग्रह के लिए प्राविधान है। अधिनियम के अनुसार बिलों के भुगतान के समय शासन और सार्वजनिक उपक्रमों के भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर स्रोत से उपकर की कटौती की जानी थी और एकत्र किए गए उपकर, बोर्ड को हस्तान्तरित किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि उक्त निधि के सृजन हेतु बोर्ड के गठन के लगभग तीन साल बाद 14 अगस्त 2008 को बैंक खाता खोला गया था।

2.4.8.2 प्राप्तियाँ एवं वास्तविक व्यय

वर्षवार निधियों की प्राप्ति एवं उसके सापेक्ष किए गए व्यय का विवरण **तालिका-2.4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका : 2.4.1 *(₹ करोड़ में)*

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ			व्यय	अन्तिम शेष
		एकत्रित उपकर	वार्षिक अभिदान/ पंजीकरण	अर्जित ब्याज		
2005-06	शून्य (31.10.2005 को)					
2006-07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2007-08	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2008-09	शून्य	1.67	शून्य	0.05	शून्य	1.72
2009-10	1.72	0.73	शून्य	0.10	शून्य	2.55
2010-11	2.55	3.33	0.005	0.18	0.02	6.05
2011-12	6.05	8.03	0.02	0.56	0.02	14.64

उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा राज्य और केंद्र सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया था। वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक प्राप्त कुल ₹ 14.68 करोड़ की धनराशि में सें बोर्ड द्वारा उपरोक्त अवधि में निधि की क्षीण उपयोगिता दर्शाते हुए कुल ₹ 4.28 लाख (0.29 *प्रतिशत*) व्यय किया गया।

2.4.8.3 वार्षिक लेखे तैयार न करना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में प्रावधानित है कि बोर्डः

(i) लेखों के वार्षिक विवरण, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करे और उसकी एक प्रति राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करे; और

(ii) ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसे निर्धारित है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य एवं केंद्र सरकार को अग्रसारित करेगा।

बोर्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि:

(क) बोर्ड द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा और तुलन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं बनाये जा रहे थे। बजाय इसके, आय एवं व्यय दर्शाते हुए एक पंजिका रखी गई थी।

(ख) वर्ष 2010-11 के लिए केवल एक वार्षिक रिपोर्ट बनाई गई थी और राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी किन्तु वह केंद्रीय सरकार को अग्रसारित नहीं की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर बोर्ड सचिव ने उत्तर दिया (सितंबर 2012) कि निर्धारित प्रपत्रों की अनुपलब्धता के कारण वार्षिक लेखे कार्यालय की साधारण पंजिका में बनाए गए थे और निर्धारित प्रपत्रों में वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

2.4.8.4 ₹ 14.68 करोड़ की धनराशि का अवरोधन

अगस्त 2008 से मार्च 2012 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण निधि में ब्याज सहित ₹ 14.68 करोड़ की धनराशि जमा की गई थी। बोर्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि कुल जमा धनराशि में से कल्याण निधि के गठन से अक्टूबर 2012 तक केवल 11 श्रमिकों के कल्याण हेतु ₹ 44333 की अल्प धनराशि का व्यय किया गया थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर बोर्ड सचिव ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2012) कि नियमों में निहित प्राविधान के अनुसार पात्र सन्निर्माण श्रमिक लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है। वर्ष 2011-12 में केवल एक श्रमिक ने चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन किया जिसे ₹ 200 की सहायता प्रदान की गई थी और वर्ष 2012-13 में नौ श्रमिकों को उनके आवेदन पर टूल्स किट के लिए ₹ 42333 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी और एक श्रमिक को शिक्षा हेतु ₹ 1800 का भुगतान किया गया था।

उत्तर, इन तथ्यों का संकेत देता है कि यद्यपि कल्याण बोर्ड और कल्याण निधि का गठन भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु किया गया था परन्तु बोर्ड द्वारा श्रमिकों के समय से पंजीकरण एवं उन्हें अभिप्रेत लाभ प्रदान करने हेतु गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे। श्रमिकों के बीच कल्याणकारी उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू शि सं) की गतिविधयों का प्रभावी संचालन नहीं किया गया जैसा कि इन तथ्यों से स्पष्ट है कि योजना के विज्ञापन हेतु क्रय किए गए पम्पलेट्स और अन्य मुद्रित सामग्री में से 63 *प्रतिशत* भण्डार में अवितरित पड़ी (अप्रैल 2012) थी।

इस प्रकार श्रमिकों के पंजीकरण में देरी और योजना का प्रचार न किए जाने से न केवल ₹ 14.68 करोड़ की धनराशि अवरूद्ध थी बल्कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी उपाय असफल रहे।

2.4.8.5 मुद्रण पर ₹ 2.68 लाख का अनियमित व्यय

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में प्राविधान किया गया है कि :

(i) समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके;
(ii) जब तक इन नियमों अथवा विशिष्ट आदेशों के अधीन छूट न दी जाए, समस्त अधिप्राप्तियाँ निविदा के माध्यम से की जाएगी; और
(iii) प्रत्येक अवसर पर ₹ 15 हजार से अधिक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विधिवत् गठित स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जाए।

बोर्ड के वर्ष 2010-11 और 2011-12 के व्यय देयकों की नमूना जाँच में देखा गया कि बोर्ड ने पम्पलेट्स, रसीद बुक और दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन पर बिना प्रतिस्पर्धात्मक या शासन से अनुमोदित दरों पर ₹ 2.68 लाख का व्यय किया।

इंगित किये जाने पर बोर्ड सचिव ने उत्तर दिया (जून 2012) कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में मुद्रण के संबंध में शासन से अनुमोदित दरों और वित्तीय नियमों का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।

2.4.8.6 ₹ 3.96 करोड़ के सांविधिक उपकर की वसूली न किया जाना/ कम वसूली

भारत सरकार ने भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु संसाधनों में संवृद्धि करने की दृष्टि से उपकर अधिनियम को अधिसूचित किया। इस अधिनियम के अनुसार निर्माण गतिविधियों पर लगे स्थापनों पर निर्माण लागत के 1 से 2 *प्रतिशत* उपकर का अधिरोपण एवं संग्रह किया जाना है। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उपकर प्राधिकारियों को उपकर भुगतान करने में की गई देरी 2 *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर अथवा उसके भाग से शास्तिक ब्याज को आकर्षित करेगी। उपरोक्त तारतम्य में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु किए गए अनुबंध की लागत का 1 *प्रतिशत* की दर पर श्रमिक कल्याण उपकर की कटौती कर बोर्ड को भुगतान करना था।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि बोर्ड के गठन से अगस्त 2012 तक कुल 489 निर्माण स्थापनों का पंजीकरण किया गया था, किन्तु राज्य में संचालित एवं अधिनियम के अंतर्गत समावेशित इकाईयों, जो उपकर भुगतान के लिए उत्तरदायी थी, का समग्र डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बोर्ड, अधिनियम के अंतर्गत समावेशित शत-प्रतिशत स्थापनाओं से उपकर संग्रह सुनिश्चित करने में असमर्थ था। इसके अतिरिक्त निर्माण अभिकरणों[22] से एकत्र की गई सूचना (अक्टूबर 2012) से पता चलता है कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 428.95 करोड़[23] के कार्यों का निष्पादन किया गया, परन्तु उन्होंने निष्पादित कराए गए कार्य की लागत के 1 *प्रतिशत* की निर्धारित दर से ₹ 3.96 करोड़ का उपकर बोर्ड को जमा नहीं किया जैसा कि **तालिका 2.4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका : 2.4.2 *(₹ लाख में)*

अभिकरण का नाम	2009-10				2010-11				2011-12			
	कार्य की लागत	एक *प्रतिशत* की दर से देय उपकर	जमा किया गया उपकर	कम वसूली	कार्य की लागत	एक *प्रतिशत* की दर से देय उपकर	जमा किया गया उपकर	कम वसूली	कार्य की लागत	एक *प्रतिशत* की दर से देय उपकर	जमा किया गया उपकर	कम वसूली
यू पी आर एन एन	1014.19	10.14	शून्य	10.14	707.46	7.07	शून्य	7.07	1137.58	11.38	शून्य	11.38
एन एन डी डी एन	464.18	4.64	शून्य	4.64	97.80	0.98	शून्य	0.98	3774.92	37.75	शून्य	37.75
यू पी एस वी एन एन	10280.45	102.80	शून्य	102.80	10366.42	103.66	8.20	95.46	8737.09	87.37	25.12	62.25
एम डी डी ए	272.15	2.72	शून्य	2.72	850.10	8.50	शून्य	8.50	5192.19	51.92	शून्य	51.92
योग	**12030.97**	**120.30**	शून्य	**120.30**	**12021.78**	**120.21**	**8.20**	**112.01**	**18841.78**	**188.42**	**25.12**	**163.30**

इसप्रकार, निर्माण स्थापनाओं से ₹ 3.96 करोड़[24] की कम वसूली की गई जो उपरोक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उपकर अधिकारियों को उपकर भुगतान के प्रेषण में की गई देरी के लिए 2 *प्रतिशत* प्रति माह की दर से दण्डात्मक ब्याज को आकर्षित करेगी।

---

[22] उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (उ प्र रा नि नि), मेडिकल कालेज यूनिट, हल्द्वानी, नगर निगम, देहरादून (न नि दे), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (उ पे स वि नि नि), मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून (म दे वि प्रा दे)।

[23] ₹ 12030.97 लाख (2009-10) + ₹ 12021.78 लाख (2010-11) + ₹ 18841.78 लाख (2011-12) = ₹ 42894.53 लाख; यानि ₹ 428.95 करोड़।

[24] ₹ 120.30 लाख (2009-10) + ₹ 112.01 लाख (2010-11) + ₹ 163.30 लाख (2011-12) = ₹ 395.61 लाख; यानि ₹ 3.96 करोड़।

2.4.8.7 कल्याणकारी उपायों का प्राविधान

बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट के प्राविधान के अनुसार कल्याणकारी योजनाएँ जैसे मातृत्व लाभ, पेंशन, भवन निर्माण अथवा क्रय हेतु अग्रिम, विभिन्न प्रकार से सक्षम श्रमिकों को पेंशन, टूल्स के लिए ऋण, अंतिम संस्कार हेतु भुगतान, मृत्यु लाभ, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा एवं विवाह हेतु वित्तीय सहायता आदि का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए था। बोर्ड के अभिलेखों की जाँच में पाया गया था कि बोर्ड द्वारा सन्निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। आगे यह पाया गया कि अगस्त 2012 तक 11 श्रमिकों को दिए गए ₹44333 के अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों पर कोई धनराशि व्यय नहीं की गई।

श्रमिकों को योजना के लाभों एवं उनको पंजीकृत किए जाने संबंध में जागरूकता पैदा करने हेतु अपनाई गई विधि के संबंध में पूछे जाने पर बोर्ड सचिव ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि निर्माण स्थलों पर शिविर आयोजनों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में विज्ञापन और पम्पलैट्स वितरण द्वारा योजना के लाभ हेतु सन्निर्माण श्रमिकों से संपर्क कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है।

बोर्ड का उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि बोर्ड के गठन के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी 11 श्रमिकों को प्रदान किए गए लाभ के अतिरिक्त किसी कल्याणकारी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

2.4.8.8 कार्यस्थलों का निरीक्षण

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक अप्रैल 2005 द्वारा उपश्रमायुक्तों/सहायक श्रमायुक्तों/श्रमप्रर्वतन अधिकारियों को निरीक्षक एवं श्रम आयुक्त को मुख्य निरीक्षक के रुप में नियुक्त किया। बोर्ड के गठन अक्टूबर 2005 से अप्रैल 2012 तक कुल 412 निरीक्षण किये गये एवं उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध 70 वाद दायर किये गये। इन वर्षों हेतु निरीक्षणों के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे तथापि, वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित 1,500 निरीक्षणों के लक्ष्य के सापेक्ष जून 2012 तक केवल 24 निरीक्षण किये गये।

2.4.8.9 मानव संसाधन प्रबन्धन

उधमसिंह नगर, हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के सहायक श्रमायुक्तों को पंजीकरण अधिकारी नामित किया गया था। पंजीकरण अधिकारियों को बोर्ड का कार्य उनके विभागीय कार्य के अतिरिक्त आवंटित किया गया था। अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि बोर्ड के गठन के पाँच वर्ष के अंतराल के बाद बोर्ड की बैठक (नवम्बर 2010) में स्टाफ की स्वीकृति का निर्णय लिया गया था। तदानुसार, शासन ने श्रमिकों के पंजीकरण हेतु 18 समूह 'ग' कर्मचारियों को आउटसोर्स से लिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण नियम से तीन कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था। कल्याण बोर्ड हेतु कोई नियमित स्टाफ नियुक्त नहीं था।

इसे सूचित करने पर बोर्ड सचिव ने स्वीकार किया (सितम्बर 2012) कि बोर्ड के लिए पृथक् रूप से कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया गया था।

2.4.8.10 अनुश्रवण तंत्र एवं आन्तरिक नियन्त्रण

राज्य स्तर पर, श्रम विभाग, बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट एवं राज्य विशेष नियमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था। तदानुसार, बी ओ सी डब्ल्यू एक्ट के कार्यान्वयन हेतु श्रमायुक्त को मुख्य निरीक्षक नामित किया गया था

एवं उपश्रमायुक्तों और सहायक श्रम आयुक्तों को स्थापनों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था। न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु अलग से शिकायत निवारण कक्ष एवं तंत्र स्थापित नहीं किया गया। शिकायत निवारण के उद्देश्य हेतु अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की गई थी। तथापि, शिकायत निवारण का कार्य श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार अनुश्रवण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त था।

2.4.9 निष्कर्ष

सरकार ने राज्य के गठन के लगभग पाँच वर्ष बाद बोर्ड का गठन किया। कल्याण बोर्ड के गठन से लगभग तीन वर्ष बाद कल्याण निधि स्थापित की गई। बोर्ड के गठन के पाँच वर्ष बाद पहले सन्निर्माण श्रमिक का पंजीकरण किया गया था, एवं बोर्ड के आरंभ होने से मात्र ग्यारह श्रमिक लाभान्वित हुए थे। बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे। राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी एवं स्थानीय श्रमिकों का सर्वे नहीं कराया गया था। अधिनियम के अंतर्गत समावेशित निर्माण स्थापनाओं, जो उपकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी थी, का डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था। अतैव बोर्ड राज्य में अधिनियम के अंतर्गत समावेशित निर्माण अभिकरणों से शत-प्रतिशत उपकर संग्रहण में असमर्थ था।

इस प्रकार बोर्ड, सन्निर्माण श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने की औपचारिकताओं की, पिछले सात वर्षों के दौरान, संरचना नहीं कर पाया, जिसके परिणामस्वरूप सन्निर्माण श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के लागू करने के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण उत्तराखण्ड शासन को संदर्भित (नवम्बर 2012) किया गया; उत्तर प्रतिक्षित था (जनवरी 2013)।

2.4.10 अनुशंसाएँ

सरकार विचार करें कि:

- राज्य में लगे प्रवासी एवं स्थानीय सन्निर्माण श्रमिकों का सर्वे कराकर तदानुसार एक डाटाबेस तैयार किया जाए।
- शत-प्रतिशत उपकर के संग्रह को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के अंतर्गत समावेशित स्थापनाओं का डाटाबेस तैयार करने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।
- व्यापक प्रचार गतिविधियों के माध्यम से श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- प्राथमिकता के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाए।
- अधिनियम के उचित कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण पद्धति सुदृढ़ की जाए।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

2.5 समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई सी डी एस)

2.5.1 परिचय

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई सी डी एस) कार्यक्रम, वर्ष 1978-79 में उत्तराखण्ड (तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा) के तीन चयनित विकास खण्डों[25] में, सेवाओं का पैकेज, जिसमें अनुपूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवाएँ, अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा और स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(क) शून्य से छः वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना;
(ख) बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए नीव रखना;
(ग) बच्चों की मृत्युदर, रूग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना;
(घ) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति एवं क्रियान्वयन का प्रभावी समन्वय हासिल करना; और
(च) उचित पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य व पोषण की आवश्यकता की देखभाल हेतु माँ की क्षमता को बढ़ाना।

वर्तमान में यह कार्यक्रम पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है और लेखापरीक्षा जाँच में इस योजना को सम्मिलित करने हेतु विशेष ध्यान दिया गया था।

2.5.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू ई सी डी) राज्य में योजना के समग्र प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। निदेशक, डब्ल्यू ई सी डी इस योजना के क्रियान्वयन अधिकारी हैं एवं सभी 105 आई सी डी एस परियोजनाओं को जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों (डी पी ओ) व विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सी डी पी ओ) के माध्यम से कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं जो कि आगे पर्यवेक्षकों द्वारा सहायतित होते हैं। आई सी डी एस सेवाएँ आँगनबाड़ी केन्द्रों (ए डब्ल्यू सी) के माध्यम से मानदेय के आधार पर कार्यरत आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों (ए डब्ल्यू डब्ल्यू) व आँगनबाड़ी सहायिकाओं (ए डब्ल्यू एच) के द्वारा प्रदान की जाती है।

2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्याः

- योजना के क्रियान्वयन के लिए नियोजन, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त था;
- निधियाँ पर्याप्त थीं एवं उनका, योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इष्टतम उपयोग किया गया था;
- योजना के अन्तर्गत प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त ढ़ाँचागत सुविधाएं उपलब्ध थी;

[25] चकराता, धारचूला एवं कीर्तिनगर विकास खण्ड।

- इस योजना के तहत् एकमुश्त सेवाओं को प्रभावी ढंग से लाभार्थियों को प्रदान किया गया था; और
- अनुश्रवण एवं मूल्याँकन की प्रणाली अस्तित्व में थी तथा प्रभावी थी।

2.5.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

- भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देशों/ आदेशों और योजना के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन में तंत्र की भागीदारी।
- विहित मापदण्डों के अनुसार इस योजना के लिए निर्धारित किये गए परिणाम एवं निष्पादन के मानक।
- राज्य सरकार द्वारा इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों को किस सीमा तक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी थीं।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण तंत्र एवं मूल्याँकन के पालन के परिणाम।

2.5.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा पद्धति एवं नमूना चयन

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यू ई सी डी) पर विषयक लेखापरीक्षा अप्रैल 2012 से अगस्त 2012 के मध्य आईसीडीएस पर विशेष ध्यान देते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि को समावेशित करते हुए सम्पादित किया गया। लेखापरीक्षा में निदेशालय (आई सी डी एस) एवं पाँच जिला[26] कार्यक्रम अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इसके अतिरिक्त 22 आँगनबाड़ी केन्द्रों का लेखापरीक्षा दल एवं विभाग के प्रतिनिधियों/ अधिकारियों द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया।

2.5.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.5.6.1 वित्तीय स्थिति

योजना पर विभाग द्वारा राज्य सरकार के बजट से, भारत सरकार द्वारा तय किये गये मानदण्डों के अनुसार, व्यय किया जाता है। इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय विवरण (एस ओ ई)/ उपभोग प्रमाण पत्र (यू सी) के आधार पर भारत सरकार द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (एस एन पी) के अतिरिक्त अवमुक्त धनराशि एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय का वर्षवार विवरण नीचे **तालिका-2.5.1** में दिया गया है:

तालिका-2.5.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	केन्द्र का प्रारंभिक अवशेष	केन्द्र से अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध केन्द्र बजट (2+3)	केन्द्र/राज्य को सम्मिलित करते हुये कुल बजट	व्यय			अंतिम अवशेष	
					केन्द्र (90%)	राज्य (10%)	कुल	केन्द्र (4-6)	राज्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009-10	13.08	35.96	49.04	61.07	46.54	5.17	51.71	2.50	-
2010-11	2.50	37.63	40.13	82.72	50.82	5.64	56.46	(-) 10.69	-
2011-12	(-) 10.69	55.63	44.94	127.25	89.98	8.00	97.98	(-) 45.04	-
योग		**129.22**	**134.11**	**271.04**	**187.34**	**18.81**	**206.15**		

स्रोतः निदेशालय से संग्रहित सूचना।

[26] अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी एवं ऊधम सिंह नगर।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ₹ 45.04 करोड़ की धनराशि विभाग द्वारा समय से व्यय विवरण प्रस्तुत न किये जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना शेष है। इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (सितम्बर 2012) कि स्टॉफ की कमी के कारण व्यय विवरण समय पर नहीं भेजे जा सके।

पुनश्च, अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि एवं उनके सापेक्ष विभाग द्वारा किये गये व्यय का 2009-10 से 2011-12 तक वर्षवार विवरण नीचे **तालिका-2.5.2** में दिया गया है:

तालिका-2.5.2 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	केन्द्र का प्रारंभिक अवशेष	केन्द्र से अवमुक्त धनराशि	कुल उपलब्ध केन्द्र बजट (2+3)	केन्द्रांश को सम्मिलित करते हुये कुल बजट	व्यय			अंतिम अवशेष	
					केन्द्र (50%)	राज्य (50%)	कुल	केन्द्र (4-6)	राज्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2009-10	6.71	18.92	25.63	65.70	18.96	18.96	37.92	6.67	-
2010-11	6.67	13.04	19.71	39.09	14.80	14.80	29.60	4.91	-
2011-12	4.91	15.35	20.26	50.07	20.51	20.51	41.02	(-) 0.25	-
योग		**47.31**	**65.60**	**154.86**	**54.27**	**54.27**	**108.54**		

स्रोतः निदेशालय से संग्रहित सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः ₹ 6.67 करोड़ एवं ₹ 4.91 करोड़ की बचत थी। एसएनपी से संबंधित विस्तृत लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा प्रस्तर 2.5.7.1 में की गयी है।

2.5.6.2 नियोजन एवं कार्यक्रम प्रबंधन

भारत सरकार के निर्देशानुसार, निदेशालय आई सी डी एस राज्य स्तर पर वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (ए पी आई पी) बनाने हेतु उत्तरदायी था एवं योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला/ विकास खण्ड स्तर के अधिकारी (डी पी ओ/ सी डी पी ओ) अपनी वार्षिक कार्य योजना (ए ए पी) बनाने हेतु उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर निदेशालय द्वारा वर्ष 2011-12 के अलावा ए पी आई पी तैयार नहीं किया गया था एवं जिला/ विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा इस अवधि में कभी भी ए ए पी तैयार नहीं किया गया था। इस ओर इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि ए पी आई पी के अभाव में योजनाओं का भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार विनियमन किया गया।

2.5.7 आँगनबाड़ी सेवाओं का पैकेज

आई सी डी एस एकीकृत सेवाएँ प्रदान करता है जिसमें (क) अनुपूरक पोषाहार, (ख) टीकाकरण, (ग) स्वास्थ्य जाँच, (घ) संदर्भित सेवाएँ, (ङ) अनौपचारिक स्कूल-पूर्व-शिक्षा और (च) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित हैं। आँगनबाड़ी कार्यकत्री टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जाँच के लिए लक्षित समूहों को चिन्हित करने में सहायक नर्स मिडवाइफ (ए एन एम) (स्वास्थ्य विभाग) के साथ सीमित भूमिका निभाती है और इसके लिए अभिलेखों

का रखरखाव स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त संदर्भित सेवाओं से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव आँगनबाड़ी केन्द्रों पर नहीं किया गया था जिसके सम्बन्ध में प्रस्तर 2.5.9.5 में विस्तार से चर्चा की गयी है। उप-योजनावार अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जाँच एवं स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नवत् हैः

2.5.7.1 अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार लाभार्थियों[27] को अनुपूरक पोषाहार एक वर्ष में 300 दिन उपलब्ध करवाया जाना था। योजना का उद्देश्य सभी लाभार्थियों का चयन करके योजना को सार्वभौम बनाना एवं कुपोषण की रोकथाम करना था। अनुपूरक पोषाहार आई सी डी एस विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वितरित किया गया था। यह आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से (क) 6 माह से 3 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के लिए टेक होम राशन (टीएचआर) और (ख) तीन से छः वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए पके पकाये भोजन के रूप में प्रदान किया जाना था।

(i) टेक होम राशन

निदेशालय आई सी डी एस, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि पूर्वोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू एफ पी) के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर कर टीएचआर का वितरण किया जा रहा था। उपरोक्त प्रयोजन के लिए डब्ल्यू एफ पी को ₹ 50.33 करोड़[28] का अग्रिम प्रदान किया गया था। टी एच आर की आवश्यकता वाले लाभार्थियों की संख्या तथा उसके सापेक्ष आपूर्ति का विवरण नीचे **तालिका-2.5.3** में दिया गया हैः

तालिका-2.5.3

लाभार्थी	2010-11					2011-12				
	लाभार्थियोंकी संख्या		वांछित टी एच आर	आपूर्त टी एच आर	कमी प्रतिशत में	लाभार्थियों की संख्या		वांछित टी एच आर	आपूर्त टी एच आर	टी एच आर में कमी *प्रतिशत में*
	सर्वे के अनुसार	पंजीकरण के अनुसार				सर्वे के अनुसार	पंजीकरण के अनुसार			
बच्चे 6 माह-3 वर्ष (140 ग्राम की दर पर)	547521	514212	30432 एमटी[29]	10320 एमटी	66	572405	555191	32784 एमटी[30]	14239 एमटी	57
गर्भवती माताएँ (175 ग्राम की दर पर)	72863	70918				78167	76828			
धात्री माताएँ (175 ग्राम की दर पर)	89704	88811				98981	97773			
अतिकुपोषित बच्चे (280 ग्राम की दर पर)	5349	5349				3562	3562			
	715437	679290				753115	733354			

स्रोतः निदेशालय से संग्रहित सूचना।

[27] छः वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे, सभी गर्भवती एवं धात्री महिलायें।

[28] 2010-11: ₹ 32.33 करोड़ एवं 2011-12: ₹ 18.00 करोड़।

[29] 30432 एमटी={514212*@140ग्रा+(70918+88811) *@175ग्रा+5349*@280ग्रा}*300 दिन।

[30] 32784 एमटी={555191*@140ग्रा+(76828+97773)*@175ग्रा+3562*@280ग्रा}*300 दिन।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि विभाग और विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू एफ पी) के बीच अनुबंध न किये जाने के कारण वर्ष 2009-10 में टी एच आर वितरित नहीं किया गया था। 2010-11 से 2011-12 मध्य टी एच आर की आपूर्ति में भारी कमी (50 *प्रतिशत* से अधिक) पायी गयी थी जैसा कि उपरोक्त तालिका (57 *प्रतिशत* से 66 *प्रतिशत*) में देखा जा सकता है।

वर्ष 2011-12 में विभाग द्वारा राज्य में धन की उपलब्धता के बावजूद अनुपूरक पोषाहार, निर्धारित मानदण्ड वर्ष में 300 दिन के सापेक्ष 124 दिन के लिए ही आपूर्ति की गयी थी जबकि चयनित जिलों में टी एच आर 110 से 183 दिन के बीच **(परिशिष्ट-2.11)** वितरित किया गया था। चयनित जिलों की 38 परियोजनाओं[31] में यह भी देखा गया कि जनवरी 2012 में टी एच आर का वितरण ही नहीं हुआ था क्योंकि निदेशालय द्वारा समय पर समझौता ज्ञापन न किये जाने के कारण डब्ल्यू एफ पी के द्वारा टी एच आर की आपूर्ति नहीं की गयी थी।

इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (सितम्बर 2012) कि पोषाहार कक्ष के गठित न होने, कर्मचारियों की कमी एवं निर्णय लेने में विलम्ब के कारण से पोषाहार का नियमित वितरण नहीं किया जा सका। विभाग का उत्तर टीएचआर के वितरण की व्यवस्था करने में इसकी असमर्थता को दर्शाता है क्योंकि अनुपूरक पोषाहार के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र 58 *प्रतिशत* से 82 *प्रतिशत* तक ही धनराशि का उपयोग किया गया था और विभाग सभी लाभार्थियों को टी एच आर उपलब्ध कराने में असफल रहा था जैसा कि उपरोक्त **तालिका-2.5.3** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, योजना के उद्देश्यों पर ₹ 50.33 करोड़[32] व्यय करने के बावजूद भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि सर्वे के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत नहीं किया गया एवं वे लाभ प्राप्त करने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्र पर नहीं आये जिससे योजना के सार्वभौमीकरण के अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, 2010-12 की अवधि में 50,523 बच्चे (शून्य से तीन वर्ष), 3,284 गर्भवती माताएँ और 2,101 धात्री माताएँ इस योजना के लाभ से पूरी तरह वंचित रहे।

(ii) पका पकाया भोजन

शासनादेश (मई 2008) के अनुसार, आँगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति[33] के माध्यम से तीन से छः वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पका पकाया भोजन प्रदान किया जाना था। विभाग ने तीन से छः वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड से सहमति लेने के बाद इसके लिए मानक एवं मेनू तय किया था।

चयनित जिलों में वर्ष 2011-12 के लिए पका पकाया भोजन कार्यक्रम के लाभार्थियों का ब्यौरा नीचे **तालिका-2.5.4** में दर्शाया गया है:

---

[31] पिथौरागढ़-5, अल्मोड़ा-5, नैनीताल-9, ऊधम सिंह नगर-10 एवं टिहरी-9।

[32] 2010-11: ₹ 32.33 करोड़ और 2011-12: ₹ 18.00 करोड़।

[33] एक समिति जिसका प्रमुख अध्यक्ष, ए डब्ल्यू डब्ल्यू/ए डब्ल्यू एच सचिव एवं लाभार्थियों के प्रत्येक वर्ग का एक सदस्य आँगनबाड़ी केन्द्र पर पकापकाया भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे।

तलिका-2.5.4 *(₹ करोड़ में)*

जिलों के नाम	सर्वे के अनुसार लाभार्थियों की संख्या	एक वर्ष में पंजीकृत	वांछित धनराशि*	नामांकित	वांछित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	दिनों की संख्या
पिथौरागढ़	**572929**	451000	4.51	120877	1.21	0.60	149
अल्मोड़ा	**728011**	604974	6.05	193204	1.93	0.66	103
नैनीताल	**501060**	227243	2.27	115074	1.15	0.42	110
ऊ सिं नगर	**992693**	531975	5.32	186837	1.87	1.98	318
टिहरी	**390023**	304365	3.04	168297	1.68	0.56	100
योग	**3184716**	**2119557**	**21.19**	**784289**	**7.84**	**4.22**	

स्रोतः चयनित जिलों से संग्रहित सूचना।

****₹ 4 प्रति लाभार्थी प्रति दिन एक माह में 25 दिन के लिए।***

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पाँच चयनित जिलों में सर्वेक्षित आँकड़े 31,84,716 बच्चों (2011-12) के सापेक्ष केवल 21,19,557 बच्चे (67 *प्रतिशत*) पंजीकृत किये गये थे। 21,19,557 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष केवल 7,84,289 बच्चे (37 *प्रतिशत*) आँगनबाड़ी केन्द्रों पर नामांकित किये गये थे। आगे, विभाग द्वारा नामांकित बच्चों के लिए ₹ 7.84 करोड़ (784289* ₹ 4 की दर पर *25 दिन) की आवश्यकता के सापेक्ष मात्र ₹ 4.22 करोड़ (54 *प्रतिशत*) का ही आबंटन किया गया था। यह भी देखा गया कि 300 दिनों के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सका तथा यह ऊधम सिंह नगर को छोड़कर, जहाँ वर्ष 2011-12 के दौरान निर्धारित मानक 300 दिनों के सापेक्ष 318 दिन पका-पकाया भोजन प्रदान किया गया, वर्ष के दौरान 100 दिनों तक रह गया।

पुनः जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा दल द्वारा तीन जिलों नैनीताल, टिहरी व ऊधम सिंह नगर के 22 आँगनबाड़ी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया और पाया गया कि (क) आँगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति की बैठकें मानकों के अनुसार (प्रति माह एक बैठक) आयोजित नहीं की जा रही थी; (ख) टिहरी जिले के आठ आँगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित 100 बच्चों के लिए आवश्यक (₹ 120000) धनराशि के सापेक्ष कम धनराशि (₹ 44890) अवमुक्त किया गया था। इस धनराशि (₹ 44890) से आठ आँगनबाड़ी केन्द्रों के मात्र 38 बच्चों को ही खिलाया जा सकता था और (ग) टिहरी जिले के चार आँगनबाड़ी केन्द्रों[34] पर धन की अनुपलब्धता के कारण पका पकाया भोजन आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा दो से ग्यारह माह तक निजी संसाधनों से प्रदान किया गया था जोकि बाद में धन की उपलब्धता पर प्रतिपूर्ति किया गया था जबकि पाँच आँगनबाड़ी केन्द्रों[35] में पका पकाया भोजन (एक से छः माह) नहीं दिया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग द्वारा बताया गया (सितम्बर 2012) कि स्टॉफ की कमी एवं निर्णय लेने में विलम्ब होने के कारण जिलों को धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा बताया गया (अगस्त 2012) कि पका पकाया भोजन उपलब्ध बजट के अनुसार प्रदान किया गया। भौतिक सत्यापन के समय डीपीओ द्वारा यह भी कहा गया कि महंगाई के कारण उपर्युक्त मानकों के अनुसार प्रति लाभार्थी ₹ 4 की दर पर पका पकाया भोजन उपलब्ध कराना संभव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसके लिए अवमुक्त बजट, कुल आवश्यक बजट का मात्र 33 से 106

[34] बाल्मिकी बस्ती, ढ़ालवाला-2, सन्दाना एवं सेमा।

[35] बखदियाना, संदाना, सेमा, कुनीर एवं किरगनी।

प्रतिशत था एवं न तो परियोजना स्तर से और न ही जनपद स्तर से निदेशालय के साथ वास्तविक स्थिति से अवगत कराने हेतु कोई माँग/ पत्राचार किया गया था। फलस्वरूप, विभाग द्वारा मानक के अनुसार पका पकाया भोजन प्रदान नहीं किया जा रहा था जो योजना के अभिप्रेत उद्देश्यों की विफलता का द्योतक था।

2.5.7.2 स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ

स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवाएँ, पोषण और स्वास्थ्य व स्कूल-पूर्व शिक्षा शामिल है। लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित पाया गया:

(i) स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल में कमियाँ

बच्चों एवं माताओं की जाँच हेतु चिकित्साधिकारी (एम ओ) एवं सहायक नर्स मिडवाइफ (ए एन एम) द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर नियमित भ्रमण करना आईसीडीएस के अन्तर्गत स्वास्थ्य देखभाल तंत्र का एक हिस्सा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमओ द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भ्रमण बहुत कम था क्योंकि 22 आँगनबाड़ी केन्द्रों के भौतिक सत्यापन में चिकित्साधिकारी द्वारा वर्ष 2011-12 में मात्र नौ आँगनबाड़ी केन्द्रों (41 *प्रतिशत*) का भ्रमण किया गया था। ए एन एम द्वारा केवल टीकाकरण के दौरान आँगनबाड़ी केन्द्र का दौरा किया गया। राज्य में कुल 17,826 कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों में से मात्र 11,607 (65 *प्रतिशत*) आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शिशु का भार मापने हेतु तराजू उपलब्ध कराया गया था। चयनित जिलों में कुल 6,928 आँगनबाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष सम्बन्धित आँकड़ा मात्र 4,178 (60 *प्रतिशत*) था।

पुनश्च, आई सी डी एस मानक के अनुसार प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक वर्ष ₹ 600 कीमत की एक मेडिसिन किट प्रदान की जानी थी। वर्षवार बजट आबंटन, कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं चिकित्सा किट की आपूर्ति नीचे **तालिका-2.5.5** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.5.5

वर्ष	बजट आबंटन (₹ करोड़ में)	व्यय	संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र	वांछित मेडिसिन किट	आपूर्ति	कमी
2009-10	1.56	शून्य	10,792	10,792	शून्य	10,792
2010-11	3.68	1.32	15,441	15,441	10,840	4,601
2011-12	2.02	1.92	17,826	17,826	12,926	4,900
योग	**7.26**	**3.24**	**44,059**	**44,059**	**23,766**	**20,293 (46%)**

स्रोतः निदेशालय से एकत्र सूचना।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 में इस हेतु आवंटित बजट ₹ 1.56 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद भी 10,792 मेडिसिन किट का क्रय नहीं किया गया था। जबकि विभाग ने 2010-11 व 2011-12 में आवंटित ₹ 5.70 करोड़ के बावजूद आवश्यक 33,267 मेडिसिन किट के सापेक्ष मात्र 23,766 (71 *प्रतिशत*) मेडिसिन किटों का क्रय किया।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत में धनराशि प्राप्त होने के कारण टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी एवं मेडिसिन किटों का क्रय नहीं किया जा सका। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में मेडिसिन किटों की कमी को स्वास्थ्य विभाग की सहायता से पूरा किया गया।

(ii) अनौपचारिक स्कूल-पूर्व शिक्षा

तीन से छः वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आँगनबाड़ी केन्द्रों पर अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जानी थी ताकि उनको नियमित प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की तैयारी के लिए सीखने की अभिवृत्ति, भावनात्मक मूल्य एवं मानसिक तैयारी के लिए विकसित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए स्कूल किट सभी कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों को प्रदान किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मानकों के अनुसार, विभाग को वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान सभी 44,059 कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्रों (2009-10 में 10,792 ए डब्ल्यू सी, 2010-11 में 15,441 ए डब्ल्यू सी व 2011-12 में 17,826 ए डब्ल्यू सी) को स्कूल पूर्व किट का क्रय व आपूर्ति की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने केवल 36,543 स्कूल पूर्व किटों (83 *प्रतिशत*) का क्रय व आपूर्ति की एवं ₹ 75.16 लाख की लागत की शेष 7,516 स्कूल पूर्व किटों (17 *प्रतिशत*) की आँगनबाड़ी केन्द्रों को आपूर्ति नहीं की गयी। पुनश्च, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया कि आँगनबाड़ी केन्द्र प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, शिक्षण सामग्री की कमी एवं पर्याप्त खेल उपकरणों की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं से ग्रसित थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि निविदायें उस समय (2009-12) संचालित हो रहे आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या के आधार पर ही आमंत्रित की गयी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस अवधि में 44,059 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित थे जबकि स्कूल पूर्व किट सिर्फ 36,543 आँगनबाड़ी केन्द्रों को ही उपलब्ध कराये गये। इस प्रकार खरीद के समय समुचित कार्ययोजना के अभाव में विभाग सभी संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों को प्री-स्कूल किट उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा।

2.5.8 आँगनबाड़ी

छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती या धात्री महिलाओं एवं किशोरियों को दी जाने वाली आई सी डी एस की सभी सेवाएँ आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आँगनबाड़ी केन्द्र 300 या उससे अधिक की जनसंख्या के लिए संचालित किये जाते हैं।

2.5.8.1 अकार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्र

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 23,159 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से राज्य सरकार द्वारा 20,067 आँगनबाड़ी केन्द्र चिन्हित किये गये जिनके सापेक्ष अप्रैल 2012 तक 17,826 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हो रहे थे। इस प्रकार कुल 2,241 आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं किये जा सके जिसके लिए विभाग द्वारा बताया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्र, ए डब्ल्यू डब्ल्यू/ ए डब्ल्यू एच/ मिनि आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों (एम ए डब्ल्यू डब्ल्यू) की लम्बी नियुक्ति प्रक्रिया एवं स्टॉफ की कमी के कारण स्थापित नहीं किये जा सके।

2.5.9 क्षमता विकास

विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ, जैसे- भवन, पर्याप्त मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था। आई सी डी एस के प्रबंधन की उपरोक्त कमियों का वर्णन निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया हैः

- राज्य के सभी 10 जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय कम्प्यूटरों एवं प्रिंटरों से सुसज्जित थे लेकिन खण्ड स्तर पर 105 सी डी पी ओ कार्यालयों में से केवल 51 (49 *प्रतिशत*) कार्यालयों में ही यह सुविधा उपलब्ध थी।
- इसी प्रकार चालन योग्य वाहन की आवश्यकता, विशेष रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुश्रवण हेतु, अत्यधिक है। वाहन सुविधा राज्य में निदेशालय एवं तेरह में से छः जिला केन्द्रों में उपलब्ध थी जबकि 105 सी डी पी ओ कार्यालयों में से सिर्फ 38 कार्यालयों में ही वाहन सुविधा उपलब्ध थी।
- अनेक संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों के अपने भवन नहीं थे एवं यदि कुछ के अपने भवन या कमरे थे भी तो यह आपूर्ति की गयी सामग्री एवं बच्चों, दोनों के लिए बहुत छोटे थे। राज्य में संचालित 17,826 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से (प्रस्तर 2.5.8.1 का संदर्भ लें) केवल 1,378 आँगनबाड़ी केन्द्रों (आठ *प्रतिशत*) के अपने विभागीय भवन थे, 6,113 आँगनबाड़ी केन्द्र (34 *प्रतिशत*) किराये के भवन में एवं 10,337 आँगनबाड़ी केन्द्र (58 *प्रतिशत*) अन्य सरकारी कार्यालयों के भवनों में संचालित हो रहे थे। इसी प्रकार कुल संचालित 17,826 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से शौचालय सुविधा सिर्फ 7,732 केन्द्रों (43 *प्रतिशत*) में उपलब्ध थी एवं पीने के पानी की सुविधा सिर्फ 5,720 आँगनबाड़ी केन्द्रों (32 *प्रतिशत*) में ही उपलब्ध थी। इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये जबाब दिया (नवम्बर 2012) कि ये सुविधाएँ जैसे कि कम्प्यूटर, वाहन, भवन आदि शासन से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही उपलब्ध करायी जायेंगी। इस प्रकार आवश्यक उपकरणों/बुनियादी सुविधाओं के अभाव में योजना का सुचारु संचालन बाधित था।



आँगनबाड़ी केन्द, वाल्मिकी बस्ती, नरेन्द्रनगर


आँगनबाड़ी केन्द, बखरियाना, नरेन्द्रनगर

2.5.9.1 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की धीमी प्रगति

आँगनबाड़ी केन्द्र के प्रभावी संचालन एवं योजना के अन्तर्गत छः प्रकार की सेवाएँ समुचित रूप से प्रदान करने हेतु मूलभूत ढ़ाँचागत सुविधा के रूप में अच्छा भवन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था। विभाग द्वारा तीन जिलों में आवश्यक 508 आँगनबाड़ी केन्द्रों (पिथौरागढ़-95, अल्मोड़ा-382 एवं टिहरी-31) के सापेक्ष अद्यतन 81 केन्द्रों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सभी कार्य अपने स्वीकृति तिथि के दो माह के भीतर पूर्ण किये जाने थे। कार्यों का जिलेवार विवरण नीचे **तालिका-2.5.6** में दिया गया हैः

तालिका- 2.5.6 *(₹ लाख में)*

जिलों के नाम	स्वीकृति वर्ष	आँगनबाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या	निर्माण एजेंसी	निर्माण लागत	अवमुक्त धनराशि	अवशेष	लेखापरीक्षा तिथि तक स्थिति
पिथौरागढ़	2008-09	03	आर ई एस	6.00	4.80	1.20	अपूर्ण (3)
अल्मोड़ा	2005-06	48	ग्राम पंचायत	12.00 (6 ए डब्ल्यू सी)	9.50 (6 ए डब्ल्यू सी)	2.50	अपूर्ण (6)
टिहरी	2008-09	04	आर ई एस	8.00	8.00	0.00	अपूर्ण (4)
	2009-10	08	बी डी ओ	24.00	12.00	12.00	अपूर्ण (6)
	2011-12	18	आर ई एस	72.00	36.00	36.00	अपूर्ण (18)
योग		**81**		**122.00**	**70.30**	**51.70**	**37**

स्रोतः डीपीओ से प्राप्त सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्वीकृत 81 कार्यों में से केवल 44 कार्य (54 *प्रतिशत*) ही पूर्ण हो सके एवं शेष 37 कार्य (46 *प्रतिशत*) निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किये जा सके थे एवं उनमें सात वर्षों तक की अवधि का विलम्ब था। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्यों में विलम्ब का मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता एवं कार्यदायी संस्था के साथ एम ओ यू न होना था। इस प्रकार, इन ढ़ाँचागत सुविधाओं के अभाव में, ए डब्ल्यू सी को उपरोक्त वर्णित मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा जैसा कि ऊपर प्रस्तर 2.5.9 में इंगित किया गया है।

2.5.9.2 मानव संसाधन की कमी

विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डी पी ओ/ सी डी पी ओ/ पर्यवेक्षकों द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों का अनुश्रवण/ पर्यवेक्षण, सांख्यिकी सहायकों द्वारा आँकड़ों का संकलन एवं ए डब्ल्यू डब्ल्यू/ ए डब्ल्यू एच/ एम ए डब्ल्यू डब्ल्यू द्वारा केन्द्रों पर अग्रगामी कार्य किया जाना था। अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया कि निदेशालय, जिला एवं विकास खण्ड (परियोजना) स्तर पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की भारी कमी थी। विभाग में अप्रैल 2012 को कर्मचारियों की स्थिति नीचे **तालिका-2.5.7** में दर्शायी गयी हैः

तालिका-2.5.7

पदनाम	स्तर	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद	कमी % में
सांख्यिकी सहायक	**जिला**	**52**	**.**	**52**	**100**
डी पी ओ	**तदैव**	**10**	**05**	**05**	**50**
सी डी पी ओ	विकास खण्ड	105	62	43	41
पर्यवेक्षक	तदैव	597	366	231	39
डी ई ओ	**जिला/ विकास खण्ड**	**07**	**01**	**06**	**86**
वरिष्ठ सहायक	जिला	34	26	08	24
अवर सहायक	**तदैव**	**57**	**28**	**29**	**51**
कनिष्ठ सहायक	**तदैव**	**62**	**24**	**38**	**61**
ए डब्ल्यू डब्ल्यू	ए डब्ल्यू सी	14947	13444	1503	10
ए डब्ल्यू एच	तदैव	14947	12453	2494	17
एम ए डब्ल्यू डब्ल्यू	**तदैव**	**5120**	**3823**	**1297**	**25**

स्रोतः निदेशालय व डी पी ओ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

स्पष्टतया, विभाग नवम्बर 2000 से पर्याप्त मानव संसाधन के बिना कार्य कर रहा था। योजना के सुचारू रूप से कार्य करने हेतु महत्वपूर्ण पद, जैसे सांख्यिकी सहायक (100 *प्रतिशत*), डी पी ओ (50 *प्रतिशत*), सी डी पी ओ (41 *प्रतिशत*), पर्यवेक्षक (39 *प्रतिशत*), डी ई ओ (86 *प्रतिशत*) एवं एम ए डब्ल्यू डब्ल्यू (25 *प्रतिशत*) भी, रिक्त थे। परिणामस्वरूप, रिक्त पदों का सम्पूर्ण कार्यभार निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों पर है। सुव्यवस्थित संगठनात्मक तंत्र का अभाव विभाग की व्यवस्था सम्बन्धी खामियों को दर्शाता है तथा उसके दक्षता पूर्वक कार्य संचालन को प्रभावित करता है। इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2012) कि स्टॉफ की भर्ती प्रक्रिया गतिमान है।

2.5.9.3 प्रशिक्षण

आई सी डी एस योजना में प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि योजना के अन्तर्गत सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार व कार्ययोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्यतया अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (पर्यवेक्षक, ए डब्ल्यू डब्ल्यू, ए डब्ल्यू एच व एम ए डब्ल्यू डब्ल्यू) की दक्षता पर निर्भर करता है। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को तीन प्रकार के नियमित प्रशिक्षण दिये जाते हैः (i) इण्डक्शन प्रशिक्षण (आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रारंभिक कार्य सौंपे जाने/ नियुक्ति पर); (ii) जॉब/ओरिएनटेशन प्रशिक्षण (सेवाकाल में एक बार); और (iii) रिफ्रेशर प्रशिक्षण (सेवा में, प्रत्येक दो साल में एक बार)।

लेखा परीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए राज्य में सात आँगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र[36](ए डब्ल्यू टी सी) संचालित थे। पर्यवेक्षकों एवं ए डब्ल्यू टी सी के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु राज्य में कोई मध्यम स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं थे। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 2009-10 से 2011-12 की अवधि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया **(परिशिष्ट-2.12)**, किन्तु राज्य की स्थापना से अब तक मध्यम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। यह भी पाया गया था कि सांख्यिकीय सहायक के पदों के रिक्त होने के कारण जिला/खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण से संबंधित आँकड़ों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

वर्ष 2011-12 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जिले वार विवरण नीचे **तालिका-2.5.8** में दिया गया हैः

तलिका-2.5.8

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	जिले जिनमें प्रशिक्षण दिया गया	कलेण्डर के अनुसार कुल प्रशिक्षुओं की संख्या (लक्ष्य)	प्रशिक्षुओं की वास्तविक संख्या (उपलब्धि)	प्रतिशत (उपलब्धि)
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	529	448	85
	चम्पावत	531	219	41
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	529	548	104
	नैनीताल	531	383	72
ऊ सिं नगर	ऊ सिं नगर	531	870	164
	नैनीताल	529	336	64

स्रोतः जिलों से प्राप्त सूचना।

[36] रजत शहरी एवं ग्रामोद्योग संस्थान, हरिद्वार; ए डब्ल्यू टी सी दुदुबाग, हरिद्वार; ए डब्ल्यू टी सी, अल्मोड़ा; भारतीय ग्रामीण महिला संघ, देहरादून; ए डब्ल्यू टी सी, पिथौरागढ़; ए डब्ल्यू टी सी, ग्वालदम, चमोली; इम्पार्ट, ऊ सिं नगर।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपलब्धि का *प्रतिशत* कम था अर्थात चम्पावत एवं नैनीताल जिलों में उपलब्धि का *प्रतिशत* क्रमशः 41 *प्रतिशत* व 64 *प्रतिशत* था।

इसे इंगित किये जाने पर जिले से संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया (जुलाई 2012) कि प्रशिक्षणार्थियों के कम सहभागिता किये जाने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये।

आगे, प्रशिक्षण केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रशिक्षण केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएँ जैसे- प्रशिक्षण कक्ष, समुचित छात्रावास की सुविधा, प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षकों का अभाव था एवं प्रशिक्षणार्थियों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के साथ ही अनुवर्ती कार्यवाही एवं प्रशिक्षणार्थियों को अनुभवी परामर्श सहायता का भी अभाव था। क्षेत्र-भ्रमण, जो कि ए डब्ल्यू डब्ल्यू प्रशिक्षण का भाग होता है, को भी छोड़ दिया गया था। लेखापरीक्षा विश्लेषण एवं भौतिक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षण से संबंधित आँकड़ों का रखरखाव न किये जाने का मुख्य कारण स्टॉफ की कमी थी।

2.5.9.4 आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण तंत्र का एक भाग है। यह संगठन के अन्दर एक स्वतन्त्र कार्य है जो संगठन को सुव्यवस्थित एवं अनुशासित दृष्टिकोण लाते हुए विभागीय नियम एवं गतिविधियों के अनुपालन के स्तर के आकलन करने के उद्देश्यों को सम्पन्न करने के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि विभाग के अन्दर आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर प्रबंधन को आश्वासन प्रदान किया जा सके।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच से विदित हुआ कि अधीनस्थ कार्यालयों की आवधिक लेखा परीक्षा हेतु विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यशील नहीं थी। यहाँ तक कि निदेशालय एवं जिला कार्यालयों की पूर्व-लेखापरीक्षा जाँच हेतु स्वीकृत दो लेखापरीक्षकों के पदों के सापेक्ष कोई भी लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं था। यह इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जबाब दिया गया (अप्रैल 2012) कि वर्ष 2008-09 से कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हुई है एवं यह कार्य शासन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ के स्थापित होने के उपरान्त ही संभव हो पायेगा।

दिशानिर्देशों के अनुसार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों[37] द्वारा क्षेत्र में आँगनबाड़ी केन्द्रों का नियमित भ्रमण, कार्यक्रम की सफलता हेतु आवश्यक था। राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न स्तर पर प्रत्येक छः माह के लिए अनुश्रवण/पर्यवेक्षण हेतु जनपदवार अग्रिम कार्ययोजना (डी ए ए पी) बनाये जाने की आवश्यकता थी।

चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अधिकारियों/ कर्मचारियों (डी पी ओ/ सी डी पी ओ/ पर्यवेक्षक) में से किसी ने भी निर्धारित मानकों के अनुसार आँगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण नहीं किया **(परिशिष्ट-2.13)**। आगे, यह भी देखा गया कि टिहरी जिले में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की स्थिति बहुत दयनीय थी जैसा कि केवल पर्यवेक्षकों द्वारा मात्र दो *प्रतिशत* पर्यवेक्षण किया गया था। विभाग द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक कोई डी ए ए पी तैयार नहीं किया गया था।

---

[37] पर्यवेक्षकः प्रत्येक माह संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र का कम से कम 50 प्रतिशत; सी डी पी ओः प्रत्येक तिमाही में 100 संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र; डीपीओः वर्ष में कुल संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र का 15 प्रतिशत; एवं निदेशकः वर्ष में 200 संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि पर्यवेक्षकों/ सी डी पी ओ/ डी पी ओ के पदों का रिक्त रहना एवं वाहनों की अनुपलब्धता आँगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण न होने के मुख्य कारण थे।

2.5.9.5 अभिलेखों का रखरखाव न किया जाना

विभागीय मैनुअल के अनुसार, योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मूल अभिलेखों का रखरखाव डी पी ओ द्वारा किया जाना था। चयनित जिलों के नमूना जाँच में पाया गया कि मूल अभिलेख जैसे-बजट नियंत्रण पंजिका, संपत्ति पंजिका, बृहद् एवं लघु निर्माण कार्यों की पंजिका, अग्रिम पंजिका, विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही पंजिका, अनुश्रवण एवं मूल्याँकन पंजिका, स्थापना पंजिका, भवन निर्माण अग्रिम पंजिका, आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों के व्यक्तिगत अभिलेख, चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति पंजिका, सूची पंजिका आदि का विभाग में डी पी ओ द्वारा रख रखाव नहीं किया जा रहा था।

22 आँगनबाड़ी केन्द्रों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आँगनबाड़ी स्तर पर निम्नलिखित अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया जा रहा थाः

- लाभार्थियों की स्वास्थ्य पंजिका का 16 आँगनबाड़ी केन्द्रों में रखरखाव नहीं किया जा रहा था।
- कुपोषित बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य जाँच हेतु 15 आँगनबाड़ी केन्द्रों में संदर्भ पर्ची जारी नहीं किये गये थे।
- स्वास्थ्य जाँच के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच, प्रसव पश्चात् स्तनपान कराने वाली माताओं की जाँच एवं नवजात शिशु व छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल की जाँच की जाती है। सभी 22 आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्वास्थ्य पर्ची, प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात् जाँच हेतु पर्ची न तो जारी की गयी और न ही इनका रख-रखाव किया गया था।

इसे इंगित किये जाने पर जिलों के अधिकारियों द्वारा तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2012) करते हुए भविष्य में अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया।

महत्वपूर्ण अभिलेखों का रखरखाव न किया जाना विभाग के कमजोर अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

2.5.10 निष्कर्ष

योजनाओं के तहत् अवमुक्त बजट का विभाग द्वारा कम उपयोग किया गया था। जिला/परियोजना अधिकारियों द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार नहीं की जा रही थी। प्रदत्त अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम एवं पका पकाया भोजन 300 दिनों के निर्धारित मानकों से अत्यन्त कम था। मेडिसिन किट व प्री-स्कूल किट जैसी सुविधाओं के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि आवंटित करने के बावजूद भी लाभार्थियों को इससे वंचित रखा गया था। राज्य में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों को संचालित करने का प्रयास नहीं किया गया था। यहाँ तक कि संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र भी मूलभूत सुविधाओं जैसे-भवन, शौचालय, पीने का पानी, भार मापने की तराजू, कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता एवं प्रशिक्षण की कमी से ग्रसित था। कर्मचारियों की कमी, प्रशिक्षण की कमी, आंतरिक लेखापरीक्षा की कमी एवं मानदण्ड के सापेक्ष कम पर्यवेक्षण ने योजना के सुचारू कामकाज में बाधा उत्पन्न की। इस प्रकार राज्य में क्रियान्वित

आई सी डी एस योजना को, जटिल क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मज़बूत करने की आवश्यकता है।

2.5.11 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार विचार कर सकती है कि:

- लाभार्थियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए चालू निर्माण कार्य को पूर्ण करने एवं मूलभूत सुविधाएँ जैसे- भवन, शौचालय, पीने का पानी, भार मापने की तराजू, उपकरण व पर्याप्त जनशक्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर महत्वपूर्ण सूचनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों/रजिस्टरों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाए।
- योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए यथानिर्धारित प्रभावी आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली एवं अनुश्रवण/ निरीक्षण, प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाए।

लेन-देन की लेखापरीक्षा

समाज कल्याण विभाग

2.6 निष्फल व्यय

परियोजना की व्यवहारिकता का आकलन किये बिना मदरसों में पढ़ रहे मुस्लिम छात्रों के लिए ई-लर्निंग कार्यक्रम (प्रोजेक्ट तालीम) पर विभाग द्वारा किये गये अनुबंध के विरूद्ध ₹ 70.00 लाख का अग्रिम भुगतान अलाभकारी सिद्ध हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी (आई टी डी ए), देहरादून के माध्यम से राज्य में संचालित विश्व बैंक सहायतित परियोजना "ई-क्लास" की तर्ज पर मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के मुस्लिम छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सरकार ने एक सहायक परियोजना "प्रोजेक्ट तालीम" शुरू की (सितम्बर 2005)। जिसकी मूल अवधारणा राज्य के विभिन्न बोर्डों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में पढ़ाये जाने वाले गणित और विज्ञान विषयों के पाठ्यक्रमों को उर्दू भाषा में उपलब्ध कराने हेतु राज्य के समस्त मदरसों को एक मल्टीमीडिया विषय-वस्तु बनाकर प्रदान कराना है। इस प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन ने परियाजना का प्रस्ताव रखा और मल्टीमीडिया सामग्री के प्रारुप विकास तथा राज्य के लगभग 100 मदरसों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संरचना उपलब्ध कराने हेतु दिल्ली स्थित एक फर्म[38] के साथ अनुबंध किया (अप्रैल 2006)। अनुबंध के अनुसार प्रोजेक्ट तालीम की लागत ₹ 2.00 करोड़ थी तथा फर्म द्वारा सम्पूर्ण कार्य अप्रैल 2006 में हुये अनुबंध की तिथि से नौ कलेण्डर माह की अवधि के अन्दर किया जाना था।

निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी (विभाग) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जून 2011) और आगे उत्तराखण्ड मुस्लिम एजुकेशन मिशन (यू एम ई एम), देहरादून से प्राप्त सूचना (अगस्त 2012) के आधार पर यह पाया गया कि परियाजना की व्यवहारिकता का मूल्यांकन किये बिना विभाग द्वारा प्रोजेक्ट तालीम का अनुबंध (अप्रैल 2006) में किया गया था जबकि पूरे राज्य में केवल दो मदरसे[39] थे जहां कक्षा-9 से 12 के लिए गणित और विज्ञान विषयों का अध्ययन कराया जा रहा था। यह तथ्य विभाग के संज्ञान में तब आया जब कक्षा 9 से 12 तक गणित और विज्ञान विषयों से सम्बन्धित मदरसों के बारे में विस्तृत जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त की गयी (अगस्त 2009)। परिणामस्वरूप, विभाग का स्वयं मानना था (फरवरी 2011) कि परियोजना के लिए केवल दो मदरसों के 907 योग्य छात्रों[40] पर इतना भारी व्यय किया जाना लाभकारी नहीं हो सकता। हालांकि, अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुरूप अप्रैल 2006 से सितम्बर 2006 के मध्य ₹ 70.00 लाख[41] की राशि का भुगतान फर्म को किया जा चुका था। अतः विभाग द्वारा परियोजना की व्यवहारिकता के अनुचित मूल्यांकन के कारण परियोजना पर व्यय अलाभकारी रहा।

---

[38] मैसर्स एस.चांद एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।

[39] (i) गुलज़ार फरीद मुस्लिम इन्टर कॉलेज, पिरान कलियर, हरिद्वार।
(ii) बाबा गरीब शाह सबरी गर्ल्स इन्टर कॉलेज, पिरान कलियर, हरिद्वार।

[40] विज्ञानः 498 छात्र और गणित : 409 छात्र।

[41] ₹ 50 लाख की राशि का भुगतान अनुबन्ध हस्ताक्षर करते समय (अप्रैल 2006) और 20 लाख की राशि का भुगतान शुरूआती रिपोर्ट को सौंपते समय (सितम्बर-2006)।

प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर (जून 2011) विभाग द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और बताया गया कि परियोजना यू एम ई एम और सरकार के स्तर पर तैयार की गयी थी तथा ₹ 70.00 लाख अवमुक्त करने के बावजूद, फर्म द्वारा तैयार परियोजना का लाभ लाभार्थियों तक नहीं पहुँच सका क्योंकि इण्टरमीडिएट स्तर के मात्र दो मदरसे थे। आगे यह भी कहा गया कि अवशेष धनराशि ₹ 1.30 करोड़ के समुचित उपयोग की संभावना धूमिल थी और इसलिए शेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि फर्म के साथ अनुबंध करने से पूर्व परियोजना की व्यवहारिकता का आंकलन विभाग द्वारा किया जा सकता था।

इस प्रकार, "प्रोजेक्ट तालीम" की व्यवहारिकता का आंकलन किये बिना अनुबन्ध के क्रियान्वयन और विभाग द्वारा फर्म को भुगतान की गयी राशि ₹ 70.00 लाख का व्यय निष्फल साबित हुआ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (अगस्त 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

समाज कल्याण विभाग

2.7 धन का अवरोधन

विभागीय नियोजन की कमी के कारण हज-हाउस के डिजाइन में बदलाव एवं नई मदों के लगातार समावेश के कारण भवन निर्माण अपूर्ण रहना तथा ₹ 5.95 करोड़ का चार वर्षों से अधिक अवरूद्ध रहना।

उत्तराखण्ड सरकार ने 800 हज यात्रियों की क्षमता के हज हाउस के निर्माण हेतु ₹ 2.70 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2003)। स्वीकृति के नियम और शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा जारी आवश्यक निर्देशों के अनुसरण और कार्यस्थल की दशाओं के अनुरूप हज हाउस का निर्माण स्वीकृत धनराशि के अन्दर पूर्ण किया जाना था। कार्य निष्पादन में देरी के कारण आगणन संशोधन के मामले में अतिरिक्त व्यय का वहन निष्पादन संस्था द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों के उपयोग द्वारा किया जाना था। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू पी आर एन एन), यूनिट-1, हरिद्वार को इस भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था (अभिकरण) नामित किया गया था (मार्च 2003)। कार्य अगस्त 2003 को प्रारम्भ किया जाना था जिसकी पूर्ण करने की निर्धारित तिथि दिसम्बर 2005 थी।

निदेशक, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी के अभिलेखों की जाँच (जून 2011) में पाया गया कि कार्य प्रारम्भ हो जाने के एक वर्ष उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा विभिन्न आधारों[42] पर ₹ 5.03 करोड़ का संशोधित आगणन प्रस्तुत किया (सितम्बर 2004)। उपरोक्त के अतिरिक्त, चहारदीवारी, एक ट्यूबवैल, ओवरहैड टैंक, लिफ्ट, एक मुख्य द्वार के साथ छोटा द्वार तथा एक गार्ड रूम के निर्माण हेतु धनराशि ₹ 66.21 लाख का अनुपूरक आगणन भी कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया (सितम्बर 2004)। राज्य सरकार द्वारा

---

[42] (i) शुरूआती प्राक्कलन पुराने निर्धारित दर (SoR) पर तैयार किये गये थे जो कि मई 2001 से लागू थे परन्तु कार्य अगस्त 2003 से प्रारम्भ किया जा सका।

(ii)आवश्यक वस्तुएं जैसे ग्रिट फिनिश, छत की ऊँचाई बढ़ाना, बाहरी विद्युतीकरण, स्वच्छता-कार्य, आग अवरोधी उपकरण और कार्य स्थल विकास, शुरूआती आगणन में सम्मिलित नहीं थे क्योंकि स्थल का चयन आगणन की स्वीकृति के पश्चात किया गया था।

(iii) हज-हाउस का नक्शा अनन्तिम था, एवं

(iv) भवन का वर्गीकरण वर्ग-बी से वर्ग-ए में उच्चीकृत करना था।

₹ 5.03 करोड़ व ₹ 66.21 लाख के उक्त आगणनों के सापेक्ष ₹ 4.98 करोड़ (क्रमशः ₹ 4.40 करोड़ व ₹ 58.20 लाख) की स्वीकृति प्रदान की गयी (नवम्बर 2005)। इसके अलावा, कुछ अतिरिक्त विद्युत कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 97.07 लाख की अलग मंजूरी भी दी गयी थी (फरवरी 2006)। उक्त सभी स्वीकृतियों की स्वीकृत राशि मार्च 2003 और फरवरी 2006 के मध्य कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कर दी गयी थी। अभिलेखों की आगे जाँच मे यह भी पता चला कि नवम्बर 2005 से दर अनुसूची में संशोधन एवं ढाँचा संरचनात्मक प्रणाली अपनाने हेतु लागत में 12 *प्रतिशत* वृद्धि को पूरा करने के लिए भी कार्यदायी संस्था ने पुनः स्वीकृति हेतु ₹ 6.45 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया (अप्रैल 2008)। हालांकि, धन के अभाव में कार्य बन्द कर दिया गया था (मई 2008)। आगे, कार्यदायी संस्था ने ₹ 7.72 करोड़ (जून 2009) और ₹ 9.14 करोड़ (फरवरी 2012) के पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किये जिन्हें शासन द्वारा अभी तक (अक्टूबर 2012) स्वीकृत नहीं किया गया था तथा आगे और संशोधन की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

कुल ₹ 5.95 करोड़ के व्यय के सापेक्ष, केवल मुख्य भवन के कार्य पूर्ण किये गये थे तथा शेष कार्य जैसे-पेवर एप्लीकेशन, वज़ू प्वाइन्ट का निर्माण, इमाम के लिए प्रार्थना प्लेटफार्म, मुख्य भवन का परिष्करण कार्य, कार्यस्थल विकास, पम्परूम, गार्डरूम व वाह्य पेटिंग इत्यादि किये जाने थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जून 2011) कि कार्यदायी संस्था द्वारा आगणनों में लगातार संशोधन तथा शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने की वजह से कार्य में विलंब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्यारम्भ से पूर्व विभाग द्वारा हज हाउस का उचित डिजाइन योजनाबद्ध नहीं किया गया था तथा अस्थायी डिजाइन पर कार्य शुरू किया गया था।

इस प्रकार, शासन/विभाग द्वारा हज हाउस के डिजाइन में परिवर्तन एवं नये मदों का लगातार समावेश, विभागीय नियोजन की कमी को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप छः वर्षों से अधिक अवधि के उपरान्त भी हज हाउस का निर्माण अपूर्ण रह गया था। इसके अलावा, ₹ 5.95 करोड़ का व्यय भी चार वर्षों से अधिक समय तक अवरूद्ध रहा।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (जून 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

खेल विभाग

2.8 अतिरिक्त परिहार्य व्यय

खेल निदेशालय भवन के निर्माण स्थल के चयन को अन्तिम रूप देने में अनिर्णयन के कारण ₹ 60.28 लाख का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

खेल निदेशालय, देहरादून के भवन निर्माण हेतु शासन ने ₹ 89.95 लाख की प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2007)। खेल कॉलेज, रायपुर, देहरादून के परिसर में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (निर्माण अभिकरण) के द्वारा कार्य कराया जाना प्रस्तावित था।

जिला खेल अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2011) एवं निदेशक, खेल, देहरादून से आगे एकत्रित सूचना (अगस्त 2012) से पाया गया कि कार्य सौंपने/ ₹ 40.00 लाख की प्रथम किस्त अवमुक्त करने (मार्च 2007) के मात्र डेढ़ माह के पश्चात, विभाग ने निर्माण अभिकरण को अगले आदेश तक कार्य प्रस्तावित स्थल पर न प्रारम्भ किये जाने हेतु आदेश दिया (मई 2007)। तत्पश्चात, विभागीय बैठक (दिसम्बर 2007) में भवन के स्थल को खेल कॉलेज परिसर, रायपुर से परेडग्राउण्ड, देहरादून में परिवर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर विभाग ने स्थल परिवर्तन के कारण के बारे में बताया (अप्रैल 2012) कि साउथ एशियन विन्टर गेम्स के आयोजन हेतु खेल कॉलेज, रायपुर में आधारभूत सुविधाओं का सृजन अपरिहार्य था तथा परेड ग्राउण्ड देहरादून को एक वैकल्पिक स्थल के रूप में रखा गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग को 2006 में ज्ञात था कि प्रथम साउथ एशियन विन्टर गेम्स उत्तराखण्ड में होने थे जो कि बाद में जनवरी 2011 में आयोजित हुये। इसी बैठक में कार्य को नये अभिकरण अर्थात् उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (देहरादून) को सौंपा गया। यद्यपि कार्य परेड ग्राउण्ड, देहरादून में स्थल लोक वादित होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका एवं विभाग द्वारा निर्णय को पूर्व में प्रस्तावित स्थल (रायपुर, खेल कॉलेज परिसर) में बदल दिया गया (सितम्बर 2009) तथा कार्य को पूर्व निर्माण अभिकरण को पुनः सौंपा गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वाद दिसम्बर 2006 में दायर किया गया था एवं स्थल परिवर्तन का निर्णय दिसम्बर 2007 में लिया गया था। अतः विभाग को खेल कॉलेज परिसर रायपुर से परेड ग्राउण्ड के लिए स्थल परिवर्तन के निर्णय से पूर्व वाद की जानकारी थी। कार्य में, ढाई वर्ष की देरी से प्रारम्भ होने के कारण अन्ततः कार्य की लागत ₹ 89.95 लाख से ₹ 150.23 लाख पुनरीक्षित हो गई जिसे शासन द्वारा मार्च 2010 में स्वीकृत किया गया एवं कार्य को उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा तदनुसार पूर्ण किया गया (जनवरी 2012)। इस प्रकार विभाग को स्थल परिवर्तन हेतु लिए गये निर्णयों के कारण ₹ 60.28 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर खेल निदेशक ने बताया (नवम्बर 2011) कि स्थल परिवर्तन का निर्णय जनहित में लिया गया क्योंकि प्रारम्भ में चयनित स्थल शहर से दूर था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि निर्माण कार्य उसी स्थल पर कराया गया जिसका विभाग ने प्रारम्भ में चयन किया था।

इस प्रकार खेल निदेशालय भवन के निर्माण के स्थल के चयन को अन्तिम रूप देने में विभाग/ शासन के अनिर्णयन के कारण ₹ 60.28 लाख का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया था (अप्रैल 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

उच्च शिक्षा विभाग

2.9 परिहार्य लागत वृद्धि

विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु बाधा-रहित कार्य स्थल उपलब्ध करवाने में विलम्ब के कारण ₹ 0.56 करोड़ लागत की वृद्धि।

राज्य सरकार ने गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर (विश्वविद्यालय) के परिसर में गृह विज्ञान कॉलेज के विस्तार कार्य हेतु ₹ 2.10 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की (दिसम्बर 2006), कि निर्माण कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण किये जायेंगें और यदि कोई लागत वृद्धि होती है तो उसे विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत से वहन किया जायेगा और कोई अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जायेगी। इस कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिये ₹ 2.10 करोड़ का समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) विश्वविद्यालय और उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (उ पे सं वि एवं नि नि) के मध्य हस्ताक्षरित किया गया (जुलाई 2007)। एम ओ यू के अनुसार कार्य सितम्बर 2007 को प्रारम्भ कर पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मार्च 2009 थी और सम्पूर्ण कार्य, स्थल एवं धनराशि की उपलब्धता की शर्त पर, निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना था।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (फरवरी-मार्च 2010) में पाया गया कि एम ओ यू के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उ पे सं वि एवं नि नि को बाधा-रहित कार्यस्थल नहीं दिया गया, जैसा कि वहाँ झाड़ी वाले पौधे थे, जिसे विश्वविद्यालय के उद्यान शाखा द्वारा साफ करके दिया जाना था। उ पे सं वि एवं नि नि के परियोजना प्रबन्धक द्वारा भी कार्य प्रारम्भ करने हेतु विश्वविद्यालय को मुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था (18 सितम्बर 2007)। विश्वविद्यालय द्वारा यद्यपि मामले के शीघ्र निपटान हेतु प्रतिक्रियात्मक भूमिका अदा नहीं की गयी जिसके कारण कार्य चार माह के विलम्ब से जनवरी 2008 में प्रारम्भ हुआ। कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् उ पे सं वि एवं नि नि ने ₹ 3.20 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन इस औचित्य के साथ प्रेषित किया (सितम्बर 2008) कि मुक्त कार्यस्थल समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया और इस बीच लो नि वि द्वारा कुरसी क्षेत्रफल की दरें पुनरीक्षित कर दी गई (फरवरी 2008)। विश्वविद्यालय द्वारा पुनरीक्षित आगणन शासन की अनुशंसा हेतु यह तथ्य जानते हुए भी प्रेषित किया गया (दिसम्बर 2008) कि पुनरीक्षण, केवल 25 फरवरी 2008 को या बाद में तैयार किये गये प्रारम्भिक आगणन (पी ई) पर लागू होना था। शासन ने दिसम्बर 2006 को दी गई स्वीकृति में उल्लिखित शर्त कि लागत वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी, के विपरीत पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष ₹ 2.73 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2009)।

विलंब के बारे में पूछे जाने पर (फरवरी-मार्च 2010) विश्वविद्यालय के नियंत्रक द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल पर झाड़ी वाले पौधे थे, जिसे विश्वविद्यालय के उद्यान शाखा द्वारा हटाया जाना था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि उद्यान शाखा भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में थी तथा कार्यस्थल को साफ कराने में विलम्ब को विश्वविद्यालय द्वारा टाला जा सकता था।

आगे विश्वविद्यालय से सूचना एकत्रित करने (अगस्त-सितम्बर 2012) पर पाया गया कि उ पे सं वि एवं नि नि ने फरवरी 2012 में, कार्य पूर्ण होने की मूल तिथि (मार्च 2009) से तीन वर्ष पश्चात् पूर्ण किया गया और ₹ 2.66 करोड़ विश्वविद्यालय द्वारा उ पे सं वि एवं नि नि को अगस्त 2012 तक अवमुक्त किये गये थे

तथा विश्वविद्यालय के पास ₹ 7.00 लाख की राशि रखी हुई थी। कार्य पूर्ण होने की तिथि से सात माह व्यतीत होने के उपरान्त सितम्बर, 2012 तक भवन विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित नहीं किया गया था क्योंकि उ पे सं वि एवं नि नि द्वारा निर्माण कार्य की कमियों को दूर किया जा रहा था (सितम्बर 2012)।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु मुक्त कार्यस्थल समय पर उपलब्ध न कराने के कारण ₹ 0.56 करोड़[43] की लागत वृद्धि हुई जिसे टाला जा सकता था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2012), उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

लोक निर्माण विभाग

2.10 ठेकेदार को अदेय लाभ

परिनिर्धारित क्षति की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.36 करोड़ का अदेय लाभ।

उत्तराखण्ड शासन ने 72.90 कि मी लम्बे अल्मोड़ा-बागेश्वर मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं अनुरक्षण हेतु, एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित ₹ 38.08 करोड़ में से ₹ 35.13 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी (अगस्त 2007)। मुख्य अभियन्ता स्तर -1 द्वारा उतनी ही राशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी (सितम्बर 2007)। परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी एम यू), एशियन डेवलेपमेन्ट बैंक (ए डी बी), लोक निर्माण विभाग (पी डब्लू डी), उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून ने ₹ 36.93 करोड़ की लागत पर ठेकेदार[44] के साथ, दिसम्बर 2008 को कार्य पूर्ण करने की तिथि अनुसूचित करते हुए अनुबंध[45] किया था (सितम्बर 2007)।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- II, अल्मोड़ा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मई 2012) में यह पाया गया था कि परिनिर्धारित क्षति (एल डी) की वसूली संविदा के सामान्य शर्तों (जी सी सी) की कण्डिका 49.1 के अनुसार, किया जाना था, जिसके अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो एल डी की वसूली सम्पूर्ण कार्य हेतु मूल अनुबंधित लागत के 2000-वांश प्रतिदिन की दर से, निकटतम हजार में पूर्णांकित करते हुए वसूल किया जाना था। सम्पूर्ण कार्य हेतु एल डी की अधिकतम राशि मूल अनुबंधित लागत के 10 प्रतिशत तक थी। ठेकेदार को कार्य धारण कराने में विलम्ब, वर्षा ऋतु, खदानों के बन्द होने तथा विभिन्न मदों में विचलन के परिणामस्वरूप निर्माण खण्ड द्वारा उक्त कार्य के लिए दिसम्बर 2009 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जबकि कार्य वास्तव में ₹ 37.94 करोड़ के व्ययोपरान्त अगस्त 2010 में, अर्थात् समयावृद्धि की समाप्ति के 227 दिन पश्चात् पूर्ण हुआ। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 3.69 करोड़[46] एल डी के रूप में वसूल किया जाना था, परन्तु खण्ड ने ठेकेदार से मार्च 2012 तक मात्र ₹ 2.33 करोड़ ही वसूल किया था और शेष राशि ₹ 1.36 करोड़ की वसूली नवम्बर 2012 तक लम्बित थी।

---

[43] ₹ 2.66 करोड़ - ₹ 2.10 करोड़।

[44] मेसर्स एन के जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, गाजियाबाद।

[45] अनुबंध संख्या 04/पी डी/पी एम यू/ए डी बी/2007 दिनांक 14.09.2007।

[46] ₹ 369278604x227/2000 = ₹ 4.19 करोड़, आरम्भिक अनुबंधित लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित ₹ 3.69 करोड़।

इसे इंगित किये जाने पर, खण्ड ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मई 2012) कि अन्य खण्डों में ठेकेदार के चालू कार्यो से शेष एल डी राशि की वसूली हेतु मुख्य अभियन्ता, स्तर-I के साथ से पत्राचार पूर्व में ही किया जा चुका है।

इस प्रकार, एल डी की वसूली नहीं किये जाने के परिणामस्वरूपः ठेकेदार को ₹ 1.36 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

प्रकरण सरकार को सन्दर्भित किया गया (नवम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

लोक निर्माण विभाग

2.11 अनियमित व्यय

मार्ग निमार्ण के एक कार्य में प्रथम स्वीकृति को यथावत् रखते हुए द्वितीय स्वीकृति के विरूद्ध ₹ 51.15 लाख का अनियमित व्यय किया जाना।

शासन ने (सितम्बर 2005) एक प्रस्ताव के आधार पर 12 कि मी लम्बे जी आई सी सुकौली से डंगरीरावल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 2.14 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी (मार्च 2006)। अधीक्षण अभियन्ता (एस ई) द्वारा ₹ 1.02 करोड़ की आंशिक तकनीकी स्वीकृति (टी एस) प्रदान की गयी थी (मार्च 2011)।

अधिशासी अभियन्ता (ई ई), प्रान्तीय खण्ड (पी डी), पिथौरागढ़ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2012) में यह पाया गया था कि उक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पाँच वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात् उपरोक्त अनुमोदन के विरूद्ध भाग-I[47] कार्य हेतु खण्ड द्वारा सात अनुबंध (जून 2011 में छः एवं जुलाई 2011 में एक) गठित किये गये, जो कि वित्तीय नियमों[48] के प्राविधानों, जिसमें स्वीकृति के पाँच वर्ष व्यतीत होने पर उसका नवीकरण किया जाना चाहिए, के विपरीत था। इस कार्य पर ₹ 51.15 लाख का व्यय (नवम्बर 2012) किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आगे यह भी संज्ञान में आया कि उपरोक्त स्वीकृति 12 कि मी के ही संरेखण में पड़ने वाली जी आई सी सुकौली-हुण्डखोला मोटर मार्ग, लम्बाई 10 कि मी (नौ कि मी नवनिर्माण और एक कि मी के पुनर्निर्माण एवं सुधार) के निर्माण हेतु, अग्रसारित प्रस्ताव (अक्टूबर 2004) के आधार पर, खण्ड द्वारा ₹ 1.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी थी (नवम्बर 2005)। इस दरमियान, मार्ग के आरम्भिक बिन्दु से 0.475 कि मी के लघु भाग के निर्माण हेतु प्रथम स्वीकृति के विरुद्ध ₹ 15.78 लाख व्यय किये गये (दिसम्बर 2009)।

जबकि उक्त कार्य हेतु ₹ 1.78 करोड़ पूर्व में ही स्वीकृत किये गये थे, तब या तो ₹ 2.14 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति अभ्यर्पित की जानी चाहिए थी और शेष दो कि मी हेतु अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए

---

[47] सर्वे, पहाड़ कटान, स्कपर एवं कच्चा नाली का निर्माण।

[48] वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-छः के प्रस्तर-380 प्रावधान करता है कि लोक निर्माण कार्य के आगणन का अनुमोदन या स्वीकृति जो वार्षिक मरम्मत कार्य से भिन्न हो, जब तक कि उक्त कार्य प्रारम्भ न कर दिया गया हो, स्वीकृति की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के उपरान्त उस कार्य का परिचालन बन्द कर दिया जायेगा।

था या द्वितीय प्रस्ताव प्रेषित करते समय प्रथम प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए था। इसके विपरीत, 12 कि मी के लिए तैयार किये गए ₹ 2.14 करोड़ के विस्तृत आगणन के सापेक्ष अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ₹ 1.02 करोड़ की आंशिक टी एस, वित्तीय नियम का उल्लघंन करते हुए प्रदान की गई (मार्च 2011) जिसके तहत भाग-I सम्बन्धित कार्य किए गए क्योंकि स्वीकृति तिथि से पाँच वर्ष पहले ही समाप्त हो चुके थे।

इसे इंगित किए जाने पर, खण्ड ने अवगत कराया (अगस्त 2012) कि जन प्रतिनिधियों की माँग पर 12 कि मी के लिए पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उस समय तक, पूर्व में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव शासन द्वारा स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि द्वितीय प्रस्ताव भेजते समय 10 किमी के प्रथम प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए था, जैसा कि उस समय तक शासन द्वारा उसे स्वीकृत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट रूप से वित्तीय नियम के प्रावधानों के प्रतिकूल था क्योंकि द्वितीय स्वीकृति को पाँच वर्षो की समाप्ति पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए था।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (नवम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

लोक निर्माण विभाग

2.12 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

खण्ड द्वारा प्राइम कोट के स्थान पर प्रथम सतह लेपन का प्रयोग करने पर ₹ 39.41 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया जाना।

शासन ने बरौटीवाला-अम्बाड़ी मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधार हेतु ₹ 4.39 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी (अगस्त 2009)। मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र द्वारा उतनी ही धनराशि की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी (जनवरी 2010)।

अधिशासी अभियन्ता (ई ई), अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2012) में पाया गया कि विस्तृत आगणन में प्राइम कोट बिछाये जाने हेतु ₹ 8.90 लाख की धनराशि प्रावधानित थी। खण्ड ने 17 अगस्त 2011 तक कार्य पूर्ण करने की तिथि निर्धारित करते हुए ₹ 4.16 करोड़ का अनुबन्ध[49] गठित किया (फरवरी 2010) था और विस्तृत आगणन के अनुसार, अनुबन्ध में प्राइम कोट का भी प्रावधान सम्मिलित किया गया था। तथापि लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि कार्य निष्पादित कराते समय, प्राईमकोट के स्थान पर अतिरिक्त मद के रुप में ₹ 48.31 लाख की धनराशि से प्रथम सतह लेपन किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 39.41 लाख का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया (जुलाई 2012) कि विशिष्टियों के अनुरूप, प्राइम कोट बिछाने के उपरान्त 24 घन्टे तक यातायात रोकने की आवश्यकता थी, लेकिन स्थानीय निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वह सम्भव नहीं था।

[49] अनुबन्ध सं. 37/अधी अभि-09/2009-10 दिनांक 18.02.2010 ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सड़क की चौड़ाई सात मीटर थी और मोर्थ की विशिष्टियों[50] के अनुसार खण्ड द्वारा मार्ग की चौड़ाई को दो भागो में बाँट कर प्राइम कोट का काम जैसा कि एक भाग में प्राइम कोट को बिछाते हुए एवं मार्ग के दूसरे भाग पर यातायात की अनुमति देते हुए कराया जा सकता था।

इस प्रकार, मार्ग की सम्पूर्ण चौड़ाई में यातायात को बन्द किये बिना प्राइम कोट बिछाकर ₹ 39.41 लाख के परिहार्य अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (नवम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

[50] कंडिका 502.6-यातायात हेतु प्रबन्ध के साथ पठित कंडिका 112.1 ।

उद्यान विभाग

2.13. उद्यान विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य अंश

उद्यान विभाग की, इसके अधिदेशों तथा लक्ष्यों के सापेक्ष, मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा में 2007-12 की अवधि में नियोजन का अभाव, वित्तीय कुप्रबंधन, अकुशल कार्यक्रम प्रबंधन, मानव संसाधन कुप्रबंधन तथा पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रणों तथा अनुश्रवण तंत्र की अनुपस्थिति प्रकट हुई। कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैः

- *विभाग 2007-12 की अवधि में कुल निर्गत केन्द्रीय धनराशि ₹ 189.24 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 140.33 करोड़ ही व्यय कर सका।*

[प्रस्तर 2.13.10.1]

- *विभाग ₹ 2.70 करोड़ की विभागीय प्राप्तियों को वसूल करने में असफल रहा।*

[प्रस्तर 2.13.10.3]

- *विभाग ने निःशुल्क वितरित किये जाने वाले बीजों के लिए किसानों से ₹ 1.36 करोड़ अनियमित रूप से वसूल कर लिये।*

[प्रस्तर 2.13.10.4(iii)]

- *अपर्याप्त सिंचाई व्यवस्था के कारण फल औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत रोपित क्षेत्रफल में 9417 हेक्टेयर की क्षति हुई।*

[प्रस्तर 2.13.12.1]

- *राज्य सरकार द्वारा कीमतों में हुई वृद्धि का निधीयन करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी न करने के कारण ₹ 2.40 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के बावजूद 'सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन इकाई' की स्थापना नहीं हो सकी।*

[प्रस्तर 2.13.12.4]

- *मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई ने पौध रोपण सामग्री की फर्जी आपूर्ति पर ₹ 0.95 लाख का भुगतान किया।*

[प्रस्तर 2.13.14.1]

- *विभाग ने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 77.65 लाख मूल्य के सब्जी बीजों का क्रय निविदाएं आमंत्रित किये बिना ही कर लिया।*

[प्रस्तर 2.13.15.1]

2.13.1 परिचय

हार्टीकल्चर (बागवानी), दो लैटिन शब्दों-होर्टस (बागीचा) और कल्चरा (कृषिकरण) का सम्मिश्रण है। उद्यान विभाग का प्राथमिक उद्देश्य-उद्यान क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई सुविधा एवं गुणवत्ता युक्त बीजों के सन्दर्भ में नई तकनीकों के क्रियान्वयन जैसे घटकों के पहुँच विस्तार के साथ-साथ किसानों के उत्पादों में गुणवत्ता वृद्धि कर बागवानी को बढ़ावा देना है। यह, उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के वर्ष 2003-04 और 2010-11 की मार्ग निर्देशिका में निर्दिष्ट, प्रभावी व वहन किये जाने योग्य सेवायें, जिसमें तकनीकी का हस्तान्तरण, भण्डारण, विपणन और औद्यानिक उत्पादों का निर्यात शामिल हैं, की परिकल्पना भी करता है। विभाग, राज्य में आधारभूत संरचना का विनिर्माण कर रेशम कीट पालन, चाय उत्पादन, औषधीय व सुगन्ध पौधों (एम ए पी) को प्रोत्साहित करने में भी शामिल हैं।

उत्तराखण्ड में, उद्यान विभाग के अन्तर्गत निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (नि उ खा प्र), रेशम निदेशालय (रे नि), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज[51] विकास इकाई (भे वि इ), उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (उ चा वि बो), जड़ी-बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (ज बू अ वि स) और सगंध पादप केन्द्र (स पा के) की स्थापना क्रमशः वर्ष 1953, 2001, 2006, 2004, 1989 व 2003 में हुई थी।

निदेशक उद्यान के अन्तर्गत 285 उद्यान सचल केन्द्र और रेशम निदेशालय के अन्तर्गत 75 रेशम फार्म संचालित होते है। इसके अतिरिक्त राज्य में दो अनुसंधान व विकास संस्थान है जैसे चमोली में ज बू अ वि स और सेलाकुई, देहरादून में स पा के, जबकि अल्मोड़ा आधारित उ चा वि बो चाय की खेती में संलग्न रहता है। यह उत्तराखण्ड शासन के सहकारी समितियों के पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

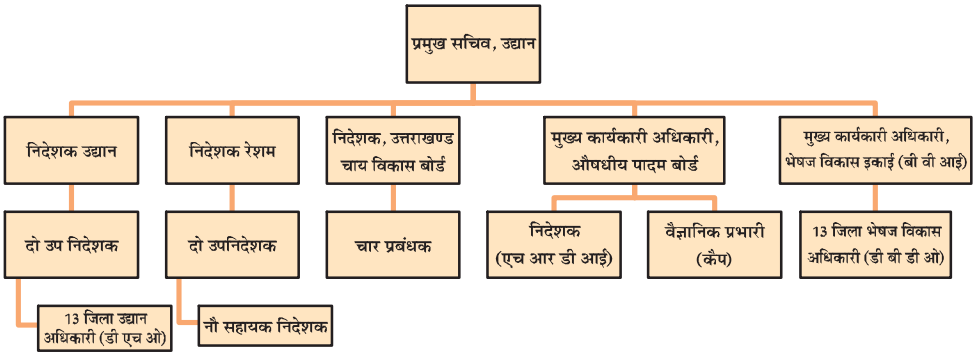
विभाग अपने कार्य 22 आहरण वितरण अधिकारियों जिसमें क्रमशः चार रे नि और एक भे वि इ से है, के माध्यम से निरूपित करते है। यह कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 3655 के सापेक्ष 64 *प्रतिशत* पर कार्य करता था जबकि वर्ग क, ख, ग एवं घ में वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति क्रमशः 70 *प्रतिशत*, 50 *प्रतिशत*, 59 *प्रतिशत* और 68 *प्रतिशत* थी।

2.13.2 संगठनात्मक ढ़ाँचा

उद्यान विभाग के प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग के प्रशासनिक प्रमुख और विभाग के सम्पूर्ण प्रभारी हैं। वे निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (नि उ खा प्र), निदेशक, रेशम (नि रे) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मु का अ), भेषज विकास इकाई (भे वि इ), जो कि विभाग की कार्यकलापों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हैं, के सहयोग से कार्य करते हैं और जिला उद्यान अधिकारियों (जि उ अ), सहायक निदेशक, रेशम और जिला भेषज विकास अधिकारियों (जि भे वि अ) के माध्यम से जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक कार्यालय, निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा, निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर, चमोली और वैज्ञानिक प्रभारी, सगंध पादप केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून भी राज्य में औद्यानिक कार्यकलापों में सहायता करते हैं। विभाग के संगठनात्मक ढाँचे को नीचे दिये गये प्रवाह **चार्ट-1** में दर्शाया गया है।

[51] भेषज एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ औषधीय पौधा/जड़ी बूटी है।

चार्ट 1



2.13.3 लेखापरीक्षा अधिदेश, क्षेत्र एवं क्रियाविधि

उद्यान विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अन्तर्गत नि उ, नि रे, मु का अ (भेषज), निदेशक (उ चा वि बो), निदेशक (जड़ी बूटी अनुसंधान संस्थान), वैज्ञानिक प्रभारी (सगंध पादप केन्द्र) और उद्यान, रेशम तथा भेषज विभाग के चयनित जिला स्तर के कार्यालयों के वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच के माध्यम से मई 2012 से अगस्त 2012 के मध्य संपादित की गयी। राज्य के 13 में से पाँच जिला स्तर के कार्यालयों[52] का चयन 'स्ट्रेटीफाइड प्रोबेविलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विद रिप्लेसमेन्ट' (एस पी पी एस डब्ल्यू आर) नमूना पद्धति के द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा ज्ञाप के निर्गमन, प्रश्नावलियों को भरवाना तथा चयनित इकाइयों और उद्यान सचल दलों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तथा रेशम फार्मों सहित अन्य मार्गी कार्यालयों से आँकड़ों के संग्रहण के माध्यम से सम्पन्न हुई। लेखापरीक्षा ने आन्तरिक रूप से तैयार प्रश्नावली के माध्यम से चयनित जिलों के उद्यानपतियों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया।

लेखापरीक्षा प्रारंभ करने से पहले लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड तथा क्षेत्र के विषय पर अपर सचिव, उद्यान विभाग तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ प्रविष्टि सम्मेलन (अप्रैल 2012) में चर्चा की गयी। प्रमुख सचिव, उद्यान तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गयी थी और शासन/ विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में सम्यक रूप से शामिल कर लिया गया है।

2.13.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलित करना था कि क्याः

- नियोजन एवं कार्यक्रम प्रबंधन मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी था;

[52] अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, हरिद्वार एवं टिहरी।

- विभाग में अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए पर्याप्त निधियाँ बजट में प्रस्तावित, आवंटित तथा उपयोग की गयी थीं;
- अधिप्राप्ति एवं भंडार नियंत्रण के लिए प्रक्रियाएँ अस्तित्व में थीं एवं प्रभावी थीं;
- मानव संसाधन प्रबंधन पर्याप्त थे एवं मानवशक्ति को प्रभावी तरीके से तैनात तथा उपयोग किया गया था;
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावी था; तथा
- अनुश्रवण एवं मूल्याँकन की प्रक्रियाएँ अस्तित्व में थीं तथा कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्याँकन करने में सक्षम थीं और वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा जानकारी हस्तांतरित की जाती थी।

2.13.5 लेखापरीक्षा के मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं:

- औद्यानिकी, रेशम उत्पादन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की मार्गदर्शिका एवं संबधित शासकीय आदेश;
- विभागीय नियम, विनियम, नियम-पुस्तिकाएँ एवं उपनियम;
- वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट नियम-पुस्तिका के प्रावधान; तथा
- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008।

2.13.6 विभाग में क्रियान्वित की जा रही योजनाएँ

उद्यान विभाग बागवानी, रेशम उत्पादन तथा औषधीय एवं सगंध पौधों (एम ए पी) को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार विभिन्न राज्य प्रायोजित एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा था। 2007-12 की अवधि में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित थाः-

- **राज्य प्रायोजित योजनाएँ:-** विभाग मधुमक्खी-पालन, उत्तर फसल प्रबंधन, मौसम आधारित उद्यान बीमा योजना, खाद्य प्रसंस्करण, शहतूत रोपण तथा चाय की खेती आदि विभागीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्ण/अंशतः राज्य प्रायोजित योजनाएँ संचालित करता आ रहा था।
- **केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ:-** विभाग मुख्यतः 'उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन', राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) तथा कैटेलिटिक विकास कार्यक्रम (सी डी पी) के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में शामिल था।

प्रतिवेदन के विभिन्न प्रस्तरों में इन योजनाओं की चर्चा की गई है।

2.13.7 विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, रेशम निदेशालय तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई राज्य में बागवानी, रेशम तथा औषधीय एवं सगंध पौधों के विकास के बहुआयामी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से कुल स्वीकृत क्षमता 3655 के सापेक्ष केवल 2345 (64 *प्रतिशत*) की मानव शक्ति के साथ कार्य कर रहे थे। इसके उपक्रम यथा उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों ने तकनीकी/ वैज्ञानिक अधिकारियों की श्रेणी में स्थायी मानव शक्ति की भर्ती नहीं की थी। इससे अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा। विभाग में भर्ती के विषय में कोई नीति नहीं है

तथा इसने आगामी पाँच वर्षों में वर्तमान श्रम शक्ति के विरूद्ध 25 *प्रतिशत* सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों के परिप्रेक्ष्य में कोई भर्ती प्रकिया प्रारम्भ नहीं की थी। विस्तृत विवरण प्रस्तर 2.13.13.1 में दिया गया है।

2.13.8 विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र

आन्तरिक नियंत्रण इस बात का पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनाया जाता है कि विभाग के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र अत्यधिक कमजोर था। नियंत्रण का वातावरण इतना प्रभावी नहीं था कि वह प्रयोज्य नियमों और विनियमों का पालन, लाभार्थियों को समयबद्ध/ समय पर सेवा उपलब्धता को बनाये रखना, लागत-लाभ अनुपात का आकलन करना, हानियों को रोकना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना, सुनिश्चित कर सके। आगे, क्षेत्र निरीक्षण के मानकों के अभाव तथा न्यून संख्या में आन्तरिक लेखा परीक्षा के कारण तंत्र के उल्लघंन के मामले प्रकाश में नहीं आ सके। विस्तृत विवरण आगे आने वाले प्रस्तर 2.13.14.1 से 2.13.14.7 तक तथा अन्य विभिन्न प्रस्तरों में दिया गया है।

2.13.9 आयोजना

विभाग के सभी कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र विस्तार, जल स्रोतों के निर्माण और बागवानी उपज, कोकून और औषधीय एवं सगंधित पौधे (एम पी एस) के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य में बागवानी, रेशम उत्पादन और हर्बल विकास को बढ़ावा देना था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग को विभिन्न कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण विकसित एवं तैयार करना था। परन्तु लेखा परीक्षा में पाया गया कि उचित आयोजना के अभाव में विभाग विभिन्न परिचालनशील योजनाओं के अन्तर्गत इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त कर सका जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है।

2.13.9.1 अपर्याप्त आयोजना

(i) आधारभूत सर्वेक्षण और विशेषज्ञों की नियुक्ति

उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य के बागवानी मिशन के परिचालन दिशानिर्देश, 2004 (2010 में संशोधित) के पैरा 2 (1) और 5.2.2 (ब), प्रस्तर संख्या 2 (ii, V) और प्रस्तर 7.1 के प्रावधान के अनुसार विभाग को लाभार्थियों की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन करने, परियोजना विशेषज्ञों की मदद से बागवानी विकास के सभी पहलुओं को शामिल कर एकीकृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और विभिन्न मिशनों[53] के अन्तर्गत आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए वार्षिक कार्य योजना (वा का यो) तैयार करने की आवश्यकता है ताकि राज्य स्तरीय संचालन समिति से अनुमोदन के बाद बागवानी विकसित करने के लिए कार्यवाही हो।

निदेशक, उद्यान ने उपबंधों का उल्लंघन करते हुए, लाभार्थियों की पहचान हेतु आधारभूत सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करके बागवानी विकास के सभी पहलुओं को एकीकृत कर परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं किया था। इसके स्थान पर विभाग द्वारा सचल दल केन्द्रों से प्राप्त सूचना के

[53] मिशन I (अनुसंधान), II (उत्पादन एवं उत्पादकता सुधार), III (उत्तर फसल प्रबंधन, विपणन एवं निर्यात) एवं IV (खाद्य प्रसंस्करण इकाई)।

आधार पर, मिशन II के अवयवों को शामिल कर ही वार्षिक कार्ययोजना तैयार की गयी थी तथा इसलिए, अन्य मिनी मिशन राज्य स्तर पर असंबोधित रह गये थे।

इसे इंगित किये जाने पर नोडल अधिकारी, बागवानी मिशन ने कहा (अगस्त 2012) कि विभाग ने उपयुक्त अभिकरण की अनुपलब्धता के कारण आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तथापि, प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि विस्तृत आधारभूत सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराया जा रहा है जो कि फरवरी 2013 तक पूर्ण हो जायेगा। उत्पादन के आँकड़े योजना बनाने एवं उत्तर फसल प्रबंधन, विपणन एवं प्रसंस्करण में आधारभूत संरचना की स्थापना में सहायक होंगे।

(ii) तकनीकी सहायक समूह का गठन

उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य के बागवानी मिशन के परिचालन दिशानिर्देश, 2004 (2010 में संशोधित) के प्रस्तर 5.4.1 के अनुसार विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए तकनीकी व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों को शामिल कर एक तकनीकी सहायता समूह का गठन करना चाहिए जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभाग को राय देने, कार्यक्रम को प्रकियाबद्ध करने, मूल्याँकन करने में सक्षमता प्रदान करेगी।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि निदेशक, उद्यान ने बागवानी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता समूह का गठन नहीं किया गया था।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया (अगस्त 2012) कि तकनीकी सहायता समूह के गठन की स्वीकृति शासन स्तर पर लम्बित है। तथापि, प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी में कहा (दिसम्बर 2012) कि विभाग के पास पर्याप्त विशेषज्ञ थे। उन्होंने यह भी बताया कि नोडल अधिकारी, एच एम एन इ एच को विशेषज्ञ के रूप में तैनात किया गया था एवं यदि आवश्यक हुआ तो अन्य को नियुक्त किया जायेगा।

2.13.9.2 आधुनिक तकनीकी का उपयोग न करना

निदेशक उद्यान ने मिशन 2004 के परिचालन दिशा निर्देश के अनुच्छेद 13.15 में निहित प्रावधानों के उल्लघंन करके एक यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य कार्ययोजना तैयार करने, जिसमें मूल्याँकन के लिए बागवानी फसलों के उत्पादन का पुर्वानुमान शामिल हो, के उद्देश्य के लिए उत्पादन के पुर्वानुमान के आकलन एवं मौसम संबधित आँकड़ो की प्राप्ति के लिए मौसम विभाग (मौ वि) और रिमोट सेसिंग एजेन्सी के साथ कोई सहयोग नहीं किया था और इसलिए उत्पादन पुर्वानुमान एवं स्थान के संबधित आँकड़े वार्षिक कार्य योजना में शामिल नहीं कर सका था।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि मौसम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़े सामान्य प्रकृति के थे जो बागवानी के विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति नहीं किए। हालाँकि, उन्होंने यह भी कहा कि मौसम के मानकों पर आधारित औद्यानिक फसलों में होने वाले रोगों के पूर्वानुमान के लिए रोग पूर्वानुमान इकाई/ मौसम स्टेशन की स्थापना गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर और उद्यान विश्वविद्यालय, भरसार में की जा रही थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि रीमोट सेन्सिंग आँकड़ो के प्रयोग से बारहमासी औद्यानिक फसलों से सबंधित उत्पादन पूर्वानुमान का मूल्याँकन संभव नहीं था।

2.13.9.3 ई-गवर्नेंस का उपयोग न करना

उत्तराखण्ड सरकार ने कुशल, सेवा उन्मुख, लागत प्रभावी एवं पर्यावरण के प्रति सजग सूचना नेटवर्क के माध्यम से एक आदर्श ई-समाज बनाने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पूरी शक्ति का दोहन करने के लिए अगस्त 2006 में आई टी नीति को अपनाया था। राज्य में क्रियान्वित किये जा रहे बागवानी का एक मुख्य कार्यक्रम-एच एम एन इ एच के दिशानिर्देशों में भी परिकल्पित है कि राज्य में बागवानी से सबंधित सभी जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु अन्य विभागों, मंत्रालयों एवं संगठन के साथ लिकेंज की स्थापना करने के लिए और योजना शुरू होने के छः मास के भीतर परियोजनाओं, लाभार्थियों से संबधित जानकारी की आनलाईन उपलब्धता को, प्राप्त करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रावधान करना है। योजना ने यह भी परिकल्पित किया कि राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित सामुदायिक सूचना केन्द्र के साथ लिंकेज को स्थापित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने जनता को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु न तो आइ टी नीति ही अपनायी और ना ही कोई बेबसाइट बनायी थी जबकि इस हेतु वर्ष 2010-11 में एच एम एन इ एच में ₹ 14.00 लाख की धनराशि उपलब्ध थी।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि सीमित ब्राडबैण्ड संयोजकता एवं राज्य डाटा केन्द्र का पूर्ण न होना इसके मुख्य अवरोधक रहे तथा उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार द्वारा मोबाईल आधारित पैकेज पर विचार किया जा रहा है।

2.13.9.4 शासी निकाय की बैठक आयोजित न किया जाना

एच आर डी आई के प्रशासनिक मामलों में नीतिगत निर्णय लिये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार के गजट नोटिफिकेशन (असाधारण) (मार्च 2003) के द्वारा प्रमुख सचिव और आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा की अध्यक्षता में शासी निकाय का गठन किये जाने का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने कहा (मई 2004) कि विभाग को प्रत्येक चार माह के अन्तराल पर शासी निकास की बैठक बुलानी चाहिए।

लेखा परीक्षा की जाँच में पाया गया कि शासी निकाय जनवरी 2004 से मार्च 2012 तक 25 बैठकों के प्रावधानों के विपरीत केवल छः बैठकें ही आयोजित कर सका था। इसके अलावा वैज्ञानिक, प्रशासनिक स्टाफ की कमी एवं वर्ष 2009 में एम ए पी क्षेत्र के पुनर्गठन के कारण बैठकें नहीं हुई थी। इसने संस्थान से जुड़े मामले में निर्धारित समय पर निर्णय लिये जाने को कुप्रभावित किया जिसके कारण संस्थान के कार्यकलापों एवं बजट में प्रगति धीमी रही। प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड (एस एम पी बी) के रूप में एक वृहत् संरचना के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु शासी निकाय का विघटन (मार्च, 2011) कर दिया गया था तथा इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

इस प्रकार, शासी निकाय की बैठक आयोजित न होने से संस्थान के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.13.10 वित्तीय प्रबंधन

उचित वित्तीय प्रबंधन में आवश्कताओं के वास्तविक आकलन के आधार पर निधियों का आवंटन तथा उपलब्ध निधि का प्रभावी उपयोग शामिल होता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि क्रियात्मक गतिविधियाँ

निधियों की कमी से प्रभावित नहीं होगीं। लेखा परीक्षा में राज्य एवं केन्द्रीय निधियों का कुप्रबंधन पाया गया जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया गया है।

सभी निदेशालयों द्वारा वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में राज्य बजट तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत संसाधनों और उनके उपयोग का विवरण नीचे **तालिका 2.13.1 (क)** तथा **तालिका 2.13.1 (ख)** में दिया गया है:

तालिका संख्या 2.13.1 (क)

निधियों के स्त्रोत

(₹ करोड़ में)

बजट के अन्तर्गत प्राप्ति का शीर्षक	विभाग का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
वेतन एवं मजदूरी	उद्यान		31.00	42.42	46.59	61.84	57.73	**239.58**
	रेशम		3.00	4.18	4.21	4.72	5.48	**21.59**
	भेषज		1.71	2.55	1.93	2.28	2.56	**11.03**
वेतन एवं मजदूरी का योग			**35.71**	**49.15**	**52.73**	**68.84**	**65.77**	**272.20**
प्रशासन	उद्यान		7.04	6.95	5.16	5.07	6.97	**31.19**
	रेशम		0.81	1.10	0.74	0.60	0.60	**3.85**
	भेषज		0.46	0.44	0.36	0.34	0.36	**1.96**
प्रशासन का योग			**8.31**	**8.49**	**6.26**	**6.01**	**7.93**	**37.00**
केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	उद्यान		28.40	20.00	20.76	29.00	39.00	**137.16**
	रेशम	0.04	1.53	0.73	5.00	8.08	7.62	**23.00**
	स्वायत्तशासी निकाय	1.25	2.46	4.38	4.42	12.28	4.29	**29.08**
केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-योग		**1.29**	**32.39**	**25.11**	**30.18**	**49.36**	**50.91**	**189.24**
राज्य प्रायोजित योजनाएँ	उद्यान		38.93	33.35	33.48	18.85	22.29	**146.90**
	रेशम		4.43	2.88	2.67	2.65	2.66	**15.29**
	भेषज		2.57	2.76	1.07	1.79	0.85	**9.04**
राज्य प्रायोजित योजनाएँ-योग			**45.93**	**38.99**	**37.22**	**23.29**	**25.80**	**171.23**
महायोग		**1.29**	**122.34**	**121.74**	**126.39**	**147.5**	**150.41**	**669.67**

स्रोतः-विभाग के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

तालिका 2.13.1 (ख)

निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

व्यय का शीर्षक	विभाग का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग	अन्तिम अवशेष
वेतन एवं मजदूरी	उद्यान	31.00	42.43	46.59	61.84	57.73	**239.59**	
	रेशम	2.66	3.76	4.16	4.71	4.96	**20.25**	
	भेषज	1.26	1.73	1.93	2.24	2.28	**9.44**	
वेतन एवं मजदूरी का योग		**34.92**	**47.92**	**52.68**	**68.79**	**64.97**	**269.28**	
प्रशासन	उद्यान	7.04	6.95	5.16	5.06	6.97	**31.18**	
	रेशम	0.72	0.97	0.65	0.58	0.54	**3.46**	
	भेषज	0.32	0.40	0.34	0.33	0.36	**1.75**	
प्रशासन का योग		**8.08**	**8.32**	**6.15**	**5.97**	**7.87**	**36.39**	

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	उद्यान	28.40	20.00	19.83	16.23	16.93	**101.39**	**35.77**
	रेशम	0.54	1.42	3.73	5.87	6.28	**17.84**	**5.16**
	स्वायत्तशासी निकाय	2.02	1.43	1.60	6.98	9.07	**21.10**	**7.98**
केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-योग		**30.96**	**22.85**	**25.16**	**29.08**	**32.28**	**140.33**	**48.91**
राज्य प्रायोजित योजनाएँ	उद्यान	38.93	33.35	33.48	18.85	22.29	**146.90**	
	रेशम	4.26	2.73	2.66	2.64	2.56	**14.85**	
	भेषज	1.99	2.70	1.05	1.64	0.75	**8.13**	
राज्य प्रायोजित योजनाएँ-योग		**45.18**	**38.78**	**37.19**	**23.13**	**25.60**	**169.88**	
महायोग		**119.14**	**117.87**	**121.18**	**126.97**	**130.72**	**615.88**	**48.91**

स्रोतः-विभाग के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना

नोटः स्वायत्तशासी निकायों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, सगंध पौधा केन्द्र तथा उत्तराखण्ड चाय बोर्ड शामिल हैं। उद्यान विभाग के राज्य बजट में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, सगंध पौधा केन्द्र तथा उत्तराखण्ड चाय बोर्ड का बजट भी शामिल है।

संसाधनों एवं उनके अनुप्रयोग के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य उदघाटित हुए:

- आयोजनेत्तर[54] मदों के अन्तर्गत व्यय प्रगामी रूप से वर्ष 2007-08 के 49 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 74 *प्रतिशत* हो गया था जबकि इसी अवधि में विभाग का आयोजनागत व्यय अननुपातिक रूप से 51 *प्रतिशत* से घटकर 26 *प्रतिशत* हो गया था।
- यह भी देखा गया कि विकासात्मक कार्यों के लिए राज्य का निधीयन वर्ष 2007-08 में 59 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2011-12 में 34 *प्रतिशत* हो गया जबकि इसी अवधि में केन्द्रीय निधीयन 41 *प्रतिशत* से बढ़कर 66 *प्रतिशत* हो गया।

इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन के कुछ अन्य बिन्दुओं का विवरण नीचे दिया गया है।

2.13.10.1 ₹ 48.91 करोड़ की धनराशि का उपयोग न हो पाना

विभाग वर्ष 2007-12 की अवधि में केन्द्र द्वारा निर्गत कुल धनराशि ₹ 189.24 करोड़ (पूर्व प्रारम्भिक अवशेष सहित) में से केवल ₹ 140.33 करोड़ व्यय कर सका, जिसके कारण प्रारम्भिक अवशेष ₹ 1.29 करोड़ से बढ़कर ₹ 48.91 करोड़ हो गया तथा परिणामस्वरूप 26 *प्रतिशत* तक निधियों की बचत हुई।

यह भी देखा गया कि निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में निधियों के उपयोग में वर्ष 2009-12 की अवधि में वार्षिक कार्ययोजना के धीमे क्रियान्वयन के कारण 95 *प्रतिशत* से लेकर 32 *प्रतिशत* तक की गिरावट[55] आयी। आगे, 'उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन' के अन्तर्गत उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के 26 *प्रतिशत* का उपयोग नहीं किया जा सका जिससे वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन अगले वित्तीय वर्षों में भी जारी रहा।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि केन्द्रीय निधियों के कम उपयोग का मुख्य कारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 में निर्धारित किये गये

[54] वेतन एवं मजदूरी तथा प्रशासन।

[55] कृपया तालिका 2.13.1 (ख) की कतार संख्या 9 देखें।

कठोर नियमों के पालन से निधियों के निर्गत करने में होने वाला प्रक्रियागत विलंब, वर्ष 2007-12 की अवधि में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्षों के बिल्कुल अन्त में निधियाँ निर्गत किया जाना तथा राज्य में गुणवत्तायुक्त पौध रोपण सामग्री का अभाव था। तथापि, उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में निधियों के उपयोग में अत्यधिक सुधार आया है।

2.13.10.2 उत्तराखण्ड स्मॉल फारमर्स ऐग्री-बिजनेस कन्सोर्टियम (यू एस एफ ए सी) द्वारा निधियों का प्रतिधारण

यू एस एफ ए सी, उद्यान विभाग, प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला उद्यान अधिकारियों को निधि अवमुक्त किये जाने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया कि जनवरी 2007 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान यू एस एफ ए सी द्वारा 19 अवसरो में से 13 अवसरों पर ₹ एक करोड़ से ₹ 15 करोड़ तक की धनराशि को 11 दिन से 86 दिन तक की देरी से निर्गत किया गया था और परिणामस्वरूप यू एस एफ ए सी ने मार्च 2007 से मार्च 2012 तक ₹ 0.67 करोड़ से ₹ 5.01 करोड़ का प्रतिधारण किया।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि निधियों के देरी से अवमुक्त किये जाने का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल एवं राज्य में होने वाले चुनाव रहे। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियाँ अवमुक्त करने, जिला स्तर पर अव्ययित धनराशि और जनपदों से कम माँग को भी इसका कारण बताया। तथापि, उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में धनराशि निर्गत करने की समय सीमा का पालन किया जायेगा।

2.13.10.3 ₹ 2.70 करोड़ के विभागीय प्राप्तियों की वसूली लम्बित रहना

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -v, (भाग-I) के अनुच्छेद 86 के अनुसार शासकीय प्राप्तियाँ नियमित रूप से वसूल करके राजकोष में जमा की जानी चाहिए एवं उन्हें सम्यक् रूप से विभागीय लेखे में अंकित किया जाना चाहिए।

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बगीचों/ पौधालयों में उत्पादित पौध रोपण सामग्री को जिला उद्यान अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत उद्यान सचल दलों के माध्यम से उद्यानपतियों को विक्रय करता था।

लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया कि विभाग ने कुल 23 विभागीय कार्यालयों में से 18 विभागीय कार्यालयों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों को ₹ 2.70 करोड़ मूल्य की पौध रोपण सामग्री (फलदार पौधे, सब्जी बीज, आलू बीज तथा शोभादार पौधे) का विक्रय किया था परन्तु जिला स्तरीय कार्यालयों की उदासीनता के चलते उनसे मूल्य वसूल नहीं किया जा सका। पुनः यह भी पाया गया कि वर्ष 2007-08 के अन्त में कुल वसूली योग्य धनराशि ₹ 2.42 करोड़ थी जो कि मार्च 2012 में बढ़कर ₹ 2.70 करोड़ हो गयी थी।

इसे इंगित किये जाने पर प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में प्राप्तियों की वसूली न होने के मामले को गम्भीर चिन्ता का विषय बताया तथा निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को वसूली तेज करने का आदेश दिया।

2.13.10.4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की निधि का कुप्रबंधन

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में प्रारंभ की गयी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) शत-*प्रतिशत* केन्द्र पोषित योजना है। इसका लक्ष्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करके कृषि क्षेत्र में चार *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है।

भारत सरकार ने आर के वी वाई के अंतर्गत 'सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट ऐज ए ड्राट कम्पेन्सेटरी प्लॉन' के लिए ₹ 3.76 करोड़ स्वीकृत किये (सितम्बर 2009)। 2.13 लाख किसानों को रबी के मौसम (बुवाई का समय अक्टूबर से दिसम्बर तक) में निःशुल्क बीज मिनी किट के वितरण द्वारा लाभान्वित करना योजना की परिकल्पित था ताकि वर्ष 2009-10 के खरीफ के मौसम (बुवाई का समय जून से जुलाई तक) में वर्षा की कमी से होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई की जा सके।

लेखापरीक्षा की जाँच में प्रकट हुआ कि विभाग ने इस योजना की धनराशि का कुप्रबंधन किया जैसा कि निम्नांकित प्रस्तरों में बताया गया हैः

(i) राज्य सरकार द्वारा ₹ 3.76 करोड़ की निधि का विलम्बित निर्गमन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने (सितम्बर 2009) के पश्चात ₹ 3.76 करोड़ की राशि को निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को निर्गत करने (फरवरी 2010) में चार माह से अधिक समय ले लिया। शासन स्तर पर होने वाले इस विलम्ब से योजना के उद्देश्य ही असफल हो गये क्योंकि रबी का मौसम (बुवाई का समय अक्टूबर से दिसम्बर तक) पहले ही समाप्त हो गया था। ₹ 3.42 करोड मूल्य के बीज क्रय किये गये (2010-11) और उन्हें किसानों को वितरित करने हेतु अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक जिला उद्यान अधिकारियों को आपूर्ति कर दिया गया। इस प्रकार बीज सहायता किसानों को लक्षित समय से सात माह से अठारह माह तक के विलम्ब से प्राप्त हुई जिससे सूखाग्रस्त किसान समय पर सहायता से वंचित रह गये।

इसे इंगित किये जाने पर प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में स्वीकार किया कि धनराशि के निर्गत करने में हुए विलम्ब से सूखाग्रस्त किसान समय पर क्षतिपूरक सहायता से वंचित रह गये तथा उन्होंने इसे कर्मचारियों की कमी से सम्बद्ध किया।

(ii) ₹ 2.20 करोड़ की धनराशि का व्ययावर्तन

₹ 3.76 करोड़ की कुल लागत वाली इस योजना का उद्देश्य 2.13 लाख किसानों को ₹ 3.12 करोड़ के मटर, बीन्स तथा मिश्रित सब्जियों के बीजों के मिनीकिट निःशुल्क उपलब्ध करवा कर उन्हें लाभान्वित करना था। इन सब्जी बीजों के साथ ₹ 49.10 लाख[56] मूल्य की खाद तथा कीटनाशक भी वितरित किये जाने थे ताकि बीजों का उचित जमाव, विकास तथा अधिक उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने केवल ₹ 1.22 करोड़ मूल्य के सब्जी बीज क्रय किये (अप्रैल-जून, 2010)। सचिव, उद्यान ने उक्त धनराशि में से ₹ 2.20 करोड़[57] हल्दी, अदरक तथा लहसुन के क्रय हेतु, इस

---

[56] क्रमशः ₹ 18.55 लाख तथा ₹ 30.55 लाख।

[57] हल्दी- ₹ 31.31 लाख, अदरक- ₹ 162.84 लाख तथा लहसुन- ₹ 25.93 लाख।

तथ्य के बावजूद कि यह चीजें योजना के प्रस्ताव में शामिल नहीं थीं, व्ययावर्तित कर दिये (जनवरी 2011)। शेष बची धनराशि में से ₹ एक लाख प्रशासनिक मदों पर व्यय किया गया तथा ₹ 33 लाख अभ्यर्पित कर दिये गये।

इस परियोजना में से उक्त मसाला बीजों का क्रय इस तथ्य के बावजूद किया गया कि मसाला बीजों के लिए 'सीड असिस्टैंस टू वेजेटेबल एण्ड स्पाइस फॉर्मर्स' के रूप में आर के वी वाई की स्ट्रीम-II के अंतर्गत एक अन्य योजना स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन थी, जिसे भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2011 में स्वीकृत कर लिया गया। आर के वी वाई के दिशा निर्देशों में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गतिविधियों का परस्पर व्यापन (ओवरलैपिंग) नहीं होना चाहिए। विभाग ने खाद तथा कीटनाशकों का क्रय न करके सब्जी बीजों के क्रय में किये गये सम्पूर्ण निवेश को भी असुरक्षित कर दिया।

शासन का उत्तर प्रतीक्षित था। (जनवरी 2013)

(iii) किसानों से ₹ 1.36 करोड़ की अनियमित वसूली

निदेशक, उद्यान के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि सभी जिला उद्यान अधिकारियों[58] ने किसानों, जिनको इस योजना के अन्तर्गत बीज वितरित किया गया था, से बीजों की लागत का 25 *प्रतिशत* (मई 2010 से अक्टूबर 2010 तक) तथा 50 *प्रतिशत* (अक्टूबर 2010 से आगे) वसूल किया था। 31 जुलाई 2012 तक कुल ₹ 1.36 करोड़ की धनराशि वसूल की गयी थी। यह धनराशि किसानों से इस तथ्य के बावजूद वसूल की गयी कि वर्षा के अभाव से उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित हुई थी तथा यह योजना वर्षा की कमी से उत्पन्न गम्भीर आर्थिक प्रभावों से उनको बचाने के लिए ही बनायी गयी थी। यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना के शर्तों तथा भावना के प्रतिकूल था जिसमें प्रावधानित है कि बीज निःशुल्क वितरित किये जायेंगे।

पुनः, जाँच से यह प्रकट हुआ कि जिला उद्यान अधिकारियों ने वसूल की गयी धनराशि अनियमित रूप से खोले गये बैक खातों में जमा कर दी थी। उन्होंने कुल वसूल धनराशि ₹ 1.36 करोड़ में से ₹ 0.54 करोड़ विभिन्न बीजों के क्रय पर व्यय कर दिये थे। बैकों में धनराशि का इस प्रकार से रखा जाना तथा तत्पश्चात व्यय किया जाना वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-V के भाग-I की अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का उल्लंघन था जिसमें नियत किया गया था कि सभी प्राप्त धनराशियाँ पूरी की पूरी कोषागार में जमा की जानी चाहिए और उन्हें विभागीय व्यय के लिए विनियोजित नहीं किया जाना चाहिए।

विभाग किसानों के हितों को संरक्षित करने में असफल रहा जो कि योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसने न केवल पूर्वोक्त नियम का उल्लंघन किया बल्कि अनियमित रूप से वसूल की गयी उक्त धनराशि को शासकीय खाते से बाहर रखकर तथा विधायिका की अनुमति के बिना उसमें से ₹ 54.02 लाख व्यय करके विधायिका के प्राधिकार का हनन भी किया।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में तथ्यों को स्वीकार किया और इसे गम्भीर मामला बताया। उन्होंने लेखा परीक्षा को आश्वासन दिया कि मामले की जाँच की जायेगी।

---

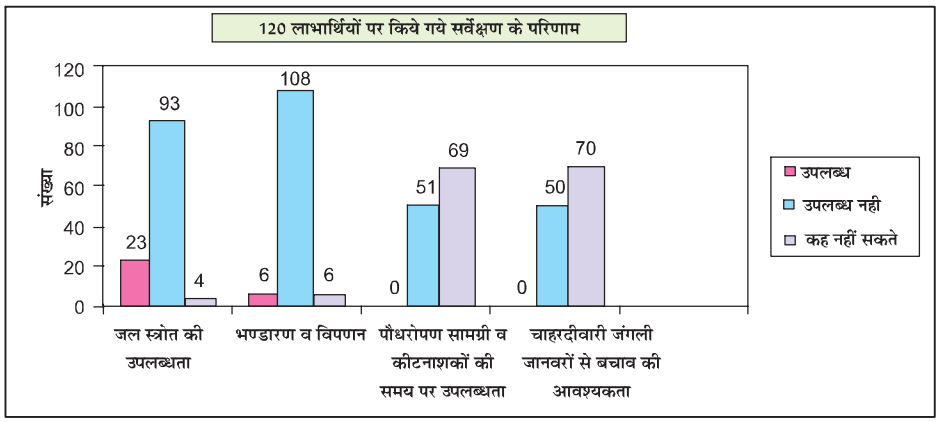
[58] जिला उद्यान अधिकारी, उधमसिंह नगर एवं जिला उद्यान अधिकारी, हरिद्वार को छोड़कर।

2.13.11 अनुपालन/औचित्य लेखापरीक्षा

2.13.11.1 लाभार्थी सर्वेक्षण

कृषकों को वास्तविक लाभ का पता लगाने के प्रयास में लेखापरीक्षा ने आन्तरिक रूप से तैयार प्रश्नावली पर आधारित चार जिलो के 108 सचल दल केन्द्रों में से 12 नमूना सचल दल केन्द्रों (11 *प्रतिशत*) के कार्य क्षेत्र से 120 उद्यानपतियों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया था। इस प्रक्रिया के दौरान लेखापरीक्षा दल के साथ एक विभागीय प्रतिनिधि हमेशा उपस्थित था। सर्वेक्षण का परिणाम **चार्ट -2** में दिया गया है।

चार्ट-2



- तिरानवे उद्यानपति (77.5 *प्रतिशत*) सिंचाई सुविधा की कमी से ग्रसित थे।
- एक सौ आठ उद्यानपतियों (90 *प्रतिशत*) को अपने औद्यानिक उत्पादन के भण्डारण एवं विपणन सुविधा सुलभ नहीं थी।
- इक्यावन उद्यानपति (43 *प्रतिशत*), विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी अन्तर्विष्ट सामग्री की गुणवत्ता एवं बोने की अवधि के बाद आपूर्त पौध रोपण सामग्री/बीज से संतुष्ट नहीं थे।
- पचास उद्यानपतियों (42 *प्रतिशत*) ने जंगली जानवरों से उद्यान नुकसान को रोकने के लिए घेरबाड़ की सुविधा चाही थी।

अनुवर्ती प्रस्तरो में इन कमियों के प्रभाव की विवेचना की गयी है।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में लाभार्थी सर्वेक्षण की प्रशंसा की थी और कहा कि सरकार के पास सीमित संसाधनों के कारण उद्यानपतियों की सभी माँगों को पूर्ण किया जाना संभव नहीं था।

2.13.11.2 *भेषज संघों द्वारा संचालित पौधशालाओं पर ₹ 8.45 लाख की हानि*

भेषज सहकारी संघ भेषज विकास इकाई, देहरादून के द्वारा पंजीकृत किये जाते हैं। उन्हें विभिन्न गतिविधियों, जिसमें विभिन्न औषधीय पौधों के कृषिकरण के लिए भेषज विकास इकाई को आवश्यक पौध रोपण सामग्री के

उत्पादन के लिए पौधशालाओं का परिचालन भी शामिल है, के लिए जिला योजना के अंतर्गत भेषज विकास इकाई से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

जिन जिलों[59] में नमूना लेखापरीक्षा की गयी उनमें परीक्षण की अवधि (अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक) में पौधशालाओं पर व्यय की गयी राशि तथा भेषज विकास इकाई को पौध विक्रय से हुई आय का विवरण **तालिका 2.13.2** में दिया गया है:

तालिका -2.13.2 *(धनराशि ₹ में)*

वर्ष / जनपद	पौधशालाओं की संख्या	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		पौधशालाओं पर व्यय	उत्पादन से आय	पौधशालाओं पर व्यय	उत्पादन से आय	पौधशालाओं पर व्यय	उत्पादन से आय	पौधशालाओं पर व्यय	उत्पादन से आय	पौधशालाओं पर व्यय	उत्पादन से आय
अल्मोड़ा	1	0	0	0	0	0	0	22725	0	35600	16212
चमोली	2	26430	0	180835	6600	43508	10000	21545	0	70590	0
देहरादून	1	22165	10650	41245	0	35191	1040	41548	2100	43745	58943
टिहरी	1	170620	0	48714	4500	41000	1800	56000	300	56000	300
योग		**219215**	**10650**	**270794**	**11100**	**119699**	**12840**	**141818**	**2400**	**205935**	**75455**

स्रोतः विभाग के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 की अवधि में इन पौधशालाओं में उत्पादित पौध रोपण सामग्री के विक्रय से प्राप्त आय इन पर हुए कुल व्यय के 1.70 *प्रतिशत* से 36.64 *प्रतिशत* के मध्य रही। भेषज संघों को वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में व्यय किये गये धनराशि के सापेक्ष 60.44 *प्रतिशत* से 98.14 *प्रतिशत* तक का भारी नुकसान हुआ। उन्हें इन पाँच वर्षों में कुल ₹ 8.45 लाख का नुकसान हुआ जो कि पौधशालाओं पर हुए कुल व्यय का 88.26 *प्रतिशत* था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भेषज संघों ने निर्माण कार्यों, पौधशालाओं की भूमि के लीज किराये तथा रक्षकों के वेतन आदि पर व्यय किया परंतु प्रत्येक वर्ष बीज बोने में असफल रहे। भेषज संघ, चमोली एवं टिहरी ने पाँच वर्षों की अवधि में केवल एक बार बीज बोया जबकि भेषज संघ, देहरादून ने वर्ष 2009-10 में बीज नहीं बोया। इसी प्रकार भेषज संघ, टिहरी ने भेषज विकास इकाई को वर्ष 2007-08 से 2010-11 के मध्य ₹ 15.51 लाख के पौधे बाजार से उपलब्ध करवाये। भेषज संघ उत्पादित पौधों का विक्रय करने के लिए भी अनिच्छुक थे। इस प्रकार, उपरोक्त वर्णन के अनुसार, अनुत्पादक कार्यों पर किये गये व्यय, बीजों के न बोने तथा उत्पादित पौधों के विक्रय न करने से सभी पौधशालाओं में लागतों की वसूली नहीं हो पायी जिसके परिणामस्वरूप यह हानि हुई।

उत्पादन तथा विक्रय का मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमास प्राप्त होने के बावजूद भेषज इकाई ने कभी भी इस योजना के अंतर्गत निष्पादन की समीक्षा नहीं की विभाग की इस असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 8.45 लाख की लागतों की वसूली नहीं हो पायी (2007-08 से 2011-12) जिससे लोकधन की हानि हुई।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि बीजों का बोना तथा पौधों का विक्रय बाजार की माँग पर निर्भर था अतः किसी विशेष वर्ष में बीज बोना तथा पौधों का विक्रय करना आवश्यक नहीं था।

[59] हरिद्वार को छोड़कर, जहाँ जिला भेषज विकास अधिकारी अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सके।

यह उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि भेषज संघ चमोली तथा टिहरी ने पाँच वर्षों में से चार वर्षों में बीज नहीं बोये लेकिन फिर भी अनुत्पादक गतिविधियों पर व्यय किया जिससे यह हानि हुई। इसी प्रकार 2007-08 से 2011-12 की अवधि में भेषज विकास इकाई ने सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों को वितरण के लिए ₹ 1.12 करोड़ की पौध का क्रय किया जो कि शासन के उक्त उत्तर का विरोधाभासी है जिसमें कहा गया था कि बाजार में कम माँग होना बीज न बोने का कारण हो सकता है।

2.13.11.3 अनुसंधान एवं विकास का अभाव

जड़ी बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान (ज बू अ वि सं) का उद्देश्य उत्तराखण्ड की लुप्त हो रही जड़ी-बूटी का सर्वेक्षण, संरक्षण, पुनरूत्पादन एवं कृषिकरण करना है। राज्य सरकार ने (सितम्बर 2006) विभिन्न जड़ी-बूटी के 47 एवं 16 प्रजातियों को क्रमशः लुप्तप्रायः एवं वहनीय ज बू अ वि सं की विदोहन योग्य श्रेणी में वर्गीकृत किया था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसे आयुर्वेद एव यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा बनाया (1989) गया था, की परिकल्पना के अनुसार संस्थान को नवीनतम अनुसंधान एवं विकास संबधित सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित करना था ताकि हर्बोनोमी के सिद्धांत पर आधारित निम्नलिखित प्रयोगशाला सुविधाओं से वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाए।

- फार्माकॉगनोसी प्रयोगशाला का संबंध जड़ी बूटी से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी वैज्ञानिक विधि से संग्रहीत करना है जिससे संग्रहकर्ता द्वारा जड़ी-बूटी की पहचान की जा सके।
- फार्माशीड प्रयोगशाला का संबंध वैज्ञानिक विधि से बीजों का संरक्षण करना है।
- फाइटोकेमेस्ट्री प्रयोगशाला का संबंध पौधों का रासायनिक विश्लेषण करना है।
- फार्माकॉलोजी प्रयोगशाला का संबंध पौधों के विभिन्न हिस्सों का मानव शरीर पर प्रभाव का अध्ययन करना है।
- माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला का संबंध पौधों के प्रत्येक अंगों का सूक्ष्म जैविक अध्ययन करना है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ज बू अ वि सं, प्रोजेक्ट प्रतिवेदन के प्रतिकूल स्वयं को प्रयोगशाला सुविधाओं से सुसज्जित नहीं कर सका और उसने पौधालय आधारित 48 वनस्पति अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप संचालित किए। पुनः संस्थान ने 2010-11 में फाइटोकेमेस्ट्री प्रयोगशाला की स्थापना के बाद 13 अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जो कि पौधों के रासायनिक विश्लेषण पर आधारित थे। इसके अलावा यह देखा गया था कि ज बू अ वि सं अपनी स्थापना (1989) से लेकर सीमित मानव शक्ति के कारण 63 दुर्लभ एवं लुप्त हो रहे जड़ी बूटियों, में से केवल पाँच[60] जड़ी बूटियों को ही संरक्षण, पुनरूत्पादन एवं कृषिकरण के लिए प्रोत्साहित कर सका।

इसके अतिरिक्त, ज बू अ वि सं ने स्वयं को सर्वेक्षण कार्य, पारम्परिक ज्ञान का अभिलेखीकरण, क्षेत्र विस्तार कार्यकलाप एवं पौधों का संग्रहण पर आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्य तक ही सीमित रखा था जो प्रयोगशाला जाँच के बिना अपूर्ण था।

इसे इंगित किए जाने पर, निदेशक, ज बू अ वि सं ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2012) और कहा कि इसका अधिदेश शेष चार सुविधाओं को स्थापित किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था तथा यह भी कहा कि वैज्ञानिक कार्मिकों की कम मानव शक्ति भी इसका मुख्य कारण था। निदेशक, ज बू अ वि सं ने यह भी कहा कि संस्थान के पास अधिकतर हिमालयी लुप्त प्रजाति के विस्तार संबंधित कृषिकरण प्रोटोकॉल नहीं था।

[60] अतीस, कुटकी, कूट, तगर एवं सर्पगन्धा।

तथापि, प्रमुख सचिव, उद्यान ने भी प्रस्थान गोष्ठी के दौरान (दिसम्बर 2012) आश्वासन दिया कि जड़ी बूटियों के सभी लुप्तप्रायः प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किये जाएंगे।

2.13.11.4 उत्तराखण्ड चाय बोर्ड, अल्मोड़ा का कार्यचालन

उत्तराखण्ड में चाय उत्पादन अल्मोड़ा में वर्ष 1835 में चाय पौध रोपण के बाद शुरू किया गया था। राज्य में चाय कृषिकरण प्रक्षेत्र वर्ष 1880 के 4426 हैक्टेयर से बढ़कर वर्ष 1950 में 8800 हैक्टेयर हो गया था। वर्तमान में जून 2012 तक चाय की खेती 752 हैक्टेयर क्षेत्रफल में होती है।

चाय की खेती के अस्तित्व को देखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के पर्वतीय विकास विभाग ने उत्तराखण्ड चाय विकास प्रोजेक्ट का सूत्रपात मार्च 1994 में किया था और इसकी जिम्मेदारी कुमाऊँ मण्डल विकास निगम (कु मं वि नि) को दी गयी थी। उद्यान विभाग के पुनर्गठन के दौरान चाय विकास को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के नियंत्रण में दे दिया गया (मई 2001) था। चाय के कृषिकरण में क्रमिक विकास के लिए उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड (उ चा वि बो) के नाम से एक पृथक उपक्रम की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। उ चा वि बो के अभिलेखों की जाँच में निम्न तथ्य पाये गए।

(i) हरी चाय की दर में संशोधन न होने के कारण ₹ 1.17 करोड़ की हानि

कौसानी बगीचा में उत्पादित हरी चाय की पत्तियों को तैयार चाय में बदलने के लिए तत्कालीन कार्यदायी अभिकरण "कु मं वि नि" (प्रथम पक्ष) ने मै0 गिरियास इन्वेस्टमेन्ट प्रा लि (द्वितीय पक्ष) के साथ दिनांक 7 जून 2001 को एक अनुबंध का गठन किया था। यह अनुबंध 25 सालों के लिए विधिमान्य होगा। अनुबंध के अनुसार कम्पनी को हरी चाय की आपूर्ति एवं निर्मित चाय के विपणन के लिए निम्नलिखित शर्तें थीं।

- मेसर्स कौसानी टी कम्पनी प्रा लि या उत्तरांचल टी कम्पनी प्रा लि में से उसके नाम एवं रूप से एक कम्पनी बनायेगा, जो भी नाम प्रथम पक्ष के संयुक्त सहयोग से उपलब्ध होगा।
- तोड़ी गयी हरी पत्ती इकाई मात्रा में *प्रतिशत* पर आधारित मानक के अनुसार कम्पनी को प्रथम पाँच वर्ष में हरी पत्ती क्रय करनी थी। हरी पत्ती के दर का विवरण **तालिका 2.13.3** में निम्नवत हैः

तालिका-2.13.3

एक किलोग्राम तोड़ी गयी पत्तियों में दो पत्तियों एवं एक कली की *प्रतिशतता*	75% एवं अधिक	70% से 74%	65% से 69%	65% से कम
दर प्रति किलो ग्राम	₹ 13/-	₹ 12/-	₹ 11/-	गुणवत्ता *प्रतिशतता* में प्रति 2 *प्रतिशत* की कमी पर दर ₹ 1 प्रति कि ग्रा कम होगा।

सोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना

- देश के दूसरे हिस्सों यथा हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, दोआर, कुन्नूर में हरी पत्ती के प्रचलित बाजार दर के आधार पर दोनो पक्ष के मध्य सहयोग पूर्ण तरीके से हरी पत्ती का मूल्य निर्धारित किया जाना था।



कौसानी चाय बागान में पत्तियों का तुड़ान कार्य (18 जून 2012)

- उ चा वि बो से खरीदी गई हरी चाय पत्ती हेतु कम्पनी को मासिक आधार पर भुगतान करना था, अन्यथा 18 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूली की जानी थी।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि उ चा वि बो अनुबंध में उल्लेखित सहयोगपूर्ण तरीके से हरी पत्ती के मूल्य निर्धारण के प्रावधान के प्रतिकूल, दर को बिना संशोधित किए (जून 2006 में अपेक्षित[61] था) लगातार हरी पत्ती की आपूर्ति पुराने दर पर ही करता रहा। उसने कम्पनी को 10967.53 क्विंटल हरी पत्ती, जिसका मूल्य ₹ 1.26 करोड़ था, की आपूर्ति 2007-12 की अवधि में ₹ 1100 से ₹ 1200 प्रति क्विंटल की औसत दर से की थी। जबकि टी रिसर्च एसोसियसन (टी आर ए) ने वर्ष 2006 में इसके मूल्य ₹ 18 - ₹ 20 प्रति किलोग्राम को वर्ष 2009 में बढ़ाकर ₹ 25-₹ 28 प्रति किलोग्राम कर दिया था, और इस प्रकार, टी आर ए द्वारा अनुसंशित न्यूनतम दर के आधार पर संगणित करने पर उ चा वि बो को 2007-12 की अवधि में ₹ 1.17 करोड़ की हानि हुई।

आपूर्त हरी पत्ती, कम्पनी को बकाया राशि एवं हुई हानि का विवरण **तालिका 2.13.4** में निम्नवत है।

तालिका सं 2.13.4 *(वजन क्विंटल में एव ₹ लाख में)*

वर्ष	आपूर्त हरी पत्ती	प्रति क्विंटल टल औसत दर (₹ मे)	कुल मूल्य	कुल भुगतान	बकाया धनराशि	टी आर ए द्वारा अनुसंशित न्यूनतम दर पर आधारित दर के असंशोधन के कारण हानि		
						न्यूनतम दर (₹ में)	प्राक्कलित मूल्य	उपार्जित हानि
2007-08	2031.56	1140	23.16	12.50	10.66	1800	36.57	13.41
2008-09	2420.72	1158	28.03	26.70	1.33	1800	43.57	15.54
2009-10	1826.20	1061	19.38	20.09	-0.71	2500	45.65	26.27
2010-11	2040.95	1145	23.37	23.38	-0.01	2500	51.02	27.65
2011-12	2648.10	1209	32.02	31.00	1.02	2500	66.20	34.18
योग 2007-12	**10967.53**		**125.96**	**113.67**	**12.29**		**243.01**	**117.05**
योग 2003-12	**16802.93**		**191.04**	**175.10**	**15.94**		**24302207**	**5198482**

सोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि कम्पनी ने अनुबंध के प्रावधानों, जिसमें कि आपूर्त हरी पत्ती का भुगतान मासिक आधार पर करना था, का अनुपालन नहीं किया तथा इसलिए, ₹ 15.94 लाख (मार्च 2012) तक बकाया राशि के रूप में जमा हो गया जिसमें ₹ 3.65 लाख वर्ष 2003-07 के अवधि का था। हरी पत्ती के दर में संशोधन से संबंधित लेखा परीक्षा टिप्पणी के जबाब में उ चा वि बो ने कहा कि कम्पनी के साथ काफी लम्बे समय से चली आ रही संवाद एवं आयोजित बैठकों के बावजूद भी कम्पनी ने दरें नहीं बढ़ायी थीं। इस प्रकार उ चा वि बो द्वारा अनुबंध के नियम एवं शर्तें 6 (जे) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हरी पत्ती के मूल्य के संशोधन के लिए नहीं किया गया जिसके कारण पूर्व की बकाया राशि ₹ 15.94 लाख को मिलाकर ₹ 1.17 करोड़ की हानि हुई।

(ii) ₹ 34.43 लाख मूल्य की हरी पत्ती लागत की वसूली न किया जाना

उ चा वि बो ने अपने बैठक (जनवरी 2006) में चाय फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया और तदनुसार चाय की गुणवत्ता बढ़ाने के दृष्टिगत जैविक हरी पत्ती को तैयार चाय में बदलने के लिए मेसर्स ट्रैम्ब्रोस टी

[61] अनुबंध दिनांक 7.6.2001 के शर्त 6 (जे) के अनुसार अनुबंध के पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद देश के दूसरे हिस्सो में हरी पत्ती के प्रचलित बाजार दर के आधार पर दोनों पार्टियों के मध्य सहयोग पूर्ण तरीके से हरी पत्ती का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इसलिए हरी पत्ती के दर का संशोधन 7, जून 2006 को देय था।

कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली के साथ उसने नौटी एवं चम्पावत में चाय फैक्ट्री लगाने के लिए अनुबंध गठित (21 मार्च 2006) किया था। इसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थीं।

- उ चा वि बो ने नौटी एव चम्पावत चाय बागान में उत्पादित होने वाली सभी हरी पत्ती की बिक्री मेसर्स टी टी सी एल को करनी थी।
- मेसर्स टी टी सी एल द्वारा उ चा वि बो को हरी पत्ती के मूल्य का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना था अन्यथा उ चा वि बो द्वारा 11 *प्रतिशत* वार्षिक दर से ब्याज प्रभारित किया जाना था।
- यह अनुबंध उत्तराखण्ड सरकार को उपर्युक्त क्लॉज में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता था जो कि दोनों पक्षों द्वारा मान्य होनी थीं।

लेखा परीक्षा की जाँच में पाया गया कि उ चा वि बो ने वर्ष 2006-07 से 2011-12 (अप्रैल 2011 तक) के दौरान ₹ 20 प्रति किलोग्राम की दर से ₹ 40.28 लाख मूल्य की 2,01,396.65 किलोग्राम हरी पत्ती की आपूर्ति की थी और कम्पनी द्वारा आपूर्ति के विरूद्ध 18 फरवरी 2010 तक सिर्फ ₹ 13.50 लाख का भुगतान किया गया था।

बगीचावार आपूर्त हरी पत्ती का मूल्य एवं मेसर्स टी टी सी एल द्वारा देय राशि के व्योरे **तालिका 2.13.5** में नीचे दिये गये हैं।

तालिका सं. 2.13.5

वर्ष	उ चा वि बो द्वारा आपूरित जैविक हरी पत्ती (किलोग्राम में)			मेसर्स टी टी सी एल को आपूर्त हरी चाय पत्ती का मूल्य (₹ लाख में)		
	नौटी	चम्पावत	योग	देय	भुगतान	बकाया
2006-07	16002.15	7262.50	23264.65	4.65	3.00	1.65
2007-08	25798.10	13222.00	39020.10	7.81	-	7.81
2008-09	28208.30	16563.00	44771.30	8.95	7.00	1.95
2009-10	19063.00	18512.90	37575.90	7.52	3.50	4.02
2010-11	22463.70	28830.20	51293.90	10.26	-	10.26
2011-12	1912.30	3558.40	5470.70	1.09	-	1.09
योग	**113447.55**	**87949.00**	**201396.55**	**40.28**	**13.50**	**26.78**
उ चा वि बो द्वारा प्रारम्भ में कम्पनी को अन्य व्यय के विरूद्ध भुगतान धनराशि						**2.09**
उ चा वि बो को 11 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से देय दण्ड-ब्याज						**5.56**
कुल योग						**34.43**

सोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

इसी प्रकार, उ चा वि बो ने अनुबंध में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी को आपूर्त हरी पत्ती के विरूद्ध मासिक आधार पर भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया, जिसके कारण बकाया राशि ₹ 28.87 लाख तथा उस पर दण्डात्मक ब्याज की राशि ₹ 5.56 लाख हो गयी थी। इसके अतिरिक्त उ चा वि बो ने अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार भुगतान करने के लिए वर्ष 2009 से पूर्व कोई कार्रवाई भी नहीं की।

जब कम्पनी, बोर्ड की बैठक (अक्टूबर 2009) में आश्वासन देने और बारम्बार अनुस्मारकों के बावजूद, मार्च 2010 तक बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थ रही तब राज्य सरकार ने प्रबन्धकारिणी समिति के परामर्श से (मार्च 2011), अनुबंध के शर्त (ix) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल किया (मार्च 2011) और कम्पनी को कुल बकाया राशि ₹ 34.43 लाख में से ₹ 30.53 लाख का भुगतान 20 अप्रैल 2011 तक करने के लिए नोटिस (अप्रैल 2011) निर्गत करने का निर्णय लिया अन्यथा हरी पत्ती की आपूर्ति रोक दी

जाएगी। तदानुसार, 21 अप्रैल 2011 से कम्पनी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण आपूर्ति रोक दी गयी थी।

इस प्रकार उ चा वि बो अनुबंध को कार्यान्वित नहीं कर सका जिसके कारण बकाया राशि बढ़ गयी थी और ₹ 34.43 लाख की हानि उठानी पड़ी थी। इसके अलावा उ चा वि बो ने चाय बनाने के लिए कोई भी चाय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं की थी जिससे एक साल बाद चाय पत्ती नहीं तोड़ने के कारण चाय पौधों पर दुष्परिणाम होने की संभावना हो सकती थी। निदेशक, उ चा वि बो ने लेखा परीक्षा के तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2012)। उन्होंने यह भी कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2010[62] के रिट याचिका सं 1232(एम/एस), जो कि निरस्त (जुलाई 2012) कर दिया गया था, के आलोक में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया (जुलाई 2010) था, जिसके कारण प्रसंस्करण इकाई की स्थापना नहीं की जा सकी थी। यद्यपि आदेश जुलाई 2012 में दिया जा चुका था, परन्तु उ चा वि बो द्वारा निर्णय की प्रति दिसम्बर 2012 को ही प्राप्त कर पाया था।

इसे इंगित करने पर, प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में आश्वासन दिया कि इस विषय में कार्रवाई की जाएगी तथा विस्तृत जबाब प्रेषित किया जायेगा।

2.13.11.5 उत्तर फसल प्रबन्धन के अन्तर्गत रज्जु मार्गों का निर्माण न होना

राज्य सरकार ने एच एम एन इ एच के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के आठ जिलों में औद्यानिक उत्पाद के विपणन में सरलीकरण के उद्देश्य से सामग्री के उठान के लिए, ₹ 5.67 करोड़ की लागत से गुरूत्व आधारित 31 रज्जु मार्गों के निर्माण के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था (2006-07)। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट की स्वीकृति इस शर्त पर दी (फरवरी 2007) थी कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार निर्माण लागत को 1:2 के अनुपात में साझा करेंगें। भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 1.89 करोड़ (33.33 *प्रतिशत*) की स्वीकृति दी थी और ₹ 94.54 लाख की प्रथम किस्त को निर्गत (फरवरी 2007) किया था।

लेखापरीक्षा की जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार ने ₹ 5.59 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी थी तथा गढ़वाल मण्डल विकास निगम (ग म वि नि) और के एम वी एन को 30 रज्जु मार्गों के निर्माण के लिए अधिकृत किया था। विभाग ने ₹ 94.54 लाख में से ₹ 81.82 लाख (मार्च 2011) के केन्द्रीय सहायता के साथ ही, राज्यांश ₹ 3.73 करोड़ में से प्रथम किस्त के रूप में ₹ 3.55 करोड़ तीन चरणों में निर्गत (दिसम्बर 2007) किया था। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय ने निर्माण कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण, राज्य सरकार से कभी भी शेष केन्द्रीय निधि ₹ 12.72 लाख की माँग नहीं की थी। कार्यदायी संस्थाएँ वर्ष 2006-07 से 30 रज्जु मार्गों में से सिर्फ पाँच[63] का ही निर्माण कर सकी थी। निर्माण कार्य की स्थिति का विवरण **तालिका 2.13.6** में दिया गया है।

---

[62] मेसर्स टी टी सी एल ने उत्तराखण्ड सरकार के आदेश दि0 30 अप्रैल 2010 को रद्द कराने के लिए एक रिट पेटिसन माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी जिसने जुलाई 2012 में पेटीशन को खारिज़ कर दिया परन्तु उ चा वि बो ने इस आदेश को दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया था।

[63] के एम वी एन और जी एम वी एन ने क्रमशः तीन और दो रज्जु मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया था।

तालिका सं. 2.13.6 (₹ लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	रज्जु मार्ग (संख्या में)	का सं	प्रा रा	नि अव	राज्यांश		केन्द्रांश		कार्य पूर्ण होने की स्थिति	
						देय	अवमुक्त	देय	अवमुक्त	पूर्ण	अपूर्ण
1	अल्मोड़ा	03	के एम वी एन	50.07	33.37	33.38	33.37	16.69	0.00	00	03
2	नैनीताल	02		30.09	30.31	20.06	20.06	10.03	10.25	01	01
3	पिथौरागढ़	01		16.51	16.62	11.00	11.00	5.51	5.62	1*	00
4	रूद्रप्रयाग	04	जी एम वी एन	66.82	46.00	44.55	41.22	22.27	4.78	1*	03
5	उत्तरकाशी	12		221.91	177.02	147.95	139.01	73.96	38.01	02	10
6	पौड़ी	01		18.95	12.63	12.63	12.63	6.32	0.00	00	01
7	देहरादून	04		96.44	87.46	64.30	64.30	32.14	23.16	00	04
8	चमोली	03		58.51	33.63	39. 1	33.63	19.50	0.00	00	03
योग		**30**		**559.30**	**437.04**	**372.88**	**355.22**	**186.42**	**81.82**	**05**	**25**

सोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

नोट- का सं-कार्यदायी संस्था, प्रा रा-प्राकलित लागत, नि अव-निधि अवमुक्त

**पूर्ण किन्तु हस्तान्तरित नहीं*

पुनः यह पाया गया कि कार्यदायी संस्थाएँ पाँच निर्मित रज्जु मार्गों में से सिर्फ तीन ही को हस्तांतरित करने में सफल हुई। दो निर्मित रज्जु मार्ग को क्रमशः कुछ कमियाँ एवं वन अनापत्ति न मिलने के कारण हस्तान्तरित नहीं किये जा सके। शेष रज्जु मार्ग या तो दोषपूर्ण निर्माण (आठ) या वन अनापत्ति न मिलने (पाँच) एवं अनुपयुक्त स्थान (12) के कारण मार्च 2012 तक अपूर्ण स्थिति में थे। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने जी एम वी एन को नियत समय पर कार्य पूर्ण न करने के कारण ब्लैक लिस्ट करते हुए, शेष 21 कार्य सिंचाई विभाग(सि वि) को सौंप दिये (दिसम्बर 2010)। तद्नुसार, जी एम वी एन ने अव्ययित धनराशि ₹ 1.91 करोड़ सि वि को स्थानान्तरित कर दी (फरवरी 2011), लेकिन सि वि को सौंपे गए सभी रज्जु मार्ग अभी भी निर्माणाधीन थे।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह पाया गया कि राज्य सरकार निर्माण कार्य की धीमी गति एवं भारत सरकार के बार बार के अनुस्मारकों के बावजूद प्रथम किस्त का गैर-उपयोग के कारण, केन्द्रीय सहायता की अगले किस्तों को प्राप्त नहीं कर सकी।

निदेशक, उद्यान ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2012) कि कार्यदायी संस्थाएँ बार-बार अनुस्मारक के बावजूद रज्जु मार्गों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी नहीं ला सकी। विभाग ने यह भी कहा कि उसे शेष केन्द्रीय सहायता की राशि की जानकारी नहीं थी। पुनः प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में आश्वासन दिया कि योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा।

इस प्रकार विभागीय कुप्रबंधन के कारण, विभाग निधि की उपलब्धता के बावजूद सक्षम उत्तर फसल प्रबंधन के लिए रज्जु मार्ग जैसी आवश्यक अवस्थापना/सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करा सका और केन्द्रीय निधि की अगली किस्तों को भी प्राप्त न कर सका।

2.13.12 क्रियान्वयन

2.13.12.1 अपर्याप्त सिंचाई सुविधा के कारण फल औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत 9417 हैक्टेयर रोपित क्षेत्रफल की क्षति

एच एम एन ई एच दिशानिर्देश छोटे एवं सीमान्त कृषकों को जोखिम कम करने की दृष्टि से वर्तमान बाजार एवं भविष्य की संभावित माँग को पूरा करने के लिए सुधारी हुई किस्मों/दशाओं के अन्तर्गत नए क्षेत्र जोड़कर उत्पादकता में वृद्धि हेतु बागवानी एवं रोपित उत्पादन फसल के क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रावधान करते हैं। पुनश्च, दिशानिर्देश में यह भी प्रावधानित है कि पूरे वर्ष में औद्यानीकरण को सहायता प्रदान करने हेतु व्यक्तियों को प्रति दो हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल प्रति फार्म ट्यूबवेल/ सामुदायिक टैक की दर पर जलस्रोत- सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाए।

एच एम एन ई एच दिशानिर्देश (2010) कंडिका 10.2.7 एवं तत्सम्बन्धी अनुलग्नक IV के 2 (1) के अनुसार, तीन वर्षों की अवधि में 60:20:20 अनुपात में व्याप्त सहायता बशर्ते की दूसरे वर्ष में 75 *प्रतिशत* उत्तर जीवितता तथा तीसरे वर्ष में 90 *प्रतिशत* उत्तर जीवित पौधे हो। इसलिए पौधों की कुल उत्तर जीवितता *प्रतिशत* पौधरोपण के तृतीय वर्ष में समग्र रूप से 67.5 *प्रतिशत* होना चाहिए।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने फल कृषिकरण के लिए क्षेत्र विस्तार योजना वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान 20292 हैक्टेयर क्षेत्रफल में ₹ 30.20 करोड़ की लागत से आरंभ की थी जिसकी परिपक्वता अवधि वर्ष 2007-08 से 2011-12 थी। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि राज्य में सिर्फ 10 *प्रतिशत* ही सिंचित भूमि थी, विभाग उक्त अवधि में 1870 ट्यूबवेल/सामुदायिक टैंक का विकास कर, सिर्फ 3740 हैक्टेयर (फल औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रफल का 18 *प्रतिशत*) कृषि क्षेत्रफल के लिए ही जल स्रोत का सृजन कर सका था।

इसलिए, इन कारणों से फल औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत लायी गयी भूमि 20292 हैक्टेयर अपने रोपण काल के तृतीय वर्ष में घटकर 4279 हैक्टैयर (21 *प्रतिशत*) रह गयी थी, और इस प्रकार विभाग ने अन्तिम सहायता (तृतीय किस्त) का भुगतान केवल 4279 हेक्टेयर के लिए ही किया था। यह सिद्ध करता था कि 9417 हेक्टेयर[64] क्षेत्रफल की क्षति हुई थी। इसलिए, निवल उत्तर जीवित क्षेत्रफल, फल औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रफल के निर्दिष्ट मानक 67.5 *प्रतिशत* से काफी कम था और ₹ 12.82 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

राज्य में वर्ष 2005-10 के दौरान फल पौध रोपण एवं जल स्रोत सृजन के समग्र वृद्धि का विवरण **तालिका 2.13.7** में नीचे दर्शाया गया है।

[64] क्षेत्रफल की क्षति-विहित मानकों (कृषि के अधीन लाए गए क्षेत्रफल का 67.5 *प्रतिशत*) के अनुसार शुद्ध उत्तर जीविता (क्षेत्रफल में) वास्तविक उत्तर जीविता क्षेत्रफल=20292 हेक्टेयर का 67.5 *प्रतिशत*=4279 हेक्टेयर-13696 हेक्टेयर=4279 हेक्टेयर=9417 हेक्टेयर।

तालिका सं. 2.13.7

रोपण से परिपक्वता की अवधि		राज्य में फल औद्योनिकीकरण का विवरण (है. में)				ज से सृ (हे.में)	रो प- (₹ लाख में) (किस्त में)				नि व्य
रोपण वर्ष	परिपक्वता वर्ष	क्षे फ	नि क्षे	नि क्षे मा	क्षे क्ष		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग	
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9	10	11	12
2005-06	**2007-08**	2495	0	1684	1684	500	324.35	**0.00**	**0.00**	**324.35**	218.92
2006-07	**2008-09**	6750	3302	4556	1254	1440	759.38	302.93	222.87	**1285.18**	238.76
2007-08	**2009-10**	5094	14	3438	3424	464	573.08	91.92	0.25	**665.25**	447.16
2008-09	**2010-11**	2338	773	1578	805	838	262.89	1.41	48.42	**312.72**	107.67
2009-10	**2011-12**	3615	190	2440	2250	498	387.57	35.21	9.67	**432.45**	269.15
योग		**20292**	**4279**	**13696**	**9417**	**3740**	**2307.27**	**431.47**	**281.21**	**3019.95**	**1281.66**

स्रोतः- मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

नोट : क्षे फ-औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत क्षेत्रफल, नि क्षे- निवल क्षेत्र तीन वर्ष की समाप्ति पर, नि क्षे मा -निर्दिष्ट मानकानुसार निवल क्षेत्रफल, क्षे क्ष - क्षेत्रफल में क्षति, ज से सृ- कमाण्ड क्षेत्रफल के जल स्रोत का सृजन, रो प व्य-रोपण पर किया गया व्यय, नि व्य-निष्फल व्यय

लेखा परीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि विभाग एच एम एन इ एच दिशानिर्देश में निर्दिष्ट औद्यानिकी को मदद करने के लिए सम्पूर्ण वर्ष हेतु आवश्यक जल स्रोतों का सृजन करने में असफल रहा जिससे कि पौधों की उत्तर जीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लाभार्थी सर्वेक्षण में जल स्रोतों की उपलब्धता की समस्या भी पायी गयी थी।

उत्तर में विभाग ने बताया (अगस्त 2012) कि जल उपलब्धता में कमी, सूखा, अन्य प्रतिकूल मौसमी स्थितियाँ एवं जंगली जानवरों के कारण फल औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। आगे बताया गया कि फल औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत पौध रोपण की जाँच के बाद विभाग क्षेत्रफल में हुई क्षति की जाँच करेगा। आगे, प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में इंगित तथ्यों का स्वीकार किया तथा क्षति के लिए राज्य की कठिन भौगोलिक संरचना, मौसमी परिस्थितियां एवं 2007-09 के दौरान भीषण सूखा पड़ने को जिम्मेदार बताया था। परन्तु, उन्होंने कहा कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना और जलागम कार्यक्रम के साथ क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विभागीय प्रत्युत्तर, जल स्रोत सृजन में उचित रुप से आयोजना न करने एवं फल पौध रोपण के सापेक्ष होने वाली क्षति को रोकने के लिए अनुश्रवण तंत्र में कमी के कारण, स्वीकार्य नहीं था।

2.13.12.2 शहतूत पौधों की अल्प उत्तर जीविता

रेशम विभाग ने वर्ष 2007-08 में रेशम उत्पादन को राज्य में बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र प्रायोजित "कैटेलिटिक विकास कार्यक्रम" (सी डी पी) के अन्तर्गत शहतूत पत्ती की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कृषकों को वित्तीय सहायता दे कर शहतूत पौध रोपण कार्यक्रम की शुरूआत की थी। आगे, विभाग ने शहतूत पौध रोपण को पटरी पर लाने के लिए प्रति कृषक 300 पौध रोपण सामग्री प्रदान करने का मानक निर्धारित किया था तथा यह भी सुनिश्चित किया गया कि पौध की उत्तर जीविता *प्रतिशत* 80 *प्रतिशत* या उससे अधिक होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने नमूना जाँच के लिए चयनित जनपदों के क्लस्टरों[65] की नमूना जाँच में 1194 लाभान्वितों में से विभाग द्वारा पौधों की उत्तर जीविता का भौतिक सत्यापन 1113 लाभान्वितों का किया गया था जिन्हें वर्ष 2008-09 से 2011-12 के मध्य 3.34 लाख पौध उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त अवधि में लाभान्वितों की संख्या, रोपित पौध एवं उनकी जीविता का विवरण **तालिका 2.13.8** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका सं. 2.13.8

(संख्या में)

वर्ष	विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेनदनानुसार लाभार्थी संख्या	रोपित पौध	पौध की उत्तर जीविता एवं लाभार्थी संख्या					
			मानक के नीचे			मानकानुसार		
			0-79			80-100		
			ला सं	पौ सं	%	ला सं	पौ सं	%
2008-09	210	63000	127	38100	60	83	24900	40
2009-10	241	72300	175	52500	72	66	19800	28
2010-11	390	117000	202	60600	52	188	56400	48
2011-12	272	81600	096	28800	35	176	52800	65
योग	**1113**	**333900**	**600**	**180000**	**54**	**513**	**153900**	**46**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

नोटः ला सं-लाभान्वितो की संख्या, पौ सं- पौध संख्या।

आगे, यह भी संज्ञान में आया कि केवल 46 *प्रतिशत* पौधे ही निर्धारित मानकानुसार जीवित रह सके थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार (जुलाई 2012) किया तथा इसके लिए असिंचित एवं अनुपयुक्त भूमि पर पौध रोपण किये जाने को जिम्मेवार बताया। प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में विभागीय स्पष्टीकरण की पुष्टि की।

इस प्रकार, शहतूत रोपण के लिए अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण शहतूत पौधों की उत्तर जीविता पर प्रभाव पड़ा।

2.13.12.3 संरक्षित औद्यानिकीकरण के विस्तार में न्यून उपलब्धि

भारत सरकार, संरक्षित औद्यानिकीकरण के अन्तर्गत शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं एण्टी-हेल नेट को बढ़ावा देने के लिए उद्यानपतियों को वित्तीय सहायता देती है।

विभाग ने वर्ष 2007-12 के मध्य ₹ 13.08 करोड़ की लागत से 1424.08 वर्गमीटर भूमि में संरक्षित खेती करने की योजना बनायी थी। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान संरक्षित खेती के अन्तर्गत लक्ष्य, आच्छादित क्षेत्रफल एवं किये गये व्यय का विवरण निम्न **तालिका 2.13.9** में दर्शाया गया है।

[65] 1. थानो, देहरादून 2. तिपरपुर, देहरादून 3. भगवानपुर, हरिद्वार 4. लक्सर, हरिद्वार एवं 5. सोमेश्वर, अल्मोड़ा।

तालिका सं. 2.13.9

वर्ष	लक्ष्य एवं लब्धियों का संक्षिप्त विवरण						
	भौतिक (वर्गमीटर क्षे फ)				वित्तीय (₹ लाख में)		
	लक्ष्य	लब्धि	कमी (%)	स्वीकृत लागत	अवमुक्त	व्यय	
						धनराशि	*प्रतिशत*
2007-08	82.40	82.40	0	170.03	170.03	170.03	100
2008-09	70.00	58.30	17	171.95	139.29	139.29	100
2009-10	52.88	27.84	47	117.29	88.33	79.75	090
2010-11	163.00	16.74	90	665.36	585.03	83.40	014
2011-12	1055.80	100.25	91	359.70	325.69	51.94	016
योग	**1424.08**	**285.53**	**80**	**1484.33**	**1308.37**	**524.41**	**040**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह पाया गया कि वार्षिक कार्ययोजना की धीमी कार्यान्वयन के कारण उपरोक्त अवधि में लब्धि में 47 *प्रतिशत* से 91 *प्रतिशत* की कमी आयी थी और लब्धि 2009-12 के दौरान किए गये व्यय के अनुपात के विरूद्ध थी। इसके अतिरिक्त, विभाग उक्त अवधि में उपलब्ध निधियों का 60 *प्रतिशत* का उपयोग करने में असफल रहा था।

नमूना परीक्षित जनपदों में से अल्मोड़ा और देहरादून के अभिलेखों की जाँच में 2008-12 के मध्य लक्षित संरक्षित खेती के सापेक्ष 70 *प्रतिशत* की कमी भी पायी गयी थी।

इसे इंगित करने पर विभाग ने बताया (अगस्त 2012) कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार निधि अवमुक्त नहीं करने के कारण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे यह भी बताया कि विभाग के पास राज्य में हाईटेक ग्रीन हाउस के निर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी ज्ञान का अभाव था। आगे, नोडल अधिकारी, हार्टीकल्चर मिशन ने स्वीकार किया कि अव्याहारिक वार्षिक कार्ययोजना के कारण लब्धि कम रही।

प्रमुख सचिव, उद्यान द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में संरक्षित खेती के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

2.13.12.4 ₹ 2.40 करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के बावजूद सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन इकाई की गैर-स्थापना

भारत सरकार ने 'असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर डेवेलपिंग एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड एलाइड एक्टिविटीज' (एसाइड) योजना के अंतर्गत सगंध पौधा केन्द्र, जो कि उस समय जड़ी-बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान की एक सहायक इकाई थी, में सुपर क्रिटिकल फ्लूड एक्सट्रैक्शन (एस सी एफ ई) इकाई की स्थापना हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया (अगस्त 2007)। एस सी एफ ई इकाई प्रायोगिक आधार पर जड़ी-बूटियों से सक्रिय यौगिक को पृथक करने के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधा के रूप में प्रयोग की जानी थी। इसका उद्देश्य प्राकृतिक उत्पाद उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाले तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के माध्यम से तेजी से बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना हिस्सा हासिल करने में सहायता पहुँचाना था।

भारत सरकार ने परियोजना की कुल लागत ₹ 3.05 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रीय घटक के अंतर्गत उपकरण के लिए ₹ 2.40 करोड़ की धनराशि निर्गत की (जनवरी एवं मार्च 2009)। यह धनराशि वित्तीय औचित्य के

प्रतिकूल चालू बैंक खाते में रखी गयी। भारत सरकार द्वारा धन निर्गत करते समय लगायी गयी तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई शर्त के अनुसार उपकरण कीमतों में होने वाली कोई भी वृद्धि जड़ी-बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा वहन की जायेगी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि निदेशक, जड़ी-बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने निविदाओं के लिए अपनी स्वीकृति देने में विलम्ब किया (जून 2009 से सितम्बर 2009 तथा पुनः मई 2010 से सितम्बर 2010) और अप्रैल 2010 में प्रथम निविदा की विशिष्टियों में परिशोधन भी किया गया। अंततः मेसर्स मेटोस इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को ₹ 3.77 करोड़ मूल्य के उपकरणों की आपूर्ति के लिए चुना गया (फरवरी 2011)। इस प्रकार उपकरणों की लागत में ₹ 1.37 करोड़ की बढ़ोत्तरी हो गयी थी।

विक्रेता के चयन (फरवरी 2011) के पश्चात शासन ने कीमतों में हुई वृद्धि का निधीयन करने के लिए बजट आवंटन करवाने के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया (फरवरी 2011)। शासन के द्वारा एस सी एफ ई की स्थापना के विषय में निर्णयन के लिए समिति बनायी गयी (नवम्बर 2011) जिसने भारत सरकार से और सहायता माँगने का प्रस्ताव किया (नवम्बर 2011)। भारत सरकार ने और सहायता देने से पहले पूर्व में स्वीकृत धनराशि के उपयोग करने के लिए कहा (जून 2012)। पूर्व में स्वीकृत धनराशि के उपयोग करने के विषय में निर्णय तभी (मई 2012) से शासन के पास लंबित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उत्तराखण्ड सरकार कीमतों में हुई वृद्धि का निधीयन करने की अपनी पूर्व प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रही। यह, इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार एसाइड योजना के अंतर्गत सहायता बढ़ाने को तैयार थी (जून 2012) यदि उत्तराखण्ड सरकार पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र दे देती, भारत सरकार की सहायता राशि के उपयोग के विषय में निर्णय लेने में भी असफल रही। दोनों ही स्थितियों में परियोजना का भविष्य अन्धकार-मय हो गया। इसके अतिरिक्त, इस धनराशि को चालू बैंक खाते में रखने के कारण ब्याज की धनराशि ₹ 29.00 लाख की हानि भी हुई जो शासन को प्राप्त हुई होती यदि इसने ₹ 2.40 करोड़ की उक्त धनराशि को बचत खाते में रखा होता।

इस प्रकार एक तरफ तो सरकार अपनी पूर्व प्रतिबद्धता को पूर्ण करने में असफल रही जबकि दूसरी तरफ इसने उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजकर और धनराशि की माँग करने के भारत सरकार के प्रस्ताव का भी लाभ नहीं उठाया जिससे राज्य के निर्यातक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गये तथा केन्द्रीय निधियाँ भी बिना उपयोग के पड़ी रहीं।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में तथ्यों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा को परियोजना में तेजी लाने का विश्वास दिलाया।

2.13.13 *मानव संसाधन प्रबन्धन एवं क्षमता निर्माण*

2.13.13.1 कार्मिकों की कमी

मानव संसाधन प्रबंधन नियमित अन्तरालों से विभागीय गतिविधियों का पर्याप्त ध्यान देते हुए कर्मिक अपेक्षाओं को निर्धारित एवं समीक्षा करने तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियुक्ति/ भर्ती एवं

क्षमता संबर्द्धन के लिए उचित/ पारदर्शी नीतियाँ बनायी/पालन की पालन किए जाने के लिए अनिवार्य बना देता हैं।

उद्यान विभाग के पास राज्य में बागवानी, रेशम एवं जड़ी-बूटी व सुगंधित पौध रोपण का विकास से संबंधित बहुआयामी उद्देश्य था और उसे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित मानव शक्ति की आवश्यकता थी।

विभाग में स्वीकृत 3655 कुल पदों के सापेक्ष 64 *प्रतिशत* कार्मिक कार्य कर रहे थे। समूह क एवं ख संवर्गो में 46 *प्रतिशत* कार्मिकों की कमी थी। जबकि समूह ग एव घ में 36 *प्रतिशत* की कमी थी।

31 मार्च 2012 को कार्मिकों की स्थिति का विवरण **तालिका 2.13.10** में दर्शाया गया है।

तालिका सं. 2.13.10

संवर्ग	उद्यान			रेशम			भेषज			योग		
	स्वी प	का क	कमी/ आधिक्य	स्वी प	का क	कमी/ आधिक्य	स्वी प	का क	कमी/ आधिक्य	स्वी प	का क	कमी/ आधिक्य
क	12	08	04	04	03	1	1	1	0	17	12	5
ख	57	26	31	10	07	3	4	3	1	71	36	35
ग	1157	737	420	149	61	88	123	49	74	1429	847	582
घ	1932	1326	606	176	108	68	30	16	14	2138	1450	688
योग	**3158**	**2097**	**1061**	**339**	**179**	**160**	**158**	**69**	89	**3655**	**2345**	**1310**
कमी का *प्रतिशत*	**34**			**47**			**56**			**36**		

स्रोत-विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

नोट- स्वी प-स्वीकृत पद, का क-कार्यरत कर्मचारी, क -कमी, अधि -अधिक

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उद्यान विकास कार्यक्रम मुख्यतः फील्ड कर्मचारियों, विशेष रूप से समूह ग एव घ के अन्तर्गत सचल दल केन्द्रों पर कार्यरत सहायक विकास अधिकारियों एवं मालियों पर निर्भर करता है, और इसलिए इन समूहों में मानवशक्ति की कमी के कारण राज्य में औद्यानिकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। पुनः मंत्री परिषद के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों जो कि माली के रूप में विभाग के लिए रीढ़ की हड्डी थे, की भर्ती पर रोक लगाने के कारण आगामी पाँच वर्षो में 585 कार्मिकों की सेवानिवृति के कारण विभागीय गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी पाया गया कि रेशम विभाग ने उचित मानव संसाधन प्रबंधन को नहीं अपनाया था जिससे कि देहरादून जनपद में माली के तीन स्वीकृत पद के सापेक्ष 15 माली पदस्थापित थे जबकि शेष 12 जनपदों में 17 स्वीकृत पद के सापेक्ष मात्र दो माली ही पदस्थापित थे।

इसके अलावा विभाग चाय बोर्ड एवं दो अनुंसधान एवं विकास संस्थानों का अनुरक्षण करता था लेकिन स्थायी वैज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति करने में विफल रहा था। परिणामस्वरूप, अनुसंधान गतिविधि, लुप्तप्राय जड़ी-बूटी के संरक्षण, औषधीय एवं सुगन्धित पौधों के वैज्ञानिक कृषिकरण एवं चाय की खेती के समुचित विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा था, जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

यह भी देखा गया कि ये कार्यालय 29,329 उद्यानपतियों, जिन्होंने एच एम एन इ एच के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों के कृषिकरण के लिए सहायता प्राप्त की थी, में से केवल सात *प्रतिशत* उद्यानपतियों को ही प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कर सके। इसके अलावा, विभाग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कुल उद्यानपतियों में 16 *प्रतिशत* अनु. जाति एवं 18 *प्रतिशत* अनु. जनजाति एवं 30 *प्रतिशत* महिला उद्यानपतियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के मानक के उल्लघंन में, अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं महिला वर्ग के उद्यानपतियों में से क्रमशः केवल पाँच, चार एवं सात *प्रतिशत* उद्यानपतियों को ही प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कर सका था। विभाग ने कहा कि अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा महिलाओं के पास उत्तराखण्ड में बहुत कम जमीन है और इससे जनपद कर्मियों द्वारा पर्याप्त संख्या में लाभार्थियों का पहचान कार्य सीमित रहा।

इस प्रकार विभाग कम संख्या में ही उद्यानपतियों को कृषि तकनीकि का प्रशिक्षण प्रदान कर सका और यथार्थवादी आयोजना न होने के कारण अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा महिला लाभार्थियों की सीमित संख्या के बावजूद, इन वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर सका।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (अगस्त 2012) कि जनपद स्तर पर पर्याप्त बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, यह भी कहा कि क्षमता निर्माण के अन्तर्गत स्वीकृत निधि से सभी लाभार्थियों को प्रशिक्षित करना संभव नहीं था।

तथापि, प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि उद्यानपतियों को नियमित रूप से ग्राम, न्याय पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर चलाये जा रहे विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता था।

2.13.14 आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र

उचित आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली का अस्तित्व में रहना यह सुनिश्चित करता है कि विभाग, संसाधनों की सुरक्षा के अलावा, अपने उद्देश्यों को व्यवस्थित, नैतिक, आर्थिक, कुशल और प्रभावी तरीके से पूरा कर रहा है। यह जवाबदेही, दायित्वों और लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन को पूरा करने में भी मदद करता है।

जब ऊपर वर्णित मानकों के साथ तुलना की जाती है, तो कमजोर नियंत्रण विभाग को प्रणाली उल्लंघनों की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा, कमजोर क्षेत्र निरीक्षण और आंतरिक लेखापरीक्षा की न्यूनता ने इन प्रणाली उल्लंघनों के लिए मार्ग खोल दिया। इसका विस्तृत विवरण प्रस्तर 2.13.14.1 से 2.13.14.7 में दिया गया है।

2.13.14.1 ₹ 94500 मूल्य की पौध रोपण सामग्री की फर्जी आपूर्ति

भेषज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिला भेषज, विकास अधिकारी हरिद्वार को 45,000 घृतकुमारी पौध की आपूर्ति करने हेतु जिला भेषज संघ, हरिद्वार को बिल संख्या 126, दिनांक 18 मार्च, 2011 के सापेक्ष ₹ 94,500 का भुगतान किया (मार्च 2011)। यह आपूर्ति बिल जिला भेषज विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं था जैसा कि अन्य बिलों के मामलों में होता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्ति पौध, जिला भेषज विकास अधिकारी की भंडार पंजिका में अंकित नहीं की गयी थी और लाभार्थियों की सूची भी उसके द्वारा तैयार नहीं की गयी थी। मार्च 2011 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन

इस प्रकार, योजनाकारों एवं निष्पादनकर्ताओं की श्रेणी में कमी के कारण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था जैसा कि क्रमशः प्रस्तर 2.13.9.3, 2.13.11.3 एवं 2.13.12.2 में विवरण दिया गया है।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने बर्हिगमन सम्मेलन में तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा (दिसम्बर 2012) कि राज्य सरकार छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ग घ के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। उन्होंने पुनः कहा कि भविष्य में, सगंध पादप केन्द्र एवं जड़ी-बूटी अनुसंधान एवं विकास संस्थान के लिए वैज्ञानिक कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी।

2.13.13.2 क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के क्षेत्र में अल्प उपलब्धि

एच एम एन इ एच के परिचालन दिशा निर्देश (मार्च 2004) के अनुसार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं मानव संसाधन विकास मिशन का अभिन्न अंग है। यह अच्छी उत्पादन प्रथाओं के साथ परिचय कराने के लिए उद्यानपतियों को कृषि तकनीक से संबधित उचित प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को बताता है।

आगे, विभाग से यह भी अपेक्षित था कि महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए उद्यानपतियों में से चयनित लाभार्थियों, को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरे वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम अग्रिम में बनाए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2008-11 के मध्य ₹ 1.04 करोड़ के व्यय से लक्षित प्रशिक्षणार्थियों (10,335) में से केवल 62 *प्रतिशत* को ही प्रशिक्षण प्रदान किया।

यह भी पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2011-12 में स्वयं एक भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था। तथापि यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में 571 कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करवाने में सफल रहा था।

आगे, पाँच जनपदों में से तीन[66] के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनपद कार्यालयों ने लक्षित लाभार्थियों में से केवल 71 प्रतिशतों को प्रशिक्षण प्रदान किया लेकिन विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को प्राथमिकता देने में विफल रहे। लक्ष्य एवं लब्धियों का विवरण **तालिका 2.13.11** में नीचे दिया गया है।

तालिका सं. 2.13.11

वर्ष	राज्य				नमूना परीक्षित जनपद									
	कृषकों को प्रशिक्षण				कुल लाभार्थी जिन्होंने औद्यानिक फसल के लिए सहायता प्राप्त की				कुल प्रशिक्षणार्थी			प्रशिक्षणार्थी		
	लक्ष्य	लब्धि	लब्धि (*प्रतिशत* में)	व्यय (₹ लाख में)	योग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	महिला	लक्ष्य	लब्धि		अनु. जाति	अनु जनजाति	महिला
										संख्या	*प्रतिशत*			
2007-08	2015	2015	100	45.23	9594	925	267	1168	535	462	86	35	29	57
2008-09	5600	3612	65	69.32	6133	569	203	709	1470	870	59	75	49	85
2009-10	2625	1735	66	30.46	8178	689	329	821	780	489	63	05	2	00
2010-11	2110	1030	49	4.69	3024	296	161	316	290	350	120	01	3	0
2011-12	0	0	0	0	2400	323	235	446	0	0	0	00	0	0
योग	**12350**	**8392**	**68**	**149.70**	**29329**	**2802**	**1195**	**3460**	**3075**	**2171**	**71**	**116**	**83**	**142**

स्रोत- विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

[66] अल्मोड़ा, चमोली एवं देहरादून।

और जून 2011 के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में घृतकुमारी का रोपण केवल 1,47,000 पौध दिखाया गया था जो कि बिल संख्या 117 दिनांक 22 सितम्बर 2010 व बिल संख्या 118 दिनांक 04 अक्टूबर 2010 द्वारा क्रय किये गये थे। इससे यह सिद्ध हुआ कि बिल संख्या 126 दिनांक 18 मार्च 2011 द्वारा क्रय की गयी 45,000 पौध की आपूर्ति तथा वितरण कभी हुआ ही नहीं था। जिला भेषज विकास अधिकारी, हरिद्वार ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि उन्होंने उक्त बिल के सापेक्ष न तो कभी कोई पौध रोपण सामग्री प्राप्त की और न ही इस विषय में उनके द्वारा कभी कोई माँग ही की गयी थी।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा पौध रोपण के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ जिला भेषज विकास अधिकारी, हरिद्वार के उत्तर को मिलाकर देखने से यह सिद्ध हुआ कि जिला भेषज संघ द्वारा की गयी आपूर्ति फर्जी थी और भेषज विकास इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जिला भेषज विकास अधिकारी, हरिद्वार के प्रतिहस्ताक्षर के न होते हुए भी अनियमित रूप से यह धनराशि संघ को भुगतान की। भेषज विकास इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि इस मामले में जाँच प्रारंभ की जायेगी। लेखापरीक्षा, उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु की गयी कार्यवाही की प्रतीक्षा करेगी।

2.13.14.2 आधिकारिक दस्तावेजों की कपटपूर्ण रचना

भेषज विकास इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो हर्बल रिसर्च एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के निदेशक भी थे, को भेषज विकास इकाई से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रत्येक मास कम से कम दस दिनों के लिए देहरादून में रहना अपेक्षित था। सचिव, उद्यान विभाग ने उन्हें इस प्रयोजन हेतु देहरादून में रहने के लिए शहर में आवास किराये पर लेने की अनुमति प्रदान की (अप्रैल 2010)।

उक्त आवास को अधिग्रहीत करने में अपनायी गयी प्रक्रियाओं से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि दिनांक 13 अप्रैल 2010, 16 अप्रैल 2010 एवं 10 जुलाई 2010 की पत्रावली टिप्पणियों में उल्लिखित धनराशियों के साथ रुपये के चिन्ह (₹) का प्रयोग किया गया था। रुपये का यह चिन्ह (₹) केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जुलाई 2010 को अनुमोदित किया गया था एवं इसका फॉण्ट फोरेडियन टेक्नॉलॉजीज द्वारा 16 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त पत्रावली टिप्पणियाँ 16 जुलाई 2010 को या इसके पश्चात, यह प्रदर्शित करने के लिए कि आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, कपटपूर्ण तरीके से बनायी गयी थीं। भेषज विकास इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष को स्वीकार किया।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि इस मामले में जाँच प्रारंभ की जायेगी। लेखापरीक्षा को दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु की गयी कार्यवाही की प्रतीक्षा रहेगी।

2.13.14.3 उद्यानपतियों को बीमा दावा का भुगतान न होना

राज्य सरकार ने उद्यान विभाग द्वारा सेब उत्पादकों के लिए प्रयोगिक आधार पर शुरू की गई परियोजना (मार्च 2008) 'मौसम आधारित फसल बीमा योजना' (मौ आ फ बी यो) के सफल क्रियान्वयन के बाद, योजना में अन्य फसलों को शामिल किया और भारत सरकार के सहयोग से 2010-11 रबी ऋतु से फसल बीमा

योजना को लागू किया था, और इस योजना के संचालन के लिए मेसर्स भारतीय कृषक बीमा कम्पनी लिमिटेड (ए आइ सी एल) को अधिकृत किया था। उद्यानपति, विभाग और भारत सरकार को प्रीमियम क्रमशः 2:1:1 के अनुपात में साझा करना था।

योजना का उद्देश्य बीमित किसानों को मौसम के मापदण्डों के प्रतिकूल परिस्थितियों/घटनाओं से प्रत्याशित फसल क्षति के कारण वित्तीय हानि की संभावनाओं से उत्पन्न कठिनाई को कम करना था। योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत थीं।

- निदेशक, उद्यान योजना के अनुश्रवण/प्रभावकारिता के आकलन के लिए जिम्मेदार थे जबकि मेसर्स ए आइ सी एल प्रीमियम के संग्रहण एवं उद्यानपतियों के दावा वितरण के लिए जिम्मेवार था।
- संबंधित सरकारों ने अपने हिस्से के प्रीमियम का भुगतान अग्रिम में करना था।
- मौसम केन्द्र से मौसम से संबधित आँकड़ों की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर उद्यानपतियों को भुगतान सीधे या बैंक खाता के माध्यम से किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स ए आई सी आई एल ने 2010-11 (रबी) से 2011-12 (रबी) तक 22,709 उद्यानपतियों का बीमा कराया था। बीमा कम्पनी ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि उसने प्रीमियम में राज्यांश के निर्गत न होने के कारण उद्यानपतियों को ₹ 70.02 करोड़ की बीमित राशि के विरूद्ध एक भी दावा का भुगतान नहीं किया था। बीमित उद्यानपतियों एवं अनिर्णीत दावा का विवरण **तालिका 2.13.12** में नीचे दिया गया है।

तालिका सं. 2.13.12 *(₹ लाख में)*

वर्ष	बीमित उद्यानपति					प्रीमियम में राज्यांश का विवरण						
	खरीफ	रबी	बीमित धनराशि			खरीफ			रबी			ए आई सी आई एल को देय अवशेष
			खरीफ	रबी	योग	देय	भुगतान	अवशेष	देय	भुगतान	अवशेष	
2010-11	0	2121	0.00	1788.21	1788.21	0	0	0	53.64	51.10	2.54	2.54
2011-12	19851	737	4707.43	506.03	5213.46	141.27	0	141.27	63.87	37.12	26.75	168.02
योग	**19851**	**2858**	**4707.43**	**2294.24**	**7001.67**	**141.27**	**0**	**141.27**	**117.51**	**88.22**	**29.29**	**170.56**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इसके अलावा, विभाग ने अनुबंध का उल्लंघन करते हुए, धन अनुपलब्धता के कारण प्रीमियम में ₹ 1.71 करोड़ के राज्यांश का भुगतान अग्रिम में नहीं किया था। जाँच में यह भी पाया गया कि निदेशक, उद्यान जो कि योजना के प्राविधिक नियंत्रक थे, मौसम केन्द्रों से समय पर यथा अपेक्षित मौसम संबंधी आँकड़े बीमा कम्पनी को उपलब्ध करवाने में विफल रहे ताकि बीमा कम्पनी दावों के निपटान बीमित अवधि की परिपक्वता के 45 दिनों के बाद कर सके।

इस प्रकार, बीमा कम्पनी, इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार और उद्यानपतियों ने प्रीमियम में अपने-अपने अंश अग्रिम में ही भुगतान कर दिए थे, ने एक भी बीमित उद्यानपतियों को दावे का भुगतान नहीं किया था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार (अगस्त 2012) करते हुए कहा था कि इस विषय में निधि निर्गत करने के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था और यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में निगरानी में सुधार किया

जाएगा। प्रमुख सचिव, उद्यान ने भी प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में तथ्यों को स्वीकार किया तथा इसके लिए बजट में निधि की अनुपलब्धता को जिम्मेवार बताया।

2.13.14.4 उद्यान कार्डों का कम संख्या में निर्गत किया जाना

राज्य सरकार ने बागवानी के अन्तर्गत क्षेत्रफल, उद्यानपतियों को सहायता से सम्बन्धित डाटा वेस संग्रहित करके बागवानी गतिविधियों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता को सुधारने तथा उद्यानपतियों को एक विशेष पहचान संख्या आवंटित करने के उद्देश्य से उद्यान कार्ड निर्गत करने का निर्णय लिया था (जुलाई 2006)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने केवल 97,106 उद्यानपतियों को उद्यान कार्ड निर्गत किया लेकिन प्रदेश स्तर पर उद्यानपतियों का डाटा बेस नहीं बनाया। यह भी पाया गया कि 2007-12 की अवधि में चयनित जिलों में कुल 87,256[67] उद्यानपतियों में से केवल 25 *प्रतिशत* को ही उद्यान कार्ड निर्गत किये गये थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने चयनित जिलों में, टिहरी को छोड़कर, मूल पंजिका का अनुरक्षण भी नहीं किया जिसकी अनुपस्थिति में बागवानी विकास का पूर्ण अनुश्रवण नहीं किया जा सका था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त 2012) तथा बताया कि विभाग के द्वारा जिला स्तरीय कार्यालयों को उद्यान कार्ड निर्गत करने एवं मूल पंजिका रखरखाव का अनुदेश दिया जायेगा। पुनः, प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में आवश्यक कदम उठाये जाने का आश्वासन दिया।

2.13.14.5 खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव

फल उत्पाद आदेश (एफ पी ओ) अधिनियम, 1955 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (एफ पी यू) को कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा परिसर को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाये रखने के लिए एफ पी ओ लाइसेंस लेना होता है। एफ पी ओ तैयार माल की पैकिंग पर गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण चिन्ह के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इकाइयों की स्थापना, उच्चीकरण तथा आधुनिकीकरण के माध्यम से बागवानी उत्पादों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तरदायी है।

निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन के लिए बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु 49 खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र संचालित करता था।



फल संरक्षण केन्द्र, गोपेश्वर चमोली में पड़ा निष्कार्य उपकरण, (04 जून 2012)

67

नमूना परीक्षित जनपद का नाम	देहरादून	हरिद्वार	टिहरी	चमोली	अल्मोड़ा	योग
कुल लाभार्थी	12517	9912	14617	24210	26000	**87256**
यू सी निर्गत	5438	2275	4782	3294	5818	**21607**
प्रतिशत	43	23	33	14	22	**25**

चयनित जिलों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि विभाग ने दो[68] चयनित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ₹ 4.72 लाख के उपकरण का क्रय किया था (मार्च 2009 एवं मार्च 2010) जो कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में तकनीकि कर्मचारियों तथा बिजली के अभाव में निष्क्रिय पड़े हुए थे। यह भी पाया गया कि चयनित जिलों में 22 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में से केवल दो[69] ने ही अपेक्षित एफ पी ओ लाइसेंस प्राप्त किया था।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (मई-जून 2012) कि उसने खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को केवल भौतिक (गंध, रंग एवं स्वाद) रूप से तथा अनुभव के द्वारा निर्धारित किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में असफल रहा तथा कारणवश उपभोक्ता का गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के हित पर भी समझौता किया गया।

2.13.14.6 अपर्याप्त क्षेत्र निरीक्षण

कार्यकलापों/ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग को यह सुनिश्चित करना था कि प्रदेश तथा जिला स्तर के अधिकारी क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से योजनाओं के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से अनुश्रवण करें। विभाग के द्वारा निरीक्षण करने वाले प्रत्येक अधिकारी के लिए निरीक्षणों की संख्या निर्धारित करते हुए तालिका बनायी जानी चाहिए थी और उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निरीक्षण करने योग्य अधिकारियों के लिए क्षेत्र निरीक्षणों की संख्या निश्चित करने वाले कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। चयनित जिलों में किये गये क्षेत्र निरीक्षणों का विवरण **तालिका 2.13.13** में दर्शाया गया है।

तालिका -2.13.13

जनपद	उद्यान सचल दलों एवं फार्मों की संख्या	निरीक्षणों का विवरण										औसत निरीक्षण	
		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12			
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
टिहरी	38	39	103	07	18	18	47	28	74	33	87	25	66
चमोली	43	14	32	05	11	00	0	00	0	02	5	04	09
अल्मोड़ा	47	24	51	11	23	10	21	12	26	0	0	11	23
देहरादून	25	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
हरिद्वार	15	28	187	32	213	35	233	32	213	35	233	32	213
योग	168	105	63	55	33	63	38	72	43	70	42	72	43

स्रोतः विभाग के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

विशेषः अनुप- अनुपलब्ध।

यह पाया गया कि हरिद्वार को छोड़कर चार चयनित जिलों में उद्यान सचल दलों तथा फार्मों का निरीक्षण *प्रतिशत* शून्य से 103 तक था। यह भी पाया गया कि जिला स्तरीय अधिकारी केवल औसतन 72 निरीक्षण प्रतिवर्ष कर सके जो कि 2007-12 की अवधि में जिलों में उद्यान सचल दलों तथा फार्मों की संख्या 168 के

[68] खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जोशीमठ एवं गोपेश्वर (चमोली)।

[69] खाद्य प्रसंस्करण इकाई, अल्मोड़ा एवं गोपेश्वर, चमोली।

सापेक्ष काफी कम थे। आगे यह भी देखा गया कि निदेशक, उद्यान ने इस अवधि में केवल छः क्षेत्र निरीक्षण किये और लेखापरीक्षा की अवधि के विगत दो वर्षों में कोई भी क्षेत्र निरीक्षण नहीं किया। साथ ही यह भी देखा गया कि केवल अल्मोड़ा जनपद में ही 57 क्षेत्र निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष 19 मामलो में कार्रवाई की गयी।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने स्वीकार किया कि उसने अनुश्रवण तथा निरीक्षण के लिए कोई मानक नहीं बनाये। परंतु उसने आगे बताया कि विभाग ने जिला उद्यान अधिकारियों का जिला स्तर पर बागवानी गतिविधियों के अनुश्रवण करने और निरीक्षण रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे। आगे, प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में बताया कि कर्मचारियों की कमी तथा वृहद कार्यक्षेत्र के कारण ही निरीक्षण की संख्या कम है।

2.13.14.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभागीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति को गंभीर दर्शाया जिससे कि आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा विभाग की कार्यपद्धति कुप्रभावित हो रही थी।

उद्यान विभाग वर्ष 1992 से 2009 के दौरान 13 जनपद स्तरीय कार्यालयों में से प्रतिवर्ष एक से चार कार्यालयों की ही आंतरिक लेखापरीक्षा संपादित कर पाया। इस विषय में तथ्य नीचे **तालिका 2.13.14** में दिये गये हैः

तालिका - 2.13.14

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	जब से आन्तरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई
1	जिला उद्यान अधिकारी, पौड़ी	1992 (1)
2	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, रानीखेत, अल्मोड़ा	1993 (1)
3	जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी एवं उद्यान विशेषज्ञ, कोटद्वार	1997 (2)
4	जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल एवं पिथौरागढ़	2000 (2)
5	जिला उद्यान अधिकारी, चमोली	2004 (1)
6	जिला उद्यान अधिकारी, यू एस नगर एवं आलू विकास अधिकारी, मुन्स्यारी	2005 (2)
7	जिला उद्यान अधिकारी, चम्पावत, टिहरी, हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग	2006 (4)
8	जिला उद्यान अधिकारी, देहरादून	2007 (1)
9	जिला उद्यान अधिकारी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर	2009 (2)

स्रोतः विभाग के द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना।

विशेषः कोष्ठक में आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित कार्यालयों की संख्या दी गयी है।

आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2010-12 में विभाग के द्वारा कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी। यह भी पाया गया कि रेशम निदेशालय ने अभी तक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित नहीं की थी। पर्याप्त संख्या में आंतरिक लेखापरीक्षा होने पर उपरोक्त प्रस्तरों में दर्शाये गये तंत्र के उल्लंघन के मामलों को रोका जा सकता था।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि आंतरिक लेखापरीक्षा की संख्या में कमी का कारण कर्मचारियों की कमी थी तथा उन्होंने इसमें सुधार लाने का आश्वासन दिया।

2.13.15 भण्डार/सामग्री प्रबंधन एवं नियंत्रण

2.13.15.1 ₹ 77.65 लाख मूल्य के सब्जी बीजों का अनियमित क्रय

निदेशक, उद्यान ने सब्जी बीजों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की (मार्च 2010)। यह निविदाएँ निरस्त कर दी गयी क्योंकि तीन में से दो निविदादाता मिनीकिट का नमूना उपलब्ध नहीं करवा सके। निविदा समिति ने, पुनः निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा करने के स्थान पर, यह सुझाव दिया कि राजकीय अभिकरण अथवा मूल उत्पादक कंपनियों से बीज क्रय किया जाए।

विभाग ने एक माह पश्चात पाँच मूल उत्पादक कंपनियों को बुलाया और एक बैठक में, जिसकी अध्यक्षता उद्यान विभाग के सचिव ने की, ₹ 77.65 लाख मूल्य के बीजों की आपूर्ति के लिए बीजों के मूल्य तय कर दिये (अप्रैल 2010)। तत्पश्चात यह बीज क्रय कर दिये गये (अप्रैल से जून 2010)।

विभाग के पास उपलब्ध दस्तावेजों में कंपनियों के चयन में अपनाये गये मापदंडों का उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ चुनिंदा कंपनियों के साथ खुली बैठक में मूल्यों को तय करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के मानकों का अभाव था। इसके अतिरिक्त, इस क्रय से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन भी हुआ जिसमें यह नियत किया गया था कि ₹ 25 लाख या अधिक का क्रय केवल निविदा के माध्यम से होना चाहिए। इससे, विभाग प्रतियोगी दरों के लाभ से भी वंचित हो गया।

इन बीजों के जिलों को वितरण से संबंधित दस्तावेजों की आगे की जाँच में प्रकट हुआ कि ₹ 4.30 लाख मूल्य के 4,428 पैकेट जिला उद्यान अधिकारियों को बुवाई के मौसम के व्यतीत होने के पश्चात, इस तथ्य के बावजूद कि यह बीज अगले बुवाई मौसम के प्रारंभ होने के पहले ही कालातीत होने जा रहे थे, वितरित किया गया। इन बीजों के आगे किसानों को वितरण की वास्तविक तिथियाँ लेखापरीक्षा के द्वारा निश्चित नहीं की जा सकीं क्योंकि वितरण पंजिकाओं में वितरण की प्रविष्टियों के सम्मुख तिथियाँ अंकित नहीं की गयी थीं।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने प्रस्थान गोष्ठी (दिसम्बर 2012) में कहा कि इस मामले में जाँच प्रारंभ की जायेगी।

2.13.15.2 ₹ 9.44 लाख मूल्य के प्रशिक्षण बैगों का अनियमित क्रय

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुच्छेद 9 एवं 12(1) में नियत है कि ₹ एक लाख से अधिक मूल्य के क्रय हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए। भेषज विकास इकाई ने पूर्वोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए वर्ष 2010-11 में प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु ₹ 9.44 लाख मूल्य के 3200 बैग दो आपूर्तिकर्ताओं से क्वोटेशन के आधार पर क्रय कर लिये (सितम्बर 2010 से मार्च 2011)।

आगे जाँच में प्रकट हुआ कि इन बैगों की भंडार पंजिका में प्रविष्टि तथा निर्गमन प्रमाणित नहीं किये गये थे। यह भी देखा गया कि भेषज विकास इकाई की भंडार प्रविष्टि में जिला भेषज विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ को 400 बैग निर्गमित दिखाये गये थे जबकि जनपद इकाई ने लेखापरीक्षा से केवल 300 बैगों की प्राप्ति की बात स्वीकार की।

भेषज विकास इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा (जुलाई 2012) कि अभिलेखों के अनुसार भेषज विकास इकाई ने 2,634 बैगों का वितरण किया था परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि वितरण संदेहपूर्ण था। उन्होंने आगे बताया कि 35 बैग भंडार में उपलब्ध थे तथा अलेखाबद्ध बैगों की संख्या 531 थी।

इस उत्तर से अलेखाबद्ध बैगों का मूल्य ₹ 1.56 लाख होता है।

प्रमुख सचिव, उद्यान ने बहिर्गमन सम्मेलन (दिसम्बर 2012) में कहा कि इस मामले में जाँच प्रारंभ की जायेगी।

2.13.16 निष्कर्ष

विभाग राज्य में बागवानी के समग्र विकास के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिना कुशल नियोजन के कार्य कर रहा था। यह 'उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन' के सभी चार मिनी मिशनों का लाभ नहीं उठा सका सिवाय मिनी मिशन- II के, जो कि केवल क्षेत्रफल विस्तार पर ही केन्द्रित था। विभाग के द्वारा केन्द्रीय निधियाँ पूर्ण रूप से उपयोग नहीं की जा सकीं और विभाग में संचालित केन्द्रीय योजनाओं एवं परियोजनाओं का कुप्रबंधन किया गया। विभाग के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक संस्थाएँ अपेक्षा के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं कर सके।

यद्यपि राज्य सरकार के पास इसके लिए अच्छी प्रकार से अभिलिखित नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ हैं, तथापि विभाग अधिप्राप्तियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने में असफल रहा था। इसके पास आने वाले वर्षों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधनों का अभाव है। कमजोर आंतरिक नियंत्रणों एवं अपर्याप्त अनुश्रवण के कारण विभाग धोखाधड़ी एवं तंत्र के अन्य उल्लंघनों के प्रति कमजोर हो गया जैसा कि प्रस्तर 2.13.14.1 'पौध रोपण सामग्री की फर्जी आपूर्ति' तथा प्रस्तर 2.13.14.2 'आधिकारिक दस्तावेजों की कपटपूर्ण रचना' के मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया।

2.13.17 अनुशंसाएँ

सरकार विचार कर सकती है किः

- उत्तर फसल प्रबंधन समेत बागवानी विकास के सभी पहलू को नियोजन मे शामिल किया जाये;
- जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान तथा सुगंध पौधा केन्द्र की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को मजबूत किया जाए तथा अनुसंधान एवं विकास के परिणामों को उद्यानपतियों के लाभ के लिए अनुप्रयोग किया जाए;
- अधिप्राप्तियों तथा भंडार नियंत्रण की प्रक्रियाएँ मजबूत बनायी जाए ताकि वह अधिप्राप्तियों में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकें; एवं
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत किया जाए ताकि तंत्र के उल्लंघनों एवं लोकधन की हेराफेरी रोकी जा सके।

अध्याय-3 : राजस्व खण्ड

3 ग सामान्य परिचय

3.1.1 समन्वयों के पुनर्गठन के अन्तर्गत, सरकार के पाँच विभागों (वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प और निबन्धन, परिवहन, मनोरंजन कर) को राजस्व खण्ड के अन्तर्गत शामिल किया गया है। ये कर-राजस्व से सम्बन्धित है। अन्य विभाग सामाजिक खण्ड, सामान्य खण्ड, और आर्थिक खण्ड के अन्तर्गत आते हैं जो कर-भिन्न राजस्व का योगदान करते हैं। कर प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र बिक्री/व्यापार पर कर है। आयुक्त वाणिज्य कर द्वारा प्रशासित सेवाओं पर कर, आबकारी आयुक्त द्वारा प्रशासित राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क, वाहनों पर कर आदि हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व खण्ड द्वारा उक्त पाँचो विभागों की 239 इकाईयों में से 106 इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गई थी। लेखापरीक्षा में 272 मामलों में कुल मिलाकर ₹ 16.18 करोड़ के राजस्व के कम कर निर्धारण/न्यूनारोपण/ राजस्व क्षति के मामले इंगित किये गये। सम्बन्धित विभागों ने 15 मामलों में अन्तर्ग्रस्त ₹ 0.15 करोड़ की न्यून कर निर्धारण व अन्य कमियां स्वीकार की।

3.1.2 लेखापरीक्षा आदेश

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

3.1.3 लेखापरीक्षा के आयोजना एवं क्रियान्वयन

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत आने वाली इकाईयों/कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, विगत लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रवृत्ति और अन्य मानकों के अनुसार उच्च, मध्यम, और निम्न जोखिम वाली इकाईयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व और कर प्रबन्धन में आलोचनात्मक मुद्दे अर्थात् बजटीय भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग (राज्य और केन्द्र) के प्रतिवेदन, कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, विगत 5 वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांख्यकीय विश्लेषण, कर प्रबन्धन के घटक, लेखापरीक्षा आच्छादन और विगत 5 वर्षों के दौरान इसके प्रभाव आदि शामिल रहते हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान, लेखापरीक्षा क्षेत्र में 239 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ शामिल थी; जिनमें से 2011-12 के दौरान 106 इकाइयाँ आयोजित व लेखापरीक्षित की गई थी।

3.1.4 राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ

3.1.4.1 वर्ष 2011-12 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उदगृहित कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तद्नुरुपी आँकड़े नीचे **तालिका-3.1.1** में दिये गये हैं:

तालिका-3.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व**					
	• कर राजस्व	2,738.75	3,044.91	3,559.04	4,405.48	5,615.62
	• करेत्तर राजस्व	668.38	699.44	631.86	678.06	1,136.13
योग		**3,407.13**	**3,744.35**	**4,190.90**	**5,083.54**	**6,751.75**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश	1,427.70	1,506.59	1,550.01	2,460.07	2,866.04
	• सहायता अनुदान	3,056.26	3,384.03	3,745.22	4,064.56	4,073.45
योग		**4,483.96**	**4,890.62**	**5,295.23**	**6,524.63**	**6,939.49**
3.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**7,891.09**	**8,634.97**	**9,486.13**	**11,608.17**	**13,691.24**
4.	**1 की प्रतिशतता 3 से**	43	43	44	44	49

स्रोत : वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 49 *प्रतिशत* (₹ 6,751.75 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उदगृहित किया गया और पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में 32.82 *प्रतिशत* (₹ 1,668 करोड़) की बढोत्तरी हुई। राजस्व प्राप्तियों का अवशेष 51 *प्रतिशत* (₹ 6,939.49 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था।

3.1.4.2 कर राजस्व

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान उदगृहित कर राजस्व का विवरण निम्न **तालिका 3.1.2** तथा वर्ष 2011-12 हेतु **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

तालिका-3.1.2

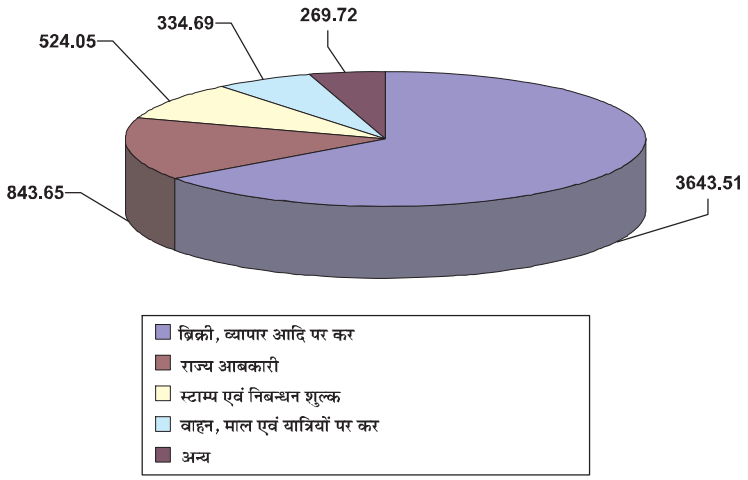
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2010-11 के सापेक्ष 2011-12 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/ कमी (-)
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,627.41	1,910.64	2,246.84	2,940.48	3,643.51	(+)23.91
2.	राज्य आबकारी	441.56	528.35	704.64	755.92	843.65	(+)11.61
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	424.27	357.46	398.70	439.50	524.05	(+)19.24
4.	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	155.26	166.98	184.56	227.26	334.69	(+)47.27
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	55.22	51.61	2.11	2.16	229.02	(+)10,502.78
6.	भू-राजस्व	23.40	17.90	8.80	18.31	10.18	(-)44.40
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	6.45	5.87	6.27	12.15	16.52	(+)35.97
8.	अन्य	5.18	6.10	7.12	9.70	14.00	(+)44.33
योग		**2,738.75**	**3,044.91**	**3,559.04**	**4,405.48**	**5,615.62**	**(+)27.47**

स्रोत : वित्त लेखे।

चार्ट-3.1

कर राजस्व



राज्य द्वारा कर संग्रह में निम्नलिखित रूझान पाये गये :

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में कर राजस्व में 27.46 *प्रतिशत* (₹ 1,210 करोड़) की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2011-12 में कुल कर संग्रह का 65 *प्रतिशत* अंशदान व्यापार, बिक्री पर कर आदि से था। वर्ष 2011-12 में राज्य आबकारी, स्टाम्प व निबन्धन शुल्क एवं वाहनों पर प्राप्त कर मिलाकर, राज्य के कुल कर संग्रह का 30 *प्रतिशत* था। व्यापार, बिक्री आदि पर कर 2005 में वैट लागू होने के बाद 34.22 *प्रतिशत* की वृद्धि दिखाने के बाद यह वृद्धि घटकर, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में सिर्फ 17.60 *प्रतिशत* वृद्धि रही क्योंकि वैट अवधि में स्थिरीकरण के साथ आई टी सी दावों में वृद्धि हुई, परन्तु 2010-11 में पुनः उछाल आया और पिछले वर्ष की तुलना में 30.87 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 23.91 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई जो कि पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में 6.96 *प्रतिशत* कम थी।
- वाणिज्य कर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, मूल्यों में वृद्धि, नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना, कर्मचारियों की कार्यदक्षता, पर्याप्त कर्मचारी और विभाग द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन में विशेष प्रयास के कारणों से हुई।
- स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन विभाग की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में 19 *प्रतिशत* (₹ 85 करोड़) की वृद्धि दर्ज हुई।

  विभाग ने बताया कि प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि, विलेख पत्रों के पंजीयन की संख्या में 1,79,980 (2010-11) से बढ़कर 2,11,379 (2011-12) होने के कारण हुई।

- विद्युत पर कर तथा शुल्क पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 227 करोड़ की एक मात्रात्मक वृद्धि दर्ज़ हुई जो कि पिछले पाँच वर्षों में सर्वाधिक था। विद्युत विभाग के अनुसार, यह वृद्धि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पिछले वर्षों के बकाया को शासकीय खातों में जमा करने के कारण हुई।
- वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 107 करोड़ की वृद्धि दर्ज़ हुई। परिवहन विभाग के अनुसार, यह वृद्धि, नये वाहनों के पंजीयन में वृद्धि, अनुमति शुल्क में वृद्धि एवं उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पिछले वर्षों का बकाया ₹ 80.11 करोड़ के जमा करने के कारण हुई।

3.1.4.3 करेत्तर राजस्व

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण निम्न **तालिका 3.1.3** तथा वर्ष 2011-12 हेतु **चार्ट 3.2** में दिया गया है:

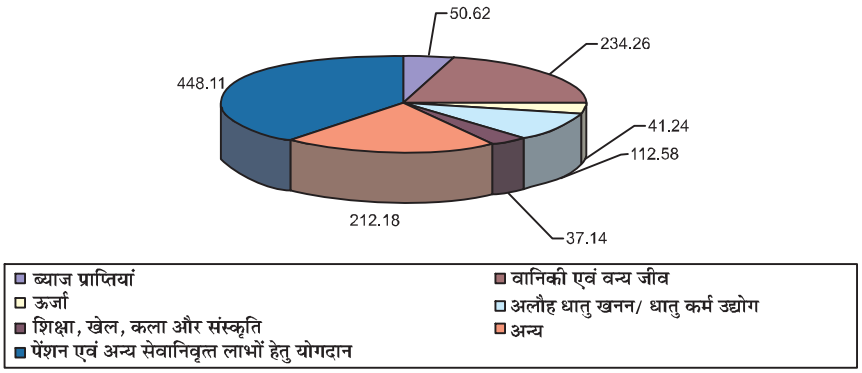
तालिका-3.1.3 *(₹ करोड़ में)*

क्रम सं	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	वर्ष 2010-11 के सापेक्ष 2011-12 में प्रतिशतता वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	41.56	68.49	53.71	53.76	50.62	(-) 5.84
2.	वानिकी एवं वन्य जीव	209.75	207.16	235.70	229.69	234.26	(+)1.99
3.	ऊर्जा	144.37	171.37	56.13	13.54	41.24	(+)204.58
4.	अलौह धातु खनन/धातुकर्म उद्योग	73.06	63.73	74.08	93.62	112.58	(+)20.25
5.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	30.69	28.66	34.18	47.47	37.14	(-) 21.76
6.	लोक निर्माण	13.96	15.53	19.50	24.83	17.85	(-) 28.11
7.	बृहद एवं मध्यम सिंचाई	5.76	5.91	5.18	5.10	8.07	(+)58.24
8.	पुलिस	5.96	7.01	9.62	11.26	11.41	(+)1.33
9.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	35.53	28.09	21.18	47.15	70.15	(+)48.78
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5.29	6.84	11.73	29.01	23.20	(-) 20.03
11.	सहकारिता	5.58	3.19	1.78	1.70	2.93	(+)72.35
12.	फसल कृषि कर्म	3.94	3.62	4.55	3.78	4.54	(+)20.11
13.	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ	26.31	27.21	37.43	49.09	448.11	(+)812.83
14.	अन्य	66.62	62.63	67.09	68.06	74.03	(+)8.77
योग		**668.38**	**699.44**	**631.86**	**678.06**	**1,136.13**	**(+) 67.56**

स्रोत : वित्त लेखे।

चार्ट-3.2

करेत्तर राजस्व



राज्य द्वारा करेत्तर राजस्व संग्रह में निम्नलिखित रूझान पाये गयेः

- करेत्तर राजस्व वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक लगभग स्थिर रहा, लेकिन इसमें पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 458 करोड़ (67.55 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व कुल प्राप्तियों का 8.30 *प्रतिशत* के साथ ₹ 1,136.13 करोड़ था।

  वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में मात्रात्मक वृद्धि उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखण्ड के बीच पहले संयुक्त रूप से तत्कालीन उत्तरप्रदेश राज्य की पेंशन देयता के विभाजन के कारण हुई। फलस्वरूप, उत्तराखण्ड राज्य को उत्तरप्रदेश से संविभाजन में ₹ 400 करोड़ की प्राप्ति हुई।
- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ (39.44 *प्रतिशत*), वानिकी एवं वन्य जीव (20.62 *प्रतिशत*) एवं अलौह धातु खनन/धातुकर्म उद्योग[1] (9.91 *प्रतिशत*) करेत्तर राजस्व के मुख्य योगदानकर्ता रहे।

निवेदन (अगस्त 2012) के बावजूद भी अन्य विभागों, जिनकी वृद्धि/कमी 20 *प्रतिशत* से अधिक थी, ने भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया।

3.1.5 बजट अनुमानों (बी ई) तथा वास्तविक में भिन्नता

वर्ष 2011-12 के लिए कर एवं करेत्तर राजस्व के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के मध्य भिन्नताएँ निम्न **तालिका 3.1.4** में वर्णित हैः

तालिका 3.1.4

(₹ करोड़ में)

क्र सं	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	भिन्नता, वृद्धि (+)/ कमी (-)	प्रतिशतता
	कर राजस्व				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	3,187.60	3,643.51	(+) 455.91	(+)14.30
2.	राज्य आबकारी	727.67	843.65	(+) 115.98	(+)15.94
3.	स्टाम्प तथा निबन्धन शुल्क	483.85	524.05	(+) 40.20	(+) 8.31
4.	वाहनों पर कर	249.53	334.69	(+) 85.16	(+) 34.13
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	75.00	229.02	(+) 154.02	(+) 205.36
	करेत्तर राजस्व				
6.	ब्याज प्राप्तियाँ	52.01	50.62	(-) 1.39	(-) 2.67
7.	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	12.21	70.15	(+) 57.94	(+) 474.53
8.	फसली कृषि कर्म	2.61	4.54	(+) 1.93	(+) 73.95
9.	पुलिस	9.01	11.41	(+) 2.40	(+) 26.64
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	17.93	23.20	(+) 5.27	(+) 29.39
11.	सड़के तथा सेतु	1.20	1.70	(+) 0.50	(+) 41.67
12.	लोक निर्माण	17.27	17.85	(+) 0.58	(+) 3.36
13.	वानिकी एवं वन्यजीव	286.83	234.26	(-) 52.57	(-) 18.33
14.	अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग	110.01	112.58	(+) 2.57	(+) 2.34

[1] अलौह धातु खनन/धातु कर्म उद्योग पर उदगृहीत रायल्टी प्रभार।

15.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	18.87	37.14	(+) 18.27	(+) 96.82
16.	ऊर्जा	235.00	41.24	(-) 193.76	(-) 82.45
17.	पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु योगदान एवं वसूलियाँ	831.00	448.11	(-) 382.89	(-) 46.08

स्रोत : प्राप्ति बजट और वित्त लेखे।

भिन्नता के कारण निम्नानुसार हैः

- वाणिज्य कर विभाग ने सूचित किया कि बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता व्यापार में वृद्धि, मूल्य वृद्धि एवं नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के कारणों से हुई।
- विद्युत विभाग के अनुसार, विद्युत पर करों तथा शुल्कों में भिन्नता उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पिछले वर्षों का बकाया शासकीय खाते में जमा करने के कारण हुई।
- परिवहन विभाग के अनुसार, भिन्नता नई गाडियों के पंजीयन में वृद्धि, अनुमति शुल्क में वृद्धि और उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा पिछला बकाया ₹ 80.11 करोड़ जमा करने के कारण हुई।
- स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग ने सूचित किया कि विलेख पत्रों के निबन्धन की संख्या में वृद्धि के कारण भिन्नता हुई।

निवेदन (अगस्त, 2012) के बावजूद भी अन्य विभागों ने, जिनमें 20 *प्रतिशत* से अधिक की भिन्नता थी, भिन्नता के कारणों को सूचित नहीं किया।

3.1.6 राजस्व प्राप्तियों के संग्रह की लागत

2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान, मुख्य राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सकल संग्रह, संग्रह पर व्यय तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता, वर्ष 2010-11 के लिए सम्बन्धित सकल संग्रह पर व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता सहित, नीचे **तालिका 3.1.5** में वर्णित हैः

तालिका-3.1.5

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	कुल संग्रह[2]	संग्रह पर व्यय	कुल संग्रह से संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2010-11 के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री/वाणिज्य कर/वैट	2009-10	2,240.84	25.63	1.14	0.75
		2010-11	2,934.95	33.46	1.14	
		2011-12	3,635.97	35.30	0.97	
2.	आबकारी	2009-10	703.71	7.33	1.04	3.05
		2010-11	755.98	8.57	1.13	
		2011-12	843.57	7.75	0.92	
3.	वाहनों पर कर	2009-10	182.16	10.64	5.84	3.71
		2010-11	223.26	13.22	5.92	
		2011-12	329.51	13.47	4.09	
4.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	2009-10	398.75	5.72	1.43	1.60
		2010-11	439.45	11.37	2.58	
		2011-12	524.02	9.40	1.79	

स्रोत : सम्बन्धित राज्य सरकार विभाग।

[2] वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 हेतु राज्य के विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सभी चार करों की संग्रह की लागत के आँकड़े तालिका में दी गई है जो कि वित्त लेखों में दर्शित आँकड़ों से मेल नहीं खाती।

इस प्रकार, राज्य आबकारी पर संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता वर्ष 2010-11 के सापेक्ष कम थी, जबकि वाहनों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन और बिक्री/वाणिज्य कर/वैट के मामले में उच्चतर थी।

बिक्री/वाणिज्य कर/वैट विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि उत्तराखण्ड में 13 जिलों में से नौ दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में है जहाँ के छोटे व्यापारी हैं, अतः संग्रहण की लागत उच्चतर थी।

परिवहन विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि पहाड़ी राज्य होने के कारण, परिचालन लागत उच्चतर है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2012) कि संग्रहण की उच्चतर लागत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि एवं जिलों के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण थी।

3.1.7 कर राजस्व के संग्रह का विश्लेषण

वर्ष 2011-12 के दौरान बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर तथा प्रवेश कर के कुल संग्रह का, पूर्व निर्धारण चरण तथा नियमित निर्धारण के पश्चात पृथक-पृथक आँकड़े, जैसे वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये थे, निम्न **तालिका 3.1.6** इंगित हैः

तालिका 3.1.6

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	पूर्व निर्धारण स्तर पर संग्रहीत धनराशि	नियमित निर्धारण के पश्चात संग्रहीत धनराशि (अतिरिक्त मांग)	कर और शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड	वापस की गई धनराशि	विभाग के अनुसार शुद्ध संग्रह	स्तम्भ 3 से 7 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्री, व्यापार पर कर/वैट	2011-12	3,509.26	145.40	1.97	26.45	3630.18	96.66
प्रवेश कर	2011-12	5.79	-	-	-	5.79	100.00

स्रोत : सम्बन्धित राज्य विभाग।

वाणिज्य कर के अन्तर्गत किया गया संग्रह, पूर्व कर निर्धारित स्तर पर 96.66 *प्रतिशत* था जबकि शुद्ध संग्रह का 3.34 *प्रतिशत* नियमित कर निर्धारण के पश्चात संग्रह किया गया।

3.1.8 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2012 को विभागों द्वारा सूचित ₹ 1490.99 करोड़ (लोक निर्माण विभाग को छोड़कर) के राजस्व बकायों में से ₹ 249.72 करोड़ (16.75 *प्रतिशत*) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसे कि नीचे **तालिका 3.1.7** में वर्णित हैः

तालिका-3.1.7

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	बकाये की धनराशि		अभ्युक्तियाँ
		31 मार्च 2012 तक	पाँच वर्षों से अधिक	
1.	**बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट**	1,073.23	199.51	₹ 73.43 करोड़ (1,341 मामलें) की वसूली *न्यायाधीन* है एवं वसूली और द्वितीय वसूली प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक थे जारी किये जा चुके है।
2.	**वाहनों पर कर**	3.82	2.29	पाँच प्रकरण (₹ 0.58 लाख) *न्यायाधीन* थे एवं शेष प्रकरणों के लिए वसूली की माँग जिलाधिकारी के माध्यम से की जा चुकी थी।

3.	**राज्य आबकारी**	0.60	0.60	₹ 24.66 लाख धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है अन्य प्रकरणों में धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
4.	**विद्युत पर कर एवं शुल्क**	269.34	-	विभाग ने बताया कि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि. से नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
5.	**मनोरंजन कर**	0.67	0.04	₹ 45.66 लाख के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
6.	**स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क**	5.48	0.59	बकाया धनराशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।
7	**भू-राजस्व**	132.02	46.69	विभाग ने बताया कि चार प्रकरण (₹ 46.69 करोड़) *न्यायाधीन* हैं।
8.	**गन्ना क्रय पर कर**	5.83	-	-
योग		**1490.99**	**249.72**	

सोत : सम्बन्धित राज्य विभाग।

सरकार को चाहिए कि बकायों की वसूली हेतु तुरन्त कार्यवाही करे विशेषकर उन प्रकरणों में जो काफी समय से लम्बित है।

3.1.9 कर निर्धारण का बकाया

2005-06 से 2010-11 की अवधि से सम्बन्धित 31 अगस्त 2012 को बिक्री कर/वैट रिटर्नों के कर निर्धारण की स्थिति का विवरण निम्न **तालिका 3.1.8** में दिया गया हैः

तालिका-3.1.8

वर्ष	कर निर्धारण हेतु मामलों की कुल संख्या			अभ्युक्तियाँ
	वर्ष के दौरान	अब तक निर्धारित	अब तक अनिर्धारित	
2005-06	1,10,620	1,10,620	--	--
2006-07	84,403	84,403	--	--
2007-08	82,172	82,172	--	--
2008-09	87,857	64,890	22,967	नवम्बर 2012 तक कालातीत होगें
2009-10	90,989	17,392	73,597	मार्च 2013 तक कालातीत होगें
2010-11	66,568	1,852	64,716	मार्च 2014 तक कालातीत होगें

सोतः सम्बन्धित राज्य विभाग

विभाग ने अवगत कराया (अक्टूबर, 2012) कि समय से निर्धारण पूरा करने के प्रयास जारी है।

3.1.10 करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के मामले, निस्तारित मामले तथा वर्ष 2011-12 में उदगृहित अतिरिक्त कर की उदगृहित माँग, का विवरण जैसे कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया, निम्न **तालिका 3.1.9** में दर्शाया गया हैः

तालिका-3.1.9

कर /शुल्क का नाम	31 मार्च 2011 को अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान पकड़े गये मामले	योग	वर्ष 2011-12 के दौरान मामलों की संख्या जिसमें निर्धारण/जाँच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त माँग की गई		31 मार्च 2012 के अनिस्तारित प्रकरणों की संख्या
				मामलों की संख्या	(₹ लाख में)	
वाणिज्य कर/वैट	1,493	4,329	5,822	4,299	1415.05	1,523

स्रोत : राज्य विभाग

विभाग द्वारा उठाई गई मांग के विरुद्ध की गई वसूली की धनराशि नहीं सूचित की गई (दिसम्बर 2012)

3.1.11 कर वापसी मामलों का निस्तारण

वाणिज्य कर विभाग ने 2011-12 में 78.72 *प्रतिशत* कर वापसी दावों का निस्तारण किया, जबकि स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के प्रकरणों में वर्ष के दौरान सभी मामले निस्तारित कर लिए गये, जैसे कि नीचे **तालिका 3.1.10** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.1.10

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्य कर		पंजीकरण एवं स्टाम्प शुल्क	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	331	1,594.67	शून्य	शून्य
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5,281	1,716.33	12	539.61
3.	वर्ष के दौरान वापसी	4,418	2,645.31	12	539.61
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	1,194	665.69	शून्य	शून्य

स्रोत : सम्बन्धित राज्य विभाग

लम्बित वापसी दावों की संख्या में वृद्धि उत्साहवर्धक नहीं है।

3.1.12 विभागों/सरकार की लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, (प्र म ले) निर्धारित नियमों के अनुसार, लेनदेनों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) तैयार की जाती हैं जिनमें निरीक्षण के समय पाई गई तथा स्थान पर ही निस्तारित न की गई, अनियमितताएँ होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती है एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को समुचित सुधार की कार्रवाई हेतु भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियाँ का अनुपालन सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करें एवं अनुपालन आख्या प्र म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर भेजें। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लाई जाती हैं।

3.1.13 राज्य सरकार के हित के संरक्षण एवं जवाबदेही लागू करने में विभागाध्यक्ष की विफलता

दिसम्बर 2011 तक निर्गत 851 निरीक्षण आख्याओं से सम्बन्धित ₹ 151.30 करोड़ के 1,797 प्रस्तर जो जून 2012 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे **तालिका 3.1.11** में दर्शाये गये हैः

तालिका-3.1.11

	जून 2010	जून 2011	जून 2012*
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,159	1,213	851
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	2,323	2,432	1,797
अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)	245.26	280.88	151.30

*विद्युत शुल्क, भू-राजस्व, विभागीय प्राप्ति एवं न्यायालय शुल्क से सम्बन्धित बकाये निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रस्तरों एवं धनराशि को दूसरे खण्डो में स्थानान्तरित कर दिया गया, अतः जून 2012 से हट गया।

30 जून 2012 को विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों व लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं अन्तर्निहित धनराशि का विवरण नीचे **तालिका 3.1.12** में दर्शाया गया हैः

तालिका-3.1.12

क्र सं.	विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	366	959	74.05
2.	मनोरंजन कर	मनोरंजन कर, विलास कर इत्यादि	46	62	1.14
3.	आबकारी	राज्य आबकारी	69	91	30.49
4.	परिवहन	मोटर गाडियों इत्यादि पर कर	98	270	34.69
5.	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	272	415	10.93
योग			**851**	**1,797**	**151.30**

निरीक्षण प्रतिवेदनों और सम्प्रेक्षा आपत्तियों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा में दर्शायी गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं को दूर करने हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा आपत्तियों के निस्तारण में अत्यधिक देरी, उनका अत्यधिक पुराने हो जाने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा वसूली/कार्यवाही करने के जोखिम को बढ़ाता है।

3.1.14 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

उत्तराखण्ड सरकार की राजस्व प्राप्तियों के निरीक्षण प्रतिवेदन के बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों के शीघ्र निस्तारण के लिए शासन द्वारा विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया। यद्यपि, लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक वर्ष 2011-12 के दौरान नहीं हुई।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार;

- सम्बन्धित विभागों को सलाह दे कि वे लेखापरीक्षा समिति की बैठक बारम्बार आयोजित करें और प्रस्तरों के निस्तारण पर निगरानी रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि माँग/वसूली समय पर की जा रही है और
- लेखापरीक्षा आपत्ति के तत्काल एवं उचित उत्तर के लिए प्रभावकारी कार्यवाही को लागू करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए साथ ही साथ कार्यालय/अधिकारियों के विरूद्ध, जो निर्धारित समय में निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों के उत्तर देने में असफल रहे हों और निर्धारित समयावधि में हानि/बकाये की वसूली के कार्य में असफल रहे हों कार्यवाही करना चाहिए।

3.1.15 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

स्थानीय निरीक्षण के दौरान देखे गये गम्भीर एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों (प्रलेख प्रस्तर) को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु, प्रस्तावित किया जाता है जिन्हे सम्बन्धित विभाग के सचिवों को उनका ध्यान आकर्षित करते हुये उनके उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ अग्रसारित किया जाता है। निर्धारित समयान्तर्गत विभाग/शासन के उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में प्रलेख प्रस्तर के तथ्यों एवं आँकड़ों को विभाग/शासन की स्वीकारोक्ति मानते हुए इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर के अन्त में उल्लिखित कर दिया जाता है।

3.1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग का प्रत्युत्तर-संक्षिप्त स्थिति

राज्य के गठन के बाद, लोक लेखा समिति की अधिसूचना मई, 2001 में जारी की गयी। भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है एवं विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं। प्रतिवेदन पर शासन द्वारा कृत कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को सरकार द्वारा समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। सरकार/विभाग द्वारा प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक टिप्पणी असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की जाती रही है। उत्तराखण्ड सरकार से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2000-01 से 2007-08 तक के राजस्व प्राप्ति प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति में 2005-06 से 2011-12 के वर्षों में विवेचित किए गए थे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणी/कृत कार्रवाई के 27 प्रकरण, 31 मार्च 2012 तक समिति के समक्ष लम्बित थे।

3.1.17 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 5 वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च 2012 तक की स्थिति निम्न **तालिका 3.1.13** में दर्शायी गई हैः

तालिका-3.1.13

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष		
		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
1.	2007-08	214	521	20.26	22	93	1.55	3	57	2.51	233	557	19.30
2.	2008-09	233	557	19.30	49	206	21.63	8	69	2.32	274	694	38.61
3.	2009-10	274	694	38.61	44	105	12.04	6	48	0.64	312	751	50.01
4.	2010-11	312	751	50.01	54	158	89.37	6	32	0.70	360	877	138.68
5.	2011-12	360	877	136.88	54	192	8.56	12	46	65.94	402	1023	79.50

जैसा कि उक्त तालिका से विदित है, वर्ष 2007-08 के प्रारम्भ में बकाया 214 निरीक्षण प्रतिवेदनों में 521 प्रस्तरों की संख्या वर्ष 2011-12 के अन्त में बढ़कर 402 प्रतिवेदनों में 1023 प्रस्तर हो गयी थी, जबकि 2007-12 अवधि में 252 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

यह इस तथ्य को इंगित करता है कि विभाग द्वारा राज्य के राजस्व के हित में कार्यवाही के सकारात्मक प्रयास नहीं किये गये, जिसके परिणामस्वरूप अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की संख्या में वृद्धि हुई।

3.1.18 स्वीकृत प्रकरणों के राजस्व की वसूली

वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रस्तरों के सम्बन्ध में, ₹ 10.49 करोड़ निहित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को विभाग/सरकार ने स्वीकार किया, जिसका, 31 मार्च, 2012 तक, मात्र ₹ 2 लाख वसूल किया गया था जैसा निम्न **तालिका 3.1.14** में इंगित किया गया है।

तालिका-3.1.14

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल मुद्रा मूल्य	स्वीकार किया गया मुद्रा मूल्य	वसूली गयी धनराशि
2005-06	7.58	3.19	0.01
2006-07	1.03	0.02	0.01
2007-08	60.48	0.05	Nil
2008-09	7.00	0.91	Nil
2009-10	8.47	6.21	Nil
2010-11	1.03	0.11	Nil
योग	**85.59**	**10.49**	**0.02**

तथ्य यह है कि स्वीकृत धनराशि का मात्र 0.19 *प्रतिशत* वसूली की गई है जो कि सरकार की प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

3.1.19 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, मोटरवाहन तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 107 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 272 मामलों में ₹ 16.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण/अल्प आरोपण/राजस्व हानि हुई, जिसमें विभाग ने 15 प्रकरणों में ₹ 0.15 करोड़ स्वीकार किया। तथापि, वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 41 प्रकरणों में ₹ 0.49 करोड़ की वसूली हुई।

3.1.20 इस रिपोर्ट के राजस्व अध्याय के विषय

इस अध्याय में, उत्तराखण्ड में वैट प्रशासन की एक निष्पादन लेखापरीक्षा और एक राज्य आबकारी विभाग पर विभागीय केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा, जिसमें कर का अल्प आरोपण, छूट एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत प्रदान किया जाना, अल्कोहल आदि पर कम वसूली के कारण राजस्व की क्षति से सम्बन्धित ₹ 6.26 करोड़ का राजस्व निहित है। ₹ 0.15 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है।

3 घ. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मुख्य अंश

उत्तराखण्ड में मूल्यवर्धित कर प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- *प्रपत्र-XVII, जो पंजीकृत व्यापारी से अन्यथा पक्षों द्वारा माल के आयात के लिये एक प्रमाणपत्र है; और उद्गम प्रमाणपत्र (ओ सी), जो व्यापारियों को राज्य के अन्दर व्यापार में बिना करारोपण किए माल के अन्य राज्य से पारगमन पर वांछनीय है, के निर्गमन एवं कर-सम्परीक्षा हेतु प्रावधान/मॉड्यूल मानचित्रित नहीं किया गया है ।*

(प्रस्तर 3.2.13.2 एवं 3.2.16.2)

- *क्षेत्रीय इकाईयों, जाँच चौकियों एवं आयुक्तालय की अन्तर्सम्बद्धता के अभाव में, कम्प्यूटरीकरण के अभिप्रेत उद्देश्य, जैसे कि आँकड़ों का ऑनलाईन संप्रेषण, विभिन्न विवरणों का प्रतिसत्यापन इत्यादि पूर्णरूप से प्राप्त न हो सका ।*

(प्रस्तर 3.2.13.5)

- *कम दर से करारोपण, उपेक्षित करयोग्य आवर्त एवं बिक्री/आवर्त के छुपाव के कारण ₹ 2.61 करोड़ कर एवं ₹ 1.97 करोड़ ब्याज का न्यूनारोपण/अनारोपण था ।*

(प्रस्तर 3.2.14.1 एवं 3.2.14.2)

- *₹ 44.12 लाख राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) की अनुमन्यता अनियमित थे। तदनुरूप, रियायत/छूट की अनुमन्यता के परिणामस्वरूप ₹ 39.88 लाख कर एवं ₹ 25.69 लाख ब्याज का न्यूनारोपण हुआ।*

(प्रस्तर 3.2.14.4 एवं 3.2.14.5)

- *यद्यपि मूल्यवर्धित कर छः वर्षों से विद्यमान है, तथापि मूल्यवर्धित कर मैन्युअल तैयार किया जाना अभी तक शेष है ।*

(प्रस्तर 3.2.16.3)

- *अपील में, 3,213 मामलों में से 762 मामले पाँच वर्षों से अधिक की अवधि से निस्तारण हेतु लम्बित थे; जिनमें ₹ 10.37 करोड़ राजस्व अन्तर्निहित था ।*

(प्रस्तर 3.2.16.4)

राज्य आबकारी विभाग की विभाग केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा

- *दो जिला आबकारी अधिकारियों ने नौ अनुज्ञापियों के विरुद्ध अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक की बिक्री करने पर धारा-64 के अन्तर्गत 23 अपराधों को दर्ज़ किया था । इन प्रकरणों को नाममात्र शमन शुल्क के भुगतान पर निस्तारित कर दिया था । इनमें 23 प्रकरणों में से दो एवं तीन अनुज्ञापियों द्वारा क्रमशः चार और तीन बार उल्लंघन किया गया ।*

(प्रस्तर 3.3.8.4)

- *शीरे से एल्कोहल के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप ₹ 20.66 लाख के राजस्व से वंचित होना।*

(प्रस्तर 3.3.8.6)

वाणिज्य कर विभाग

3.2 उत्तराखण्ड में मूल्यवर्धित कर प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड में मूल्यवर्धित कर प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँचने के लिये किया गया था कि क्या राज्य के राजस्व की अभिरक्षा के लिये विभाग द्वारा जारी किये गये नियमों एवं परिपत्रों तथा मूल्यवर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की उचित प्रणाली विद्यमान है। 2008-09 से 2011-12 अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा में कमियों, जैसे कि कम्प्यूटरीकृत मॉड्यूल्स में विभिन्न सुविधाओं का मानचित्रित न होना, कर का न्यूनारोपण, रियायत एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमन्यता, जनशक्ति की कमी, अधिक संख्या में लम्बित अपील के मामले, कर-सम्परीक्षा की कमी इत्यादि पायी गयी।

मुख्य अंश

- ***प्रपत्र-XVII, जो गैर-पंजीकृत व्यापारियों द्वारा माल के आयात के लिये प्रमाणपत्र है और उद्गम प्रमाणपत्र (ओ सी), जो व्यापारियों को राज्य के अन्दर व्यापार में बिना करारोपण किए माल के अन्य राज्य से पारगमन पर वांछनीय है, के निर्गमन एवं कर-सम्परीक्षा हेतु प्रावधान/मॉड्यूल मानचित्रित नहीं किया गया है।***

  (प्रस्तर 3.2.13.2 एवं 3.2.16.2)

- ***क्षेत्रीय इकाईयों, जाँच चौकियों एवं आयुक्त कार्यालय की अन्तर्सम्बद्धता के अभाव में कम्प्यूटरीकरण के अभिप्रेत उद्देश्य, जैसे कि आँकड़ों का ऑनलाईन संप्रेषण, विभिन्न विवरणों का प्रतिसत्यापन इत्यादि पूर्णरूप से प्राप्त न हो सके।***

  (प्रस्तर 3.2.13.5)

- ***करो को कम दरों पर आरोपित करने, करयोग्य कारोबार को छुपाने व बिक्री/कारोबार को कमतर दिखाने के कारण* ₹ 2.61 करोड़ के कर एवं ₹ 1.97 करोड़ के ब्याज का न्यूनारोपण/अनारोपण।**

  (प्रस्तर 3.2.14.1 एवं 3.2.14.2)

- ***₹ 44.12 लाख राशि के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) की अनुमन्यता अनियमित थी। इसी प्रकार, रियायत/छूट के अनियमित अनुमन्यता के परिणामस्वरूप ₹ 39.88 लाख के कर एवं ₹ 25.69 लाख के ब्याज का न्यूनारोपण हुआ।***

  (प्रस्तर 3.2.14.4 एवं 3.2.14.5)

- ***यद्यपि मूल्यवर्धित कर प्रणाली छः वर्षों से विद्यमान है तथापि मूल्यवर्धित कर मैन्युअल तैयार किया जाना शेष है।***

  (प्रस्तर 3.2.16.3)

- ***3,213 मामलों में से 762 मामलों में किए गए अपील पाँच वर्षों से अधिक की अवधि से निस्तारण हेतु लम्बित थे जिनमें ₹ 10.37 करोड़ राजस्व अन्तर्निहित था।***

  (प्रस्तर 3.2.16.4)

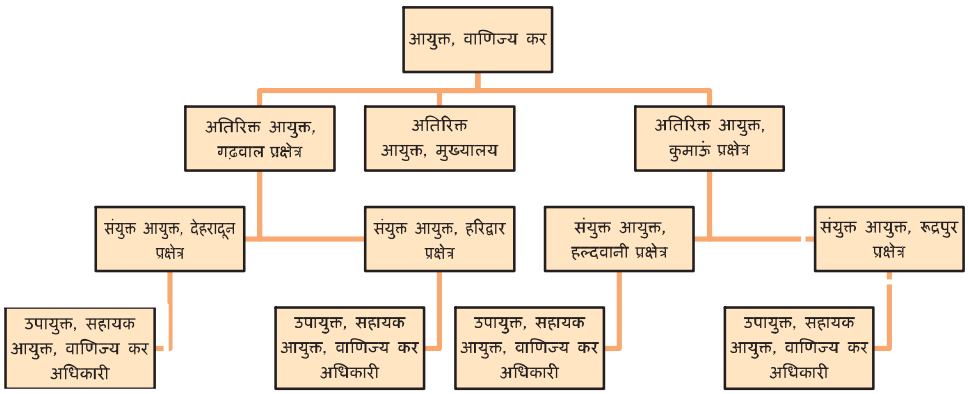
3.2.1 प्रस्तावना

मूल्यवर्धित कर (वैट) एक बहुबिन्दु कराधान प्रणाली है जहाँ माल उपभोक्ता तक पहुँचने तक, उत्पादन एवं वितरण श्रृंखला में विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर, कर के अधीन है। उत्तराखण्ड राज्य में वैट प्रणाली, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अंगीकरण एवं संसोधन आदेश, 2002 को निरसित करके तथा कर प्रशासन में अधिक दक्षता एवं कराधान प्रणाली में निष्पक्षता लाने हेतु "उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर (यूवैट) अधिनियम, 2005" नामक एक अधिनियम अक्टूबर 2005 के पहले दिन से अस्तित्व में आया। अधिनियम में व्यापारियों के पंजीयन, रिटर्न दाखिल करने, कर की वसूली एवं वापसी, कर की दरों, अपील एवं पुनरीक्षण, अर्थदण्ड इत्यादि से सम्बन्धित XI अध्याय समावेशित है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ **परिशिष्ट-3.1** में उद्धृत हैं।

वाणिज्य कर विभाग कर निर्धारण, वैट के आरोपण एवं संग्रहण हेतु उत्तरदायी है तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, नियमों एवं इस सम्बन्ध में जारी परिपत्रों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

3.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:



3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से सम्पादित किया गया था कि:

- प्रपत्रों की प्राप्ति निर्गम एवं उपयोग की प्रणाली पर्याप्त थी;
- क्या व्यापारियों के पंजीयन एवं उनके द्वारा रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली प्रभावकारी थी;
- कम्प्यूटरीकरण की दक्षता एवं प्रभावकारिता तथा यह सुनिश्चित करना कि क्या विद्यमान सूचना प्रौद्योगिकी नियन्त्रण पर्याप्त था;

- करारोपण एवं संग्रहण, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) की अनुमन्यता, छूट एवं रियायत तथा वापसी का भुगतान प्रचलित अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप हैं;
- दक्ष एवं प्रभावी तरीके से मानव संसाधन का प्रबन्धन किया गया है; तथा
- क्या विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण पर्याप्त एवं प्रभावी है।

3.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गयेः

- उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005;
- उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005;
- उत्तराखण्ड प्रवेश कर अधिनियम, 2008;
- उत्तराखण्ड प्रवेश कर नियम, 2009; तथा
- विभागीय परिपत्र एवं अधिसूचनाएँ।

3.2.5 लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि की क्रमशः विभाग के मुख्यालय, 23 उपायुक्त (कर निर्धारण) {उ आ (क नि)} में से छः[3], 47 सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) {स आ (क नि} वाणिज्य कर अधिकारी (वा क अ) सहित, में से 14[4] तथा 22 जाँच चौकियों एवं आठ सचल दस्ते में से एक जाँच चौकी[5] तथा एक सचल दस्ता[6] के अभिलेखों एवं कम्प्यूटरीकृत आँकड़ों की नमूना जाँच के माध्यम से मई, 2012 से सितम्बर, 2012 की अवधि के दौरान सम्पादित की गयी।

इकाईयों का नमूना "प्रोबैबिलिटी प्रपोर्सनल टू साइज विद आउट रिप्लेसमेन्ट (पी पी एस डब्ल्यू ओ आर) विधि" द्वारा किया गया। प्रवेश गोष्ठी दिनांक 23 जुलाई, 2012 को सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन के साथ की गयी थी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गयी। सरकार/विभाग को उनकी प्रतिक्रिया हेतु मसौदा प्रतिवेदन दिनांक 14 नवम्बर, 2012 को प्रेषित किया गया था।

प्रस्थान गोष्ठी में निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बन्ध में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन के साथ चर्चा की गयी (17 दिसम्बर, 2012)। सरकार के उत्तर को प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर समाविष्ट कर लिया गया है।

---

[3] उ आ-I हरिद्वार-उ आ ,II रूड़की-उ आ ,I एवं V देहरादून-उ आ ,II काशीपुर तथा उ आ-II हल्द्वानी।

[4] स आ-II ,III एवं V देहरादून-स आ ,II ऋषिकेश-स आ ,स आ कोटद्वार ,I एवं II रूड़की-स आ ,II हरिद्वार-स आ ,स आ किच्छा ,III रुद्रपुर-स आ ,II हल्द्वानी-स आ ,I अल्मोड़ास आ नैनीताल तथा स आ रामनगर।

[5] जाँच चौकीनारसन।

[6] स आ सचल दस्ता हल्द्वानी।

3.2.6 आभारोक्ति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्य कर विभाग के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

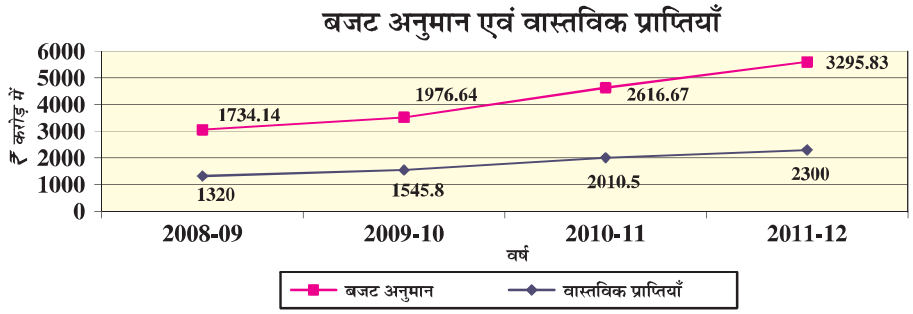
3.2.7 राजस्व का रूझान

2008-09 से 2011-12 की अवधि के बजट अनुमान के साथ महालेखाकार (ले व हक), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किये गये वित्त लेखे के अनुसार वैट के कर संग्रहण तथा पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि दर निम्न **तालिका-3.2.1** में दिया गया है:

तालिका-3.2.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वैट का संग्रहण	भिन्नता (*प्रतिशत*)	राज्य की कुल प्राप्ति	कुल प्राप्तियों में वैट का *प्रतिशत*	पिछले वर्ष की तुलना में वैट की वृद्धि दर (%)
2008-09	1320.00	1734.14	(+) 31	8634.98	20	16.52
2009-10	1545.80	1976.64	(+) 28	9486.13	21	13.98
2010-11	2010.50	2616.67	(+) 30	11608.16	23	32.37
2011-12	2300.00	3295.83	(+) 43	13691.24	24	25.95



उक्त से स्पष्ट है कि वैट के संग्रहण एवं राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वैट के अंश में बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। लेखापरीक्षा में आच्छादित सभी वर्षों के वैट संग्रह बजट अनुमानों से अधिक थे। आगे देखा गया कि वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2011-12 में बजट अनुमान यथार्थवादी नहीं थे क्योंकि ये पिछले वर्षों के वैट संग्रह से भी कम थे। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 में वृद्धि दर 32.37 *प्रतिशत* तक पहुँच गयी।

3.2.8 पंजीकृत व्यापारी

2008-09 से 2011-12 की अवधि में राज्य में पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या में बढ़ोत्तरी हुई, जैसा कि **तालिका-3.2.2** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2.2

वर्ष	पंजीकृत व्यापारियों की कुल संख्या
2008-09	66607
2009-10	79316
2010-11	84759
2011-12	84323

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2008-12 की अवधि के दौरान पंजीकृत व्यापारियों की संख्या में 66,607 से 84,323 तक वृद्धि हुई, जिसने वैट संग्रह में वृद्धि में अंशदान किया जिस पर उपरोक्त प्रस्तर 3.2.7 में चर्चा किया जा चुका है।

3.2.9 वैट संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान, मुख्यशीर्ष- व्यापार, बिक्री आदि पर कर (0040) के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किये गये व्यय एवं सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता के साथ ही सकल संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय प्रतिशतता नीचे **तालिका-3.2.3** में दिया गया हैः

तालिका-3.2.3 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	सकल संग्रहण[7]	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का *प्रतिशत*	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2008-09	1902.38	22.69	1.19	0.91
2009-10	2240.84	25.63	1.14	0.88
2010-11	2934.95	33.46	1.14	0.96
2011-12	3635.97	35.30	0.97	0.75

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग संग्रहण लागत में कमी करने में सफल रहा, लेकिन ये अखिल भारतीय औसत से उच्च थे। तथापि, लेखापरीक्षा इसकी सराहना करता है, संग्रहण लागत को अखिल भारतीय औसत के समतुल्य या कम पर लाने के लिये अधिक प्रयत्न की आवश्यकता है।

3.2.10 निरसित अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व बकायों की वसूली

क. 30 सितम्बर, 2005 को निरसित अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 36.50 करोड़ के बकाए लम्बित थे। इनमें से, 31 मार्च, 2012 तक न वसूल हुई कुल धनराशि का विवरण वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त विवरण के अभाव में, निरसित अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वसूली लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सका।

ख. माँग व वसूली की निगरानी हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संधारित आर-3 पंजिका की नमूना जाँच में देखा गया कि ₹ 12.99 लाख बीस वर्षों से अधिक से वसूली हेतु लम्बित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3.2** में सोदाहरण वर्णित है। यद्यपि विभाग द्वारा समस्त मामलों में वसूली प्रमाणपत्र (आर सी) जारी किये गये थे, तथापि काफी समय से लम्बित इन वसूलियों को या तो वसूली या अपलेखन, यदि वसूली सम्भव न हो, के माध्यम से निस्तारण हेतु अग्रिम कार्यवाही आरम्भ नहीं की गयी थी।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने आयुक्त, कर को पुनः वसूली प्रमाणपत्र जारी करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र जारी करने तथा विभाग के अधिकृत अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित करने का निर्देश दिया (दिसम्बर, 2012)। पुराने बकायों, जो वसूली योग्य नहीं हैं, के मामलें में सचिव, वित्त ने विभाग के सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारियों को

[7] वैट पर संग्रहण, मनोरंजन कर, वैटमोटर स्प्रिट्स पर कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर सम्मिलित है।

राजस्व विभाग के अधिकृत अधिकारियों के साथ तीन माह के भीतर नियमों के अन्तर्गत अपलेखन की कार्यवाही आरम्भ करने का निर्देश दिया।

3.2.11 प्रपत्रों की प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग की प्रणाली

विभाग रियायती प्रपत्रों के मुद्रण हेतु निविदा आमन्त्रित करता है तथा मुद्रण के दौरान किसी दुरुपयोग से बचने हेतु निविदा के साथ-साथ आपूर्ति आदेशों में विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। मुद्रण के पश्चात् इन प्रपत्रों को विभाग के मुख्यालय के भण्डार द्वारा प्राप्त किया जाता है। भण्डार से इन प्रपत्रों को संयुक्त आयुक्तों को उनकी आवश्यकतानुसार निर्गत किया जाता है। संयुक्त आयुक्तों द्वारा पुनः इन प्रपत्रों को माँगपत्र के आधार पर कर निर्धारण प्राधिकारियों अर्थात् उ आ एवं स आ को जारी किया जाता है। इन प्रपत्रों को कर निर्धारण प्राधिकारियों से, विभाग द्वारा समय-समय पर नियत शुल्क के भुगतान पर, पंजीकृत व्यापारियों को प्राप्य है।

विभाग ने कम्प्यूटर के माध्यम से प्रपत्रों के निर्गमन हेतु एक फार्म मॉड्यूल विकसित किया है। सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त से प्रपत्रों के प्राप्त होने पर, उनकी श्रृंखला/क्रमांक को "मास्टर प्रविष्टि" के रूप में फार्म मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाता है। इन्हें मॉड्यूल द्वारा उत्पन्न क्रम संख्या के अनुसार व्यापारी को निर्गत किया जाता है।

नमूना चयनित इकाईयों में चार प्रपत्रों यथा प्रपत्र सी, एफ, XI एवं XVI को मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्ति, निर्गम एवं उपयोग की प्रणाली का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित कमियाँ देखी गयीः

- गढ़वाल सम्भाग की 12 चयनित इकाईयों में केवल प्रपत्र सी, एफ एवं XVI को मॉड्यूल के माध्यम से निर्गत किये जा रहे थे।
- कुमाऊँ सम्भाग की आठ चयनित इकाईयों में से सात में केवल प्रपत्र XVI को मॉड्यूल के माध्यम से निर्गत किया जा रहा था।

पुनः, जहाँ प्रपत्रों को मॉड्यूल के माध्यम से निर्गत किये जा रहे थे, यह देखा गया कि महत्वपूर्ण आँकड़ों, जैसे खोए/निरस्त प्रपत्रों, जमा शुल्क, चालान संख्या एवं दिनांक के विवरण को मॉड्यूल में उपलब्ध संगत खानों में प्रविष्ट नहीं किये गये थे। कतिपय व्यापारियों के मामलों में, डेटाबेस में स्थायी लेखा संख्या (पैन संख्या) को भी प्रविष्ट नहीं किया गया था।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने बताया कि कार्यात्मक प्रपत्र मॉड्यूल स्थानीय सर्वर पर आधारित है तथा वेब आधारित प्रपत्र मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। यह मॉड्यूल लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों को सही करने के पश्चात् ही चालू किया जायेगा। इस मॉड्यूल के चालू किये जाने के पश्चात्, प्रपत्रों के निर्गमन में भी एकरूपता होगी। पुनः बताया कि सिस्टम में बैकलॉग को भरने हेतु दिनांक 14 मई, 2012 को आयुक्त, कर द्वारा एक परिपत्र जारी किया जा चुका है। सचिव, वित्त ने इसे कड़ाई से पालन हेतु निर्देश दिया।

3.2.12 व्यापारी प्रबन्धन

अधिनियम की धारा 3 (7) सपठित धारा 15 में प्रावधान है कि कोई व्यापारी कर का दायी होगा, यदि माल के विक्रय का उसका कुल कारोबार ₹ पाँच लाख है तथा ऐसा व्यापारी ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति के अनुसार, जैसा कि विहित की जाए, अपने आपको पंजीकृत करायेगा। पुनः अधिनियम की धारा 15 (4) (घ) में प्रावधान है कि बीयर सहित मदिरा का प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार को ध्यान में न रखते हुए राज्य में व्यापार प्रारम्भ करने की तारीख से पंजीयन हेतु दायी होंगे।

(क) यह देखा गया कि नमूना चयनित 14 स आ (क नि) में से केवल दो[8] ने पंजीयन हेतु दायी अपंजीकृत व्यापारियों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया तथा लेखापरीक्षा अवधि में पता लगाये गये समस्त 40 व्यापारियों को पंजीकृत कराया।

(ख) लेखापरीक्षा ने आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, देहरादून को 342 व्यापारियों, जिन्हें 2008-09 से 2011-12 की अवधि में देहरादून परिक्षेत्र में रोड़ी, बजरी, बालू एवं ग्रिट के उत्खनन हेतु खनन विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी किया गया था, की एक सूची यह सत्यापित करने हेतु अग्रसारित किया (16 अगस्त, 2012) कि क्या पंजीयन हेतु दायी व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है। विभाग ने अक्टूबर, 2012 तक उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

(ग) विभाग से वैसे व्यापारियों, जिन्हें विभाग की विशेष जाँच शाखा (एस आई बी) द्वारा पंजीयन हेतु चिन्हित किया गया था, की कुल संख्या तथा उसके विरूद्ध पंजीकृत हुए व्यापारियों की संख्या का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया था। विभाग ने अक्टूबर, 2012 तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी।

(घ) पंजीयन के लिये दायी अपंजीकृत व्यापारियों का पता लगाने हेतु आवधिक सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में वैट अधिनियम या जारी किसी अधिसूचना/अनुदेश में, मानक/लक्ष्य निर्धारित नहीं थे।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने आयुक्त, कर को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये टिप्पणियों पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

(ङ) तीन व्यापारियों के मामलों में, स्टॉक लेखे में 4 *प्रतिशत* एवं 12.5 *प्रतिशत* के बिना विभाजन के प्रारम्भिक तथा अन्तिम स्टॉक में माल का कुल मूल्य दर्शाने से दुर्विनियोजन का अवसर रहता है।

(च) अनेक मामलों में रिटर्न के साथ संलग्न क्रय सूची में वस्तु का नाम अंकित नहीं था, जिसके अभाव में कर की सही दर/आई टी सी सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने क्रय सूची में वस्तु का नाम, प्रारम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक विभाजन सम्बन्धी परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

---

[8] स आ किच्छा एवं स आ अल्मोड़ा।

(छ) अधिनियम के अन्तर्गत बीयर सहित शराब का प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार पर ध्यान न रखते हुए पंजीयन का दायी होगा। मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इस मामले को इंगित किया गया था, जिसमें विभाग ने कहा था कि मामले पर ध्यान दिया जायेगा तथा कार्यवाही की जायेगी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि न तो व्यापारियों ने स्वयं पंजीयन करवाया और न ही विभाग ने उनको पंजीकृत करने की कार्यवाही आरम्भ की।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने सचिव एवं आयुक्त, आबकारी को मदिरा/बीयर की दुकान के परिचालन के पूर्व व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग से टिन संख्या प्राप्त करने के प्रावधान बनाने के सम्बन्ध में पत्र जारी करने का निर्देश दिया। सचिव ने पुनः निर्देश दिया कि वर्तमान में ऐसे व्यापार में शामिल व्यापारियों के पंजीयन हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए।

3.2.13 कम्प्यूटरीकरण

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) ने वाणिज्य कर विभाग हेतु एक वेब आधारित वैट अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकसित किया। सॉफ्टवेयर में डीलर एडमिनिस्ट्रेशन, रिटर्न माड्यूल, फार्म मैनेजमेन्ट, टिनएक्सिस एवं पेमेन्ट मॉड्यूल नाम से मॉड्यूल्स हैं।

3.2.13.1 अच्छी परम्पराएँ

(क) विभाग ने रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से व्यापारियों के पंजीयन हेतु प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू किया। व्यापारी पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन करते हैं तथा विभाग द्वारा आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर टिन संख्या आवंटित कर दिया जाता है।

(ख) रिटर्न मॉड्यूल व्यापारियों द्वारा दाखिल विवरणी पर निगरानी रखता है। समय पर अपनी विवरणी दाखिल न करने वाले व्यापारियों की सूची बनायी जा रही थी तथा ऐसे व्यापारियों को नोटिस दिया गया था। ऐसे व्यापारियों के पंजीयन, जो नोटिस के पश्चात् भी अपनी विवरणी दाखिल नहीं करते, निलम्बित किये गये थे।

3.2.13.2 प्रणाली परिकल्पना में कमियाँ

यह देखा गया कि अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में कतिपय मुख्य विशिष्टियाँ अनुपस्थित थीं, जो निम्न वर्णित हैं:

- सॉफ्टवेयर में पृथक रूप से प्रान्तीय एवं केन्द्रीय पंजीयन को निरस्त करने हेतु प्रावधान नहीं था। स आ (क नि), कोटद्वार की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तीन व्यापारियों ने अपने केन्द्रीय पंजीयन को निरस्त करने हेतु आवेदन किया था, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पंजीयन को निरस्त नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रान्तीय पंजीयन भी एक साथ ही निरस्त हो जाता था।
- फार्म मॉड्यूल की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मॉड्यूल में खोए/निरस्त प्रपत्रों की कुल संख्या को प्रविष्ट करने का प्रावधान था, लेकिन इन प्रपत्रों की क्रम संख्या को प्रविष्ट करने का प्रावधान नहीं था। पुनः, मॉड्यूल की संवीक्षा में देखा गया कि प्रपत्रों के लिए जमा शुल्क की धनराशि हेतु खानें तो है, लेकिन जमा किए गए शुल्क एवं जारी प्रपत्रों की संख्या में कोई नियन्त्रण नहीं है। इस प्रकार

की अधिप्रमाणन नियन्त्रण के अभाव में, व्यापारी के खाते में अवशेष राशि के न होने पर भी उनको प्रपत्र जारी किये गये थे।

- फार्म मॉड्यूल में उद्गम प्रमाणपत्र (ओ सी)[9] के निर्गमन हेतु प्रावधान नहीं था। इसे हस्तलिखित रुप से जारी किया जा रहा था।
- यह देखा गया कि फार्म मॉड्यूल में प्रपत्र-XVII[10] निर्गमन हेतु प्रावधान नहीं था। तथापि जाँच चौकियों हेतु विकसित सॉफ्टवेयर में प्रपत्र-XVII के विवरण प्रविष्ट करने हेतु प्रावधान था तथा इन विवरणों को नमूना जाँच चौकी, नारसन में पंजी 1 तथा पंजी 2[11] में प्रविष्ट किये जा रहे थे। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मॉड्यूल के माध्यम से प्रपत्र-XVII के निर्गमन हेतु प्रावधान के अभाव में, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जाँच चौकी के आँकड़ों को प्रतिसत्यापन हेतु उपयोग नहीं किया जा सका।
- सॉफ्टवेयर में सचल दस्ता से सम्बन्धित आँकड़ों के संकलन हेतु प्रावधान नहीं था।
- सॉफ्टवेयर में विलम्ब से भुगतान तथा उस पर देय ब्याज की गणना हेतु प्रावधान नहीं था।
- सॉफ्टवेयर में कर वापसी से सम्बन्धित आँकड़ों को लेने हेतु प्रावधान नहीं था।
- सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम आई एस) प्रतिवेदनों को तैयार करने हेतु प्रावधान नहीं था, जो कि वर्तमान में हस्तलिखित तैयार किये जा रहे हैं।
- ऐसे व्यापारियों, जिनका कारोबार ₹ 50 लाख से अधिक है, को ई-फाईलिंग रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य था। यह देखा गया कि सॉफ्टवेयर में 'क्रय सूची' एवं 'विक्रय सूची', जो विवरणी के अत्यधिक महत्वपूर्ण संलग्नक होते हैं, के संग्रहण हेतु प्रावधान नहीं था। तथापि, ऐसे संलग्नकों को विवरणी के साथ कागजी प्रति के रूप में संलग्न किया गया था। क्रय/विक्रय के विवरण की अनुपलब्धतता से कम्प्यूटर के माध्यम से रिटर्न का प्रतिसत्यापन करने में बाधा पहुँची, जैसा कि प्रस्तर-3.2.14.2 एवं 3.2.14.4 में चर्चा किया गया है।
- कर सूचना विनिमय प्रणाली (टिनएक्सिस), भारत के केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा विभिन्न राज्यों में फैले समस्त अन्तर्राज्यीय व्यापारियों का एक केन्द्रीकृत एक्सचेंज है। टिनएक्सिस, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं के बि क अधिनियम के अन्तर्गत जारी वैधानिक प्रपत्रों, जो अन्य राज्यों द्वारा जारी किया जाता है तथा रियायत/छूट के दावे हेतु व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, के प्रतिसत्यापन में सक्रियता से निगरानी करने में मदद करता है। यह देखा गया कि जारी प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के विवरण टिनएक्सिस पर अपलोड नहीं किये गये थे।

---

[9] जो कि प्रान्त के अन्दर व्यापार में ऐसे मालतु व्यापारियों के पारगमन हे, जो अन्य राज्य से होकर गुजरने पर उस राज्य में बिना कर लगे, को आवश्यकता होती है।

[10] जो पंजीकृत व्यापारियों से इतर पक्षों द्वारा माल के आयात हेतु एक प्रमाणपत्र होता है।

[11] **पंजी 1:** एक पंजिका विक्रेता व्यापारी एवं परिवहनकर्ता के विवरण /जिसका रखरखाव जाँच चौकी पर किया जाता है और जिसमें क्रेता, अभिलिखित किये जाते हैं।

पंजी 2: एक पंजिका प्रमात्रा एवं राशि तथा, जिसका रखरखाव जाँच चौकी पर किया जाता है और जिसमें माल का विवरण अर्थात् नाम, उपयोग किये गये प्रपत्रों के विवरण अभिलिखित किये जाते हैं।

3.2.13.3 सूचना प्रौद्योगिकी नियन्त्रण की सामान्य कमी

कम्प्यूटरीकृत प्रणाली अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नियन्त्रण में प्रोग्राम विधि, नीति एवं प्रक्रिया सम्मिलित होता है, जो इकाई की सम्पत्ति तथा इसके अभिलेखों की विश्वसनीयता एवं शुद्धता की सुरक्षा तथा प्रबन्धन मानक के परिचालन को सुनिश्चित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी नियन्त्रण में निम्नलिखित सामान्य कमियाँ देखी गयीः

- कार्यालय कार्य के लिए स्थापित कम्प्यूटरों के उपयोग में एन्टी-वॉयरस सॉफ्टवेयर का अनुज्ञापित संस्करण नहीं पाया गया।
- प्रयोक्ता को अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन में सॉफ्टवेयर को समझने हेतु अभिलिखित प्रयोक्ता दिग्दर्शिका नहीं है।
- कम्प्यूटर प्रणाली में किसी विफलता की स्थिति में आपदा नियन्त्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं थी।

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने प्रस्थान गोष्ठी में बताया कि क्रियाशील फार्म मॉड्यूल स्थानीय सर्वर पर आधारित है तथा वेब आधारित फार्म मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। इस मॉड्यूल को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों को दूर करने के पश्चात् ही प्रारम्भ किया जायेगा। इस मॉड्यूल को प्रारम्भ किये जाने के पश्चात्, प्रपत्रों के निर्गमन में भी एकरूपता होगी। विभाग ने यह भी बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये आपत्तियों को नोट कर लिया गया है तथा आई टी अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। प्रपत्र-XVII, एम आई एस तथा सचल दस्ता के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में आयुक्त, कर ने बताया कि जाँच चौकियों के समापन पर पुनर्गठन के पश्चात् ध्यान दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में टिप्पणी करना सम्भव नहीं है। सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक कार्यवाही की जाये।

3.2.13.4 आँकड़ों की विश्वसनीयता

एक व्यापारी की "पंजीयन तिथि" एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि उस पर व्यापारी विशेष का वैट निर्धारण निर्भर करता है। यह देखा गया कि 2,269 व्यापारियों में से 209 व्यापारियों के मामलों में सॉफ्टवेयर में उपलब्ध इस मुख्य खानें में भरे गए आँकड़े, उसके हस्तलिखित अभिलेखों से भिन्न थे।

इसे इंगित किये जाने पर, इकाईयों ने बताया कि भिन्नता लिपिकीय त्रुटि के कारण थी और इसे ठीक कर लिया जायेगा। चूँकि व्यापारियों का डेटाबेस एक आधार होता है जिस पर सम्पूर्ण सॉफ्टवेयर पैकेज़ की प्रभावकारिता निर्भर होती है, अतः इस मुख्य खानें में अशुद्ध आँकड़ों के मौजूद होने से डिजीटल आँकड़ों की विश्वसनीयता पर गम्भीर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने आयुक्त, कर को निर्देश दिया कि सम्बन्धित संयुक्त आयुक्तों को प्रकरण को देखने एवं उपचारी कदम उठाने का निर्देश दें।

3.2.13.5 जाँच चौकियों का कम्प्यूटरीकरण

जाँच चौकी क्रेडिट दावों के प्रतिसत्यापन एवं अन्तर्राज्यीय व्यापार में शामिल व्यापारियों द्वारा कर के सही भुगतान की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अतः उनका कम्प्यूटरीकरण तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से ऑनलाईन सम्बद्धता महत्वपूर्ण माना जाता है।

नमूना चयनित में नारसन स्थित जाँच चौकी की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ देखी गयीः

- इस जाँच चौकी का क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय से ऑनलाईन सम्बद्धता नहीं थी।
- प्रत्येक जाँच चौकी पर पंजी 1, 2, 3, 4 एवं 5 नामक पाँच पंजियों का रखरखाव किया जाता है। पंजी 1, 2, 3 एवं 4 का रखरखाव माल की गतिविधि का पता लगाने हेतु किया जाता है जबकि पंजी 5 में जब्ती तथा प्रतिभूति जमा का विवरण होता है। हिल्ट्रॉन ने जाँच चौकियों हेतु "चेकपोस्ट ऑटोमेशन सिस्टम" नाम का एक सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है। जाँच चौकी, नारसन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि सॉफ्टवेयर आंशिक रूप से प्रचालित था, क्योंकि कम्प्यूटर में केवल पंजी 1, 2 एवं 3 के आँकड़ों की ही प्रविष्ट किया गया था तथा पंजी 4 एवं 5 को हस्तलिखित रूप से तैयार किया गया था, यद्यपि सॉफ्टवेयर में ये भी प्रावधानित थे। हालाँकि पंजी 3 तथा पंजी 4 एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित थे, जबकि पंजी 3 में प्रविष्ट किये गये आँकड़ें तभी उपयोगी हो सकते थे, जब पंजी 4 में आँकड़ों की प्रविष्टि की जाती।
- जाँच चौकी पर उपलब्ध अतिरिक्त सर्वर अकार्यशील था। इस प्रकार, किसी दोष या ध्वस्त होने के कारण, सर्वर खराब होने की स्थिति में कार्य पुनः प्रारम्भ करने का प्रबन्ध नहीं था।

इकाई ने उत्तर में बताया कि सर्वर को ठीक कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रस्थान गोष्ठी में, आयुक्त ने बताया कि 38 वी-सैट क्रय किये जा चुके हैं एवं उनके स्थापन के पश्चात् ऑनलाईन सम्बद्धता उपलब्ध हो जायेगी। आई टी अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, को त्वरित अनुपालन हेतु निर्देश दिया जा चुका है।

3.2.14 यूवैट अधिनियम का कार्यान्वयन

नमूना चयनित इकाईयों की लेखापरीक्षा में अधिनियम एवं नियमों के प्रभावी तरीके से लागू करने में विभिन्न कमियाँ प्रकट हुई, जैसा अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लेखित है।

3.2.14.1 कर का न्यूनारोपण/अनारोपण

यूवैट अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, किसी व्यापारी द्वारा देय कर उसके कराधेय कारोबार पर ऐसी दर से आरोपित किया जायेगा, जो अधिनियम की अनुसूचियों में विहित किया जाए।

- चार उ आ (क नि)[12] तथा 12 स आ (क नि)[13] (वा क अ सहित) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 23 व्यापारियों के मामलों में ₹ 3.11 करोड़ की कुल बिक्री पर कम दर से करारोपति किया गया था, जिसके फलस्वरूप ₹ 26.69 लाख के कर का न्यूनारोपण तथा ₹ 18.34 लाख ब्याज देय था, जैसा कि **परिशिष्ट-3.3** में वर्णित है।

---

[12] उ आ -(क नि)। देहरादून-(क नि) उ आ, II रूड़की-(क नि) उ आ, II काशीपुर एवं उ आ -(क नि)II हल्द्वानी।

[13] स आ -(क नि)II एवं V देहरादून-(क नि) स आ, I एवं II रूड़की-(क नि) स आ, III-(क नि) स आ, देहरादून (वा क अ) II हल्द्वानी स आ, -(क नि) स आ, नैनीताल (क नि)II हरिद्वार-(क नि) स आ, I अल्मोड़ाक) च्छा एवं स आकि (क नि) स आ, कोटद्वार (क नि) स आ, -(निII ऋषिकेश। (वा क अ)।

- तीन उ आ (क नि)[14] तथा पाँच स आ (क नि)[15] (वा क अ सहित) के अभिलेखों की संवीक्षा में, यह देखा गया कि 11 व्यापारियों के ₹ 12.93 करोड़ के विक्रय संव्यवहार पर करमुक्त वस्तु मानते हुए करारोपित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ कर अनारोपित रहा। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.25 करोड़ ब्याज भी देय था, जैसा कि **परिशिष्ट-3.4** में वर्णित है।

धारा 4 (5) (ख) सहपठित नियम 14 (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी कार्य सम्बन्धी ठेकों के निष्पादन में उपयोगित माल के रूप में सम्पत्ति के अन्तरण सम्बन्धी शुद्ध कारोबार पर ऐसे दर पर कर अदा करेगा, जो विहित किया जाए। शुद्ध कारोबार की गणना करने में ठेकेदार द्वारा प्राप्त या प्राप्य कुल धनराशि में से माल, जिसकी खरीद या बिक्री पर कर आरोपित या आरोपणीय है तथा कार्य सम्बन्धी ठेकों के निष्पादन में मजदूरी को दर्शाने वाली धनराशि को घटा दिया गया हो।

- स आ (क नि) नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि मेसर्स परियोजना प्रबन्धक, उ प्र राज्य निर्माण निगम लिमिटेड, अल्मोड़ा द्वारा सरकारी भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में क्रमशः ₹ 5.20 करोड़ एवं ₹ 7.21 करोड़ प्राप्त किया गया था। कर निर्धारण के दौरान, कर निर्धारण प्राधिकारी ने संविदाकार को इस तर्क के साथ दोनों वर्षों में छूट दिया कि संविदाकार द्वारा सामग्री का बिक्री/अन्तरण नहीं किया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारी का तर्क उपरोक्त प्रावधानों के संगत नहीं था, क्योंकि, क्रमशः वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के शुद्ध कारोबार पर कर आरोपणीय था। संविदाकार द्वारा क्रय किये गये सामग्री की मात्रा का विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा आरोपणीय कर की धनराशि का अवधारण नहीं किया जा सका, क्योंकि सामग्री के प्रकार के आधार पर 12.5 एवं 4 *प्रतिशत* की भिन्न दरें है।

छुपाया गया कर योग्य कारोबार

- दो स आ (क नि)[16] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एक संविदाकार के प्रकरण में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में, शुद्ध कर योग्य कारोबार के अवधारण हेतु संविदाकार द्वारा व्यय किये वास्तविक मजदूरी प्रभार ₹ 11.52 लाख की बजाय उसके द्वारा प्राप्त धनराशि (₹ 2.45 करोड़) का 30 *प्रतिशत* घटाया गया था। पुनः एक संविदाकार के प्रकरण में, शुद्ध कारोबार के अवधारण हेतु संविदाकार द्वारा प्राप्त कुल धनराशि ₹ 20 लाख में से ₹ 8.92 लाख की बजाय ₹ 9.56 लाख के क्रय को घटाया गया था। ₹ 62.63 लाख के ऐसे छुपाये गये कर योग्य कारोबार के कारण ₹ 6.25 लाख के कर का अनारोपण तथा उस पर ₹ 2.76 लाख ब्याज देय था, जैसा कि **परिशिष्ट-3.5** में वर्णित है।

उपरोक्त प्रकरणों में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था; (जनवरी 2013)।

अधिनियम की धारा 3 (1) सहपठित धारा 58 (1) (XXV) (ज) में प्रावधान है कि किसी व्यापारी द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत कर प्रभारित एवं आरोपित किया

---

[14] उ आ -(क नि)II एवं V देहरादून तथा उ आ -(क नि)II हल्द्वानी।

[15] स आ-(क नि) V देहरादून-(क नि) स आ, नैनीताल (क नि) स आ, I अल्मोड़ा-(क नि) स आ, II ऋषिकेश तथा स आ किच्छा (क नि)।

[16] स आ -(क नि)V देहरादून-(क नि) स आ, II हल्द्वानी।

जायेगा। पुनः, यदि किसी व्यापारी द्वारा बिक्री बीजक जारी किया गया है एवं उसको अपनी लेखाबहियों में शुद्धतया लेखाबद्ध करने में असफल रहा, तो एक सौ रूपये या समाहित कर की दुगुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, आरोपणीय है।

- उ आ (क नि)-V, देहरादून की नमूना जाँच में पाया गया कि मेसर्स- रूद्रा वुड पैक, मंगलौर, रूड़की, नामक व्यापारी ने वर्ष 2007-08 में मेसर्स असाही इण्डिया ग्लास लिमिटेड, रूड़की को ₹ 4.72 करोड़ की बिक्री घोषित किया था, जिसमें से ₹ 4.03 करोड़ तथा ₹ 68.84 लाख की बिक्री क्रमशः 4 *प्रतिशत* एवं 12.5 *प्रतिशत* की दर से करयोग्य घोषित किया था। लेखापरीक्षा ने विक्रेता एवं क्रेता के कर निर्धारण अभिलेखों की प्रतिसत्यापन में पाया गया कि ₹ 4.72 करोड़ की कुल बिक्री 12.5 *प्रतिशत* की दर से की गयी थी। पुनः सत्यापन में पाया कि क्रेता व्यापारी को इस क्रय पर 12.5 *प्रतिशत* की दर से ₹ 58.96 लाख धनराशि की दावाकृत आई टी सी अनुमन्य किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी द्वारा मेसर्स असाही इण्डिया ग्लास लिमिटेड, रूड़की को बिक्री की धनराशि पर वास्तविक करयोग्य दर का पता लगाने एवं विभाजन करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.03 करोड़ की करयोग्य बिक्रय कारोबार पर ₹ 34.30 लाख कर का न्यूनारोपण रहा । इसके अतिरिक्त, ₹ 23.15 लाख ब्याज एवं ₹ 68.60 लाख अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।
- उ आ (क नि)-V, देहरादून के अभिलेखों की एक नमूना जाँच में देखा गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी[17] के प्रकरण में वर्ष 2007-08 की ₹ 22.83 करोड़ की कुल बिक्री पर कर आरोपित किया। व्यापारी द्वारा प्रस्तुत संगत वर्ष की बिक्री सूची की जाँच में देखा गया कि व्यापारी का उस वर्ष की बिक्री कारोबार ₹ 23.38 करोड़ का था। इसके परिणामस्वरूप, छुपाई गई बिक्री की धनराशि ₹ 54.81 लाख पर ₹ 2.19 लाख कर एवं ₹ 1.48 लाख ब्याज वंचित रहा तथा अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उपरोक्त प्रकरणों में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

3.2.14.2 बिक्री के छुपाव के कारण करापवंचन

अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि किसी व्यापारी द्वारा देय कर उसके करयोग्य कारोबार पर ऐसी दर से आरोपित किया जायेगा, जो अधिनियम की अनुसूचियों में विहित हो।

एक व्यापारी मेसर्स रूद्रा वुड पैक, रूड़की की गोपनीय पत्रावली से कर निर्धारण आदेश की जाँच में यह पाया गया कि व्यापारी ने माह जनवरी एवं फरवरी, 2007 के अपने आवधिक विवरणी में ₹ 1.59 करोड़ की बिक्री घोषित किया एवं तत्पश्चात् वर्ष 2006-07 हेतु "शून्य" बिक्री घोषित करते हुए पुनरीक्षित विवरणी इस तर्क के साथ दाखिल किया कि माल अद्योमानक होने के कारण वापस प्राप्त हो गया था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण आदेश (गोपनीय पत्रावली में रखे गए) में उल्लिखित किया कि विक्रेता एवं क्रेता व्यापारी द्वारा समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार, कर निर्धारण प्राधिकारी ने "शून्य" बिक्री के कारण उक्त अवधि हेतु कोई कर आरोपित नहीं किया। लेखापरीक्षा को सम्बन्धित व्यापारी की संगत वर्ष की

[17] मेसर्स रूद्रा वुड पैक, रूड़की।

कर निर्धारण पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण लेखापरीक्षा द्वारा कर निर्धारण आदेश में उल्लिखित दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने प्रतिसत्यापन में पाया कि व्यापारी द्वारा वास्तव में उ आ (क नि)-II रूड़की में पंजीकृत व्यापारी मेसर्स असाही इण्डिया ग्लास लिमिटेड, रूड़की को उसी वर्ष में ₹ 4.12 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री किया था। पुनः जाँच में पाया गया कि व्यापारी ने मेसर्स असाही इण्डिया ग्लास लिमिटेड, रूड़की को कुल बिक्री कारोबार ₹ 4.12 करोड़ हेतु बिक्री बीजक जारी किया था तथा क्रेता व्यापारी द्वारा दावाकृत ₹ 51.26 लाख की आई टी सी (12.5 *प्रतिशत* की दर से) अनुमन्य की गई थी। इस प्रकार, व्यापारी ने ₹ 2.53 करोड़ की करयोग्य बिक्री को छुपा लिया था। छुपाव का पता लगाने में कर निर्धारण प्राधिकारी असफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 31.59 लाख कर का अनारोपण तथा ₹ 26.07 लाख ब्याज देय था। इसके अतिरिक्त, अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उपरोक्त प्रकरण में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

3.2.14.3 ब्याज का कम आरोपण/जमा न किया जाना

अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (4) एवं विभागीय परिपत्र में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी नियत तिथि तक कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा व्यापारी ऐसे नियत तारीख से उक्त कर के भुगतान तक 15 *प्रतिशत* वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

चार उ आ (क नि)[18] तथा 11 स आ (क नि)[19] के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा माँग प्रेषित किए जाने पर 24 व्यापारियों ने कम ब्याज जमा किया तथा 40 व्यापारियों ने बिल्कुल ब्याज जमा नहीं किया। पुनः देखा गया कि व्यापारियों द्वारा ब्याज की धनराशि जमा न किये जाने के बावजूद भी आर-3 पंजिका से माँगों को हटा/निरस्त कर दिया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ब्याज के कम आरोपण/जमा न किए जाने की वसूली हेतु कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.53 लाख ब्याज कम/जमा नहीं हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट-3.6** में उल्लेखित है।

उपरोक्त प्रकरणों में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2013)।

3.2.14.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमन्यता

अधिनियम की धारा 6 (3) एवं (8) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यापारी को माल, जिसकी बिक्री इस अधिनियम के अन्तर्गत करमुक्त है, हानि एवं छूट, जॉब वर्क, उपभोज्य (दिनांक 31 मार्च, 2008 तक) तथा अधिनियम की अनुसूची-III में विनिर्दिष्ट विशेष श्रेणी माल के सिवाय, राज्य के भीतर क्रय किये गये माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का लाभ अनुमन्य होगा। पुनः धारा 58 (1) (XI) एवं (XXXV) (च) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी आई टी सी का गलत दावा करता है, तो पाँच हजार रूपये या दावाकृत धनराशि का तीन गुना, जो भी अधिक हो, के भुगतान का दायी होगा।

---

[18] उ आ -(क नि)I एवं V देहरादून-(क नि) उ आ, II हल्द्वानी तथा उ आ -(क नि)II रुड़की।

[19] स आ -(क नि)III एवं V देहरादून-(क नि) स आ, रामनगर (क नि) स आ, I एवं II रुड़की-(क नि) स आ, III रूद्रपुर (क नि) स आ, -(क नि) स आ, कोटद्वारII ऋषिकेश-(क नि) स आ, II हल्द्वानी-(क नि) स आ, II हरिद्वार एवं स आ -(क नि)I अल्मोड़ा।

- व्यापारियों को रिर्टन के साथ प्रस्तुत क्रय सूची के आधार पर आई टी सी का लाभ अनुमन्य था। लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि आई टी सी का लाभ अनुमन्य करने के पूर्व प्रतिसत्यापन की प्रक्रिया बहुत कम थी। आई टी सी का लाभ अनुमन्य किये जाने के पूर्व प्रतिसत्यापन के माध्यम से इसके दावे की वास्तविकता की पुष्टि हेतु कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। प्रतिसत्यापन प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप आई टी सी की अनियमित अनुमति दी गई, जैसा कि निम्नवत् हैः

- उ आ (क नि)-II, रूड़की की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि व्यापारी मेसर्स असाही इण्डिया ग्लास लिमिटेड, रूड़की द्वारा वर्ष 2006-07 में उ आ (क नि)-V देहरादून में पंजीकृत व्यापारी मेसर्स रूद्रा वुड पैक, रूड़की से ₹ 4.12 करोड़ धनराशि के माल के क्रय पर दावा किये गये ₹ 51.26 लाख आई टी सी (12.5% की दर से) अनुमन्य किया गया (जैसा कि प्रस्तर 3.2.14.2 में चर्चा की गयी है)। प्रतिसत्यापन में देखा गया कि क्रेता व्यापारी ने ₹ 1.59 करोड़ धनराशि का माल अवमानक होने के कारण वापस कर दिया। पुनः विक्रेता व्यापारी ने क्रेता व्यापारी से वापस प्राप्त माल के समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, वापसी माल पर आई टी सी निरस्त होनी चाहिए थी। प्रतिसत्यापन के अभाव में, कर निर्धारण के दौरान माल वापसी तथा इसके समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 19.91 लाख धनराशि की अनियमित आई टी सी अनुमन्य की गयी। इसके अतिरिक्त, ₹ 59.74 लाख का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

- दो उ आ (क नि)[20] तथा सात स आ (क नि)[21] (वा क अ सहित) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि 14 व्यापारियों के प्रकरण में करमुक्त माल, उपभोज्य आदि पर कुल धनराशि ₹ 24.21 लाख की अनियमित आई टी सी अनुमन्य की गयी, जैसा कि **परिशिष्ट-3.7** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने बताया कि मामले को देखा जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त प्रकरणों में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी, 2013)।

3.2.14.5 रियायत/छूट की अनियमित अनुमन्यता

अधिनियम की धारा 4 (7) (क) एवं (ङ) सपठित यूवैट नियम, 2005 के नियम 23 (1) में प्रावधान है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत, यदि कोई कराधेय माल किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी को बेच दिया जाय और ऐसा अन्य व्यापारी, विक्रेता व्यापारी को प्रपत्र XI में इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास मान्यता प्रमाणपत्र है, तो विक्रेता व्यापारी ऐसे माल के सम्बन्ध में रियायती दर पर कर का देनदार होगा।

---

[20] उ आ (क नि)I एवं V देहरादून।

[21] स आ -(क नि)V देहरादून-(क नि) स आ, नैनीताल (क नि) स आ, II हरिद्वार-(क नि) स आ, I-(क नि) स आ, अल्मोड़ा (वा क अ) III वा) -(क नि) किच्छा एवं स आ-(क नि) स आ, पुररूद्र (क आII ऋषिकेश। (वा क अ)।

पुनः अधिनियम की धारा 63 एवं नीचे दिए गए टिप्पणी के अनुसार, जो व्यक्ति प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी करता है जिसमें अपना यह अभिप्राय प्रकट करे कि वह अपने द्वारा क्रय किये गये माल का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिये करेगा जिससे कोई कर देय न होगा या रियायती दर पर देय होगा, किन्तु उसका उपयोग ऐसे प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिये करे, तो प्रमाणपत्र या घोषणा पत्र को गलत समझा जायेगा, तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र जारी न किया गया होता। धारा 58 (1) (XXIX) एवं (छ) में, अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 *प्रतिशत* से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपण करने का प्रावधान है।

(i) दो उ आ (क नि)[22] तथा स आ (क नि)[23] के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि दो व्यापारियों ने ₹ 14.62 लाख धनराशि के क्रय माल के विरूद्ध प्रपत्र XI जारी किया था, परन्तु मान्यता प्रमाण के अन्तर्गत माल आच्छादित नहीं थे, जबकि एक व्यापारी ने अपने मान्यता प्रमाण पत्र की तिथि से पूर्व ₹ 1.23 लाख मूल्य के क्रय हेतु प्रपत्र XI जारी किया था। इस प्रकार, व्यापारी द्वारा विक्रेता को रियायती प्रपत्र का अनधिकृत निर्गमन के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.93 लाख ब्याज एवं ₹ 6.34 लाख अर्थदण्ड भी देय है, जैसा कि **परिशिष्ट-3.8** में वर्णित है।

इसे इंगित किये जाने पर, लेखापरीक्षित इकाईयों ने उत्तर दिया कि मामले को देखा जायेगा तथा तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ii) यूवैट नियम, 2005 के नियम 23 (1), (3) एवं (4) के अन्तर्गत यदि मान्यता प्रमाणपत्र धारक कोई व्यापारी किसी माल के विनिर्माण के प्रयोजन से कोई माल खरीदे, तो वह, यदि उसमें रियायत लेना चाहे तो, विक्रेता व्यापारी को प्ररूप XI में एक घोषणा पत्र देगा। किसी वित्तीय वर्ष में जारी किया गया सादा प्रपत्र उस वित्तीय वर्ष एवं ऐसे वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों के दौरान किये गये क्रय या विक्रय के सम्व्यवहार के लिये भी विधिमान्य होगा। किसी एकल प्रपत्र में, एक कर निर्धारण वर्ष से अधिक के क्रय या विक्रय का सम्व्यवहार आच्छादित नहीं होगा।

चार उ आ (क नि)[24] तथा पाँच स आ (क नि)[25] के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 13 व्यापारियों ने ₹ 4.88 करोड़ विक्रय धनराशि के विरूद्ध 67 घोषणा प्रपत्र (प्रपत्र-XI) दाखिल किये थे। कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन विक्रयों पर रियायती दर से कर आरोपित किया, यद्यपि इसके समर्थन में प्रपत्र विहित समय सीमा के बाहर के सम्व्यवहार से सम्बन्धित थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 38.57 लाख के कर का कम आरोपण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 24.76 लाख ब्याज भी आरोपणीय था, जैसा कि **परिशिष्ट-3.9** में वर्णित है।

---

[22] उ आ -(क नि)I हरिद्वार एवं उ आ -(क नि)II काशीपुर।

[23] स आ किच्छा। (क नि)।

[24] उ आ -(क नि)I हरिद्वार-(क नि) उ आ, II रूड़की-(क नि) उ आ, II-(क नि) उ आ, काशीपुर, II हल्द्वानी।

[25] स आ (क नि)/वा क अ रामनगर-(क नि) स आ, II -(क नि) स आ, हल्द्वानी (वा क अ)IIIस, रूद्रपुर (वा क अ) आ स, किच्छा (क नि) -(क नि) आII ऋषिकेश।

इसे इंगित किये जाने पर, उ आ-II, रूड़की ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई आपत्ति को भविष्य में ध्यान दिया जायेगा। जबकि उ आ-II काशीपुर ने उत्तर दिया कि रियायती दर पर बिक्री के विरूद्ध प्रपत्र प्राप्त किया गया था। नैसर्गिक न्याय के आधार पर, कर को पूर्ण दर से आरोपित नहीं किया जा सकता था। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नियम में विहित समय सीमा के बाहर के सम्व्यवहार हेतु प्रपत्र जारी करने का प्रावधान नहीं है। अन्य इकाईयों ने बताया कि मामले को देखा जायेगा एवं तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(iii) अधिनियम के अनुसार, प्रपत्र 3ख के स्थान पर प्रपत्र XI प्रतिस्थापित किया गया था, प्रपत्र 3ख को विभागीय परिपत्र सं0 3897 दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 के द्वारा 1 अप्रैल, 2007 से अवैध घोषित कर दिया गया था।

स आ (क नि) नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रपत्र 3ख, इसके अवैध घोषित किये जाने की तिथि के पश्चात् जारी किया था (जुलाई, 2007)। एक व्यापारी ने इन चार प्रपत्र 3ख के आधार पर वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 17.09 लाख के कारोबार पर दिनांक 1 अप्रैल, 2007 के बाद रियायत प्राप्त की थी। इस प्रकार, प्रपत्रों को जारी करने तथा रियायत प्रदान करने से परिपत्र का उल्लंघन हुआ।

उपरोक्त प्रकरणों में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी, 2013)।

3.2.14.6 मान्यता प्रमाणपत्र का निरस्त न होना

अधिनियम की धारा 4 (7) (क) एवं (ख) में प्रावधान है कि यदि कोई माल किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी को बेच दिया जाय और ऐसा अन्य विक्रेता व्यापारी को नियत प्रपत्र में और रीति से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि उसके पास मान्यता प्रमाणपत्र है, तो विक्रेता व्यापारी ऐसे माल के सम्बन्ध में रियायती दर पर कर का देनदार होगा। पुनः अधिनियम (यथासंशोधित) में प्रावधान है कि करयोग्य माल के विनिर्माण करने वाले व्यापारी को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

अधिनियम के अनुसार, विनिर्माण से ऐसे कार्यकलाप अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी नई और भिन्न वस्तु में रूपान्तरण हो जाता है। पुनः बिक्री कर आयुक्त, उ प्र बनाम मेसर्स लालकुँआं स्टोन क्रेशर, लालकुँआं हल्द्वानी के प्रकरण में दिनांक 14 मार्च, 2000 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्थर को तोड़कर बोल्डर, बालू एवं ग्रिट बनने से किसी नई वस्तु का रूपान्तरण एवं उत्पादन नहीं होता है एवं इस प्रकार, इसे विनिर्माण करना नहीं समझा जा सकता है।

एक उ आ (क नि)[26] तथा दो स आ (क नि)[27] के अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि आटा, मैदा व सूजी का विनिर्माण करने वाले दो व्यापारियों[28] के प्रकरण में मान्यता प्रमाणपत्र निरस्त नहीं किया गया था जबकि अगस्त, 2009 से आटा, मैदा, सूजी करमुक्त घोषित कर दिया गया था। इन व्यापारियों के मान्यता प्रमाणपत्र निरस्त किये जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि व्यापारी करयोग्य माल का विनिर्माण नहीं कर रहे

---

[26] उ आ -(क नि)II रूड़की।

[27] स आ (क नि)/वा क अ किच्छारामनगर। (क नि) स आ।

[28] मेसर्स उत्तरांचल रोलर फ्लोर मिल्स, रूड़कीमेसर्स जगदीश फ्लोर मिल्स, रामनगर।

थे। पुनः पत्थर को तोड़ने में शामिल दो व्यापारियों[29] के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रमाणपत्र निरस्त नहीं किया गया था, जबकि ये व्यापारी विनिर्माण की श्रेणी में नहीं आते थे। मान्यता प्रमाणपत्र निरस्त न किये जाने से करमुक्त माल के विनिर्माता को कर के रियायती दर पर कच्चा माल, प्लान्ट एवं मशीनरी, पैकिंग सामग्री इत्यादि क्रय करने की छूट से करापवंचन की गुंजाईश हो सकती है।

उपरोक्त प्रकरण में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी, 2013)।

3.2.14.7 टी डी एस का जमा न किया जाना/विलम्ब जमा

अधिनियम की धारा 35 (4), (8) व (9) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कार्य संविदा के अनुसरण में भुगतान के लिये उत्तरदायी हो, ऐसा भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती की धनराशि की कटौती करेगा तथा उसे उस माह, जिसमें कटौती की गई, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा। ऐसा न करने पर, काटने योग्य लेकिन न काटी गई या काटी गयी लेकिन जमा न की गयी धनराशि के दुगुने से अनधिक धनराशि के अर्थदण्ड सहित 15 *प्रतिशत* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भागीदार होता है।

स आ (क नि) नैनीताल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एक व्यापारी[30] ने एक ठेकेदार को वर्ष 2007-08 में ₹ 34.86 लाख के भुगतान पर जुलाई, 2007 में धनराशि ₹ 79,934 टी डी एस के रूप में काटी थी, जिसे 31 अगस्त, 2007 तक सरकारी कोषागार में जमा किया गया था, लेकिन उसे 14 सितम्बर, 2007 को जमा किया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने विलम्बित जमा पर न तो अर्थदण्ड और न ही ब्याज आरोपित किया।

पुनः एक ठेकेदार[31] ने संविदी विभाग से वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में क्रमशः ₹ 5.20 करोड़ तथा ₹ 7.21 करोड़ प्राप्त किया किन्तु किए गये भुगतान पर कोई टी डी एस नहीं काटा गया था। कर निर्धारण के दौरान, कर निर्धारण प्राधिकारी टी डी एस की कटौती न किए जाने का पता लगाने तथा संविदी को सूचित करने में असफल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने पर, लेखापरीक्षिती इकाई ने बताया कि मामले को देखा जायेगा तथा कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रकरणों में सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन से उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी, 2013)।

3.2.14.8 जाँच चौकियों की कार्यपद्धति

- जब एक मालवाहन, राज्य से गुजर कर किसी अन्य राज्य में जाता है, तो पंजी 3 में प्रविष्टि की जाती है तथा प्रवेश बिन्दु की जाँच चौकी पर तीन प्रतियों में "बहती" प्रदान की जाती है जो निकास बिन्दु की जाँच चौकी पर पंजी 3 में विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पूर्व पंजी 4 में निरस्त होगा। बहती के निरस्तीकरण की जिम्मेदारी वाहनस्वामी/चालक पर होती है। अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह

[29] मेसर्स तराई स्टोन क्रेशर, किच्छादेव पुष्प माइनिंग इण्ड्रस्ट्रीज़, किच्छा।

[30] अधिशासी अभियन्तावृत्त नैनीताल।,ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग।

[31] मेसर्स परियोजना प्रबन्धकअल्मोड़ा।,उ प्र राज्य निर्माण निगम।

पाया गया कि ऐसे वाहन, जिसकी "बहती" विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् निरस्त हुई थी, उन पर एक सौ रूपये प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लगाया गया था। ऐसे वाहनस्वामी, जो निकासी बिन्दु पर बहती बिल्कुल भी निरस्त नहीं कराये, को नोटिस जारी किया गया था। पुनः परिवहनकर्ताओं/स्वामियों द्वारा इस आशय का शपथपत्र, कि माल की राज्य में बिक्री नहीं किया गया है, प्रस्तुत करने पर इन नोटिसों एवं बहतियों को निरस्त किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि 21 मामलों, जिसमें नोटिस जारी करने के पश्चात् "बहती" निरस्तीकरण किया गया था तथा निरस्तीकरण में विलम्ब की अवधि 36 से लेकर 46 माह थी, में अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था। इस प्रकार, "बहती" के विलम्ब से निरस्तीकरण में अर्थदण्ड के आरोपण में एकरूपता नहीं थी। पुनः लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसे मामलों में अर्थदण्ड के आरोपण हेतु कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं था।

प्रस्थान गोष्ठी में, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने विभागीय अधिकारियों को इस बिन्दु पर जाँच के आदेश दिये।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि लोहा एवं इस्पात विनिर्माताओं तथा कोयला व्यापारियों के द्वारा अन्य राज्यों से बिना प्रपत्र XVI के आयातित कोयले पर ₹ 125 प्रति टन की दर से (समाधान योजना के अन्तर्गत) कर आरोपित किया गया था। जबकि वैट अधिनियम/नियमों में, लोहा एवं इस्पात विनिर्माताओं या कोयला व्यापारियों हेतु समाधान योजना हेतु कोई प्रावधान नहीं है। आरोपित कर वैट अधिनियम और नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं थे।

इसे इंगित किये जाने पर, लेखापरीक्षित इकाई ने उत्तर दिया कि पुराने प्रावधानों के आधार पर कर आरोपित किया गया था। हालाँकि लेखापरीक्षा को पुराने प्रावधान के समर्थन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

प्रस्थान गोष्ठी में, आयुक्त, कर ने बताया कि उ प्र व्यापार कर अधिनियम (उत्तराखण्ड में यथाअंगीकृत) के अन्तर्गत कतिपय परिपत्र/आदेश अब भी प्रभावी है। पुनः सचिव वित्त ने आयुक्त, कर को इस सम्बन्ध में प्रावधानों के संज्ञान में लेने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

3.2.15 मानव संसाधन प्रबन्धन

3.2.15.1 जनशक्ति की कमी

जनशक्ति की उपलब्धता, एक विभाग के सुचारु तथा कुशल कार्य हेतु एक महत्वपूर्ण कारक होता है। यह पाया गया कि यद्यपि आच्छादित अवधि के दौरान कर निर्धारण वादों की संख्या में 66,607 से 84,323 तक की वृद्धि थी, तथापि जनशक्ति विशेषकर 'ख' एव 'ग' संवर्ग, जो मुख्यतः कर निर्धारण, प्रतिसत्यापन और अभिलेखों के सामान्य रखरखाव में कर निर्धारण प्राधिकारी की सहायता हेतु उत्तरदायी होता है, की भारी कमी थी। 31 मार्च, 2012 को विभाग की जनशक्ति की स्थिति निम्न **तालिका-3.2.4** में दर्शाया गया हैः

तालिका-3.2.4

संवर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मी	कमी	कमी *प्रतिशत* में
वर्ग क	57	52	05	9
वर्ग ख	294	189	105	36
वर्ग ग	989	418	571	58
योग	**1340**	**659**	**681**	**51**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 51 *प्रतिशत* की कुल कमी है तथा यह वर्ग 'ख' में 36 *प्रतिशत* एवं वर्ग 'ग' में 58 *प्रतिशत* थी। पुनः, देखा गया कि नमूना लिये गये छः उ आ (क नि) एवं 14 स आ (क नि) में से एक उ आ (क नि)[32] एवं सात स आ (क नि)[33] में, लेखापरीक्षा अवधि में कोई आशुलिपिक तैनात नहीं था। इस प्रकार, विभिन्न संवर्गों में पदों की कमी, जैसा कि उपरोक्त तालिका में बताया गया है, के कारण कर प्रशासन के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

पुनः आयुक्त कर, उत्तराखण्ड के पत्र[34] दिनांक 06 मई, 2006 के अनुसार रोड़ी, बजरी, पत्थर तथा बालू ढोने हेतु वाहन के बाहर जाने पर उनके अभिलेखों को निर्धारित प्रोफार्मा में नारसन सहित छः जाँच चौकियों में रखा जाना था। इसके लिए, वा क अ ग्रेड-II के अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाना था। पुनः, इस प्रयोजन हेतु सम्भाग के अतिरिक्त आयुक्त को वर्ग ग तथा वर्ग घ कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना था। नारसन जाँच चौकी की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि न तो कर्मचारी तैनात थे और न ही ऐसे अभिलेखों का रखरखाव किया गया था।

प्रस्थान गोष्ठी में, विभाग ने बताया कि आयुक्त/शासन स्तर पर कर्मचारियों की कमी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

3.2.15.2 जनशक्ति का असमान वितरण

खातापालक तथा आशुलिपिक, व्यापारियों के अभिलेखों की अभिरक्षा एवं रखरखाव तथा कर निर्धारण में कर निर्धारण प्राधिकारी की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमूना इकाईयों की लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि व्यापारियों के कर निर्धारण/गोपनीय पत्रावलियों का अनुचित रूप से रखरखाव/अम्बार लगे हुये थे। आवश्यक अभिलेख यथा पंजीयन प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण रिपोर्ट, विवरणी तथा कर निर्धारण आदेश को आगामी सन्दर्भ हेतु व्यापारियों की संगत पत्रावली में उचित रूप से नत्थी नहीं किया गया था। अभिलेखों के रखरखाव हेतु प्रत्येक खातापालक पर व्यापारियों की कुल संख्या के प्रति कोई मानक नियत नहीं था। नमूना इकाईयों से संग्रहित सूचना के विश्लेषण पर पाया गया कि प्रत्येक खातापालक पर व्यापारियों की कुल संख्या 280 से लेकर 2,591 तक थी।

---

[32] उ आ हरिद्वार। (क नि)।

[33] स आ -(नि क)II, III एवं V देहरादून-(क नि) स आ, II रुड़की-(क नि) स आ, कोटद्वार (क नि) स आ, II हरिद्वार (क नि) स आ, नैनीताल।

[34] सं312 0/आयुक्त करउत्तराखण्ड,/वाणिज्य कर/जाँ चौ।

3.2.15.3 प्रशिक्षण

विभाग की क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन होता है। आवधिक प्रशिक्षण देकर कर्मचारियों के कौशल तथा क्षमता को उन्नत किया जा सकता है। नमूना इकाईयों तथा आयुक्तालय से संग्रहित सूचना से ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा कोई वार्षिक प्रशिक्षण योजना तैयार नहीं किया जा रहा था। पुनः, 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि में वैट के बेहतर कार्यान्वयन हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। 2008 एवं 2009 बैच के नव नियुक्त वा क अ तथा स आ को प्राथमिक विभागीय प्रशिक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। पुनः, विभाग ने वर्ष 2010-11 में तीन दिवसीय प्रशिक्षण (काशीपुर, देहरादून तथा हरिद्वार सम्भाग में प्रत्येक हेतु एक दिन) तथा 2011-12 में काशीपुर तथा हल्द्वानी सम्भाग में एक दिवसीय प्रशिक्षण के सिवाय मॉड्यूल्स के नियन्त्रण हेतु कोई कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। वर्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण, कर्मचारियों के कौशल को प्रशिक्षित/उन्नयन हेतु पर्याप्त नहीं हो सकते है।

प्रस्थान गोष्ठी में, विभाग ने बताया कि अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही गतिमान है।

3.2.16 अनुश्रवण तथा आन्तरिक नियन्त्रण

3.2.16.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा, बेहतर परिणाम हेतु प्रशासन की सहायता, सलाह तथा मार्गदर्शन करता है। यह स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन भी करता है कि क्या संगठन के क्रियाकलापों को कुशल और प्रभावी ढंग से सम्पादित किया जा रहा है।

यह देखा गया कि विभाग ने कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का सृजन नहीं किया है।

3.2.16.2 कर-लेखापरीक्षा

अधिनियम की धारा 25 (8) के अनुसार, व्यापारियों के अभिलेखों, व्यापारिक माल तथा सम्बन्धित अभिलेखों की कर-लेखापरीक्षा, कर-लेखापरीक्षा शाखा में तैनात अधिकारियों या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत विभाग के अन्य अधिकारियों, जिनमें कर निर्धारण प्राधिकारी सम्मिलित है या कर-लेखापरीक्षा शाखा के किसी अधिकारी, जो उस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त आयुक्त से निम्न पद पर न हो, द्वारा शुद्धता, दावों/आई टी सी की अनुमन्यता तथा व्यापारी द्वारा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सम्पादित की जा सकती है।

कर-लेखापरीक्षा शाखा, कमियों तथा अनियिमतताओं को प्रकाश में लाने के साथ ही उपचारी कदम उठाने में सलाह तथा सुझाव देने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विभाग की कर-लेखापरीक्षा शाखा से संग्रहित सूचना से ज्ञात हुआ किः

- 2008 में शाखा सृजित हुई तथा सरकार को शाखा हेतु स्वीकृत पद विलम्ब से अगस्त, 2012 में प्रेषित किया गया था, जो अब तक विचारणीय था। तथापि, शाखा में मार्च, 2012 को आन्तरिक व्यवस्था के रुप में एक वर्ग 'क', दो वर्ग 'ख' तथा चार वर्ग 'ग' अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे।

- प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में वार्षिक योजना तैयार नहीं किया जाता था।
- 2008-12 की अवधि में कर-लेखापरीक्षा हेतु उ आ (क नि) तथा स आ (क नि) एवं व्यापारियों की चयनित कुल संख्या निम्न **तालिका-3.2.5** में प्रदर्शित किया गया हैः

तालिका-3.2.5

अवधि	कर-लेखापरीक्षा हेतु चयनित			
	कुल उ आ (क नि)	कुल व्यापारी	कुल स आ (क नि)	कुल व्यापारी
2008-09	17	57	05	10
2009-10	13	31	03	07
2010-11	19	119	47	344
2011-12	21	144	-	-

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 में कर-लेखापरीक्षा हेतु चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ व्यापारियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि थी। जबकि, वर्ष 2011-12 में कर-लेखापरीक्षा हेतु स आ (क नि) को चयनित नहीं किया गया था।

- कर-लेखापरीक्षा हेतु मैनुअल, जो कि प्रभावी लेखापरीक्षा हेतु एक सन्दर्भ बिन्दु होगा, नहीं था।
- शाखा के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया था, जैसा कि कर-लेखापरीक्षा हेतु अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकसित नहीं था।

3.2.16.3 मैनुअल की रचना

मैनुअल, प्रक्रियाओं को मानचित्रित करता है तथा वैट को संचालित करने के साथ-साथ अधिनियम पर प्रशिक्षण आयोजित करने में एक सन्दर्भ बिन्दु प्रदान करता है। यह प्रभावी अनुश्रवण हेतु आन्तरिक नियन्त्रण के ढाँचे की नींव भी रखता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वैट हेतु मैनुअल तैयार नहीं किया गया था। मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, विभाग ने प्रस्थान गोष्ठी में सूचित किया था कि एक समिति का गठन किया जा चुका था तथा वैट शासन काल हेतु पुराने मैनुअल को अद्यतन किया जा रहा था जिसे जो अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि, वैट छः वर्षों से अधिक समय से विद्यमान है, विभाग दिसम्बर, 2012 तक मैनुअल पूर्ण नहीं कर सका।

3.2.16.4 अपील प्रकरणों की स्वीकृति एवं निस्तारण

दिनांक 31.03.2012 को लम्बित अपील मामलों की कुल संख्या को निम्न **तालिका 3.2.6** में तालिकाबद्ध किया गया हैः

तालिका-3.2.6

अवधि	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान मामलों की कुल संख्या		अन्तिम शेष
		स्वीकृत	निस्तारित	
2008-09	1981	1224	639	2566
2009-10	2566	1767	1899	2434
2010-11	2434	3289	2674	3049
2011-12	3049	2834	2670	3213

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अधिकरणों तथा अपीलीय अदालतों में लम्बित 3,213 मामलों में से 1,420 मामले समाहित धनराशि ₹ 37.19 करोड़ 1-2 वर्ष के बीच की अवधि के, 1031 मामले समाहित धनराशि ₹ 19.30 करोड़ 2-5 वर्ष के बीच की अवधि के तथा 762 मामले समाहित धनराशि ₹ 10.37 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक के निस्तारण हेतु लम्बित थे। लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि दाखिल अपील के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है

3.2.16.5 डाक पंजिका की निगरानी में कमी

आर 29 पंजिका (प्राप्त डाक की पंजिका) की जाँच में देखा गया कि कई रसीदें खाली छोड़ दी गयी थी तथा सम्बन्धित कर निर्धारण प्राधिकारी ने निरस्त नहीं किया था, जिससे ऐसे रसीदों के दुरूपयोग की सम्भावना हो सकती है। पुनः, यह भी पाया गया कि कुछ क्षेत्रीय इकाईयों में मुद्रित आर-29 पंजिका की अनुपलब्धता के कारण मुद्रित के बजाय हाथ से बनी रसीदें जारी की गयी थी। यह भी पाया गया कि हाथ से बनी रसीदों को क्रम से जारी नहीं किया गया था, जैसा कि रसीद संख्या की पुनरावृत्ति पाई गई।

प्रस्थान गोष्ठी में, विभाग ने बताया कि आई टी अनुभाग, मुख्यालय, वाणिज्य कर द्वारा एक मॉड्यूल विकसित किया जा चुका है, जिसमें सभी डाक प्राप्तियाँ कम्प्यूटर के माध्यम से होंगी। पुनः, सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन ने डाक प्राप्ति की प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र मॉड्यूल के कार्यान्वयन का निर्देश दिया।

3.2.17 निष्कर्ष

वैट संग्रहण, राज्य के कर-प्राप्तियों का एक प्रमुख हिस्सा है। जबकि, यह प्रशंसनीय है कि वैट के संग्रहण एवं साथ ही राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में वैट के हिस्सेदारी में बढ़ती प्रवत्ति थी, निष्पादन लेखापरीक्षा में देखा गया कि विभाग में पंजीयन हेतु दायी व्यापारियों का पता लगाने हेतु तंत्र अपर्याप्त था। यद्यपि विभाग में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया आरम्भ किया जा चुका था, तथापि सॉफ्टवेयर के सभी मॉड्यूल का पूर्णतया परिचालन किया जाना बाकी था। विद्यमान सॉफ्टवेयर में संवेदनशील क्षेत्रों यथा कर-लेखापरीक्षा, उद्गम प्रमाणपत्र टिकट, प्रपत्र-XVII एवं सचल दस्ता से सम्बन्धित आँकड़ों को प्राप्त करने हेतु प्रावधान नहीं थे। जाँच चौकियां आयुक्तालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अन्तर्सम्बद्ध नहीं थी। कर का गैर/कम आरोपण, ब्याज और अर्थदण्ड तथा रियायत/आई टी सी की अनियमित अनुमन्यता और विभिन्न दावों के प्रतिसत्यापन की कमी के मामले थे। विभाग 50 *प्रतिशत* से अधिक जनशक्ति की कमी के साथ कार्य कर रहा था। आन्तरिक नियन्त्रण तंत्र कमजोर था, जैसा कि विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी। कर-लेखापरीक्षा, जो कर व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, की उपेक्षा किया गया था, जैसा कि उसके लिये पद स्वीकृत नहीं थे। राज्य में वैट को लागू होने के छः वर्षों के पश्चात् भी वैट मैनुअल तैयार नहीं किया गया है।

3.2.18 अनुशंसाएँ

शासन निम्न अनुशंसाओं पर विचार कर सकती है कि:

- कर व्यवस्था में सुधार करने तथा व्यापारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु जनशक्ति को युक्तियुक्त बनाया जाये।

- कम्प्यूटरीकृत किये जाने वाले क्षेत्रों हेतु मॉड्यूल्स का विकास तथा सॉफ्टवेयर में विद्यमान मॉड्यूल्स का पूर्ण परिचालन सुनिश्चित किया जाये।
- विभागीय कर्मचारियों के लिये वैट प्रशासन और कम्प्यूटरीकरण हेतु आवधिक रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण को सम्पादित किया जाये।
- आई टी सी दावों के प्रतिसत्यापन हेतु एक प्रभावी प्रणाली का विकास किया जाये।
- करमुक्त माल के विनिर्माण में संलग्न व्यापारियों के मामलों में किसी दुरूपयोग से सुरक्षा हेतु मान्यता प्रमाणपत्र निरस्त किया जाये।
- वैट प्रशासन के प्रभावी परिचालन हेतु आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा को मजबूत किया जाये।
- वैट अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की प्रभावी व्यवस्था हेतु वैट मैनुअल तैयार किया जाये।

राज्य आबकारी विभाग

3.3 राज्य आबकारी विभाग की विभाग केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा

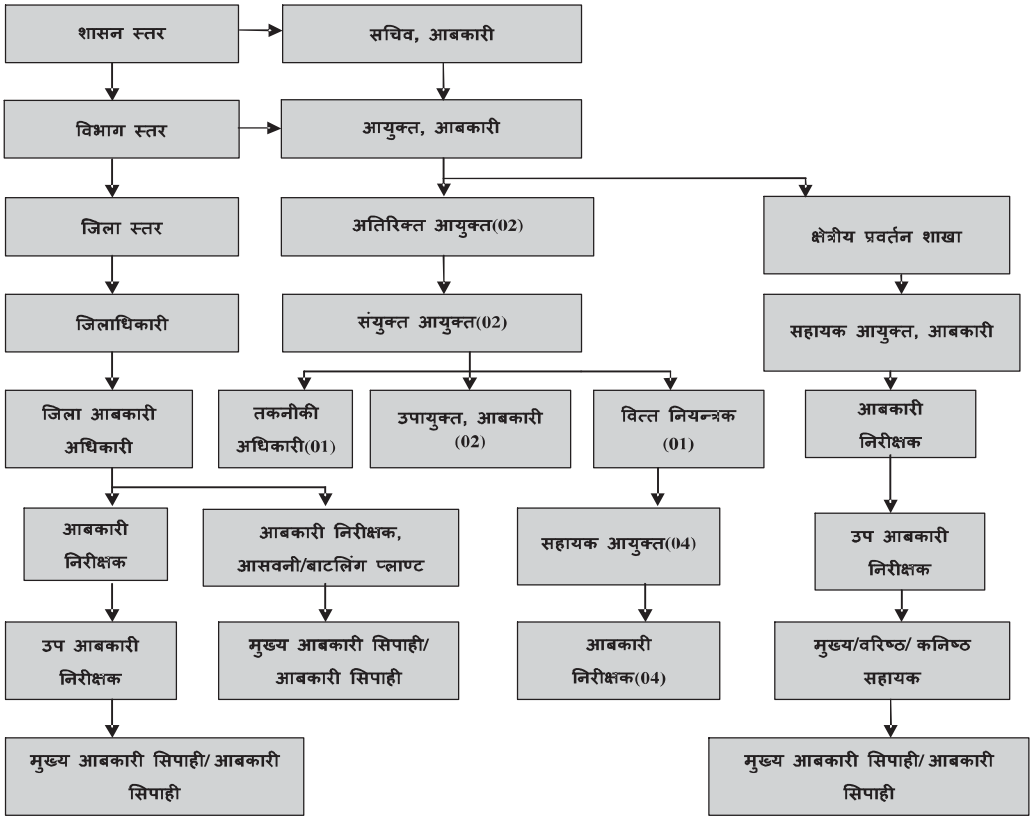
3.3.1 प्रस्तावना

विभाग आबकारी मादक पेयों के नीति-निर्धारण, उत्पादन, विनिर्माण, विक्रय, क्रय एवं परिवहन पर नियन्त्रण रखता है। आबकारी राजस्व राज्य के कर राजस्वों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। विभाग, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल) और देशी मदिरा (सी एल) पर नीति निर्धारित कर प्रवर्तन क्रिया-कलाप और राजस्व संग्रह दोनों कार्य करता है । विभाग आबकारी सम्बन्धित अपराधों को पता लगाने, निवारण, अन्वेषण तथा अधिनियम के अनुसार, अभियुक्तों पर अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी है ।

राज्य आबकारी शुल्क संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 51 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। उत्तराखण्ड में, आबकारी शुल्क संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (सं प्रा आब अधि) के अन्तर्गत लगाया और शासित होता है। यही सं प्रा आब अधि, 1910 उत्तराखण्ड राज्य में अंगीकृत किया गया था। सं प्रा आब अधि, 1910 और उसके अधीन बनाये गये नियम मादक पेयों के उत्पाद, विनिर्माण, क्रय एवं विक्रय और उन पर आबकारी शुल्कों को वसूलने के कानूनों को शासित करते हैं। आबकारी राजस्व का अधिकांश भाग एल्कोहल से प्राप्त होता है, जो मुख्यतः चीनी के विनिर्माण के दौरान सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाले शीरे से आसवनी में उत्पादित होता है। एल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे सी एल तथा आई एम एफ एल जैसे व्हिस्की, ब्रॉण्डी, रम व जिन का विनिर्माण किया जाता है। आबकारी शुल्क के इतर, अनुज्ञापन शुल्क भी आबकारी राजस्व का हिस्सा होता है। जिला कलेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी (जि आ अ)/सहायक आबकारी आयुक्त (स आ आ) की सहायता से जिले में मदिरा की दुकान स्थापित करने हेतु उत्तरदायी होता है।

3.2.2 विभागीय संरचना

राज्य स्तर पर, विभाग का मुखिया आयुक्त होता है जो सचिव, आबकारी के अधीन कार्य करता है। आयुक्त की सहायता हेतु आयुक्तालय में दो अपर आयुक्त, दो संयुक्त आयुक्त तथा दो उपायुक्त होते हैं। जिला स्तर पर, जिला आबकारी अधिकारी की सहायता हेतु आबकारी निरीक्षक, उप आबकारी निरीक्षक और आबकारी सिपाही होते हैं। आबकारी विभाग का संगठनात्मक ढाँचा चार्ट में नीचे दिया गया है:



3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि :

- विभाग ने मदिरा के विनियमन के माध्यम से दक्षता एवं प्रभावकारिता पूर्वक राजस्व संग्रहीत किया;
- मदिरा के विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों के आवंटन और मदिरा के विनिर्माण में आबकारी शुल्क एवं अन्य लागू करों एवं शुल्कों के आरोपण और संग्रहण को विनियमित करने वाले प्रावधान एवं प्रणाली पर्याप्त थी तथा उनका अनुपालन किया जा रहा था; और
- राजस्व रिसाव एवं उससे सम्बन्धित अपराधों का पता लगाने एवं निवारण हेतु एक पर्याप्त निगरानी एवं नियन्त्रण प्रणाली मौज़ूद थी।

3.3.4 लेखापरीक्षा प्रणाली और लेखापरीक्षा के क्षेत्र

विभाग केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा में 13 जि आ अ में से 8[35], राज्य आबकारी आयुक्त, देहरादून सहित चार[36] आसवानियों/भराई संयंत्रों के अभिलेखों की नमूना जाँच 23 जुलाई, 2012 से 5 सितम्बर, 2012 के

[35] जि आ अ अल्मोड़ा, जि आ अ देहरादून, जि आ अ हरिद्वार, जि आ अ नैनीताल, जि आ अ पिथौरागढ़, जि आ अ टिहरी गढ़वाल, जि आ अ ऊधमसिंहनगर (रूद्रपुर) और जि आ अ उत्तरकाशी।

मध्य, वित्तीय वर्ष 2009-12 हेतु की गई। जि आ अ का चयन राजस्व प्राप्ति की प्रमात्रा के आधार पर किया गया और इन इकाईयों के साथ चार आसवानियों/भराई संयंत्र भी चयनित किए गए थे।

विभाग केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रारम्भ होने की सूचना सचिव को दी गई थी (20 जुलाई, 2012) तथा प्रस्थान गोष्ठी अतिरिक्त सचिव/आयुक्त, आबकारी विभाग के साथ 15 दिसम्बर, 2012 को सम्पन्न हुई। शासन का उत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

3.3.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से उद्गृहीत किए गए हैं :

- सं प्रा आबकारी अधिनियम, 1910;
- उत्तराखण्ड आबकारी नियमावली;
- राज्य आबकारी नीति, वर्ष 2011-12;
- शासकीय आदेश, नियम और विनिर्देश; और
- वित्तीय नियमों और दूसरे बजट मैनुअलों के प्रावधान।

3.3.6 राजस्व का रूझान

वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए राज्य आबकारी विभाग के बजट आंकलन के साथ-साथ वास्तविक प्राप्तियों और राज्य की कर प्राप्तियों में इसके अंशों को नीचे **तालिका- 3.3.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-3.3.1 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	बजट आंकलन	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन आधिक्य (+)/ कमी (-)	विचलन का *प्रतिशत*	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक राज्य आबकारी प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों के साथ *प्रतिशत*
2009-10	598.22	704.64	+106.42	+17.79	3,559.04	19.80
2010-11	686.93	755.92	+68.99	+10.04	4,405.48	17.16
2011-12	727.67	843.65	+115.98	+15.94	5,615.62	15.03

स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट

उपरोक्त से यह देखा गया कि विभागीय राजस्व 2009 में ₹ 704.64 करोड़ से ₹139.01 करोड़ बढ़कर 2012 में ₹ 843.65 करोड़ तक हो गया। यद्यपि, कुल कर प्राप्तियों में इसका अंश 19.80 *प्रतिशत* (2009-10) से घटकर 15.03 *प्रतिशत* (2011-12) तक हो गया।

3.3.7 आबकारी शुल्कों के संग्रह की लागत

2009-12 अवधि के दौरान राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रह, संग्रह पर व्यय और इस व्यय के सकल संग्रह का *प्रतिशत* साथ ही साथ विगत वर्षों के सकल संग्रह पर संग्रहण की लागत का अखिल भारतीय औसत नीचे **तालिका-3.3.2** में दिया गया है:

[36] आसवानी : 1. बाजपुर आसवानी, बाजपुर, ऊधमसिंहनगर; 2. दून आसवानी, देहरादून 3. आई जी एल आसवानी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर और 4. वॉटलिंग प्लाण्ट; रेडिको खेतान, बाजपुर, ऊधमसिंहनगर।

तालिका-3.3.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रहण की लागत	सकल संग्रह से संग्रहण की लागत का *प्रतिशत*	पूर्व वर्ष की संग्रहण की लागत के *प्रतिशत* का अखिल भारतीय औसत
2009-10	704.64	7.33	1.04	3.66
2010-11	755.92	8.57	1.13	3.64
2011-12	843.65	7.75	0.92	3.05

स्रोतः वित्त लेखे और विभागीय आँकड़े ।

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि 2009-12 अवधि के दौरान राज्य आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड के संग्रहण की लागत अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी।

3.3.8.1 राजस्व बकाया

राज्य आबकारी विभाग की 31 मार्च, 2012 को राजस्व बकाया की स्थिति **तालिका 3.3.3** में निम्नवत् दी गई है। निम्न तालिका से यह देखा गया कि ₹ 55.38 लाख का बकाया 5 वर्षों से अधिक का था ।

तालिका-3.3.3

अवधि	31 मार्च, 2007 को बकाया अवशेष		31 मार्च, 2012 को बकाया अवशेष		वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली *(₹ लाख में)*	वसूली की *प्रतिशत*
	प्रकरणों की संख्या	धनराशि *(₹ लाख में)*	प्रकरणों की संख्या	धनराशि *(₹ लाख में)*		
दस वर्षों से अधिक	02	22.21	02	17.39	4.82	22
पाँच वर्षों से अधिक एवं दस वर्ष तक	03	37.99	03	37.99	-	-
योग	05	60.20	05	55.38	4.82	8

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना

लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 55.38 लाख की कुल बकायों में से ₹ 37.99 लाख की वसूली की तीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित थी (जुलाई, 2012), जबकि दो अन्य बकायेदार जो हरिद्वार से सम्बन्धित थे, से ₹ 22.21 लाख की धनराशि वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि इन अनुज्ञापियों के पास कोई सम्पत्ति नहीं थी। जिला हरिद्वार के दो जिला आबकारी अधिकारियों (जि आ अ) को जिम्मेदार पाया गया क्योंकि विभागीय जाँचोंपरान्त जिला कलेक्टर के द्वारा अनुज्ञापन प्रदान करने के पूर्व अनुज्ञापियों की परिसम्पत्तियों की जाँच में असफल थे। फलस्वरूप, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उनके विरूद्ध ₹ 6.30 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया। इनमें से एक जि आ अ द्वारा ₹ 4.82 लाख की पूरी धनराशि राजकोष में जमा करा दी गयी जबकि दूसरे द्वारा ₹ 1.48 लाख के अर्थदण्ड के विरूद्ध ₹ 4700 प्रतिमाह की दर से जून, 2012 से जमा किया जा रहा है। इस प्रकार, बकायेदारों की परिसम्पत्तियों के गैर-सत्यापन के फलस्वरूप ₹ 15.91 लाख के राजस्व की क्षति जो कि वसूली की जाने वाली राशि (₹ 22.21 लाख) तथा दो जि आ अ से वसूली योग्य धनराशि (₹ 6.30 लाख) के अन्तर से हुई।

आयुक्त, आबकारी ने उत्तर दिया (15 दिसम्बर, 2012) कि दो जिला आबकारी अधिकारियों से ₹ 6.30 लाख की वास्तविक क्षति की वसूली की जा रही है (3 अगस्त, 2012 तक), जबकि विभाग द्वारा ₹ 15.91 लाख की क्षति के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

3.3.8.2 अधिसमय शुल्क का पुनरीक्षण न किया जाना

आयुक्त आबकारी के आदेशानुसार (21 सितम्बर, 2004) आसवनी/बाटलिंग प्लाण्ट में पदस्थ कर्मचारी को यदि किसी अवकाश के दिनों में आसवनी/प्लाण्ट में उपस्थित रहना आवश्यक होता है तो आसवक को निर्धारित दरों[37] पर शासन को अधिसमय शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

जिला आबकारी अधिकारियों, उ सि नगर, रुद्रपुर (आई जी एल आसवनी, काशीपुर, बाजपुर आसवनी, बाजपुर एवं रेडिको खेतान बाटलिंग प्लाण्ट, बाजपुर) एवं देहरादून (दून आसवनी) के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2009-12 के दौरान ₹ 10.01 लाख का अधिसमय शुल्क उक्त तीनों आसवनियों एवं एक बाटलिंग प्लाण्ट से निर्धारित दरों पर प्राप्त किया गया था। ये दरें सात वर्ष पुरानी थीं और छठा वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में भी काफी वृद्धि हुयी, फिर भी सम्बन्धित आबकारी कर्मियों के समय- समय पर बढ़ाये गये वेतन एवं भत्तों के संदर्भ में शासन द्वारा अधिसमय शुल्क की दरों में परिवर्तन हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया।

आयुक्त, आबकारी ने बताया (15 दिसम्बर, 2012) कि आसवनी/बाटलिंग प्लाण्ट में लगे कर्मचारियों के अधिसमय शुल्क के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव बनाकर शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3.3.8.3 प्रवर्तन क्रियाकलाप

सं प्रा आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 48 व 49, एक आबकारी अधिकारी, जो आबकारी में उपनिरीक्षक से नीचे का पदधारी न हो, को अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों के सम्बन्ध में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी के अधिकारों के समान शक्तियाँ देता है। इन शक्तियों में विनिर्माण एवं विक्रय स्थलों पर किसी भी समय, दिन या रात में प्रवेश एवं निरीक्षण का अधिकार सम्मिलित है तथा ऐसे स्थानों में पाये गये किन्ही सामानों, बर्तनों, औजारों, उपकरणों, मादक वस्तुओं, लेखा बहियों एवं पंजिकाओं की जाँच और परीक्षण कर सकता है।

चार जि आ अ[38] से सम्बन्धित प्रवर्तन दल द्वारा वर्ष 2009-12 के दौरान छापे पर आधारित सूचना का विवरण निम्न **तालिका-3.3.4** में दिया गया है

तालिका-3.3.4

क्र. सं.	वर्ष	संचालित छापों की संख्या	दर्ज़/पंजीकृत मामलों की संख्या	छापों की संख्या के सापेक्ष दर्ज़/पंजीकृत मामलों की प्रतिशतता
1	2009-10	1,226	392	32
2	2010-11	1,254	401	32
3	2011-12	1,643	456	28

[37] आबकारी निरीक्षक : ₹ 60 प्रति घण्टा, आबकारी लिपिक/उप निरीक्षक : ₹ 36 प्रति घण्टा एवं आबकारी सिपाही : ₹ 32 प्रति घण्टा।

[38] अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी एवं उत्तरकाशी ।

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि अपराधियों के विरूद्ध दर्ज/पंजीकृत मामले, वर्ष 2009-12 के दौरान संचालित कुल छापों के 28 से 32 *प्रतिशत* के मध्य थे।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई-अगस्त, 2012), सम्बन्धित जि आ अ ने बताया (जुलाई-अगस्त, 2012), कि अधिकांश छापों में अपराधियों के नाम/पहचान नहीं मालूम हुये थे। पुनः जि आ अ, नैनीताल ने बताया (अगस्त, 2012) कि विभाग में पर्याप्त प्रवर्तन कार्य हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। दर्ज/पंजीकृत मामलों के निम्न *प्रतिशत* को देखते हुए अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्यों कों विश्लेषित करने हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने एवं प्रवर्तन क्रियाकलाप में लगे कर्मियों को आवधिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

3.3.8.4 अधिकतम् फुटकर मूल्य (एम आर पी) से अधिक पर मदिरा की बिक्री

सं प्रा आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 34 (बी) में वर्णित है कि इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स परमिट या पास स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी उसके धारक द्वारा या उसके नौकर द्वारा या प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुमति से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके किसी नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन की दशा में इसे निरस्त या निलम्बित कर सकता है। एम आर पी से अधिक पर मदिरा का विक्रय उन शर्तों में से एक है जो अनुज्ञाप्ति के नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो जि आ अ (टिहरी और उत्तरकाशी) ने नौ अनुज्ञापियों के विरूद्ध एम आर पी से अधिक पर मदिरा के विक्रय सम्बन्धी 23 अपराधों[39] को धारा-64 के अन्तर्गत दर्ज किया। इन प्रकरणों को शमन शुल्क के भुगतान पर निस्तारित कर दिया गया था। इन 23 प्रकरणों में से दो एवं तीन अनुज्ञापियों द्वारा क्रमशः चार और तीन बार उल्लंघन किया गया।

आयुक्त, आबकारी ने उत्तर दिया (15 दिसम्बर, 2012) कि फुटकर दुकानों के लाईसेन्स के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित दुकानों के पुनः आबंटन में आबकारी राजस्व की सम्भावित क्षति और मदिरा की तस्करी को देखते हुए नहीं की गई तथा शमन की कार्यवाही सं प्रा आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-74 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी।

विभागीय उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यह विभाग की जिम्मेदारी थी कि एम आर पी से अधिक पर मदिरा की बिक्री के निवारण हेतु फुटकर विक्रय केन्द्रों द्वारा अनुज्ञप्ति के नियम व शर्तों का बारम्बार उल्लंघन के मामलों में कठोर कार्यवाही (लाईसेन्स का निलम्बन/निरस्तीकरण) करनी चाहिये थी।

3.3.8.5 फुटकर विक्रय केन्द्रों द्वारा रसीद का निर्गमन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता को अपने द्वारा की गयी खरीद पर रसीद प्राप्त करने का अधिकार है।

---

[39] **टिहरी** : (i) श्री मंगल सिंह, चम्बा-3, (ii) श्री रतन मणि लेखावर, छाम-3 (iii) श्री अव्वल सिंह, घनसाली-4, (iv) श्री शूरवीर सिंह, धनोल्टी-2 **उत्तरकाशी** : (i) श्रीमती समुद्रो देवी, उत्तरकाशी-4, (ii) श्री चन्द्र देव, चिन्यालीसैंण-2 (iii) श्री पूर्ण चन्द रमोला, बड़कोट-2, (iv) श्री जीत सिंह, डुन्डा-3।

पुनः आबकारी नीति, 2010-11 में बताया गया कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में स्थित उच्चतम लाईसेन्स फीस वाली विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों द्वारा उपभोक्ता को मदिरा की बिक्री पर रसीद जारी करना आवश्यक है। तथापि, उपभोक्ता से अधिक मूल्य (प्रस्तर 3.3.8.4 का सन्दर्भ लें) लेने की सम्भावना को कम करने के लिये आबकारी नीति में फुटकर बिक्री दुकानों द्वारा रसीद जारी करना अनिवार्य कर देना चाहिए।

आयुक्त, आबकारी ने उत्तर दिया (15 दिसम्बर, 2012) कि प्रत्येक विक्रय केन्द्र द्वारा मदिरा की बिक्री की रसीद जारी करने के प्रस्ताव को आबकारी नीति, 2013-14 में शामिल करने हेतु सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त जि आ अ को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है (23 नवम्बर, 2012) कि प्रत्येक विक्रय केन्द्र उपभोक्ता को रसीद जारी करना सुनिश्चित करें।

3.3.8.6 शीरे से एल्कोहल का कम उत्पादन

आसवनी विनियमन नियमावली के नियम 15 (बी) में प्रावधान है कि शीरे में उपस्थित किण्वीय शर्करा के प्रत्येक कुन्तल से न्यूनतम 52.5 एल्कोहलिक लीटर (ए एल) एल्कोहल का उत्पादन होना चाहिये। इस प्रयोजन हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे का संकलित नमूना लेकर परीक्षण के लिये एल्कोहल तकनीशियन को भेजना होता है। शीरे से एल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन को अवस्थित रखने में असफल होने पर अर्थदण्ड के आरोपण के अतिरिक्त आसवानियों के लाईसेन्स को रद्द एवं प्रतिभूति जमा को जब्त किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी, आबकारी, बाजपुर सहकारी आसवनी, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर एवं दून वैली आसवनी कुँआवाला, देहरादून के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि लिये गये मिश्रित नमूना जाँच (अप्रैल, 2011 व जनवरी, 2012) में से तीन प्रकरणों (नीचे तालिका- 3.3.5 में विस्तृत रूप से वर्णित है) में मानक के अनुसार 7594.14 कुन्तल किण्वीय शर्करा से न्यूनतम 398692.35 ए एल के विरूद्ध मात्र 366912.80 ए एल का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार, एल्कोहल का उत्पादन 31779.55 ए एल कम होने के कारण सरकार को ₹ 20.66 लाख (₹ 65 प्रति ए एल दर पर) के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

तालिका-3.3.5

क्र. सं.	आसवनी का नाम	प्रकरणों की संख्या	शीरे की मात्रा (कुन्तल में)	किण्वीय शर्करा (कुन्तल में)	वांछित उत्पादन (ए एल में)	वास्तविक उत्पादन (ए एल में)	कमी (ए एल में)	धनराशि (₹ में) ₹ 65 प्रति ए एल की दर से
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	बाजपुर सहकारी आसवनी	2	18,635	6705.65	352046.79	320381.40	31665.39	2058251
2-	दून वैली आसवनी	1	2,121	888.49	46645.56	46531.40	114.16	7420
योग		**3**	**20,756**	**7594.14**	**398692.35**	**366912.80**	**31779.55**	**2065671**

तथापि, विभाग द्वारा बाजपुर आसवनी के एक प्रकरण में केवल ₹ 0.50 लाख अर्थदण्ड आरोपित और वसूल किया गया, लेकिन लाईसेन्स के निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति जमा को जब्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी (सितम्बर, 2012)।

आयुक्त, आबकारी ने प्रस्थान गोष्ठी में उत्तर दिया (15 दिसम्बर, 2012) कि आसवनी विनियमन नियमावली के नियम 15 (बी) के अन्तर्गत बाजपुर आसवनी के एक प्रकरण में प्रतिभूति जमा से ₹ 0.50 लाख जब्त किया गया। विभागीय उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि नियमों में प्रावधान था कि अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रतिभूति जब्त करने के साथ-साथ आसवनी का लाइसेन्स भी निरस्त करना था।

3.3.8.7 जनशक्ति प्रबन्धन

राज्य में क्षेत्रीय कर्मियों की 31 मार्च, 2012 को स्थिति नीचे **तालिका- 3.3.6** में दी गई है :

तालिका-3.3.6

पदनाम	स्वीकृत पद	वास्तविक तैनाती	कमी	कमी (*प्रतिशत* में)
आबकारी निरीक्षक	73	35	38	52
उप आबकारी निरीक्षक	42	27	15	36
मुख्य आबकारी सिपाही	61	55	06	10
आबकारी सिपाही	190	42	148	79

स्रोतः राज्य आबकारी दिग्दर्शिका 2011-12

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि क्षेत्रीय कर्मियों में 10 से 79 *प्रतिशत* के मध्य कमी से, प्रवर्तन कार्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ। जबकि क्षेत्रीय कर्मियों की तैनाती की समीक्षा में देखा गया कि 27 उप आबकारी निरीक्षकों[40] में से पाँच उन क्षेत्रों में तैनात थे जहाँ पर मार्च, 2012 को कोई भी पद स्वीकृत नहीं था । इसी प्रकार, 55 में से 17 (31 प्रतिशत) मुख्य आबकारी सिपाही सात जिलों[41] में स्वीकृत पदों के विरूद्ध, बिना किसी उचित कारण के तैनात थे। राज्य की 13 जाँच चौकियों में आबकारी अपराधों की जाँच हेतु, प्रत्येक जाँच चौकी पर एक आबकारी निरीक्षक, एक उप आबकारी निरीक्षक व दो आबकारी सिपाहियों के पद विभाग द्वारा स्वीकृत थे जबकि केवल एक आबकारी निरीक्षक कौड़िया जाँच चौकी, पौड़ी तथा दूसरी जाँच चौकियों में 12 भूतपूर्व सैनिक (आबकारी सिपाही के समान) मादक पदार्थों के परिवहन की जाँच हेतु चौबीसों घंटे हेतु तैनात थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा उपलब्ध जनशक्ति का उचित उपयोग नहीं किया जा सका, जिसने आबकारी अपराधों की रोकथाम व पता लगाने और मदिरा अनुज्ञापियों पर आई एम एफ एल/सी एल बिक्री की अनुज्ञापन की शर्तों को पालन कराने हेतु प्रभावी नियन्त्रण रखने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया।

आयुक्त, आबकारी ने उत्तर दिया (15 दिसम्बर, 2012) कि क्षेत्रीय कर्मियों की भर्ती हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। स्वीकृत पदों से अधिक तैनात कर्मियों पर आगामी स्थानान्तरण सत्र में कार्यवाही की जाएगी।

---

[40] हरिद्वार : क्षेत्र-3 लक्सर, चमोली : क्षेत्र-1 चमोली, उत्तरकाशी : क्षेत्र-2 पुरोला, अल्मोड़ा : भिकियासेन एवं चम्पावत : क्षेत्र-2 टनकपुर कुल पाँच उप आबकारी निरीक्षक ।

[41] (i) देहरादून-7 (ii) हरिद्वार-4 (iii) पौड़ी-2 (iv) अल्मोड़ा-1 (v) चम्पावत-1 (vi) नैनीताल-1 एवं पिथौरागढ़-1 कुल-17 मुख्य आबकारी सिपाही।

3.3.8.8 कर्मचारियों का प्रशिक्षण

प्रवर्तन शाखा के कर्मियों हेतु कार्य की प्रकृति को देखते हुए उनके कौशल उन्नयन एवं ज्ञान का वर्तमान स्तर का उन्नयन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। शारीरिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त, कर्मचारियों हेतु वर्तमान संचार क्रांति युग में साक्ष्यों का विश्लेषण एवं संचार मामलों के प्रति ध्यान दिया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि विभाग द्वारा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया है।

आयुक्त, आबकारी ने उत्तर दिया (15 दिसम्बर, 2012) कि नई भर्ती हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है तथा सभी हथियार एवं गोलाबारूद की उपलब्धतता के पश्चात्, पुलिस विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3.3.8.9 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण

अधीनस्थ कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज पर आश्वासन प्राप्त करने हेतु विभाग में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं था क्योंकि इस प्रयोजन हेतु उच्च पदधारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के लिए कोई औपचारिक प्रबन्ध/मानक नहीं थे।

आयुक्त, आबकारी ने उत्तर दिया (15 दिसम्बर, 2012) कि भविष्य में अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

3.3.9 निष्कर्ष

राज्य आबकारी पर विभाग केन्द्रस्थ अनुपालन लेखापरीक्षा में अनेक कमियाँ प्रकट हुई। आसवनी/बाटलिंग प्लाण्ट में तैनात आबकारी कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं भत्ते में बढ़ोत्तरी के बावजूद समयोपरि शुल्क वर्ष 2004 से पुनरीक्षित नहीं किया गया था। बारम्बार किये गये अपराधों के मामलों में, सं प्रा आबकारी अधिनियम, 1910 के अनुसार कठोर प्रावधान (अनुज्ञापन का निलम्बन/निरस्तीकरण) प्रारम्भ नहीं किये गये। आसवनियों में शीरे से एल्कोहल के कम उत्पादन के मामले थे। क्षेत्रीय कर्मियों की कमी से प्रवर्तन कार्यकलाप में बाधा पहुँची। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य एवं उच्च पदधारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण हेतु कोई औपचारिक योजना के अभाव में आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र अपर्याप्त पाया गया।

3.3.10 अनुशंसाएँ

प्रणाली एवं अनुपालन में सुधार के लिए, सरकार निम्न सुझावों पर विचार करेः

- संचार एवं साक्ष्यों के विश्लेषण हेतु प्रवर्तन शाखा को मूलभूत संरचना सहायता मुहैया कराना;
- फुटकर विक्रय केन्द्रों को अधिक मूल्य लेने से रोकने हेतु उनके द्वारा मदिरा की बिक्री पर रसीद जारी करना; एवं
- बारम्बार अपराधों के मामलों में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार कठोर कदम उठाना ।

अध्याय-4: आर्थिक खण्ड (पी एस यूज)

4ई सामान्य प्रस्तावना

4.1.1 खण्ड के पुनर्गठन के अन्तर्गत, सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (सा क्षे उ) को एक साथ आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत मिला दिया गया है, जिसमें 20 विभाग शामिल हैं। इस खण्ड के कुछ मुख्य विभाग उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, कृषि, सूचना प्रौघोगिकी, ग्रामीण एवं लघु उद्योग आदि हैं। राज्य में कुल 22 कम्पनियाँ एवं 2 सांविधिक निगम हैं। राज्य की कार्यरत सा क्षे उ की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यक गतिविधियों को चलाने हेतु की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य की सा क्षे उ राज्य की अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थान रखती हैं। सितम्बर 2012 तक उनके अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के सा क्षे उ ने वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 3258.60 करोड़ का कारोबार किया **(परिशिष्ट 4.1)**। उनका कारोबार राज्य के वर्ष 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) ₹ 60898 करोड़ के 5.35 *प्रतिशत* के बराबर था। राज्य के सा क्षे उ की मुख्य गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। कार्यरत सा क्षे उ ने 2011-12 **(परिशिष्ट 4.1)** में ₹ 562.75 करोड़ की हानि वहन की। इनमें (सा क्षे उ) 31 मार्च 2012 तक 18,329[1] कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2012 को 24 सा क्षे उ थे, जिनका विवरण नीचे **तालिका-4.1.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1.1

सा क्षे उ के प्रकार	कार्यरत सा क्षे उ	अकार्यरत सा क्षे उ [2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[3]	18	04[4]	22
सांविधिक निगम	02	-	02
योग	**20**	**04**	**24**

इनमे से कोई भी कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी।

4.1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सम्पादित की जाती है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों की कम से कम 51 *प्रतिशत* दत्त पूँजी लगी होती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसकी कम से कम 51 *प्रतिशत* दत्त पूँजी पर सरकार/ सरकारों, सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी सम्मिश्रण का नियंत्रण हो उसे कम्पनी अधिनियम की धारा 619- ब के तहत सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानी गई सरकारी कम्पनी) समझा जाता है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले) द्वारा नियुक्त किये

---

[1] विवरण 16 सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।

[2] अकर्यरत सा क्षे उ वे हैं जिनकी प्रचालन कार्यविधियाँ बंद कर दी गई है।

[3] 619-ब कम्पनी शामिल हैं।

[4] कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल्स फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टस लिमिटेड, यू पी ए आई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परिसमापन में)।

जाते हैं, के द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ब) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने विधानों द्वारा नियंत्रित होती हैं। राज्य के दो सांविधिक निगमों में से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिये नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपा गया था जिसे नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तो के अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक विस्तारित किया गया है।

4.1.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) में निवेश

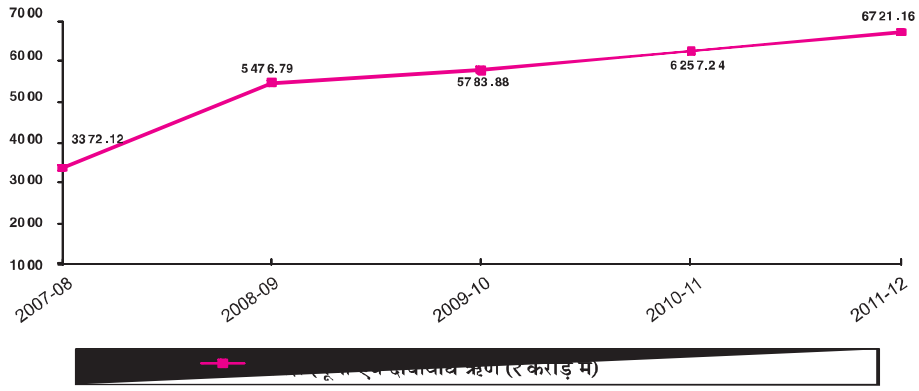
31 मार्च 2012 को 24 सा क्षे उ (619-ब कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) का कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 6721.16 करोड़ था, जिसका विवरण **तालिका 4.1.2** में दिया गया हैं।

तालिका 4.1.2 *(₹ करोड़ में)*

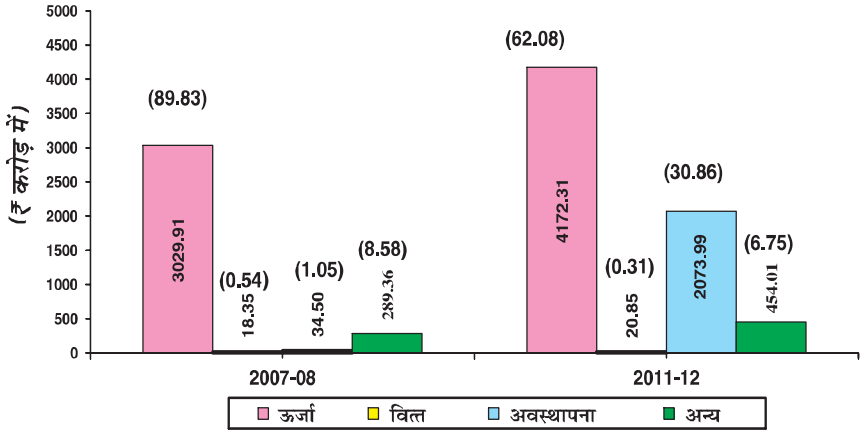
सा क्षे उ के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत सा क्षे उ	1726.07	2755.96	4482.03	2111.59	127.16	2238.75	6720.78
अकार्यरत सा क्षे उ	0.38	-	0.38	-	-	-	0.38
योग	**1726.45**	**2755.96**	**4482.41**	**2111.59**	**127.16**	**2238.75**	**6721.16**

राज्य सा क्षे उ में सरकारी निवेश का विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है।

31 मार्च 2012 को, राज्य सा क्षे उ में कुल निवेश का 99.99 *प्रतिशत* कार्यरत सा क्षे उ में एवं शेष 0.01 *प्रतिशत* अकार्यरत सा क्षे उ में था। कुल निवेश में 57.10 *प्रतिशत* पूँजी तथा 42.90 *प्रतिशत* दीर्घावधि ऋण था। यह निवेश वर्ष 2007-08 के ₹ 3372.12 करोड़ से 99.32 *प्रतिशत* बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 6721.16 करोड़ हो गया जैसा कि निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।



31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2012 के अन्त में अर्थव्यवस्था के विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निवेश एवं उनके *प्रतिशत* निम्न बार चार्ट में दर्शाए गए हैं। यद्यपि, मुख्य निवेश (62.08 *प्रतिशत)* ऊर्जा क्षेत्र में था, राज्य में निवेश का जोर मुख्यतः अवस्थापना क्षेत्र की ओर उन्मुख था जिसका *प्रतिशत* वर्ष 2007-08 के 1.05 *प्रतिशत* से बढ़कर 2011-12 में 30.86 *प्रतिशत* हो गया।



(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश पर खण्डों में निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

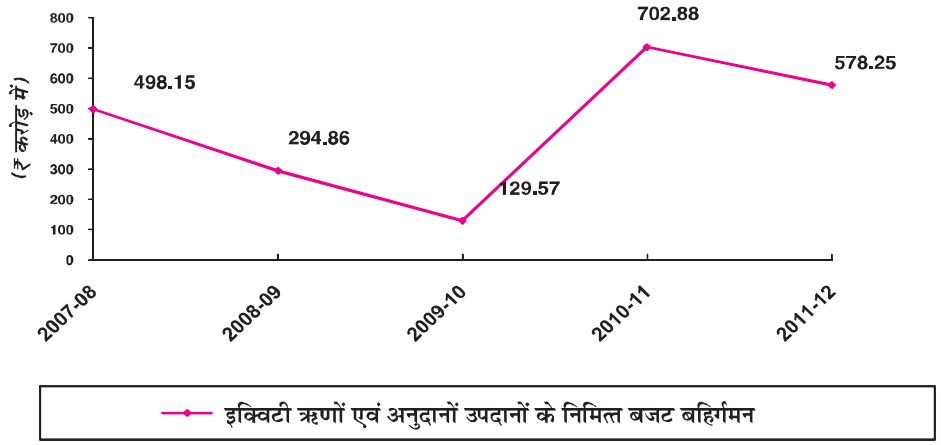
4.1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण

राज्य के सा क्षे उ से सम्बन्धित इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/ उपदान तथा गारण्टी हेतु बजट से बहिर्गमन का विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है। 31 मार्च 2012 को समाप्त तीन वर्षों का सार **तालिका - 4.1.3** में नीचे दिया गया है।

तालिका 4.1.3 *(₹ करोड़ में)*

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि	सा क्षे उ की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूँजी बहिर्गमन	3	104.01	3	603.71	4	44.00
2.	बजट से ऋण बहिर्गमन	2	24.32	3	65.70	5	458.02
3.	अनुदानों/उपदान का बहिर्गमन	6	1.24	3	33.47	5	76.23
4.	कुल बहिर्गमन (1 + 2 + 3)	-	129.57	5	702.88	-	578.25
5.	जारी की गई प्रतिभूतियाँ	2	277.54	2	279.98	1	1.35
6.	प्रतिभूति वचनबद्धता	3	1,428.81	3	289.75	5	1110.90

इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजट बहिर्गमन का पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्न ग्राफ में दिया गया है:



राज्य की सा क्षे उ द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 498.15 करोड़ से ₹ 578.25 करोड़ हो गया था।

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में प्रतिभूति वचनबद्धता की राशि ₹ 1428.81 करोड़, (तीन सा क्षे उ) की थी, जो 31 मार्च 2011 को घटकर ₹ 289.75 करोड़ (तीन सा क्षे उ) हो गयी तथा 31 मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 1110.90 करोड़ (पाँच सा क्षे उ) तक हो गई जैसा कि **परिशिष्ट 4.3** में वर्णित है। राज्य सरकार ने सभी सा क्षे उ से एक *प्रतिशत* की दर से तथा भुगतान न करने वाले सा क्षे उ से दो *प्रतिशत* की दर से प्रतिभूति शुल्क भारित किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान दो सा क्षे उ (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा ₹ 11.03 करोड़ के प्रतिभूति शुल्क राज्य सरकार को भुगतान किए गए।

4.1.5 सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षे उ के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया प्रतिभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षे उ एवं वित्त विभाग को अन्तरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2012 को इनकी स्थिति नीचे **तालिका-4.1.4** में दी गई है:

तालिका - 4.1.4 *(₹ करोड़ में)*

से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षे उ के अभिलेख के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	1760.02	3837.66	2077.64
ऋण	674.89	2883.11	2208.22
प्रतिभूतियाँ	1187.45	1110.90	76.55

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20 सा क्षे उ के आँकड़ों में अन्तर था और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। राज्य सरकार एवं सा क्षे उ को अन्तरों के मिलान के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए।

4.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) की कार्यकुशलता

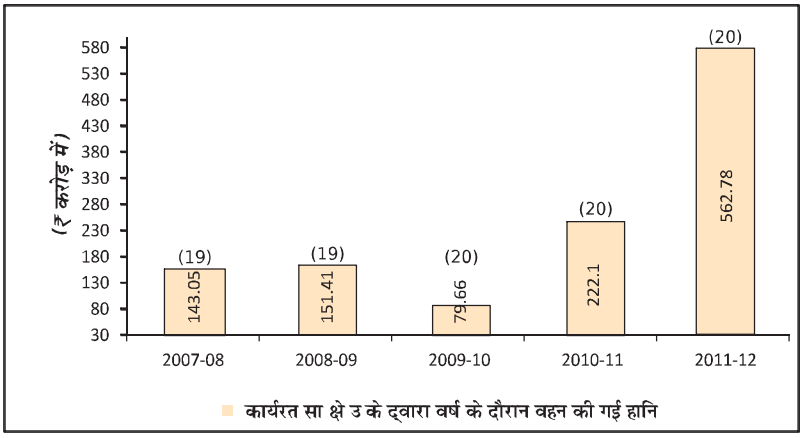
सा क्षे उ की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम ***परिशिष्ट 4.1*** में निर्दिष्ट हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) से सा क्षे उ के कुल कारोबार का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षे उ की गतिविधियों के विस्तार को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की समयावधि के लिये कार्यरत सा क्षे उ के कारोबार एवं राज्य स घ उ का विवरण नीचे **तालिका 4.1.5** मे दर्शाया गया है।

तालिका - 4.1.5 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कारोबार[5]	1,481.94	1,527.06	1,722.95	2,539.52	3,258.60
राज्य स घ उ	34,549.00	40,159.00	46,872.00	52,143.00	60,898.00
कारोबार का राज्य स घ उ से *प्रतिशत*	4.29	3.80	3.68	4.87	5.35

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) पर कारोबार का *प्रतिशत* 2007-08 में 4.29 *प्रतिशत* से 2009-10 में 3.68 *प्रतिशत* होकर घट गया था तथा 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान इसने क्रमशः 4.87 *प्रतिशत* तथा 5.35 *प्रतिशत* की वृद्धि की।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में राज्य के कार्यरत सा क्षे उ को हुई हानि को निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है।



(कोष्ठकों के आँकड़े सम्बन्धित वर्षों के दौरान कार्यरत सा क्षे उ की संख्या को दर्शाते हैं)

5 30 सितम्बर 2011 के नवीनतम अन्तिमकृत लेखों के अनुसार कारोबार।

बार चार्ट से यह दृष्टिगत है कि कुल हानि वर्ष 2007-08 के ₹ 143.05 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 562.78 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011-12 के दौरान 20 कार्यरत सा क्षे उ में से आठ सा क्षे उ ने ₹ 60.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 12 सा क्षे उ को ₹ 623.47 करोड़ की हानि हुई। स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 33.38 करोड़) एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 17.23 करोड़) लाभ अर्जित करने वाले मुख्य सा क्षे उ थे। उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 527.48 करोड़), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (₹ 37.58 करोड़) डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 16.22 करोड़) एवं पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) (₹ 9.50 करोड़), हानि उठाने वाले मुख्य सा क्षे उ थे।

सा क्षे उ को हानि मुख्यतः वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, परियोजना के कार्यान्वयन, उनके परिचालन एवं अनुश्रवण की कमियों के कारण हुई। नि म ले की नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य सा क्षे उ ने ₹ 2319.60 करोड़ की हानि वहन की एवं ₹ 7.12 करोड़ का अलाभकारी निवेश बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण निम्न **तालिका - 4.1.6** में दिया गया है।

तालिका - 4.1.6 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
शुद्ध लाभ (हानि)	(-)79.66	(-) 221.62	(-) 562.77	(-) 864.05
नि म ले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ऐसी हानि जिनसे बचा जा सकता था	1,283.32	711.76	324.52	2319.60
अलाभकारी निवेश	-	6.29	0.83	7.12

नि म ले के प्रतिवेदनों में इंगित की गई उक्त हानि सा क्षे उ के अभिलेख की नमूना जाँच पर आधारित हैं। उपर्युक्त स्थिति सा क्षे उ की कार्यप्रणाली में व्यवसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

राज्य सा क्षे उ से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय परिसीमाएँ जैसे-नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण, कारोबार आदि नीचे **तालिका-4.1.7** में दिए गए हैं।

तालिका - 4.1.7 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (*प्रतिशत में*)	-	-	0.96	0.98	-
ऋण	2356.08	2387.65	2588.39	2,465.29	2883.12
कारोबार[6]	1481.91	1527.06	1722.95	2,539.52	3258.60
ऋण/कारोबार अनुपात	1.59:1	1.56:1	1.50:1	0.97:1	0.88:1
ब्याज अदायगियाँ	158.78	156.53	124.82	271.63	288.64
संचित हानियाँ (-)	(-)291.71	(-) 283.60	(-) 420.39	(-) 807.79	(-) 1905.97

(कारोबार के अन्तर्गत दर्शाए गए आँकडे जो केवल कार्यरत सा क्षे उ के हैं, को छोड़कर अन्य आँकड़े सभी सा क्षे उ से सम्बन्धित हैं)

[6] कार्यरत *सा क्षे उ* के कारोबार उनके 30 सितम्बर 2011 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार।

यह देखा जा सकता है कि ऋण के आँकड़े 2007-08 में ₹ 2,356.08 करोड़ से 2009-10 में ₹ 2,588.39 करोड़ के बीच बढ़ते क्रम में रहा, परन्तु 2010-11 में मामूली सी गिरावट आई तथा आगे 2011-12 में बढ़कर ₹ 2,883.12 करोड़ हो गया। ऋण-कारोबार अनुपात 2007-08 में 1.59:1 से घटकर 2011-12 में 0.88:1 हो गया था क्योंकि कारोबार वृद्धि दर ऋण वृद्धि दर से आगे बढ़ गयी थी। संचित हानि 2007-08 के ₹ 291.71 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1905.97 करोड़ हो गई।

राज्य सरकार ने सा क्षे उ के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सभी सा क्षे उ के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई दत्तांश पूँजी पर न्यूनतम लाभांश प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार आठ सा क्षे उ ने ₹ 60.72 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, परन्तु उनके द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं की गयी।

4.1.7 लेखे के अन्तिमकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-ब के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा एवं विधायिका को प्रस्तुत करना, उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। कार्यरत सा क्षे उ के द्वारा सितम्बर 2012 तक लेखे को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति का विवरण निम्न **तालिका 4.1.8** में दर्शायी गई है:

तालिका-4.1.8

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत सा क्षे उ की संख्या	19	20	20	20	20
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखे की संख्या	10	13	12	28	15
3.	बकाया लेखे की संख्या	128	135	143	135	140
4.	प्रत्येक सा क्षे उ के अनुसार औसत बकाया (3/1)	6.74	6.75	7.15	6.75	7
5.	कार्यरत सा क्षे उ जिनके लेखे बकाया हैं	19	20	20	19	20
6.	बकाए की अवधि	1 से 21 वर्ष	1 से 22 वर्ष	1 से 23 वर्ष	1 से 24 वर्ष	1 से 25 वर्ष

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान लेखाओं के अंतिमीकरण में बकाया 128 से 143 के बीच थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान राज्य सा क्षे उ औसतन एक भी लेखाओं को निपटाने में असफल रही जिस कारणवश बकाये में बढ़ोत्तरी हुई। सा क्षे उ के अनुसार लेखे के अंतिमीकरण में हुई देरी का मुख्य कारण, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी थी। राज्य सा क्षे उ को पिछले लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे स्थिति को अद्यतन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, अकार्यरत सा क्षे उ के लेखे भी अंतिम रूप दिये जाते हेतु बकाया थे। चार अकार्यरत सा क्षे उ में से, एक उपक्रम जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी तथा शेष तीन अकार्यरत सा क्षे उ[7] के लेखे, 21 से 25 वर्षों से बकाया थे।

[7] कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल फोन्स लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टस लिमिटेड।

राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान पाँच सा क्षे उ में ₹ 1168.42 करोड़ का निवेश किया था (इक्विटीः ₹ 624.54 करोड़, ऋणः ₹ 522.33 करोड़ तथा अनुदान/ उपदान ₹ 21.55 करोड़), जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, उनका विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दिया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं के उल्लंघन के अतिरिक्त लेखाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी एवं लोकधन के दुरूपयोग होने का जोखिम हो सकता है।

प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि इन इकाईयों की क्रियाकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन सा क्षे उ के लेखे को निर्धारित समय सीमा में अन्तिम रूप दिया जाये तथा स्वीकार किये जायें। उपरोक्त **तालिका 4.1.8** से यह देखा जा सकता है कि कार्यरत सा क्षे उ के लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकायों की मात्रा 2007-08 के 128 से बढ़कर 2011-12 में 140 तक हो गई। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इस प्रकरण को सभापति, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) उत्तराखण्ड के माध्यम से विभागों के विभागाध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया (29 जून 2011) जिससे कि लेखाओं के बकाया का शीघ्रता से परिसमापन किया जा सके।

4.1.8 अकार्यरत सा क्षे उ का समापन

31 मार्च 2012 के अनुसार चार अकार्यरत सा क्षे उ थे। इनमें से, एक सा क्षे उ ने परिसमापन की प्रक्रिया चालू की है।

अकार्यरत सा क्षे उ के बन्द होने के चरणों को नीचे दी गई **तालिका 4.1.9** में दिया गया हैः

तालिका - 4.1.9

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	कुल अकार्यरत सा क्षे उ की संख्या	04[8]	-	04
2.	उक्त (1) में से निम्न संख्या	-	-	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01[9]	-	01
(ब)	स्वैच्छिक समापन (परिसमापक नियुक्त)	-	-	-
(स)	बन्दीकरण अर्थात् बन्द करने के आदेश/ निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03	-	03

वर्ष 2011-12 के दौरान, कोई भी कम्पनी/ निगम अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुए थे। एकमात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड है, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 20 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी। कम्पनी अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक बन्दीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्रतर है तथा इसे सशक्त रूप से अपनाने/ अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार अपनी अकार्यरत कम्पनियों को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार करें।

4.1.9 लेखा टिप्पणियाँ और आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2011-12 के दौरान सात कार्यरत कम्पनियों ने अपने 14 लेखापरीक्षित लेखे (प्र म ले) को अग्रेषित किए। 30 सितम्बर 2012 तक 12 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा दो कम्पनियों को गैर-

[8] कुम्ट्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टस लिमिटेड तथा यू पी ए आई लिमिटेड।

[9] कम्पनी जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से समापन की प्रक्रिया में थी।

समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। नि म ले द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षको और नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे **तालिका-4.1.10** में दिया गया है।

तालिका-4.1.10 *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	4	168.70	7	174.57	3	26.04
2.	हानि में वृद्वि	7	16.19	7	247.12	6	234.81
3.	आर्थिक तथ्यों को उदघोषित न किया जाना	3	169.52	6	1251.59	2	11.41

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक कम्पनी अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (यू एस आई डी सी) के वर्ष 2009-10 की लेखा को छोड़कर, सभी 13 लेखाओं को अर्हता प्रमाणपत्र प्रदान किए।

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2009-10)

- भा जी बी नि के ऋण रकम पर मूल धन तथा ब्याज की वापसी में चूक के लिए दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप अनारक्षित ऋण, देय ब्याज का अधोविवरण तथा ₹ 3.68 करोड़ के लाभ का अधिविवरण हुआ।
- सोबला-II परियोजना, जो एन एच पी सी परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गयी, पर किया गया व्यय ₹ 1.63 करोड़ का प्रावधान न किये जाने के कारण उतनी ही राशि के चालू पूँजीगत कार्य तथा लाभ प्रत्येक में ₹ 1.63 करोड़ का अधिविवरण हुआ।
- उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग को 2001 से मार्च 2011 की अवधि के लिए जारी ₹ 10.21 करोड़ के देयक विद्युत शुल्क, जिसकी वसूली संदेहास्पद थी, का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप लाभ के साथ-साथ विविध देनदार मद में उतनी ही राशि का अधिविवरण हुआ।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (2009-10)

- सरकार को देय दण्डात्मक गारंटी शुल्क का प्रावधान न होने के परिणामस्वरुप हानि तथा चालू देयताएँ मद में ₹ 10.40 करोड़ का अधोविवरण हुआ।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निर्गमित कर-मुक्त पावर बॉण्ड्स पर वर्ष 2006-07 और 2009-10 के लिए ब्याज के दायित्व का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप विविध लेनदार एवं हानि में ₹ 66.52 करोड़ का अधोविवरण हुआ।

यू पी हिल इलॅक्ट्रानिक लिमिटेड (1997-98)

- विविध देनदार पर जो 18 वर्ष पुराने थे, उन पर डूबत एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान न होने के परिणामस्वरुप विविध देनदारो का अधिविवरण तथा ₹ 1.16 करोड़ का हानि का अधोविवरण दर्शाया गया।

पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2010-11)

- सरकार को देय दण्डात्मक गारंटी शुल्क का प्रावधान न होने के परिणामस्वरुप चालू देयताएँ मद का अधोविवरण तथा ₹ 3.30 करोड़ का लाभ का अधिविवरण हुआ।
- ठेकेदार को दिए गए सात वर्ष से भी पुराने विविध अग्रिम, जिनकी वसूली संदिग्ध है, का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ऋण एंव अग्रिम मद में ₹ 3.10 करोड़ का अधिविवरण तथा उतनी ही धनराशि की हानि का अधोविवरण हुआ।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, जिसकी लेखापरीक्षा नि म ले को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अनुसार सौंपी गयी, के एक वर्ष (2010-11) के लेखे को वर्ष 2011-12 के दौरान अन्तिम रूप दिया गया। नि म ले की टिप्पणियों के 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे **तालिका-4.1.11** में दिया गया हैः

तालिका-4.1.11 *(₹ करोड़ में)*

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	5	40.84	-	-
2.	हानि में बढोत्तरी	1	2.11	5	5.25	1	24.11
3.	आर्थिक तथ्यों को उदघोषित न किया जाना	-	-	3	23.73	-	-
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	370.30	-	-	1	0.47

सांविधिक निगम अर्थात उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2010-11 के लेखाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नलिखित है:

- उत्तराखण्ड सरकार से वर्ष 2002-03 से 2008-09 के दौरान ₹ 21.02 करोड़ के ऋण पर ₹ 15.76 करोड़ के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देयताओं तथा घाटों पर ₹ 15.76 करोड़ का अधोविवरण हुआ।
- उ प्र जल निगम को देय ₹ 0.90 करोड़ (वर्ष 2006-07 तक) के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देयताओं तथा घाटों पर ₹ 0.90 करोड़ का अधोविवरण हुआ।
- निगम द्वारा सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त ब्याज ₹ 6.69 करोड़ को अपनी आय के रूप में दर्शाया गया, जो लेखा नियम/ प्रचलन के विरूद्ध है। ब्याज पर प्राप्त आय को पृथक से दर्शाया जाना चाहिए था।

4.1.10 आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत नि म ले द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार, लेखापरीक्षित कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टेड अकाउटेंट्स) को चाहिए कि आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2011-12 में 14 कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा/ आंतरिक नियंत्रण तंत्र में संभावित सुधारों पर की गई मुख्य टिप्पणियों का व्याख्यात्मक ब्यौरा नीचे **तालिका-4.1.12** में दिया गया हैः

तालिका - 4.1.12

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिन पर अनुशंसाएँ की गई	*परिशिष्ट-5.2* के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	भण्डार व कलपुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	3	A2, A10, A14,
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरुप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का अभाव	6	A5, A10, A13, A14 , A2 & A17
3.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थितियाँ, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास की कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण को दिखाने वाले अभिलेख का रख रखाव न करना	6	A5, A2, A10, A13, A14 & A12

4.1.11 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की लेखापरीक्षा राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत की जाती है जबकि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत सौंपी गई है। नि म ले द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) का सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुतिकरण की स्थिति को नीचे **तालिका-4.1.13** में दर्शाया गया है:

तालिका - 4.1.13

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए		
			पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के कारण
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2004-05	2005-06 से 2008-09	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

पृ ले प प्रतिओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब सांविधिक उपक्रमों पर विधायिका के नियन्त्रण को कमजोर करती है, तथा उन उपक्रमों की वित्तीय जवाबदेयता भी कम हो जाती है।

4.1.12 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने किसी भी सा क्षे उ के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की कोई योजना नहीं बनायी थी।

4.1.13 ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राज्य में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत सितम्बर 2002 को गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) का उद्देश्य विद्युत दरों को तर्कसंगत बनाना, राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण एवं वितरण से संबंधित मामलों में परामर्श देना तथा लाइसेंस जारी करना है। वर्ष 2011-12 के दौरान उ वि नि आ द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर दो आदेश तथा 17 आदेश अन्य मामलों में जारी किये गए थे।

4 एफ. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मुख्य अंश

"पावर ट्रान्समिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड" की निष्पादन लेखापरीक्षा

- वर्ष 2007-08 के आरम्भ में कम्पनी के पारेषण नेटवर्क में 4390.50 मेगावोल्ट एम्पेयर (मे वो ए) पारेषण क्षमता तथा 1894 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) अतिउच्च तनाव पारेषण लाइनों सहित 30 अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) उपकेन्द्र थे जो कि बढ़ाकर 4990.50 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 2319.20 सी के एम अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाइनों के साथ 35 अतिरिक्त उच्च तनाव उपकेन्द्र कर दिए गए।

(प्रस्तर 4.2.8.1)

- उपकेन्द्रों के निर्माण में 15 से 17 महीनों का विलम्ब तथा लागत में ₹ 10.08 करोड़ की वृद्धि हुई। लाइनों के निर्माण में 8 से 40 महीनों की समय वृद्धि तथा लागत में ₹ 71.11 करोड़ की वृद्धि पायी गयी।

(प्रस्तर 4.2.9.1)

- श्रीनगर-सतपुली लाइन (51.70 सर्किट कि मी) तथा श्रीनगर II- सतपुली लाइन (64 सर्किट कि मी) के निर्माण में क्रमशः 391.30 प्रतिशत तथा 123.64 *प्रतिशत* व्यय करने के बाद भी इन्हें पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 6 वर्ष तथा 7 वर्ष का विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.2.9.2)

- वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विद्यमान पारेषण क्षमता 30 *प्रतिशत* निरर्थक को छोड़कर 1489.59 मेगा वोल्ट एम्पेयर से 1774.77 मे वो ए तक अधिक आगणित की गयी। कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक भार तथा उच्च विद्युत प्रवाह (वोल्टेज) का होना पारेषण के नेटवर्क के सृजन में अवैज्ञानिक योजना को प्रतिबिम्बित करता है।

(प्रस्तर 4.2.10)

- कम्पनी ने नौ अवसरों पर ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन किया (अप्रैल 2010) जिसके फलस्वरूप कम्पनी को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के वि नि आ) को नौ लाख रूपये के दण्ड का भुगतान करना पड़ा।

(प्रस्तर 4.2.14.4)

- आपदा प्रबन्धन (अ प्र) कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष एक मॉक ड्रिल किया जाना चाहिए था। तथापि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी द्वारा किसी उपकेन्द्र में कोई मॉक ड्रिल नहीं की गयी।

(प्रस्तर 4.2.15.1)

- कम्पनी की हानि में 85.19 प्रतिशत की पर्याप्त कमी आयी, यह हानि 2007-08 में ₹ 13.98 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 2.07 करोड़ हो गई। आगे, कम्पनी का ऋण-इक्विटी अनुपात 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6.02:1 से घटकर 3.12:1 हो गया। ऋण-इक्विटी अनुपात में कमी का मुख्य कारण 2009-10 से तथा उससे आगे सरकारी ऋण का इक्विटी में परिवर्तन है।

(प्रस्तर 4.2.17.1)

- वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कम्पनी की प्रणाली उपलब्धता क्रमशः 99.24, 99.14 तथा 99.50 प्रतिशत रही। इस उत्कृष्ठ निष्पादन के लिए, ऊर्जा मन्त्रालय, (एम ओ पी) भारत सरकार (जी ओ आई) ने कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता के लिए स्वर्ण कवच (गोल्ड शील्ड) से पुरस्कृत किया (मार्च 2012)।

(प्रस्तर 4.2.19)

- यद्यपि वर्ष 2007-08 में कम्पनी का अन्तिम अवशेष भण्डार 22 महीने के उपभोग के लिए था, जो 2011-12 में बढ़कर 29 महीने के उपभोग के बराबर हो गया फिर भी न तो भण्डार का न्यूनतम/ अधिकतम स्तर निर्धारित किया और न ही मूल्य आधारित (ए बी सी स्तर) विश्लेषण किया अथवा सामग्री की आवश्यकता को पुनः क्रमित करने का स्तर निर्धारित किया।

(प्रस्तर 4.2.20.2)

- उपखण्डों तथा लाइनों के वार्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वर्षवार संचयी निष्पादन अभिलेख न तो संधारित और न ही समेकित किए जा रहे थे। पारेषण प्रणाली की लाइनों तथा उपकेन्द्रों के निष्पादन में सुधार के लिए उठाये गये कदमो से कम्पनी के निर्देशक मण्डल को मासिक/ त्रैमासिक अथवा वार्षिक रुप से अवगत नहीं किया जा रहा था जो सूचना प्रणाली प्रबंधन के प्रतिवेदनों को न्यूनतम महत्व दिए जाने को प्रतिबिम्बित करता है।

(प्रस्तर 4.2.21.1)

- कम्पनी का आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउण्टेंट की फर्मों को दिया गया था। तथापि यह पाया गया कि वाह्य एजेन्सी द्वारा किए गए आन्तरिक लेखापरीक्षा का स्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा फर्म ने न तो प्रणाली की त्रुटियाँ प्रतिवेदित की और न ही महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को इंगित किया तथा अपने प्रतिवेदन को गणितीय लेखांकन की त्रुटियों तक ही सीमित रखा तथा व्यय के औचित्य के पक्ष की अनदेखी की।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

- 31 मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की बैठक कम से कम 10 बार की अपेक्षा सात बार ही आयोजित की गयी। आगे, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 292 ए (5) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकों को भी सभी बैठकों मे उपस्थित रहना चाहिए था परन्तु किसी भी बैठक में इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

संव्यवहार लेखापरीक्षा

- बैंक द्वारा सहमति पत्र का उल्लंघन करते हुए अवशेष राशि जमा करने/ अन्तरण में विलम्ब तथा कम्पनी (उ पॉ का लिमिटेड) की कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के फलस्वरूप ₹80.99 लाख के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.3)

- कम्पनी (उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) द्वारा आबंटन की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भूखण्ड का आंवटन निरस्त करने में असफलता के परिणामस्वरूप अन्य क्रेता को अक्टूबर 2009 में निर्धारित दर पर भूखण्ड आबंटित न होने के कारण कम्पनी को ₹ 3.14 करोड़ की फलित हानि हुई।

(प्रस्तर 4.4)

निष्पादन लेखापरीक्षा

4.2 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

उत्तराखण्ड में विद्युत का पारेषण तथा ग्रिड संचालन का प्रबन्धन तथा नियन्त्रण पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा किया जाता है। यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अध्यधीन 27 मई 2004 को निगमित की गयी तथा 31 मार्च 2012 को कम्पनी के पास 2319.20 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) अतिरिक्त उच्च पारेषण लाइनें तथा 4990.50 मेगा वोल्ट एम्पेयर (मे वो ए) की स्थापित क्षमतावाले 35 उप-केन्द्र थे। वर्ष 2011-12 में कम्पनी का कारोबार ₹132.93 करोड़ था। 31 मार्च 2012 को कम्पनी में 867 कर्मचारी नियोजित थे।

मुख्य अंश

योजना और विकासः 2007-08 के आरम्भ में कम्पनी के पारेषण नेटवर्क में 4390.50 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 1894 सर्किट किमी अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाईनों सहित 30 अतिरिक्त उच्च तनाव उपकेन्द्र थे जो बढ़ाकर 4990.50 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 2319.20 सर्किट कि मी अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाइनों के साथ 35 अतिरिक्त उच्च तनाव उपकेन्द्र कर दिए गए।

(प्रस्तर 4.2.8.1)

परियोजना प्रबन्धनः उपकेन्द्रों के निर्माण में 15 से 17 माह का विलम्ब तथा लागत में ₹ 10.08 करोड़ की वृद्धि हुई थी। लाईनों के निर्माण में 8 से 40 माह की समयवृद्धि तथा लागत में ₹ 71.11 करोड़ की वृद्धि देखी गयी।

(प्रस्तर 4.2.9.1)

चालू परियोजना की पूर्णता में विलम्बः श्रीनगर-सतपुली लाइन (51.70 सर्किट कि मी) तथा श्रीनगर-II-सतपुली लाइन (64 सर्किट कि मी) के निर्माण में क्रमशः 391.30 *प्रतिशत* तथा 123.64 *प्रतिशत* व्यय करने के बाद भी इन्हें पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 6 वर्ष तथा 7 वर्ष का विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.2.9.2)

पारेषण प्रणाली का निष्पादनः वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान में विद्यमान पारेषण क्षमता 30 *प्रतिशत* निरर्थक को छोड़कर 1489.59 मे वो ए से 1774.77 मे वो ए तक अधिक आगणित की गयी। कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक भार तथा उच्च विद्युत प्रवाह (वोल्टेज) का होना पारेषण के नेटवर्क के सृजन में अवैज्ञानिक योजना को प्रतिविम्बित करता है।

(प्रस्तर 4.2.10)

ग्रिड प्रबन्धनः कम्पनी ने ग्रिड अनुशासन का नौ अवसरों पर उल्लंघन किया (अप्रैल 2010) जिसके फलस्वरूप कम्पनी को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के वी नि आ) को नौ लाख रूपये का दण्ड देना पड़ा।

(प्रस्तर 4.2.14.4)

आपदा प्रबन्धनः आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष एक कृत्रिम अभ्यास किया जाना चाहिए था तथापि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी द्वारा किसी भी उपकेन्द्र में कोई कृत्रिम अभ्यास नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.15.1)

वित्तीय प्रबन्धनः कम्पनी की हानि में 85.19 प्रतिशत की पर्याप्त कमी आयी, यह हानि 2007-08 में ₹ 13.98 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 2.07 करोड़ हो गई। आगे, कम्पनी का ऋण-अंशदान (इक्विटी) अनुपात 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6.02:1 से घटकर 3.12:1 हो गया। ऋण-अंशदान अनुपात में कमी का मुख्य कारण 2009-10 और बाद में सरकारी ऋण का अंशदान में परिवर्तन है।

(प्रस्तर 4.2.17.1)

प्रणाली उपलब्धताः वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कम्पनी की प्रणाली उपलब्धता क्रमशः 99.24, 99.14 तथा 99.50 *प्रतिशत* रही। इस उत्कृष्ट निष्पादन के लिए ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता के लिए स्वर्ण शील्ड से पुरस्कृत किया (मार्च 2012)।

(प्रस्तर 4.2.19)

सामग्री प्रबन्धनः यद्यपि वर्ष 2007-08 में कम्पनी का अन्तिम अवशेष भण्डार 22 माह के उपभोग के लिए था जो 2011-12 में बढ़कर 29 माह तक के उपभोग के लिए हो गया फिर भी न तो भण्डार का न्यूनतम/ अधिकतम स्तर निर्धारित किया और न ही मूल्य आधारित (ए बी सी स्तर) विश्लेषण किया अथवा सामग्री की आवश्यकता को पुनः क्रमित करने का स्तर निर्धारित किया।

(प्रस्तर 4.2.20.2)

शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण तथा नियन्त्रणः उपखण्डों तथा लाईनों के वार्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वर्षवार संचयी निष्पादन अभिलेख न तो संधारित और न ही समेकित किये जा रहे थे। पारेषण प्रणाली की लाइनों तथा उपकेन्द्रों के निष्पादन में सुधार के लिए उठाये गये कदमों से कम्पनी के निर्देशक मण्डल को मासिक/ त्रैमासिक अथवा वार्षिक रुप से अवगत नहीं किया जा रहा था जो सूचना प्रणाली प्रबन्धन के प्रतिवेदनों को न्यूनतम महत्व दिए जाने को प्रतिविम्बित करता है।

(प्रस्तर 4.2.21.1)

आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षाः कम्पनी का आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउण्टेंट की फर्मों को दिया गया था। तथापि यह पाया गया कि बाह्य एजेन्सी द्वारा किए गए आन्तरिक लेखापरीक्षण का स्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षक फर्म ने न तो प्रणाली की त्रुटियाँ प्रतिवेदित की और न ही महत्वपूर्ण अभियुक्तियों को इंगित किया तथा अपने प्रतिवेदन को गणितीय लेखांकन की त्रुटियों तक ही सीमित रखा तथा व्यय के औचित्य पक्ष की अनदेखी की।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

लेखापरीक्षा समितिः 31 मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की बैठक कम से कम 10 बार की बजाए केवल सात बार ही आयोजित की गयी। आगे, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 292 ए (5) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकों को भी सभी बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए था परन्तु किसी भी बैठक में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

4.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने 2012 तक सभी के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार की जिसमें कहा गया कि देश के लिए सुदृढ़ और समन्वित विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए पारेषण प्रणाली में कुशल और समन्वित कार्यवाही के अतिरिक्त पर्याप्त और यथासमय निवेश आवश्यक है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय/ राज्य पारेषण उपयोगिताओं के साथ समन्वय से राष्ट्रीय तथा राज्य ग्रिड विकसित करने को भी मान्यता दी गई है। उत्तराखण्ड में विद्युत पारेषण तथा ग्रिड प्रचालन का प्रबन्धन तथा नियंत्रण, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा किया जाता है, जो दक्ष, पर्याप्त तथा सम्यकरूप से समन्वित ग्रिड प्रबन्धन तथा ऊर्जा का पारेषण प्रदान करने के लिए अधिदेशाधीन है। कम्पनी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन से विघटन के बाद कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी का निगमन 27 मई 2004 को हुआ तथा वह उत्तराखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग को प्रतिवेदन करती है।

कम्पनी का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय निदेशक मण्डल में निहित है। कम्पनी का दैनिक कार्य निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), निदेशक (मानव संसाधन) तथा कम्पनी सचिव की सहायता से प्रबन्ध निदेशक जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी हैं, द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान कम्पनी ने ऊर्जा की 7300.37 मिलियन इकाई प्रेषित की जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 12069.84 मिलियन इकाई हो गयी, इस प्रकार 2007-12 के दौरान औसत वृद्धि 65.33 *प्रतिशत* दर्ज की गयी। 31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास 2319.20 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) तथा 35 उपकेन्द्रों के साथ 4990.50 मेगा वोल्ट एमपीयर (मे वो ए) की स्थापित क्षमता वाला पारेषण का नेटवर्क था जो 400 किलो वोल्ट (के वी), 220 के वी तथा 132 के वी पर 39345.10[10] मिलियन इकाई (एम यू) वार्षिक पारेषण में समर्थ था।

2007-08 में कम्पनी का कारोबार ₹ 78.02 करोड़ था जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 132.93 करोड़ हो गया तथा 2007-08 और 2011-12 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.21 तथा 0.22 *प्रतिशत* के बराबर था। 31 मार्च 2012 को कम्पनी में 867 कर्मचारी नियोजित थे।

यह कम्पनी की प्रथम निष्पादन लेखापरीक्षा है अतः इससे पूर्व कम्पनी की गतिविधियों पर कोई भी निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं की गयी थी।

[10] 4990.50 × 0.90 पी एफ × 24 × 365/1000=39345×10 एम यू।

4.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यविधि

मई 2012 से अक्टूबर 2012 के दौरान सम्पन्न की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा में कम्पनी के अन्तिम पाँच वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक का निष्पादन आच्छादित है। लेखापरीक्षण में मुख्यालय के विभिन्न शाखाओं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, दो अँचलों- प्रत्येक मुख्य अभियन्ता के अधीन, अधिशासी अभियन्ताओं के अधीन 22 खण्डों में से 6 खण्डों की विभिन्न शाखाओं के अभिलेख की संवीक्षा समाहित थी। खण्ड कार्यालय पूँजीगत/राजस्व प्रकृति के कार्यों के सम्पादन के साथ लेखांकन इकाई का भी कार्य करते हैं। 22 खण्डों में से 6 खण्ड सिम्पल रेण्डम सैंम्पलिंग विद्आउट रिपलेसमेण्ट विधि द्वारा चयनित किए गए।

निष्पादन लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि में कम्पनी ने पाँच उपकेन्द्र (क्षमता: 600 मे वो ए) तथा 10 पारेषण लाइनों/ 11 वेज (लम्बाई 425.20 सर्किट कि मी) का निर्माण किया। इसमें से तीन उपकेन्द्रों (क्षमताः 320 मे वो ए) तथा पाँच पारेषण लाइनों (लम्बाई 213.53 स कि मी) के निर्माण सम्बन्धी अभिलेख का परीक्षण किया गया।

लेखापरीक्षा मानदण्डों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई कार्य विधि में प्रवेश गोष्ठी के दौरान शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करना, प्रधान कार्यालय तथा चयनित इकाईयों में अभिलेख की संवीक्षा लेखापरीक्षित कार्मिकों के साथ विचार विनिमय, लेखापरीक्षा मानदण्डों के सन्दर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, प्रश्न पूछना, प्रस्थान गोष्ठी के दौरान शीर्ष प्रबन्धन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा करना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप प्रबन्धन/ सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए निर्गत करना, सम्मिलित था।

4.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य आकलन करना था कि क्याः

- परिप्रेक्ष्य योजना राष्ट्रीय विद्युत नीति/ योजना तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गयी तथा योजना की असफलता के प्रभाव का आकलन, यदि कोई हो;
- पारेषण प्रणाली का संचालन तथा अनुरक्षण मितव्ययिता, दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी ढ़ंग से सम्पन्न किया गया;
- पारेषण प्रणाली मितव्ययिता, दक्षतापूर्वक तथा प्रभावीढंग से विकसित की गयी तथा समर्पित की गयी;
- अपरिहार्य व्यवधान के सापेक्ष संचालन की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की गयी थी;
- समय पर बिल देने तथा संग्रहण पर जोर देते हुए प्रभावी तथा दक्ष वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली तथा यथा-समय टैरिफ संशोधन के लिए सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था थी;
- सामग्री अभिप्राप्ति तथा सामग्री नियन्त्रण तन्त्र सक्षम तथा प्रभावशाली था;
- राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप दक्ष तथा प्रभावी ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए गए तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना; तथा

- वर्तमान/चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए, चिन्हित त्रुटियों के निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय करने, लेखापरीक्षा/आन्तरिक लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों का तत्काल तथा पर्याप्त रूप से उत्तर देने के लिए अनुश्रवण प्रणाली है।

4.2.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन के लिए लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से ग्रहण किए गए:-

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना तथा राष्ट्रीय टैरिफ के प्रावधान;
- कम्पनी की परिपेक्ष्य योजना तथा परियोजना के प्रतिवेदन;
- मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारित, साम्यता तथा नैतिकता के सिद्धान्तों के सन्दर्भ में संविदा प्रदान करने की मानक प्रक्रिया;
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) का टैरिफ निर्धारण किये जाने के लिए प्रस्तुत वार्षिक राजस्व की आवश्यकता (ए आर आर), परिपत्र, नियमावलियाँ तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली के प्रतिवेदन;
- पारेषण योजना मानदण्ड़ों की नियमावली (एम टी पी सी);
- तकनीकी इन्टरफेंस संहिता (सी टी आई)/ ग्रिड संहिता, योजना, संचालन, संयोजन संहिता युक्त;
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी)/ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) द्वारा निर्गत मानक/ दिशानिर्देश;
- ऊर्जा मन्त्रालय (एम ओ पी) द्वारा गठित समिति की पारेषण की सर्वोत्तम पद्धति की अनुशंसा प्रतिवेदन;
- पारेषण परियोजना के कार्यान्वयन में जटिल तत्वों का विश्लेषण करने के लिए ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रतिवेदन; तथा
- आँचलिक ऊर्जा समिति (आर पी सी)/ आँचलिक भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) के प्रतिवेदन।

4.2.5 लेखापरीक्षा पद्धति

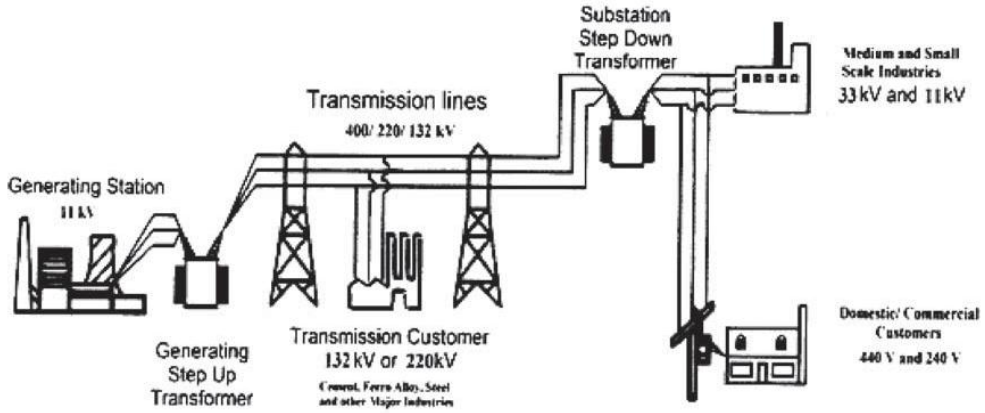
लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण कियाः

- कम्पनी की कार्यसूची टिप्पणी तथा कार्यवृत्त, वार्षिक प्रतिवेदन लेखाओं तथा आँचलिक ऊर्जा लेखाओं (आर ई ए) की समीक्षा;
- ऋण फाइलों, भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों की संवीक्षा;
- वार्षिक बजट के आँकड़ो तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित पूर्णता प्रतिवेदन का विश्लेषण;
- उ वि नि आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्धारित टैरिफ;
- परियोजना के निष्पादन, अधिप्राप्ति, धन की प्राप्ति तथा व्यय सम्बन्धी अभिलेख की संवीक्षा;
- प्रविष्टि एवं प्रस्थान गोष्ठी के दौरान प्रबंधन के साथ चर्चा; तथा
- निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवदेन का प्रारूप प्रबन्धन/शासन को उनकी टिप्पणी के लिए निर्गत करना।

4.2.6 पारेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

विद्युत पारेषण, ऊर्जा का उच्च वोल्टेज; सामान्यतया 132 किलोवोल्ट तथा अधिक पर लम्बी दूरी तक अन्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा संयन्त्रों में अपेक्षाकृत कम वोलटेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा, पारेषण में हानि कम करने तथा ग्रिड में दक्षता बढ़ाने के लिए पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज में परिवर्तित की जाती है। उपकेन्द्रों में उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली में वोल्टेज को एक स्तर तक दूसरे स्तर में बढ़ाने/ घटाने; प्रणाली में अथवा प्रणाली के बाहर की विद्युत प्रणालियों तथा स्विचिंग उपकरणों के संयोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाली सुविधायें हैं। उत्पादन केन्द्रों में वोल्टेज बढ़ानेवाले पारेषण उपकेन्द्र लम्बी दूरी तक पारेषण के लिए वोल्टेज बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रान्सफार्मरों का प्रयोग करते हैं।

विद्युत ऊर्जा का भण्डारण नहीं किया जा सकता, अतः उत्पादन का आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक पारेषण प्रणाली की माँग के सभिकर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण की परिष्कृत प्रणाली जिसे ग्रिड प्रबंधन कहते हैं, की आवश्यकता होती है। पारेषण प्रक्रिया की सचित्र प्रस्तुति नीचे दी गयी हैः



4.2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड तथा पद्धति कम्पनी के प्रबन्धन को 25 मई 2012 को आयोजित प्रवेश गोष्ठी में स्पष्ट कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष कम्पनी तथा राज्य सरकार को 31 अक्टूबर 2012 को सन्दर्भित किए गए थे तथा 20 दिसम्बर 2012 को आयोजित प्रस्थान गोष्ठी में भी उन पर चर्चा की गयी। प्रस्थान गोष्ठी में प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (मानव संसाधन) तथा विभिन्न शाखाओं के मुख्य अभियन्ता उपस्थित थे। कम्पनी ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर दिसम्बर 2012 में दिया। राज्य सरकार ने अलग से उत्तर नहीं दिया। तथापि निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय उनके द्वारा दिए गए उत्तरों तथा प्रस्थान गोष्ठी में अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

4.2.8 योजना तथा विकास

4.2.8.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना

केन्द्रीय पारेषण सुविधा (सी टी यू) तथा राज्य पारेषण सुविधाओं (एस टी यूज) का मुख्य उत्तरदायित्व सभी सम्बन्धित एजेन्सी यथा पारेषण सुविधा, राज्य नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) से समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय विद्युत योजना (एन ई पी) पर आधारित नेटवर्क योजना तथा विकास करना है। दसवीं योजना की समाप्ति पर (मार्च 2007) देश की पारेषण प्रणाली में 765/एच वी डी सी/400/230/220 के वी की 1.98 लाख (सर्किट किलोमीटर) की पारेषण लाइनें थीं जिन्हें 11वीं योजना की समाप्ति (मार्च 2012) तक बढ़ाकर 2.93 लाख सर्किट कि मी करने की योजना थी। राष्ट्रीय विद्युत योजना ने 2006-07 की समाप्ति पर अन्तर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का आकलन 14,100 मेगावाट (एम डब्ल्यू) किया तथा 11वीं योजना में 23,600 मेगावाट जोड़ने की योजना थी जिससे अन्तर क्षेत्रीय क्षमता बढ़कर 37,700 मेगावाट हो जाए।

2007-08 के आरम्भ में कम्पनी के नेटवर्क में 4390.50 मेगावोल्ट एम्पेयर (एम वी ए) तथा 1894 सर्किट कि मी अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) पारेषण लाइनों के 30 अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) वाले उपकेन्द्र थे। यह पारेषण नेटवर्क 31 मार्च 2012 तक बढ़कर 4990.50 मे वो ए तथा 2319.20 सर्किट कि मी अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाइनों के 35 अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) वाले उपकेन्द्र हो गये।

कम्पनी राज्याभ्यान्तर पारेषण प्रणाली की योजना तथा विकास के लिए उत्तरदायी है। क्षमता में वृद्धि के लिए माँग का आकलन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यद्यपि उ वि नि आयोग द्वारा 9 अप्रैल 2007 को निर्गत ग्रिड संहिता के अनुसार कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) के लिए राज्य विद्युत योजना तैयार करनी अपेक्षित थी परन्तु कम्पनी ने ऐसा नहीं किया। तथापि कम्पनी ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं पर आधारित तथा भार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारेषण कार्यों के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों का विवरण समाविष्ट करते हुए प्रतिवर्ष निवेश योजना उ वि नि आ को प्रस्तुत की। तथापि इसे भार के पूर्वानुमान से सन्दर्भित नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी के पास वर्तमान भार की स्थिति सम्बन्धी आँकड़े थे परन्तु आकल्पित भार वृद्धि की गणना के लिए प्रचलित-विश्लेषण नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी ने पूर्ण पारेषण तंत्र, वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) की माँग तथा ऊर्जा निष्क्रमण अनुयोजना के साथ योजना व विकास योजना को अगस्त 2012 में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) के समक्ष प्रस्तुत किया। तथापि, तथ्य यह है कि कम्पनी ने राज्य विद्युत योजना को प्रस्तुत करने में पाँच वर्षों (31 मार्च 2012 तक) का विलम्ब किया।

4.2.8.2 पारेषण नेटवर्क तथा उसकी वृद्धि

कम्पनी ने 580 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 558.51 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) पारेषण लाइनें स्थापित करने के लक्ष्य के साथ से पंचवर्षीय योजना (2007-12) बनायी। इसके सापेक्ष कम्पनी ने 2007-08 से

2011-12 की अवधि में पाँच उपकेन्द्रों के साथ 600 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 425.20 स कि मी (76.13 *प्रतिशत*) पारेषण लाइनों का लक्ष्य प्राप्त किया तथा 133.31 सी के एम[11] की कमी रह गयी। वन विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में तथा रास्ते के लिए स्पष्ट अधिकार प्राप्त करने में विलम्ब कमी के मुख्य कारण थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी की अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) स्तर पारेषण क्षमता **परिशिष्ट 4.5** में दी गयी है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, कम्पनी कोई भी पारेषण लाइन के निर्माण अथवा पारेषण क्षमता में वृद्धि में असफल रही। कम्पनी की पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विद्युत योजना के दिशा-निर्देशों तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा अप्रैल 2007 में निर्गत ग्रिड कोड के अनुरूप नहीं थी क्योंकि इसमें अन्तर्राज्यीय तथा राज्याभ्यान्तर पारेषण प्रणाली के सम्बन्ध में पर्याप्त विवरण समाविष्ट नहीं किए गए थे। इसमें ट्रान्सफार्मर्स, केपेसिटर्स, रिएक्टर्स आदि जैसे अतिरिक्त उपकरण जिनकी कम्पनी को निकट भविष्य में आवश्यकता हो, अलग नहीं किए गए।

वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान, वोल्टेज के अनुसार क्षमता वृद्धि-योजना, वास्तविक वृद्धि, क्षमता में कमी आदि **परिशिष्ट 4.6** में दी गयी हैं। कम्पनी ने वन विभाग से अनुमति तथा रास्ते का स्पष्ट अधिकार अग्रिम में नहीं प्राप्त किया। अतः 558.51 सर्किट कि मी के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.2.9 पारेषण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन

पारेषण परियोजना में अवधारणा से प्रारम्भ करने तक अनेक गतिविधियाँ समाहित होती हैं। पारेषण परियोजना में प्रमुख गतिविधियाँ (i) परियोजना का व्यवस्थापन, मूल्याँकन तथा अनुमोदन का चरण, (ii) परियोजना का कार्यान्वयन चरण हैं। परियोजना कार्यान्वयन की अवधि घटाने के लिए, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पारेषण परियोजनाओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया (फरवरी 2005):

- पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जटिल तत्वों का विश्लेषण करना;
- केन्द्रीय पारेषण सुविधाओं तथा राज्य पारेषण सुविधाओं की उत्तम प्रथाओं का कार्यान्वयन; तथा
- आदर्श पारेषण परियोजना हेतु 24 मास की अवधि के निर्धारण का सुझाव।

टास्क फोर्स ने पारेषण प्रणालियों की पूर्णता के लिए गति बढ़ाने के लिए निम्न उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव दिया तथा अनुशंसा की (जुलाई 2005)।

- तैयारी की विभिन्न गतिविधियाँ यथा सर्वेक्षण अभिकल्प तथा परीक्षण, वन तथा अन्य साविधिक अनुमति के लिए प्रसंस्करण, निविदा गतिविधियाँ आदि परियोजना मूल्याँकन तथा अनुमोदन चरण से पहले/ समानान्तर करना तथा पारेषण लाइन परियोजना की संस्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त हो जाए तो निर्माण गतिविधि तुरन्त आरम्भ करना।

[11] नई 132 के वी लाईन का लक्ष्य था-273.90 सी के एम - उपलब्धि 173.20 सी के एम = कमी 100.70 सी के एम तथा नई 220 के वी लाईन का लक्ष्य था 284.61 सी के एम- उपलब्धि 252 सी के एम = कमी 32.61 सी के एम ।

- टावर रचना की रूपरेखा का मानक सुनिश्चित करना जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में 6 से 12 महीने की बचत की जा सके।

4.2.9.1 कम्पनी ने परियोजना के समय पर पूर्ण होने के लिए टास्क फोर्स समिति द्वारा दिए गए विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। फलस्वरूप, 2007-12 के दौरान कुछ उपकेन्द्रों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ जैसा नीचे तालिका **4.2.1** में दिया गया हैः

तलिका 4.2.1

उपकेन्द्रों का कार्यान्वयन *(₹ करोड़ में)*

क्षमता के वी में	उप केन्द्रों का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण करने की वास्तविक तिथि (समय वृद्धि)	प्रदत्त लागत	वास्तविक लागत (लागत वृद्धि)	समय वृद्धि तथा लागत वृद्धि के कारण
220	महुआखेड़ा गंज-काशीपुर	जून 2010 सितम्बर 2011 तक विस्तृत	नवम्बर 2011 (17 महिने)	74.99	74.99	कम्पनी द्वारा कंट्रोल तथा रिले पैनल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय लिया गया
132	सतपुली	अगस्त 2009	जनवरी 2011 (15 महिने)	4.43	9.58 (5.15)	कम्पनी द्वारा ठेकेदार को भूमि देने में विलम्ब
132	सिमली	जनवरी 2008	जुलाई 2009 (17 महिने)	6.40	11.33 (4.93)	कम्पनी द्वारा ठेकेदार को भूमि देने में विलम्ब

कम्पनी प्रबन्धन ने उपरोक्त प्रकरणों में उत्तर नहीं दिया।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह भी आया कि कम्पनी मार्ग का अधिकार, वन की अनुमति आदि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण पारेषण लाइनों का कार्य यथा मनेरी-भाली-II- ऋषिकेश, डी सी घुत्तू-घनशाली, घनशाली-चम्बा तथा सतपुली-कोटद्वार पूर्ण नहीं कर सकी फलतः आठ महिने से चालीस महिने की समय वृद्धि हुई तथा लागत में ₹ 71.11 करोड़ की वृद्वि हुई जैसा **परिशिष्ट 4.7** में दिया गया है।

प्रबंधन का उत्तर नियमानुसार था।

- **220 के वी मनेरी भाली-द्वितीय ऋषिकेश लाइनः** प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि यह वन विभाग की अनुमति में विलम्ब के कारण हुआ (मई 2008)। प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कम्पनी ने वन विभाग से अनुमति का प्रकरण ठेकेदार को संविदा प्रदान करने के बाद तैयार करना आरम्भ किया तथा मूल प्रकरण जो अगस्त 2005 में प्रस्तुत किया था। वन विभाग द्वारा अपने प्रश्नों के साथ सितम्बर 2005 में वापस कर दिया गया था। वन विभाग को प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद सैद्धान्तिक अनुमोदन दिसम्बर 2007 में तथा अन्तिम अनुमोदन मई 2008 में प्राप्त हुआ। कम्पनी को भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय की टास्क फोर्स की पारेषण परियोजनाओं पर उपरोक्त अनुशंसाओं के उल्लंघन के कारण लागत वृद्धि सहन करनी पड़ी।
- **220 के वी डी सी घुत्तु-घनशालीः** प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि समयवृद्धि वन के गलियारे की अनुमति में विलम्ब के कारण हुई। पेड़ों का कटान अक्टूबर 2011 में पूर्ण हुआ। प्रबन्धन का उत्तर

युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि परियोजना का वन विभाग से अनुमोदन अप्रैल 2009 में प्राप्त हो गया था तथा कम्पनी द्वारा इस लाइन के लिए अभिकल्पित टावर; पहले परीक्षण के दौरान असफल हो गया, उसके अभिकल्प में संशोधन किया गया तथा पुनः परीक्षण किया गया, जिसके कारण कार्य में विलम्ब हुआ।

- **132 के वी सतपुली-कोटद्वार लाइनः** प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विलम्ब तथा लागत वृद्धि का मुख्य कारण कम्पनी द्वारा पर्वतीय भूभाग के अनुकूल कार्य की मात्रा में परिवर्तन था। लाइन की वनानुमति अप्रैल 2008 में प्राप्त की गयी थी तथा वन गलियारा जनवरी 2010 में साफ कर दिया गया था। कम्पनी का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि वन विभाग से सैद्धान्तिक अनुमोदन मार्च 2006 में मिल गया था। विलम्ब का मुख्य कारण कम्पनी द्वारा वन विभाग की प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में अतिरिक्त समय लेना था।

कम्पनी ने उक्त लाइनों पर ₹ 140.91 करोड़ व्यय किया जिसमें से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) ने मार्च 2012 तक केवल ₹ 54.03 करोड़ की अनुमति दी तथा कम्पनी को शेष राशि अपने संसाधनों से वहन करनी पड़ी।

4.2.9.2 चालू परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब

कम्पनी ने 132 के वी डी सी श्रीनगर-सतपुली पारेषण लाइन (51.70 स कि मी) तथा 132 के वी श्रीनगर II-सिमली पारेषण लाइन (64 स कि मी) के निर्माण के लिए एक निजी फर्म[12] के साथ अगस्त 2004 तथा अक्टूबर 2005 में क्रमशः ₹ 10.92 करोड़ तथा ₹ 38.96 करोड़ के दो अनुबन्ध किए। उक्त परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि क्रमशः अगस्त 2006 तथा वनानुमति से छः महीने थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2012) कि श्रीनगर-सतपुली लाइन (51.70 स कि मी) का निर्माण अगस्त 2006 की निर्धारित तिथि से छः वर्ष के विलम्ब के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी ठेकेदार को जुलाई 2012 तक स्पष्ट मार्ग का अधिकार उपलब्ध करवाने में असफल रही जिसके कारण कम्पनी को जुलाई 2012 तक आनुषंगिक व्यय सहित ₹ 53.65 करोड़ (391.30 *प्रतिशत* अधिक) का निष्फल व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि परियोजना की लागत में वृद्धि टावर के डिजाइन में परिवर्तन तथा नगर पालिका पौड़ी की भूमि जहाँ एक टावर खड़ा करना था प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुई, तथा कार्य सितम्बर 2012 में पूर्ण किया गया। तथापि तथ्य है कि कम्पनी को विस्तृत सर्वेक्षण के समय स्पष्ट मार्ग का अधिकार चिह्नित कर लेना चाहिए था तथा विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक अनुमति पूर्व में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

श्रीनगर II -सिमली लाइन (64 स कि मी) के सम्बन्ध में ठेकेदार ने पारेषण लाइन के वन रहित क्षेत्र 22.38 स कि मी (34.97 *प्रतिशत*) पर निर्माण कार्य पूरा कर दिया। कम्पनी ने जुलाई 2012 तक पारेषण लाइन पर अनुषांगिक प्रभार सहित ₹ 48.17 करोड़ व्यय किए (23.64 *प्रतिशत* से ऊपर)। प्रदत्त लागत के 123.64

[12] मेसर्स रणजीत सिंह एण्ड कम्पनी।

प्रतिशत व्यय करने के बाद भी कम्पनी वनेत्तर भूमि में उक्त लाइन का केवल 34.97 *प्रतिशत* ही निर्माण कर सकी। संविदा अक्टूबर 2005 में प्रदान की गयी तथा अनुबन्ध के अनुसार पूर्णता की तिथि वनानुमति से छः महीने थी। परन्तु ठेका प्रदान करने के बाद सात वर्ष व्यतीत होने के बाद भी शेष क्षेत्र के लिए वनानुमति अभी भी प्राप्त की जानी थी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सैद्धान्तिक वनानुमति अप्रैल 2010 में प्राप्त कर ली थी तथा अन्तिम अनुमोदन भूमि के अन्तरण के बाद, जो प्रक्रिया में थी, प्रदान की जाएगी। कम्पनी का उत्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल वन अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अनुबन्ध किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में, अनुबन्ध अक्टूबर 2005 में सम्पादित किया गया तथा वनानुमति के लिए प्रकरण नोडल कार्यालय, देहरादून को विलम्ब से अप्रैल 2009 में प्रस्तुत किया गया जिसके बाद प्रकरण दिसम्बर 2012 तक शर्तें पूरी करने के लिए कम्पनी तथा नोडल अधिकारी के बीच घूमता रहा। शेष प्रमुख बाधा, कम्पनी तथा सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में असमर्थता थी। यदि कम्पनी ने पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया होता तो लागत तथा समयवृद्धि कम की जा सकती थी।

4.2.9.3 उत्पादन क्षमता तथा पारेषण सुविधाएँ

राष्ट्रीय विद्युत नीति (रा वि नी) में उत्पादन क्षमता तथा पारेषण सुविधाओं में अन्तर का परिहार करने के लिए नई उत्पादन क्षमताओं की योजना को ध्यान में रखते हुए पारेषण क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गयी। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पारेषण सुविधाओं तथा उत्पादक कम्पनी की उत्पादन योजना में समानता होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने समीक्षा अवधि के दौरान पाया (जून 2012) कि केवल दो उत्पादन केन्द्र यथा-मनेरी भाली- II (304 मेगावाट) तथा भिलंगना (24 मे वा) चालू किए गए। प्रथम कार्य राज्य की उत्पादन सुविधा द्वारा फरवरी 2008 में तथा द्वितीय एक निजी उत्पादक[13] द्वारा नवम्बर 2011 में पूर्ण किया गया। कम्पनी उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा पारेषण में सफल रही।

4.2.9.4 उत्तराखण्ड एकीकृत पारेषण परियोजना के क्रियान्वयन में शिथिलता

कम्पनी ने उत्तराखण्ड में व्यापक ऊर्जा निकासी प्रणाली तथा राज्य में गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एकीकृत नेटवर्क के विकास के लिए एकीकृत पारेषण प्रणाली आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) को प्रस्ताव किया (सितम्बर 2006)। प्रस्तावित परियोजना में वर्ष 2004 की चौथी तिमाही के कीमत पर आधारित ₹ 2446.74 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर यमुना, भागीरथी अलकनन्दा तथा शारदा घाटियों में प्रस्तावित 5406.50 मेगावाट (मे वा) ऊर्जा निकासी परिकल्पित थी।

योजना के वि प्रा द्वारा जनवरी 2007 में तथा ऊर्जा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में अनुमोदित की गयी। परियोजना का वित्त पोषण पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन (पी एफ सी) तथा एशियन डेवलपमैन्ट बैंक (ए डी बी) द्वारा भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से किया गया। प्रस्तावित परियोजनायें

[13] मेसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड।

मार्च 2012 तक पूर्ण की जानी निर्धारित थी। कम्पनी ने उत्तराखण्ड एकीकृत पारेषण परियोजना योजना के उ ए पा प यो के अधीन 2007-08 से 2011-12 तक 1887 स कि मी लाइनों तथा 2190 मेगा वोल्ट एम्पीयर (मे वो ए) के उपकेन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित उ ए पा प योजना की प्राक्कलिक लागत एवं पूर्णता की लक्षित तिथि का विवरण परिशिष्ट **4.8** में दिया गया है।

उ ए पा प के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के संज्ञान में निम्न बातें आयीः

4.2.9.5 अनुबन्ध प्रदान करना

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 2080.25 करोड़ की प्राक्कलित लागत सहित 20 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जिनके सापेक्ष ₹ 603.43 करोड़ के केवल 10 अनुबन्धों को अन्तिम रूप देकर प्रदान किया जा सका। इनमें से केवल तीन परियोजनायें[14] पूर्ण की जा सकी तथा तीन में से यथा 400 के वी उप केन्द्र रूड़की से 220 के वी उप केन्द्र रूड़की 220 के वी डबल सर्किट लाइन समय पर पूरी की गयी (नवम्बर 2010) तथा शेष दो 17 से 22 महीने के विलम्ब से पूरी की गयी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह भी आया कि कम्पनी ने परियोजनायें एक साथ आरम्भ करने की बजाए पृथक-पृथक आरम्भ किया। कम्पनी ने 400 किलो वोल्ट एम्पीयर (के वी ए) श्रीनगर उपकेन्द्र के निर्माण कार्य का ठेका दिया तथा उससे सम्बद्ध मुख्य श्रीनगर काशीपुर लाइन का कार्य आरम्भ करने के लिए पहल नहीं की। इसी प्रकार कम्पनी ने 400 के वी द्विपरिपथ (डबल सर्किट) विष्णुगाड-कुवारीपास लाइन के निर्माण कार्य का ठेका दिया परन्तु कुवारीपास से सम्बद्ध 400 के वी गैस इन्सुलेटिड उपकेन्द्र का निर्माण कार्य का ठेका अभी तक (दिसम्बर 2012) नहीं दिया गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि श्रीनगर विद्युत गृह का 400 के वी उपकेन्द्र का ठेका एक ठेकेदार[15] को 06.05.2011 को दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 220 के वी बारम्बरी-श्रीनगर लाइन का ठेका अन्य ठेकेदार[16] को 23.04.2011 को दिया गया है। श्रीनगर काशीपुर लाइन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब अलकनन्दा घाटी का सम्पूर्ण उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। कुवारीपास उपकेन्द्र का ठेका उत्पादकों की आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। प्रबन्धन का उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि 400 के वी द्विपरिपथ (डी सी) श्रीनगर काशीपुर लाइन उपकेन्द्र का प्रकरण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) के लिए प्रस्तुत था तथा 400 के वी द्विपरिपथ (डी सी) श्रीनगर काशीपुर लाईन का अनुमोदन 400 के वी श्रीनगर उपकेन्द्र के अनुमोदन के साथ ही प्राप्त कर लेना चाहिए था क्योंकि यह उपकेन्द्र की मुख्य सम्बद्ध लाइन है। उपकेन्द्रों तथा उसकी सम्बद्ध लाइनों का काम एक साथ आरम्भ किया जाना चाहिए था जिससे

---

[14] 220 के वी डी सी लाईन, 400 के वी एस एस रूड़की से 220 के वी एस एस रूड़की तक (निर्धारित समापन तिथिः 31.12.2010 तथा वास्तविक समापन तिथिः 24.11.2010), 220 के वी डी सी लाईन भिलंगना - III से घनसाली लाईन (निधारित समापन तिथिः 17.01.2010 तथा वास्तविक समापन तिथिः 04.11.2011) तथा 220 घनसाली- चम्बा लाईन (निधारित समापन तिथिः 25.04.2008 तथा वास्तविक समापन तिथिः 30.09.2009)।

[15] मेसर्स टाटा परियोजना।

[16] मेसर्स हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

काशीपुर उपकेन्द्र के भार वहन में सहभागिता तथा कुमाऊँ अंचल नेटवर्क के सुदृढीकरण का अभिप्रेत उद्देश्य पूरा होता, ऐसा न होने के कारण योजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

4.2.9.6 ब्याज की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने ₹ 185.68 करोड़ में 400 कि वी द्विपरिपथ (डी सी) लोहारीनागपाल कोटेश्वर लाइन के निर्माण कार्य का ठेका एक निजी कम्पनी[17] को दिया (फरवरी 2009)। अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्पनी ने ठेकेदार को 9.07 *प्रतिशत* की वार्षिक दर से ब्याज पर ₹ 18.57 करोड़ गतिशीलता अग्रिम दिया (मार्च 2009)।

उत्तराखण्ड सरकार के जल विद्युत परियोजनाओं को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय (जनवरी 2011) के फलस्वरूप कम्पनी ने अनुबंध निरस्त कर दिया क्योंकि लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी तथा ठेकेदार से गतिशीलता अग्रिम ब्याज सहित वापस करने के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2011)। ठेकेदार ने कम्पनी के अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। अतः कम्पनी ने ठेकेदार की ₹ 18.57 करोड़ की बैंक गारंटी का नकदीकरण कर दिया (दिसम्बर 2011)।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा निवेदन किया (दिसम्बर 2012) कि गतिशीलता अग्रिम पर ब्याज की राशि ठेकेदार के ₹ 44.04 करोड़ के बिलों अथवा ₹ 18.59 करोड़ की निष्पादन गारंटी, जो कम्पनी ने अपने पास रोक कर रखी है तथा मई 2013 तक वैध है, से वसूली कर ली जाएगी।

तथापि, तथ्य है कि अनुबंध निरस्त करने के 21 महीने बाद भी मोबलाइजेशन एडवान्स पर ₹ 4.49 करोड़[18] ब्याज की वसूली बकाया थी (दिसम्बर 2012) जब कि वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार वसूल की जानी चाहिए थी।

4.2.9.7 मोबलाइजेशन एडवान्स पर ब्याज प्रभारित न करना

कम्पनी ने 400 किलो वोल्ट (के वी) द्विपरितथ तपोवन-पीपलकोटी श्रीनगर तथा पीपलकोटी में 400 के वी द्विपरिपथ विष्णुप्रयाग मुजफ्फर नगर पारेषण लाइन के 220 के वी द्विपरिपथ लता-तपोवन-जोशीमठ पारेषण लाइन तथा 220 के वी द्विपरिपथ जोशीमठ-पीपलकोटी पारेषण लाइन के कार्यान्वयन के लिए एक निजी कम्पनी[19] से क्रमशः ₹ 64.38 करोड़, ₹ 24.63 करोड़ तथा ₹ 60.59 करोड़ के तीन अनुबंध किए (अप्रैल 2011)। अनुबंध के नियम तथा शर्तों के अनुसार कम्पनी ने ₹ 14.95 करोड़ (अनुबंध मूल्य का 10 *प्रतिशत*) गतिशीलता अग्रिम के रूप में सितम्बर 2011 से नवम्बर 2011 के मध्य ठेकेदार को अवमुक्त किए। निविदा प्रलेख इस तथ्य पर कि क्या अग्रिम ब्याज सहित था अथवा ब्याज मुक्त था, अस्पष्ट था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि जैसा अपेक्षित था, ठेकेदार को ब्याज मुक्त गतिशीलता अग्रिम निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि गतिशीतला अग्रिम सम्बन्धी अनुच्छेद में कम्पनी द्वारा संशोधन किया गया (सितम्बर 2011) तथा निश्चय किया गया कि

---

[17] मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड।

[18] ₹ 18.57×32×9.07/12×100= ₹ 4.49 करोड़।

[19] मेसर्स टाटा परियोजना लिमिटेड, सिकन्दराबाद।

मोबलाइजेशन एडवान्स पर 9.07 *प्रतिशत* की दर से ब्याज लिया जाये। ठेकेदार ने मोबलाइजेशन एडवान्स पर ब्याज सम्बन्धी संशोधित उपबन्ध इस अभ्युक्ति के साथ अस्वीकार कर दिया कि निविदा दस्तावेज तथा हस्ताक्षरित अनुबंध में ब्याज का उल्लेख नहीं था। अन्ततः कम्पनी ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2011) कि ब्याज युक्त मोबलाइजेशन एडवान्स वाला उपबन्ध लागू नहीं होगा, यद्यपि कम्पनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा पावर फाइनेन्स कापोरेशन से लिए गए ऋण पर 11 *प्रतिशत* की दर से ब्याज दे रहा था।

इस प्रकार, निविदा दस्तावेज तथा अनुबंध में ब्याज का उपबन्ध समाहित न करने के कारण दिसम्बर 2012 तक मोबलाइजेशन एडवान्स पर ₹ 1.47 करोड़[20] का ब्याज नहीं लिया जा सका।

प्रबन्धन ने निवेदन किया (दिसम्बर 2012) कि परियोजना का वित्त पोषण पारेषण एशियन डेवलपमैन्ट बैंक द्वारा किया जा रहा था तथा ए डी बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गतिशीलता अग्रिम पर ब्याज प्रभार का कोई प्रावधान नहीं है तथा प्रबन्धन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मामलों का भविष्य में ध्यान रखा जाये।

4.2.9.8 उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना योजना (यू आई टी पी अनुयोजना) का अनसुलझा लागत प्रतिलब्धित तन्त्र

उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना (यू आई टी पी) योजना के अधीन, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (ए डी बी) को 250 मिलियन अमेरिकन डालर तथा पावर फाइनेन्स कापोरेशन (पी एफ सी) को ₹ 800 करोड़ की निधि उपलब्ध करवानी पड़ी। निधि का 70 *प्रतिशत* एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के सम्बन्ध में दी जाने वाली भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से आना था, जिसमें से 90 *प्रतिशत* अनुदान के रूप में तथा 10 *प्रतिशत* ऋण के रूप में होना था। शेष 30 *प्रतिशत* उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में उपलब्ध करवाया जाना था। पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन के सम्बन्ध में दी जाने वाली निधि का 70 *प्रतिशत* ब्याज की लागू दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जाना था तथा 30 *प्रतिशत* उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में दिया जाना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने उपरोक्त योजना पर जून 2012 तक ₹ 41.97 करोड़ पहले ही व्यय कर लिए थे व मार्च 2012 तक ₹ 603.43 करोड़ के 10 अनुबंध किए थे। ₹ 1218.80 करोड़ की प्राक्कलित लागत वाले छः अनुबंध अन्तिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में थे। तथापि, उक्त निवेश की टैरिफ के माध्यम से वसूली की सम्भावना निम्न कारणों से कठिन प्रतीत होती है:

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) उक्त निवेश का टैरिफ के माध्यम से वसूली के लिए सहमत नहीं था (दिसम्बर 2011), क्योंकि नेटवर्क से निष्क्रमित 50 *प्रतिशत* से अधिक ऊर्जा राष्ट्रीय ग्रिड के लिए उपयोग की जाएगी तथा निवेश अन्तर्राज्यीय पारेषण सुविधा जैसी मानी जाएगी। अतः अनुमति केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) से प्राप्त की जानी चाहिए। उ वि नि आयोग ने आगे कहा (दिसम्बर 2011) कि कम्पनी योजना की सम्पूर्ण वार्षिक लागत की वसूली के लिए उत्तरदायी होगी तथा इस उद्देश्य के लिए अनुज्ञापी (कम्पनी) उ स पा योजना के अधीन विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकेन्द्रों/ लाइन की

[20] ₹ 14.95 करोड़×9.07×13/12/100=₹ 1.47 करोड़।

सम्पूर्ण क्षमता के अनुरूप लाभार्थियों के साथ पर्याप्त संख्या में पारेषण सेवा का अनुबंध करने का पूरा प्रयास करेगी।

तथापि, कम्पनी योजना में निवेश की लागत वसूली तन्त्र विकसित करने में अब तक (दिसम्बर 2012) असफल रही। परिणामस्वरूप, कम्पनी के लिए योजना के अधीन सृजित किए जाने वाले उपकेन्द्रों तथा लाइनों के अनुरक्षण के अतिरिक्त ऋण तथा ब्याज का प्रतिदान करना कठिन होगा।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि समेकित ऊर्जा पारेषण योजना किसी भी पारेषण युटिलिटी द्वारा देश में पहली बार प्रस्तावित की गयी है तथा कम्पनी ने विभिन्न घाटियों में सभी जल विद्युत उत्पादको को नेटवर्क में संयोजन को ध्यान में रखते हुए यह योजना विकसित की है। उच्च वोल्टेज पर परिचालक समूह के साथ बहुपरिपथ टावर निर्माण से वनों की बचत तथा उत्तराखण्ड ग्रिड के सुदृढीकरण, राज्यान्तर्गत तथा अन्तर्राज्यीय ऊर्जा विनिमय तथा उत्तर भारत में ग्रिड संयोजन सुलभ होगा। कम्पनी ने अनसुलझा लागत वसूली तन्त्र का विषय के वि नि आ के समक्ष रखा है तथा कम्पनी के पास अब तक (दिसम्बर 2012) योजना में निवेश का वसूली तन्त्र नहीं था।

4.2.9.9 लाइन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ₹ 6.29 करोड़ की अप्रतिलब्धि

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (जून 2012) कि वर्तमान ऋषिकेश-धरासू तथा चम्बा-धरासू लाइनों के टिहरी बाँध जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण स्थानान्तरित की जानी आवश्यक थी। तथापि, लाइन का स्थानान्तरण कार्य दिसम्बर 2012 तक अपूर्ण था। कम्पनी ने उपर्युक्त सन्दर्भित लाइनों के 15 टावरों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टी एच डी सी) से ₹ 7.79 करोड़ का दावा किया (जनवरी 2010)। टी एच डी सी ने ₹ 1.50 करोड़ का भुगतान जुलाई 2010 में किया। कम्पनी द्वारा टी एच डी सी से ₹ 6.29 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा निवेदन किया (दिसम्बर 2012) कि राशि टी एच डी सी से वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.2.9.10 लाइन के निर्माण का लक्ष्य अप्राप्त रहना

उपकेन्द्रों के संयोजन के उद्देश्य से कम्पनी ने 132 किलो वोल्ट (के वी) द्विपरिपथ पारेषण लाइन 220 के वी उपकेन्द्र (पी जी सी आई एल) से 132 के वी उपकेन्द्र पिथौरागढ़ के निर्माण के लिए पूर्णता की निर्धारित तिथि (11.03.2011) सहित ₹ 5.46 करोड़ का एक अनुबंध (मार्च 2010) एक निजी फर्म[21] के साथ किया। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (जून 2012) कि कम्पनी ने ठेकेदार को जनवरी 2011 में मोबलाइजेशन एडवान्स के रूप में ₹ 0.54 करोड़ का भुगतान किया। उक्त लाइन के निर्माण का कार्य जून 2012 तक आरम्भ नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने निवेदन किया (जून 2012) कि मार्ग के सर्वेक्षण की अधिसूचना के बाद जनता द्वारा 07 अप्रैल 2010 के सर्वे के सन्दर्भ में आपत्तियाँ उठायी गई। प्रस्तावित मार्ग में परिवर्तन तथा अनुनय के बाद जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा नए मार्ग के लिए 4.68 हे भूमि का प्रकरण फरवरी 2011 में वन विभाग

[21] मेसर्स कश्मीरी लाल कन्सट्रक्शन्स।

को प्रस्तुत किया गया। वनभूमि के उपयोग के लिए पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय से इस शर्त पर सैद्धान्तिक अनुमोदन मिला (अप्रेल 2011) कि वन विभाग के पक्ष में दोगुनी प्रतिपूरक भूमि अन्तरित की जाए। भूमि स्थानान्तरण तथा पट्टे पर दिए जाने के मामले की प्रक्रिया चालू थी तथा उपरोक्त कारणों से कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन का उत्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि पारेषण लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने की पूर्व से ही वांछित मार्ग का अधिकार तथा वनानुमति थी। कम्पनी ने इन सांविधिक अनुमतियों की उपेक्षा की तथा अनुबंध कर दिया जिससे कार्यारम्भ में विलम्ब हुआ। आगे परियोजना में समय तथा लागत वृद्धि से इन्कार नहीं किया जा सकता।

4.2.9.11 स्थापित टावरों की गंभीर हालत

बिंदाल ऋषिकेश माजरा डबल सर्किट लाइन के 132 किलो वोल्ट (के वी) के 16 टावर देहरादून की बिंदाल नदी के तल पर स्थित है, जिसमे से 14 टावर गंभीर हालत में थे क्योंकि इनकी नींव एवं पुश्ते को हर बरसात के मौसम से नदी में बाढ़ की वजह से कटाव का खतरा था। जैसा कि निम्न तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिखाया गया हैः



बिंदाल नदी पर नींव के साथ टावर की फाइल फोटो



बिंदाल नदी पर क्षतिग्रस्त नींव के साथ टावर की फाइल फोटो

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2012) कि हर बरसात के मौसम में नदी में पानी के बढ़े हुए प्रवाह के कारण कम्पनी को बिजली की आपूर्ति बनाए रखने में कठनाई का सामना करना पड़ा। वर्ष 2007-08 के दौरान अगस्त 2007 को 18-अ टावर भारी बाढ़ की वजह से ढ़ह गया। फलस्वरूप 48 घंटे से अधिक समय तक क्षेत्र में पूर्ण अंधकार रहा तथा एक महीने से ज्यादा तक विद्युत आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रही।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान टावरों को नुकसान से बचाने के लिए कम्पनी ने इन टावरों की नींव के संरक्षण पर ₹ 1.10 करोड़ का व्यय किया। तथापि, संरक्षण कार्य अस्थायी प्रकृति का था तथा कम्पनी हर बरसात के मौसम में एक ही कार्य बार-बार करने के लिए मजबूर हुई।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2012) कि कम्पनी टावरों की नींव को मजबूत बनाने के लिए संभावित व्यवहार्य समाधान पर विचार कर रही थी। कम्पनी का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कम्पनी इन टावरों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था को अपनाने में विफल रही।

इसी तरह, 66 के वी रूड़की-पथरी पारेषण लाइन के दो पोल गंभीर स्थिति में रूड़की की सोलानी नदी के तल पर स्थित थे। यह लाइन पथरी पावर हाउस से विद्युत की निकासी कर 132 के वी उपकेन्द्र रूड़की को प्रेषित करने की वजह से काफी महत्वपूर्ण थी।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अगस्त 2011 में भारी बाढ़ की वजह से 9 एवं 11 नामक दो पोल ढह गए तथा पथरी पावर हाउस में उत्पादित बिजली की निकासी नहीं की जा सकी। इस वजह से छः दिनों तक विद्युत निकास न होने से 20.40 मेगावॉट (एम डब्लू) प्रतिदिन की दर से विद्युत उत्पादन का नुकसान हुआ तथा इसे 22 अगस्त 2011 तक ही बहाल किया जा सका।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को माना (दिसम्बर 2012) और कहा कि पर्याप्त सावधानियाँ बरती जा रही थी तथा पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए ज्यादा दूरी वाले एक नए 132 के वी के टावर का निर्माण अब किया जा चुका था। प्रबंधन ने उत्पादन हानि को भी स्वीकार्य किया।

4.2.9.12 पारेषण लाइन के निर्माण पर ₹ 20.48 करोड़ की हानि।

220 किलो वोल्ट (के वी) डबल सर्किट सिंगल जेबरा घुत्तू-घनसाली पारेषण लाइन के निर्माण, परीक्षण, संचरण एवं आपूर्ति के लिए एक निजी फर्म[22] से दो समझौते (मई 2009) क्रमशः ₹ 8.12 करोड़ तथा ₹ 10.65 करोड़ में किये गये।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2012) कि उक्त पारेषण लाइन के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य एक निजी जनरेटर (मै/एस बी एच पी एल) द्वारा उत्पादित विद्युत (24 मेगावाट) की निकासी थी। ₹ 20.48 करोड़ का व्यय उपरोक्त जनरेटर के डिपोजिट कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उपरोक्त लाइन का निर्माण एक निजी जनरेटर के डिपोजिट कार्य के रूप में उत्पादित विद्युत निकासी के लिए समर्पित था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त लाइन पर किया गया व्यय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) ने भी अनुमन्य नहीं किया।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि यू ई आर सी ने अंतर राज्य ओपेन एक्सेस को वर्णित करने वाला विनियमन (2010) वर्ष 2010 में ही जारी किया था। कम्पनी द्वारा पारेषण शुल्क के निर्धारण के संबंध में एक याचिका दायर की गयी थी (जून 2012) जो कि यू ई आर सी के समक्ष विचारधीन थी। हालाँकि, यह तथ्य है कि कम्पनी द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) द्वारा जारी (दिसम्बर 2009) अंतर राज्य पारेषण सिस्टम (आई एस टी एस) में कनेक्टिविटी के लिए आवेदन के प्रसंस्करण की प्रक्रिया का उल्लंघन किया था, जिसके अनुसार 250 मेगावाट या उससे अधिक के हाइड्रो जनरेटर को अपने खर्चे पर समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसका निर्माण पारेषण यूटिलिटी द्वारा किया जाएगा। इस मामले में, निजी जनरेटर केवल 24 मेगावाट विद्युत पैदा कर रहा था। अतः लाइन के निर्माण की लागत उसके द्वारा वहन की जानी चाहिए थी।

[22] मेसर्स रणजीत सिंह।

इस प्रकार, आई एस टी एस पर सी ई आर सी के दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण कम्पनी को ₹ 20.48 करोड़ का नुकसान सहन करना पड़ा क्योंकि इस राशि को न तो यू ई आर सी ने अनुमन्य किया (दिसम्बर 2012) न ही इस सम्बन्ध में जनरेटर द्वारा कोई भुगतान किया गया।

4.2.9.13 उपकेन्द्रों की स्थापित क्षमता का कम उपयोग।

132 किलो वोल्ट (के वी) भूपतवाला, हरिद्वार उपकेन्द्र वर्ष 2004-05 में 80 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम वी ए) क्षमता के साथ शुरू किया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 2012) कि प्रारम्भ से इस उपकेन्द्रों की 80 एम वी ए की स्थापित क्षमता तथा 56 एम वी ए की क्षमता 30 *प्रतिशत* मार्जिन के बाद, के सापेक्ष केवल 22.14 एम वी ए से 32.40 एम वी ए की सीमा में ही पारेषण क्षमता का उपयोग किया गया। यह कम्पनी द्वारा लोड़ का गलत आंकलन दर्शाता है जिसके फलस्वरूप उपकेन्द्रों से पूर्ण वित्तीय लाभ नहीं पाया जा सका।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से 33 के वी रिंग सिस्टम द्वारा लोड को पुनर्वितरित करने के लिए अनुरोध किया गया था। हरिद्वार एक धार्मिक केन्द्र हैं तथा अस्थिर लोड़ की वजह से अतिरिक्त क्षमता महत्वपूर्ण है। हालाँकि यह तथ्य है कि कुभ मेले का आयोजन बारह वर्ष में एक बार तथा अर्द्धकुम्भ का छः वर्ष में एक बार होता है। इस प्रकार अतिरिक्त क्षमता का उपयोग निकट स्थित ज्वालापुर उपकेन्द्र का लोड साझा करने के लिए किया जा सकता था जो कि अतिभारित था। उपकेन्द्र का लोड पुनर्वितरण अभी तक क्रियान्वित नहीं था (दिसम्बर 2012)।

4.2.10 पारेषण प्रणाली का निष्पादन

उच्च गुणवत्ता तथा न्यूनतम अवरोध वाली विद्युत प्रवाह के लिए एक्सट्रा हाई टेंशन (ई एच टी) उपकेन्द्रों के उचित रखरखाव पर कम्पनी का निष्पादन निर्भर करता है। उपकेन्द्रों तथा लाइनों के क्रियान्वयन के दौरान लाइन हानि कम करने और बिजली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए घटक उपप्रणालियों के भीतर माँग आपूर्ति प्रोफाइल की पहचान की जाती है तथा प्रणाली सुधार योजनाओं द्वारा वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार किये जाते है। ये योजनाएँ मौजूदा ट्रान्सफॉर्मर क्षमता की वृद्धि के अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर का स्थापना, अतिरिक्त लाइनें बिछाने के लिए तथा कैपिसिटर बैंक की स्थापना के लिए है। प्रणाली के संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम) के संबंध में कम्पनी के प्रदर्शन पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत निकासी के लिए तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे लोड को संभालने के लिए कम्पनी ने पारेषण लाइनें तथा विभिन्न वोल्टेज स्तर के ई एच टी उपकेन्द्र का निर्माण किया। एक ट्रान्सफॉर्मर उच्च दक्षता पर आल्टरनेटिंग करंट (ए सी) के वोल्टेज को अन्य वोल्टेज में बदल देता है। वोल्टेज के स्तर को, प्रक्रिया में कम से कम नुकसान के साथ ए सी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऊर्जा की निकासी सामन्तयाः 220 किलो वोल्ट (के वी) उपकेन्द्र पर की जाती है। मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले पाँच सालों में कम्पनी द्वारा निर्मित पारेषण क्षमता (220 के वी) के समानान्तर पारेषित क्षमता (सबसे अधिक माँग की पूर्ति) का विवरण **तालिका 4.2.2** में नीचे दिया गया हैः

तालिका 4.2.2

पारेषण क्षमता (एम वी ए में)				
वर्ष	स्थापित क्षमता	30 फीसदी छोड़ने के बाद क्षमता	सबसे अधिक माँग गैर संपाती माँग के साथ	अतिरिक्त (3-4)
1	2	3	4	5
2007-08	4550.50	3185.35	1410.58	1774.77
2008-09	4550.50	3185.35	1471.76	1713.59
2009-10	4590.50	3213.35	1575.29	1638.06
2010-11	4630.50	3241.35	1751.76	1489.59
2011-12	4990.50	3493.35	1974.11	1519.24

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सकल पारेषण क्षमता प्रत्येक वर्ष आवश्यकता से अधिक थी। 30 *प्रतिशत* अतिरेक छोड़ कर भी मौजूदा पारेषण क्षमता, वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के मध्य 1489.59 एम वी ए से 1774.77 एम वी ए अधिक था। कुछ स्थानों[23] पर व्यापक अधिकार, उच्च वोल्टेज पारेषण नेटवर्क के निर्माण में अवैज्ञानिक योजना को दर्शाता है जैसा कि अनुच्छेद 4.2.9.13 व 4.2.11.2 में चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार्य किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि वर्तमान में कम्पनी के पास अतिरिक्त पारेषण क्षमता है, किन्तु यह व्यापक योजना तथा भविष्य की लोड जरूरतों को ध्यान में रखकर है तथा इसका निकट भविष्य में ही उपयोग कर लिया जाएगा।

4.2.11 पारेषण उपकेन्द्रों का निष्पादन

4.2.11.1 उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

पारेषण योजना मानदण्ड मैनुअल (एम टी पी सी) अलग-अलग उपकेन्द्रों के लिए अधिकतम अनुमानित क्षमता बताता है जैसा कि 320 मेगा वोल्ट एमपीयर (एम वी ए) 220 किलो वोल्ट (के वी) के लिए तथा 150 एम वी ए 132 के वी उपकेन्द्र के लिए। उपकेन्द्रों की अधिकतम अनुमानित क्षमता की जाँच में पता चला (अगस्त 2012) कि किसी भी 220 के वी व 132 के वी उपकेन्द्र ने अनुज्ञात स्तर का अतिक्रमण नहीं किया। यह भी पाया गया कि 132 के वी तथा ऊँची क्षमता वाले, प्रत्येक उपकेन्द्र पर न्यूनतम दो ट्रान्सफॉर्मर होने चाहिए। इसके अलावा, पारेषण योजना और सुरक्षा मानक (टी जी एस एस) जो कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा जारी किया गया है के अनुसार उपकेन्द्र में ट्रान्सफॉर्मर की संख्या की इस प्रकार योजना बनाई जानी चाहिए कि एक ट्रान्सफॉर्मर के खराब होने की स्थिति में शेष ट्रान्सफॉर्मर 80 *प्रतिशत* लोड आपूर्ति कर सकें।

लेखापरीक्षा ने काशीपुर, पंतनगर, रूड़की, हरिद्वार तथा देहरादून के विभिन्न क्षमता के अनुरक्षण एवं परिचालन (ओ एण्ड एम) खण्ड के 16 उपकेन्द्रों के नमूना जाँच में पाया गया (अगस्त 2012) कि किसी भी उपकेन्द्र के पास किसी भी क्षमता का अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर एन-1 आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नहीं था। यद्यपि यह कम्पनी के एन-1 (प्रत्येक उपकेन्द्र पर आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किसी भी क्षमता के अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर की आवश्यकता थी) आकस्मिक स्थिति के निर्देशों (जून 2011) के अनुसार

[23] काशीपुर, पन्तनगर, बाजपुर, कोटद्वार, ज्वालापुर, मंगलौर, भगवानपुर तथा रूड़की।

अनिवार्य था। यह भी देखा गया कि किसी ट्रान्सफॉर्मर के खराब होने कि स्थिति में स्थापित ट्रान्सफॉर्मर 80 *प्रतिशत* भार वहन करने में सक्षम नहीं थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया एवं कहा कि (दिसम्बर 2012) क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित है तथा भार को प्रत्येक उपकेन्द्र पर स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के लिए नए उपकेन्द्र स्थापित किए जा रहे थे। हालाँकि, कम्पनी एन-1 आकस्मिक स्थिति पर फिर भी शांत रही।

4.2.11.2 उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता के सापेक्ष अधिक लोड

लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 2012) कि वर्ष 2005-06 में सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने के लिए 200 मेगावोल्ट एमपीयर का एक 220 किलो वोल्ट (के वी) का उपकेन्द्र सिडकुल हरिद्वार में चालू किया, जो कि 30 *प्रतिशत* सुरक्षा मार्जिन छोड़ने के बाद, वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक अपने पारेषण क्षमता से 140 एम वी ए के विरूद्ध 168 एम वी ए से 205 एम वी ए तक अधिक पर चल रहा था। तथापि कम्पनी ने स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की यह उपकेन्द्र के उपकरणों के भारी नुकसान का कारण बन सकता है।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाना विचाराधीन था।

इसी प्रकार, से 80 एम वी ए की स्थापित क्षमता वाले 132 के वी उपकेन्द्र, ज्वालापुर तथा कोटद्वार, 30 *प्रतिशत* की सुरक्षा मार्जिन छोड़ने के बाद वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान 56 एम वी ए के स्थान पर क्रमशः 73.67 एम वी ए से 81.53 एम वी ए तक तथा 65 एम वी ए से 70 एम वी ए तक उपयोग किए गए। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया कि कम्पनी ने उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए न तो स्थापित क्षमता बढ़ाई नहीं अतिरिक्त भार अन्य उपकेन्द्र पर स्थानांतरित किये।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 30 *प्रतिशत* का मार्जिन छोड़ने के बाद देहरादून खण्ड के 132 के वी उपकेन्द्र बिंदाल एवं माजरा तथा रूड़की खण्ड के 132 के वी उपकेन्द्र रूड़की तथा भगवानपुर 2009-10 से 14 से 42 एम वी ए तक अतिभारित थे। इस प्रकार, कम्पनी दो अवसरों पर विफल रही, किसी ट्रान्सफॉर्मर के खराब होने की स्थिति में एन-1 आकस्मिक आवश्यकता तथा उपरोक्त वर्णित उपकेन्द्र दो वर्षों से अधिक समय से अतिभारित चल रहे थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किये तथा कहा (दिसम्बर 2012) कि उपकेन्द्र केवल आकस्मिक हालात में ही अतिभारित चल रहे हैं तथा निवारक कार्यवाही भी की जा रही थी। हालाँकि यह तथ्य फिर भी बना रहा कि उपरोक्त उपकेन्द्र अभी तक अतिभारित चल रहे थे (दिसम्बर 2012)।

4.2.11.3 वोल्टेज प्रबंधन

अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के अनुज्ञापीयों को हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रिड का वोल्टेज हमेशा सीमा में रहे। भारतीय ग्रिड कोड के अनुसार, राज्य पारेषण उपयोगिता (एस टी यू) को 380-420 के वी, 198-245 के वी तथा 119 से 145 के वी वोल्टेज क्रमशः 400 के वी, 220 के वी तथा 132 के वी पर बनाए रखनी चाहिए। पाँच अनुरक्षण एवं परिचालन खण्ड (400 के वी तथा 132 के वी काशीपुर, तथा 220 के वी पंतनगर) कुमाऊँ क्षेत्र के तथा दो खण्ड (132 के वी देहरादून तथा 220 के वी रूड़की) गढ़वाल क्षेत्र

के वर्ष 2007-12 के जनवरी से मई माह के बस वोल्टेज के नमूना जाँच (अगस्त 2012) से पता चला कि 132 के वी के आठ[24] उपकेन्द्रों में वोल्टेज 100 के वी से 150 के वी की सीमा में दर्ज हुई थी जो कि निर्धारित अधिकतम 145 के वी तथा न्यूनतम 119 के वी वोल्टेज की सीमा में नहीं थे।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि इस मुद्दे को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

4.2.12 लाइनों का प्रबंधन

4.2.12.1 अतिरिक्त उच्च तनाव वाली लाइनें (ई एच टी)

जैसा कि पारेषण योजना मानदण्ड मैन्यूअल (एम टी पी सी) में बताया गया है, अनुमन्य लाइन लोड आमतौर पर थर्मल लोड लिमिट (टी एल एल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। टी एल एल ऊर्जीकृत कंडक्टर के तापमान को सीमित कर लाइनों की शिथिलता तथा तन्यता ताकत के ह्रास को रोकता है। टी एल एल लाइनों के अधिकतम विद्युत प्रवाह को सीमित करता है। एम टी पी सी के अनुसार 132 के वी लाइन के साथ एल्यूमिनियम कन्डक्टर स्टील रीइन्फोर्स (ए सी एस आर) पैन्थर 210 वर्ग मि मी कन्डक्टर का टी एल एल 366 एम्पीयर (एम पी) था।

कम्पनी के पास मार्च 2012 तक गढ़वाल तथा कुमाऊँ क्षेत्र में 132 के वी के कुल 58 फीडर थे। लाइन लोडिंग की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2012) में पता चला कि काशीपुर, हरिद्वार, पंतनगर तथा रूड़की खण्ड के 26 फीडरों में से दस[25] की नमूना जाँच में पता चला कि ये 380 से 480 एम्पीयर पर भारित थे, जो कि 366 एम्पीयर के निर्धारित मानदण्ड से ऊपर थे। लाइनों का क्षमता से अधिक भारण करने से वोल्टेज में उतार चढ़ाव ऊँची पारेषण हानि तथा लगातार रूकावट/ ब्रेकडाऊन हुए।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किये एवं कहा (दिसम्बर 2012) कि निर्धारित सीमा से विचलन केवल आकस्मिक परिस्थितियों में होता है तथा मानदण्डो को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.2.12.2 बस बार संरक्षण पैनल

एक विद्युत उपकेन्द्र पर अंदर आने व बाहर जाने वाली पारेषण लाइन तथा ट्रान्सफॉर्मर के अन्तर्जुड़ाव का प्रयोग करने के लिए बस बार का उपयोग किया जाता है। बस बार संरक्षण पैनल (बी बी पी पी) बस बार के दोष को सीमित कर पूरे विद्युत तंत्र को अनावश्यक ट्रिपिंग से बचाता है तथा उन्हीं ब्रेकर्स पर चयनात्मक ट्रिपिंग सुनिश्चित करता है जो बस बार पर दोष निवारण के लिए आवश्यक हो। ग्रिड नॉर्म तथा बेस्ट प्रेक्टिस इन ट्रांसमिशन सिस्टम के अनुसार ग्रिड व्यवधान के दौरान प्रणाली स्थिरता बनाए रखने के लिए तथा 220 के वी बस पर तेजी से दोष दूर करने के लिए सभी 220 के वी उपकेन्द्रों में बी बी पी पी को चालू स्थिति में रखा जाता है।

---

[24] 132 के.वी. काशीपुर, 132 के.वी. पंतनगर, 132 के.वी. बाजपुर, 132 के.वी. कोटद्वार, 132 के.वी. ज्वालापुर, 132 के.वी. मंगलौर, 132 के.वी. भगवानपुर तथा 132 के.वी. रूड़की।

[25] 132 के.वी. काशीपुर-1, 132 के.वी. जसपुर, 132 के.वी. बाजपुर, 132 के.वी. कोटद्वार, 132 के.वी. ज्वालापुर, 132 के.वी. रूद्रपुर-पंतनगर, 132 के.वी. किच्छा-रूद्रपुर, 132 के.वी. किच्छा-सितारगंज, 132 के.वी. मंगलौर-रूड़की तथा 132 के.वी. रूड़की-भगवानपुर।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (अगस्त 2012) कम्पनी के सात 220 के वी उपकेन्द्र जहाँ बी बी पी पी स्थापित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि कम्पनी ने सभी सात उपकेन्द्रों में पैनल प्रदान किया था, जिसमें से केवल पाँच चालू स्थिति में थे तथा दो कार्य करने की हालत में नहीं थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किये एवं कहा (दिसम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् सितम्बर 2012 को सभी बी बी पी पी स्थापित कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने 132 के वी उपकेन्द्र काशीपुर तथा रामनगर में स्थापित करने के लिए दो बस कप्लर के वर्ष 2010-11 में ₹ 0.73 करोड़ में खरीदे। उपरोक्त बस कप्लर क्रमशः जून/ जुलाई 2011 में रामनगर तथा काशीपुर उपकेन्द्रों में स्थापित कर दिये गए। स्थापना के एक वर्ष बाद भी उपरोक्त बस कप्लर उपयोग नहीं किये जा सके क्योंकि उन्हें पैनल से नहीं जोड़ा गया तथा बस कप्लर को खरीदने का उद्देश्य विफल रहा।



132 के वी एस एस काशीपुर के बस कप्लर का असंयोजित पैनल

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं कहा (दिसम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् उपरोक्त बस कप्लर सितम्बर 2012 को चालू कर दिये गए थे।

4.2.13 रख रखाव

4.2.13.1 करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर (सी टी) का निष्पादन

करेंट ट्रान्सफॉर्मर (सी टी) विद्युत ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण एवं गहन लागत वाले घटक है, उनके जीवन काल को बढ़ाना तथा रख-रखाव का खर्च कम करना विशेष रूप से आवश्यक है। सी टी के परिचालन स्थिति की विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए सामान्तयः तेल जाँच जैसे की मानक आयल डिजाल्व गैस एनलसिस (डी जी ए) की जाती है। सी टी इनसूलेशन के लिए, इंन्सूलेटेड तरल तथा ठोस इंसूलेशन इंप्रेगनेटेड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इस इन्सुलेटेड प्रणाली की वास्तविक स्थिति का मूल्याँकन के लिए आमतौर पर डी जी ए का उपयोग किया जाता है, सी टी विफलता की स्थिति में तरल इन्सूलेशन का इस प्रकार डिगेडियेशन होता है कि गैसों का योग विफलता का कारण चिन्हित करने में सक्षम हो पाता है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ट्रान्सफॉर्मर विफलता की घटनाओं को नीचे **तालिका 4.2.3** में दर्शाया गया हैः

तालिका 4.2.3

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	विफल ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	गारंटी अवधि के दौरान विफल ट्रान्सफॉर्मर की संख्या	साधारण[26] कार्यदायी जीवन में विफल ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या	रख रखाव एवं मरम्मत पर व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	1645	02	शून्य	02	0.16
2008-09	1648	09	शून्य	09	0.99
2009-10	1648	13	शून्य	13	0.41
2010-11	1679	14	शून्य	14	0.17
2011-12	1690	30	शून्य	30	0.17

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने तंत्र में 45 सी टी जोड़े हैं। विफल ट्रान्सफॉर्मरों की संख्या भी वर्ष 2007-08 मे दो से वर्ष 2011-12 में बढ़कर 30 हो गई। सी टी की विफलता का मुख्य कारण उपकेन्द्रों का अतिभारण (ओवरलोडिंग) था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी सी टी के रखरखाव एवं मरम्मत के खर्चों को कम करने में सफल रही थी।

4.2.13.2 हॉट लाइन खण्ड का कार्य

पारेषण प्रणाली का नियमित एवं आवधिक रखरखाव इसके निर्बाध संचालन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश में पारेषण की सर्वोत्तम प्रथाओं को अद्यतन करने वाली कमेटी की रिपोर्ट में न केवल लाइनों की नियत गश्त बल्कि लाइनो के रखरखाव के विभिन्न तकनीकों को भी बताया है, जिसमें हाट लाइन रखरखाव, हाट लाइन धुलाई, इंसूलेटर की पंचर खोज, पोर्टेबल अर्थिंग हाट लाइन उपकरण, लाइन का कंपन माप थर्मो स्कैनिंग तथा उपकरणों का प्रदूषण माप सम्मिलित है।

हॉट लाइन तकनीकी (एच एल टी) में उपकेन्द्र तथा लाइन के रख रखाव के कार्य जैसे कि हॉट स्पॉट नटो तथा बोल्ट को क्रमशः कंडक्टर को नुकसान की जाँच इंसूलेटर का बदला जाना इत्यादि बिना लाइन बंद किये, करने की परिकल्पना की गई है। इसमें निवारक अनुरक्षण के तौर पर सभी उपकेन्द्रों तथा लाइनों की थर्मो स्कैनिग शामिल है। एच एल टी को भारत में 1958 में पेश किया गया था। कम्पनी के पास अप्रैल 2007 को कोई हॉटलाइन खण्ड उपकेन्द्र नहीं था तथा यही स्थिति दिसम्बर 2012 तक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (अप्रैल 2012) हॉट लाइन खण्ड तथा थर्मो विजन कैमरे के अभाव में कम्पनी चोटियों पर, नदी में तथा घने जंगलों में स्थित टावरों को स्कैन करने की स्थिति में नहीं थी। आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त के संदर्भ में कोई लिखित मैन्यूअल/ दिशानिर्देश नहीं तैयार किये गये थे। हॉट लाइन खण्ड के अभाव में कम्पनी के पास निवारक अनुरक्षण तथा जोखिम भरे क्षेत्र का अग्रिम में पहचान करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

[26] ट्रान्सफॉर्मर का साधारण जीवन 25 वर्ष है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि हॉट लाइन का निर्माण तथा रखरखाव अत्यन्त खर्चीला है, कम्पनी इसके विषय में निकट भविष्य में विचार करेगी।

4.2.13.3 पारेषण हानियाँ

जनरेटिंग स्टेशन से जब ऊर्जा का पारेषण एक वितरण तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है, उसमें कुछ ऊर्जा की हानि होती है जिसे टी एण्ड डी हानि कहते है। पारेषण हानि जनरेटिंग स्टेशन/ ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा तथा वितरण कम्पनी को भेजी गई ऊर्जा के बीच का अंतर है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) के अनुसार पारेषण हानि की अनुमन्य सीमा क्रमशः दो एवं पाँच *प्रतिशत* थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समीक्षा अवधि के दौरान पारेषण हानि सीमा में थी तथा 1.35 *प्रतिशत* से 1.88 *प्रतिशत* **(परिशिष्ट 4.9)** के बीच थी एवं उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) द्वारा निर्धारित दो एवं पाँच *प्रतिशत* की स्वीकार्य सीमा के अन्तर्गत थी।

पिछले पाँच वर्षों में कम्पनी की पारेषण हानि सी ई ए एवं यू ई आर सी द्वारा निर्धारित मानदण्ड़ों के भीतर रहे जो कि प्रशंसनीय था।

4.2.14 ग्रिड प्रबंधन

4.2.14.1 ग्रिड का रखरखाव और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की समीक्षा

पारेषण और ग्रिड प्रबन्धन उत्पादन स्टेशनों से वितरण कम्पनियों/ उपभोक्ताओं तक बिजली पहुचाने का एक आवश्यक कार्य है। ग्रिड प्रबन्धन पलपल- परस्पर बिजली व्यवस्था में ऊर्जा सतुलन के लिए विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता और विद्युत प्रणाली की दक्षता सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबन्धन का कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) के द्वारा जारी किए गये ग्रिड के मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। नेशनल ग्रिड में पाँच आँचल, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी ग्रिड समाहित है, इसमें से प्रत्येक का एक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र आर एल डी सी है जो उस क्षेत्र में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष संस्था है।

उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) जो उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र नई दिल्ली को एक घटक है। राज्य में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन सुनिश्चित करता है। दो क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र जो डाटा अधिग्रहण और एस एल डी सी को हस्तान्तरण में सहायता तथा 132 के वी और 33 के वी उपकरणों के पर्यवेक्षी नियन्त्रण में सहायता करते हैं। एस एल डी सी, उत्पादन कम्पनियों और राज्य के भीतर बिजली के संचरण में लगे हुए अनुज्ञप्ति धारियों पर फीस लगाता और सग्रहण करता है जैसा कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्देशित किया गया है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य का एस एल डी सी स्वतन्त्र रूप से संचालित नहीं हो रहा था बल्कि पारेषण उपयोगिता का संघटक था। यू ई आर सी के निर्देशों के बावजूद कम्पनी ने एस एल डी सी के कार्य को पृथक नहीं किया और एस एल डी सी के लेखों को अभी तक पृथक नहीं किया गया है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि एस एल डी सी के लेखों को पृथक करना सरकार का विशेषाधिकार था पूर्व में चल रहे अभ्यास के अनुसार शुरू में खातों को अलग से तैयार किया गया था परन्तु बाद में उनको कम्पनी के लेखो के साथ विलय कर दिया गया। यद्यपि यह तथ्य है कि यू ई आर सी के निर्देशानुसार एस एल डी सी के लेखों को अलग से तैयार किया जाना चाहिये था, परन्तु अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)।

4.2.14.2 भार निगरानी के लिए आधारभूत संरचना

ग्रिड मानदण्डों के अनुसार सभी उपकेन्द्रों के लिए भार पारेषण केन्द्रों में आपातकाल के दौरान पारेषण प्रणाली एवं भार के दक्षता की निगरानी के लिए दूरस्थ टर्मिनल इकाईयाँ/ सब स्टेशन प्रबंधन प्रणतियाँ (आर टी यूज/ एस एम एसज) आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2012) कि कुल सात 220 के वी उपकेन्द्रों तथा, 132 के वी के 26 उपकेन्द्रों एवं 13 जनरेटर में से कुल सात जनरेटर[27] (53.85 *प्रतिशत*) और तीन उपकेन्द्रों[28] (9.09 *प्रतिशत*) के पास आर टी यूज थे जो कुशल ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली के लिये वास्तविक समय डेटा रिकार्डिंग करते थे। आगे राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) उपरोक्त व्यवस्था के साथ एकीकृत नहीं किया गया था और एस एल डी सी के पास डाटा स्टोर अथवा बैकअप की सुविधा नहीं थी। अतः इसने स्वयं को ग्रिड मानक के अनुसार पारेषण की दक्षता के लिए बने अनुश्रवण केन्द्र की बजाय एक प्रेक्षण केन्द्र तक सीमित रखा।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति के पश्चात (लगभग 80 *प्रतिशत*) उपकेन्द्रों में आर टी यूस स्थापित कर दिये है और बाकी में निकट भविष्य में स्थापित कर दिये जायेगें।

4.2.14.3 आवृत्ति प्रबन्धन द्वारा ग्रिड अनुशासन

ग्रिड कोड के अनुसार ग्रिड के कुशल संचालन के लिए पारेषण उपयोगिताओं को ग्रिड अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। ग्रिड के सभी घटक सदस्यों को अप्रैल 2006 से मार्च 2009 के दौरान प्रणाली आवृति को 49 और 50.5 हर्टज के बीच, अप्रैल 2009 से अप्रैल 2010 के बीच 49.2 और 50.3 हटर्ज और मई 2010 से 49.5 और 50.2 हटर्ज, बनाये रखना था, जिसके बहुत से कारण जैसे, उत्पादन क्षमता में कमी, अधिक माँग, लोड उत्पादन बैलेंश के रखरखाव में ग्रिड की अनुशासनहीनता, अपर्याप्त लोड निगरानी और प्रबंधन और ग्रिड आवृति का एक तय सीमा से आवृति ऊपर एवं नीचे होना था। ग्रिड अनुशासन को लागू करने के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) तीन प्रकार के उल्लघंन सन्देशों (अ ब स) को जारी करता है। सन्देश अ तब जारी किया जाता है जब आवृत्ति 49.2 हटर्ज से कम और ओवर ड्रावल 50 मेगावाट (एम डब्लू) से अधिक है अथवा अनुसूची का 10 *प्रतिशत*, जो भी कम है। उल्लंघन बी सन्देश तब जारी किया जाता है जब आवृत्ति 49.2 हर्टज से कम और ओवरड्रावल दस मिनट से अधिक 50 और 200 मेगावाटस के बीच में रहता है या 200 मेगावाट से अधिक तथा पाँच मिनट से अधिक समय तक हो संदेश स (गम्भीर प्रकृति) सन्देश ब

---

[27] छिब्बरों, खोदरी, चीला तथा एम.बी. -1, 220 के.वी.एस.एस से जुड़ा हुआ है तथा धालीपुर, ढकरानी एवं कुलहाल 132 के.वी. एस.एस से जुड़ा हुआ है।

[28] 220 के.वी. एस.एस.: ऋषिकेश एवं चम्बा तथा 132 के.वी. एस.एस. माजरा, देहरादून।

के जारी करने के 15 मिनट बाद जारी किया जाता है जब आवृत्ति लगातार 49.2 हर्टज से नीचे और ओवरड्रावल 100 मेगावाट या दस *प्रतिशत* अनुसूची जो भी कम हो होता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल 2012) कि अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय एस एल डी सी ऋषिकेश ने जारी किये गये सन्देशों के रिकार्ड का रखरखाव नहीं किया था इस सम्बन्ध में एस एल डी सी ने कहा (मई 2012) कि उत्तराखण्ड में केवल एक पारेषण उपयोगिता और एक वितरण कम्पनी कार्य करती है, इसलिए ग्रिड़ अनुशासन बनाये रखने के लिए एस एल डी सी प्राथमिक ग्रिड उपकेन्द्र (कम्पनी के प्रतिनिधि) को निर्देश जारी करती है और कम्पनी के प्रतिनिधि माध्यमिक उपकेन्द्रों (वितरण के प्रतिनिधि) को भार कम करने के लिए प्रेषित कर देते हैं।

अ, ब और स सन्देश प्रणाली को रिकॉर्ड न करने के कारण, सन्देश उनकी अत्यावश्यकता का प्रभावी ढ़ंग से प्रसारण नहीं किया जा सका था। जो ग्रिड की स्थिरता के लिए एक खतरा और निर्धारित ग्रिड कोड का उल्लघंन था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद ए बी और सी सन्देशों को रिकॉर्ड करने का सार्थक प्रयास शुरू किया जा रहा है।

4.2.14.4 ग्रिड अनुशासन

ग्रिड अनुशासन बनाये रखने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) ग्रिड की कम आवृत्ति में ओवरड्रावल जिससे ग्रिड को क्षति पहुँचे, का याचिका स्वतः स्फूर्त संज्ञान में लेता है। लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2012) कि कम्पनी ने ग्रिड अनुशासन का नौ बार उल्लघंन किया (अप्रैल 2010), परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ नौ लाख का जुर्माना देना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन का मुख्य कारण माँग और अनुसूची में अन्तर रहा है जो वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) द्वारा निर्धारित होता है। अप्रैल 2010 के बाद से कम्पनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था और ग्रिड आवृत्ति का रखरखाव मानकों के अनुसार किया जा रहा था। तथापि, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ग्रिड अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी कम्पनी की थी।

4.2.14.5 बैकिंग डाऊन निर्देश (बी डी आई)

जब आवृत्ति एक आदर्श सीमा से अधिक होती है अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें विद्युत उत्पादन अधिक तथा निकासी कम (आवृत्ति 50 हर्टज से अधिक), उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) सुरक्षित एकीकृत ग्रिड संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में ऊर्जा व्यवस्था के संचालन को मित्तव्ययी और दक्षता को बनाये रखने के लिए जनरेटरों को उत्पादन कम करने के लिए बैकिंग डाऊन निर्देश जारी करता है। जनरेटरों द्वारा एस एल डी सी के निर्देशों को न मानने पर इसे ग्रिड कोड का उल्लंघन माना जायेगा और वे दण्ड के अधिकारी होगें। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने 8.78 एम यू पर 23 अवसरों पर बी डी आई जारी किया जिनका जनरेटरों द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि में पूर्ण पालन किया गया। यह प्रशंसा योग्य था कि जनरेटरों द्वारा बी डी आई निर्देशों का शत *प्रतिशत* अनुपालन किया गया।

4.2.14.6 ऊर्जा खरीद की योजना

कम्पनी, अनुबन्धित उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर केन्द्रीय क्षेत्र और भविष्य के प्रतिबद्ध परियोजनाओं तथा राज्य की वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता के मूल्याँकन पर परामर्श कर, ऊर्जा आपूर्ति की एक लम्बी योजना बनाती है। यह दिन प्रतिदिन के ऊर्जा की आवश्यकता का निर्धारण कर एक दिन पहले उसकी योजना बनाती है। राज्य की कुल आवश्यकता, कुल ऊर्जा आपूर्ति और ऊर्जा की कमी के पाँच वर्ष 2007-08 से 2011-12 का विवरण नीचे **तालिका 4.2.4** में दिया गया है:

तालिका 4.2.4 *(मिलयन यूनिट में)*

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	कुल ऊर्जा की आवश्यकता	7052.18	7848.19	8936.15	9853.88	10577.93
2	कुल ऊर्जा की आपूर्ति[29]	6847.61	7769.73	8355.74	9293.81	10277.98
3	ऊर्जा की कम आपूर्ति	204.57	78.46	580.41	560.07	299.95
4	ऊर्जा की कमी *प्रतिशत* में	2.90	0.99	6.50	5.68	2.83

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से सूचना)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा कमी का *प्रतिशत* घटने की प्रवृति में है अर्थात् 2009-10 में 6.50 से 2011-12 में 2.83 *प्रतिशत*।

माँग-आपूर्ति में अन्तर भी वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच का यू आई शुल्क के तहत एस एल डी सी के प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाक के आधार पर निकाला जाता है। यू आई शुल्क पूर्व प्रतिबद्ध दैनिक कार्यक्रम, से ऊर्जा की आपूर्ति एवं खपत में विभिन्नता के आधार पर लगाया जाता है। यह शुल्क प्रणाली आवृत्ति के समय आपूर्ति/ खपत के समय से भिन्न होता है। अतः यह आपूर्ति के समय ऊर्जा के मामूली कीमत को दर्शाता है। यू आई शुल्क लगाना कम आवृत्ति की स्थिति के दौरान केन्द्रीय जनेरटिंग स्टेशन से अधिक आहरण पर अंकुश लगाने के लिए एक वाणिज्यिक निवारक के रूप में काम करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2012) कि राज्य की वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 2502.15 मिलियन यूनिट (एम यू) यू आई ओवर ड्राल की जिसकी लागत ₹ 1126.27 करोड़ थी तथा प्रति इकाई लागत ₹ 3.72 से ₹ 5.66 के बीच थी। ऊर्जा कमी का *प्रतिशत* घटते क्रम में था क्योंकि वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) माँग की आवश्यकतानुसार ऊर्जा की ओवर ड्राल करती थी परिणामस्वरूप महँगी ऊर्जा का भार उपभोक्ता को वहन करना पड़ा था।

4.2.15 आपदा प्रबंधन

4.2.15.1 आपदा प्रबंधन का उद्देश्य प्रणाली में बड़े बैक्र डाउन के प्रभाव को कम करना तथा कम से कम सम्भव समय में उसे बहाल करना होता है। सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, सभी ऊर्जा कम्पनियों को स्थापित करना चाहिए ताकि बड़े विफलता के समय पारेषण प्रणाली को तत्काल बहाल किया जा सके। आपात कालीन

[29] उत्पादन सहित, लघु और दीर्घावधि की खरीद तथा आहरण केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से।

बहाली प्रणाली, डीजल जनरेटर सेट, वाहन, अग्नि शमन उपकरणों, कुशल और विशेष जनशक्ति का उपयोग कर इसका कार्यान्वयन किया जाता है।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, नई दिल्ली आपदा के मामले में एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। कम्पनी द्वारा वर्ष में एक बार डी एम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ब्लैक स्टार्ट[30] परिचालन के दौरान उत्पादन केन्द्र को चालू करने के लिए मॉक ड्रिल का सम्पादन किया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी ने किसी भी सब स्टेशन पर 2007-08 से 2011-12 के दौरान कोई मॉक ड्रिल नहीं किया था।

4.2.15.2 आपदा प्रबन्धन की अपर्याप्त सुविधायें

अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) वाले उपकेन्द्रों पर डीजल जनरेटिंग (डी जी) सेट्स एवं सिन्क्रोस्कोप्स[31] जो आपदा प्रबन्धन (डी एम) की सुविधा के एक भाग के रूप में होते हैं तथा मुख्य जनरेटिंग केन्द्रों को जोड़ते हैं कि उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2012) कि 400 के वी, 220 के वी और 132 के वी के कुल 35 उप केन्द्रों पर डी जी सेट एवं सिन्क्रोस्कोप्स उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त बारिश और बाढ़ में इक्टा हुए पानी की निकासी के लिए पम्प सैट भी आवश्यक है। डी जी और पम्प सैट की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा ने निम्न दृष्टान्त देखे।

- भारी वर्षा के परिणामस्वरूप बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाने के कारण 132 के वी उपकेन्द्र भूपतवाला हरिद्वार द्वारा आच्छादित क्षेत्र पूर्णतया अन्धकार में डूबा हुआ था क्योंकि सभी पैनल 19 सितम्बर 2010 से 22 सितम्बर 2010 तक बुरी तरह प्रभावित थे, जैसा कि नीचे दिखाये गये फोटोग्राफ से स्पष्ट है।



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान स्विच यार्ड की फाईल फोटो



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो

[30] वह प्रक्रिया जो आंशिक या पूर्ण अंधेरे से बाहर निकलने के लिए आवश्यक हो।

[31] एक ए सी विद्युत प्रणाली यह वह युक्ति है जो एक डिग्री को प्रदर्शित करती है जिसमें दो पद्धति जनरेटर या ऊर्जा तन्त्र एक दूसरे से जुड़ते हैं।

- इसी प्रकार, 17 अगस्त 2011 को भारी वर्षा के कारण 132 के वी उपकेन्द्र काशीपुर में पानी भर गया और पूर्ण व्यवस्था को बन्द करना पड़ा जो 24 से 36 घन्टे बाद शुरू हो पायी क्योंकि सभी पैनल बाढ़ के पानी द्वारा बुरी तरह प्रभावित थे। पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति इस अवधि में बुरी तरह प्रभावित हुई।



132 के वी एस एस काशीपुर के फीडर की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो



132 के वी एस एस काशीपुर की बाढ़ के दौरान बिल्डिंग की फाईल फोटो

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (जून 2012) और कहा कि उपकेन्द्रों पर डी जी सेट की आवश्यकता थी क्योंकि ब्रेक डाऊन प्राकृतिक आपदा और ब्लैक आउट के समय ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 132 के वी सब स्टेशन लक्सर भी 16.08.2011 को बाढ़ और भारी वर्षा के कारण प्रभावित था और पूरी व्यवस्था बन्द करनी पड़ी थी तथा 12 घन्टे बाद ही बहाली हो पाई क्योंकि उपकेन्द्र में तीन फीट और नियन्त्रण कक्ष में एक फीट पानी इकट्ठा हो गया था तथा सभी पैनल प्रभावित हुए थें। इस अवधि के दौरान पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई जैसा कि नीचे दिखाये गये फोटोग्राफ से स्पष्ट है:



132 के वी एस एस लक्सर की बाढ़ के दौरान स्विच यार्ड की फाईल फोटो



132 के वी एस एस लक्सर के कन्ट्रोल रूम की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो

यदि कम्पनी डी जी/ पम्पसैट पहले से ही स्थापित रखती तो विद्युत आपूर्ति में लम्बी बाधा की स्थिति से बचा जा सकता था। उपर्युक्त घटना के बावजूद कम्पनी ने डी जी सेट/ पम्प सेट खरीदकर उपकेन्द्रों पर अब तक स्थापित नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने मेटल डिटेक्टर की स्थापना/ प्रावधान तथा आतंकी घटना, तोड़ फोड़ तथा बम की आशंका जैसी कठिन स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए सुरक्षा बल को स्थल की सुरक्षा सौंपने के लिए, असुरक्षित उपकेन्द्रों की पहचान नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कम्पनी किसी भी आपदा का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी। कम्पनी के पास आपदा से उबरने अथवा कार्य की निस्तरता बनाये रखने की कोई अभिलेखीय योजना नहीं की जिसका अनुसरण आपातकाल के दौरान किया जा सके।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि डी जी सभी नये उपकेन्द्रों पर स्थापित किये गये हैं और अगले वित्त वर्ष में महत्वपूर्ण उपकेन्द्रों पर स्थापित करने की योजना है। तथापि, आपदा से उबरने तथा कार्य की निस्तरता बनाये रखने की अभिलेखीय योजना के अभाव के सम्बन्ध में कम्पनी के पास कोई जवाब नही था।

4.2.16 ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा

पारेषण हानि का निर्धारण तथा उसे कम करने के लिए ऊर्जा का लेखाकंन एवं लेखापरीक्षा आवश्यक है। पारेषण हानि की गणना मीटर रीडिंग यंत्र (एम आर आई) द्वारा की जाती है। उत्पादन से पारेषण (जी टी) और पारेषण से वितरण (टी डी) सीमा मीटरिंग बिन्दु से रीडिंग प्राप्त की जाती है। 31 मार्च 2012 को 85 अन्तर सीमा मीटरिंग बिन्दु, टी डी (68) और जी टी (17) थे। सभी पी टी और जी टी बिन्दुओं को 0.5 एक्यूरेसी क्लास के मीटर उपलब्ध कराये गये थे।

21 फीडरो के साथ पाँच खण्डों[32] के प्रत्येक वर्ष (2007-08 से 2011-12) के तीन महीनों, मार्च से मई तक की अवधि के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान आँकड़ों के विश्लेषण से निर्दिष्ट हुआ कि फीडरों की पारेषण की हानियाँ, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई ए) द्वारा निर्धारित मानकों के अन्दर थी।

4.2.17 वित्तीय प्रबन्धन

4.2.17.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एवं वाणिज्यिक सक्षमता को सुनिश्चित करना था। वर्ष 2011-12 को समाप्त पाँच वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई तालिका **4.2.5** में दिखाया गया है।

[32] 400 के.वी. ओ एण्ड एम काशीपुर, 132 के वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 220 के वी ओ एण्ड एम पंतनगर, 220 के वी ओ एण्ड एम देहरादून तथा 220 के वी ओ एण्ड एम रुड़की।

तालिका 4.2.5 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12[33]
अ. देयता					
प्रदत्त पूँजी	102.58	122.28	172.09	187.09	227.41
आरक्षित एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान सहित)	(-) 0.65	(-) 21.02	(-) 48.03	(-) 57.58	(-) 37.36
उधार (ऋण निधियाँ)	617.37	607.68	644.48	692.00	710.19
चालू देयता एवं प्रावधान (सी एल)	139.16	168.27	164.91	203.04	186.28
कुल	**858.46**	**877.21**	**933.45**	**1024.68**	**1086.52**
ब. सम्पत्तियाँ					
सकल ब्लॉक	524.78	557.76	612.81	690.94	793.74
घटाओं : ह्रास	197.46	231.73	254.09	273.66	295.48
पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सी डब्लू आई पी)	321.56	373.97	263.17	299.83	267.01
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (सी एल)	209.58	177.22	311.55	307.56	321.25
कुल	**858.46**	**877.21**	**933.45**	**1024.68**	**1086.52**
टैक्स के बाद का लाभ/हानि, लाभ/ हानि खाते के अनुसार	(-) 13.98	(-) 19.05	(-) 26.97	(-) 9.50	(-) 2.07
ऋण-समता अनुपात	6.02:1	4.97:1	3.74:1	3.70:1	3.12:1
ब्याज (कुल निर्माण के दौरान का ब्याज जो पूँजीकृत हुआ[34])	16.08	22.25	27.83	30.57	36.87
कुल प्रतिफल	80.72	87.22	78.68	102.83	135.25
नियोजित पूँजी[35]	651.96	637.47	578.62	599.59	643.51
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय *प्रतिशत* में	12.38	13.68	13.59	17.15	21.02

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी की हानि में 85.19 *प्रतिशत* की कमी आयी जो वर्ष 2007-08 में ₹ 13.98 करोड़ से वर्ष 2011-12 ₹ 2.07 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त कम्पनी का ऋण-समता अनुपात 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6.02:1 से घटकर 3.12:1 हो गया। ऋण-समता अनुपात में कमी का मुख्य कारण सरकारी ऋण का वर्ष 2009-10 के बाद से इक्विटी में बदलना है।

पूँजी पर प्रतिफल का *प्रतिशत* वर्ष 2007-08 में 12.38 *प्रतिशत* से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 21.02 *प्रतिशत* हो गया जो कि पूँजी कार्य प्रगति में कमी के कारण वर्ष 2007-08 में ₹ 321.56 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 267.01 करोड़ और कार्यशील पूँजी जो सकल चालू सम्पत्ति का ₹ 3.08 करोड़ वर्ष 2007-08 से सकल चालू दायित्व जो वर्ष 2011-12 में ₹ 121.82 करोड़ की कमी के कारण हुआ।

यह भी देखा गया कि कम्पनी की उधार की रकम जो वर्ष 2007-08 में ₹ 617.37 करोड़ थी, 2011-12 में बढ़कर ₹ 710.19 करोड़ हो गयी।

[33] 2011- 12 के सम्बन्ध में विवरण अनंतिम है।

[34] निर्माण के दौरान ब्याज।

[35] नियोजित पूँजी = नेट स्थायी सम्पत्ति (डब्लू. आई.पी सहित) + ऋण और अग्रिम छोड़कर कार्यशील पूँजी सहित।

4.2.17.2 कार्य परिणाम का विवरण जैसे राजस्व वसूली शुद्ध अधिशेष/हानि तथा आय एवं प्रति इकाई पारेषण की लागत वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि नीचे दी गयी **तालिका 4.2.6** में दर्शायी गयी है:

तालिका 4.2.6 *(₹ करोड़ में)*

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12[36]
1	आय					
	राजस्व	78.02	86.71	75.81	101.74	132.93
	अन्य आय ब्याज/अनुदान सम्मलित	2.70	0.51	2.87	1.09	2.32
	कुल आय	**80.72**	**87.22**	**78.68**	**102.83**	**135.25**
2	पारेषण					
(अ)	स्थापित क्षमता (एम वी ए)	4550.50	4550.50	4590.50	4630.50	4990.50
(ब)	उत्पादन इकाईयों से प्राप्त ऊर्जा (मी यूज में)[37]	7400.60	10033.37	11449.90	11449.90	12298.99
	कुल	**7400.60**	**10033.37**	**11449.90**	**11449.90**	**12298.99**
(स)	पारेषण में हानि (एम यूज में)	100.23	186.84	194.78	214.75	229.15
	कुल ऊर्जा प्रेषित (अ)+(ब)-(स)-एम यूज में	**7300.37**	**9846.53**	**11255.12**	**11235.15**	**12069.84**
3	व्यय					
(अ)	स्थायी लागत					
(i)	कार्मिक लागत	30.12	31.09	33.97	37.69	45.94
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	10.07	8.76	9.24	12.76	14.66
(iii)	ह्रमस	30.62	34.27	22.36	19.57	21.82
(iv)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार (पूँजीकृत के बाद निबल)	16.08	22.25	27.83	30.57	36.87
	कुल स्थायी लागत	**86.89**	**96.37**	**93.40**	**100.59**	**119.29**
(ब)	परिवर्तनशील लागत-मरम्मत एवं रखरखाव	7.81	9.91	12.25	11.75	18.03
(स)	कुल लागत 3 (अ) + (ब)	94.70	106.28	105.65	112.34	137.32
4	वसूली (₹ प्रति इकाई)	0.11	0.09	0.07	0.09	0.11
5	स्थायी लागत (₹ प्रति इकाई)	0.12	0.10	0.08	0.09	0.10
6	परिवर्तनशील लागत (₹ प्रति इकाई)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
7	कुल लागत (₹ प्रति इकाई) (5 + 6)	0.13	0.11	0.09	0.10	0.11
8	अंशदान (₹ प्रति इकाई) (4-6)	0.10	0.08	0.06	0.08	0.10
9	लाभ(+)/ हानि(-) (4-7) (₹ प्रति इकाई)	**-0.02**	**-0.02**	**-0.02**	**-0.01**	**-**

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आकड़ों से संकलित सूचना)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रति इकाई वसूली अस्थिर रही है और प्रति इकाई लागत में वर्ष 2007-08 से 2011-12 में ₹ 0.13 से ₹ 0.11 (15.38 *प्रतिशत*) की कमी हुई। इसके अतिरिक्त कुल वसूली वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में बढ़कर ₹ 54.53 करोड़ हो गयी तथा 2007-12 की अवधि के दौरान प्रति इकाई अंशदान भी ₹ 0.06 से ₹ 0.10 के बीच अस्थिर रहा।

[36] 2011-12 के सम्बन्ध में विवरण अनंतिम है।

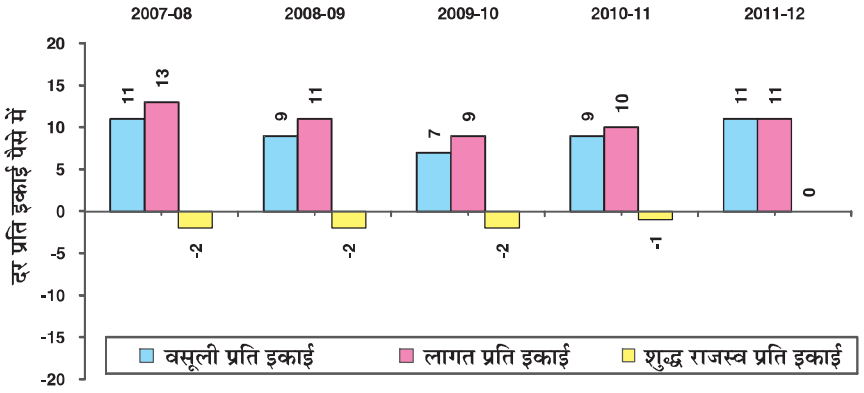
[37] निजी उत्पादन सहित।

घटक/ तत्व थे जो वर्ष में कुल लागत का क्रमशः 33.45, 26.85 और 15.89 *प्रतिशत* प्रतिनिधित्व करते थे।

4.2.17.3 संचालन लागत एवं वसूली

कम में हानि कम करने तथा ग्रिड में दक्षता बढ़ाने के लिए पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज में परिवर्तित की जाती है। उपकेन्द्रों में प्राप्त वोल्टेज विद्युत प्रणाली में वोल्टेज को एक स्तर तक इससे स्तर बढ़ाने/ घटाने प्रणाली में अधिक प्रणाली के बाहर की विद्युत प्रणाली

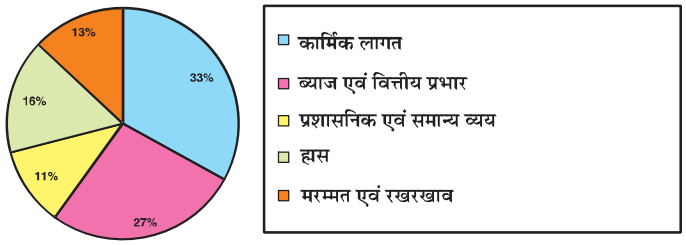
वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी ने स्थायी आधार पर राज्य के वितरण (यू पी पी सी एल) ईकाई से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा तय टैरिफ प्राप्त किया था। तथापि, 2011-12 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रति यूनिट लागत और शुद्ध राजस्व वसूली की स्थिति नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शाया जा सकता है:



उपरोक्त से यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा अर्जित कुल राजस्व कुल लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। कम्पनी पारेषण क्षमता में वृद्धि, नये उपकेन्द्रों एवं पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए पूर्णतया ऋण पर निर्भर थी। हानियों का मुख्य कारण बढ़ते कर्मचारियों की लागत, ब्याज एवं वित्तीय प्रभार है जिसे वर्ष 2007-12 के दौरान कम्पनी को वहन करना पड़ा था।

4.2.17.4 लागत के तत्व

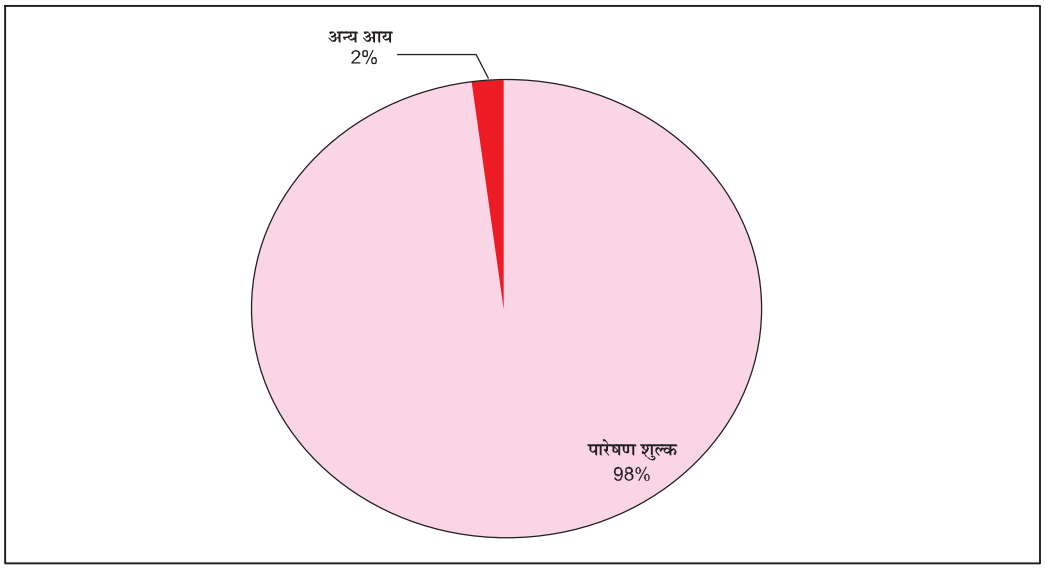
2011 -12 में लागत के मुख्य तत्वों का अलग-अलग *प्रतिशत* नीचे पाई चार्ट में दिया गया है:



वर्ष 2011-12 के दौरान, कर्मचारी लागत (33 *प्रतिशत*), ब्याज एवं वित्त प्रभार (27 *प्रतिशत*) और ह्रास (16 *प्रतिशत*) कम्पनी के लागत एवं कुल व्यय के मुख्य धारक थे। यह विचारणीय है कि उपर्युक्त तीनों धारक (76 *प्रतिशत*) स्थायी लागत के भाग हैं, कम्पनी के लिए निकट भविष्य में इन धारकों पर व्यय कम करना कठिन हो सकता हैं।

4.2.17.5 राजस्व के तत्व

पारेषण शुल्क राजस्व का एक प्रमुख तत्व है। वर्ष 2011-12 के लिए राजस्व का अलग-अलग (ब्रेक अप) *प्रतिशत* नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।



उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कम्पनी का पारेषण शुल्क कुल राजस्व का 98 *प्रतिशत* था।

4.2.17.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) शुल्क का संग्रहण

राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) शुल्क 2010-11 से शुरू हुआ था और कम्पनी ने यह शुल्क ₹ 0.03 करोड़ की राशि एक प्राइवेट जनरेटर[38]/ओपन एक्सेस पर मार्च 2012 तक आरोपित किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2012) कि राज्य की एस एल डी सी अपने लेखों का अलग से रखरखाव नहीं कर रही थी और वह कम्पनी के एक भाग की तरह कार्य कर रही थी। परिणामस्वरूप एस एल डी सी ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) के समक्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) अलग से प्रस्तुत नहीं की इसलिए इसने राज्य के वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से मार्च 2012 तक एस एल डी सी शुल्क के रूप में कोई वसूली नहीं की।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और व्यक्त किया कि राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इस मामले में अतिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

[38] मेसर्स बी.एच.पी.एल.।

4.2.17.7 वितरण कम्पनी (उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) से अधिभार का संग्रह

कम्पनी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) पर टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट आवटित क्षमता दरों पर मासिक पारेषण बिल प्रस्तुत करती है। बिलों का भुगतान बिल जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर किया जाना है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (मई 2012) कि यू पी सी एल द्वारा न तो कोई साखपत्र (एल सी) अभी तक खोला गया था और न ही समझौते में दण्ड का प्रावधान ही सम्मिलित किया गया था। साख पत्र के अभाव में यू पी सी एल द्वारा शुल्क के भुगतान में 15 से 45 दिन तक विलम्ब किया गया था। परिणामस्वरूप, पारेषण बिलों में ब्याज का नुकसान हुआ। कम्पनी द्वारा कोई दण्डात्मक शुल्क नहीं लगाया जा सका क्योंकि यू पी सी एल के साथ किये गये समझौते में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकारा और कहा (दिसम्बर 2012) कि वितरण कम्पनी के साथ साख पत्र यथा समय खोला जायेगा।

4.2.18 टैरिफ निर्धारण

एक कम्पनी की वित्तीय व्यवहार्यता इस पर निर्भर करती है कि वह बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हुए अपने संचालन से इतना आधिक्य उत्पादित करे (निष्पक्ष रिटर्न सहित) कि उसकी परिचालन आवश्यकता तथा भविष्य में पूँजी विस्तार कार्यक्रम का वित्त पोषण हो सके। राजस्व सग्रह कम्पनी के कोष को बढ़ाने का मुख्य स्रोत है। टैरिफ से सम्बन्धि बिन्दुओं (मुद्दों) की चर्चा निम्न हैः

कम्पनी की टैरिफ सरंचना उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा अनुमोदन के अधीन था। यह आगे इस बात के अधीन है कि कम्पनी अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) निर्दिष्ट तिथि को प्रस्तुत करे और उस पर कोई आपत्ति आरोपित न हो। कम्पनी से यह अपेक्षित था कि वह अपना प्रत्येक वर्ष का ए आर आर; पिछले वर्ष के 30 नवम्बर तक प्रस्तुत कर दें। यू ई आर सी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की, ऐसे संशोधनो/शर्तों के साथ जो युक्तिसंगत हो सकते हो तथा सार्वजनिक तथा दूसरे हितधारियों के सभी सुझाव तथा आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त, स्वीकार करता है। ए आर आर प्रस्तुत करने की नियत तिथि, वास्तविक तिथि, टैरिफ याचिका की अनुमोदन तिथि और पुनरीक्षित, टैरिफ की प्रभावी तिथि नीचे **तालिका 4.2.7** में दिया गया है:

तालिका 4.2.7

वर्ष	प्रस्तुतीकरण की देय तिथि	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	विलम्ब दिनों में	अनुमोदन की तिथि	प्रभावी तिथि
2007-08	30-11-2006	02-03-2007	89	18-03-2008	01-04-2007
2008-09	30-11-2007	स्वयं ही कार्यवाही शुरू कर दी	-	18-03-2008	01-04-2008
2009-10	30-11-2008	31-12-2008	31	21-10-2009	01-04-2009
2010-11	30-11-2009	30-11-2009	-	06-04-2010	01-04-2010
2011-12	30-11-2010	29-11-2010	-	10-05-2011	01-04-2011

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से सूचना संकलित)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि कम्पनी वर्ष 2008-09 में ए आर आर प्रस्तुत नहीं कर सकी और वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 की याचिका विलम्ब से प्रस्तुत की गयी थी। कम्पनी द्वारा 2008-09 की ए आर

आर याचिका समय पर प्रस्तुत न करने के कारण यू ई आर सी ने ट्रैरिफ स्वयं ही संशोधित कर दिया। 2004 के विनियमन 56 (4) के अनुसार और पारेषण गतिविधि के लिए टैरिफ निर्धारण की सेवा एवं शर्तों के अनुसार कम्पनी यू ई आर सी को अपनी राजस्व आवश्यकता जो उसके पारेषण व्यवसाय की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक है, ए आर आर प्रस्तुत करनी है। जिसकी वसूली की अनुमति यू ई आर सी टैरिफ और शुल्क के माध्यम से देता है जो कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत होता है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ए आर आर प्रस्ताव और आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव नीचे की **तालिका 4.2.8** में दिया गया हैः

तालिका 4.2.8

पारेषण टैरिफ						
वर्ष	कम्पनी			यू ई आर सी		
	पारेषण की कुल क्षमता (एम डब्लू)	राजस्व आवश्यकता (₹ करोड़ में)	टैरिफ ₹/के डब्लू/महीना	पारेषण की कुल क्षमता (एम डब्लू)	राजस्व आवश्यकता (₹ करोड़ में)	टैरिफ ₹/के डब्लू/महीना
2007-08	1792.00	155.93	72.51	1792.00	91.19	42.40
2008-09	यू ई आर सी द्वारा स्वयं ही कम्पनी के ए आर आर का अनुमोदन क्योंकि कम्पनी ए आर आर प्रस्तुत करने में असफल रही				86.71	-
2009-10	1809.27	144.84	92.22	1809.27	102.53	65.28
2010-11	1891.59	172.68	91.29	1891.59	101.74	53.79
2011-12	1989.68	247.10	103.51	1989.68	131.82	55.22

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से सूचना संकलित)

विनियमन के अनुसार, कम्पनी नियन्त्रणीय मदों (प्रचालन एवं रखरखाव, नियोजित पूँजी पर प्रत्याय, ह्रास और बिना टैरिफ वाली आय) के सम्बन्ध में व्यय का विवरण यू ई आर सी के समक्ष प्रस्तुत करेगी जो बदले में समीक्षा करेगा तथा जहाँ आवश्यक है युक्तिसंगत समायोजन करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2012) कि कम्पनी ने 2008-09 को छोड़कर वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए ₹ 720.55 करोड़ की राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव पेश किया जिसके सापेक्ष यू ई आर सी ने कुल ₹ 427.28 करोड़ की अनुमति दी। यू ई आर सी ने स्वयं ही कम्पनी को 2008-09 के लिए ₹ 86.71 करोड़ का टैरिफ दिया। आगे, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि लेखापरीक्षित खातों तथा सम्पत्ति के पूँजीकरण के अभाव में कम्पनी का 2004-05 से 2010-11 का अंतिम ट्रूइंग अप अभी भी लम्बित पड़ा था। इसके कारण कम्पनी को अस्वीकृत व्यय/ लागत स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना पड़ा।

कम्पनी ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान हानि उठायी थी और मार्च 2012 तक कम्पनी की संचयी हानि ₹ 103.87 करोड़ थी। कम्पनी की संचयी हानि को कम किया जा सकता था। यदि कम्पनी अपने ए आर आर ट्रूइंग अप को यू ई आर सी के समक्ष प्रस्तुत कर देती।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि बहु-वर्षीय टैरिफ याचिका एक महीने के अन्दर यू ई आर सी के समक्ष दायर की जायेगी।

4.2.19 प्रणाली की उपलब्धता

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) विनियमन 2004 के अनुसार यदि कम्पनी अपने आल्टरनेटिव करंट प्रणाली के लक्ष्य की उपलब्धता 98 *प्रतिशत* प्राप्त कर लेती है तो वह पूरी वार्षिक पारेषण शुल्क की वसूली की हकदार है और यदि उसकी उपलब्धता 98 *प्रतिशत* से कम होती है तो वार्षिक पारेषण शुल्क (ए टी सी) यथानुपात कम हो जायेगा। कम्पनी की प्रणाली की उपलब्धता 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में क्रमशः 99.24, 99.14 और 99.50 *प्रतिशत* थी।

इस मेधावी प्रदर्शन के लिए भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता पर गोल्ड शील्ड से सम्मानित (मार्च 2012) किया गया था जो प्रशंसनीय था।

4.2.20 सामग्री प्रबन्धन

4.2.20.1 सामग्री प्रबन्धन के महत्वपूर्ण कार्यों में भण्डार नियन्त्रण नीति, सामग्री खरीद की प्रणाली और अप्रचलित भण्डार का निपटान निर्धारित है। यद्यपि, कम्पनी के पास प्रलेखित अधिप्राप्ति एवं अनुबन्ध नियमावली थी, तथापि केन्द्रीय भण्डार द्वारा समुचित कार्यचालन के अभाव में अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था और मितव्ययी अधिप्राप्ति एवं भण्डार पर कुशल नियन्त्रण के लिए भण्डार नियन्त्रण तन्त्र का अभाव था।

4.2.20.2 भण्डार मानकों का निर्धारित न किया जाना

2007-08 से 2011-12 की अवधि के प्रारम्भिक रहातिया खरीद, निर्गम और अंतिम रहातिया का विवरण तालिका **4.2.9** में नीचे दिया गया हैः

तालिका 4.2.9 *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	उपभोग (प्रति वर्ष)	उपभोग (प्रति माह)	शुद्ध अन्तिम रहतियाँ (आर्थिक चिटठी के अनुसार)	अन्तिम रहतियाँ महीनों के उपभोग के सन्दर्भ में
2007-08	15.52	1.29	28.26	21.91
2008-09	18.12	1.51	23.43	15.52
2009-10	13.48	1.12	22.03	19.67
2010-11	19.02	1.58	26.61	16.84
2011-12	12.48	1.04	30.39	29.22

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से सूचना संकलित)

हालाँकि कम्पनी की अंतिम रहतियाँ 2007-08 में 21.90 महीनों के बराबर थी जो 2011-12 में बढ़कर 29.22 महीनो के उपभोग के बराबर हो गयी, फिर भी अभी तक कम्पनी ने न तो भण्डार रखने का कोई न्यूनतम/अधिकतम स्तर निर्धारित किया था और न ही कोई अ ब स विश्लेषण ही किया गया था, या सामग्री की आवश्यकता के लिए कोई पुनर्आदेश की सीमा भी निर्धारित किया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी की स्थापना के समय ₹ 21.53 करोड़ की रहतियाँ वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से स्थानान्तरित हुआ था और यह अभी भी कम्पनी के रहतियें में पड़ा है। इसको कुल रहतियों से घटाने के बाद कम्पनी की अंतिम रहतियाँ उपभोग के हिसाब से 5.21 महीनें के लिए शेष

बचता है जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी भण्डार का अधिकतम और न्यनूतम सीमा, अ ब स विश्लेषण और सामग्री खरीद के लिए मित्तव्ययी आदेश मात्रा को न अपनाने के मामले में मौन रहीं थी। इसके अतिरिक्त वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) द्वारा स्थानान्तरित ₹ 21.53 करोड़ का भण्डार कम्पनी की रहतिये का ही एक हिस्सा था।

4.2.20.3 भण्डार का भौतिक सत्यापन न होना

सामान्य वित्तीय नियम 116 (1) के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। कम्पनी के पास दो केन्द्रीय स्टोर गढ़वाल जोन का ऋषिकेश और कुमाँऊ जोन का हल्द्वानी में हैं। ये स्टोर 2009-10 में स्थापित हुए थे। तथापि ये स्टोर पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने भण्डार लेखा तथा लेजर का रखरखाव नहीं किया था। भण्डार का भौतिक सत्यापन इसकी स्थापना से ही नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप कम्पनी के पास भण्डार नियंत्रण का कोई तन्त्र नहीं था।

पाँच वर्षों के दौरान क्षेत्र इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आधार पर कम्पनी द्वारा संकलित अप्रचलित और स्क्रैप सामग्री की कीमत नीचे **तालिका 4.2.10** में दिया गया हैः

तालिका 4.2.10 *(₹ करोड़ में)*

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आधिक्य/अप्रचलित/असेवायोग्य/स्क्रैप	21.54	21.54	21.55	23.89	23.89

(स्रोतः कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि समीक्षा की अवधि में स्क्रैप और अप्रचलित सामग्री के मूल्य में मामूली वृद्धि हुई थी। उपरोक्त रहतियों का समाधान विवरण नहीं बनाया गया था। कम्पनी ने स्क्रैप और अप्रचलित सामग्री के निपटान की कोई कार्यवाही नहीं की थी। स्टोर में बेकार पड़ी सामग्री को अन्य यूनिटों में उपयोग हेतु स्थानान्तरित भी नहीं की गयी थी।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि स्क्रैप/ आधिक्य/ बेकार/ अचल सामग्री की नीलामी हेतु कदम उठाए जा रहे है।

4.2.20.4 बेकार पड़ा कन्डक्टर (राशि ₹ 83.00 लाख)

लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2012) कि 400 के वी काशीपुर लाईन के निर्माणावधि में खण्ड (400 के वी रखरखाव एवं परिचालन काशीपुर) ने 2005-06 में ₹ 83.00 लाख का अल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित (ए सी एस आर) मूस कन्डक्टर का आवश्यकता से अधिक क्रय कर लिया था और यह सितम्बर 2006 से खण्ड के खुले स्थान में बिना उपयोग के पड़ा था।



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान स्विच यार्ड की फाईल फोटो



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि काशीपुर खण्ड में पड़ा कन्डक्टर खुले में पड़ा होने के कारण खराब नहीं होता है और यह बहुत जल्द ही उपयोग में लाया जायेगा। तथापि, यह तथ्य अभी भी है कि छः वर्ष बीतने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो सका था और यह खुले मैदान में पड़ा है।

4.2.21 शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण एवं नियन्त्रण

4.2.21.1 कम्पनी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह के एक विशाल संगठन के मितव्ययितापूर्वक, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सफल संचालन के लिए प्रचालन सेवा मानकों तथा लक्ष्यों की प्रलेखित प्रबन्धन प्रणाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लक्ष्य एवं मानकों के सापेक्ष उपलब्धि को प्रतिवेदित करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) होनी चाहिए। कमियों का उल्लेख करने तथा अगले वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उपलब्धियों के समीक्षा की आवश्यकता होती है। सामान्यतया लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उसकी उपलब्धि एक संगठन को आत्म निर्भर बनाए।

400/220/132 के वी उपकेन्द्रों का निष्पादन विभिन्न पैरामीटरों यथा अधिकतम और न्यूनतम बोल्टेज स्तर, ब्रैकडाउन, बोल्टेज प्रोफाइल को ग्रिड सहिता मानकों के अनुसार दर्ज/ रखरखाव किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2012) कि उपकेन्द्रों एवं लाईनों के वर्ष वार संचयी निष्पादन का न तो रखरखाव किया जा रहा था और न ही वार्षिक निष्पादन के मूल्याँकन के लिए इसका संकलन ही किया जा रहा था। तथापि, क्षेत्रीय खण्ड, इकाईयों तथा स्थापित यन्त्रों के निष्पादन के सम्बन्ध में मासिक एम आई एस प्रतिवेदने संकलित करते है। यद्यपि इन पुस्तिकाओं को कारपोरेट कार्यालयों को अग्रसारित किया जा रहा था लेकिन इन्हें सत्यापन के लिए माहवार एवं वर्षवार नहीं रखा गया था।

इसके अलावा एम आई एस रिर्पोट से पता चला कि यन्त्रों की सफाई के कार्यक्रम जैसे सर्किट ब्रेकर (सीबीज), तेल बदलने की अगली तिथि, ओन लोड टेप चेंजर का ओपरेशन रखरखाव के कार्य की तिथि, उपकेन्द्र बैट्ररी का समीक्षा निष्पादन, रिले का निष्पादन, फीडरो के ब्रैक डाऊन के कारणों का विश्लेषण इत्यादि का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। कम्पनी के निदेशक मण्डल (बी ओ डी) को उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निष्पादन प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी और व्यवस्था में आगे के सुधार के लिए मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक स्तर पर उठाये गये कदम यह प्रदर्शित करते थे कि एम आई एस प्रतिवेदन को न्यूनतम महत्व दिया जा रहा था।

इस सम्बन्ध में अच्छे एम आई एस प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता हैः

- कम्पनी को चाहिए की वह नये उपकेन्द्रों और पारेषण लाईनो के निर्माण तथा पारेषण क्षमता में वृद्धि के लिए मील के पत्थर के आधार पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करें।
- कम्पनी को चाहिए कि वह प्रभावी प्रबन्धन के लिए एक उपयुक्त एम आई एस युक्ती जिसमें सब-स्टेशनो की ओवर लोडिंग, लगातार बोल्टेज परिवर्तन और उपकेन्द्रों के लोड साझा परिवर्तन के डाटा संकलित हो तैयार करें।
- निदेशक मण्डल को कम्पनी के सम्पूर्ण प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए।

- कम्पनी को एक रिर्पोट बनानी चाहिए जो उपकेन्द्रों, लाईनो और यन्त्रों के आवर्ती रखरखाव की पहचान करती हो।
- कम्पनी को भण्डार के उचित उपयोग के लिए एक सूचना तन्त्र विकसित करना चाहिए।

4.2.21.2 पारेषण और वितरण योजनाओं के लाभ की परिकल्पना की समीक्षा

समीक्षा अवधि में कम्पनी ने पाँच अतिरिक्त हाई टेंशन (ई एच टी) उपकेन्द्रों का निर्माण एवं अर्पण और कुल 425.20 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त हाई टेंशन लाइन खड़ा किया था। पारेषण एवं वितरण योजना (टी एण्ड डी) का अनुमोदन करते समय कम्पनी ने नई योजना द्वारा इस रूप में लाभ की परिकल्पना की थी। लाइन हानियों में कमी वोल्टेज स्तर में सुधार एवं भार विधि जैसी उपलब्धि हासिल करनी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने ऐसा कोई तन्त्र/ प्रणाली विकसित नहीं की थी जो टी एण्ड डी योजना लागू होने पर उससे प्राप्त होने वाले लाभो का वास्तव में निर्धारण कर सकें। इसके अतिरिक्त नयी परियोजनाओं के अर्पण के बाद से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों से, प्रतिपुष्टि (फीड बैक) जो आवश्यक थी, प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रबंधन ने व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि उपकेन्द्रों और लाईनों के निर्माण से प्रणाली को लाभ हुआ है, जैसा कि प्रणाली में अतिरिक्त लोड चल रहा था और प्रणाली की उपलब्धता 99.5 *प्रतिशत* से अधिक थी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने यह नहीं बताया है कि नया उपकेन्द्रों प्रणाली के लिए कैसे लाभकारी है। नये उपकेन्द्रों तथा लाइनों से प्राप्त लाभ की पुष्टि करने के लिए कम्पनी ने कोई अध्ययन भी नहीं किया था।

4.2.21.3 आन्तरिक नियन्त्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसकी अभिकल्पना; परिचालन में निपुणता, वित्तीय प्रतिवेदन में विश्वसनीयता एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के समुचित संचालन एवं प्रभावकारिता तथा त्रुटि एवं गबन का पता लगाने के लिए प्रायोग्य विधियों एवं संविधियों का पालन करने में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए की गयी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2012) कि वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से अलग होने से पहले उपमहाप्रबन्धक (वित्त) की अध्यक्षता में इसकी एक अलग आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग थी। जून 2004 को अलग होने के बाद कम्पनी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि वर्ष 2006-07 तक यू पी सी एल की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग कम्पनी की लगातार आन्तरिक लेखापरीक्षा करती रही। कम्पनी ने 30 नवम्बर 2009 को 24वीं बोर्ड बैठक में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाहरी संस्था से कराने का निर्णय लिया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य कम्पनी ने बाहर की फर्म[39] को ₹ 6.50 लाख वार्षिक के आधार पर दिया था। यद्यपि, यह देखा गया कि बाहरी फर्म द्वारा किया गया आन्तरिक लेखापरीक्षा मानक के अनुसार नहीं था जैसा कि फर्म ने प्रतिवेदन में न तो प्रणाली की खामियों और न ही महत्वपूर्ण आपत्तियों को दर्शाया था और

[39] मेसर्स एल.बी.झा एण्ड कम्पनी।

अपने प्रतिवेदन को केवल अंक गणितीय लेखाकंन की सीमा तक सीमित रखा और व्यय के औचित्य की अनदेखी की गई।

कम्पनी को स्वयं अपनी लेखापरीक्षा विंग को विकसित करने की आवश्यकता है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना के प्रस्ताव को निदेशक मण्डल के समक्ष पेश किया गया था और यह शीघ्रातिशीघ्र स्थापित हो जाएगा।

4.2.21.4 लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को एक लेखापरीक्षा समिति (ए सी) की स्थापना करनी चाहिए जो कि समय-समय पर लेखापरीक्षकों के साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा क्षेत्र सहित लेखापरीक्षक की आपत्ति और अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण, बोर्ड में रखने से पूर्व विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का अनुपालन हो रहा है।

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की स्थापना की। कम्पनी अधिनियम के अनुसार लेखापरीक्षा समिति को अर्द्धवार्षिकीय एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करनी चाहिए थी। इसका तात्पर्य यह है कि लेखापरीक्षा समिति की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा परीक्षा में पाया गया (अगस्त 2012) कि पाँच वर्षों की अवधि में लेखापरीक्षा समिति ने कम्पनी अधिनियम के अनुसार 10 बार के बजाय 7 अवसरों पर ही बैठक की थी। लेखापरीक्षा समिति 2007-08 से 2008-09 के दौरान 2 अवसरों पर ही मिली थी। इसके अतिरिक्त धारा 292ए (5) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की बैठको में उपस्थित होना चाहिए, लेकिन इसका एक भी बैठक में अनुपालन नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकारा (सितम्बर 2012) और व्यक्त किया कि भविष्य के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

4.2.22 पर्यावरण प्रबन्धन

4.2.22.1 खतरनाक कचरे का अनुचित निपटान

उपकरण एस एफ 6 सीबी जिसमें सल्फर हेक्साफलोराइड़ प्रयोग होती है, का उपयोग पारेषण उपकेन्द्रों के स्विचिंग उद्देश्यों और ट्रासफॉर्मरों और लाईनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान एस एफ 6 सीबीज सफेद या भूरी ठोस राख निकालते हैं। इस उत्पाद के सम्पर्क में आने से खुजली और दर्दनाक जलन होती है। अतः इस प्रक्रिया में उत्सर्जित राख, मानव शरीर तथा पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है।

एस एफ 6 सीबी के रखरखाव/ ओवर हॉलिग की प्रकिया के दौरान ठोस राख डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक कपड़े, सफाई में प्रयोग होने वाला कपड़ा, साँस लेने वाले फिल्टर ब्रेकर की आणुविक छलनी, गैस कार और वैक्यूम फिल्टर उपकरणो का निपटान करने की उचित आवश्यकता होती है।

सभी सामग्री जो एस एफ 6 सीबी के रखरखाव/ ओवर हालिग के समय सफाई की प्रकिया में प्रयोग होते है को एक 55 गैलड्रम में रखकर और उसका निपटान एक खतरनाक कचरे के रूप में किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा के दौरान 110 एस एफ 6 सीबी जो 6 संचालन एव रखरखाव खण्डों[40] कें 20 उपकेन्द्रों में स्थापित थे कि नमूना जाँच की गयी। इन एस एफ 6 सीबीज की ओवर हॉलिग और रखरखाव 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6 से 12 अवसरो पर किये जाने के अधीन था। फिर भी यह देखा गया कि कम्पनी ने खतरनाक कचरे के प्रभावी निपटान के लिए कोई तरीका नहीं बनाया था।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा आपत्ति के स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और व्यक्त किया कि एस एफ 6 सीबीज का रखरखाव एस एफ 6 गैस चैम्वर को बिना खोले किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार खतरनाक कचरे के निपटान के लिए प्रत्येक उपकेन्द्र पर तन्त्र विकसित किया जायेगा।

4.2.22.2 सुरक्षा उपायों का पालन न करना

राईट ऑफ वे (आर ओ डब्लू), वह वन क्षेत्र जिसमें 132 किलों वोल्ट (केवी) से 400 के वी पारेषण लाईन का निर्माण होता है, के बीच 18 मीटर से 52 मीटर तक की चौडाई सीमा होनी चाहिए। इस आर ओ डब्लू में पेड़ों की ऊँचाई चार मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि जंगल को आग के नुकसान और पारेषण हानि से बचाया जा सके।

कम्पनी के पास 2319.20 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) लाइन है; जिसमें से 785.86 सी के एम लाइन (लगभग 33.87 *प्रतिशत*) घने जंगली क्षेत्र में पड़ता है एवं इन लाइनों का रखरखाव कम्पनी के साथ परिचालन एवं रखरखाव (ओ एण्ड एम) खण्डों[41] द्वारा किया जा रहा था।

उच्च वोल्टेज तार तथा पेड़ों के टहनियों में टकराने के कारण जंगल में आग लगना बारम्बार होने वाली घटना है।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2012) कि कम्पनी की ओ एण्ड एम खण्डों द्वारा गस्त अनिर्धारित तरीके से होती थी, इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि कम्पनी के पास गस्त के सिवाय, लाइनों/ पर्यावरण बचाने, जंगल की हानि बचाने, जीव और वनस्पति को आग से बचाने का कोई और तरीका नहीं था। नियमित गस्त के अभाव में वनस्पति/ पेड़ों की वृद्धि जो आर ओ डब्लू के अन्तर्गत पड़ती है, का सत्यापन नहीं किया गया एवं पेड़ों की लम्बाई एवं जोखिम क्षेत्र की पहचान समय पर न होने के कारण जंगल की आग और पर्यावरण के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता ।

इसलिए, कम्पनी की रोकथाम के उपाय के लिए वन क्षेत्र में लाइनों के गस्त की एक प्रलेखित कार्य योजना बनानी चाहिए थी।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि गस्त ओ एण्ड एम मैन्युल के अनुसार की जा रही थी। तथापि, लेखापरीक्षा के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी ने निवारक उपाय के तौर पर वन क्षेत्र में आने वाली लाइनों के गस्त के लिए एक प्रलेखित कार्य योजना बनाने का आश्वासन दिया।

---

[40] 400 के.वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 132 के.वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 220 के.वी ओ एण्ड एम पंतनगर, 220 के.वी ओ एण्ड एम देहरादून, 220 के.वी ओ एण्ड एम रूड़की तथा 220 के.वी ओ एण्ड एम सिडकुल, हरिद्वार।

[41] 132 के वी ओ एण्ड एम अल्मोड़ा, 132 के वी ओ एण्ड एम हल्द्वानी, 400 के वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 132 के वी ओ एण्ड एम श्रीनगर, 400 के वी ओ एण्ड एम ऋषिकेश, 220 के वी ओ एण्ड एम देहरादून तथा 220 के वी ओ एण्ड एम ऋषिकेश।

4.2.23 निष्कर्ष

कम्पनी एक किफायती, कुशल और प्रभावी तरीके से उत्तराखण्ड एकीकृत पारेषण परियोजना, स्कीम को लागू करने में विफल रही है। इस योजना की राजस्व क्रियाविधि अभी तक अनसुलझा था। कम्पनी तय पाँच वर्षों की अवधि में परियोजनाओं को पूर्ण करने में असफल रही। योजना और परियोजना प्रबन्धन में कमी के कारण कम्पनी प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन में असामान्य विलम्ब के कारण 7 से 40 महीने की समय वृद्धि हुई। उपकेन्द्रों का निर्माण बिना उचित भार संचलन का अध्ययन के किया गया था। परिणास्वरूप, उपकेन्द्रों का कम उपयोग हुआ। कुछ मामले ट्रासफॉर्मरों और लाईनों की निर्धारित सीमा से असामान्य ओवर लोडिग के रहे। 132 किलो वोल्ट (के वी), 220 के वी एवं 400 के वी के कम्पनी के 35 उपकेन्द्रों में से केवल सात उपकेन्द्र, ग्रिड के बचाव एवं सुरक्षा के लिए, रिमोट टर्मिनल इकाई के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) से सम्बद्ध किये गये थे। आपदा प्रबन्धन के लिए सुरक्षा उपाय एवं बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त थे। 2004-05 से 2010-11 तक की अवधि के लिए टैरिफ ट्रूईंग अप याचिका दायर करने में देरी हुई। कम्पनी ने न तो भण्डार प्रबन्धन के लिए कोई मापदण्ड बनाये थे और न ही स्टॉक की न्यूनतम/ अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। हालाँकि कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता के रखरखाव पर भारत सरकार, ऊर्जा मत्रांलय द्वारा गोल्ड शील्ड से सम्मानित किया गया था। कम्पनी द्वारा जारी सभी बी डी आई निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया था। समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी की पारेषण हानि मापदण्डों के भीतर रही थी।

4.2.24 अनुशंसाएँ

सरकार/ कम्पनी विचार कर सकती है किः

- इस सुनिश्चिय के द्वारा कि ठेका देने से पहले सभी आवश्यक अनुमोदन/सांविधिक मंजूरियाँ प्राप्त कर ली गई हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब नहीं हैं, एक प्रभावशाली अनुश्रवण प्रणाली प्रस्तावित की जाए;
- समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए नई योजनाएँ स्वीकार करने से पहले अपूर्ण योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि उपकेन्द्रों का निर्माण केवल समुचित भार विश्लेषण के बाद ही किया जाता है;
- ग्रिड कोड के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र का रखरखाव किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनरेटरों और उपकेन्द्रों को ग्रिड की सुरक्षा एवं बचाव के लिए, वास्तविक समय आधार पर दूरस्थ टर्मिनल यूनिट (आर टी यू) द्वारा एस एल डी सी से जोड़ा गया है;
- भण्डार प्रबन्धन प्रणाली के लिए मानक निर्धारित करना जो भण्डार की अधिकतम, न्यूनतम और पुनः आदेश सीमा तय करें;
- आपतकाल की स्थिति में शीघ्र नेटवर्क की बहाली के लिए एक आपदा प्रबन्ध प्रणाली विकसित करना;
- निवारक रखरखाव एवं जोखिम वाले क्षेत्रों की पूर्व में ही पहचान करने के लिए हॉट लाइन खण्डों की स्थापना की जाए; तथा
- निवारक उपाय के रूप में वन क्षेत्र में स्थित लाइनों के गस्त के लिए एक प्रलेखित कार्य योजना विकसित की जाए ।

लेन देन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

4.3 ब्याज की हानि

समझौता ज्ञापन का उल्लघंन करते हुए अवशेष राशियों के जमा करने/अन्तरण में विलम्ब तथा कम्पनी की दुर्बल आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के फलस्वरूप ₹ 80.99 लाख के ब्याज की हानि।

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) और भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई)/पंजाब नेशनल बैंक (पी एन बी) के बीच जुलाई/मई 2003 को, देहरादून में मुख्य बैंक खाता सहित उत्तराखण्ड के विविध जिलों में बैंकिंग व्यापार चलाने हेतु, समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) हस्ताक्षर किए गए थे। एम ओ यू में यह प्रावधान था कि:-

(i) मुख्य प्राप्ति खाता वह प्राप्ति निधि खाता होगा जिसमें कम्पनी की सभी प्राप्तियाँ और बैंक की शाखाओं में प्राप्ति खाताओं से हस्तान्तिरत निधियाँ प्रतिदिन मुख्य व्यय खाता में जमा एवं हस्तान्तिरत की जायेगी (उपबन्ध 3.1)।

(ii) राजस्व संग्रहण में लगे सम्बन्धित खण्डों की सभी प्राप्तियाँ शाखा-प्राप्ति खाते में जमा होनी थी (उपबन्ध 5.2)।

(iii) खण्ड के शाखा प्राप्ति खातों में जमा सम्पूर्ण शेष राशि, सभी सम्बन्धित बैंक शाखाओं द्वारा प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार और बैंक अवकाश होने पर तुरन्त अगले कार्य दिवस को कार्यशील घंटों की समाप्ति पर विन्ड्लास काम्पलैक्स शाखा (एस बी आई) तथा पलटन बाजार (पी एन बी) (एस्लेहाल), देहरादून के मुख्य प्राप्ति खाते में हस्तान्तरित/प्रेषित किए जायेगें (उपबन्ध 5.3)।

(iv) धन प्रेषण प्राप्ति शाखाएँ, यू पी सी एल के प्राप्ति खाते में निधि के जमा करने में हुए दिनों की देरी हेतु बैंक के लागू प्राइम लैन्डिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक वार्षिक दर पर ब्याज देने की उत्तरदायी होंगी, जिसकी गणना एम ओ यू के उपबन्ध 5.6 के अनुसार की जायेगी (उपबन्ध 5.7) ।

कम्पनी के गोपेश्वर खण्ड की नमूना जाँच (जनवरी 2012) में पाया गया कि शाखा प्राप्ति खातों की शेष राशियों को कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते में हस्तान्तरित करने में एक दिन से तीस दिन तक की देरी हुई थी। हरिद्वार खण्ड (शहरी) एवं हरिद्वार खण्ड (ग्रामीण) से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भी निधियों के हस्तान्तरण में देरी पाई गई थी, जिससे यह भी दर्शित है कि देरी अप्रैल 2009 से थी तथा खण्डों द्वारा प्रभावी कदम उठाने के बावजूद भी बैंक ने ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि बैंक विवरण का नियमित मिलान करने में खण्ड असफल रहे थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी का मुख्यालय इस मामले को समय पर बैंक के साथ नहीं उठा सका, जो कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा और कहा (दिसम्बर 2012) कि ब्याज की धनराशि जो बैंक पर देय है की वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है और इसके अतिरिक्त सभी वितरण खण्डों को अनुदेश दे दिये गये है कि वे एम ओ यू के अनुसार निधियों का नियमित प्रेषण सुनिशचित करें और पिछले तीन वर्षों के ब्याज की राशि मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराएँ, यदि कोई है तो। यद्यपि कम्पनी के हरिद्वार खण्ड ने बैंक से प्रारम्भ में ब्याज का दावा (अगस्त 2011) किया था, जिसे कि बाद में (दिसम्बर 2012) पुनरीक्षित किया परन्तु बैंक से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह तथ्य कि खण्ड/कम्पनी एम ओ यू

के उपबन्ध 5.6 एव 5.7 को प्रभावी रूप से लागू कर पाने में असफल रहे थे जिसके कारणवश ₹ 80.99 लाख[42] के ब्याज राशि की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (सितम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4.4 ₹ 3.14 करोड़ की परिहार्य हानि

भूखण्ड आबंटन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने में कम्पनी के असफल रहने एवं अक्टूबर 2009 की निर्धारित दर से अन्य क्रेता को भूखण्ड आबंटन न करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.14 करोड़ की हानि।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना व फलतः अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन एवं राज्य के घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि करना तथा राज्य के संसाधन आधार का महत्वपूर्ण विस्तार करना था।

कम्पनी द्वारा, निधारित की गई नीति में विहित भूखण्ड आबंटन से संबंधित नियमों एवं शर्तों के प्रावधान के अनुसार आवंटी को अधिकतम दो वर्ष की समयावधि के अन्दर फैक्ट्री भवन का निर्माण कार्य तथा यंत्र व मशीनरी संस्थापित कर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा, जिसमें असफल होने पर जमा राशि की जब्ति सहित भूखण्ड का आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा। कम्पनी ने फार्मास्यूटीकल्स उत्पाद बनाने हेतु एक प्राइवेट कम्पनी[43] (आवंटी) को फार्मासिटी, सैलाकुई, देहरादून में 8,092 वर्ग मीटर भूखण्ड ₹ 76.47 लाख की लागत पर (मई 2005) आवंटित किया। भूखण्ड आबंटन पत्र की शर्त 8 के अनुसार भूखण्ड की लागत का अद्यतन भुगतान प्राप्ति एवं लीज डीड के सम्पादन के बाद ही भूखण्ड का कब्जा हस्तान्तरित होगा। आंवटी को वचनबद्धता भी देनी थी कि लीज डीड को सम्पादित करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड आबंटन के 60 दिन के अन्दर ले लिया जायेगा।

लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2012) में पाया गया कि कम्पनी ने आबंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एवं आवंटी द्वारा दी गई वचनबद्धता की अनदेखी करते हुए लीज डीड सम्पादित किये बिना ही सितम्बर 2005 (19.09.2005) में भूखण्ड का कब्जा दे दिया। जबकि लीजडीड तब तक (नवम्बर 2012) सम्पादित नहीं की गई थी, यह भी देखा गया कि आबंटन के छः वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी न तो अवशेष प्रीमियम ₹ 28.66 लाख कम्पनी ने आवंटी से वसूल किए और ना ही फैक्ट्री भवन का निर्माण किया (नवम्बर 2012) गया था। कम्पनी के निरीक्षण प्रतिवेदन (सितम्बर 2011) के अनुसार, केवल आर आर सी कालम एवं प्रथम तल की सीढ़ी के ही निर्माण किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा स्थल के भौतिक निरीक्षण (नवम्बर 2012) पर पाया गया था कि कम्पनी के आखिरी निरीक्षण प्रतिवेदन (सितम्बर 2011) के बाद से कोई भी प्रगति नहीं हुई थी।

आबंटन पत्र के नियम व शर्तों के अनुसार फैक्ट्री भवन का निर्माण कार्य दो वर्ष अर्थात मई 2007 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था तथा उसके बाद व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन निर्धारित अवधि में फैक्ट्री भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण, कम्पनी द्वारा भूखण्ड का निरस्तीकरण पत्र निर्गत किए बिना ही जमा राशि ₹ 37.15 लाख आवंटी को नवम्बर 2007 में वापस कर दी। निरस्तीकरण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के आधार पर आवंटी ने उक्त राशि कम्पनी को नवम्बर 2007 में ही वापस कर दी थी। इसके बाद कम्पनी ने भूखण्ड के आबंटन को रद्द करने के लिए अन्तिम निरस्तीकरण नोटिस (मई 2010) आवंटी को प्रेषित किया। तत्पश्चात भूखण्ड के निरस्तीकरण के लिए एक दूसरा नोटिस आवंटी को जारी किया गया (अक्टूबर 2011), किन्तु नवम्बर 2012 तक भूखण्ड आबंटन को निरस्त नहीं किया गया।

---

[42] गोपेश्वर खण्ड-₹ 14.03 लाख, हरिद्वार (शहरी)-₹ 27.02 लाख और हरिद्वार ग्रामीण-₹ 39.94 लाख।

[43] मैसर्स सैंगफ्रॉइड इन्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड।

यद्यपि कम्पनी की नीति, नियम व शर्तों के अनुसार मई 2007 में भूखण्ड का आबंटन निरस्त हो जाना चाहिए था और समस्त जमाराशि जब्त करते हुए भूखण्ड को बोली लगाने की प्रक्रिया के जरिए नीलामी कर लेना चाहिए था।

इस प्रकार, भूखण्ड निरस्त न करने के कारण, अक्टूबर 2009 की दर के अनुसार कम्पनी को ₹ 3.14 करोड़[44] की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, कुल ₹ 62.92 लाख (अवशेष प्रीमियम सहित ₹ 28.66 लाख और ब्याज ₹ 23.80 लाख, शेष लीज किराया और सर्विस टैक्स ₹ 3.48 लाख और रखरखाव व्यय ₹ 6.98 लाख) आवंटी पर देय थे (नवम्बर 2012)। इसके अतिरिक्त कम्पनी का उद्देश्य जोकि राज्य का औद्योगीकरण व इसके जरिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना था, अपूर्ण रहे।

इसे इंगित करने (जनवरी 2012) पर कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2012) कहा कि आवंटी द्वारा फैक्ट्री के निर्माण में ₹ 50.75 लाख खर्च किये जाने के कारण कम्पनी ने भूखण्ड निरस्त नहीं किया। अब भूखण्ड का निरस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा भूखण्ड के पुनः आवंटन पर अक्टूबर 2009 में निश्चित दर के अनुसार, ₹ 3.14 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि भूखण्ड के निरस्तीकरण या पुनः आवंटन के पक्ष में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने आवंटी से नवम्बर 2012 तक अवशेष प्रीमियम ₹ 28.66 लाख और ब्याज ₹ 23.80 लाख भी वसूल नहीं किया।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (नवम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

(**अश्विनी अत्रि**)

देहरादून **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड**

दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

(**विनोद राय**)

नई दिल्ली **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

दिनांक

[44] भूखण्ड क्षेत्र = 8092 मी x @ ₹ 3875 प्रति मीटर (अक्टूबर 2009 में कम्पनी द्वारा निर्धारित दर) = ₹ 3.14 करोड़।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भः प्रस्तर 2.1 पृष्ठ 5)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 से संबंधी प्रावधानः

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 में राज्य की संचित निधि में से किये गये सभी संव्यवहारों, (II) आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से संबंधित सभी संव्यवहारों, (III) सभी व्यवसाय विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं तथा तुलनपत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा निहित है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 14 में किसी निकाय या प्राधिकरण जिसका पर्याप्त वित्तपोषण राज्य की संचित निधि में से अनुदानों या उधारों से किया जाए,के प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा (II) ऐसे निकाय या प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि में से किसी वित्तीय वर्ष में दिये गऐ अनुदान या उधार एक करोड़ रूपये से कम नहीं हैं वहां सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के प्रावधान निहित है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 16 में उन सभी प्राप्तियों की लेखापरीक्षा जो भारत की और प्रत्येक राज्य की संचित निधि में संदेय है और यह समाधान कि उस बारे में सभी नियम और प्रकियाएं राजस्व के निर्धारण संग्रहण और उचित आंबटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिये लेखाओं की लेखापरीक्षा और उनकी बाबत रिपोर्ट देने के प्रावधान निहित है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) में निहित है **कि** राज्य विधायिका द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों के (जो कंपनियां न हों) लेखाओं की लेखापरीक्षा संबंधित विधानों के उपबंधों के अनुसार किए जाने के प्रावधान निहित हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के प्रावधानों में निहित है कि किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं संबद्ध सरकार के मध्य तय हों।

परिशिष्ट -2.2

(सन्दर्भः प्रस्तर; 2.13; पृष्ठ 8)

31 मार्च 2012 को लम्बित विभागीय टिप्पणियों (सामान्य और सांख्यिकीय प्रस्तरों के अतिरिक्त) का विवरण

क्रम सं.	विभाग	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	योग
1	कृषि	1											1
2	कारागार	1											1
3	राजस्व	2	7	4	4	2	5	1	2				27
4	सिंचाई	3				1		1					5
5	लोक निर्माण विभाग	2	2		4	3	2		10				23
6	चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			1	2	1	1						5
7	ग्राम्य विकास					2	3						5
8	शिक्षा		1				1		2				4
9	खेल एवं युवा कल्याण			1	1								2
10	पेयजल निगम				1	2		3					6
11	समाज कल्याण				1				1				2
12	वन				2								2
13	मत्सय					1							1
14	पर्यटन					3	2						5
15	वित्त							1					1
16	पुलिस								1				1
17	एन आर एच एम (एकल)								1				1
18	विशेष भू-अध्याप्ति अधिकारी	1											1
													93

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भः प्रस्तर 2.2.6; पृष्ठ 18)

योजना के कार्यान्वयन में सम्बद्ध सरकारी पदाधिकारियों के कार्य और जिम्मेदारियाँ

पद	राज्य अधिसूचना के अनुसार कार्य और उत्तरदायित्व
प्रमुख सचिव	राज्य सरकार स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख और योजना के कार्यान्वयन में राज्य समन्वयक के रुप में कार्य करेगा । अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राज्य समन्वयक को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना जिसमें विभिन्न कर्मियों की तैनाती होनी थी, इसमें राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस ई जी सी) और राज्य रोजगार गारंटी निधि की स्थापना करना भी कार्यों में शामिल है । राज्य समन्वयक के कार्य इस प्रकार हैं ; अ) समय से राज्यांश निर्गत करना, आयोजना बनाना और राज्य में योजना का कार्यान्वयन, ब) माँग पर रोजगार न उपलब्ध कर पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, स) स्थानीय भाषा के माध्यम से स्थानीय जागरुकता, द) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास, य) एम आई एस का विकास, और र) योजना की भौतिक तथा वित्तीय लेखा परीक्षा आदि ।
जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के रुप में नामित (डी पी सी)	जिला कार्यक्रम समन्वयक समग्र आयोजना और योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्य एजेन्सियों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार है ।
मुख्य विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के रुप में नामित	जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करना
जिला विकास अधिकारी, उप जिला कार्यक्रम समन्वयक के रुप में नामित	मुख्य विकास अधिकारी की सहायता करना
खण्ड विकास अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी के रुप में नामित	अ) प्रगति वाले कार्यों की आवधिक निरीक्षण करना ब) आवेदकों के शिकायतों का निवारण करना स) ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार के भीतर सभी कार्यों की नियमित सामाजिक अंकेक्षण किया जाना सुनिश्चित करना ।
उप कार्यक्रम अधिकारी (डी पी ओ)	कार्यक्रम अधिकारी की सहायता करना
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वी डी ओ)	ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र समन्वय
कनिष्ठ अभियन्ता (क अ)	कनिष्ठ अभियन्ता को तकनीकी आगणन तैयार करना, कार्यों की माप आदि कार्य सौंपे गये हैं ।
ग्राम रोजगार सहायक (ग्रा रो स)	ग्रा रो स का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का रख रखाव करना, निर्धारित खातों सहित यह सुनिश्चित करना कि यह दस्तावेज सार्वजनिक जाँच के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके ; पंजीकरण की प्रक्रिया देखना, जॉब कार्ड का वितरण, कार्यों की माँग के विरुद्ध दिनांकित प्राप्ति का प्रावधान, रोजगार आवेदन पत्रों की देख-रेख, कार्य का आवंटन, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान और यह सुनिश्चित करना कि अपेक्षित ग्राम सभा की बैठकें और सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन हो रहा है।

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना और राज्य अधिसूचना

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भः प्रस्तर 2.2.7.3; पृष्ठ 24)

नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयकों (डी पी सी) के लेबर बजट का विवरण

जि का स का नाम	मूल रुप से डी पी सी द्वारा संकलित			डी पी सी द्वारा संशोधित एवं राज्य को प्रेषित		
	वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित कार्यों की संख्या	कार्य की आंकलित लागत (₹ लाख में)	आंकलित मानव दिवस (लाख में)	वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित कार्यों की संख्या एवं राज्य को प्रेषित	कार्यों की आंकलित लागत (₹ लाख में)	आंकलित मानव दिवस (लाख में)
2008-09						
जि का स अल्मोड़ा	14663	31002	254.81	10228	7765	63.82
जि का स देहरादून	5421	12624	125.87	4824	10000	82.19
जि का स पिथौरागढ़	9612	17352	53.29	2476	1633	13.42
जि का स पौड़ी	6480	7788	80.56	6480	7788	80.56
योग	**36176**	**68766**	**514.53**	**24008**	**27186**	**239.99**
2009-10						
जि का स अल्मोड़ा	7142	7266	43.49	5149	2848	17.09
जि का स देहरादून	3165	12130	61.41	1612	1973	11.84
जि का स पिथौरागढ़	8815	14085	62.26	2887	1857	11.14
जि का स पौड़ी	9821	15016	90.11	11946	3511	21.07
योग	**28943**	**48497**	**257.27**	**21594**	**10189**	**61.14**
2010-11						
जि का स अल्मोड़ा	5921	8069	48.41	5921	2551	14.44
जि का स देहरादून	3588	11548	78.92	881	2428	14.56
जि का स पिथौरागढ़	9097	13879	76.68	4657	3352	18.98
जि का स पौड़ी	10986	16250	97.50	6113	4872	27.58
योग	**29592**	**49746**	**301.51**	**17572**	**13203**	**75.56**
2011-12						
जि का स अल्मोड़ा	7282	5895	29.47	3466	2806	14.03
जि का स देहरादून	6109	11184	63.08	3530	3218	16.09
जि का स पिथौरागढ़	11374	20316	84.30	7169	5006	25.03
जि का स पौड़ी	11396	20543	103.32	4157	4256	21.39
योग	**36161**	**57938**	**280.17**	**18322**	**15286**	**76.54**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भः प्रस्तर 2.2.8.2; पृष्ठ 27)

नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयकों (जि का स) की वित्तीय स्थिति

जनपदः अल्मोड़ा *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	धन आवंटन				कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अव्ययित धनराशि
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	विविध प्राप्तियाँ			
2008-09	3.24	3.34	0.42	3.76	0.24	7.24	6.31	0.93
2009-10	0.93	15.83	1.76	17.59	0.94	19.46	17.07	2.39
2010-11	2.39	18.87	2.10	20.97	0.08	23.44	21.07	2.37
2011-12	2.37	16.41	1.82	18.23	0.26	20.86	20.17	0.69

जनपदः पिथौरागढ़ *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	धन आवंटन				कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अव्ययित धनराशि
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	विविध प्राप्तियाँ			
2008-09	0.56	11.16	1.29	12.45	0.02	13.03	7.86	5.17
2009-10	5.17	28.45	3.16	31.61	0.27	37.05	23.44	13.61
2010-11	13.61	23.51	2.61	26.12	0.13	39.86	37.83	2.03
2011-12	2.03	46.06	5.12	51.18	0.12	53.33	50.03	3.30

जनपदः पौड़ी *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	धन आवंटन				कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अव्ययित धनराशि
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	विविध प्राप्तियाँ			
2008-09	0.94	11.48	1.32	12.80	1.18	14.92	8.81	6.11
2009-10	6.11	29.46	2.94	32.40	-	38.51	32.76	5.75
2010-11	5.75	26.39	3.26	29.65	0.20	35.60	34.58	1.02
2011-12	1.02	41.22	4.58	45.80	0.90	47.72	45.40	2.32

जनपदः देहरादून *(₹ करोड़ में)*

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	धन आवंटन				कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अव्ययित धनराशि
		केन्द्रांश	राज्यांश	योग	विविध प्राप्तियाँ			
2008-09	3.92	10.61	1.26	11.87	-	15.79	11.09	4.70
2009-10	4.70	25.20	0.58	25.78	0.07	30.55	12.86	17.69
2010-11	17.69	2.26	2.46	4.72	0.64	23.05	22.19	0.86
2011-12	0.86	15.87	1.66	17.53	0.17	18.56	17.93	0.63

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.6 (अ)

(संदर्भः प्रस्तर 2.2.9.1; पृष्ठ 29)

राज्य, नमूना जाँच किये गये जि का स और नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड में रोजगार सृजन का विवरण

वर्ष	सृजित रोजगार मानव दिवस में (लाख में)			रोजगार की माँग करने वाले कुल परिवारों की संख्या			प्रति परिवार को उपलब्ध कराये गये रोजगार के औसत दिनों की संख्या		
	राज्य	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयक	नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड	राज्य	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयक	नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड	राज्य	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयक	नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड
2007-08	80.34	0	0	189263	0000	0	42	0	0
2008-09	104.33	26.43	7.09	298741	88584	22768	35	30	31
2009-10	182.39	58.95	15.24	522304	221994	45531	35	27	33
2010-11	230.21	71.25	19.78	542391	221213	51883	42	32	38
2011-12	215.82	70.86	17.94	515919	190333	47175	42	37	38
					औसत		**39**	**32**	**35**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.6 (ब)

(संदर्भः प्रस्तर 2.2.9.1; पृष्ठ 29)

राज्य, नमूना जाँच किये गये जि का स और नमूना जाँच किये गये कार्यक्रम अधिकारियों में रोजगार सृजन का विवरण

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की कुल संख्या			सृजित रोजगार मानव दिवस में (लाख में)			100 दिनों का रोजगार प्रदान किये गये परिवारों की कुल संख्या		
	राज्य	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयक	नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड	राज्य	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयक	नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड	राज्य	नमूना जाँच किये गये जिला कार्यक्रम समन्वयक	नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड
2007-08	358734	0	0	80.34	0	0	15658 (04%)	0	0
2008-09	817753	274717	67618	104.33	26.43	7.09	12633 (02%)	4587 (02%)	1349 (02%)
2009-10	893496	317176	83127	182.39	58.95	15.24	20664 (02%)	6793 (02%)	1542 (02%)
2010-11	974529	354014	90392	230.21	71.25	19.78	25412 (03%)	5416 (02%)	1526 (02%)
2011-12	1010169	366817	91545	215.82	70.86	17.94	26118 (03%)	5080 (01%)	974 (01%)
						औसत	**(03%)**	**(02%)**	**(02%)**

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भः प्रस्तर 2.2.12; पृष्ठ 35)

एम आई एस और एम पी आर में वर्णित आँकड़ों का विवरण

जनपद		पिथौरागढ़			अल्मोड़ा			पौड़ी			देहरादून		
विषयवस्तु		2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12	2009-10	2010-11	2011-12
जाबकार्ड निर्गत परिवारों की संख्या	एम पी आर	62264	76684	84298	94660	96976	99078	103766	108376	109621	56486	71978	73820
	एम आई एस	76172	83149	84197	98737	100564	101055	106908	108838	109964	56842	61446	62644
	अंतर	**13908**	**6465**	**101**	**4077**	**3588**	**1977**	**3142**	**462**	**343**	**356**	**10532**	**11176**
	(% में)	***22***	***8***	***0.12***	***4***	***4***	***2***	***3***	***0.43***	***0.31***	***1***	***15***	***15***
रोजगार की माँग करने वाले परिवारों की संचयी संख्या	एम पी आर	46670	71845	53992	70242	50655	42332	85150	74194	78987	19932	24519	15022
	एम आई एस	32786	48667	50940	37512	45395	40056	40733	67706	57844	7357	22695	15594
	अंतर	**13884**	**23178**	**3052**	**32730**	**5260**	**2276**	**44417**	**6488**	**21143**	**12575**	**1824**	**572**
	(% में)	**30**	***32***	***6***	***47***	***10***	***5***	***52***	***9***	***27***	***63***	***7***	***4***
रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संचयी संख्या	एम पी आर	46670	71845	53992	70242	50655	42332	85150	74194	78987	19932	24519	15022
	एम आई एस	32554	48366	50797	36186	45071	39845	40197	67600	57690	6948	22614	15318
	अंतर	**14116**	**23479**	**3195**	**34056**	**5584**	**2487**	**44953**	**6594**	**21297**	**12984**	**1905**	**296**
	(% में)	***30***	***33***	***6***	***48***	***11***	***6***	***53***	***9***	***27***	***65***	***8***	***2***
संचयी सृजित मानव दिवस	एम पी आर	1597200	2375000	2637400	1215200	1304800	1072900	2321000	2139000	2443500	762000	1306000	932500
	एम आई एस	965928	2146183	2499483	825014	1222967	1080441	837622	2185578	2021475	219675	1195983	728558
	अंतर	**631272**	**228817**	**137917**	**390186**	**81833**	**7541**	**1483378**	**46578**	**422025**	**542325**	**110017**	**203942**
	(% में)	***40***	***10***	***5***	***32***	***6***	***1***	***64***	***2***	***17***	***71***	***8***	***22***
कुल उपलब्ध धनराशि (₹ लाख में)	एम पी आर	3705.15	3985.65	5332.96	1945.44	2344.36	2086.74	3851.4	3560.47	4772.05	3054.59	2305.56	1856.22
	एम आई एस	3386.67	4257.13	5254.45	1531.95	2353.66	2096.09	3011	3563.99	4779.02	3060.04	3012.59	1776.34
	अंतर	**318.47**	**271.48**	**78.51**	**413.49**	**9.3**	**9.3**	**840.40**	**3.52**	**6.97**	**5.45**	**707**	**79.88**
	(% में)	***09***	***07***	***01***	***21***	***0.4***	***0.45***	***22***	***0.10***	***0.15***	***0.18***	***31***	***04***
कुल व्यय (₹ लाख में)	एम पी आर	2344.36	3783.03	5003.23	1706.70	2106.89	2017.18	3276.66	3458.03	4540.19	1285.64	2219.29	1793.40
	एम आई एस	1528.29	3787.09	4924.86	991.00	2111.59	1992.88	957.76	3472.73	4513.71	209.06	1963.99	1789.99
	अंतर	**816.07**	**4.06**	**78.36**	**715.70**	**4.70**	**24.30**	**2318.90**	**14.70**	**26.47**	**1076.58**	**255.30**	**3.41**
	(% में)	***35***	***0.11***	***1.57***	***42***	***0.22***	***1.2***	***71***	***0.43***	***0.58***	***84***	***12***	***0.19***

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भः प्रस्तर 2.2.13.1; पृष्ठ 36)

पदस्थापन स्थिति

राज्य स्तर पर

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (*प्रतिशत* में)
जिला अभियन्ता	13	02	11(85)
कम्प्यूटर प्रोगामर	13	01	12(92)
कम्प्यूटर सहायक (जनपद हेतु)	13	00	13(100)
कम्प्यूटर सहायक (विकास खण्ड हेतु)	95	77	18(19)
कनिष्ठ अभियन्ता	614	221	393(64)
ग्राम रोजगार सहायक	1811	648	1163(64)

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

नमूना जाँच किये गये जनपद स्तर पर

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (*प्रतिशत* में)
जिला अभियन्ता	04	02	02(50)
उप कार्यक्रम अधिकारी	40	14	26(65)
कनिष्ठ अभियन्ता	290	84	206(71)
ग्राम रोजगार सहायक	839	246	593(71)
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	728	417	311(43)

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

नमूना जाँच किये गये विकास खण्ड स्तर पर

विकास खण्ड का नाम	उप कार्यक्रम अधिकारी			कनिष्ठ अभियन्ताओं की संख्या			ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की संख्या			ग्राम रोजगार सहायकों की संख्या		
	स्वी.पद	कार्यरत	कमी	स्वी.पद	कार्यरत	कमी	स्वी.पद	कार्यरत	कमी	स्वी.पद	कार्यरत	कमी
डीडीहाट	**01**	**00**	01(100)	06	02	04(67)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	67	08	59 (88)
मुन्सियारी	**01**	**00**	01(100)	09	02	07(78)	19	08	11(58)	31	16	15 (48)
भिकियासैण	**01**	**00**	01(100)	10	01	09 (90)	20	09	11(55)	98	03	95 (97)
द्वाराहाट	**01**	**00**	01(100)	11	01	10 (91)	21	11	10 (48)	29	05	24 (83)
धौलादेवी	**01**	**00**	01(100)	08	01	07 (88)	18	05	13 (72)	26	04	22 (85)
विकास नगर	**01**	**00**	01(100)	05	02	03 (60)	15	14	01 (07)	17	00	**17 (100)**
चकराता	**01**	**00**	01(100)	09	02	07(78)	16	16	00 (00)	25	00	**25 (100)**
पौड़ी	**01**	**00**	01(100)	06	02	04 (67)	16	07	09 (56)	16	07	09 (56)
खिर्सू	**01**	**01**	00(00)	03	02	01(33)	13	08	05 (38)	11	02	09 (82)
एकेश्वर	**01**	**00**	01(100)	04	04	00 (00)	20	09	11(55)	10	06	04 (40)
योग	**10**	**01**	**09(90)**	**71**	**19**	**52(73)**	**158**	**87**	**71(45)**	**330**	**51**	**279(85)**

कोष्ठक में दिखाए गए आँकड़े प्रतिशतता को दर्शाते है

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

परिशिष्ट-2.9

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.7.1; पृष्ठ 45)

लोकसभा चुनाव-2009 के दौरान अधिक व्यय को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

जिलों का नाम	विधान सभा क्षेत्रों की संख्या	फर्मों/ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत बिल	प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद अनुशंसित बिल	भुगतान की गई राशि	निर्धारित सीमा के अनुसार अनुमन्य व्यय*	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय (कॉलम 5-6)	(*प्रतिशत में*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अल्मोड़ा	06	34.80	28.92	28.92	04.80	24.12	502
बागेश्वर	02	14.51	07.18	07.18	01.60	05.58	349
चमोली	03	07.66	07.66	07.66	02.40	05.26	219
चम्पावत	02	05.03	05.03	05.03	01.60	03.43	214
देहरादून	10	16.61	13.12	13.12	08.00	05.12	64
नैनीताल	06	23.22	19.43	19.43	04.80	14.63	305
पिथौरागढ़	04	05.27	05.27	05.27	03.20	02.07	65
रूद्रप्रयाग	02	02.22	02.22	02.22	01.60	0.62	39
टिहरी	06	33.44	16.00	16.00	04.80	11.20	233
उधमसिंहनगर	09	25.62	25.62	25.62	07.20	18.42	256
उत्तरकाशी	03	07.46	07.08	07.08	02.40	04.68	195
कुल	**53**	**175.84**	**137.53**	**137.53**	**42.40**	**95.13**	

******प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु व्यय के लिए निर्धारित सीमा ₹ 0.80 लाख है।***

परिशिष्ट-2.10

(सन्दर्भः प्रस्तर 2.3.7.1; पृष्ठ 45)

विधान सभा चुनाव-2012 के दौरान अधिक व्यय को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

जिलों का नाम	विधान सभा क्षेत्रों की संख्या	फर्मों/ ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल/दावें	विभागीय प्राधिकारियों द्वारा विवरणों की सत्यापन के बाद पारित/ अनुशंसित बिल	अगस्त 2012 तक किया गया भुगतान	फर्म/ठेकेदारों को भुगतान हेतु लम्बित धनराशि	निर्धारित सीमा के अनुसार अनुमन्य व्यय*	निर्धारित सीमा से अधिक व्ययाधिक्य (कॉलम 4-7)	
							धनराशि	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
चमोली	03	10.87	10.87	10.87	*शून्य*	04.80	06.07	*126*
रूद्रप्रयाग	02	07.67	07.67	03.20	04.47	03.20	04.47	*140*
बागेश्वर	02	09.99	09.48	04.25	05.23	03.20	06.28	*196*
नैनीताल	06	23.47	23.21	*शून्य*	23.21	09.60	13.61	*142*
हरिद्वार	11	53.68	34.63	09.79	24.84	17.60	17.03	*97*
टिहरी	06	45.67	25.42	14.98	10.44	09.60	15.82	*165*
अल्मोड़ा	06	34.80	28.92	28.92	*शून्य*	09.60	19.32	*201*
उधमसिंहनगर	09	63.41	63.41	19.89	43.52	14.40	49.01	*340*
चम्पावत	02	08.30	08.30	*शून्य*	08.30	03.20	05.10	*159*
उत्तरकाशी	03	13.77	10.11	00.43	09.68	04.80	05.31	*111*
कुल	**50**	**271.63**	**222.02**	**92.33**	**129.69**	**80.00**	**142.02**	

* *प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हेतु व्यय के लिए निर्धारित सीमा ₹ 1.60 लाख।*

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भः प्रस्तर 2.5.7.1; पृष्ठ 64)

आई सी डी एस सेवाएँ (2011-12)

जिलों के नाम	300 दिनों के सापेक्ष अनुपूरक पोषाहार का वितरण		स्वास्थ्य जाँच *प्रतिशत* में	कुपोषण के मामलों की संख्या	गंभीर कुपोषण के मामलों की संख्या	संदर्भित मामलों की संख्या
	टी एच आर	पका पकाया भोजन				
पिथौरागढ़	110	149	58	839	48	147
अल्मोड़ा	122	103	10	104874	475	0
नैनीताल	141	110	73	158634	1693	106
ऊधम सिंह नगर	183	318	08	356915	17503	11913
टिहरी	170	100	11	12859	393	343
योग	**726**	**780**	**160**	**634121**	**20112**	**12509**

स्रोतः जिलों से एकत्रित सूचना के आधार पर गणना की गयी है। योजना के अन्तर्गत टी एच आर व पका पकाया भोजन के दिवसों की संख्या विभाग द्वारा वास्तविक रूप से लाभन्वित लाभार्थियों की संख्या के आधार पर किया गया है।

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भः प्रस्तर 2.5.9.3; पृष्ठ 71)

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का नाम	वर्ष 2009-10					
	ए डब्ल्यू डब्ल्यू		ए डब्ल्यू एच		पर्यवेक्षक	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
इण्डक्शन	420	131	0	0	0	0
जॉब	1960	859	1050	437	75	0
रिफ्रेशर	1400	939	1400	1455	75	0
कुल	3780	1929	2450	1892	150	0
	वर्ष 2010-11					
इण्डक्शन	0	0	0	0	0	0
जॉब	1225	1041	2100	862	0	0
रिफ्रेशर	1960	2016	700	2487	250	0
कुल	3185	3057	2800	3349	250	0
	वर्ष 2011-12					
इण्डक्शन	4760	4560	0	0	0	0
जॉब	980	993	1050	1032	125	0
रिफ्रेशर	280	256	350	291	275	0
कुल	6020	5809	1400	1323	400	0

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भः प्रस्तर 2.5.9.4; पृष्ठ 72)

पर्यवेक्षण का विवरण (2011-12)

जिलों के नाम	कुल संचालित आँगनबाड़ी	पर्यवेक्षण अधिकारी			औसत पर्यवेक्षण के मानक	किया गया पर्यवेक्षण	कमी (*प्रतिशत* में)
		पदनाम	स्वीकृत	तैनात			
पिथौरागढ़	1054	पर्यवेक्षक	17	16	372#	166	55
		सी डी पी ओ	05	05	400	99	75
		डी पी ओ*	01	01	158$	81	49
		निदेशक	01	01	200	00	100
अल्मोड़ा	1860	पर्यवेक्षक	17	15	656	116	82
		सी डी पी ओ	05	05	400	123	69
		डी पी ओ*	01	01	279	70	75
		निदेशक	01	01	200	00	100
नैनीताल	1329	पर्यवेक्षक	43	38	185	98	47
		सी डी पी ओ	09	07	400	62	85
		डी पी ओ*	01	01	199	49	75
		निदेशक	01	01	200	00	100
ऊधम सिंह नगर	2112	पर्यवेक्षक	85	46	149	70	53
		सी डी पी ओ	10	07	400	87	78
		डी पी ओ*	01	01	317	14	96
		निदेशक	01	01	200	00	100
टिहरी	1690	पर्यवेक्षक	48	28	211	04	98
		सी डी पी ओ	09	03	400	00	100
		डी पी ओ*	01	01	254	00	100
		निदेशक	01	01	200	00	100

* परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी (संबंधित जिला) जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे।

पर्यवेक्षकः (कुल आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या का 50 *प्रतिशत* प्रतिमाह * 12/पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पद)

सी डी पी ओः एक तिमाही में 100 कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्र।

$ डी पी ओः (कुल आँगनबाड़ी केन्द्रों का 15 *प्रतिशत*)

निदेशकः एक वर्ष में 200 कार्यशील आँगनबाड़ी केन्द्र।

परिशिष्ट-3.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.1 पृष्ठ 133)

अधिनियम के मुख्य अंश

अधिनियम के मुख्य अंश निम्नवत् हैः

- कोई व्यापारी या व्यक्ति, जो कारोबार कर रहा है और इस अधिनियम के अधीन कर का दायी है, उस तारीख, जब से वह प्रथम बार ऐसे कर का भुगतान करने के लिये दायी है, से तीस दिन के भीतर अपने आपको पंजीकृत करायेगा ।
- यूवैट के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी को एक अद्वितीय ग्यारह अंकीय पंजीयन संख्या प्रदान किया जाता है, जो तीन घटकों से बने "कर भुगतानकर्ता पहचान संख्या" या टिन के नाम से जाना जाता है । प्रथम दो संख्याएं राज्य संकेत दर्शाती है (उत्तराखण्ड का राज्य संकेत 05 है), सात डिजीटल क्रम संख्या, उस क्रम संख्या को दर्शाती है जो पंजीकृत व्यापारियों की पंजिका में प्रविष्टि के अनुसार राज्य में सभी व्यापारियों हेतु क्रमवार है तथा दो अंकों में नियन्त्रण अंक, जैसा कि आयुक्त द्वारा रखा जाय, होते हैं ।.
- प्रणाली मूलरूप से व्यापारियों के इच्छापूर्वक कर भुगतान करने तथा ईमानदारीपूर्वक और आवधिक रूप से विवरणी दाखिल करने पर विश्वास करता है ।
- यह, कराधेय माल की बिक्री के विरूद्ध क्रय पर भुगतान किए गए कर हेतु क्रेडिट, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) के नाम से जाना जाता है, प्रदान करता है । परिणामस्वरूप सम्पूर्ण कर का भार युक्तियुक्त होता है ।
- यदि किसी कर अवधि में आई टी सी उस अवधि की कर देयता की अपेक्षा अधिक होती है, तो उसे केन्द्रीय बिक्री कर (के बि क) अधिनियम, 1956 के अधीन उस कर अवधि की कर देयता, यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित की जायेगी और अवशेष धनराशि को बकाया कर, अर्थदण्ड या ब्याज के विरूद्ध समायोजित की जायेगी और अधिक धनराशि उत्तरवर्ती कर अवधियों में आगे ले जाई जायेगी तथा ऐसी धनराशि उस अवधि के लिये आई टी सी का लाभ समझी जायेगी ।
- ***कर की दरेः***

अनुसूची I	करमुक्त माल
अनुसूची II	भाग 'क'- इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर एक प्रतिशत की दर से कर देय होगा ।
	भाग 'ख'- इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर चार प्रतिशत की दर से कर देय होगा ।
	भाग 'ग'- इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर विक्रय के प्रत्येक बिन्दु पर प्रत्येक के समाने विनिर्दिष्ट दर से कर देय होगा ।
अनुसूची III	इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशेष प्रवर्ग के माल पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट विक्रय के प्रत्येक बिन्दु (नि0 या आ0) पर उसके सामने विनिर्दिष्ट दर पर कर देय होगा ।
अनुसूची IV	इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यापारियों या व्यक्तियों को या के द्वारा किसी माल का विक्रय विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, पूरे या आंशिक कर से मुक्त रहेगा ।
अनुसूची V	इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, किसी कराधेय माल के क्रय पर उसके द्वारा दिये गये कर की वापसी का हकदार होगा ।

- ***प्रोत्साहनः***

छोटे व्यापारियों, जिनके आवर्त ₹ 50 लाख तक है, को एक सरल एवं आसान समाधान योजना उपलब्ध कराया गया है । योजना वैकल्पिक है तथा योजना अपनाने वाले व्यापारियों को सम्पूर्ण आवर्त पर एक प्रतिशत की दर से कर भुगतान करने की आवश्यकता होती है और आई टी सी अनुमन्य नहीं होती है तथा विस्तृत अभिलेख और लेखों के रखरखाव से छूट होती है ।

- ***अर्थदण्ड का प्रावधानः***

अधिनियम, व्यापारियों द्वारा किये गये अपराधों हेतु अर्थदण्ड का प्रावधान करता है । देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करना होगा ।

- **रियायत/छूट हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रपत्र**

प्रपत्र-सी	अन्तर्राज्यीय व्यापार में रियायत लेने हेतु घोषणा का प्रपत्र
प्रपत्र-ई-1, ई-2	पारगमन में बिक्री से छूट हेतु घोषणा का प्रपत्र
प्रपत्र-एफ	स्टॉक अन्तरण पर छूट हेतु घोषणा का प्रपत्र
प्रपत्र-एच	छूट हेतु निर्यात का प्रमाणपत्र
प्रपत्र-I	विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाईयों को विक्रय में छूट हेतु घोषणा का प्रपत्र
प्रपत्र-XI	मान्यता प्रमाणपत्र धारक व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट माल हेतु रियायत के दावे हेतु घोषणा का प्रपत्र
प्रपत्र-XVI	पंजीकृत व्यापारी द्वारा माल के आयात हेतु घोषणा का प्रपत्र
प्रपत्र-XVII	पंजीकृत व्यापारियों से ईतर पक्षों द्वारा माल के आयात हेतु घोषणा का प्रपत्र

परिशिष्ट-3.2

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.10 पृष्ठ 136)

वसूली हेतु लम्बित बकायों की सूची (आर 3 पंजिका के अनुसार)

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष/तिथि	आर सी सं0 एवं जारी करने की तिथि	धनराशि (₹)
1.	उ आ (क नि)-II, वा क, रूड़की	मे0 ओम प्रकाश रमेश चन्द्र, मंगलौर	88-89/26.03.92	13/22.08.93	33,210
2.	स आ (क नि) खण्ड-I वा क, रूड़की (वा क अ सहित)	मे0 राम किशन पुत्र चमन लाल, रूड़की	76-77/31.03.81	13/07.10.82	1,650
		मे0 सोहन लाल, रूड़की	77-78/31.03.82	46/08.05.83	1,720
		मे0 सोहन लाल, रूड़की	78-79/31.03.82	46/08.05.83	1,760
		तदैव	79-80/31.03.82	46/08.05.83	1,160
		मे0 नेशनल इले0, केमिकल एवं सैनिटरी स्टोर, रूड़की	88-89	-	7,042
		मे0 रामा जनरल एवं इलेक्ट्रिकल स्टोर, रूड़की	90-91	16/22.09.99	28,285
		मे0 सुरेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुन सिंह, रूड़की	91-92	189/18.09.99	85,500
3.	स आ (क नि) वा क, रामनगर (वा क अ सहित)	मे0 हिन्दुस्तान फार्मास्यूटिकल, रामनगर	77-78/28.11.80	72/16.02.81	6,000
		तदैव	77-78/28.11.80	73/16.02.81	10,000
		मे0 कमलेश कुमार मुकेश कुमार, रामनगर	79-80/13.01.84	6/05.08.84	15,573
		तदैव	80-81/28.12.84	7/07.11.85	7,094
		तदैव	81-82/10.01.86	13/16.06.86	28,888
		तदैव	82-83/17.10.86	1/20.03.87	24,872
		मे0 भारद्वाज टिम्बर एजेन्सी, रामनगर	84-85/29.12.88	43/24.04.89	70,506
4.	स आ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	मे0 दिलीप सिंह एण्ड सन्स, पलटन बाजार, देहरादून	77-78/30.08.80	822/07.11.80	2,240
		मे0 दुआ इण्ड0, रायपुर रोड, देहरादून	76-77/31.03.81	258/05.11.97	1,680
		मे0 शुभ संविदा सहकारी समिति, सहस्रधारा रोड	76-77/31.03.82	269/15.01.90	2,000
		मे0 डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव फेडरेशन लि0, देहरादून	82-83/28.11.87	-	1,72,000
		मे0 डोसा एण्ड स्नैक्स, राजपुर रोड, देहरादून	83-84/30.01.88	216/27.08.88	6,720
		मे0 डेल्टा इन्जी0, राजपुर रोड, देहरादून	82-83/30.03.88	318/05.09.2000	84,000
		तदैव	82-83/30.03.88	250/22.08.88	51,000
		तदैव	83-84/30.03.88	322/05.09.2000	1,67,000
		तदैव	83-84/30.03.88	321/05.09.2000	60,000
5.	स आ (क नि) खण्ड-III वा क, देहरादून	मे0 सन्त सिंह सूरी एण्ड सन्स, राम मार्केट, देहरादून	75-76/26.04.80	481/02.02.88	4,329
		तदैव	80-81/07.08.80	483/02.02.86	4,800
		तदैव	79-80/30.10.80	487/02.02.80	15,235
		मे0 स्टार लाईट क्लब, लिटन रोड, देहरादून	78-79/24.07.82	317/27.04.90	2,595
		मे0 सन्त सिंह सूरी एण्ड सन्स, रामा मार्केट, देहरादून	80-81/03.12.84	309/20.10.86	19,665
		मे0 इन्टरनेशनल इन्जीनीयर, हरिद्वार रोड, देहरादून	81-82/12.03.86	210/03.08.88	4,800
		मे0 शशि कान्त सिराज़ भग, नेहरू कालोनी, देहरादून	81-82/19.07.86	448/22.03.86	9,000
		तदैव	80-81/01.12.86	447/22.03.86	18,200
		मे0 सोहन लाल सागर सिंह, रामा मार्केट, लुधियाना	87-88/30.09.91	1/10.04.92	39,600
		मे0 सावन सिंह ज्ञान सिंह, जम्मू	87-88/31.03.92	17/24.09.92	52,800
6.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हल्दवानी	मे0 शिव शंकर शिव नारायन धूपवाले, हल्दवानी	75-76/20.10.81	10/31.10.81	1,472
		मे0 शिव ट्रेडर्स, भोलानाथ गार्डेन, हल्दवानी	82-83/26.02.86	339/12.12.90	3,830
		मे0 शालीमार ट्रेडर्स, का0 रोड, हल्दवानी	83-84	28/13.10.88	10,526
		मे0 प्रेम शंकर अवस्थी, हल्दवानी	88-89/23.02.92	1/05.06.93	12,539

7.	स आ (क नि) खण्ड-I वा क, अल्मोड़ा	मे0 सहकारी संघ, तल्ला सालाम, लमगदा, अल्मोड़ा	78-79/ 25.06.81	156/04.04.82	1,081
		मे0 सुभाष चन्द्र जैन एण्ड सन्स, अल्मोड़ा	78-79/30.08.82	71/21.08.83	28,760
		मे0 राधा ट्रेडिंग कम्पनी, अल्मोड़ा	79-80/26.08.83	25/13.12.83	4,350
8.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हरिद्वार	मे0 अरविन्द उद्योग, कनखल	77-78/27.02.82	17/14.09.96	3,767
		मे0 गंगा सेल्स कारपोरेशन, लक्सर, हरिद्वार	78-79/09.03.83	178/28.09.99	3,800
		मे0 राम प्रकाश एण्ड सन्स, हरिद्वार	80-81/26.03.81	9/03.11.03	13,824
		मे0 कर्नल भाटिया फार्म, हरिद्वार	81-82/12.02.86	-	14,372
		मे0 पदम सिंह ठेकेदार, हरिद्वार	87-88/29.02.92	105/03.07.2000	19,800
		मे0 दयाल ठेकेदार, चिड़ियापुर, हरिद्वार	88-89	236/25.02.96	13,200
9.	स आ (क नि) खण्ड-III वा क, रूद्रपुर	मे0 श्री प्लास्टिक स्टोर, रूद्रपुर	78-79/12.11.82	54/02.09.83	5,215
		मे0 ज्योति स्वीट्स इण्ड0, आर आर क्वार्टर, रूद्रपुर	81-82	98/20.06.86	5,000
10.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, ऋषिकेश	मे0 सुरेन्द्र कुमार अश्विनी कुमार, ऋषिकेश	80-81/10.03.84	20/27.11.2001	1,371
		मे0 सुधार कुमार कम्पनी, ऋषिकेश	82-83/20.01.87	14/27.01.2001	18,518
		तदैव	83-84/10.02.88	69/27.01.2010	21,237
11.	स आ (क नि) वा क, कोटद्वार	मे0 युनूस एण्ड दिनेश बाडीमेकर, कोटद्वार	87-88/25.03.89	-/15.07.89	33,000
		मे0 निर्बल सिंह बाडीमेकर, कोटद्वार	87-88/28.06.90	-/08.10.90	8,800
		मे0 अग्रवाल टिम्बर ट्रेडर्स, कोटद्वार	87-88/23.03.92	-/27.05.92	30,854
		मे0 बृज मोहन सिंह खल विक्रेता, कोटद्वार	82-83/21.01.88	-/30.03.88	3,114
	योग				12,99,354

परिशिष्ट-3.3

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.14.1 पृष्ठ 142)

कर का न्यूनारोपण

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माल का नाम	माल का मूल्य (₹)	कर का अन्तरीय दर	कर की अन्तरीय धनराशि (₹)	ब्याज (31.03.12 तक) (₹)	अभ्युक्तियां
1.	उ आ (क नि)-I, वा क देहरादून	मे0 वोल्टाज़ लि0, आर जी एम प्लाज़ा, चकराता रोड, देहरादून	2007-08	ए सी, वाटर कूलर पार्ट्स (कॉपर ट्यूब, कॉपर पाईप)	59,89,840	8.5% (12.5-4)	5,09,136	3,43,667	
		मे0 पी सी एल इन्टरटेक, देहरादून	2008-09	ठेकेदार	-	-	8,073	-	आर-3 पंजिका के अनुसार, व्यापारी ने ₹ 8,20,846 के बजाय ₹ 8,12,773 जमा किया ।
2.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, देहरादून	मे0 गुप्ता कलर कम्पनी, देहरादून	2008-09	रंग	8,13,925	8.5% (12.5-4)	69,184	36,322	
3.	उ आ (क नि)-II, वा क रुड़की	मे0 ओम इन्टरप्राईजेज, रुड़की	2007-08	टॉफी	6,91,977	8.5% (12.5-4)	58,818	39,702	
4.	स आ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	मे0 पायमा इन्डस्ट्रीज़, डी ए वी कालेज रोड, देहरादून	2006-07	सॉफ्ट ड्रिन्क्स	8,23,370	8.5% (12.5-4)	69,986	57,738	
		मे0 प्रताप म्यूजिक हाउस, देहरादून	2006-07	म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेन्ट्स	4,78,404	8.5% (12.5-4)	40,664	33,548	
		मे0 किशोर एण्ड कम्पनी, पलटन बाजार, देहरादून	2006-07	इलेक्ट्रॉनिक गुड्स	17,06,367	8.5% (12.5-4)	1,45,041	1,19,659	
		मे0 किशोर एण्ड कम्पनी, पलटन बाजार, देहरादून	2007-08	इलेक्ट्रॉनिक गुड्स	7,44,010	8.5% (12.5-4)	63,241	42,688	
5.	स आ (क नि) खण्ड-I वा क, रुड़की	मे0 जगदम्बा प्लास्टिक वर्क्स, चाव मण्डी, रुड़की	2007-08	प्लास्टिक शीट्स	48,89,878	8.5% (12.5-4)	4,15,640	2,80,557	
6.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, रुड़की	मे0 किशोर कैण्डीज़, सलेमपुर, रुड़की	2007-08	कैण्डी/कन्फेक्शनरी	21,65,689	8.5% (12.5-4)	1,84,084	1,24,257	
	वा क अ (क नि) खण्ड-II वा क, रुड़की	मे0 यश इन्टरप्राईजेज, रुड़की	2007-08	मशीनरी स्पेयर पार्ट्स	6,70,870	8.5% (12.5-4)	57,024	38,491	
7.	उ आ (क नि)-II वा क, काशीपुर	मे0 आई जी एल लि0, बाजपुर रोड, काशीपुर	2008-09	अल्यूमीनियम स्क्रैप	20,36,584	8.5% (12.5-4)	1,73,110	90,883	
8.	वा क अ (क नि) खण्ड-III वा क, देहरादून	मे0 सम्राट ट्रेडर्स, आज़ाद नगर, रायपुर रोड, देहरादून	2007-08	अल्यूमीनियम स्क्रैप	2,12,885	8.5% (12.5-4)	18,095	12,214	

	मे0 जय इन्टरप्राईजेज, 4 इन्दर रोड, देहरादून	2007-08	मोटर स्पिंग लीफ *(कमानी)*	13,67,979	8.5% (12.5-4)	1,16,278	78,488		
		2006-07	मोटर स्पिंग लीफ *(कमानी)*	10,57,839	8.5% (12.5-4)	89,916	74,181		
		2005-06 (01.10.05 to 31.03.06)	मोटर स्पिंग लीफ *(कमानी)*	3,09,240	8.5% (12.5-4)	26,285	24,642		
9.	उ आ (क नि)-II, वा क हल्दवानी	मे0 महालक्ष्मी ट्रेडिंग कं0, हल्दवानी	2007-08	आयुर्वेदिक ऑयल	7,12,213	8.5% (12.5-4)	60,538	40,863		
10.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हल्दवानी	मे0 राठौर ट्रेडर्स, हल्दवानी	2008-09	सेनेटरी गुड्स	2,21,152	8.5% (12.5-4)	18,798	9,869		
11.	स आ (क नि) वा क, नैनीताल	मे0 एच के श्रदर्स, मल्लीताल, नैनीताल	2007-08	बिसलेरी, हेयर ऑयल	4,04,084	8.5% (12.5-4)	34,347	23,184		
		मे0 प्रिया फोटो मैक्स, मल्लीताल, नैनीताल	2007-08	फोटोस्टेट मशीन	9,16,713	8.5% (12.5-4)	77,921	52,597		
12.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हरिद्वार	मे0 एम एच इण्डस्ट्रीयल इन्जीनियर्स, हरिद्वार	2007-08	ल्यूबिक्रेन्ट (इण्डस्ट्रीयल ऑयल)	2,02,757	16% (20-4)	32,441	21,898		
		मे0 जागृति प्लास्टिक लि0, हरिद्वार	2007-08	एंढसिव एवं केमिकल	10,80,895	8.5% (12.5-4)	91,876	62,016		
13.	स आ (क नि) खण्ड-I वा क, अल्मोड़ा	मे0 श्री लक्ष्मी एजेन्सी, अल्मोड़ा	2007-08	बल्ब	15,81,936	8.5% (12.5-4)	1,34,465	90,764		
14.	स आ (क नि) वा क, कोटद्वार	मे0 अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोटद्वार	2007-08	बिस्कुट, कुरकुरे	1,24,630	8.5% (12.5-4)	10,594	7,151		
15.	स आ (क नि) वा क, किच्छा	मे0 शील चन्द्र एण्ड प्रा0 लि0, लालपुर, किच्छा	2006-07	प्लास्टिक स्क्रैप (पुराना	14,74,050	8.5%	1,25,294	1,03,368		
			2007-08	बारदाना)	3,76,085	(12.5-4)	31,967	21,578		
16.	वा क अ (क नि) खण्ड-II वा क, ऋषिकेश	आर पी इन्टरप्राईजेज, ऋषिकेश	2007-08	इलेक्ट्रिक गुड्स	70,500	8.5% (12.5-4)	5,992	4,045		
	योग				**3,11,23,872**		**26,68,808**	**18,34,370**		

परिशिष्ट-3.4

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.14.1 पृष्ठ 142)

कर का अनारोपण

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माल का नाम	माल का मूल्य (₹)	कर की दर	कर की धनराशि (₹)	ब्याज (31.03.12 तक) (₹)	अभ्युक्तियां
1.	स आ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	मे0 पी सी डेवेलपर्स, सहस्रधारा रोड, देहरादून	2007-08	टी एम टी	19,54,182	4%	78,167	52,763	
2.	उ आ (क नि)-V, वा क देहरादून	यूरेका फोर्ब्स	2007-08	एक्वा गार्ड, वैक्यूम क्लीनर, एअर प्यूरीफायर	1,14,08,793	12.5%	14,26,099	9,62,617	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार,वॉरण्टी क्लेम को बिक्री समझा जाय ।
			2008-09	तदैव	57,08,806	12.5%	7,13,601	3,74,641	तदैव
		वेन्कीज़ इण्डिया लि0 (फीड डिवीजन)	2006-07 (01.04.06 to 18.12.06)	संतुलित कुक्कुट आहार	7,18,72,878	12.5%	89,84,110	74,11,891	
3.	उ आ (क नि)-II, वा क हल्दवानी	मे0 एम आर एफ लि0, हल्दवानी	2005-06 (भाग II)	टायर, ट्यूब, फ्लैप	10,07,461	12.5%	1,25,933	1,18,062	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वॉरण्टी क्लेम/फ्री रिप्लेसमेन्ट के कारण दावाकृत हानि को बिक्री समझा जाय ।
			2006-07		26,78,278		3,34,785	2,76,198	
			2007-08		58,17,943		7,27,243	4,90,889	
		मे0 अपोलो टॉयर्स, हल्दवानी	2005-06 (भाग II)	टायर, ट्यूब, फ्लैप	40,94,609	12.5%	5,11,826	4,79,837	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वॉरण्टी क्लेम/फ्री रिप्लेसमेन्ट के कारण दावाकृत हानि को बिक्री समझा जाय ।
			2006-07		60,14,590		7,51,824	6,20,255	
			2007-08		80,01,190		10,00,149	6,75,101	
		मे0 श्री महालक्ष्मी ट्रेडिंग कं0, हल्दवानी	2007-08	हर्बल मेहंदी	89,525	12.5%	11,191	7,554	
4.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हल्दवानी	मे0 पूजा भण्डार, हल्दवानी	2007-08	परफ्यूम	79,033	12.5%	9,879	6,668	बिक्री का छुपाव
5.	स आ (क नि) वा क, नैनीताल	मे0 आईस लैण्ड, मल्लीताल, नैनीताल	2007-08	हाजमोला, आयुर्वेदिक उत्पाद	1,99,031	12.5%	24,879	16,793	
6.	स आ (क नि) खण्ड-I वा क, अल्मोड़ा	मे0 महालक्ष्मी ट्रेडर्स, अल्मोड़ा	2007-08	जनरल गुड्स	1,36,351	4%	5,454	3,681	

7.	स आ (क नि) खण्ड-II, ऋषिकेश	मे0 मोहन मोटर्स, ऋषिकेश	2007-08	मोटर पार्ट्स	15,31,291	12.5%	1,91,411	1,29,202	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार,वॉरण्टी क्लेम को बिक्री समझा जाय ।
			2008-09	तदैव	21,89,235	12.5%	2,73,654	1,43,668	तदैव
8.	स आ (क नि) वा क, किच्छा	मे0 एन एल डी के इन्टरप्राईजेज, किच्छा	2006-07	पेस्टीसाईड	3,19,077	4%	12,763	10,529	
9.	उ आ (क नि)-II, वा क देहरादून	मे0 ओबरॉय मोटर्स लि0, देहरादून	2004-05	मोटर पार्ट्स	42,14,534	12.5%	5,26,817	5,26,817	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार,वॉरण्टी क्लेम को बिक्री समझा जाय ।
			2006-07		19,54,763		2,44,345	2,01,585	
योग					**12,92,71,570**		**1,59,54,130**	**1,25,08,751**	

परिशिष्ट-3.5

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.14.1 पृष्ठ 142)

पलायित कराधेय कारोबार

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	सकल भुगतान (₹)	काटी गई मजदूरी प्रभार (₹)	कटौती योग्य वास्तविक मजदूरी प्रभार (₹)	कर निर्धारित किये गये कराधेय कारोबार (₹)	वास्तविक कराधेय कारोबार (₹)	पलायित कराधेय कारोबार (₹)	कर की दर	पलायित कारोबार पर कर (₹)	ब्याज (31.03.12 तक) (₹)	अभ्युक्तियां
1.	स आ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	मे0 मन्नू लाल एण्ड सन्स, देहरादून	2008-09	85,67,858	25,70,357	47,710	40,44,351	65,66,997	17,65,852 7,56,794	12.5% 4%	2,20,731 30,272	1,15,884 15,893	निर्धारिती द्वारा संलग्न विभाजन विवरण के आधार पर 70 % एवं 30 % के अनुपात में लिया गया है ।
		मे0 मन्नू लाल एण्ड सन्स, देहरादून	2009-10	1,59,35,944	47,80,783	11,04,456	70,98,669	1,07,74,997	25,73,430 11,02,898	12.5% 4%	3,21,679 44,116	1,20,630 16,543	तदैव
2.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हल्दवानी	मे0 आर के इन्जीनियर एण्ड कॉन्ट्रैक्टर, हल्दवानी	2005-06 (भाग II)	20,00,000	6,00,000	6,00,000	4,44,000	5,07,836	63,836	12.5%	7,979	7,480	अधिक वापसी ₹ 7,929 (₹ 24,500-₹ 16,521)
योग				2,65,03,802	79,51,140	17,52,166	1,15,87,020	1,78,49,830	62,62,810		**6,24,777**	**2,76,430**	

परिशिष्ट-3.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर 3.2.14.3 पृष्ठ 145)

ब्याज का कम जमा

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर की धनराशि (₹)	अवधि	देय ब्याज (₹)	जमा ब्याज (₹)	कमी (₹)	अभ्युक्तियां
1.	उ आ (क नि)-I, वा क देहरादून	मे0 पी सी एल इन्टरटेक, देहरादून	2008-09	8,20,846	41 माह एवं 09 दिन (01.10.2008 से 09.02.2012)	4,23,762	14,073	4,09,689	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।
2.	स आ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	मे0 सिटी सेन्टर, पल्टन बाजार, देहरादून	2007-08	1,17,221	43 माह एवं 10 दिन (01.10.2007 से 10.05.2011)	63,494	58,610	4,884	क नि प्रा ने 01.05.2008 से ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
		मे0 डिकोर इण्डिया, ई सी रोड, देहरादून	2006-07	1,01,863	59 माह एवं 01 दिन (01.10.2006 से 01.09.2011)	75,166	21,658	53,508	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।
3.	स आ (क नि) वा क, रामनगर	मे0 द कार्बट हाइडे, ढिकुली, रामनगर	2006-07	17,061	46 माह एवं 07 दिन (01.10.2006 से 07.08.10)	9,860	12	9,848	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
4.	स आ (क नि) खण्ड-I वा क, रुड़की	मे0 रुड़की इन्विपमेन्ट एण्ड मॉडल्स, अम्बर तालाब, रुड़की	2007-08	44,784	52 माह एवं 20 दिन (01.10.2007 से 20.02.2012)	29,483	3,360	26,123	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।
5.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, रुड़की	मे0 एस एस वॉयर प्रोडक्ट इण्डस्ट्रीज, रुड़की	2007-08	5,097	49 माह एवं 10 दिन (01.10.2007 से 10.11.11)	3,143	63	3,080	तदैव
6.	उ आ (क नि)-V, वा क देहरादून	सीमेन्ट ट्रेडर्स, विकास नगर, देहरादून	2007-08	26,576	43 माह एवं 03 दिन (01.10.07 से 03.05.11)	14,318	3,424	10,894	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
		निरुपति एल पी जी इण्डस्ट्रीज़ लि0, सेलाकुई, देहरादून	2007-08	2,54,220	45 माह एवं 28 दिन (01.10.07 से 28.07.11)	1,45,965	1,39,821	6,144	तदैव

		पण्डित सेवक राम राजा राम, विकास नगर, देहरादून	2007-08	2,387	42 माह एवं 12 दिन (01.10.07 से 12.04.11)	1,265	613	652	तदैव
7.	वा क अ (क नि) खण्ड-III वा क, देहरादून	मे0 स्नेहा ट्रेडर्स, 108/12-3, धरमपुर, देहरादून	2007-08	4,656	48 माह एवं 23 दिन (01.10.07 से 24.10.11)	2,838	344	2,494	क नि प्रा ने 01.11.2007 से ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
		मे0 शिवम मोटर्स, ए-158, नेहरू कालोनी, देहरादून	2007-08	6,479	46 माह एवं 24 दिन (01.10.2007 से 24.08.11)	3,790	281	3,509	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
8.	उ आ (क नि)-II, वा क हल्दवानी	मे0 टूडर इण्डिया लि0, हल्दवानी	2007-08	3,97,230	42 माह एवं 20 दिन (01.10.07 से 20.04.11)	2,11,856	2,01,050	10,806	तदैव
9.	वा क अ (क नि) खण्ड-III वा क, रूद्रपुर	मे0 साई इन्टरप्राईजेज, रूद्रपुर	2007-08	8,844	47 माह एवं 5 दिन (01.10.07 से 05.09.11)	5,214	4,425	789	क नि प्रा ने 01.05.2008 से ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
10.	स आ (क नि)/वा क अ (क नि) वा क, कोटद्वार	मे0 बाबा फरीद्दीन ग्रामोद्योग संस्थान, कोटद्वार	2006-07	53,569	55 माह एवं 19 दिन (01.10.06 से 19.05.11)	37,253	1,000	36,253	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
		मे0 राज ब्रदर्स, कोटद्वार	2007-08	6,024	43 माह एवं 29 दिन (01.10.07 से 29.05.11)	3,311	800	2,511	तदैव
		मे0 रावत एजेन्सी, कोटद्वार	2007-08	7,879	42 माह एवं 29 दिन (01.10.07 से 29.04.11)	4,231	1,169	3,062	तदैव
		मे0 महालक्ष्मी इन्टरप्राईजेज, कोटद्वार	2007-08	7,172	42 माह एवं 14 दिन (01.10.2007 से 14.04.11)	3,807	1,776	2,031	तदैव

	मे0 राजस्थान मार्बल स्टोर, कोटद्वार	2007-08	5,552	47 माह एवं 6 दिन (01.10.2007 से 06.09.11)	3,276	1,048	2,228	तदैव	
	मे0 आर के सेल्स कॉरपोरेशन, कोटद्वार	2007-08	21,955	43 माह एवं 18 दिन (01.10.07 से 18.05.11)	11,965	11,700	265	तदैव	
	मे0 ब्रह्मा देव अमित कुमार, कोटद्वार	2007-08	13,217	44 माह एवं 8 दिन (01.10.07 से 08.06.11)	7,313	4,822	2,491	तदैव	
	मे0 अम्बिका ग्रामोद्योग सन्स, सिताबपुर, कोटद्वार	2007-08	22,122	42 माह एवं 8 दिन (01.10.2007 से 08.04.2011)	11,688	6,704	4,984	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।	
	मे0 पी के ट्रेडर्स, कोटद्वार	2007-08	4,810	43 माह एवं 1 दिन (01.10.07 से 01.05.11)	2,587	2,540	47	तदैव	
	मे0 गढ़वाल स्टेशनरी, कोटद्वार	2007-08	6,073	47 माह एवं 6 दिन (01.10.07 से 06.09.11)	3,583	200	3,383	तदैव	
11.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, ऋषिकेश	मे0 होटल वसुन्धरा पैलेस, ऋषिकेश	2007-08	17,120	40 माह एवं 7 दिन (01.10.07 से 07.02.2011)	8,610	428	8,182	क नि प्रा ने 01.10.2007 से ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
योग				**19,72,757**		**10,87,778**	**4,79,921**	**6,07,857**	

ब्याज का गैर-जमा

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर की धनराशि (₹)	अवधि	कर जमा की तिथि	देय ब्याज (₹)	अभ्युक्तियां
1.	उ आ (क नि)-II, वा क, रूड़की	मे0 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, रूड़की	2007-08	3,04,525	53 माह 04 दिन (01.10.07 से 04.03.12)	05.03.2012	2,02,255	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
2.	स आ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	मे0 न्यू कैम इन्टरप्राईजेज, सुभाष रोड, देहरादून	2006-07	6,840	62 माह 28 दिन (01.10.06 से 28.12.11)	29.12.2011	5,381	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।
		मे0 पंजाब रेस्टूरेन्ट, राजपुर रोड, देहरादून	2007-08	23,837	48 माह 21 दिन (01.10.07 से 21.10.11)	22.10.2011	14,511	तदैव
		मे0 गुरजास कलेक्शन, राजपुर रोड, देहरादून	2009-10	11,037	26 माह 23 दिन (01.10.09 से 23.12.11)	24.12.2011	3,693	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
		मे0 अधिशासी अभियन्ता, सी पी डब्ल्यू डी, सेन्ट्रल सेक्टर-I, देहरादून	2007-08	12,19,479	47 माह 08 दिन (01.10.07 से 08.09.11)	09.09.2011	7,20,509	तदैव
		मे0 सिल्वरलाईन आटोमोबाईल, राजपुर रोड, देहरादून	2007-08	20,186	46 माह 17 दिन (01.10.07 से 17.08.11)	18.08.2001	11,750	क नि प्रा ने 01.05.2008 से ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
		मे0 सनराईज बेकर्स, घोसी गली, देहरादून	2006-07	27,317	45 माह 13 दिन (01.10.06 से 13.07.10)	14.07.2010	15,514	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
		मे0 सनराईज बेकर्स, घोसी गली, देहरादून	2007-08	61,734	55 माह 04 दिन (01.10.07 से 04.05.12)	05.05.2012	42,545	तदैव
	वा क अ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	प्रथम क्रिएशन, राजपुर रोड, देहरादून	2006-07	17,451	47 माह 12 दिन (01.10.06 से 12.09.10)	13.09.2010	10,339	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।
		मे0 प्रियन्का इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून	2006-07	3,413	46 माह 17 दिन (01.10.06 से 17.08.10)	18.08.2010	1,986	तदैव
3.	स आ (क नि) वा क, रामनगर	मे0 डे लाईट फर्नीचर एण्ड टिम्बर, रामनगर	2008-09	19,272	44 माह 29 दिन (01.10.08 से 29.06.12)	30.06.2012	10,832	तदैव

		मे0 एम आर हेल्थ केयर प्रा0 लि0, रामनगर	2009-10	17,779	25 माह 23 दिन (01.10.09 से 23.11.11)	24.11.2011	5,726	तदैव	
		मे0 भगवती मेटल्स, रामनगर	2008-09	2,227	43 माह 14 दिन (01.10.08 से 14.05.12)	15.05.2012	1,210	तदैव	
4.	वा क अ (क नि) खण्ड-I वा क, रुड़की	मे0 क्वालिटी इन्जीनियरिंग कार्पो0, पुरानी तहसील, रुड़की	2007-08	4,167	52 माह 01 दिन (01.10.07 से 01.02.12)	02.02.2012	2,710	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।	
5.	स आ (क नि)-II, वा क, रुड़की	मे0 आर सी केमिकल्स, देहरादून रोड, रुड़की	2007-08	678	49 माह 03 दिन (01.10.07 से 03.11.11)	04.11.11	416	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।	
		मे0 आर सी केमिकल्स, देहरादून रोड, रुड़की	2007-08	5586	49 माह 03 दिन (01.10.07 से 03.11.11)	04.11.11	3,428	तदैव	
6.	उ आ (क नि)-V वा क, देहरादून	मे0 सुधीर जनरल स्टोर, पलटन बाजार, देहरादून	2007-08	20,748	44 माह 07 दिन (01.10.07 से 07.06.11)	08.06.11	11,472	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।	
7.	वा क अ (क नि) खण्ड-II वा क, हल्दवानी	मे0 डिजीटल सॉल्यूशन, हल्दवानी	2007-08	4,381	49 माह 23 दिन (01.10.07 से 23.11.11)	24.11.11	2,725	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।	
	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हल्दवानी	मे0 पैशन इनकॉरपोरेशन, हल्दवानी	2007-08	14,885	47 माह 07 दिन (01.01.07 से 07.09.11)	08.09.11	8,788	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।	
8.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हरिद्वार	मे0 विशाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	2007-08	7,203	45 माह 28 दिन (01.10.07 से 28.07.11)	29.07.11	4,136	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।	
9.	वा क अ (क नि) खण्ड-I वा क, अल्मोड़ा	मे0 महेश एजेन्सीज, अल्मोड़ा	2007-08	32,458	11 माह	31.07.12	2,678	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।	
10.	वा क अ (क नि) खण्ड-III वा क, रुद्रपुर	मे0 रुद्रा इन्टरप्राईजेज	2007-08	11,330	46 माह 28 दिन (01.10.07 से 28.08.11)	29.08.11	6,647	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश नहीं दिया ।	
11.	स आ (क नि)/वा क अ (क नि) वा क, कोटद्वार	मे0 रीता पेन्सिल उद्योग, कोटद्वार	2007-08	8,234	42 माह 3 दिन (01.10.07 से 03.04.11)	04.04.11	4,333	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।	

	मे0 रोहित इन्टरप्राईजेज, कोटद्वार	2007-08	8,689	42 माह 26 दिन (01.10.07 से 26.04.11)	27.04.11	4,656	तदैव
	मे0 राम कुमार सवाल राम, कालागढ़	2007-08	15,752	46 माह (01.10.07 से 31.07.11)	01.08.11	9,057	तदैव
	मे0 कुकरेती मेडिकल ट्रेडर्स, कोटद्वार	2007-08	12,405	43 माह 19 दिन (01.10.07 से 19.05.11)	20.05.11	6,766	तदैव
	मे0 कुकरेती मेडिकल कं0, कोटद्वार	2005-06	11,404	67 माह 19 दिन (01.10.05 से 19.05.11)	20.05.11	9,641	तदैव
	मे0 इन्जा ऑयरन एण्ड बिल्डिंग मेटेरियल, कोटद्वार	2007-08	7,373	47 माह 15 दिन (01.10.07 से 15.09.11)	16.09.11	4,378	तदैव
	मे0 नारदा ट्रेडिंग कं0, कोटद्वार	2007-08	6,115	42 माह 7 दिन (01.10.07 से 07.04.11)	08.04.11	3,228	तदैव
	मे0 विशाल ट्रेडर्स, बेजरो, कोटद्वार	2007-08	5,459	42 माह 5 दिन (01.10.07 से 05.04.11)	06.04.11	2,877	तदैव
	मे0 जय दुर्गा आटा उद्योग, कोटद्वार	2007-08	3,683	49 माह 25 दिन (01.10.07 से 25.11.11)	26.11.11	2,294	तदैव
	मे0 नेगी ए-वन कार्ड बॉक्स मेकर, सतपुली	2007-08	2,760	43 माह 3 दिन (01.10.07 से 03.05.11)	04.05.11	1,487	तदैव
	मे0 जाहिद एण्ड सन्स, कोटद्वार	2007-08	10,276	44 माह 1 दिन (01.10.07 से 01.06.11)	02.06.11	5,656	तदैव
	मे0 चौहान ज्वैलर्स, कोटद्वार	2007-08	14,430	52 माह 1 दिन (01.10.07 से 01.02.12	02.02.11	9,386	तदैव
	मे0 अन्जली इन्टरप्राईजेज, कोटद्वार	2006-07	50,000 25,000	55 माह 11 दिन (01.10.06 से 11.05.11) 61 माह 13 दिन (01.10.06 से 13.11.11)	12.05.11 14.11.11	53,802	तदैव
	मे0 देवभूमि फ्लोर मिल, कोटद्वार	2007-08	13,989	46 माह 9 दिन (01.10.07 से 09.08.11)	10.08.11	8,096	तदैव
	मे0 सिद्धबली उद्योग, बलभद्रपुर	2007-08	7,202	49 माह 16 दिन (01.10.07 से 16.11.11)	17.11.11	4,459	तदैव

	मे0 ट्रैरिस्ट स्वीट शाप, कोटद्वार	2007-08	7,530	43 माह 17 दिन (01.10.07 से 17.05.11)	18.05.11	4,100	तदैव	
	मे0 शिव नारायण मल राम अग्रवार, कोटद्वार	2007-08	11,363	43 माह 17 दिन (01.10.07 से 17.05.11)	18.05.11	6,188	तदैव	
	मे0 गायत्री मेडिकल, कोटद्वार	2007-08	7,646	43 माह 8 दिन (01.10.07 से 08.05.11)	09.05.11	4,135	तदैव	
	मे0 श्री राम मार्बल ट्रेडर्स, कोटद्वार	2007-08	14,706	45 माह 21 दिन (01.10.07 से 21.07.11)	22.07.11	8,401	तदैव	
	मे0 शिव समृद्धि ट्रेडर्स, कोटद्वार	2007-08	4,202	49 माह 1 दिन (01.10.07 से 01.11.11)	02.11.11	2,575	तदैव	
12.	वा क अ (क नि) खण्ड-II वा क, ऋषिकेश	मे0 ऋषि जनरल स्टोर, ऋषिकेश	2008-09	2,002	45 माह 13 दिन (01.10.08 से 13.07.12)	14.07.12	1,137	क नि प्रा ने कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज जमा करने का आदेश दिया ।
योग				**20,86,753**		**12,45,903**		

परिशिष्ट-3.7

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.14.4 पृष्ठ 145)

आई टी सी का अनियमित लाभ

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष/माह	माल का विवरण	माल का मूल्य (₹)	कर की दर	दावाकृत/ स्वीकृत आई टी सी (₹)	अनुमन्य आई टी सी (₹)	अन्तर (₹)	अभ्युक्तियां
1.	उ आ (क नि)-I वा क, देहरादून	मे0 भारतीय खाद्य निगम, देहरादून	2005-06 (01.10.05 to 31.03.06)	चावल	38,44,235	4%	1,53,769	शून्य	1,53,769	पारगमन तथा भण्डारण हानि होने से आई टी सी अनुमन्य नहीं ।
2.	स आ (क नि) खण्ड-V वा क, देहरादून	मे0 ग्रैण्ड बेकरी, पलटन बाजार, देहरादून	2007-08	कच्ची सामग्री, पैकिंग मैटेरियल एवं यीस्ट	9,43,858 1,16,596	4% 12.5%	33,232	26,274	6,958	कुल बिक्री का 49.79% करमुक्त था ।
		मे0 ग्रैण्ड बेकरी, पलटन बाजार, देहरादून	2008-09	कच्ची सामग्री, पैकिंग मैटेरियल एवं यीस्ट ईंधन	5,33,902 3,85,337 90,338 1,51,409	4% 1% 12.5% 10.5% (12.5-2)	26,430	24,492	1,939	कुल बिक्री का 53.25% करमुक्त था ।
		मे0 ग्रैण्ड बेकरी, पलटन बाजार, देहरादून	2009-10	कच्ची सामग्री, पैकिंग मैटेरियल यीस्ट	3,90,326 1,24,953 89,906	4% 1% 12.5%	17,951	14,036	3,915	कुल बिक्री का 50.05% करमुक्त था ।
		मे0 सनराईज बेकर्स, घोसी गली, देहरादून	2006-07	कच्ची सामग्री, पैकिंग मैटेरियल एवं यीस्ट	19,41,106 6,87,974	4% 12.5%	1,43,486	1,08,690	34,796	कुल बिक्री का 33.58% करमुक्त था ।
		मे0 सनराईज बेकर्स, घोसी गली, देहरादून	2007-08	कच्ची सामग्री, पैकिंग मैटेरियल एवं यीस्ट	15,63,207 4,22,210	4% 12.5%	1,09,700	76,735	32,965	कुल बिक्री का 33.45% करमुक्त था ।

3.	उ आ (क नि)-V वा क, देहरादून	बहल एजेन्सी, राजपुर, देहरादून	2008-09	रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन	4,03,52,593 13,900	12.5% 4%	50,82,980	50,57,560	25,420	
		एलीगेन्ट ऑटो एसेसरीज़, सेलाकुई, देहरादून	2007-08	उपभोज्य माल	5,67,114	4%	22,685	शून्य	22,685	उपभोज्य माल पर 31.03.2008 तक आई टी सी अनुमन्य नहीं था।
4.	स आ (क नि) वा क, नैनीताल	मे0 प्रकाश नारायण नरेन्द्र कुमार, मल्लीताल, नैनीताल	2007-08 (04/2007 to 05/2007)	सिगरेट	55,21,224	करमुक्त	6,90,153	शून्य	6,90,153	माल करमुक्त होने से आई टी सी अनुमन्य नहीं ।
		मे0 रामा इन्टरप्राईजेज, मल्लीताल, नैनीताल	2007-08 (04/2007 to 05/2007)	तदैव	73,07,997	करमुक्त	9,13,500	शून्य	9,13,500	माल करमुक्त होने से आई टी सी अनुमन्य नहीं ।
5.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, हरिद्वार	मे0 ओम ट्रेडर्स, हरिद्वार	2007-08	सीमेन्ट	27,142	12.5%	3,393	शून्य	3,393	हानि पर आई टी सी प्रदान की गई थी ।
6.	स आ (क नि) खण्ड-I वा क, अल्मोड़ा	मे0 चन्द्र दत्त नन्द किशोर जोशी, अल्मोड़ा	2007-08 (04/2007 to 05/2007)	बीड़ी	33,69,339	करमुक्त	4,21,167	शून्य	4,21,167	आई टी सी @12.5% की दर से प्रदान की गई, यद्यपि माल करमुक्त थे ।
	वा क अ (क नि) खण्ड-I वा क, अल्मोड़ा	मे0 प्रकाश कलर लैब, अल्मोड़ा	2005-06 (द्वितीय भाग) 2006-07 2007-08	केमिकल	72,971 2,96,886 99,902	12.5%	9,121 37,111 12,488	शून्य	58,720	जॉब वर्क में उपभोगित माल पर आई टी सी प्रदान की गई ।
7.	वा क अ (क नि) खण्ड-III वा क, रूद्रपुर	मे0 अम्बिका आटोमोबाईल्स, रूद्रपुर	2007-08	ल्यूब्रिकेन्ट्स	24,025	20%	4,805	शून्य	4,805	ल्यूब्रिकेन्ट पर आई टी सी अनुमन्य नहीं, जैसा कि यह नि0 या आ0 में करयोग्य है ।
8.	स आ (क नि) वा क, किच्छा	मे0 चावला ट्रेडर्स, किच्छा	2007-08 (04/2007 to 05/2007)	सिगरेट	2,94,014	करमुक्त	36,752	शून्य	36,752	माल करमुक्त होने से आई टी सी अनुमन्य नहीं ।
9.	वा क अ (क नि) खण्ड-II वा क, ऋषिकेश	मे0 लक्ष्मी ट्रेडिंग कं0, ऋषिकेश	2007-08	सिगरेट	45,435	करमुक्त	5,679	शून्य	5,679	माल करमुक्त होने से आई टी सी अनुमन्य नहीं ।
	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, ऋषिकेश	मे0 पूनम स्टोर, ऋषिकेश	2007-08	सिगरेट	34,190	करमुक्त	4,274	शून्य	4,274	माल करमुक्त होने से आई टी सी अनुमन्य नहीं ।
योग					**6,93,12,089**		**77,28,677**	**53,07,787**	**24,20,891**	

परिशिष्ट-3.8

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.14.5 पृष्ठ 146)

प्रपत्र-XI का अनधिकृत निर्गमन

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि	माल का विवरण	माल का मूल्य (₹)	कर की दर	कर की अन्तरीय दर	कर की अन्तरीय धनराशि (₹)	ब्याज (31.03.12 तक) (₹)	अर्थदण्ड (₹)	अभ्युक्तियां
1.	उ आ (क नि)-I वा क, हरिद्वार	मे0 रेविन लाईफ साइंस प्रा0 लि0, सिडकुल, हरिद्वार	2007-08	24.01.07	कुर्सी, बुक शेल्फ, इलेक्ट्रिकल आईटम, इलेक्ट्रिक वस्तु	13,00,943	12.5%	8.5% (12.5-4)	1,10,580	74,642	5,20,377	माल, जिसके लिये प्रपत्र जारी किये गये, मान्यता प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं थे ।
2.	उ आ (क नि)-II वा क, काशीपुर	मे0 जिन्दल फ्रोजेन फूड्स प्रा0 लि0, काशीपुर	2008-09	18.08.04	मशीनरी पार्ट्स	1,23,316	8%	5.5% (8-2.5)	6,782	6,782	49,326	वर्ष 2004-05 हेतु प्रपत्र जारी किये गये थे (मान्यता तिथि के पूर्व) ।
3.	स आ (क नि) वा क, किच्छा	मे0 शील चन्द्र इण्डस्ट्रीज, लालपुर, किच्छा	2006-07	-	मशीनरी पार्ट्स एवं केमिकल	1,60,837	12.5%	8.5% (12.5-4)	13,671	11,279	64,335	माल, मान्यता प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं थे ।
योग						**15,85,096**	**-**	**-**	**1,31,033**	**92,703**	**6,34,038**	

परिशिष्ट-3.9

(सन्दर्भः प्रस्तर 3.2.14.5 पृष्ठ 146)

प्रपत्र-XI पर अनियमित रियायत

क्रम सं0	इकाई का नाम	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष (अवधि, जिसके लिये जारी)	प्रपत्र-XI संख्या	विभाग से जारी करने का वर्ष व तिथि	माल का विवरण	माल का मूल्य (कर सहित) (₹)	माल का मूल्य (कर रहित) (₹)	कर की अन्तरीय दर	कर का अन्तरीय धनराशि (₹)	ब्याज (31.03.12 तक) (₹)	अभ्युक्तियां
1.	उ आ (क नि)-I वा क, हरिद्वार	मे0 अरिहन्त इलेस्टोप्लास्ट (प्रा0) लि0, सिडकुल, हरिद्वार	2007-08	010720	2010-11 (30-11-10)	लगेज कम्पोनेन्ट	1,82,17,066	1,75,16,410	8.5% (12.5-4)	14,88,895	10,05,004	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
		मे0 हर्बल कान्सेप्ट्स हेल्थ केयर (प्रा0) लि0, हरिद्वार	2007-08	075411	2010-11 (06-09-10)	हेयर ऑयल/कास्मेटिक	3,12,173	3,00,166	8.5% (12.5-4)	25,514	17,222	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				075410	2010-11 (06-09-10)	हेयर ऑयल/कास्मेटिक	8,75,208	8,41,546	8.5% (12.5-4)	71,531	48,283	प्रपत्र समय सीमा के बाहर तथा ₹ 5 लाख से अधिक के लिये जारी किया गया।
				075409	2010-11 (06-09-10)	हेयर ऑयल/कास्मेटिक	15,08,966	14,50,928	8.5% (12.5-4)	1,23,329	83,247	प्रपत्र समय सीमा के बाहर तथा ₹ 5 लाख से अधिक के लिये जारी किया गया।
				075408	2010-11 (06-09-10)	हेयर ऑयल/कास्मेटिक	15,68,075	15,07,764	8.5% (12.5-4)	1,28,160	86,508	प्रपत्र समय सीमा के बाहर तथा ₹ 5 लाख से अधिक के लिये जारी किया गया ।

				075406	2010-11 (06-09-10)	हेयर ऑयल/कास्मेटिक	18,00,530	17,31,279	8.5% (12.5-4)	1,47,159	99,332	प्रपत्र समय सीमा के बाहर तथा ₹ 5 लाख से अधिक के लिये जारी किया गया ।
				075405	2010-11 (06-09-10)	हेयर ऑयल/कास्मेटिक	22,97,597	22,09,228	8.5% (12.5-4)	1,87,784	1,26,754	प्रपत्र समय सीमा के बाहर तथा ₹ 5 लाख से अधिक के लिये जारी किया गया ।
				075407	2010-11 (06-09-10)	हेयर ऑयल/कास्मेटिक	4,73,099	4,54,903	8.5% (12.5-4)	38,667	26,100	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
2.	उ आ (क नि)-II वा क, रुड़की	बिल केयर लि0, रुड़की	2008-09	048613	2011-12 (13-12-11)	अल्यूमीनियम फॉयल्स	97,774	95,857	2% (4-2)	1,917	1,006	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				048614	2011-12 (13-12-11)	अल्यूमीनियम फॉयल्स	3,51,888	3,44,988	2% (4-2)	6,900	3,622	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				048615	2011-12 (13-12-11)	अल्यूमीनियम फॉयल्स	2,62,348	2,57,204	2% (4-2)	5,144	2,701	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
3.	स आ (क नि) वा क, रामनगर	मे0 इण्डियन हर्ब्स इक्स्ट्रक्शन, रामनगर	2008-09	018850	2007-08 (19-03-08)	बर्बरिन हाइड्रोक्लोराइड	5,00,000	4,90,196	2% (4-2)	9,804	5,147	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				018851	2007-08 (19-03-08)	बर्बरिन हाइड्रोक्लोराइड	5,00,000	4,90,196	2% (4-2)	9,804	5,147	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				018852	2007-08 (19-03-08)	बर्बरिन हाइड्रोक्लोराइड	5,00,000	4,90,196	2% (4-2)	9,804	5,147	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				018853	2007-08 (19-03-08)	बर्बरिन हाइड्रोक्लोराइड	1,93,200	1,89,412	2% (4-2)	3,788	1,989	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।

			018854	2007-08 (19-03-08)	बबरिम हाइड्रोक्लोराइड	5,00,000	4,90,196	2% (4-2)	9,804	5,147	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
	वा क अ (क नि) वा क, रामनगर	मे0 इकराम स्क्रैप डीलर	249390	2011-12 (18-08-11)	एम एस स्क्रैप	-	91,800	2% (4-2)	1,836	964	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
			249391	2011-12 (18-08-11)	एम एस स्क्रैप	-	76,500	2% (4-2)	1,530	803	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
			249392	2011-12 (18-08-11)	एम एस स्क्रैप	-	57,600	2% (4-2)	1,152	605	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
		मे0 हाजी रईस एण्ड सन्स, मंगलौर रोड, भवानीगंज, रामनगर	249403	2011-12 (18-08-11)	एम एस स्क्रैप	-	66,000	2% (4-2)	1,320	693	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
		मे0 के जी एन स्क्रैप डीलर, रामनगर	255513	2011-12 (01-10-11)	एम एस स्क्रैप	67,830	66,500	2% (4-2)	1,330	698	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
			255514	2011-12 (01-10-11)	एम एस स्क्रैप	66,785	65,475	2% (4-2)	1310	688	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
4.	उ आ (क नि)-II वा क, काशीपुर	आई जी एल, काशीपुर	095100	2011-12 (27-08-11)	केमिकल	4,36,800 *(05/08)* 3,25,500 *(06/08 to 03/09)*	4,24,078 3,19,118	9.5% (12.5-3) 10.5% (12.5-2)	40,287 33,507	21,151 17,591	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
			095103	2011-12 (27-08-11)	केमिकल	9,79,200	9,60,000	10.5% (12.5-2)	1,00,800	52,920	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।

		2008-09	095101	2011-12 (27-08-11)	केमिकल	7,65,000	7,50,000	10.5% (12.5-2)	78,750	41,344	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
5.	उ आ (क नि)-II वा क, हल्दवानी	मे0 एन बी मिनरल कारपोरेशन, हल्दवानी	2008-09	084810	2011-12 (11-08-11)	रॉ मैनेसाईट	2,57,555	2,52,505	10.5% (12.5-2)	26,513	13,919	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
			2008-09	084811	2011-12 (11-08-11)	तदैव	3,54,871	3,47,913	10.5% (12.5-2)	36,531	19,179	तदैव
			2008-09	094649	2011-12 (25-08-11)	तदैव	5,00,555	4,85,976	9.5% (12.5-3)	46,168	24,238	तदैव
			2008-09	094650	2011-12 (25-08-11)	तदैव	5,71,411	5,54,768	9.5% (12.5-3)	52,703	27,669	तदैव
			2008-09	094651	2011-12 (25-08-11)	तदैव	3,97,891	3,90,089	10.5% (12.5-2)	40,959	21,503	तदैव
			2008-09	094652	2011-12 (25-08-11)	तदैव	4,92,669	4,83,009	10.5% (12.5-2)	50,716	26,626	तदैव
			2008-09	094653	2011-12 (25-08-11)	तदैव	4,52,528	4,43,655	10.5% (12.5-2)	46,584	24,457	तदैव
			2008-09	094654	2011-12 (25-08-11)	तदैव	7,54,303	7,39,513	10.5% (12.5-2)	77,649	40,766	तदैव
			2008-09	094655	2011-12 (25-08-11)	तदैव	4,35,253	4,26,719	10.5% (12.5-2)	44,805	23,523	तदैव
			2008-09	094790	2011-12 (15-09-11)	तदैव	-	2,47,584	10.5% (12.5-2)	25,996	13,648	तदैव
			2008-09	094791	2011-12 (15-09-11)	तदैव	-	2,84,853	10.5% (12.5-2)	29,910	15,703	तदैव
			2008-09	094792	2011-12 (15-09-11)	तदैव	-	4,91,564	10.5% (12.5-2)	51,614	27,097	तदैव
			2008-09	094793	2011-12 (15-09-11)	तदैव	-	4,12,941	10.5% (12.5-2)	43,359	22,763	तदैव
			2008-09	094794	2011-12 (15-09-11)	तदैव	-	3,73,931	10.5% (12.5-2)	39,263	20,613	तदैव
			2008-09	094795	2011-12 (15-09-11)	तदैव	-	4,58,703	10.5% (12.5-2)	48,164	25,286	तदैव

6.	वा क अ (क नि) खण्ड-II वा क, हल्द्वानी	मे0 कैमसिल्थ लैब, हल्द्वानी	2007-08	019917	2010-11 (22.07.10)	केमिकल	67,080	64,500	8.5% (12.5-4)	5,482	3,700	तदैव
				025455	2010-11 (09.02.11)	केमिकल	1,136	1,092	8.5% (12.5-4)	93	63	तदैव
7.	वा क अ (क नि) खण्ड-III वा क, रूद्रपुर	मे0 साई इन्टरप्राईजेज	2007-08	019334	2010-11 (07.04.10)	स्पे	-	9,984	8.5% (12.5-4)	849	66,062	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				019507	2010-11 (06.05.10)	ल्यूब्रीकेन्ट	-	2,57,797	16% (20-4)	41,248		
				019508	2010-11 (06.05.10)	ल्यूब्रीकेन्ट	-	3,48,584	16% (20-4)	55,773		
8.	स आ (क नि) वा क, किच्छा	मे0 निधि ग्रामोद्योग, किच्छा	2006-07	070708	2009-10 (09.03.10)	कोर	-	4,38,070	8.5% (12.5-4)	37,236	30,720	तदैव
				070709	2009-10 (09.03.10)	कोर	-	4,77,743	8.5% (12.5-4)	40,608	33,502	तदैव
				070710	2009-10 (09.03.10)	कोर	-	4,78,252	8.5% (12.5-4)	40,651	33,537	तदैव
				070711	2009-10 (09.03.10)	कोर	-	4,65,591	8.5% (12.5-4)	39,575	32,649	तदैव
				070712	2009-10 (09.03.10)	कोर	-	4,92,116	8.5% (12.5-4)	41,830	34,510	तदैव
				070598	2009-10 (06.02.10)	कोर वीनियर	-	1,01,774	8.5% (12.5-4)	8,651	7,137	तदैव
			2007-08	069104	2010-11 (21.09.10)	कोर	-	4,81,716	8.5% (12.5-4)	40,946	27,639	तदैव
				069105	2010-11 (21.09.10)	कोर	-	4,48,516	8.5% (12.5-4)	38,124	25,734	तदैव
				069106	2010-11 (21.09.10)	कोर	-	4,58,272	8.5% (12.5-4)	38,953	26,293	तदैव
				069107	2010-11 (21.09.10)	कोर	-	4,55,833	8.5% (12.5-4)	38,746	26,154	प्रपत्र समय सीमा के बाहर जारी किया गया ।
				069108	2010-11 (21.09.10)	कोर	-	4,99,771	8.5% (12.5-4)	42,481	28,675	तदैव

				069109	2010-11 (21.09.10)	कोर	-	4,71,528	8.5% (12.5-4)	40,080	27,054	तदैव
				069110	2010-11 (21.09.10)	कोर	-	4,14,742	8.5% (12.5-4)	35,253	23,796	तदैव
9.	स आ (क नि) खण्ड-II वा क, ऋषिकेश	मे0 गंगा पैकेजिंग, हरिद्वार रोड, ऋषिकेश	2008-09	004229	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,91,017	1% (4-3)	4,910	2,578	तदैव
				004230	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	89,743	1% (4-3)	897	471	तदैव
					2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	3,87,579	2% (4-2)	7,752	4,070	तदैव
				004231	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,98,236	2% (4-2)	9,965	5,232	तदैव
				004232	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,80,580	2% (4-2)	9,612	5,046	तदैव
				004233	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,82,134	2% (4-2)	9,642	5,062	तदैव
				004234	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,56,143	2% (4-2)	9,123	4,790	तदैव
				004235	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,95,784	2% (4-2)	9,916	5,206	तदैव
				004239	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,30,091	2% (4-2)	8,602	4,516	तदैव
				004240	2007-08 (22.11.07)	कोरुगैटेड बॉक्स	-	4,51,962	2% (4-2)	9,039	4,745	तदैव
योग								**4,87,60,413**		**38,56,798**	**24,75,744**	

परिशिष्ट- 4.1

(सन्दर्भः प्रस्तर 4.1.1 एवं 4.1.6, पृष्ठ 165 एवं 169)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम, जिनके लेखे पूर्ण कर लिए गए थे

(स्तम्भ 5 (अ) से 6 एवं 8 से 10 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्व लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव[1]	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि(-)	नियोजित पूँजी[2]	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[3]	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व हमस से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	हमस	शुद्व लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													(5b +5d)	11/10
कृषि एवं समवर्गी														
1.	उत्तराखण्ड सीड़ एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2010-11	2011-12	4.28	1.08	0.70	2.50	105.76	गैर समीक्षा	4.08	8.43	50.50	3.58	7.09%
क्षेत्रवार योग				4.28	1.08	0.70	2.50	105.76		4.08	8.43	50.50	3.58	**7.09%**
वित्त														
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1993-94	2012-13	0.10	0.03	-	0.07	0.54	(-) 0.39	0.50	(-) 0.63	1.09	0.10	9.17%

[1] लेखा टिप्पणियो के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं नि म ले की टिप्पणियों का शुद्व प्रभाव शामिल हैं और लाभ में वृद्धि तथा हानि में कमी को (+) से तथा लाभ में कमी तथा हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।

[2] वित्तीय कम्पनियों/निगमों के प्रकरण में जहाँ नियोजित पूँजी की गणना प्रदत्त पूँजी, मुक्त निधि, बंधपत्र, जमा तथा उधारी (पुनः वित्त पोषक सम्मिलित) के अन्तिम तथा शुरूआती शेषों के औसत के रूप में की जाती है, को छोड़कर नियोजित पूँजी शुद्व स्थायी सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य प्रगति सम्मलित है) जमा कार्यरत पूँजी को दर्शाती है।

[3] नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना लाभ - हानि खाते के लाभ और ब्याज को जोड़कर की गई है।

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्व लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+) /हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रमस से पूर्व शुद्ध लाभ / हानि	ब्याज	ह्रमस	शुद्व लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक)	1986-87	2002-03	(-) 0.02	-	-	(-) 0.02	0.10	-	0.50	(-) 0.04	0.46	(-) 0.02	-
4.	उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2011-12	0.19	0.34	0.04	(-) 0.19	-		3.91	(-) 0.04	27.10	0.15	0.55%
क्षेत्रवार योग				**0.27**	**0.37**	**0.04**	**(-) 0.14**	**0.64**	**(-)0.39**	**4.91**	**(-) 0.71**	**28.65**	**0.23**	**0.80%**
अवसंरचना														
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2009-10	2011-12	34.06	0.48	0.20	33.38	8.13	(-) 0.92	28.50	205.15	242.15	33.86	13.98
6.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड[4]	2009-10	2012-13	(-) 1.65	-	0.04	(-) 1.69	1.17	(-) 0.01	3.00	(-) 2.36	0.61	(-) 1.69	-
क्षेत्रवार योग				**32.41**	**0.48**	**0.24**	**31.69**	**9.30**	**(-) 0.93**	**31.50**	**202.79**	**242.76**	**32.17**	**13.25%**
विनिर्माण														
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1999-2000	2002-03	(-) 0.84	-	-	(-) 0.84	2.80	-	1.63	(-) 5.80	2.90	(-) 0.84	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लि0 (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1996-97	1997-98	(-) 1.19	-	-	(-) 1.19	0.29	-	0.35	(-) 6.95	0.35	(-) 1.19	-

[4] कम्पनी मार्च 2008 में निगमित हुई और इसके प्रथम लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्ध लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व हमस से पूर्व शुद्ध लाभ / हानि	ब्याज	हमस	शुद्ध लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लिमिटेड फार्मली लॉर्डन इलैक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्री लि0 (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	2000-01	2008-09	0.01	-	-	0.01	0.05	0.72	3.25	(-) 0.14	8.25	0.01	0.12%
10.	उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0	1997-98	2011-12	(-) 0.29	-	0.02	(-) 0.31	1.61	(-)4.42	8.95	(-) 1.17	4.99	(-) 0.31	-
11.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12	(-) 4.30	9.17	0.32	(-) 13.79	49.25	गैर समीक्षा	17.99	(-) 59.18	77.69	(-) 4.62	
12.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2011-12	(-) 4.22	11.72	0.27	(-) 16.21	48.40	गैर समीक्षा	6.00	(-) 94.89	40.03	(-) 4.49	
क्षेत्रवार योग				**(-) 10.83**	**20.89**	**0.61**	**(-) 32.33**	**102.40**	**(-)3.70**	**38.17**	**(-) 168.13**	**134.21**	**(-)11.44**	
ऊर्जा														
13.	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2009-10	2011-12	(-) 357.46	76.60	93.42	(-) 527.48	1935.75	(-) 77.95	5.00	(-) 1743.76	1758.40	(-) 450.88	-
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	237.83	150.33	70.27	17.23	531.68	(-) 15.96	624.18	169.51	2995.34	167.56	5.59%

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें पूर्ण किए गए	शुद्व लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रास से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्व लाभ / हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2010-11	2012-13	40.64	30.57	19.57	(-) 9.50	101.74	(-) 6.40	177.09	(-) 96.86	821.63	21.07	2.56%
क्षेत्रवार योग				**(-) 78.99**	**257.50**	**183.26**	**(-) 519.75**	**2569.17**	**(-)100.31**	**806.27**	**(-) 1671.11**	**5575.37**	**(-)262.25**	
सेवाएं														
16.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2002-03	2010-11	2.31	1.05	0.30	0.96	105.67	(-) 0.04	13.42	0.07	29.50	2.01	6.81%
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2010-11	4.22	1.71	1.51	1.00	61.64	(-) 0.04	5.76	(-) 7.75	(-)30.13	2.71	-
क्षेत्रवार योग				6.53	2.76	1.81	1.96	167.31	(-) 0.08	19.18	(-)7.68	(-) 0.63	4.72	
प्रकीर्ण														
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	2009-10	2011-12	5.66	-	0.09	5.57	77.20	गैर समीक्षा	0.05	19.08	19.97	5.57	27.89%
क्षेत्रवार योग				**5.66**		**0.09**	**5.57**	**77.20**		**0.05**	**19.08**	**19.97**	**5.57**	**27.89%**
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**(-)40.67**	**283.08**	**186.75**	**(-) 510.50**	**3031.78**	**(-) 105.41**	**904.16**	**(-) 1617.33**	**6050.83**	**(-) 227.42**	
ख. कार्यरत सविधिक निगम														

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्व लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+) /हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रमस से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रमस	शुद्व लाभ /हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
अवसंरचना														
1.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम	2010-11	2012-13	(-)31.19	5.56	0.83	(-) 37.58	38.01	(-) 24.11	2253.82	(-) 51.35	1675.74	(-) 32.03	-
क्षेत्रवार योग				**(-)31.19**	**5.56**	**0.83**	**(-) 37.58**	**38.01**	**(-) 24.11**	**2253.82**	**(-) 51.35**	**1675.74**	(-) 32.03	**-**
सेवा														
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2008-09	2010-11	0.10	-	14.77	(-) 14.67	188.81	(-) 0.56	79.74	(-) 237.22	(-) 35.14	(-) 14.67	-
क्षेत्रवार योग				**0.10**	**-**	**14.77**	**(-) 14.67**	**188.81**	**(-) 0.56**	**79.74**	**(-) 237.22**	**(-) 35.14**	**(-) 14.67**	**-**
योग 'ख' (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**(-)31.09**	**5.56**	**15.60**	**(-) 52.25**	**226.82**	**(-) 24.67**	**2333.56**	**(-) 288.57**	**1640.60**	**(-) 46.70**	**-**
कुल योग (क + ख)				**(-)71.76**	**288.64**	**202.35**	**(-)562.75**	**3258.60**	**(-)130.08**	**3237.72**	**(-)1905.90**	**7691.43**	**(-) 274.12**	
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्ती														
1.	यू.पी.ए.आई. लिमिटेड[5]	1988-89	1999-2000	(-) 0.01	-	-	(-) 0.01	-	-	0.17	(-) 0.05	0.10	(-) 0.01	-

[5] दिनांक 31.03.1991 से कम्पनी परिसमापन में है।

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	लेखे की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण किए गए	शुद्व लाभ (+)/हानि (-)				कुल कारोबार	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव	प्रदत पूँजी	संचित लाभ (+) / हानि (-)	नियोजित पूँजी	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का *प्रतिशत*
				ब्याज व ह्रमस से पूर्व शुद्व लाभ/हानि	ब्याज	ह्रमस	शुद्व लाभ/ हानि							
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क्षेत्रवार योग				**(-) 0.01**	**-**	**-**	**(-) 0.01**	**-**	**-**	**0.17**	**(-) 0.05**	**0.10**	**(-) 0.01**	**-**
विनिर्माण														
2.	कुम्ट्रौन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1989-90	1990-91	(-) 0.02	-	-	(-) 0.02	-	-	0.18	(-) 0.02	0.12	(-) 0.02	-
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड(उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की सहायक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज़ लि0 (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की सहायक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**(-) 0.02**			**(-) 0.02**			**0.18**	**(-) 0.02**	**0.12**	**(-) 0.02**	
योग ग. (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**(-) 0.03**			**(-) 0.03**			**0.35**	**(-) 0.07**	**0.22**	**(-) 0.03**	
कुल योग (क +ख +ग)				**(-)71.79**	**288.64**	**202.35**	**(-)562.78**	**3258.60**	**(-)130.08**	**3238.07**	**(-) 1905.97**	**7691.65**	**(-) 274.15**	

परिशिष्ट– 4.2

(सन्दर्भः प्रस्तर 4.1.3 पृष्ठ 166)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से संबधित, 31 मार्च 2012 को अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋणों एवं जन शक्ति को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 5 (अ) से 6 (द) के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी[6]				2011-12 के अंत में बकाया ऋण[7]				2011-12 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्त्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एंव तराई डेवलपमैन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड[8]	कृषि	फरवरी 1969	1.70	0.84	3.77	6.31	7.00	-	-	7.00	1.11:1 (1.35:1)	536
क्षेत्रवार योग				**1.70**	**0.84**	**3.77**	**6.31**	**7.00**	**-**	**-**	**7.00**	**1.11:1**	**536**

[6] प्रदत्त पूँजी में आवेदित अंश पूँजी सम्मिलित है।

[7] वर्ष 2010-11 के बकाया ऋण में दीर्घावधि ऋण को प्रर्दशित करता है।

[8] उपरोक्त में 619 - ब की कम्पनी सम्मिलित है जो कि क्रम संख्या - 01 है।

क्र. स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2011-12 के अंत में बकाया ऋण				2011-12 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्त्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
वित्त													
2.	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	जून 1974	0.20	-	0.30	0.50	1.17	0.04	1.64	2.85	5.7:1 (5.3:1)	21
3.	कुमाँऊ अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम की सहायक)	पर्वतीय विकास	जून 1975	0.22	-	0.28	0.50	-	-	-	-	-	NIL
4.	उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	अक्टूबर 2001	13.12	3.88	-	17.00	-	-	-	-	- (0.12:1)	83
क्षेत्रवार योग				**13.54**	**3.88**	**0.58**	**18.00**	**1.17**	**0.04**	**1.64**	**2.85**	**0.16:1**	**104**
अवसंरचना													
5.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	वित्त	जुलाई 2002	26.00	-	2.50	28.50	6.00	-	-	6.00	0.21:1 (0.21:1)	18

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2011-12 के अंत में बकाया ऋण				2011-12 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्त्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
6.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	वित्त	मार्च 2008	4.00	-	-	4.00	2.00	-	-	2.00	0.50:1 (0.67:1)	51
क्षेत्रवार योग				**30.00**	**-**	**2.50**	**32.50**	**8.00**	**-**	**-**	**8.00**	**0.25:1**	**69**
विनिर्माण													
7.	ट्रांस केबल्स लिमिटेड (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	नवम्बर 1973	-	-	1.63	1.63	2.75			2.75	1.69:1 (1.69:1)	-
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लि0 (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	मार्च 1978	-	-	0.35	0.35	-	-	-	-	- (20.80:1)	78

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2011-12 के अंत में बकाया ऋण				2011-12 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्त्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
9.	उत्तराखण्ड चाय विकास निगम लिमिटेड फार्मली नॉरर्दन इलैक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इन्डस्ट्री लि0 (कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विकास	जनवरी 1974	-	-	3.25	3.25	-	-	-	-	-	-
10.	उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 (यू.पी.हि.इ.लि)	पर्वतीय विकास	जून 1985	8.95	-	-	8.95	-	-	-	-	-	105
11.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	फरवरी 1972	17.54	-	0.45	17.99	33.77	-	-	33.77	1.88:1 (2.06:1)	569
12.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	चीनी एवं गन्ना विकास	दिसम्बर 2001	6.00	-	-	6.00	52.42	-	3.15	55.57	9.26:1 (8.54:1)	638
क्षेत्रवार योग				**32.49**	**-**	**5.68**	**38.17**	**88.94**	**-**	**3.15**	**92.09**	**2.41:1**	**1390**

ऊर्जा												
13.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	फरवरी 2001	577.00	-	-	577.00	509.72	311.28	127.10	948.10	1.64:1 (1.11:1)	4087
14.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	फरवरी 2001	805.46	-	-	805.46	188.99	2.80	909.89	1101.68	1.37:1 (1.48:1)	2365
15.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	ऊर्जा	मई 2004	227.41	-	-	227.41	109.16	-	403.50	512.66	2.25:1 (2.62:1)	973
क्षेत्रवार योग				**1609.87**	**-**	**-**	**1609.87**	**807.87**	**314.08**	**1440.49**	**2562.44**	**1.59:1**	**7425**
सेवाएं													
16.	कुमाँऊ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 1971	13.42	-	-	13.42	41.39	-	-	41.39	3.08:1	1027
17.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड	पर्वतीय विकास	मार्च 1976	6.80	-	-	6.80	42.19	-	-	42.19	6.20:1 (0.63:1)	720
क्षेत्रवार योग				**20.22**	**-**	**-**	**20.22**	**83.58**	**-**	**-**	**83.58**	**4.13:1**	**1747**
प्रकीर्ण													
18.	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड	सैनिक कल्याण	मार्च 2004	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2011-12 के अंत में बकाया ऋण				2011-12 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्त्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
क्षेत्रवार योग				**1.00**	**-**	**-**	**1.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
योग क (सभी क्षेत्रवार-कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**1708.82**	**4.72**	**12.53**	**1726.07**	**996.56**	**314.12**	**1445.28**	**2755.96**	**1.60:1**	**11271**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
अवसंरचना													
1.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	पेयजल	नवम्बर 2002	2031.85	-	-	2031.85	-	-	1.64	1.64	0.001:1	2878
क्षेत्रवार योग				**2031.85**	**-**	**-**	**2031.85**	**-**	**-**	**1.64**	**1.64**	**-**	**2878**

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2011-12 के अंत में बकाया ऋण				2011-12 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्त्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
सेवा													
2.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	यातायात	अक्टूबर 2003	70.50	9.24	-	79.74	125.52	-	-	125.52	1.57:1 (1.57:1)	4180
क्षेत्रवार योग				**70.50**	**9.24**	**-**	**79.74**	**125.52**	**-**	**-**	**125.52**	**1.57:1**	**4180**
योग ब (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				**2102.35**	**9.24**	**-**	**2111.59**	**125.52**	**-**	**1.64**	**127.16**	**0.06:1**	**7058**
कुल योग (क + ख)				**3811.17**	**13.96**	**12.53**	**3837.66**	**1122.08**	**314.12**	**1446.92**	**2883.12**	**0.75:1**	**18329**
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	यू.पी.ए.आई. लिमिटेड	कृषि	अप्रैल 1977	0.15	-	0.02	0.17	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**0.15**	**-**	**0.02**	**0.17**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
विनिर्माण													
2.	कुम्ट्रौन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	पर्वतीय विभाग	अप्रैल 1987	-	-	0.18	0.18	-	-	-	-	-	
3.	उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की सहायक)	पर्वतीय विभाग	जुलाई 1987	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी				2011-12 के अंत में बकाया ऋण				2011-12 का ऋण इक्विटी अनुपात (पूर्ववर्त्ती वर्ष)	जनशक्ति (कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)	(7)	(8)
4.	उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टर्ज़ लि0 (उत्तर प्रदेश हिल्स इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की सहायक)	पर्वतीय विभाग	जुलाई 1989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				**-**	**-**	**0.21**	**0.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
योग 'ग' (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				**0.15**	**-**	**0.23**	**0.38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल योग (क +ख +ग)				**3811.32**	**13.96**	**12.76**	**3838.04**	**1122.08**	**314.12**	**1446.92**	**2883.12**	**0.75:1**	**18329**

परिशिष्ट- 4.3

(सन्दर्भः प्रस्तर 4.1.4 पृष्ठ 167)

मार्च 2012 के अन्त में वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान व उपदान, प्राप्त प्रत्याभूतियाँ, बकायों की माफी, ऋण अपलेखन एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण तथा गारन्टी वचनबद्वता को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 3 (अ) से 6 (द) के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट से बाहर इक्विटी /ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारन्टी और वर्ष के अन्त में उसकी वचनबद्वता[9]		वर्ष में बकायों की माफी			कुल
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	ऋण/पुनर्भुगतान अपलेखन	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/ दंडात्मक ब्याज माफी	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	5(अ)	5(ब)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
(अ) कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
1.	उत्तराखण्ड सीड्स एंव तराई डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-	-	-	2.54	8.81	11.35	-	-	-	-	-	-
2.	उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	1.22	1.35	-	4.84	-	4.84	1.35	12.49	-	-	-	-
3.	स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लिमिटेड	-	-	59.62	-	-	59.62	-	-	-	-	-	-
4.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	-	299.16	-	0.14	-	0.14	-	250.00	-	-	-	-

[9] आँकड़े वर्ष के अन्त में कुल बकाया गारन्टी को दर्शाते हैं।

क्र.स.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	वर्ष के दौरान बजट से बाहर इक्विटी /ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान एवं उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारन्टी और वर्ष के अन्त में उसकी वचनबद्वता[10]		वर्ष में बकायों की माफी			कुल
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	वचनबद्धता	ऋण/पुनर्भुगतान अपलेखन	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	ब्याज/ दंडात्मक ब्याज माफी	
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	5(अ)	5(ब)	6(अ)	6(ब)	6(स)	6(द)
(अ) कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
5.	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	3.67	53.08	-	-	-	-	-	846.91	-	-	-	-
6.	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	38.11	-	-	-	-	-	-	0.95	-	-	-	-
7.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड[11]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	डोईवाला शुगर कम्पनी	-	4.32	-	0.28	-	0.28	-	-	-	-	-	-
9.	किच्छा शुगर मिल्स	-	-	-	-	-	-		0.55	-	-	-	-
योग (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)		**44.00**	**357.91**	**59.62**	**7.80**	**8.81**	**76.23**	**1.35**	**1110.90**				
ख. कार्यरत सांविधिक निगम													
उत्तराखण्ड परिवहन निगम		-	**100.11**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (अ+ ब)		**44.00**	**458.02**	**59.62**	**7.80**	**8.81**	**76.23**	**1.35**	**1110.90**	**-**	**-**	**-**	**-**

[10] आँकड़े वर्ष के अन्त में कुल बकाया गारन्टी को दर्शाते हैं।

[11] कम्पनी मार्च 2008 में निगमित हुई और इसके प्रथम लेखे अभी प्राप्त नही हुए हैं।

परिशिष्ट - 4.4

(सन्दर्भः प्रस्तर 4.1.7 पृष्ठ 171)

राज्य सरकार द्वारा कम्पनियो में किया गया निवेश जिनके लेखे 30 सितम्बर 2012 तक अन्तिमीकृत हुए को दर्शाती विवरणी

(स्तम्भ 4 एवं 6 से 8 के आँकड़े ₹ करोड़ में)

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	अन्तिमीकरण के लिए लम्बित लेखाओं की अवधि	जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश			
					अंश पूंजी	ऋण	अनूदान	अन्य का उल्लेख (उपदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ								
1.	उत्तराखण्ड सीडस एवं तराई डेवलेपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2010-11	4.08	2011-12	-	-	-	11.35
2.	उत्तराखण्ड बहुद्देशीय वित्त एंव विकास निगम लिमिटेड	2003-04	3.91	2004-05	2.29	-	-	
				2005-06	0.76	-	-	
				2006-07	4.22	-	-	
				2007-08	1.22	-	-	
				2008-09	-	-	0.09	
				2009-10	0.05	-	0.29	
				2010-11	-	-	7.45	
				2011-12	1.22	1.35	3.36	1.48
3.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	28.50	2010-11	-	-	10.22	-
				2011-12	-	-	-	59.62

क्र. स.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष जहाँ तक लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	लेखाओं को अन्तिम रूप देने की बकाया अवधि	जिनके लेखे बकाया थे उन पर राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश			
					अंश पूंजी	ऋण	अनूदान	अन्य का उल्लेख (उपदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.	उत्तराखण्ड स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	3.00	2010-11	-	2.00	-	
				2011-12	1.00	-		
5.	डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड	2010-11	6.00	2011-12	-	4.32	-	0.28
6.	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	5.00	2010-11	572.00	162.42	-	-
				2011-12	-	299.16	0.14	-
7	उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड	2010-11	624.17	2011-12	3.67	53.08	-	-
8	पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड	2010-11	177.09	2011-12	38.11	-	-	-
योग क. (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)			**851.67**		**624.54**	**522.33**	**21.55**	**72.73**
ख. कार्यरत सांविधिक निगम				वर्ष 2011-12 के दौरान उपयोग किया गया ऋण				
उत्तराखण्ड परिवहन निगम		**2008-09**	**79.74**	**2009-10**	-	-	-	-
				2010-11	-	-	-	-
				2011-12	-	**100.11**	-	-

परिशिष्ट 4.5

(सन्दर्भ प्रस्तर 4.2.8.2; पृष्ठ 184)

2007-08 से 2011-12 के दौरान ई एच टी स्तर पर पारेषण क्षमता को दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अ. उपकेन्द्रों की संख्या							
1	वर्ष के शुरू में	30	32	32	33	34	30
2	वर्ष में वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष में की गयी वृद्धि	2	-	1	1	1	5
4	वर्ष के अन्त में कुल उपकेन्द्रों का योग (1+3)	32	32	33	34	35	35
ब. ट्रान्सफॉर्मरों की क्षमता (एम वी ए)							
1	वर्ष के शुरू में क्षमता	4390.50	4550.50	4550.50	4590.50	4630.50	4390.50
2	वर्ष में वृद्धि/बढोत्तरी का लक्ष्य	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष में की गई क्षमता वृद्धि	160	-	40	40	360	600.00
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	4550.50	4550.50	4590.50	4630.50	4990.50	4990.50
स. पारेषण लाइने (सी के एम)							
1	वर्ष के शुरू में	1894	1992.8	1992.8	2168.5	2268.5	1894
2	वर्ष में वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-	-
3	वर्ष में की गई वृद्धि	98.80	-	175.70	100	50.70	425.20
4	वर्ष के अन्त में लाइनों की कुल संख्या (1+3)	1992.8	1992.8	2168.5	2268.5	2319.2	2319.20

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

परिशिष्ट 4.6

(सन्दर्भ प्रस्तर 4.2.8.2; पृष्ठ 184)

पिछले पाँच वर्षो के दौरान 2011-12 तक वोल्टेज वार क्षमता, वृद्धि लक्ष्य; वास्तविक वृद्धि व कमी को दर्शानेवाला विवरण

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
400 के वी एस एज (संख्याओं में)						
1	वर्ष के शुरू में	2	2	2	2	2
2	वर्ष में वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	-	-	-	-	-
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	2	2	2	2	2
5	वृद्धि में कमी (2-3)					
400 के वी ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता (एम वी ए)						
1	वर्ष के शुरू में	1110	1110	1110	1110	1110
2	वर्ष में वृद्धि/बढ़ोत्तरी का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	-	-	-	-	-
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	1110	1110	1110	1110	1110
5	वृद्धि/बढ़ोत्तरी में कमी (2-3)	-	-	-	-	-
400 के वी लाईन (सी के एम)						
1	वर्ष के शुरू में	172	172	172	172	172
2	वर्ष के लिए वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	-	-	-	-	-
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	172	172	172	172	172
5	वृद्धि में कमी (2-3)	-	-	-	-	-
220 के वी एस एज (संख्याओं में)						
1	वर्ष के शुरू में	6	6	6	6	6
2	वर्ष में वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	-	-	-	-	1
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	6	6	6	6	7
5	वृद्धि में कमी (2-3)					
220 के वी ट्रासफार्मरों की क्षमता (एम वी ए)						
1	वर्ष के शुरू में	1730	1730	1730	1730	1730
2	वर्ष में वृद्धि/बढ़ोत्तरी का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	-	-	-	-	200
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	1730	1730	1730	1730	1930
5	वृद्धि/बढ़ोत्तरी में कमी (2-3)	-	-	-	-	-

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
220 के वी लाईन (सी के एम)						
1	वर्ष के शुरू में	545	545	545	659	759
2	वर्ष के लिए वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	-	-	114	100	38
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	545	545	659	759	797
5	वृद्धि में कमी (2-3)					
132 के वी एस एसज (संख्याओं में)						
1	वर्ष के शुरू में	22	24	24	25	26
2	वर्ष में वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	2	-	1	1	-
4	वर्ष के अन्त में (1+3)	24	24	25	26	26
5	वृद्धि में कमी (2-3)					
132 के वी ट्रासफार्मरों की क्षमता (एम वी ए)						
1	वर्ष के शुरू में	1550.50	1710.50	1710.50	1750.50	1790.50
2	वर्ष में वृद्धि/बढ़ोत्तरी का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	160	-	40	40	160
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	1710.50	1710.50	1750.50	1790.50	1950.50
5	वृद्धि/बढ़ोत्तरी में कमी (2-3)					
132 के वी लाईन (सी के एम)						
1	वर्ष के शुरू में	1177	1275.8	1275.8	1337.5	1350.2
2	वर्ष के लिए वृद्धि का लक्ष्य	-	-	-	-	-
3	वर्ष के दौरान वास्तविक वृद्धि	98.80	-	61.70	12.70	-
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	1275.80	1275.80	1337.50	1350.20	1350.20
5	वृद्धि में कमी (2-3)					

परिशिष्ट 4.7

(सन्दर्भ प्रस्तर 4.2.9.1;पृष्ठ 186)

2007-12 के दौरान पारेषण लाइनों के कार्य सम्पादन अधिनिर्णत में देरी को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड में)

क्षमता के वी में	लाईनो का नाम	पूर्ण होने की तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि (समय वृद्धि)	अधिनिर्णित लागत	वास्तविक लागत (लागत वृद्धि)	समय एवं लागत वृद्धि का कारण
220	मनेरीभाली - II ऋषिकेश (80.40 सी के एम)	नवम्बर 2005	अप्रैल 2009 (40 माह)	17.12	52.65 (35.53)	कम्पनी ने वन भूमि प्रकरण की प्रक्रिया को देरी से शुरू किया और वन भूमि की रूकावट को हटाने की निर्धारित आवश्यकता में अधिक समय लगा।
220	डी सी घुतू घनसाली (2 x 19.38 सी के एम)	जनवरी 2010	अक्टूबर 2011 (20 माह)	18.77	20.48 (1.71)	इस लाइन के टावर का डिजाइन कम्पनी ने बनाया था और आवश्यक टाईप टैस्ट, टैस्टिंग बेड़ की अनुपलब्धता से, टाईप टेस्ट में देरी हुई। प्रथम टेस्ट के दौरान टावर असफल हो गया और उसका डिजाइन बदला गया और दोबारा टेस्ट किया गया। राईट ऑफ वे (आर ओ डब्लू) की समस्याओं और गैलरी से पेड़ न काटे जाने के परिणामस्वरूप प्रक्रिया में अवरूद्धता और कार्य में देरी हुई।
220	घनसाली-चम्बा (35 सी के एम)	अगस्त 2008	सितम्बर 2009 (11 माह)	20.73	17.87	वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में कम्पनी द्वारा अधिक समय लेने तथा ठेकेदार का साफ रास्ता (आर ओ डब्ल्यू) देने में विलम्ब के कारण।
132	सतपुली-कोटद्वार (46.70 सी के एम)	मई 2009	जनवरी 2010 (आठ माह)	16.04	49.91 (33.87)	वन भूमि रूकावट की आवश्यक प्रक्रिया को हटाने की प्राप्ति और वन भूमि गैलरी से पेड़ों के कटान में कम्पनी ने अधिक समय लिया।

परिशिष्ट 4.8

(सन्दर्भ प्रस्तर 4.2.9.4; पृष्ठ 188)

कम्पनी की उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना (यू आई टी पी) की योजना को दर्शाने वाला विवरण

उत्पादन योजना	पारेषण कार्य	सी के एम /क्षमता	वर्ष 2004 के चौथी तिमाही के अनुसार प्राक्कलित लागत		वर्ष 2004 के दूसरी तिमाही के अनुसार प्राक्कलित लागत	लक्ष्य
			एम यूज डालर में	₹ करोड में		
(I) यमुना बेसीन						
आराकोट (72 एम डब्लू) तुनीपलासू (42 एम डब्लू) हनोल तुनी (45 एम डब्लू) मोरी हनोल (63 एम डब्लू)	220 के वी डी सी मोरी-नागोन- खोदरी लाइन	2x100	18.60	80.00	175.00	2010-11
	220 के वी डी सी आराकोट त्यूनी-मोरी लाइन	2x40	7.45	32.00	50.00	2010-11
	220 के वी आराकोट त्यूनी-मोरी लाइन, त्यूनी प्लासू का लीलो	2x2	0.37	1.60	2.50	2010-11
	220 के वी आराकोट त्यूनी-मोरी लाइन, हनोल त्यूनी का लीलो	2x3	0.56	2.40	3.75	2010-11
	220 के वी आराकोट त्यूनी-मोरी लाइन, मोरी हनोल का लीलो	2x2	0.37	1.60	2.50	2010-11
जखोल सनकरी (33 एम डब्लू)	220 के वी डी सी जखोल संकरी - मोरी (220 के वी) लाइन	2x30	5.58	24.00	37.50	2010-11
	220 के वी जकोल संकरी-मोरी (220 के वी) लाइन नेटवार मोरी का लीलो	2x8	1.47	6.40	10.00	2010-11
	220 के वी लखवार-खोदरी, ब्यासी का लीलो	2x5	0.93	4.00	6.25	2010-11
नटवर मोरी (33 एम डब्लू)	220 के वी मोरी खोदरी लाइन नौगांव का लीलो	2x5	0.93	4.00	6.25	2010-11
	220 के वी मोरी एस एस	2x50 एम वी ए	13.95	60.00	150.00	2009-10
ब्यासी (120 एम डब्लू) लखवाड़ (300 एम डब्लू)	220 के वी उपकेन्द्र नौगांव	2x50 एम वी ए	13.95	60.00	150.00	2011-12
योग (708 एम डब्लू)		**200 एम वी ए**	**64.16**	**276.00**	**593.75**	
(II) भागीरथी बेसीन						
लोहारी नागपाला (600 एम डब्लू) पाला मनेरी	400 के वी डी सी लाहोरी नागपाला-कोटेश्वर लाइन और लाहोरी नागपाला-कोटेश्वर लाइन, पाला मनेरी का लिलो	2x92	40.00	184	464.25	2010-11

(480 एम डब्लू) कोटीभेल I-अ (195 एम डब्लू) कोटीभेल I-ब (320 एम डब्लू) कोटीभेल एस टी II (530एम डब्लू) भिलंगना - I (22.5 एम डब्लू) भिलंगना - II (49 एम डब्लू) भिलंगना - III (24 एम डब्लू)	400 के वी एस एस रूड़की, पी जी सी आई एल- 220 के वी एस एस रूड़की से 220 के वी रूड़की लाइन	2x15	2.79	12.00	18.75	2011-12
	220 के वी डी सी कोटलीभेल एस टी - II- रूड़की लाइन	2x90	25.12	108.00	247.50	2011-12
	220 के वी डी सी कोटली भेल - I ब- कोटलीभेल-II लाइन एवं कोटलीभेल - II से इस लाइन का लीलो	2x34.5	6.51	28.00	60.38	2011-12
	220 के वी डी सी भिलंगना- III घनसाली लाइन	2x15	2.79	12.00	18.75	2007-08
	220 के वी डी सी भिलंगना- III घनसाली लाइन, भिलंगना II का लीलो	2x1	0.17	0.74	1.25	2007-08
	220 के वी घनसाली-चम्बा लाइन	2x50	9.30	40.00	40.00	2007-08
	220 के वी घनसाली एस एस	2x50 एम वी ए	0.23	50.00	6.25	2008-09
	220 के वी बे, चम्बा की ओर	1	11.63	1.00	87.50	2008-09
योग (2220.5 एम डब्लू)			**98.54**	**435.74**	**944.63**	
(III) अंलकनन्दा बेसिन						
लता तपोवन (171 एम डब्लू)	400 के वी डी सी विष्णु गाड-क्वारीपास (पीपलकोटी) लाइन	20	9.30	40.00	75.00	2010-11
बद्रीनाथ (140एम डब्लू)	400 के वी डी सी विष्णु गाड-क्वारीपास (पीपलकोटी) लाइन, विष्णु गाड पीपलकोटी का लीलो	3	1.40	6.00	11.25	2011-12
	400 के वी विष्णु प्रयाग-मुज्फरनगर लाइन, क्वारीपास का लीलो	5	2.33	10.00	23.75	2011-12
विष्णु गाड (520 एम डब्लू)	400 के वी डी सी क्वारीपास (पीपलकोटी) कर्णप्रयाग लाइन	45	20.93	90.00	213.75	2010-11
पीपल कोटी (444 एम डब्लू)	400 के वी डी सी श्रीनगर 400 के वी उपकेन्द्र श्रीनगर पावर हाऊस (एच ई पी)	6	2.79	12.00	22.50	2010-11
	220 के वी तपोवन-जोशीमठ लाइन	21	4.19	16.80	26.25	2010-11
भवाला नन्दप्रयाग (132 एम डब्लू)	220 के वी डी सी तपोवन-जोशीमठ लाइन, बद्रीनाथ का लीलो	62	11.63	50.00	77.50	2010-11
	220 के वी डी सी जोशीमठ-क्वारीपास (पीपलकोटी) लाइन	30	8.37	36.00	82.50	2010-11
	220 के वी डी सी देवसारी-कर्णप्रयाग लाईन	26	4.56	20.80	32.50	2010-11
नन्दप्रयाग लंगासू (141 एम डब्लू)	220 के वी नन्दप्रयाग-कर्णप्रयाग लाइन का लीलो	20	3.72	16.00	25.00	2010-11
	220 के वी डी सी नन्दप्रयाग-कर्णप्रयाग लाइन लंगासू का लीलो	8	1.51	6.40	10.00	2010-11
देवसारी	400 के वी डी सी कर्णप्रयाग-श्रीगनर लाइन	70	32.56	140.00	332.50	2011-12
	220 के वी डी सी ब्रहमवारी-श्रीनगर लाइन	70	13.02	56.00	87.50	2010-11

(300 एम डब्लू)	400 के वी डी सी श्रीनगर-काशीपुर लाइन	140	40.93	200.00	525.00	2011-12
	400 के वी (I सी के टी) क्वारीपास (पीपलकोटी)-श्रीनगर लाइन, कर्णप्रयाग का लीलो	10	4.65	20.00	37.50	2011-12
सिगोंली भटवाड़ी (60 एम डब्लू) गोरीकुंड (19 एम डब्लू)	400 के वी (II सी के टी) क्वारीपास (पीपलकोटी)-श्रीनगर लाइन, कर्णप्रयाग का लीलो	16	7.44	32.00	60.00	2011-12
	220 के वी ब्रह्मवारी-श्रीनगर लाइन, शींगोरी भटवारी का लीलो	10	1.86	8.00	12.50	2010-11
	132 के वी डी सी गौरीकुंड-ब्रह्मवारी लाइन	30	4.65	20.00	37.50	2010-11
फाटाबंयाग (11 एम डब्लू)	132 के वी डी सी गौरीकुंड-ब्रह्मवारी लाइन, फाटाबयांग का लीलो	5	0.70	3.00	6.25	2010-11
	400 के वी एस एस कर्णप्रयाग	2x240 एम वी ए	34.65	125.00	350.00	2011-12
	400 के वी एस एस क्वारीपास (पीपलकोटी)	2x240 एम वी ए	29.07	125.00	312.50	2010-11
	400 के वी एस एस श्रीनगर	2x240 एम वी ए	18.60	80.00	250.00	2010-11
	400 के वी एस एस काशीपुर में 400 के वी एस एस श्रीनगर बे,	1	0.93	4.00	12.50	2010-11
	220 के वी एस एस ब्रह्मवारी	2x50 एम वी ए	13.95	60.00	150.00	2009-10
	220 के वी बे, श्रीनगर	2	0.47	2.00	12.50	2010-11
योग (1938 एमडब्लू)			**274.21**	**1179.00**	**2786.25**	
(IV) शारदा बेसीन						
खासीवाड़ा (260 एम डब्लू)	220 के वी मदकोट-कासीवाड़ा लाइन	12	2.33	10.00	15.00	2010-11
	400 के वी डी सी ऊर्थीग सोबला -पिथौरागढ़	105	34.42	148.00	393.75	2011-12
ऊर्थींग सोबला (280 एम डब्लू)	400 के वी डी सी ऊर्थीग सोबला-पिथौरागढ़ लाइन धारचूला का (220 के.वी.) लीलो	10	4.65	20.00	37.50	2011-12
	400 के वी खासीबारा पिथौरागढ़ लाइन	95	40.93	164.00	356.25	2010-11
	220 के वी डी सी पिथौरागढ़ (पी जी सी आई एल) - अल्मोड़ा	80	14.88	64.00	100.00	2010-11
	220 के वी मदकोट एस.एस.	2x25 एम वी ए	11.63	50.00	125.00	2010-11
	220 के वी एस एस धारचूला	2x50 एम वी ए	11.63	50.00	150.00	2010-11
	220 के वी एस एस अल्मोड़ा	2x100 एम वी ए	11.63	50.00	87.50	2010-11
योग (540 एमडब्लू)			**132.10**	**556.00**	**1265.00**	
सकल योग			**569.01**	**2446.74**	**5589.63**	

परिशिष्ट 4.9

(सन्दर्भ प्रस्तर 4.2.13.3; पृष्ठ 201)

2007-08 से 2011-12 के दौरान पारेषण हानियों को दर्शाने वाला विवरण

विवरण	यूनिट	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पारेषण के लिए प्राप्त ऊर्जा	एम यूज	7400.60	10033.37	11449.90	11449.90	12299.00
शुद्ध ऊर्जा प्रेषित	एम यूज	7300.37	9846.52	11235.15	11235.15	12069.84
वास्तविक पारेषण हानि	एम यूज	100.23	186.84	214.75	214.75	229.15
	प्रतिशतता	1.35	1.86	1.82	1.88	1.86
सी ई ए के मानक के अनुसार पारेषण हानि का लक्ष्य	प्रतिशतता	5	5	5	5	5
यू ई आर सी के मानक के अनुसार पारेषण हानि का लक्ष्य	प्रतिशतता	2	2	2	2	2
पारेषण हानि जो यू ई आर सी के मानक से अधिक है। (पैरा 1.9 पंक्ति चार के अनुसार प्रति इकाई प्राप्ति की कीमत)	एम यूज	-	-	-	-	-
	₹ प्रति इकाई दर	-	-	-	-	-
	₹ करोड़ में	-	-	-	-	-

(स्रोतः कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

संक्षिप्त शब्दों का शब्दकोष

क्र.स.	संक्षेप	विस्तृत रूप
1.	ए सी	लेखापरीक्षा समिति
2.	ए डी बी	एशियन विकास बैंक
3.	ए एल डी सीज	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
4.	ए आर आर	कुल राजस्व आवश्यकता/वार्षिक राजस्व आवश्यकता
5.	बी बी पी पी	बस बार प्रोटेक्शन पैनल
6.	बी डी आई	बैकिंग डाऊन निर्देश
7.	बी ओ डी	निदेशक मण्डल
8.	बी एच ई एल	भारत हेवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड
9.	सी बी	सर्किट ब्रैकर
10.	सी ई ए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
11.	सी ई आर सी	केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग
12.	सी के एम	सर्किट किलोमीटर
13.	सी टी	करंट ट्रांसफॉर्मरर्स
14.	सी टी आई	तकनीकी कोड इन्टरफेस
15.	सी टी यू	केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी
16.	सी वी सी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
17.	डी सी	डबल सर्किट
18.	डी जी सेट	डीजल जनरेटिग सेट
19.	डी जी ए	प्रवित गैस विशलेषण
20.	डी एम	आपदा प्रबन्धन
21.	डी पी आरस	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
22.	ई एच टी	अतिरिक्त हाईटेन्शन
23.	जी आई एस	गैस पृथक्करण सब-स्टेशन
24.	जी ओ आई	भारत सरकार
25.	जी ओ यू	उत्तराखण्ड सरकार
26.	जी टी	उत्पादन से पारेषण
27.	एच एल टी	हॉट लाइन तकनीक
28.	एच टी	हाई टेन्शन
29.	एच जेड	हर्ट्ज (आवृत्ति)
30.	के वी	किलो वोल्ट
31.	एल सी	साख पत्र
32.	एल आई एल ओ	लूप इन लूप आउट
33.	एम ए	मोबलाइजेशन एडवान्स
34.	एम डी	प्रबन्ध निदेशक
35.	एम आई एस	प्रबन्ध सूचना तंत्र

36.	एम ओ पी	ऊर्जा मंत्रालय
37.	एम ओ यू	समझौता ज्ञापन
38.	एम आर आई	मीटर रिडिंग यंत्र
39.	एम टी पी सी	पारेषण आयोजना मापदण्ड का मैनुवल
40.	एम यू	मिलियन यूनिट
41.	एम वी ए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
42.	एम डब्लू	मेगावाट
43.	एन ई पी	राष्ट्रीय विद्युत नीति
44.	एन टी पी सी	राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम
45.	ओ एण्ड एम	परिचालन एवं रखरखाव
46.	ओ एल टी सी	ऑन लोड टैप चेंजर
47.	पी एफ सी	ऊर्जा वित्त निगम
48.	पी एफ आर	परियोजना वित्तीय प्रतिवेदन
49.	पी जी सी आई एल	पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड
50.	पी टी सी यू एल	पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड
51.	क्यू ए/क्यू सी	गुणवत्ता आश्वासन/गुणवत्ता नियंत्रण
52.	आर ई ए	क्षेत्रीय ऐनर्जी लेखा
53.	आर एल डी सी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
54.	आर ओ डब्लू	राइट ऑफ वे
55.	आर पी सी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
56.	आर टी यूज	रिमोट टर्मिनल यूनिट
57.	एस सी	सिंगल सर्किट
58.	एस ई पी	राज्य विद्युत योजना
59.	एस एल डी सी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
60.	एस एम एसस	उपकेन्द्र प्रबन्ध प्रणालियाँ
61.	एस एस	उपकेन्द्र
62.	एस टी यू	राज्य पारेषण यूटीलिटी
63.	टी एण्ड डी	पारेषण तथा वितरण तक
64.	टी डी	पारेषण से वितरण तक
65.	टी एच डी सी	टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड
66.	टी एल एल	ताप लोडिंग सीमा
67.	यू ई आर सी	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
68.	यू आई टी पी	उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना
69.	यू पी सी एल	उत्तराखण्ड ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड